## सर्वाधिकार सुर्राज्ञत

प्रथम सस्करण १६५३ द्वितीय सस्करण १६५५ जितीय सस्करण १६५७ चतुर्थ सस्करण १६५६

#### अध्याय १

# भारतीय अर्थशास्त्र का अर्थ

श्रर्यशास्त्र को श्रध्ययन की सुविधा के लिए दो मागों में बॉटा गया है जिनमे से एक माग 'सैंद्रान्तिक श्रर्यशास्त्र' (Theory of economics) श्रीर दूसरा माग 'व्यवहारिक श्रर्यशास्त्र' (Applied economics) कहा जाता है। सेद्रान्तिक श्रर्यशास्त्र में हम कुछ ऐसे श्राधारभूत सिद्रान्तों का श्रध्ययन करते हैं जो श्रावश्यकताश्रों (wants) की पूर्ति के सम्बन्ध में मनुष्य के व्यवहार की विवेचना करते हैं जब कि उद्देश्य दिये हो श्रीर उनकी पूर्ति के साधन श्रप्यांत्र हों तथा उनके विभिन्न प्रयोग हो। श्रर्यशास्त्र में इन श्राधारभूत सिद्रान्तों को हम उत्पादन, उपभोग विनिमय श्रीर वितरण के श्रन्तर्गत श्रध्ययन करते हैं। सीमात उपयोगिता के हास का नियम, उत्पादन के नियम, लगान का सिद्रान्त श्रीर रोजगार तथा व्यवसाय चक के सिद्रान्त श्रर्यशास्त्र के इन श्राधारभूत सिद्रान्तों के ही उदाहरण हैं। हम सैद्रान्तिक श्रर्यशास्त्र का श्रद्ययन या तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं या विश्लेपणात्मक दृष्टि से। यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से श्रप्ययन किया जाय तो इसका रूप 'श्रर्यशास्त्र की विचारधारा का इतिहास' जैसा हो जाता है श्रीर दूसरी स्थिति में विश्लेषणात्मक श्रर्यशास्त्र भी कहते हैं। Economics) जैसा हो जाता है जिसे संदोप में केवल श्रर्यशास्त्र भी कहते हैं।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न है। इसमें उन समस्यात्रों का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्नों के बीच पैदा हो जाती हैं, जैसे कृषि और उद्योग की समस्यायें, उत्पादन, आयात और निर्यात, बैंक और मुद्रा व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, आदि। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र की माँति, व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं और ऐसी स्थित में अर्थशास्त्र 'आर्थिक इतिहास', (Economic History) का रूप धारण कर लेता है। यदि विश्लेषण की दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह 'वर्तमान आर्थिक समस्याओं के अध्ययन' का रूप ले लेता है।

सैद्धान्तिक श्रर्थशास्त्र की उत्पत्ति वास्तव में मनुष्य के व्यवहार के कुछ श्राधारमूत सिद्धान्तों श्रीर जनता की श्राधिक स्थिति के श्रावार पर होती है। उदा-हरगा के लिये, प्राचीन श्रर्थशास्त्र के सिद्धान्तो पर हगलैंड की १८ वीं शताब्दी की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पदा। इसके बाद जनता थी श्राधिक रिशति में श्रमेक परिवर्तन हुए श्रीर उन परिवर्तनों के पलरक्षण श्राधिक विद्यानों में भी सशोधन परिवर्दन होते गये। जैसे ही नयी परिस्थितको उत्पाद हुई उनकी ज्यादया करने के लिये या तो पहले के श्राधिक सिद्यान्ती था जिस्तार विया गया ना नये सिद्धान्ती का जन्म हुआ। हम वर्तमान भी श्राधिक समस्यात्रा का श्रप्यक्षण करने के लिये या त्राधिक हतिहास लाकने के लिए श्रथ्यान्य व सिद्धान्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तक श्रीर ज्याहा कि एक्श्यान में परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है।

भारतीय छार्यशारत्र—भारतीय त्रयंशास्त्र घराहाम्क त्रयंशास्त्र रा एक छात्र है। इसक अन्तर्गत वर्तमान समय की श्रित पार्थिक समकारा ना प्रथ्ययन किया जाता है, जैसे, जनवन्दी, भूमिन्न गा, मैनिन्न एकेन्सा मन्तर्गा, ह पादि त्रोर साथ ही उनका उत्पत्ति कारणों का भी किन्न । क्या जाता है। इस त्रर्थ में भारतीय प्रथ्यास्त्र का प्रथ्ययन विश्लेषणा मा हा जाता है। इस प्रथं में भारतीय प्रथ्यास्त्र का प्रथ्ययन विश्लेषणा मा हा जाता है। इसने पह अन्तर किया जाता है कि वर्तमान छार्थिक पनिक्तियों हा सही स्वर्ध भी जताया ताय कि जाय, विभन्न घटनात्रों के कारणों का समकाया जाय और यह भी जताया ताय कि जिन घटनात्रों के उत्पत्र होने की सम्भावना थी, पह प्रया नहीं को समान समय की समस्यात्रों का छाष्ययन करने और हो जाता है। वर्तमान समय की आर्थित समस्यात्रों का छाष्ययन करने और इसकी मार्वा प्रवृत्तियों का प्रथ्यता से सह से संवर्ध छास्त्र की सहायता सेते हैं। यदि अर्थशास्त्र के सिद्धात ।भन्न-भित्त हैं तो हम जिन परिशामों पर पहुंचते हैं वह भी अवस्य भिन्न होंगे। इसलिये भारतीय अर्थशास्त्र का मुर्ययन चहुत कुछ हमारे सेद्धातक अर्थशास्त्र के जनन पर निर्भर रस्ता है।

जैसा कि इस पहले यह जुके हैं भारत में विभिन्न श्रार्थिक समस्याश्रों के पेतिहासिक विकास का प्रध्ययन 'मारत का श्रार्थिक इतिहास' कहा जाता है। श्रार्थिक इतिहास में घटनाने नमानुसार लियी जाती हैं। भारतीय श्रार्थशास्त्र' को साय-साय दिया गया है श्रीर पाटक को इन दोनों श्र्यों का साय-साय श्रार्थिक करना पहला है। इससे पाटक के लिये शावश्यक श्रीर सम्मिन्यत समस्याश्रों को समस्ता श्रीर वर्तमान समस्याश्रों पर ध्यान नेन्द्रित करना फाटन हो जाता है। यह बात निस्सन्देह सही है कि भारत के श्रार्थिक इतिहास के श्रीर्थयन ने श्राधार पर ही वर्तमान श्रार्थिक समस्याश्रों का सही श्रद्ध्ययन किया जा सकता है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि यदि हम भारत ने श्रार्थिय इतिहास श्रीर मारतीय

श्रर्थशास्त्र को एक मे मिला दे तो वर्तमान श्राधिक समस्याएँ, जिन पर पाठ्क को ध्यान देना श्रावश्यक है, भारत के श्राधिक इतिहास के विस्तृत विवेचन में लुप्त हो जाती है। इसिलिये इस पुस्तक मे यह प्रयत्न किया गया है कि भारतीय श्रथशास्त्र की समस्याएँ श्राधिक इतिहास के विस्तृत वर्णन मे खो न जायँ। जहाँ श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा है वहाँ तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये श्राधिक इतिहास का कुछ विश्तृत वर्णन किया गया है। परन्तु विशेष जोर मारत की वर्तमान श्राधिक समस्याश्रों के विवरणात्मक श्रोर विश्लेषणात्मक श्रव्ययन प्रदिया गया है।

अन्य परिभाषाये—पूर्व लिखित परिभाषा के अनुसार भारतीय अर्थशास्त्र भारत को वर्तमान आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। परन्तु भारतीय अर्थशास्त्र की इसके अतिरिक्त तीन और परिभाषायें दी गयी हैं:—

- (१) भारत की आर्थिक विचारधारा के विकास के अध्ययन को भारतीय अर्थशास्त्र कहा गया है। प्राचीन भारत में मैद्रान्तिक अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया था। भारतीय आर्थिक विचारधारा पश्चिमी आर्थिक विचारधारा के साथ-साथ विकास नहीं कर सभी है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के सिद्रान्तों के चेत्र में भारत ने अवश्य कुछ योगदान किया है। यदि इस पर विचार न किया जाय तो भारतीय आर्थिक विचारधारा पूर्णत्या प्राचीन भारत की देन है। यदि यह मान भी लिया जाय कि भारतीय आर्थिक विचारधारा आधुनिक सैद्रान्तिक अर्थशास्त्र के साथ विकास कर सकी है तब भी हम उसे भारतीय अर्थशास्त्र का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अर्थ है जब कि आर्थिक विचारधारा का इतिहास, चाहे वह भारतीय हो या यूरो-पीय, 'सैद्रान्तिक अर्थशास्त्र' के अन्तर्गत आता है।
- (२) यह कहा गया है कि भारत की सामाजिक श्रीर घामिक स्थिति एक विशेष प्रकार की है, उसकी गठन श्रीर उसमें निहित विचारघारा श्रन्य देशों से भिल्न है इसिलये भारतीय परिहियतियों के श्रनुक्ल हमे विल्कुल ही नये प्रकार के श्रार्थिक सिद्धान्तों का सुजन करना चाहिए श्रीर उसे 'भारतीय श्रर्थशास्त्र' कहना चाहिए। न्यायाधीश रानाडे ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्थिति पश्चिमी देशों से नितान्त भिल्न है, प्रतियोगिता (Competition) से कहीं श्रिषिक प्रभावशाली यहाँ के रीति-रिवान श्रीर राज्य के नियम हैं, साथ ही किसी समक्तीते की श्रपेक्। समाज में सम्मान श्रिषक प्रभाव रखता है। यहाँ न पूँजी गतिशील है श्रीर न श्रम श्रीर न इनमे इतना उत्साह (enterprising) श्रीर बुद्धि ही है कि गतिशील बनें। मजदूरी श्रीर लाम भी निश्चत है, जनसख्या

श्रपने नियम के ध्रनुसार उहती जाती है परन्तु नीमारियां ग्रीर ग्रकाल से उसमें कमी भी होती रहती है, उत्पादन वी माधा प्राय स्थिर है, यदि एक वर्ष फसल श्चच्छी हो गयी तो वह स्रगले वर्ष के श्रनिश्चित मोष्ठम से होने वाली हानि की पूर्ति का साधन बन जाती है। इसके ग्राधार पर न्यायाधीश रानाढे इस परिणाम पर पहुँचे कि श्रादुनिक श्रर्यशास्त्र के मिदान्तों में जिन वातों को निश्चित श्राधार मान लिया गया है वह भारत म लागू ही नहीं होती विल्फ यह वास्तव में गलत दिशा की श्रोर ले जाती है। इससे कुछ लोग इस परिगाम पर पहुँचे कि भारत की ग्रार्थिक स्थिति को समझने के लिये नये ग्रार्थिक सिदानतों की ग्रायश्यकता है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहां है। कोई भी श्रार्थिक सिद्धान्त, चाहे वद पश्चिमी देशों में विकसित हुआ हो या पूर्वी देशां में, ब्यापक रूप में सारे विश्व पर लागू होता है। यार्थिक सिदान्त मनुष्य के स्वमाव पर ग्राधारित होता है श्रीर मनुष्य का स्वभाव सर्वत्र समान होता है। यदि श्रार्थिक सिद्धान्त का उचित निरूपण् किया गया है तो वह सर्वत्र लागू होगा। परन्तु यह मानना पढ़ेगा कि आर्थिक विद्यान्त स्थिर विद्यान्त नहीं होता और न वह अपरिवर्तनशील ही होता है। यदि श्रार्यिक स्पिति में परिवर्तन हुया तो श्रार्थिक चिद्रान्त में भी परिवर्तन होगा। इगलैंड में पाचीन सेटान्तिक ग्रर्थशास्त्र का जो निकास हुगा वह इंगलैंड की उस समय की आर्थिक हियनियों पर आधारित था। वह यदु भाव्य नीति (Laissez faire) श्रौर स्नतन न्यापार (Free trade) के सिद्धान्तों पर श्राघारित या। परन्तु बाद में जब विशेष रूप में युरोपीय देशों म यह पता चला कि स्वतन्न न्यापार आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकृत है तो फोड़िन लिस्ट तथा अन्य अर्थ-शास्त्रियों की त्रालोचना के ब्राघार पर स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त में ब्रावश्यक सशोधन किया गया श्रोर कम विक्रित देशों के सरहरण के लिये तटकरों (Tariffs) तथा अन्य उपायों का महत्व स्वीकार किया गया । सोनियत सव की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ समाजवाद श्रीर त्रार्थिक नियोजन के सिद्धानतों मे भी परि-वर्तन होता गया। इघर कुछ वर्षों से पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए चेत्रों की अपर्धिक समस्यात्रों के कारण आर्थिक सिद्धान्तों में परिवर्तन-परिवर्द्धन हो रहा है। भारत मे श्रान्यात्मिक विचारधारा से प्रमावित 'श्रावश्यकता' का एक विल्कुल नया सिङ्गात निकसित हो रहा है निसे 'श्रावश्य-कता रहित होने का विद्वान्त' (Theory ef wantlessness) कहा जाता है। यह पश्चिम के छावश्यकता के सिद्रान्तों से नितान्त मिन्न है। यह समव है कि विभिन्न देशों की बदलती परिहियतियों से प्रभावित हाकर, जिनमें भारत भी समिलित है, भविष्य में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों मे और भी संशोधन हो । परन्त जातिवाद, सयुक्त-परिवार की प्रया, अम और पृजी में गतिशीलता का श्रमाव, इत्यादि इस बात को सिद नहीं करते कि इस देश के लिये नये प्रकार के श्रार्थिक सिदान्तों की श्रावश्यकता है। मॉग श्रोर पूर्ति का सिदान्त जितना भारत में लागू होता है उतना ही श्रन्य देशों में भी लागू होता है। इसलिये इमारी भारत की भिन्न परिस्थितियों के कारण नये प्रकार के श्रार्थिक सिदान्तों का विकास करने की माँग उचित नहीं है, साथ ही इन विशेष सिदान्तों श्रीर नियमों को जो केवल मारत में लागू होंगे 'मारतीय श्रर्थशास्त्र' का नाम देना न्यायसगत नहीं है।

(३) यह भी कहा गया है कि यदि उपभोग, उत्पादन, विनिमय स्नौर वितरण के स्नार्थिक सिद्धान्तों का विवेचन भारतीय उदाहरणों के साथ किया गया हो तो उसे भारतीय स्नर्थशास्त्र कहा जाना चाहिये। किसी भी सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समकाने के लिये निश्चय ही कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है परन्तु इससे ही वह 'भारतीय स्नर्थशास्त्र' नहीं हो जाता। यदि कोई पाट्य पुस्तक स्नम्रेज विद्यार्थियों के लिये लिखी जाय तो यह स्वाभाविक ही है कि 'उसमें स्नम्नेजी या हगलैंड के उदार हरण दिये जायेंगे। इसी प्रकार यदि कोई पाट्य पुस्तक भारतीय विद्यार्थियों के लिये लिखी जाय तो उसमें भारत के उदाहरण दिये जायेंगे। परन्तु इतने से ही वह 'स्नमेजी स्नर्थशास्त्र', या 'भारतीय स्नर्थशास्त्र' नहीं बन जाते। इन परिस्थितियों में वह केवल सैद्धान्तिक स्नर्थशास्त्र रहता है चाहे उसमें किसी भी देश के उदाहरण दिये गये हों।

इससे स्पष्ट है कि भारतीय श्रयंशास्त्र भारत की वर्तमान श्रार्थिक समस्यात्रों का ठीक वैसा हो श्रय्ययन है जैसा श्रन्य देशों में किया जाता है। वर्तमान श्रार्थिक समस्याश्रों का श्रथ्ययन करने के लिये श्रन्य देशों की माँति ही भारत में भी हम देश की समस्याश्रों पर उन श्रार्थिक सिद्धान्तों को लागू करते हैं जो सर्वत्र सत्य सिद्ध हो चुके हैं या उन्हें सभी स्वीकार करते हैं। इसलिये श्रयंशास्त्र के श्रार्थिक सिद्धान्तों को भारत की श्रार्थिक स्थिति पर लागू कर हम जिन परिणामों पर पहुँचते हैं तथा जिन प्रवृत्तियों का पता लगाते हैं उनको भारतीय श्रयंशास्त्र' कहते हैं तो यह नितान्त न्यायसगत है।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता

(१) यदि इम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सही सही समक्तना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इम भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। इसके अध्य-यन से इम यह जान सकते हैं कि इम प्रगति कर रहे हैं या नहीं, यदि कर रहे हैं तो किस सीमा तक और यदि प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण क्या हैं। (२) भारतीय श्रयंशास्त्र के अध्ययन से इम अपने देश जी अन्य देशों के खाय बुलना कर सकते हैं त्योर इस अकार की बुलना से यह जान सकते हैं कि इम किम फेकार तथा किस दिशा में सिकय टोकर अपनी किमयों को दूर कर सकते हैं और आधिक उर्जान के अभीष्ट स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। (३) भारतीय अर्थणान्त्र का अध्ययन करके ही इस भिवष्य के लिये अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। पद्ध-वर्षीय योजना तैयार करने में और योजनाओं को प्रमुखता देने में योजना श्रायोग को भारतीय अर्थशान्त्र के अध्ययन पर ही अपने निर्धारा को श्रावारित करना पड़ा। भारत के आधिक विभाग में को बुद्धियों यह गरी है तथा आयोग ने आधिक प्रगति की वाछित गिन से उन्हें दूर कर देने के सुम्काव भारताय श्रयंशास्त्र के अध्ययन के आधार पर हा दिये हैं।

#### श्रध्याय २

t

## प्राकृतिक साध**न**

#### भौगोलिक स्थिति

किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति तथा उनके व्यवसायों पर उम देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाक शक्ति, वर्षा, जलवायु ओर उसकी बनस्पति तथा उसके वन्य एवम् पालत् पशुओं का विशेष प्रमाव पड़ता है। इस-लिये भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है।

भौतिक विशेषताऍ—भारतीय सब का च्रेनकल १२६६६४० वर्ग मील है। उत्तर से दिल्ल तक इस देश की लम्बाई २००० मील श्रीर पूर्व से पिक्षम तक १७०० मील है। इसकी भौतिक सीमा ८२०० मील श्रीर सामुद्रिक सीमा ३५०० मील है। कर्क रेखा इसकी बीचों-बीच से दो भागों में बॉटती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण किटबन्ध में श्रीर दिल्ला उष्ण किटब्ध में स्थित है। जम्मू श्रोर काश्मीर तथा श्रम्हकर १६५३ में निर्मित श्रॉध राज्य सिहत भारत सब में राज्यों के पुनर्स्वकन के पूर्व २६ राज्य थे। १ नवम्बर १६५६ में राज्यों का पुनर्स्वगठन होने के पक्षात् अब भारत सब में १४ राज्य यथा श्रॉध प्रदेश, श्रासाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, मैस्र, उद्यीस, पजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बद्वाल, जम्मू श्रीर काश्मीर, तथा केन्द्रीय प्रशासन के दिक्षी, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, श्रहमन-निकोवार द्वीप समूह श्रीर लेकहिव, मिनिकाय, श्रामिन्दिवी द्वीप समूह नामक ६ प्रदेश हैं।

भारत उत्तर में हिमालय, उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में पर्वतश्रेणियो, दिल्ला में बगाल की खाडी श्रोर हिन्द महासागर श्रोर पश्चिम में श्ररब सागर द्वारा बिरा हुश्रा है। भारत को चार विभिन्न मौगोलिक भागों में बॉटा जा सकता है (१) हिमालय, (२) गङ्गा का मैदान, (३) दिल्ला पठार, (४) तटवर्ती प्रदेश। हिमालय की श्रेणियाँ १५०० मील की लम्बाई में श्रोर १५० मील से लगा कर २५० मील तक की चौड़ाई में फैली हुई हैं। हिमालय उत्तर की वर्फीली वायु से तथा उत्तरीय विदेशियों के श्राक्रमण से भारत की सदा से रक्षा करता श्राया है। इसके कारण उत्तरीय सीमा के मार्गो से व्यापार में भी वाधा पहुँची है। मान-स्न को रोक कर भारत के उत्तरीय भाग की प्रचुर वर्षा का साधन हिमालय ही रहा है। मारत को श्रनेकों नदियों का उद्गम हसी भाग से हुश्रा है। यहाँ बहु- मूल्य वन पाये जाते हैं जिनका पूर्ण प्रयोग होना राभी वाकी है। इसका श्राध-काश भाग काश्मीर ज़ीर जम्मू की घाटियों तथा पूर्वीय चाय क चेत्रों को छोड़ कर खेती के जायोग्य है।

गद्धा का मैटान पूर्व से पश्चिम की श्रोर लगभग १५०० मील लम्बा स्वीर उत्तर से दिल्ला की श्रोर १५० से लगाकर २५० मील तक सीटा है। यहाँ श्रनेकों निद्याँ श्रपनी महायक निद्यों के खाथ बहती है। यहाँ श्रीम बहुत उपनाक है श्रीर इखीलिए यहाँ की जनसँरया का घनत्व भी सनमे श्रीयक है। रेश के बहुत बड़े-उड़े नगर इखी भाग में स्थित है।

पठारी भाग को विष्याचल पर्वत शेणी के दक्षिण में स्थित है, दो भागा में बीटा जा सकता है। (अ) मध्य भारतीय पठार श्रीर (ब) दिनगी पटार !

पटारी माग गद्धा के मेटान के निषरीत श्रनेकों पर्यंत के शियों ने भरा हुआ है। इनकी ऊँचाई १५०० से ४४०० फोट तक है। उस माग के टोनों श्रोण पूर्वीय श्रोर पिश्चमीय घाट की पर्वत शेखियों हैं। पठाण स्यय पगरीला जीए ऊँचानीचा है। इसका विस्तार पूरे दिल्लिया की पदािश्यों तक है जो कही-एही पर ४००० फीट ऊँची हैं जैसे नील घाटी श्रीर कार्टमाम की पहािश्यों। इस पठार से होकर नर्मदा श्रीर तासी निहयों वहतीं हैं जो श्रद्य सागर में गिरती हैं शीर महानरी, कृष्णा तथा कावेरी जो बगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बनो की इस प्रदेश में कमी है पर खीनज पटार्थ पयास माणा में मिलते हैं। समुद्री तट कटे हुए नहीं हैं। इसलिये स्वामाविक बन्दरगाह केवल विजगायहम, कोचीन श्रीर कालीकट हैं। पूर्वी श्रीर पश्चिमी तटों की भूमि उपजाक है। वहाँ पर्यास चर्मा होती है तथा चावल चाय श्रीर कहवा पैटा होता है।

जलवायु घोर वर्षा—भारत की जलवायु मानस्नी तथा उप्ण प्रदेशीय है। यहाँ की तीन प्रमुख ऋतुर्ये निम्न हें (१) मार्च के श्रारम्भ ने जून के श्रन्त तक गमी की ऋतु, (२) जून के श्रत से खितम्बर के श्रत तक वर्षा ऋतु श्रीर (३) श्रवहूबर से फरवरी के श्रत तक शीत ऋतु । श्रवेल श्रीर मंदे के महीनों में स्थं की किरणें चीची लम्बवत परती हें श्रीर ये महीने देश ने चब से श्रविक गर्म होते हैं। उत्तरी-पूर्वी भारत में मई के महीने का श्रीचत तापकम १००° फैरनहाइट होता है श्रीर गगा के डेल्टा में लगभग प्रभू फें। किर्मी स्थानों पर तापकम ११७° ११८० फें। मी हो जाता है। जून के मध्य में मानस्नी हवायें चलने लगती है श्रीर विजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। श्रिधकाश वर्षा दिस्तिणी-पश्चिमी मानस्न के कारण होती है। उत्तरी-पूर्वीय मानस्न ट्रावनकोर कोचीन तथा महास के कुछ भागों में वर्षा का कारण होती है। श्रीतकाल में

जनवरी के महीने में उत्तर से दिल्या के भागों में तापकम बदलता रहता है।

वर्षों के दिल्टकोग से देश को चार मुख्य भागों में बॉटा जा सकता है। दिन गरम और राते ठंडी होती हैं। (१) श्रात्यधिक वर्षा वाला भाग जहाँ ५०" के लगमग वर्षा होती है जैसे श्रासाम, बगाल, उत्तरी बिहार, प्रायद्वीप का पश्चिमी तट ग्रीर कुछ पूर्वीय तट के माग, (२) साधारण वर्षा वाले माग जहाँ ४०" से लगाकर 50" तक वर्षा होती है जैसे उदीसा, दिश्वणी विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ग्रीर पिश्वमी घाट की पहाड़ियाँ; (३) बहुत कम वर्षा वाले भाग जहाँ २०" से ४०" तक वर्षा होती है जैसे मद्राप, मैसर, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान श्रीर पूर्वीय पजाब श्रीर (४) सूखे रेगिस्तानी भाग जहाँ २०" से भी कम वर्षा होती है जैसे राजपूताना का रेगिस्तान, पश्चिमी काश्मीर श्रीर पनान के माग। मारतवर्ष में वर्षा की मुख्य विशेषता उसकी भ्रनिश्चितता है। यह ठीक ही कहा गया है कि भारतीय कृषि 'वर्षा का जुम्रा' है। यदि वर्षा समय से पर्याप्त हो गई तब तो फसल अन्छी होगी, किसान प्रसन्न होंगे और अन पर्याप्त होगा। पर यदि वर्षा देर से हुई और अनियमित रूप से हुई, कहीं अत्यधिक और कहीं अतिन्यून, तो स्वा पहेगा बाढ श्रायेगी श्रीर लोगों

भूमि-भारत की भूमि को निम्न भागों मे बाटा गया है (1) कॉप मिट्टी की कठिनाइयों की सीमा न रहेगी। (11) कालां मिट्टी (111) लाल मिट्टी जिसमें लाल चिकनी श्रौर पीली मिट्टी मिली होती है (1V) तेटेराइट मिट्टी (V) रेतीली मिट्टो (VI) लवणयुक्त श्रीर चारिल मिट्टो श्रीर (vii) जीया मिट्टी। इनमे से प्रथम चार तो मुख्य हं श्रीर दूसरी चार गीया जो कि कहीं-कहीं पाई जाती है। "प्रथम तीन प्रकार की मिष्टियों में पोटाश श्रीर चूना पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है पर उनमें फास्फोरिक एसिड, नाइद्रोजन श्रोर स्मुस बहुत कम हैं। लेटेराइट मिट्टी में झूमस की मात्रा पर्याप्त है पर अन्य रसा-यनिक गुण कम है। कॉप मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ श्रीर बड़ी श्रासानी मे काम में लाई जाने योग्व है। यह मिट्टी सम्पूर्ण सिंघ, गंगा के मैदान में तथा पूर्वी श्रीर पश्चिमी तट प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी जिसमें नमी को रोक रखने की शक्ति श्रपार होती है स्प्रीर जो बहुत चिपचिषी होती है दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है श्रीर लाल मिट्टी इसी भाग के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मध्यभारत, श्रासाम, पूर्वी-पश्चिमी घाट के किनारे पाई जाती हैं"। जल ध्रीर विद्युत के साधन — चूंकि भारत में श्रनेक निद्या श्रीर

मरने हैं इसिलये यहाँ पानी श्रीर विद्युत के साधनों की कमी नहीं है परन्तु खेद है कि इन साधनों का श्रमी तक उचित रीति से उपयोग नहीं किया जा सका है।

प्रति वर्ष भारत की नदियों में लगभग एक ग्ररा ३५ करोट ६० लाख एकर फुट पानी वह जाता है परन्तु इसमें से रेपल ७ मरोए ६० लाग एकए फ़र या मुल का केवल ५ ६ प्रतिशत विचाई के काम में लाया जाता है। पनुमान नगाया गया है कि ४५ करोट एकड़ फुट पानी सिचाई के काम में लाया जा सकता है। संमव है प्रथम पचरर्पाय योजना की पड़ी योजनाएं। को प्रायान्त्रित कर दैने से अधिक पानी का उपयोग किया जा उके श्रीर तब विजली का भी प्रधिक मात्रा में उत्पादन रिया जा सबेगा। इसके प्रतिरिक्त सिचाई की दृष्ट छोटी गोगनायें भी है जिनसे तालायों, कुत्रों त्रार नहरों का पानी भी सिचार के राम में लाया जा सकेगा। वर्तमाग समय मे ५ परोह (५ लाग एवट भूमि पर छिचाई होती है, जिसमें से २ परोट १० लाख एकड़ भूमि नहरों द्वारा सीची जाती है, १ प्ररोड़ ५० लाख से उछ रम एरड़ भूमि कुयों द्वारा भीची जाती है, ६० लाख एफड़ से उछ रम माम कुछ। द्वारा सीची जाती है जोर लगमग ७० लाख एकए जन्य सामनो के द्वारा। कृषि की सनमे बढ़ी समस्या सिचाई के लिये उपलब्ध जल की मात्रा बढाना है। मुमि की उत्पादन शक्ति, खादान, दालें, तथा कृषि के श्रन्य माल की कुल मात्रा, जिनका उत्पादन किसान कर सकता है, बहुत बुछ सिवाई की सुविधा पर निर्भर करता है। बन तक किमान के पास अपनी रोती में सिचाई करने के पर्याप्त साधन नहीं है तब तक चाहे वह कितना ही क्रयल श्रीर साहसी नयों न हों, श्रपना उत्पादन नहीं वढा सकता है।

भारत मे शक्ति के मुख्य साधन तेल, को नला श्रोर पानी हैं। भारत में पेट्रोलियम की कमी अवश्य है पर को यले की रानि बहुत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खानों में कुल को यला लगभग २० श्रस्न टन होगा। इसका एक चोयाई को यला बहुत श्रन्छ। को यला है श्रीर उसका प्रयोग बातुशों ने सबेध में सीमत रहना चाहिये। निम्नकोटि के को यले का प्रयोग शक्ति उत्पादन के लिये किया जा सकता है। परन्तु भारतीय उत्योगों श्रीर कृषि के लिये विद्युत शक्ति का समुचित प्रयोग श्रात्मक दि। परन्तु भारतीय उत्योगों श्रीर कृषि के लिये विद्युत शक्ति का समुचित प्रयोग श्रात्मक श्रीर श्रीर श्रीर श्रीर विश्वास की गति बड़ी घोमी रही है। इस वर्ष तक के जल १६२३४१ किलोबाट विद्युत शक्ति पेटा भी गई थी। १६३५ में यह शक्ति पचगुनी बढ़ गई श्रीर १००४०२ किलोबेट हो गई। प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रारम्भ में २३ लाख किलोबाट विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रयन्य था। नई योजनाशों के फलस्वरूप यह बढ़ कर ३४ लाख किलोबाट हो गयी। इससे यह सिंद होता है कि देश को श्रीधम विद्युत शक्ति प्रदान करने वाली पोजनायें सफल रही हैं। दितीय पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत विश्वास किलोबाट शक्ति के बढ़ाने का विचार किया है। जब सब दीर्घकालीन

योजनायें तीन या चार पचवर्षीय योजनाश्चों के श्रन्त तक पूर्ण हो जायंगी तब विद्युत शिन्त लगभग ७० लाख किलोबाट बढ जायगी। हमारे देश में समस्या केवल श्रिषक विद्युत शक्ति के उत्पादन की ही नहीं है बरन् यह भी है कि विद्युत शिक्त पर्याप्त मात्रा में इतने सस्ते मूल्य पर लोगों को श्राप्त हो सके कि किसान, फैनट्टी वाले श्रीर श्रन्य साधारण कारीगर उसका श्रासनी से प्रयोग कर सकें।

### वनस्पति श्रोर जानवर

विशाल चेत्रफल, विभिन्न भोगोलिक स्थितियों, विभिन्न जलवायु इत्यादि के कारण भारत में वे छन प्रकार के वन, फलों के नाग, छीर खेती की उपज जो आयः उच्छ, श्रांत छोर छमशीतोष्ण जलवायु वाले भू-चेत्रा में पाये, जाते हैं प्राप्त हैं। देश में पालतू तथा वन्य पशु भी यनेक प्रकार के मिलते हैं।

वन—भारत में बनों का चेत्रफल लगभग १४ करोड़ ७७ लाख एकड है, जिसमें से ४ करोड़ ३५ लाख एकड़ जगल दिल्लियों भाग में, ३ करोड़ ६७ लाख एकड़ मध्यम भाग में, ३ करोड़ ६४ लाख एकड़ पूर्वी भाग में और ७ करोड़ ६८ लाख ७० हजार एकड़ उत्तरी-पश्चिमी भागों में स्थित है। दितीय महायुद्ध के समय श्रीर श्रानेक राज्यों में नमींदारी उन्मूलन के पूर्व बहुत बड़ी सख्या में वृत्त काटे गए, जिसके परिणामस्त्ररूप देश के बन-भदेश का चेत्रफल बहुत कम हो गया है। बनों से देश को बहुत श्राधिक लाभ होते हैं। उनमें डेंघन श्रीर हमारती लकड़ी तो प्राप्त होती ही है, इसके श्रातिरक्त (१) वे श्रीयोगिक उपयोग के लिए बाँस, सवाई व श्रन्य घासें, लाख, गांद हत्यादि भी प्रदान करते हैं, (२) वे भूमि- ज्ञारण (Soil erosion) रोजते हैं, भूमि की उर्वरता को सुरक्तित रखते हैं, श्रीर (३) पशुश्रों के लिए चरागाह भी प्रदान करते हैं।

वन राष्ट्रीय श्राय के श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सावन हैं। उनसे उद्योगों के लिए श्रमेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं। भारत क बनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याएँ यह हैं कि: (१) वनों के चेत्रफल म वृद्धि की जाय, (२) देश में जितने प्रकार के वृद्ध पाए जाते हैं उनका सरहाण किया जाय श्रोर (३) यथासमय नई जाति के वृद्ध भी उगाने प्रारम्भ हों। भारत सम्कार ने वन नीति से सम्बन्धित मई १९५२ के प्रस्ताव में भारतीय वनों की सुरद्धा श्रोर उनके विकास की श्रावश्यकता पर ध्यान दिया। उस प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की कुछ भूमि का एक-तिहाई भाग वनों के रूप में रहे। हिमालय-प्रदेश, दक्षिण श्रोर श्रन्य पर्वतीय चेत्रों पर वना के श्रन्तर्गत कुल भूमि का द०%रऐगा, जब कि समतल चेत्रों में कुल भूमि २०% पर जगल उगाए जायेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों की विकास-

सम्बन्बी नीति के त्रम्तर्गत यह व्यवस्था रखी गई थी कि (श्र) पुद्ध के समय में जो माग विल्कुल उजद गए थे, उनका नवकरण (renovation) हो, (व) जहाँ यधिक मात्रा में भूमि-सर्ग हुया था, वहाँ जगल लगाए जाय, (स) वनों में श्रावागमन के साधनों का विकास किया जाय, (द) ईधन के श्रमान को दूर करने के लिए गाँवों में श्रिधिक बाग लगाए जायं, श्रीर (य) कर्ड प्रकार की ऐसी लकड़ी, नो श्रव तक इमारती लकड़ी के रूप में काम में नहीं आरही थी, उसे ठीक ढग से सिकाने श्रीर मसाला लगाकर मनत्रूत बनाने के बाट श्रिधिकाधिक प्रयोग में लाया जाय। राज्य सरकारों की वन-सम्बन्धी नीति न तो मई १६५२ के वन-नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव के विल्कुल श्रनुकूल है श्रार न वनों की वेन्द्रीय सिमात (Central Board of Forests) के अनुरूप है। इस वन केन्द्रीय सिमिति की बैठक जून १६५३ को देहरादृन में हुई थी जिसने कई प्रस्ताव पास किए श्रीर जिनका उद्देश्य यह या कि राज्य सरकार भारत-सरकार की वन-नीति को कियात्मक रूप दें। १६५० में मारत-सरकार ने 'वन महोत्सव श्रान्दोलन' प्रारम किया, जिसका उद्देश्य यह है कि भारत से जगलों का अभाव दृर किया जाय। कितु अभाग्यवश इस कार्य-क्रम के अतर्गत लगाए गए अधिकांश वृत्त पानी न मिलने श्रीर लाप्रवाही के कारण सूख गए । श्रधिक वृत्त लगवाना श्रीर जब तक वे काफी बढ़े न हो जाय इनकी टेखमाल करते रहना तो ग्रावश्यक है ही, किंतु उसके साय-साय यह भी आश्यक है कि ईंघन अथवा अन्य किसी उपयोग के लिए खड़े वृत्त न कटवाए जायं।

मछली-उद्योग—"मारत के लम्बे समुद्र-तट पर अस्व मुहाने, नमकीन पानी वाली मीलें श्रीर स्थिर जलाशय हैं, जिनमें काफी मछलियाँ प्राप्त होती हैं। नमकीन पानी वाला चेत्र लगभग १० करोड़ ६० लाख एकड़ है, जिसमें चिल्का मील मी शामिल है। यह चिल्का मील २,५६,००० एकड़ के विस्तार में फैली हुई है और इससे प्रतिवर्ष ३,००० टन मछली प्राप्त होती हैं। मछली-उद्योग से भारत की राष्ट्रीय-श्राय में प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये श्राते हैं। यह मछली-उद्योग सुख्यत दो प्रकार ना है (१) देश के अदर का मछली उद्योग (Inland fisheries), (२) समुद्री मछली-उद्योग (marine fisheries)। मछली पकड़ने के आँवड़े भारत में विश्वस्त रूप से प्राप्त नहीं हैं। भारत में प्रतिवर्ष समुद्री मछलियों का उत्पादन लगभग १०० लाख मन है श्रीर ताजे पानी की मछलियों का उत्पादन स्थ लाख मन से कुछ कम होता है। श्रायात द्वारा प्राप्त मछलियों को मिलाकर भारत में प्रतिवर्ष २७० लाख मन की कुल पूर्ति होती है, जिसमें से ७०% मुहाने श्रीर समुद्र की मछलियों श्रीर श्रेष ३०% ताजे पानी की मछलियों होती हैं।

इसका श्रयं यह है कि प्रतिवर्ण प्रति व्यक्ति को ३४ पंड मछली मिलती है, जो निश्चित रूप से अपर्याप्त है। उत्तरप्रदेश और पजाब की श्रपेचाइत ट्रावनकोर को चीन, पिश्चमी बगाल श्रीर बम्बई में प्रति व्यक्ति मछली का उपयोग श्रिक है।" यह श्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्भ में मछलियों की कुल उत्पत्ति लगमग १० लाख मीट्रिक टन यी जिसका २०% घरेल् उपयोग के लिये थी श्रोर बाकी समुद्री मछली श्रयवा बेचने के लिये देश के अदर से प्राप्त मछलियों थी। प्रथम योजना के फलस्वरूप ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि मछलियों की उत्पत्ति १०% वह नायगी। १६५५—५६ में मछलियों की उत्पत्ति ११ लाख लाए मिट्रिक टन से कुछ श्रिक थी। दूसरी पचपर्षीय योजना में मछलियों का उत्पत्ति का उत्पत्ति का उत्पत्ति का सहिक टन हो जायगा। वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति मछलियों का वार्षिक उपभोग ४ पीएड से कम ही है। जनता का मोजन सतुलित करने के लिये यह आवश्यक है कि मछलियों का उपभोग बढाया जाय।

समुद्री मछलियों के उत्पादन की यहाने के लिए मछली पकड़ने में वैज्ञानिक यत्रों के प्रयाग करने की प्रावश्यकता है, क्यों कि प्रमी तक एक सीमित चेत्र में ही मछलियों का शिकार किया जाता है। जहाँ तक देश के अदर मछली पकड़ने का सम्मन्य है, इस बात की आवश्यकता है कि मछलियों का पीपण करने और उनके शिकार करने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया। "भारत के वर्तमान जलायायों में प्रमुख रूप से तालान और मीलें आती है। कार्प (Carp) मछलियों बहुधा भारतीय समुद्रों में पीपित होती है। चूँकि यह वॅघे हुये पानी में अडे नहीं देतीं, इमीलिये उन्हें प्रतिवर्ष पीपित करने की आवश्यकता होती है। यदि वँचे हुए पानी में कार्प मछलों के कृतिम अपडोत्पादन (artificial spawning) को विकित किया जाय, तो मछली-उद्योग का भी विकास होगा। मछलियाँ या तो ताजी खाई जाती हैं या उन्हें भविष्य में खाने के लिए धूप में सुखा लिया जाता है या नमक में जमा लेते हैं। शेप ऐसी मछलियाँ जो खाने के योग्य नहीं रह जाती हैं उनकी खाद बना लेते हैं। मछली-उद्योग के द्वारा हमें मछलियाँ तो प्राप्त होती हैं, इसके अतिरिक्त सर्डीन (Sardines), शार्क लिवर तेल (shark liver oil) जैसी अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं।

कृषि उत्पादन—भारतवर्ष में उष्ण कटिनन्घ, श्रर्घ उष्ण कटिनन्घ श्रोर समग्रीतोष्ण कटिनन्घ में उत्पन्न होने वालो निविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में खाद्यान ग्रीर व्यवसायिक दोनों ही प्रकार की फसलें सिम्मलित हैं, किन्दु प्रमुख रूप से खाद्यान्न ही श्रिषिक उगाए जाते हैं। उक्त कथन हसी नात से स्पष्ट हो जाता है कि खेती की जाने वाली कुल भूमि क प्रश्र भाग पर खाद्यात्र का ही उत्पादन किया जाता है।

हमारे यहाँ रवी श्रीर खरीफ टो मुख्य फर्सलें होती हैं। रारीफ फर्सलों के श्रन्तर्गत मुख्यतः चावल, ज्वार, वाजरा, मक्का, कपास, गला श्रीर म्रॅगफली बोईं जाती है श्रोर रवी फर्सलों में गेहूं, जो, चना, मटर, श्रलसी श्रीर मरसों श्राटि की खेती की जाती है। "चावल की खेती गगा की घाटी, पजाब के पहाड़ी जिला, उत्तर-प्रदेश, विहार, पश्चिमी बगाल, श्रासाम, पश्चिमी घाट श्रोर उद्दीसा न मद्रास के समुद्रतटीय भागों में होती है। पजान, पेप्स, उत्तर-प्रदेश व मध्य प्रदेश के श्रीप-काश माग पर गेहूं की रोती की जाती है। गला गगा ने मैटान, मद्रास, मेम्र, उद्दीसा, हैदराबाट श्रीर पंजाब में स्थाया जाता है। मृगफली, श्रलसी, श्रटी, तिल्ली, तिलहन श्राटि महास के उत्तरी भागों से श्रीर कपास दिल्लाए प्लेटो के उत्तरी-दिल्लिणी मागा व पजान में स्थान पर होती है। जूट प्रमुख रूप से बगाल में पैटा होता है। कहना, चाय, रवद, जाली मिर्च श्रीर इलायची के पेट श्रनामनाई श्रार कार्टमन (cardamom) की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। मालायार तट पर उने नारियल के घने-घने वृद्धों से गरी के गोले त्यार रस्तियाँ पनाने के लिए जटाएँ प्राप्त होती है। इन्हीं खेनों से देश भर के लिए काजू की माँग पूरी की जाती है।"

१६५१ की गणना के अनुसार इस देश का मोगोलिङ सेन्नफल लगभग ६१ करोड़ २५ लाख एकड़ है, कितु इसमें से केनल ६२ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि ही गाँव के पुराने लेखों (record) में दर्ज मिलती है। इस सेन्नफल में से लगभग २६ वरोड ६५ लाख एकड़ भूमि पर खेती की जाती है। यदि हम इस सेनफल में उन सेनों के मी अनुमानित आँकडे जोड लें जहाँ से कोई सूचना प्राप्त नहां होती तो खेती की जाने वाली कुल भूमि लगभग ३४ करोड़ एकड़ हो

१ जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ है वहाँ खरीफ फसल जुन में, नहीं तो फिर वरसात शुरू हो जाने पर जुलाई में वोई जाती है श्रीर जाने में काटी जाती है। रवी फसल बरसात समाप्त हो जाने पर अन्त्वर-नवन्वर में योई जाती है श्रीर श्रप्रेल मई में माटी जाती है। गन्ना जनवरी-फरवरी में वोया जाता है श्रीर श्रपले जाने में शक्कर के कारखाने में पिराई होने के समय तक तैयार हो जाता। यह पिराई नवन्वर-दिसम्बर से प्रारम होता है। यद्यपि गन्ना रबी फसल समाप्त हो जाने पर वोया जाता है, फिर भी हमें प्ररीफ की फसलों के श्रन्तर्गत इसिलए शामिल किया जाता है कि इसका क्टाई खरीफ की फसलों के साथ ही होती है।

जायगी। १६५६-५७ में कुल श्रन की उपज ५७३ लाख टन हुई थी, जिसमें से चावल की उपज २८१ लाख टन, नेहूँ ६१ लाख टन, ज्वार श्रीर वाजार १०३ लाख टन श्रीर श्रन्थ श्रन्न ६८ लाख टन थी। इसके श्रितिस्त ११४ लाख टन रालें, चना श्रादि की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार १६५६-५७ में कुल श्रन्न की उपज ६८७ लाख टन हुई थी। इतना श्रन्न भारत की जनता को खिलाने के लिये पर्याप्त नहीं था श्रीर इसलिये विदेश के श्रन्न पर निर्मर रहना पडा। पर इचित व्यवस्था से खाद्यान्न के सम्बध में देश के श्रात्म निर्मर हो सकने की सम्भावना है। श्रन्न के श्रितिस्त खेती से श्रनेक प्रकार के कच्चे माल की भी उपज होती है। १६५६-५७ में गन्ने की उपज ६५ लाख टन, जुरू की ४२.५ लाख गाँठ, रुई ४७.५ लाख गाँठ श्रीर तिलहन ६० लाख टन हुई थी। देश में जितना इन कच्चे मालों का उत्पादन होता है वह इमारी श्रावण्यकता के दृष्टिकोण से कम है। इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये काफी समय तक हमें श्रायात पर निर्मर रहना पढेगा।

पशु पालन-मार्त में पशुयो की बहुत य्रधिकता है। इनकी सख्या संसार के पशुद्रों की सख्या (रूस के पशुद्रों को छोड़कर) का है है। १६५१ की पशु-गण्ना के अनुसार भारत में कुल २६ करोड़ २२ लाख ५० हजार पशु ई जिनमें से १५ करोड़ ५० लाख गाय-वेल, ४ करोड़ ३२ है लाख मैंस-भैसे, ३ करोड ६० लाख मेड़ें, ४ करोड़ ७० लाख वर्करे-वकरियाँ, ४५ लाख से कुछ कम सुग्रर, १५ लाख घोडे, १२ लाख ५० इजार गवे, ६,२६,००० कॅट ग्रीर ६०,००० खचर है। इसके अतिरिक्त ६ करोड़ ७१ लाख ३० इनार मुर्गे-मुर्गियाँ और ६२ लाख ६० इजार वत्तर्थें हैं। किन्तु मारत के पशुश्रो की नस्त बहुत खराब है। यहाँ एक गुप्य भ्रीसत से प्रतिवर्ष ४१३ पीड दूध देती है, जब कि दूसरे देशों की गाएँ प्रतिवर्ष २००० से ७००० पौड तक दूध देती हैं। भारत में कुछ श्रन्छी नस्ल के भी पशु हैं, जैसे गुजरात की काँकरेज ख्रीर सीराष्ट्र की गिरि गाएँ दूध देने श्रीर श्रच्छे वछडे उत्पन्न करने के लिए ससार की सर्वोत्तम नस्लों में गिनी जाती हैं। किन्तु वेकार व निकम्मे पशुत्रों की सख्या अपेक्। कत बहुत अधिक है जो किसानो के लिए तिनक भी सहायक सिद्ध नहीं होते हैं श्रीर उनके लिए भार-स्वरूप बनकर रहते हैं। भारत में विविध प्रकार के जगली जीव श्रीर पन्नी भी पाये नाते हैं, किन्तु अमाग्यवश "हमारे यहाँ के शेंग, गेंडा, चीता श्रादि प्रमुख नगली नीवों की नरल समाप्त हो रही है। भारतीय नीवों को सरज्ञ्ण देने, उनकी नस्ल को सुरिच्चित रखने श्रीर उन्हें प्राकृतिक व मानवीय वातावरण में एन्तुलित रखने के लिए भारत-सरकार ने अप्रैल, १६५२ में जगली जीवों के लिए एक

केन्द्रीय बोर्क की स्थापना की"। पित्त्यों व सरस्या के लिए एक राष्ट्रीय सिर्मात (National Committee for Bird Protection) भी बनाई गई है। यह आशा की जाती है कि इन सस्थाओं से भारतीय पित्त्यों श्रीर जगली जीवों का सरस्या ग्रीर विकास होगा।

### खनिज-पदार्थ

किसी देश के श्रीयोगिक निकास के लिए उसकी सिनज सम्पत्ति का निशेष महत्व होता है। खिनल सम्पत्ति को निक्नलिसित वर्गों में बाँटा गया है.—(१) श्रधातु खिनज (non-metallic minerals), (२) धातु खिनज (metallic minerals) श्रीर (३) ईघन (fuels)। श्रधातु सिनज के अन्तर्गत श्रिममुक्तिका, सीलीमेनाइट, मेगनेसाइट, बालू, चुना श्रीर नमक श्रादि श्राते हैं। धातु सिनज के श्रन्तर्गत सोना, चाँटी, जस्ता, राँगा, टिन, ताँत्रा, श्रादि श्राते हैं श्रीर ईधनों के श्रन्तर्गत कोयला तथा पेट्रोलियम श्राते हैं।

भारत में कोयले, कच्चे लोहे, मंगनीज, बीमसाइट श्रीर श्रवरक जैसे खीनज पदायों की बहुतायत है, रिफ्त क्टरीज (refractories), एब्रेसिव (abrasives), चूना श्रोर जिप्सम भी पर्याप्त मान्ना में उपलब्ध हैं श्रीर श्रवरक, टिटानियम श्रीर कच्चा थोरियम भी काफी बढ़ी मान्ना में पाया जाता है। परन्तु दुर्भाग्य से ताँवा, टिन, सीसा, जस्ता, गिलट, कोबाल्ट, गवक श्रीर पेट्रोल जैसे महत्वपूर्ण रानिजों की बहुत कभी है श्रोर इनके श्रभाव को पूरा करने के लिए हमें श्रधिकतर श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है।

"लानों की दृष्टि से सबसे श्राधक महत्वशाली माग छोटा नागपुर का पठार है, जिसे गोंडवाना भी कहते हैं, जिसमें दृष्ट्यिय बिहार, दृष्ट्यिय पश्चिमी बगाल उत्तरी उद्दीसा श्राते हैं। कोयला, लोहा, श्रवरक श्रीर लांबा श्रादि श्रिध-काश इसी माग से पाप्त होते हैं। कोयला विशेषकर क्तरिया, रानीगज के सेत्रों से निकाला जाता है पर वसुत्रगार (Ligmit) के रूप में दृष्ट्यियी पूर्वी हैदराबाद, दृष्ट्यियी मन्य प्रदेश और दिल्लियी पूर्वी मद्रास के समुद्री तट पर भी पाया जाता है। लोहा मैस्र में श्रीर श्रवरक उत्तरी मद्रास और राजस्थान में पाया जाता है। हल्मेनाइट श्रीर मोनेजाइट (Ilmenite and Monazite) जो युद्र कालीन महत्ता रखने वाली घातुर्ये हैं, ट्रावन्कोर के तटीय प्रदेश की बालू में पायी जाती हैं। मेगनेखाइट मद्रास की खिल्या मिट्टी वाली पहाड़ियों पर श्रीर सोना मैस्र के कोलार स्त्रेय में पाया जाता है। बौक्साइट स्टीटाइटिजिप्सम इमारतों के बनाने में काम श्राने वाले पत्थर नमक, श्रिशमृत्यिका, कोसन्डम फलर्स श्रयं श्रादि भी पर्याप्त

मात्रा में यहाँ पाये जाते हैं। ससार भर की अवरक की उत्पत्ति का ६०% भारत में उत्पन्न होता है। मेगनीज, इल्मेनाइट, मोनेजाइट, लाहा आदि ससार भर में सबसे अधिक भारत में ही मिलते हें। भारत की घातुओं को पूर्णरूप से काम में नहीं लाया गया है। देश में पैट्रोलियम की कमी है केवल आसाम में ही इसके कुयें हैं। इन कुओं से माप्त उत्पत्ति बहुत ही नगयय है। इसी प्रकार अन्य घातुओं की जैसे राँगा, गन्यक, चोदी, जस्ता, टिन, पारा आदि की उत्पत्ति देश की आवश्यकता से बहुत कम है।

#### अध्याय ३

## जन संख्या

किसी देश के ग्रार्थिक विकास का वहाँ की जनसंख्या से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की सख्या, उनका स्वास्थ्य, श्रवस्था खी श्रीर पुरुप की सख्या का श्रनुपात, जन्म श्रोर मृत्यु दर श्रीर देश में प्राप्त खिनज पदार्थों के सम्बन्ध में उनके उद्योग श्रादि सब उनकी स्थिति श्राधिक निश्चित करते हैं। यह एक वढ़े विचार की बात है कि मारतवर्ष जो कि ससार का सबसे श्रधिक धना वसा देश है सबसे गरीब भी है। इसलिये यहाँ की समस्या जन सख्या के वृद्धि की दर में कमी श्रीर प्राकृतिक साधनों के उपयोग में वृद्धि करने की है।

भारत की जनसंख्या १८६१ में २३ ५६ करोड थी, १६२१ में बढकर २४'८१ करोड हुई जो १६३१ में २७ ५५ करोड, १६४१ में ३१ २८ करोड़ और १६५१ में ३५ १८ करोड़ हो गई। १६२१ तक तो जनसंख्या की वृद्धि में अकाल और वीमारियो द्वारा कभी होती रही और अन्न की उपज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पूरी पढ़ती रही। परन्तु १६२१ के पृश्चात जनसंख्या में अन्न की उपज की उपज की उपज की उपज की उपज की अन्न की किटनाहयों का सामना करना पड़ा। १६५१ की जनगणना रिपोर्ट, १६२१ को महान विभाजक (The Great Divide) के नाम से व्यक्त करती है, क्योंकि (१) इसके पहिले जनसंख्या न्यूनाधिक घटती हुई सी थी परन्तु इस वर्ग के बाद से निरन्तर बढ़ती रही है, और (२) इस वर्ष के पहिले तक भूमि का प्रयोग भी जनसंख्या ने वृद्धि के अनुकृत्व ही बढ़ता रहा पर इसके बाद से अन्न की कमी हाती गई।

े वृद्धि की दर—१९५१ तक के पिछले १० वर्षों में भारत की जनसख्या लगभग ४ १४ करोड़ के बढ़ गई है जो १२३% की वृद्धि कही जा सकती है अयवा जिसे १३%प्रतिवर्ष की वृद्धि कह सकते हैं। यह वृद्धि विभिन्न भागों में विभिन्न गित से हुई है। पजाब, अरहमान और नीकोवार टापुओं में ०५ प्रतिशत और ६६ प्रतिशत कमश कमो हुई है। अन्य राज्यों में से दिल्ली (६२ १%), कुर्ग (३० ५%), त्रिपुरा (२१.६%), मैसूर (२१ २%), त्रिवकुर कोचीन (२१ १%) और बम्बई

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> इस स<sup>र्</sup>या में जम्मू काश्मीर श्रोर श्रासाम के श्रादिवासियों की सख्या सम्मिलित नहीं है।

२० ८%) में सबसे श्रधिक वृद्धि हुई, हिमानल प्रदेश (२'७%), पेप्यू (२ ६%), निन्ध्य प्रदेश (६%), उड़ीसा (६'२%), मोपाल (७ २%), मध्य प्रदेश (७'६%) श्रीर निहार (१ ६%) में वृद्धि को गति श्रपेजाकृत कम रही।

जन्म और मृत्यु दर — जन सख्या में वृद्धि और कमी जन्म और मृत्यु दर के अन्तर पर निभर होती है। इधर पिछले वर्षों में भारत की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है। जन्म दर जो कि १६३१ में ३५ प्रति इजार थी घट कर १६४१ में ३२ १ पित इजार, और १६५० में २४.८ प्रति इजार हो गई। मृत्यु दर जो कि १६३१ में २५ ६ प्रति इजार घी, घट कर १६४१ में २१ ६ प्रति इजार और १६५० में १६ प्रति इजार हो। गई। इस प्रकार इम कह सकते हैं कि जन्म दर में मृत्यु दर की अपेद्धा अधिक कमी हुई। चूँ कि जन्म और मृत्यु के आँकडे विश्वस्त नहीं हैं इसिलए १६५१ की जनमण्याता रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाय है कि १६४१-५० के बीच के दस वर्षों में जन्म दर का औसत ४० प्रति इजार प्रति-वर्ष जनसख्या में वृद्धि हुई है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इमारे देश में विश्वस्त अप्रांक हे अप्रांग्य हे पर इम यह तो कहसकते हैं कि जनसख्या की वृद्धि की दर बढ़ती गई है।

जन्म दर में कमी विवाह की अवस्था बढ़ाने, आतम सथम और गर्भ निरोध के कृत्रिम उपायों के अनुसार सम्भव हो सकती है। परन्तु जल्दी ताक्स्य अवस्था को प्राप्त करने तथा आधिक अथवा अन्य कारणों से विवाह की अवस्था बढ़ाना सम्भव नहीं है। देर में विवाह करने की प्रथा पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है हतने पर भी उन लोगों में अभी भी विवाह की अवस्था कम हो है। आतम-स्थम बहुत ही किठिन है। उसके लिये पाय: हममें आतमबल की कमी है जिसके कारण उसकी सफलता में सन्देह है। गर्भ निरोधक कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग निम्न कारणों में विशेष प्रचलित नहीं हो सका है. (१) उन के विकद धामिक भावना, (२) उनका अधिक मूल्य, (३) जनता में उनके प्रयोग करने के ढगों के प्रति अनमिशता, (४) इस सम्बन्ध में परामर्श और शिक्षा देने वाले अस्पतालों की कमी। यदि कृत्रिम उपायों का प्रयोग प्रचलित करना है तो इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करना अत्यन्त आवश्यक होगा।

डा॰ स्टोन का मुरिश्चित काल मखाली ('Safe Persod method') का प्रयोग भी सस्ता श्रीर सफाई की दृष्टि से उपयुक्त होते हुये भी श्रीषक लोकपिय नहीं हो पाया है क्योंकि श्रीधकाश जनता इस मणाली का सफलतापूर्वक उपयोग करना नहीं जानती।

यह दुर्भाग्य की वात है कि जन सावारण (महत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को संम्मलित करते हुये) परिवार नियोजन की आवश्यनता तथा उसके उपायों से अनामज हैं। वे सब बात भाग्य के मगेप छोड़ देते हैं। इसके कारण परिवार नियोजन का कार्य अपने देश में एक किटन समस्या के स्प में उपस्थित है। "प्रयम पचवधीय योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन काय के प्रांत जनता में सिवय सहानुभात की मावना जगाना और वर्तमान ज्ञान के आधार पर तत्सम्बन्धी परामर्श और सेवा के साधना के विकास की और रहा है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध परामर्श और सेवा के साधना के विकास की और रहा है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में मेपाजक जेवकीय और साख्य के अन्ययन का कार्य भी किया गया। राज्यों, स्थानीय रस्थाओं, वैज्ञानिक सस्थाओं को ११५ परिवार नियोजक आप्रधालया और १६ सारयकीय तथा जैवकीय समस्याओं के प्रांत स्थोज करने वाली योजनाओं को अनुदानो द्वारा सहायता दी गई। वृसरा पचवर्षीय योजना में इस क्यंक्रम में वृद्ध करने का विचार किया गया है"।

"यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रांत ५०,००० व्यक्तियों वे लिए प्रत्येक नगर श्रीर क्स्बों में एक श्रोपधालय खोला जाय। छोटे कस्बों ग्रोर गाँवों में घीरे-धीरे प्राराम्भक स्वास्थ्य सस्याश्रों के सहयोग में ग्रोपवालय खोले जायं। इन श्रोपधालया का कार्य जनता में इस समस्या के प्रति जागरुरता उत्पन्न करना होगा श्रोर उन्हें इस सम्वन्ध में परामर्श श्रोर सेवा प्रदान करनी होगी। वगलौर में एक वेन्द्रीय प्रशिन्दण विरुज्जलय (clinic) का खोला जाना विचाराधीन है। वम्बई में कृत्रिम उपायों का परीचालय स्थापित हो रहा है। प्रत्येक भपितक विद्यायियों श्रीर उपचारिकाश्रों को परिवार नियोजन की शिक्षा देना श्रावश्यक है प्रत्येक श्रोपधालय में परिवार नियोजन सेवा विभाग स्थापित होना चाहिये। यह भी प्रस्ताव किया गया है। क भैपाजक जैवकीय तथा ग्रांक्डों से सम्बन्धित श्रन्वेपण सस्था स्थापित की जाय। ५ करोड़ रु० का प्रयन्ध परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिये निारचत कर हिया गया है। यह श्राशा की जाती है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के खन्त तक लगभग ३०० विरुज्जालय नगरों में श्रीर २००० विरुज्जालय गाँवों में स्थापित कर हिये जायंगे?।

मृत्युसंख्या की दर-मृत्युसका की दर शारीरीक कारणों श्रीर वाता-वरण पर निर्मर करती है। शारी।रक दशा पोक्टिक तत्वा, स्वच्छता, चिनित्सा की सुविधा इत्यादि पर निमर करती है। वातावरण की दशा बाढ श्रकाल, युद्ध इत्याद पर निर्मर करती है। मृत्युसरया की दर प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रही है परन्तु प्राप्त श्रॉक्टों के श्रनुसार मृत्युसरया की दर घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा की सुविधा बढ़ी है श्रोर सफाई की श्रोर श्रिक व्यान दिया जाने लगा है। यह त्रांशा की जाती है कि मित्रिंग में चिकित्सा की मुनिधा में वृद्धिहोने के साथ-साथ मृत्युसख्या की दर भी घटती जायगी। बहुमुजी योजनात्रों के पूरा हो जाने के बाद त्राकाल क्यार बाद का जोर कम हो जायगा। भारत में चच्चों की मृत्युसख्या क्राधिक होने से मृत्युसख्या की दर ऋषिक है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल जितने बच्चे पेदा होते हैं उनमें मे १५ प्रतिशत एक वर्ष की श्रायु होने से पहले ही मर जाते हैं। सरकारी तौर पर की गई गएना के अनुसार यह पता चना है कि इन बच्चों में से ५० प्रतिशत पैदा होने में एक महीने के अन्दर मर जाते हैं श्रोर ६० प्रतिशत पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं।

भारत में प्रतिवर्ष अनेक वीमारियों जैसे हैं जा, चेवक, प्लेग, ज्वर श्रीर डिसेन्ट्री इत्यादि से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। है जा, चेवक श्रीर प्लेग महा-मारियों हैं। सभी वीमारियों से कुल जितने लोगों की मृत्यु होती हैं उसका ५.१ प्रतिशत इन महामारियों के शिकार होते हैं। इससे प्रकट है कि महामारियों के कारण बहुत अविक मृत्यु नहीं होती है। विभिन्न बीमारियों ने होने वाली मृत्युश्रों के ५७५ प्रतिशत का कारण अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। अस्पतालों की सुविधा वढा कर, स्वास्थ्य-सुधार की योजना लागू कर, लोगों की बीमारियों के आक्रमण से वचने की शक्ति वढाकर साथ ही लोगों को आत्मविश्वासी और माग्य पर कम निर्मर बनाकर मृत्युसख्या की ऊँची दर के कारणों को दूर किया जा सकता है।

स्त्री-पुरुपों का अनुपात—भारत में पुरुपों की सख्या स्त्रियों से अविक है परन्तु मद्राय, उड़ीसा, त्रिवाक्तर कोचीन और कच्छ में यह स्थिति विपरीत है। इन राज्यों में स्त्रियों की सख्या पुरुपों से अधिक है। १६५१ की जन-गणना के अनुसार कच्छ में सबसे अधिक स्त्रियों हैं। यहाँ प्रति हजार पुरुपों के पीछे १०७६ स्त्रियों हैं। कुर्ग में स्त्रियों की सख्या अन्य सब राज्यों से कम है। यहाँ प्रति हजार पुरुपों के पीछे दिश स्त्रियों ही। इस स्थिति के अनेक सामाजिक, धार्मिक और (Biolgical) कारण हैं। प्राय: सभी वर्ग को जनता और विशेषकर हिन्दू समुदाय लड़की की अपेज्ञा लड़के को अधिक चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि लड़कियों की उचित देख-रेख नहीं की जाती है और उनकी प्राय: मृत्यु हो जाती है। धार्मिक भावना के अतिरिक्त इसका एक कारण यह है कि समाज में शिज्ञा का प्रसार कम है और लोग समाज में स्त्री के महत्व को ठोक-ठीक नहीं समक्त पाते हैं। इससे प्राय: लड़कियों की विशेष देख माल नहीं की जाती है। प्रसव के समय अनेक स्त्रियों की मृत्यु हो जाने से भी स्त्रियों की सख्या कम है।

श्रवरथा—भारत में बच्चे श्रीर नवयुत्रकों तो जनसरया में प्रधानता है। १६५१ में १४ वर्ष तक के लोग २८ ३%, १५ में ३४ वर्ष तक के लोग ३३%, १५ से ५४ वर्ष तक के लोग २० ४% और ५५ वर्ष के जगर के लोग केवल ८२% थे। श्रन्य देशों में, जैम फ्रान्स, इद्गलेगड, जर्मनी, उत्तरी श्रमरीका श्राटि में, स्थिति इसके निपरीत है। इन देशों में ५५ वर्ष श्रोर इसके जगर की श्रवस्था वाले व्यक्ति कुल जनसख्या के फ्रमश: २१ ४%, २१ १४%, १६ १% श्रीर १६ ६% है।

घनत्व श्रोर वितर्ए-भारत में ग्रीसत जनसंख्या का धनत्व ३१२ प्रति वर्ग मील है। घनत्व की मात्रा एक प्रदेश से दृखरे प्रदेश में बटलती हुई है। एक श्रोर दिल्ली मे ३०१७, द्रायन्कार कोचीन में २०१५ प्रति वर्ग मील है तो दृष्टरी श्रोर प्रराहमान निकाबार में १०, श्रोर उच्छ में ३४ प्राप्त वर्ग मील है। इस वटलते हुये वनत्व का कारण प्राकृतिक बनायट, भृमि तथा वर्षा है। इन कारणो पर ही भूमि के उचित प्रयोग की मात्रा निर्मर है। इस लंदे पनत्व की समस्या का अन्ययन प्राकृतिक मागो के आधार पर अधिक युक्तिसगत होगा। उस दृष्टियोण सिन्बगगा के मेदान के निचले भाग में धनत्य ८३२ ग्रीर ऊपर के माग में धनत्य ६८१, मालावार कोवन मे ६३८, टिस्णी मट्टास म ५५४, उत्तरी मद्रास श्रीर उदीसा के समुद्री तट पर ४६१ है। ये भाग बहुत श्रिधिक घनत्व वाले कहै जा सकते हैं। दिल्ली भाग में, टत्तरी भाग में, गुजरात वाठियानाड़ में, जहीं पर जनसंख्या का घनत्व साधारण की।ट का है, प्रतिवर्ग मील में कमरा ३३२, २४७, २४६ ब्रौर २२६ व्यक्ति निवास करते हैं। टिच्छि पटार के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी केन्द्रीय पहाड़ियों में, पूर्वी पठार में, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में, हिमालय, पश्चिमी हिमालय श्रीर रेगिस्तानी भागों मे जनसख्या का घनत्व स्मश १६२, १६४, १६३, ११८ ६८ श्रीर ६१ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील है। जनसंख्या के इस असमान वितरण के कारण प्रत्येक स्थान पर प्राप्त प्राकृतिक मुविधान्त्रों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया है।

भूमि के प्रयोग सम्बन्धी र्शांकड़ों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि (श्र) योक्प नहीं ससार भर में जनसंख्या का घनत्व सबसे श्रिधिक है भारत की तुलना में श्रिधिक श्रागे नहीं है। श्रोंसत भारतीय श्रपनी भूमि का ४३% खेती के काम लाता है जब कि श्रोंसत योक्पीय वेवल ६० प्रांतशत ही काम में लाता है। (व) संयुक्त राज्य श्रमेरिका श्रीर सावियत रूस के व्यक्तियों के पास योक्प निवासियों श्रीर भारतीयों की श्रपेचा श्राधिक भृमि है। भारत में भूमि पर जनसंख्या के भार का दुछ श्रनुमान इस वात से लगता है कि वोये हुये खेतों में जनसंख्या के प्रांत व्यक्ति का श्रीसत ० ८२ एकड़ है।

यदि कटिवन्घों के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण पर विचार किया जाय तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसख्या ६ ३२ करोड़ श्रयवा कुल जनसंख्या का १८% है। पूर्वी भारत की (जिसमें बिहार. उड़ीसा, पञ्छिमी बगाल, श्रासाम, मनीपुर, त्रिपुरा श्रीर सिकिम श्राते हैं) जन-सख्या ६ करोड़ या कुल जनसंख्या का २५% है। दिल्ला भारत (जिससे मद्रास, मैसर, ट्रावनकोर कोचीन श्रीर कुर्ग श्राते हैं) की जनसख्या ७५६ करोड़ या कुल जनसख्या की २१% है। पन्छिमी भारत की जनसख्या जिसमे वम्बई, सीराब्द्र श्लीर कच्छ श्राते हैं ४.०७ करोड़ या ११% है। मन्यमारत की जनसंख्या जिसके श्रन्त-र्गत मध्यभारत, हैदराबाद, भोपाल ग्रौर विन्ध्य प्रदेश ग्राते हैं ५ २३ करोड़ या १५% है । उत्तरी पश्चिमी मारत की जनसंख्या जिसके ब्रन्तर्गत राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, जम्मू त्रौर काश्मीर ( त्राकडे सम्मिलित नहीं हैं ), श्रजमेर दिल्ली, विलासपुर, श्रौर हिमालय प्रदेश त्राते हैं, ३ ५ करोड़ या १०% है। यदि भूभागों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो इम कइ सकते हैं कि उत्तरी मैदान की जनसख्या३६ १%, प्रायद्वीप पहाडियों ग्रीर दक्षिणी पठार की जनसख्या २० ४%, पूर्वी घाट ग्रीर समुद्री तट की जनसङ्या १४ ५%, पश्चिमी घाट ख्रौर समुद्री तट की जनसंख्या ११ २%, हिमालय के 'भूभाग की जनसख्या ४ ८% है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि देश के उपजाऊ मैदानों में श्रधिकाश जनसंख्या वसी हुई है।

मध्यप्रदेश का चेत्रफल सबसे श्रिषक है, श्रधांत् १३०२७२ वर्ग मील, तथा इसके पश्चात् राजस्थान है जिसका चेत्रफल १३०२०७ वर्ग मील है, जर्बाक जन-सख्या उत्तर प्रदेश की सबसे श्रिषक श्रयांत् ६ ३ करोड़ है श्रीर इसके पश्चात् मद्रास, बिहार, श्रीर वम्बई हैं जिनकी जनसख्या कमशः ५७, ४ तथा ३ ५६ करोड़ है। विव्य प्रदेश तथा दिल्ली के श्रतिरिक्त जिनकी जनसख्या कमशः ३५७ लाख तथा १७.४ लाख है—किसी भी स श्रीर द राज्य की जनसख्या १० लाख से श्रिषक नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश श्रयहमन श्रीर निकोवार द्वीप है जिसकी जनसख्या केवल ३०६७१ है। भारत की श्रिषकतर जनता गावों में निवास करती है। ३५७ करोड़ की कुल जनसख्या में से केवल ६२ करोड़ श्रयवा १७३% नगरों ग्रीर कस्वों में (जिनकी सख्या ३०१८ है) रहती है श्रीर शेष २६५ करोड़ या ८२७% जनसख्या गांवों में रहती है जिनकी सख्या भ्रयू८०८६ है। देश के श्रीद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप गांवों की जनसख्या निरन्तर नगरों की श्रोर बढती जा रही है। १६२१ में ८६,७% जनसख्या गांवों में निवास करती थी श्रीर ११२% नगरों में। १६४१ में ८६ १% गांवों में श्रीर १३६% नगरों में निवास करने लगी श्रीर १६५१ में, जैसा कि ऊपर बताया जा

चुका है, ८२'७% गाँवों मे श्रीर १७ ३% नगरों में रहने लगी। दिल्ली श्रीर श्रज-मेर के छोटे राज्यों को छोडकर जहाँ कि शहर की श्रावादी कमश ८३% श्रीर ४३% है, बढ़े राज्यों में वमबई श्रीर शीराष्ट्र के राज्य सबसे श्राधिनक हैं जहाँ ३४% श्रीर ३१% जनसङ्गा नगरों में रहती है।

भारत के ७३ शहरों की आवादी एक लाख के ऊपर है। आसाम और पेप्ट में ऐसा कोइ नगर नहीं है। 'स' राज्यों के सात भागों केवल नई दिल्ली अजमेर और भूपाल ऐसे नगर हैं। देश के सबसे बढ़े नगरों में वस्वई की जनसख्या २८ ३५ लाख, है, कल कत्ता की २५ ४६ लाख, मद्रास की १४ १६ लाख, हैदराबाद की १० ८६ लाख, दिल्ली की ६ १५५ लाख, अहमदाबाद की ७ ८८ लाख, और वगलीर की ७ ७६ लाख है।

धर्म और विवाह—भारत में श्रनेक घर्मों के मानने वाले रहते हैं पर हिन्दुओं की सख्या प्रधान है। १९५१ में ३५७ करोड़ की श्रावादी में से ३०°३ करोड़ हिन्दू थे, ३५ करोड मुसलमान, ८२ लाख ईसाई, ६२ लाख सिम्ब, १६ लाख जैन २ लाख बोद १ लाख जोराष्ट्रियन (पारसी), १७ लाख श्राधवासियों के धर्मावलम्बी तथा १ लाख श्रन्य धर्मों के पालन करने वाले थे।

मारत में प्रति १०,००० व्यक्तियों (श्ररण्थियों को छोड़ कर) में प्रश्च पुत्रप तथा ४८६७ छी हैं। इनमें २५२१ पुत्रप व १८६६ छियाँ श्रविवाहित हैं। श्रयांत् छियों ग्रीर पुत्रपों को मिलाकर कुल जनसंख्या ४४'१% श्रविवाहित हैं। बाल विवाह रोक कानून के होते हुए भी देश में श्रत्यिक वाल-विवाह होते हैं। १९५१ की जन गणना के श्रनुसार लगभग २८३००० पुद्रष्' ६११८००० विवाहित छियाँ, ६६००० विधुर श्रोर १३४००० विधवायें ५ श्रोर १४ वप की श्रवस्था के बीच की थीं। इसी रिपोर्ट के श्रनुसार लगभग ६२०००००० विवाह वाल विवाह निरोधक नियम के प्रतिकृत हुये थे।

्र व्यवसाय—देश भर के ७०% व्यक्ति कृषि पर और ३०% अन्य व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। धौराष्ट्र, बच्छ, अनमेर दिल्ली अन्डमान, नीकोबार में खेती करने वालों की सख्या की तुलना में अन्यप्रकार के व्यवसायियों की सख्या अधिक है। पिश्चमी बगाल ओर वम्बई प्रदेशों में जो सबसे अधिक औदीतिक प्रदेश हैं वहाँमों खेती करने वालों की सख्या व्यवसायियों से बढ़ी हुई है। हिमाञ्चल प्रदेश और सिकिम में कृषि करने वालों की सख्या इल आवादी की ६०% है। प्रत्येक १०० भारतवासियों में ४७ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास अपने खेत हैं, ६ आसामी हैं, १३ विना भूमि के अमिक हैं, १ जमीन्दार है अपवा लगान पर/आशित हैं और १० उद्योगों में लगे हुए हैं अथवा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं,

६ व्यापार करते हैं, २ यातायात में लगे हें छोर १२ विभिन्न प्रकार की नौकरियों में लगे हैं। १६५१ की जनगणना के छनुसार ३५७ व्यक्तिगों में से २४% करोड़ किसान छोर १० द करोड़ खेती के छातिरक्त छन्य कार्य करने वाले लोग थे। २४६% करोड़ किसानों में से १६७३ करोड़ छपने निजी लेते पर खेती करने वाले थे। ३९६ करोड़ ऐसे किसान थे जो दूसरों के खेत्र करने वाले थे, ४८४ ५ करोड़ कृषि कार्य करने वाले मजदूर थे छौर ०५३ करोड़ खेती करने वाले वमींदार या लगान पर छाश्रित व्यक्ति थे। १० द करोड़ छन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों में से ३७ करोड़ कृषि के छातिरक्त छन्य उत्यक्ति के कार्य में लगे थे, २१३ करोड़ व्यापार में लगे थे, ०५६ करोड़ यातायात में लगे थे छौर ४३ करोड़ विभिन्न नौकरियों में लगे थे। १६

#### ग्रध्याय ४

## सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ

सामाजिक ग्रीर घामिक व्यवस्था ग्री का जनता के ग्राधिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह भौतिक सुख समृद्धि ख्रीर सम्पत्ति के सम्रह के प्रति जनता के दृष्टिकोण को, साय ही इन उद्देश्यों की पुति के लिए जनता के प्रयन्नों को निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्थाएँ त्रोद्योगिक श्रोर वाणिय्य सगठनों को प्रभावित करती हैं साध ही व्यापार श्रोर उद्योग का किस प्रकार सगठन किया जाना चाहिये इस पर भी इन व्यवस्थात्रो का प्रभाव पड़ता है। भाग्त मे जाति प्रणाली ह्योर संयुक्त परि-वार की प्रथाओं का भी देश के ग्रार्थिक सगठन पर काफी प्रमाव पढ़ा है, पर्दा-प्रथा, ग्रहिंसा पर विश्वास श्रोर धर्म क प्रति सामान्य जनता के दृष्टिकोस् ने उनकी श्राधिम-गतिविधि को निर्धारित एवम् सचालित किया है। पर्दा-प्रथा के कारण उच-जाति की महिलाएँ देश के आर्थिक-कार्य में भाग नहीं लेती हैं और इस प्रकार जनता को निर्धन रखने में यह प्रथा सहायक सिद होती है। ऋहिसा के र्दाष्टकोण श्रौर इस घार्मिक भावना से कि पन्दर श्रौर नील-गाय (जो वास्तव मे गाय नहीं है। पवित्र हैं इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे फसल तथा श्रन्य मूल्यवान सम्पत्ति की मारी ज्ञति होती है । घामिक संस्थायां को जैसे मन्दिरों. मठों श्रीर प्रखाड़ों को जनता जो टान देती है उससे इन सस्पाश्रों ने बहुत श्रधिक मात्रा में सम्पत्ति का सग्रह कर लिया है जिसका परिखाम यह होता कि (१) इन सस्यात्रों को चलाने वाले पुजारी? पाएंडे तथा श्रन्य लोग श्रालसी हा जाते हैं श्रोर वेकार पढ़े रहते हैं श्रीर इस प्रकार देश उनके श्रम का लाभ उठाने से विचत रह जाता है, (२) इस प्रकार जो धन इन्छा होता है वह तिजोरियों में बन्ट रखा जाता है श्रीर देश के श्रार्थिक विकास के कार्य मे इसका उपयोग नहीं होता है। विश्व के श्रम्य उन्नत देशों में जनता द्वारा की गई वचत काफो पहिले देश के श्रीद्योगिक तथा कृषि विकास के लिए उपलब्ध हो गई छोर पृनी निर्माण की प्रति-किया को प्रोतसाहन मिला। परन्तु भारत में धार्मिक सगटनों के प्रभुत्व श्रीर शास्त्रों के इस ब्राटेश से कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी कमाई का कुछ ब्रश इन सस्यान्त्रों को दान देना चाहिए **य्रोर साथ ही र्मान्टरों** त्रीर मठों के प्रति जनता की गहरी अदा होने से देश मे पूजी निर्माण का कार्य बहुत शिथिल पड़ गया। देश के उत्तराधिकार कानूनों से भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति का अनुचित रूप में छोटे-छोटे हिस्सों में विमाजन होता गया है। यदि भारत में सामाजिक श्रोर घामिक व्यवस्थाएँ भिन्न प्रकार होतीं तो देश की ह्यायिक प्रगति भी मिन्न प्रकार की होती।

जातिप्रया-जाति प्रथा इमारे देश की प्राचीनतम प्रयात्रों में से है। एक परिभाषा के श्रनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक ऐसा सग्रह है जिसका एक नाम है, जो उसके श्रन्तर्गत श्रानेवाले लोगो के व्यवसाय सम्बन्धित होता है श्रौर इस नाम से ही उसके श्रन्तर्गत श्रानेवाले लोगों का व्यवसाय से मालूम हो जाता है। इसके साथ ही यह दावा किया जाता है कि किसी पीराणिक मानव या देवता से इसका वश चला है, इसके अन्तर्गत आनेवाले लोगों का एक पेशा है, श्रीर राय प्रकट करने के श्रधिकारी व्यक्ति इसे एक ही समुदाय समम्तते हैं जिसमे समानता है। इमें यह मालूम नहीं है कि जाति प्रणाली का विकास कैमे हुआ। जाति प्रया सभवत: श्रम-विभाजन श्रीर विशेषश्रता के सिद्धात पर श्राधारित रही होगी। प्राचीनकाल में हिन्दू समाज चार भागों में विभक्त था, अर्थात ब्राह्मण जो श्राध्यामिक नेता, विद्वान श्रौर पुजारी होते थे, चत्रिय जो योदा श्रीर प्रशासक थे, वैश्य जो व्यापारी स्त्रीर सौदागर थे, स्त्रीर शुद्र जो निम्नकोटि के कार्य करते थे, अन्य लोगो की सेवा करते थे-इन अन्य लोगों मे अधिकार प्रथम तीनो वर्ग के लोग हो हाते थे। इस चार जातियो की प्रणाली से हमें कार्य का विभाजन स्रष्ट मालूम होता है । साथ ही यह प्रयत्न भी प्रकट होता है कि विभिन्न लोग विभिन्न कायों में दचता प्राप्त करें। श्रारभ में जाति प्रणाली वशगत या पुशतैनो नहीं थी श्रीर एक जाति का व्यक्ति अपने प्रयक्तों के बल पर अपनी जाति से उच्च जाति मे प्रवेश पा सकता था। परन्त बाद में जाति प्रथा ब्रात्यन्त कट्टर रूप धारण कर गई श्रीर निश्चित रूप वशगत हो गई। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक उपजातियाँ श्रीर इन उपजातियों के भी श्रनेक निम्न रूपों को जन्म दिया गया जिसस यह सारी व्यवस्था ग्रत्यन्त जिंटल हो गई।

श्रारम्भ में जाति-प्रणाली से कुछ लाम थे: (१) इस व्यवस्था से किसी कार्य में श्रीर ज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त की जा सकती थी जिससे जो कुछ कार्य किया जाता था उसके गुण में बहुत सुधार होता जाता था। प्राय वेटा वही व्यवसाय श्रपनाता था जो उसका बाप करता था श्रीर इस व्यवसाय के लिए बाप उसे उचित शिक्षा दे देता था। इस प्रकार एक विशेष प्रकार का कार्य श्रीर तत्सम्बन्धी ज्ञान एक परिवार में वश्रगत रूप से चला श्राता था श्रीर वेटा बाप से उस व्यवसाय की योग्यता प्राप्त कर कार्य श्रीर तत्सम्बन्धी कीन एक परिवार में वश्रगत रूप से चला श्राता था। परिहर्तों की सुप्रसिद्ध विद्वत्ता, भारतीय योद्धाश्रों की श्रपूर्व सफलताएँ श्रीर उच्चकोटि की भारतीय दस्त-कारी सभी श्राशिक रूप से इस विशेष योग्यता के ही फल थे जो स्वय इसी जाति-प्रणाली का परिणाम था, (२) जाति-प्रणाली ने उन कष्टमय तथा परेशानियां के दिनों में जब कि भारत पर विजातियों ने इमले किये थे हिन्दू-जाति की शुद्धता को

वनाये रखने में बहुत सहायता मिली। जाति-प्रणाली की कट्टरता के फलस्वरूप ही विजेतायों और विजितों के बीच आवश्यकता से अधिक रक्त-सम्मन्य नहीं हो पाया इसमें काफी रूकावट पड़ी, ओर (३) जाति प्रणाली ने आरम्भ से ही हिन्दुओं को अन्य लोगों के विश्वासों और धमों के प्रति सिह्च्यु वने रहने का पाठ सिखाया है। इसी कारण विभिन्न जातियों और धमों के लोग भारत में शांति और भाई चारे के साथ रहते आये हैं इसमें तिनक भी असत्य नहीं है कि आरम्म में भारत में जाति प्रणाली ने प्राय. उसी उद्देश्य की पूर्ति की जिसकी यूरोप में गिल्ड-प्रणाली (Guild System) ने की जिसके अन्तर्गत गिल्ड के सदस्यों को टैक्निकल शिक्षा दी जाती थी ग्रोर उनके अन्य हितों की देखमाल की जातों थी।

परन्तु श्राधानक काल में जाति प्रणाली श्रश्यम्त जटिल श्रीर श्रपरिवर्तन-शील हो गई है, उसमे एक प्रकार की कटरता आ गई है और फलस्वरूप इससे देश की आर्थिक प्रगति में सहायता मिलने की अपेन्ना हानि ही अधिक हुई है। वाति प्रणाली के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि: (१) यह आवश्यक नहीं है कि वैश्य का पुत्र अच्छा व्यापारी हो ग्रीर बाह्यण का पुत्र अच्छा पुजारी हो। यह बिल्कुल सभव है कि ब्राह्मण या वैष्य के पुत्र में ऐसी योग्यता है कि वह अत्यन्त कुशल मोची वन सके। परन्तु जाति प्रया उच जाति के लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जो कार्य छोटी जातियों को सौंपे गये हैं। इसी प्रकार यदि कोई शुद्र बहुत शिक्षित श्रीर विद्वान मले हो परन्तु वह किसी मन्दिर का पुजारो नहीं बन सकता। यह जात प्रया ही उसके मार्ग में सबसे वही वावा बन जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा फिसी व्यक्तिको ऐसे उत्तम कार्य करने से रोकती है निसकी उसमे पर्याप्त ज्ञमता ग्रीर योग्यता हो । (२) ग्रस्पृश्यता ग्रीर इससे उदसुत ग्रन्य कठिनाइयों ने कारण जाति-प्रया जनता के सरल-स्वाभाविक प्रवाह में वाधक बन जाती है। किसी देश के याथिक विकास के लिए पजी और श्रम की निर्वाध गति-शीलता श्रत्यन्त श्रावश्यक होती है। जाति प्रथा ने इसको रोक रखा है श्रोर इस सीमा तक हमारे देश में श्रीयोगिक तथा कृषि क्रातियों का श्रमाव रहा है। (३) क्टर जाति प्रथा के कारण इम श्रम-सम्मान (dignity of labour) को भूल गये हैं और इससे अन्य लोगों के विश्वासो, धर्मों और दृष्टिकोणों के प्रति हमारी सहिष्णुता की भावना भी कम हो गई है। इसीलिए इससे गतिरोध उत्पन्न हो गया है, हमारा समाज अस्थिर हो गया है ख्रोर हममें स्वय ब्रागे बढकर पथ प्रदर्शन करने तथा साहस की भावना लुस हो गई है।

सौमाग्य से गत कुछ वर्षा से जाति-प्रया ट्टर रही है। भारत में रेलों के निर्माण, इसके प्रसार, यात्रा की सुविघाओं में वृद्धि, रेला, वस या इवाई जहाज की यात्रा में विभिन्न जाति के लोगों से होने वाले ग्रनिवार्य जन-सम्पर्क के फलस्वरूप जाति-प्रणाली की कट्टरता कम हो गई। अग्रेजी शिचा प्रणाली चौर अग्रेजी कानून के ब्रन्तर्गत सभी जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया गया थोर सभी जातियों के लोगों को कोई भी व्यवसाय ग्रपनाने की छूट दे दी गई। पेशा श्रपनाने मे जाति-प्रया की बाधा नहीं रही। शूद्र जाति के व्यक्ति श्रप्यापक, मजिस्ट्रेट ग्रीर उच्च सैन्याधिकारी वने ग्रीर उच्च जाति के लोग जिन्हें ग्रपना कार्थ सिद्ध करना होता था इन प्रधिकारियों के सम्पर्क में श्राये श्रीर जाति प्रथा की कटरता का पालन नहीं कर सक। जाति-प्रथा के कारण ही अनेक (एन्दुर्ज़ों ने श्रन्य घमों का स्वीकार कर लिया। इसकी स्वय हिन्दू-समुदाय में प्रतिकिया हुई श्रीर श्रर्थ-समाज जैसे सुधारवादो श्रान्दोलन हुए जिन्होने जाति-प्रया को तोहने में बहुत बड़ा कार्य किया है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस इसके विरुद्ध सवर्ष करती रही ्रै श्रीर भारतीय सविधान में श्रस्ष्ट्रयता को भारी श्रपराध माना गया है द्योर उनको बरानार अवसर प्रदान किया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अब परिगणित जाति के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने की नीति अपना रही हैं। इन सब प्रयत्नों से जाति-प्रथा की कष्टरता कम हो गई है स्त्रीर मारत के त्रार्शनक नीजवान इसकी अधिक परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोग या वह लोग जो ग्रामी ग्रापने गाँवो या करवों की सीमा से ग्रापने को मुक्त नहीं कर सके हैं श्रीर जिनका दृष्टिकीण श्रमी भी सकुचित बना हुया है, श्रम भी इस जाति-प्रथा की कट्टरता की मावना से प्रस्त है परन्तु इनकी सख्या घीरे-घीरे घटती जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि जाति-प्रथा समाप्त होती जा रही है परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ग्राव भी जाति-प्रथा का जोर है ग्रीर भारतीय ग्राधिक प्रणाली को उससे बरावर इति हो रही है।

संयुक्त परिवार की प्रथा (Joint Family System)—स्युक्त परिवार प्रथा मारत की प्राचीनतम प्रथाओं में से एक है। देश में सामान्यतः भ्राधिक इकार्ड एक व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। बहुत में व्यक्तियों ने संयुक्त परिवार से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है श्रीर वह श्रलग रहने लगे है परन्तु फिर भी परिवार सगठन में स्युक्त-परिवार प्रया की पूर्ण प्रधानता है। समुक्त परिवार में सामान्यतया पिता परिवार का प्रधान होता है ग्रीर परिवार के ग्रन्य पुरुष तथा स्त्रियों उसके ग्राबीन होते हैं। वह साथ रहते हैं साथ खाते-पीते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, साथ ही समाज में समके समान सम्बन्ध होते हैं। यह ठीक कहा गया है कि छोटे पेमाने में संयुक्त-परिवार साम्यवाद का उदाहरस है। यदि संयुक्त परिवार का उचित सगठन किया जाय

तो वहाँ यह सिद्धान्त लागू होता है कि "प्रत्येक सदस्य सब के लिए श्रीर सारा परिवार प्रत्येक के लिए" (each for all and all for each) अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पूरे समूह के लिए उत्तरदायी है स्त्रौर पूरा समूह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार प्रथा के कुछ श्रार्थिक लाम हैं---(१) इससे रहन-सहन का व्यय घट जाता है क्योंकि खाना साथ पकाया जाता है, नौकर चाकर समान होते हैं श्रीर श्रन्य समी मुविधाश्रों का सयुक्त रूप से उपमीग किया जाता है। वह पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सभी सुविधाएँ इसमें निहित हैं। यदि लोग श्रलग-श्रलग रहते हैं तो रहन सहन का कुल व्यय परिवार के व्यय से बहुत अधिक होगा, (२) इससे सम्पत्ति श्रीर भूमि का छोटे-छोटे भागों में विभा-जन नहीं होता, भूमि पर मिलकर खेती की जाती है जिससे श्रार्थिक चेत्र में श्रनेक लाभ होते हैं श्रीर श्रन्य रूपों में भी काफी लाम होता है। सयुक्त परिवार की पूँजी निखरी हुईं नहीं होती विलिक एक साथ जमा रहती है श्रीर उसको श्रन्य उत्पादन कार्यों मे या त्रागामी उत्पादन कार्य का प्रसार करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु यदि संयुक्त परिवार दूट जाय श्रीर लोग श्रलग-श्रलग रहने लगे तो यह समन है कि उनके पास पर्याप्त प्जी न हो, ख्रीर (३) संयुक्त परिवार मथा वीमारी, मृत्यु या त्रन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनात्रों के श्रवसर पर एक प्रकार से वीमा का कार्य करती है। विघवात्रों, अनायो और वृद्धों का सयुक्त परिवार में अन्य सदस्यों की तरह ही पालन-पोपण होता है। गत कुछ वपों से पश्मि देशों मे वृद व्यक्तियों को, जो कार्य नहीं कर सकते श्रीर निर्धन हैं, उनकी सन्तानों ने उन्हें विना किसी सहारे के छोड़ देने की प्रकृति हो गई है। सयुक्त पिरवार प्रथा के श्रन्तर्गत ऐसा संमव नहीं है।

परन्तु सयुक्त परिवार-प्रणाली की श्रनेक द्दानियाँ मी हैं: (१) चूकि प्रत्येक व्यक्ति को मोजन, कपढ़े, रहने प्रादि की पूरी सुविधा उपलब्ध है इसलिए उन लोगो में जो चरित्र की हिंद्र से श्रन्छे नहीं कहे जा सकते हैं श्रोर जिनमें दूर दृष्टि का श्रमाव होता है श्रालस्य पेटा हो जाता है। इन प्रथा से उनके श्रालसी स्वमाव को वल प्राप्त होता है। सम्यवाद के श्रन्तर्गत चूकि सुगतान कार्य के श्राधार पर नहीं बल्कि श्रावश्यकता के श्राधार पर किया जायगा श्रतएव तब यह किनाई उत्पन्न हो जायगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी च्रमता के श्राक्त्रण उत्तम कार्य कैसे कराया जाय। इसी प्रकार सयुक्त-परिवार-प्रणाली में व्यक्ति की सभी श्रावश्य-कताश्रो की उसके द्वारा किये गये कार्य की गयाना किये विना ही पूर्ति हो जाती है इससे कुछ लोगों में निठल्ले वेठे रहने श्रोर श्रालसी वन जाने की प्रकृति पैदा हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि स्पये का मूल्य वही व्यक्ति श्रव्छी प्रकार सम-

मता है जो रुपया कमाता है। इसलिए सयुक्त परिवार में आलसी और निठल्ले लोगों के फिज्ल-खर्च बनने की पूरी संमावना रहती है, (२) सयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत लोगों की गतिशीलवा का हास हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनमें आगे बढ़कर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति का मी हास हो जाता है। लोगों को घर में बैठे रहने की आदत पह जाती है और फलस्वरूप साहसपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति से हाथ था बैठते हैं, उनमे वह स्फूर्ति, सिक्रयता और साहस नहीं रहता जो देश की आर्थिक उन्नति के लिये प्रावश्यक होता है, और (३) सयुक्त परिवार में छोटे-छोटे मगडे पैदा होते रहते हैं, ईच्यां-हेष बढता है और इसके फलस्वरूप सुकदमेवाजी भी हो जाती है जो कि अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है।

इधर कुछ वर्षों से समुक्त परिवार प्रथा विशृखालत हो रही है। यद्यपि श्रमी भी यह परिवार-सगठन का प्रधान रूप है फिर भी सयुक्त परिवार त्याग कर श्रलग रहने वालो की सख्या बढ रही है। (१) शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात युवक शहरी जीवन का अम्यस्त हो जाता है स्त्रीर किसी कारखाने में नौकरी कर लेता है या है शहर मे व्यापार कार्य में लग जाता है ग्रौर उसे सयुक्त परिवार से पृथक होकर रहना पड़ता है, (२) जीवन-सवर्ष में वृद्धि होने से ग्रीर जीवन-निर्वाह के साधनों को जुटाने की कठिनाइयों से न्यक्ति संयुक्त परिवार के बन्धन से मुक्त होना चाहता है। ग्रपनी पक्षी ग्रौर बचा का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेना संयुक्त-परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त रुपया कमा लेने से कहीं श्रिधिक सरल होता है, (३) जहाँ तक धनवान व्यक्तियो का प्रश्न है श्राय कर कानून श्रीर हाल ही में सम्पत्ति कर (estate duty) कानून बन जाने से संयुक्त-परिवार प्रथा टूटने लगी है। यदि संयुक्त-परिवार के कमाने वाले सदस्यों की ग्राय ग्रायकर के लिये निर्घारित न्यूनतम ग्राय से कम है तो वह सपुक्त-परिवार से अलग होकर आयकर के बोम से बच सकते हैं परन्तु यदि साथ रहें तो सभी की आय जोड़ कर इतनी हा सकती है कि आयकर से मुक्ति न मिल सके । उदाहरण के लिये यदि एक परिवार में चार पुरुष है और वह कुल ६ हजार रपया प्रति वर्ष कमाते है तो उनको श्राय-कर देना पड़ेगा क्योंकि कानून के श्चनुसार हिन्दू-संयुक्त परिवार की ८४०० रुपया वार्षिक श्राय से श्रविक श्राय पर श्राय-कर देना पढ़ता है। परन्तु यदि चारो व्यक्ति संयुक्त-परिवार से सम्बन्ध विच्छेदकर ले श्रीर श्रलग-श्रलग रहने लगे तो प्रत्येक चार हजार रुपया वार्षिक कमा सकता है श्रीर उसे श्राय-कर भी नहीं देना पडेगा क्योंकि कानून के श्रनु-सार व्यक्तिगत् स्राय ४२०० रुपया वार्षिक होने पर ही स्राय-कर लगेगा। इसी मकार सम्पत्ति-कर कानून के श्रन्दर्गत व्यक्ति गत रूप से एक लाख की सम्पक्ति

पर श्राय-कर की छूट प्राप्त है परन्तु सयुक्त-परिवार में प्रत्येक पुरुप सदस्य को केवल ५० हजार रुपये की सम्पत्ति पर ही सम्पत्ति-कर से छूट प्राप्त है, इससे श्रिषिक की सम्पत्ति होने पर कर चुनाना पहेगा परन्तु यदि वह सयुक्त-परिवार से श्रालग हो जाय तो एक लाख रुपये को सम्पत्ति पर उसे कोई कर नहीं देना पटेगा। इसके श्राति कि कि सी की मृत्यु हो जाने पर यह समव है कि संयुक्त-परिवार को सम्पत्ति कर चुकाना पढे जब कि पृथम रहने पर ऐसा होना इतना प्रधिक सम्भय नहीं है। कर-सम्बन्धी यह कानून घनवान वर्ग की सयुक्त-परिवार प्रथा को तोड रहे हैं।

पचायत (Panchayat)—प्राचीन भारत मे पचायत श्रत्यन्त महत्वपूर्ण् सस्या थी जिसे प्रशासन, न्याय श्रीर राजस्व सभी श्रधिकार प्राप्त थे। परन्तु जैसे- जैसे समय बीतता गया श्राधिक परिस्थितियों मे परिवर्तन होने से तथा प्रशासन श्रीर न्याय के केन्द्रीकरण् से पचायता का महत्व घट गया श्रीर कमश वह नगर्य हो गर्यो। देश के कुछ भागों मे पचायने स्थापित रहीं परन्तु केवल एक सामाजिक सस्या के रूप में जहाँ लोग श्रापस में मिल सकते, गप्प कर सकते श्रीर हुक्का पी सकते थे श्रीर कभी कभी छाटे-मोटे कगड़े भी तय कर लिये जाने थे। परन्तु पचायत ने प्रशासन श्रीर न्याय के जैत्र में श्रपना प्रभावशाली रूप खो दिया।

परन्तु इघर कुछ वर्षों से महात्मा गांधी आर राष्ट्रीय काग्रेस के द्वारा इस व्यवस्था के प्रति विशेष रुचि दिखायी जाने के कारण पचायत-प्रणाली की पुनः जीवन प्रदान किया गया है श्रीर पचायतों को कानूनी मान्यता श्रीर कुछ प्रशासन तथा न्याय अधिकार प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों ने आवश्यक कानून भी बनाये हैं। परन्तु अब तक पचायतें सन्तापजनक नार्य नहीं कर पानी हैं न्योंकि जिन लोगों को पचायतों का कार्य सौपा गया है वह निरह्मर हैं श्रीर प्रशासन तथा अदालत की कार्य-प्रणाली नी उनको आवश्यक जानकारी नहीं है, साथ ही उनके पास धन का भी अभाव है।

पचायतों का कार्यचेत्र बढाने का प्रयत्न किया जा रहा है श्रीर उन्हें श्राधिक नियोजन का प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयत्न हो रहा है। स्विधान के ४० वे श्रनुच्छेट में कहा गया है कि राज्य प्राम पञ्चायतों की स्थापना करने श्रीर उन्हें त्वशासन की इकार्ड बनाने के लिए श्रावण्यक ग्रिषकार दिलाने के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा। राज्य सरकारों द्वारा पञ्चायतों को कुछ ग्रिधकार प्रदान किये गये हैं परन्तु यह उतने नहीं हैं जितने की सविधान में व्यवस्था की गई है।

जून १९५४ में शिमला में स्वायत्त-शासन मित्रयों का सम्मेलन हुया था जिसमें यह सिकारिश की गई कि पचानतों को श्रिषक प्रभावशाली बनाने के लिए श्रिविक व्यापक श्राधिक, प्रशासकीय ग्रौर न्याय ग्रीधकार दिये जाने चाहियें।

यह सुक्ताव दिया गया कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में 'नीचे से ऊपर की श्रोर' योजना बनायी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए श्रीर ग्राम को ही नियोजन की इकाई बनाना चाहिए। श्रुखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने जुलाई १६५४ मे त्रपने श्रजमेर त्रिधिवेशन में इस बात पर विचार किया श्रौर श्रनुमान है कि उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि पञ्चायतों को स्वशासन को प्रभावशाली श्राधारभृत इकाई श्रीर नीचे से योजना बनाये जाने के लिए आबारभूत एजेन्सी बनाया जायगा। एक गाँव सभा का निर्माण सारा गाँव करेगा और निर्वाचन के आधार पर आम पचायत बनायेगा जो गाँव समा की कार्यकारिए। होगी। पचायत को जो कार्य सौपे जायँगे उनमे लगान वस्ली, भूमि सम्बन्धी कागजात रखने (इन्दराज), समान उप-योगिता की सरकारी जमीन का प्रवन्ध, काशत के लिए लगान पर जमीन देना, बहुधन्धी ग्राम सहकारी समितियो का विकास करना श्रीर श्रपने श्रधिकार चेत्र के श्रन्दर सार्व-जनिक उपयोग के कार्यों के लिए सब से अनिवार्यत. कार्य करना आदि नाय सम्मिलित हैं। प्राम के विकास की नीति पचायत निर्धारित करेगी, यौर भूमिन्न-रण, वनो के विकास, इवन के सुरित्तत सृष्ट जमा करने, बॉव ग्रौर जलाशय बनाने, वयस्क शिज्ञा, अञ्छे बीजों की पूर्ति, और काश्त के नये और सुधरे हुए उपायों को लागू करने की समस्याश्चों पर भी पचायत विचार करेगी श्चौर इस दिशा में स्नावश्यक कार्रवाई करेगी।

दितीय पचवर्णीय योजना नीचे से ऊपर की स्रोर बनाई गई है। राज्य सरकारों ने एक-एक गाँव के स्रयवा गाँवों के समूहों के लिये जैमे तहसील, तालुका, विकास-पीली की इकाइयों के स्राधार पर योजना बनवाई है। इस कार्य में पचायतों ने बहुत महत्वशाली सहयोग दिया है पर यह कहना कठिन है कि स्थानीय योजनास्रों के बनाने में वे यथार्थ में कार्यशील रही हैं स्रौर ये स्थानीय योजनायें इस योग्य रही हैं कि उनको राज्य द्वारा बनाई योजना में सम्मिलित कर लिया जाता। जो कुछ भी हो पचायत के सदस्या को यह जान हो गया है कि द्वितीय योजना की सफलता के लिये उनके सहयोग की स्रावश्यकता है। इससे स्थानीय लोगो का उत्साह स्रवश्य बढ़ा है और वे योजना के प्रति जागरूक हो गये हैं।

सरकार की नीति यह है कि "प्रत्येक गाँव में ख्रोर विशेषकर उन चेत्रों में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवाछ्रो छोर सामुदायिक विकास योजनाछ्रो के लिए चुने गये ई एक कानून के छावार पर पचायत की स्थापना की जाय। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में पंचायतो की सख्या ⊏२०⊏७ से बढ़ कर ११७५६३ हो गई। ॄ्बितीय योजना के कार्यक्रम के छनुषार १६६०−६१ तक ग्राम पचायतों की सख्या वढ कर २४४५६४ हो जायगीं"। यह सीचना युक्तिसगत है कि भविष्य में पचायतों को अधिका।धक महत्ता दी जापनी श्रीर वे योजना की कार्य रूप में प्रिणित करने का एक प्रभावशाली सावन हो जायंगी। परन्तु ग्रभी तक तो प्राम पचायतों का कार्य बहुत ही प्रसतापजनक रहा है। इसके अनेक कारण हैं जैसे (१) "प्राम पचायतों के प्रभावशाली न ही सकने का स्वत्म बड़ा कारण उनके पास साधन का अभाव रहा है। बहुत सी पचा बतो की प्रति व्यक्ति वाषिक ग्राय २ ग्रा॰ या ३ ग्रा॰ रही हैं"। टेक्जेशन इन्ववायम कमीयन (१६५३-५४) ने अपनी रिपोट में इस बात की श्रोर व्यान श्राकापत विया था कि पादेशिक सरकारें "पचायतो को कुछ वरों के लगाने का श्रविकार दे कर उन्हें अपने श्राप श्रपनी सहायता करने के लिये छोड़ देती है। इसका परिणाम यह होता है ि प्राय पचायतें ग्रारम्म होते ही वरं। के ग्रारम्भ वरन के कारण जनता को कापभाजन उन जाती है छोर यदि करों का छारम्भ न उर्ने तो नि। फ्रय हो कर जनता की दृष्टि में नीचे गिर जाती हैं"। इसालये पचायता के कार्य का सफल बनाने के लिये सबसे श्राविक श्रावश्यक बात यह है कि उन्टे पयास विच महान जिया जाय। (२) दूसरी काँटनाई यह है कि पच।यता के ऊपर उनके साधनी श्रीर शक्ति की श्रपेसा श्रत्यांवक कार्य भाग डाल दिया गया है। प्रादेशिक सरवारे जिन्होंने पचायता को श्रानेक उत्तरदानित्य सीप न्यसे हैं पचायतो मे व्यावश्यक्ता से ब्रावक श्राशा करती है। हिल्दिक बोट ब्रोर पचावता के दित भी श्रापस में टकराते हैं क्योंकि टानों के कार्य सेत्र एक दसरे की सीमा का श्रवितमण करते हैं। इस सम्बन्ध में टेक्जेशन इपन्यापरी कमीशन ने यह सिफारिश की है कि ग्राधिक चेत्र ग्रीर उत्पादन सम्बन्धी वार्य नो सहकारी समातयो द्वारा श्राधक श्रन्छी तरह किये जा सकते हैं। उन्ह नियांमत रूप से पचायतों के श्रन्तर्गत श्राये हुए कायों से श्रलग रर टेना चाहिये। इम इसे भी श्रावश्यक सममत है कि पचायतों के लिये नियमावली म दिये गये श्रसस्य कार्यों के स्यान पर थोडे ने चुने हुये कार्य ही दिये जार्ने ताकि उनका जिला वोर्ड तथा श्रन्य स्थानीय श्राम बोर्ड के कार्यों से सामजस्य सम्मव हो सके। (३) पंचायतों के मेम्बरों को उन कार्यों की काई शक्ता नहीं मिली है जो उनको दिये गये हैं। उनके विचार प्राचीन हैं, उधर उनके मन में स्थानीय कारणों से उत्पन्न द्वेप भावना भरी है, इसालये जो समस्यायें उनक सामने श्रज्ञान ग्राशज्ञा ग्रोर जाति द्वेप के कारस् उपस्थित हैं उनको दृर करने के लिये उनके विचार में वे ही पुराने टग ग्राते हैं जिससे वे अपना कर्त्तव्य सतीपजनक टग से पूरा नहीं कर पाते।

#### अध्याय ४

# कृपि उत्पादन और नीति

मारत कृषि प्रधान देश है। भारत का कुल चेत्रफल अन्तिम गणाना के अनुसार लगभग ८१ करोड़ २० लाख ५० हजार एकड है, परन्तु आधे से बहुत कम भूमि कृषि के काम आ रही है।

पथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के पहिले ही योजना आयोग ने कुछ प्रदेशों मे पिछले ४० वर्षों में विभिन्न फरालो के उगाने में लगी हुई भूमि की जॉच की। इससे यह पता लगा कि (१) खेती की जाने वाली भूमि का चेत्र-फल उत्तर-प्रदेश को छोडकर कही भी विशेष मात्रा में नहीं बढ़ा। एक से अधिक फोरले उगाने वाले चेत्र मे २०% को वृद्धि हुई, परन्तु यह वृद्धि बढती हुई जनसख्या की तुलना में नगरथ थी, (२) सिचाई का चेत्रफल १०% वढा जो कि मुख्यत. नहरों के विस्तार का परिणाम था, (३) पग्ती छोड़ी हुई भूमि का चेत्रफल १६२०-४० तक के ही स्तर पर रहा । उसके बाद कुछ वृद्धि रुई का उत्पादन करने वाले चेत्रों में हुई क्यों कि यकायक रुई उत्पादन चेत्र में कमी आ गई श्रीर खेत परती छोड़ दिये गये। किस प्रकार की फसर्ले उगाने की प्रवृति प्राय. लोगो की रही, इसका योजना श्रायोग ने अध्ययन किया श्रीर इस परिगाम पर पहुँचे कि (१) पिछले १० वर्षों मे यद्यपि दुइरी फसल उत्पन्न करने के कारण फसलों के अन्तर्गत कुल त्तेत्र में वृद्धि हुई पर कोई भी नया भूमि का भाग खेती के कार्य मे नहीं लाया गया, (२) मूल्यो में परिवर्तन के कारण फसलो की किस्म में परिवर्तन स्रा गया यद्यपि स्रधिकाश ये फसले छोटे-छोटे खेतो मे उत्पन्न की जाती थीं (३) खाद्यान तथा व्यवसायिक फसलों के बीच श्रदला-बदला किसी विशेष ढग पर नहीं हुई वरन मौसम फसलो के हेर-फेर, मूल्य परिवर्तन ऋौर किसान की श्रार्थिक शक्ति पर निर्मर रही।

खाद्यान और कच्चे माल में कमी—यह श्राक्षर्य की वात है कि कृषि-प्रधान देश होते हुए भी भारत में खाद्यान की कमी है और उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव है। इन अभावा के मुख्यत तीन कारण हैं: (१) १९३६ में पूर्मा को भारत से श्रुलग कर देने के कारण देश के अन्दर ही प्राप्त हो जाने वाली खाद्यान की मात्रा में १३ लाख टन की कमी हो गई, (२) १९४७ में देश-विमाजन हो जाने के कारण उस मात्रा में ७ ५ लाख टन की और कमी हो गई, (३) देश की जनसच्या प्रतिवप १% प्रतिरात की दर से बढ रही है, परन्तु खाद्यान की माना
में इसी दर से वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप खाटान का श्रमाव हो
गया। सन् १६४६ ५० में देश को ४६० लाख टन प्रन्न की उत्पत्ति प्रीर सरकारी
गोदाम तथा विदेशों से मँगाये श्रम को मिलाकर प्रति वयस्क १३७१ प्रोस श्रम
प्रतिदिन पडता था। यदि जनसख्या श्रिषक होती तो प्रति व्यक्ति श्रम का माग
श्रार भी कम होता। पौष्टिक पटार्थ सलाहकार समिति के विचारानुसार प्रति स्वस्य
व्यक्ति (वयस्क) १४ श्रास श्रम प्रतिदिन प्रावश्यक है। उसलिए प्रथम पञ्चनपीन
योजना ने ७६ लाख टन श्रम की उपज वहाने का निश्चय किया था।

पोष्टिक पदार्थ मलाहकार श्रांमित के सुक्ताव के अनुसार सन्तुलित मोजन के लिये प्रत्येक व्यक्ति का ३ श्रांस टाल प्रतिदिन खानी चाहिये। १६५०-५१ में देश लाख टन दाल पेदा हुई, जिसमें से सरकारी स्टाक, बीज इत्यादि के लिय २० प्रतिश्वत निकाल देने क प्रश्वात् प्रति वयस्क को प्रतिदिन २१ श्रोस टाल मिली। इस प्रकार प्रथम पञ्चवर्षाय योजना के अन्तगत बढ़ी हुई जनसङ्या के श्रातिष्क श्रावश्यकता ५ लाख टन की ब्रोर ३ श्रांस प्रति व्यक्ति के हिसाब से ४० लाख टन की श्रातुमानित की गई थी।

१६५०-५१ म ५१ लाख टन तिलह्न की उपन हुई जिसमें से लगभग १६ लास ६० इजार टन तेल पाप्त हुन्ना। साबुन, रग तथा वार्निश बनाने के काम में प्रयुक्त तेल को अलग करने क पश्चात् शेप १६ लाख टन तेल घरेलू कार्यों के लिए बचा। इसके अनुसार प्रति वयस्क को प्रतिदिन ०५ ग्रीस तेल मिला, जो श्रावश्यकता से बहुत कम या ग्रीर इसलिए उसकी मात्रा बढानी श्रावश्यक सममी गई। नहीं तक क्यास का प्रश्न है, १९५० ५१ में २६ लाख ७० हजार गाँठो का उत्पादन हुआ (प्रत्येक गाठ का वजन ३६२ पोड) जर कि खपत ४० लाख ७० इजार गाँठों की थी। उत्पादन श्रीर खपत के इस श्रन्तर को प्रतिवर्ष लगभग इजार गाँठों का आयात वरके पूरा किया गया। अनुमान लगाया गया है कि १९५६ में ५४ लाख गाठों की ग्रावश्यकता होगी। जुट के उत्पादन के विपय में सरकारी तार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-५२ में ३३ लाख कच्चे जुट की गाँठों का उत्पादन किया गया। प्रौर मेस्टा (Mesta) की ६ लाख गाँठें पेदा की गई, जो जूट से घटिया किस्म की उपज है श्रीर जिसका उपयोग ज्ट न मिलने पर किया जाता है। श्रनुमान है कि १९५६ में ७२ लाख गाँठों की त्रावश्यकता होगी। इस प्रकार माँग ग्रीर पूर्ति में ३३ लाख गांठों का ग्रन्तर रह गया।

इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम

में खाद्यान श्रोर उद्योगों के लिए कच्चे माल होनों का ही श्रमाव था। भारत को स्वावलम्बी बनाने श्रोर विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि देश के श्रन्दर ही इनका उत्पादन बहाया जायगा। यदि समस्या केवल खाद्यान्न या ज्यवसायी फसलों की पूर्ति की मात्रा बहाने की होती, तो इसके लिये घीरे-धीरे एक फसल की जमीन को दूसरी फसन के उत्पादन के लिये ज्यवहार में लाया जा सकता था। परन्तु समस्या दोनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की थी, जिससे माँग श्रीर पृति के बीच का भारी श्रन्तर दर किया जाय।

खाद्यान जॉच कमेटी की रिपोर्ट-कमेटी, जिसके श्रव्यन्त श्री श्रशोक मेहता थे तथा जिसने नवम्बर १९५७ में श्रपनी रिवोर्ट प्रस्तुत की, इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खाद्यान की कुल उत्पत्ति १६५३-५४ के ६८६७ लाख टन से घट कर १६५४-५५ में ६७१ र लाख टन तथा १९५६-५७ में ६५२ ६ लाख टन हो गयी। इसके त्रनन्तर प्रवृत्ति मे परिवर्तन हुन्ना ऋौर १६५६-५७ में खाद्योत्पादन बढकर ६८६ ९ लाख टन हो गया। खाद्यात्र के मूल्यों एवम् खाद्य सामग्री के श्रमाव की वृद्धि निम्न कारणों से हुई। (1) कुपकों ने ग्रापनी उत्पत्ति का श्रधिक भाग स्वय रख लिया। अतएव मूल्यों की वृद्धि में जितना विक्रीत-ग्रातिरिक (marketed surplus) की कमी का हाथ या उतना उत्पादन की कमी का नहीं था। १६५५-५६ में मोटे अनाज (millets) की उत्पत्ति मे ३० लाख टन की कमी हुई जिसने मूल्य वृद्धि का क्रम प्रारम किया श्रीर १६५५-५६ में चावल तथा गेहूं की मॉग बढने के कारण खाद्यात्र के मूल्य वढने लगे। यद्यपि बाद मे उत्पादन बढ गया किन्तु मूल्यों में फिर भो वृद्धि होती रही। (11) द्वितीय योजना के अन्तर्गत होने वाले न्यय तथा वैंक उदार की वृद्धि ने भी मूल्य-स्तर के वढाने में मदद की, तथा (111) "खाद्य स्थिति के बारे मे श्रत्यधिक श्राशावादिता ने श्रनेक राज्यों में खाद्यात्पादन की वृद्धि के प्रयक्तों को या तो शिथिल कर दिया या उनमें तीवता नहीं श्राने दी"।

भारत की जन सख्या की प्रतिवर्ष १३ – २ प्रतिशत वृद्धि के आघार पर कमेटी ने अनुमान लगाया कि खाद्याओं की माँग में बहुती हुई जनसख्या के कारण १०% तथा आय की वृद्धि से ४.७ प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार दिवीय याजना में खाट्यान्नो की माँग १४३ से १५ प्रतिशत तक वढ जायगी अर्थात् १६५५ ५६ में ६६० लाख टन से बढकर १६६०-६१ में ७६० लाख टन हो जायगी जबिक उत्पत्ति में केवल १०३ लाख टन की वृद्धि की आशा की जाती है जिसके फलस्ररूप १६६०-६१ तक उत्पत्ति बढकर ७७५ लाख टन हो जायगी। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कुछ अगामीवर्षों में प्रतिवर्ष २०-३० लाख टन खाट्यान्न का आयात करना आवश्यक होगा।

कमेटी ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में मूल्य-स्पायित्व (price stabilisation) की नीति की विकारिश की। (1) इस हेतु उन्होंने उद्याधिकारों से युक्त 'मूल्य-स्थायित्व परिषद' (Price Stabilisation Board) की नियुक्ति प्रस्तावित की जिसके कार्य म्हारनीति का निर्वारण तथा उमे लागू करने के उपायों का निर्णय करता था। (11) नीति को कायान्त्रित करने के लिए खाद्यान्त स्थानित सगठन (Foodgrains stabilisation Organisation) के निर्माण की भी िकपरिश की गई। यह सगठन खाद्य श्रोर क्वाप मत्रालय का एक विभाग हो सकता है या एक परिनियत निगम (Statutory corporation) ग्रथवा स मित दायित्व वाली क्म्पनी का रूप भी ले सकता है। यह सगठन खादान वाजार में एक व्यापारी की मौति काम करेगा श्रोर श्रन्त स्थ-स्वन्ध (bufferstock) का काम करेगा श्रयीत मुल्य भारने पर खरीदेगा जो और बढने पर वेचेगा । (111) खाद्य मत्रालय तथा मूल्य स्यानित्व परिपट की सहायना के लिए केन्द्रीय साद्य परामर्श समिति (Centralfood Advisory Council) के निर्माण की भी सिकारिश की गई। (vi) प्रधगानुकृत एवम् विश्वासनीय श्रांकडे एकत्र करने के लिए मूल्य-जानकारी-सैभाग ( price Intelligence Division ) की स्थापना की भी सिफारिश हुई। परामर्श समिति तथा जानकारी सभाग की सहायता से मूल्य-सामयित्व परिषद का उद्देश्य मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर सतर्कता वरतने तथा समय समय पर न केवल सामान्य मृल्य न्तर के स्थिर बनाये रखने वरन् विभिन्न वस्तु ग्री के मूल्यों में ग्रनुचित श्रन्तर को रोकने के लिये श्रावञ्यक कार्यावाही की तिफारिश करना या।

इस बात को न्यान में रखते हुये कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वतन्न व्यापार ग्रावाछनीय है तथा पूर्ण-नियत्रण (Full fledged Control) ग्रायिक एवम् प्रधा- स्वीय कठिनाटयों से भरा है, कमेटी ने एक मध्य-मार्ग की सिफारिण की जिसके ग्रावात नियत्रण का कट्रोल खुले बाजार में खाद्याच्न के कम विकय तक सीमित रहेगा, थोक व्यापार का ग्रशत. समाजीकरण होगा, श्रनुजा (License) द्वारा रोप बाजार में कार्यशील व्यापारियों पर नियत्रण होगा, गेहूं ग्रीर चावल का पर्याप्त स्टॉक रखा जायगा तथा ग्राव्य प्रक साथ सामन्नी के उपमोग ग्रीर उत्पादन की वृद्ध के लिये प्रचार का सगठन किया जायगा।

जत्पादन मृतृत्ति—स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरात भारत में खाद्यान्न श्रौर श्रन्य कृषि-सम्बन्धा अच्चे माल के उत्पादन में कभी श्रा गई है। १६५० ५१ में खाद्यात्र का उत्पादन ५०० लाख टन हुश्रा, अविक १६४६-५० में इनका उत्पादन ५४० लाख टन हुश्रा था। कृषि-सम्बन्धी कच्चे मालों की उत्पादन प्रवृत्ति थोडी भिन्न थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के तुरन्त बाद उत्पादन में कभी आ गई, किन्तु तत्पश्चात् उसमें फिर वृद्धि हो गई। १६४८-४६ में तिलहन का उत्पान ४५ लाख टन, कपास का १७ लाख ७० हजार गाँठो और कच्चे जूट का २० लाख ७० हजार गाँठो तक ही घटकर रह गया। गन्ने का उत्पादन भी कम होकर ४८ लाख ७० हजार टन ही रह गया। किन्तु अगले वर्षों में इन कच्चे मालो के उत्पादन में वृद्धि हुई और १६५०-५१ में, जब कि खाद्यान्न का उत्पादन गिरता जा रहा था, उनकी उपज बहनी प्रारम्भ हुई।

'श्रिषक-प्रज्ञ-उपजास्रो' श्रान्दोलन के बावजूद खाद्याज के उत्पादन में कमी श्राई। बहुत समव है कि खाद्याच उत्पादन के सरकारी श्राँकडे बिल्कुल सही न हो। परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सही श्राँकडे चाहे कुछ भी हों, श्रनेक कारणों से खाद्यान्न का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में काफी गिर गया:

- (१) देश के कुछ भागों में सुला पहने ग्रौर कहीं-कही बाढ श्रा जाने से खाद्यात्र के उत्पादन में श्राशिक कमी श्रवश्य हुई है, परन्तु केवल प्रकृति का कीप ही उत्पादन की गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (२) यह भी सुकाव दिया गया है कि क्रिय-सामग्री की ऊँची कीमते भी कुछ अश तक कृषि-उत्पादन घटने का कारण हैं। साधारण रूप से अधिक कीमत का अर्थ है अधिक उत्पादन, परन्तु जहाँ तक किसान का सम्मन्य है आय की लोच (Elasticity) ऋणात्मक (negative) है। इसका तात्पर्य यह है कि किसान कुछ आय चाहता है और जब कीमतें अधिक होती हैं तो वह थोड़ा सा उत्पादन करके उसे प्राप्त कर लेता है, किन्तु जब कीमतें कम होती हैं तो उसे अधिक उत्पादन करना पडता है। इसलिये जैसे हो खाद्याक की कीमतें वहीं, उसने अपना उत्पादन कम कर दिया। च्रिक कीमतों और उत्पादन के पारस्परिक सम्मन्ध का विस्तारएवंक अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए यह कहना समय नहीं है कि यह सिद्धान्त भारत में कहाँ तक लागू होता है।
- (३) खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आने का एक कारण यह भी है कि गन्ने, रुई श्रीर जूट की श्रविक आवश्यकता होने के कारण खाद्यान के उत्पादन में प्रयुक्त भूमि के कुछ भाग में अन व्यवसाई कसले वोई जाती है।

मारत-सरकार के 'अधिक-अन्न-उपजाश्रो' श्रान्दोलन से खाद्यान की कमी
पूर्ति करने की जो श्राशा की गई थी, उसमे श्रिधिक सफलता नहीं हुई क्योंकि
(श्र) इस श्रान्दोलन में पहले से ही काश्त की जाने वाली जमीन में उत्र इन
बढाने की श्रिपेद्या नयी भूमि को खेती के योग्य बनाने पर अधिक जोर दिया गया।
यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी श्रीर इससे निकट मिक्षिय में उत्पादन बढाने की

श्राशा नहीं की जा संप्रती थी। 'प्रिषिक-श्राप उपवाश्रा' प्रान्टोलन की नीति मे परिवर्तन कर एक श्रहपकालीन पोलनाको पर जोर दिया गया रे, जिसके सम्तर्भत सामान का उपादन बढ़ाने के लिए गीन थीर साद दी नाती के पीर साप ही साथ मिचाई की भी व्यवस्था का जाती है। प्रारंग म यह श्रान्दोलन हेग के उन भागा में चलाया गया था जहाँ छिचाई की मुविधाएँ नहीं थी छीर इसिविण सन्तोपजन र परिगाम नदी निक्ले । बाद पी नीत बदल दो गई श्रार या नाम्बा को उन्ही स्थला पर चलाया गया है जहाँ छिचाइ यो मुस्थि पहल ही म यी या सरलता से ज्ञावरपकतानुसार व्यवस्था की जा साती थी। इसमा परिमाम उड निक्ला कि 'श्रधिक श्रम उपनाप्राः' प्रान्टोलन म सन्तोपजनक प्रगति एई, (ब) यह 'प्रत्यन्त रोड का विषय है कि 'ग्रायिक-ग्रज्य-उपनाग्री 'ग्रान्नोरान का काय मार जिन ग्राधिकारियों को सावा गया है वह संव ईमानदारी ग्रांग रागन से कार्य नहीं करते हैं। बहुत सी बातों में काम कुछ नहीं किया जाना, फेनल कागजी खाना पूरी कर दी जाती है छीर प्रतुत बार एसा भी होता है । क नो बीज या खाद प्रादि क्रिसानों को मिलनी चाहिए था, उने या हो बेच दिया गमा या उसका रुपया स्वय रख लिया गया । इस ग्रान्दानन म या शिर्धा भी नियोजन के अन्तर्गत याजना को सुचाद रूप में पायांत्यत उपने ने जिए एक ऐसे सगडन की श्रावश्यकता है जो कि मुसगीटत रो श्रीर जिसके यमचारी पूर्णरूप ने ईमान-दार हां, (स) रिसानों ने भी 'श्रधिम-श्रय-उपजाश्रो । श्रान्टालन को उत्तना सहयोग नहीं दिया जितना उनसे श्राशा की जाता वी।

१६५४-५५ ग्रीर १६५५ ५६ में हुई उत्पादन की भोड़ी सी वभी को छोड़ कर १६५० के उपरान्त खाद्याल के उत्पादन में सन्तीयजनम वृद्धि हुई है। १६५०-५१ में भारत में सायाल का उत्पादन ५०० लाग्व दन था जो १६५८-५४ में ६८० लाख दन हो गया। स्वतं ग्रीक वृद्धि चानल के उत्पादन में हुई ग्रीर इसके बाद कमशः गेहूँ, नाजरा, त्यार ग्रीर जी की उपन बढ़ी। गायाल के उत्पादन में यह वृद्धि इन कारणी से हुई, (१) मीसम की अनुमून परिम्मितियाँ, (२) १६५० ५१ में पारम किए गए स्विटित उत्पादन मार्यक्रम (Integrated Production Programme) की समलता, (३) चानल उत्पन्न करने की जापानी पद्धित का प्रयोग, सिचाई की ग्रीक मुन्यवाएँ ग्रीक किसानों को ग्रायिक सहायता के रूप में रासायनिक साद (Fertilisers) ग्रादि देना।

१६५४-५५ तथा १६५५-५६ में उत्पादन घटकर क्रमश ६७११ लाख दन तथा ६५२६ लाख दन होने के कारण (1) देश के कुछ भागों म सूखा, (11) दर्वरक तथा श्रच्छे वीनों का श्रभाव तथा (111) राष्य सरकारों द्वारा प्रयहों मे दिलाई देना था जो अशत. उनकी लापरवाही तथा अशत दितीय योजना के खायान की उत्पित और कृषि पर अपर्याप्त त्यान देने के फलस्वरूप हुई। १६५६ ५७ में उत्पादन के ६८६.६ लाख टन तक बढ़ जाने के बावजूद भी पिछले दो वपों में उत्पादन के गिरने से मूल्य बढ़ गये जिसके फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति को बड़ी विटनाई का समना करना पड़ा। खायान का आयात, जो १६५१ के ४७ लाख टन के ऊँचे स्तर से घटकर १६५४ में ८ लाख टन तथा १६५४ में ७ लाख टन हो गया था, पुन १६५६ में बढ़कर १४९ लाख टन तथा १६५७ में ३७ लाख टन हो गया।

कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति कुछ भिन्न ही रही है। १९५२-५३ में कई श्रीर ज्रूट का उत्पादन पिछले वर्ष के ही स्तर पर (३२० लाख श्रीर ४६० लाख गाँठ कमशा.) रही पर तिलहन श्रीर गन्ने की उपन कमशा: ४७ लाख टन श्रीर ५० लाख टन हो गई। श्रगले वर्षों में ज्रूट को छोड़कर इन सभी १९५६-५७ में श्रनुमान किया जाता है कि तिलहन ६० लाख टन, कई ४७५ लाख गाँठ ज्रूट ४२५ लाख गाँठ श्रीर गन्ना ६५ लाख टन होगा।

प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रान्तर्गत—प्रथम पचवर्षीय योजना का ध्येय पाद्यान तथा उद्योगों में काम श्राने वाले कच्चे माल की उत्पत्ति इस दृष्टि-कोण से बढ़ाने का था कि (१) देश श्रात्म निर्मरता प्राप्त कर ले, (२) मारतीय उद्योगा को माँग पूरी हो सके श्रार (३) प्रति व्यक्ति श्रन्न का उपभोग बढ़ाया जा सके।

प्रथम पचवपीय योजना के लच्य

वस्तुये	ग्राधार माने हुये साल मे उत्पत्ति	प्रस्ताथित घ्यतिरिक्त उत्पत्ति	प्राप्त कर लेने	श्राधार माने हुये वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान	५४० लाख टन	७६ लाख टन	६१६ लाख टन	<b>\$</b> &
तिलइन	५१ लाख टन	४ लाख टन	५५ लाख टन	5
गना	५६ लाख टन	७ लाख टन	६३ लास टन	१३
(गुड़) रुई	२६ लाख गाँठें	१३ लाख गाँउँ	४२ लाख गाठे	४५
जूट	३३ लाख गाँठें	२१ लाख गाँठे	५५ लाख गाँठें	६४

<sup>ः</sup> तांशाक्षों के लिए ग्राधार वर्ष १६४६-५० है ग्रीर ग्रन्य के लिये १६५०-५१ है।

खाद्यान में प्रस्तावित ७६ लाख टन की वृद्धि में से ४० लाख टन चावल, २० लाख टन मेहूँ, १० लाख टन चना श्रीर श्रन्य दालें श्रीर ५ लाख टन में श्रन्य श्रन्त हैं। जैसा कि उत्पर समेत किया जा चुका है। उपज ६५० लाख टन हुई। (प्रजाय ६१६ लाख टन के जो कि लक्ष्य था) मेहूँ, चना श्रीर टालों के उपज की माना प्रस्तावित लक्ष्य से श्रिष्ठिक बढ गई है परन्तु चावल की उपज पिछले वर्ष में बढ़ने के पण्चात् १६५४ ५५ में बाढ श्रादि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण घट गई। यह कमी समार के सभी चावल उत्पन्न करने वाले देशों में हुई थी। पर १६५५ ५६ में किर उत्पत्ति कुछ बढ़ी। व्यवसायिक कसलों में से तिलहन श्रीर मई की उत्पत्ति योजना के श्रनुकूल बढ़ी पर जुट श्रीर गन्ने की उपज में कमी हुई।

प्रथम रोजना के काल मे अन की उत्पत्ति में वृद्धि सिंचाई की सुनिघाओं के बहने, पाट के प्रयोग म आधिक्य और विकार भूमि को खेती के काम में लाने के लिये फिर से अधिकृत करने के कारण हुई, परन्तु यह बता सकना कठिन होगा कि विस कारण से कितनी वृद्धि हुई है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—न्यपि द्वितीय योजना नें उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है पर कृषि के प्रति उदावीनता नहीं दिखाई गई है। द्वितीय योजना में इस बात पर ध्यान रक्खा ग्या है कि प्रथम योजना के कार्य में विकास हो और कृषि उत्पत्ति तथा कच्चे माल की उत्पत्ति में हमारा देश यथासम्भव आत्मिनर्भर हो जाय। दूसरे, यह अब अच्छी तरह समक्त में आ गया है कि खेती का चेत्रफल बढा लेने मात्र में ही उत्पत्ति में आवश्यक वृद्धि न हो सकेगी। अन्त में यद्यि खायाल की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है पर दूसरी योजना में उन वस्तुओं की सख्या काफी वड़ी है जिनकी उत्पत्ति बढ़ाने का ध्येय है। ऐसी वस्तुओं में चान, काली मिर्च, लास, नारियल, वृक्कफल, सुपाड़ी मी सम्मिलित हैं। इससे भारतीय किसानों की उन्नति में ।स्थरता और विदेशी विनियन से अधिक आय प्राप्त होगी।

यदि वर्तमान दर से ही श्रन्न का उपमाग चलता रहे तो योजना श्रायोग के श्रनुसार वढी हुई जनसंस्ता को ७०५ लाख दन श्रन्न की श्रावश्यकता होगी परन्तु प्रति व्यक्ति श्रन्न का उपयोग १८३ श्रांस प्रतिदिन कर देने का विचार है, इसिलये कुल श्रन्न की श्रावश्यकता ७५० लाख दन होगी। इसी ग्राधार पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में १६६०-६१ तक १०० लाख मेन की उपज बढाने का निश्चय किया गया। ग्रन्न की इस वृद्धि में चावल की ३० से ४० लाख दन, गेहूं की २० से ३० लाख दन, श्रौर श्रन्य श्रनों की १५ से २० लाख दन, श्रौर श्रन्य श्रनों की १० से ३० लाख दन श्रौर दालों की १५ से २० लाख दन वृद्धि सोची गई है। बाद मे ऐसा प्रतीत हुश्रा कि खाद्यान के

जान न के केवल उत्पत्ति न माना दी। यदि सनी मिन् भगपूर काम गरे सी उन्हें लगभग ७२ लाग जुड़ का बिटों ही गामिर देवला होगा। इस ह प्रतिसिक्त १५०,००० गिर्ट पहन पामा के लिरे नाहिते। (in) माने प्राप्त न गृह का उत्यादिन विदे पर गृह सम्भाद ही करेगा हि प्रति करण प्रतिहित १९०६ गीम का उपयोग वर सकेगा। (iv) मानु की मान्य की कामण सम्भाह की उपर मही नमी जिला के उपयोग वर सकेगा। (iv) मानु की मान्य की कामण उमकी जिला के दर्भी कामण पदी। इसके गोटामी में तन्याह तका कि पर का उसकी जिला उपरा मुहर मिर गया। इसलिये दितीन की ना । उस्तार कि पर ह को के कामण उमका मुहर जी दिशा गया है, न कि उत्यादन के माना की वृद्धि पर।

### वाशान नीति

मूल्य नीति—गाणान प सम्बन्ध ने गरवार की नीति है कि (१) भारत की सायान वे सम्बन्ध में स्वावतलको प्रनापा जाप, (२) प्रन तक समाप की स्थिति रहती है तन तक सायान के मूल्यों और क्लिन्स पर निवंत्रण रमा पाय, जिसमें उपभोक्ताश्चां की कठिनाई दर का लीत पहाँ पक समा हो देश के सभी मागों में समान लाधार पर सभी की स्वायान मित्र सहें, लीर (३) कि नान की उसके उत्पादन का उचित नृत्य प्राप्त हो सहे ।

पचवर्षाय योजना मे यह टाय ही कहा गया है वि "नूर्य " बढ्रेन-पटने में खावान्त पर प्रमुख रूप में प्रमाय पड़ता है। याद मूहप पर निपपण राजना है ता यह श्रावश्यक है कि सायान्त हा भाव पर स्तर रता जत्य जो देश पो गरीब जनता की पहुँच के बाहर न हो। सारत ना उत्तमान स्थिति न पाट राजारन की पूर्ति में योड़ी मी कमी श्राह, तो भाग श्रपेताज़त श्रीधक चट वायेंगे। मात्रान्त का मात्र बढ़ जाने से रहन-ग्रहन का रार्च बढ़ जाता है फ्रीर उत्पादन व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए ऐसी नीति निसमे सभी श्रीर भाग बह ना र्सार रुपया लगाने का पार्य कम ही ठप हो जाय, उत्पाटक में निए पिसी भी मन में लामदाक नहीं है। इस नारण खात्रान्न नीति निर्धान्ति करने समग्र इन समी वार्तो पर विचार करना आवश्यर है।" श्राष्ट्रचर्य की बात है कि पालना स्पापाग द्वारा इस सदी सियान्त का प्रतिपादन किए जाने के नाद भी भारत सरकार की नीति इसके विल्कुल निपरीत है। सामान्त के भाव कॅने रनो गए हैं, जिससे उपभोक्ताश्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा श्रीर उपानों के उत्पादन-व्यय में भी वृद्धि हुई। साद्यान्न ऊँचे भागों के समधन में यह कहा गया है कि (१) यदि खाद्यान्न के भाव गिराए जार्ये तो किछान खाद्यान्न के स्थान पर गन्ना, कपाछ श्रौर जूट बोयेगा, जिनके भाव श्रपेद्धाकृत श्रपिक कॅंचे हैं। किसान स्वभा- वतः ही इन ऊँची भीमतों की ब्रार ब्राकृष्ट होगा, ब्रीर (२) खाटान्न के भाव केवल भारत में ही ऊँचे नहीं हैं, बिल्क यह स्थिति सारे विश्व में है। जब तक विश्व के ब्रन्य देशों में प्रातास्त्र के भाव नहीं गिरते हैं, तब तक देश में खादास्त्र का ब्रभाव होने के प्रार्ग भाव उम नहीं किए जा सकते हैं।

इन नवीं में सत्य का श्रश बहत श्रधिक नहीं है। प्रथम तर्क के सम्बन्ध में यह ध्यान देने याग्य बात है कि गनने, क्यास श्रीर जूट की कीमत श्रधिक इनलिये है उयाकि सरकार ने इनकी कीमत केंची दर पर निश्चित कर रखी है। यदि ब्रास्म से हो व्यवसायी फमलो आर सायान्न के मूल्यों में कुछ सम्बन्ध निश्चित किया गया शैता तो इस महार की गरबड़ी कभी नहीं होती। जैसा कि पहले कहा जा सहा हैं क्षिमामा के सम्बन्ध में मुल्य और उत्पादन में उल्टा सम्बन्ध होता है। यदि न्यवसायो-फसल ग्रोर पायाच होनो के मूल्य कम रखे जाते तो होनां के उत्पादन में वृद्धि होती। परन्त सरकार द्वारा व्यवसायी-फराल का भाव केंचा कर दिए नाने से सारी स्थित ही बटल गई ब्रोर काफी इति पहुँची। इसका ब्रव एक यह उपाय हैं कि कपास, जूट, गरने इत्यादि के मूल्य कम किए जायें। इससे दो लाम होगे . (१) उद्योगो का उत्पादन न्यय कम होगा ग्रीर (२) खाद्याल के माव घट जायेंगे। जहाँ तक तुनरे तर्क का सम्पन्ध है, मारन में खात्रान का भाव इसलिए ऊँचा नहीं है कि विश्व के बाजारों के माव भी ऊँचे है। उसका कारण तो यह है कि मारत का उत्पादन बहुत कम है। कुछ समय पूर्व भारत में खाद्यान का भाव विश्व-बाजार के भाव की अपेदाकृत कहीं अधिक था। यदि यह तर्क सही है तो उस समय भारतीय कीमतों को इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए था। भारत में ऊँची कीमता की समस्या फेनल दो उपायों से हल की जा सकती है-या तो उत्पादन बढाया जाय अथवा श्रायात में वृद्धि की जाय । क्योंकि अधिक क्यय होने के कारण खायान का अधिक आयात कर सकना समय नहीं है, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि यही है कि देश में उत्पादन की वृष्टि की जाय। यदि खाद्याच श्रोर व्यवसायी फ़सलों के लिए प्रयुक्त भूमि में पति एकड़ का उत्पादन बहाया जाय. तो दोनों फसलों का उत्पादन बहाया जा सकता है। यह ग्रावश्यक नहीं है कि एक फसल बोई जाने वाली जमीन पर दुसरी फलल बोई जाय । सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे बीज श्रीर श्रिषिक पाद के द्वारा प्रति एकइ उत्पादन बढ़ा सकना समव है।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सबसे पहले १९५४ के मध्य में सरकार का ध्यान इस ख्रांर आकर्षित किया गया कि वह ऐसी नीति कार्यान्यित करे जिससे 'किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके'। पिछले वर्षों में साधाझ के मूल्य ध्राधिक थे और सरकार उन्हें नियन्त्रित करने में मयनशील थी। किन्तु जन जुलाई १९५४ में नई कमल तेयार टोनर बाजार मे प्राई, तो पनान मे गेहूं का भाव १० रुपए प्रति मन से भी कम हो गया। धपुर श्राहि उत्तर-प्रदेश को भी कुछ महिया में नेहूँ लगभग १० चयया प्रति मा के हिसाब से विकने लगा। मूल्यों में यह गिरायट उसलिए प्रार्वे कि (१) गेर् उत्यव करन वाले श्रधिकाश चेत्रों में पिछले वर्षों की अपेचाकृत अविक उत्पादन हुआ, (२) कप-शक्ति कम हो जाने के कारण बहुत से लोगों ने गेडू का उपयोग वरना बन्द कर दिया, निसके फलस्वरूप उसरी माँग में कमी ह्या गई, (३) यातायात के गाधनी की अधिक सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण वह समय न था कि जिन नेत्रा में गेहैं का उत्पादन होता है वहाँ से वह उन रेन्ट्रों को शीमतापूर्वर भेजा जा सके जहीं उसकी खपत होती है। फलन मिडिया में उसका भाव गिर गया, त्रोर (४) जिन श्रन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों न नेहूं के भाव न। गिराने में सहायता दी, उनके पीछे एक मनावैज्ञानिक कारण भी या श्रोर वह यह कि जिश्व मर में गेहूँ की पृति वह गई थी ग्रीर उसक मूल्य में बमी प्रा गड़ थी। इस सकट की दूर करने के लिए पजाव सरकार ने स्वय १० रुपया प्रति मन के दिसान से कुछ गर्ह रारीदा । उत्तर-प्रदेश सरकार भी ऐसा ही करने के लिए तेयार थी, किन्तु कालान्तर में मूल्या मे वृद्धि हो जाने पर सरकार ने गेहूं परीटना स्नापश्यक समझा। जब कि गेहूँ श्रोर चने के मूल्य मे अत्यधिक नीचे गिरने वी प्रशृत्ति दिलाई पढ़ने लगी तम चुनी हुई वस्तुत्रों के मूल्यों की सहापता देने की नीति (Selective price support policy) ना अनुसरण निया गया और अप्रैल १६५५ में नेह, जून में चना और त्रगस्त में चावल इसके अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गरे। जुलाई १६५५ से खायात्रा के मूल्य त्राविकार के बाहर जाने लगे क्यांकि बाह त्रादि प्राकृतिक प्रकोषा के कारण खरीफ की फसल विलक्षल नष्ट हो गयी थी। सरकार की मूल्य स्थिर रखने की नीति के कारण थोडे समय के लिये अन्न की पूर्ति में कमी आ गयी श्रीर जनता की घारणा कुछ ऐसी हो गई कि मूल्य यह गया।

यिद खाद्यात्र या उत्योगा में प्रयुक्त होने वाले कन्ने मालों के मूल्यों के एक निश्चत सीमा से श्राविक कमी हो जाय, तो उनका सरकार द्वारा खरीदना उसी मीमा तक उचित होगा जहाँ तक उससे किसानो का भला होता है, क्योंकि उनके दिनों को सुरक्तित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना श्रमिकों या उपमोक्ताश्रों के हितों की रज्ञा करना। किन्तु इस नीति से कई हानियाँ हैं (१) यदि मूल्य वरावर गिरते गए तो सरकार को भारी ज्ञित उठानी पढ़ जायगी, (२) समय है कि सरकार जमा किए हुए गल्ले को बैंच न सके श्रीर उसे पर्याप्त समय तक स्टाक में ही रखना पढ़ेगा, श्रीर (३) यदि सरकार किसी ग्रनाज को एक ही भाव पर

र्वेचने के लिए जोर देती है तो धामान्य मृल्य स्तर में कृतिमता उत्पन्न हो जायगी।
यदि कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मृल्य गिर जाता है तो इसके फलस्वरूप श्रन्य
कीमतों में भी कमी श्रा जायगो। इस प्रकार क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण
किसानों को तो लाभ होगा ही, उसके श्रितिरक्ति सम्पूर्ण श्रार्थिक व्यवस्था भी
लाभान्त्रित होगी क्योंकि खाटाच की कीमतों के गिर जाने से सामान्य मृल्य-स्तर
निश्चित रूप से कम हो जायगा।

नियन्त्रण (Controls)—सरकार की सायान्न तथा थान्य सामग्रियों पर नियन्त्रण लगाने की नीति की उण्योगिता पर बहुत विवाद चला था। नियत्रण लगाने का समर्थन करते हुए कहा गया है कि (१) गरीव जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ख्रीर अभाव अस्त च्रेत्रों को खाद्यान्न भेजते रहने के लिए सरकार द्वारा नियत्रण लगाना श्रावश्यक है। नियत्रण न लगाने से खाद्यात्र की कीमतें बढेंगी श्रोर इससे निर्धन जनता को श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पडेगा, (२) योजना की सफलता के लिए नियत्रण श्रावश्यक है, क्योंकि नियोजन ग्रोर विनियन्त्रण (De-control) साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। किन्त इन तकों में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि स्वय नियंत्रण लगाने से ही श्रभाव की स्थिति पेदा हो जाती है। यदि नियत्रण हटा दिया जाय तो बहुत सभव है कि गल्ले इत्यादि के छिपाकर रखे गए स्टाक खुले बाजार में ब्राने लगें ब्रौर उनके वितरण में सुघार हो जाय जिसके फलस्वरूप ब्रामाव की स्थिति भा दूर हो जाय। चुँ कि खादान क वही आँकडे प्राप्त नहीं है, इचलिए की कमी की मात्रा का ठीक पता चला सकता कठिन है। यह कहा गया है कि जिन श्रिधिकारियां पर खाद्यान्न-नियत्रण लागू करने का उत्तरदायित्व है वह श्रिभाव को श्रावश्यकता से अधिक ऑकते हैं जिससे वह काफी समय तक उस पद पर कार्य कर सके। यदि नियत्रण इटा दिया जायगा तो यह कृत्रिम स्थिति स्वय दुर हो जायगी। जहा तक नियोजन का प्रश्न है, यह सच है कि विदेशी ज्यापार श्रीर विदेशी पूँजी पर कुछ सीमा तक नियत्रण रखना आवश्यक है, परन्तु यही तर्क खात्राञ्च-नियनग् पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि योजना की सफलता के लिए नियत्रण का होना आवश्यक है।

यदि नियत्रण कुशलता पूर्वक लागू किए जाते श्रीर उनको प्रभावशाली बनाने के लिए कडे उपायों को श्रपनाया जाता तो रिपति में सुधार होना सैमव था, परन्तु भारत में नियत्रण जितनी श्रिषक कठिनाइयाँ इल नहीं कर पाते उससे कहीं श्रिषक कठिनाइयाँ पेदा कर देते हैं। उपमोक्ताश्रों, ज्यापारियां श्रीर दुकान- टारां सभी को ग्रनेक फठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। यटि नियत्रण लाग् न हो ता विशेष हानि नहीं होती है, परन्तु वदि लागू करके भी उनका कुणलता पूर्वक सचालन न किया जाय तो सुविवा की श्रपेचा कष्ट श्रधिक बढ जाता है ग्रोर हानि भी होती है। यदि उस प्रकार के नियत्रण की हटा दिया जाय तो निअप ही स्थिति म सुपार होगा। फिर जम तक नियमण लागू रहेगा, देश की श्राधिक व्यवस्था प्रपन सामान्य स्तर पर नहीं श्रा सकती है। सामग्री नियन्नस् र्सामिति (Commodity Controls Committee) ने इस पात की ग्रोर न्यान हिया और यह नताया कि ''राजाल में ग्राम भी कमी ननी हुई है। इसलिए जन तक यातापात सम्मन्धी कठिनाइपा है आर प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्यरूप दुमिच पड़ने भी सभापना बनी हुई है तप तक गाद्याय भी यनुभृति व उपलब्धि में सम्प्रान्यत आदेश (Foodgrains Licensing and Procurement Order, 1952) व अन्य पुरक आदेशा का पालन किया जाना अनिवार्य है"। जैसा कि बाद की स्थिति ने कात होता है, नियतरा ने स्वय ही सामान का अभाव उत्पन्न वर दिया था। यद्यपि सामगी नियनण समिति व श्रन्य लोगों का विचार था कि वर्तमान परिस्थिति मे नियत्रण हटाना सभव नहीं होगा. हिन्त उसे हटा देने से खाद्यान का स्थिति निश्चित नप में सुधर गउँ है।

मारत के उस समय साय-मन्त्री स्वर्गीय श्री रफी ग्रहमद किदवई की यह वारणा थी कि सायात्र का नियत्रण कर देने से स्थिति सुधर जायगी। उन्होंने मई १६५२ को अपने एक सावजिनक भाषण में क्हा कि जिन राज्यों में साधान्न का उत्पादन उनकी आवश्यकता ने ग्रीधिक हो रहा है वहाँ में नियत्रण हट जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दो तीन राज्यों के अन्तर्गत देहातों में भी राशनिङ्ग (Rationing) है, वह भी हटा लेना चाहिये। किदवई माह्य की इस घारणा का सरकारी और गर सरकारी देनों ही सेत्रों में विगेध किया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में श्री सी० राजगोपालाचारी ने श्रीगणेश किया और २६ जून १६५२ को मद्रास से खायान नियत्रण हटा लिया। यह विनियन्त्रण की दिशा में पहला कदम था। कुछ पारम्मिक कठिनाइयाँ अवश्य हुई किन्तु साद्यान चिनियन्त्रण में पर्याप्त सफलता मिली। उत्तर प्रदेश, विहार श्रादि कई राज्यों ने मद्रास का

श सामग्री नियत्रण सिमिति की नियुक्ति २४ श्रवटूचर १६५२ को काउन्सिल श्रॉव स्टेट्स के उपसभापिन श्री एस० बी० इप्णमृति राव की श्रध्यत्तता में की गई थी। इस सिमिति ने खाद्याच का विनियत्रण श्रारम होने के थोडा पहिले ही २० जुलाई १६५३ को त्रपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी।

श्रनुसरण किया श्रोर वितन्तर १९५२ तक यह विनियन्त्रण ६ राज्यों में लागू हो गया। धीरे-वीरे यह जोर पकड़ता गया स्त्रीर १६५३ तक केन्द्र व राज्य सरकारा ने खाद्यान के वितरण त्रोर उसके मूल्य पर से नियन्त्रण इटाने का काम बिल्कुल पूरा कर लिया ज्यार, बाजरा, मनका, जा जैसे मोटे श्रानाजों पर से १ जनवरी १६५४ को नियन्त्रण इटा लिया गया, इसके साथ ही इन मोटे अनाजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जा प्रतिबन्ध या वह सौराष्ट्र, मन्यभारत स्रोर उत्तर-प्रदेश के ११ जिला को छोड़कर सभी जगहीं से हट गया। बाद को यह प्रतिवन्य भी इटा लिया गया। चावल का विनियन्त्रण १० जुलाई १९५४ से लागू किया गया। उसे एक राज्य से दूधरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा है और अब देश के सभी भागों में उसका व्यापार स्वतन्त्रतापूर्वक किया ना सकता है। सभी तक चावन श्रनिवार्य रूप से प्राप्त करना पड़ता था, किन्तु विनियन्त्रण लागू होने से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त चावल के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण भी बन्द हो गया है।
"जिस कमिक विनियन्त्रण (Gradual de control) को राजा जी

१९५२ में प्रारम्भ किया था, वह चावल का पूर्ण विनियन्त्रण हो जाने के उपरान्त अपनी चरमावस्था पर पहुँच गया"। अतर-प्रदेशीय प्रतिनन्ध जो गेहूँ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने क सम्बन्ध में लागू किया गया था वह नियत्रण का अतिम हा या और १८ मार्च ८६५५ मे वह मो उठा लिया गया। इसमे १०

वर्ष तक लागू नियन्त्रण का द्यत हो गया। विनियन्त्रण के समर्थकों ने यह द्याशा दिला रखी यी कि खादान्न-नियन्त्रण के फलस्यरूप श्रकाल, खाद्यान के सम्बन्ध में स्थानीय श्रमाव (Local scarcity) श्रीर श्रन्य श्रापत्तियाँ उत्पन्न हो जायेंगी, किन्तु मान्यवश ऐसा कुछ मी घटित नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि खाद्यात्र नियन्त्रण के कारण श्रज के अभाव को कृत्रिम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं ख्रीर जिन अधिकारियों को खाद्यान्न-नियन्त्रण का कार्य-भार सींपा गया था, स्वार्थरत होकर त्रपना हित साध रहे थे। नियन्त्रण हट जाने से (१) खाद्यान का श्रमाव होने की जो मन स्थिति वन गई थी वह दूर हो गई। इस म श्रितिश्क मुनाफा लारी श्रीर चोरवाजारी का भी श्रन्त हुआ, (२) देश में लाद्यान के वितरण की स्थिति सुधर गई, (३) लाद्यान का भाव कम हो गया जिसक फलर। रूप लागा के रहन-सहन की लागत घटी श्रीर किसानों को भी श्रधिक उत्पादन करने में प्रवृत्त होना पड़ा, जिससे वे उतनी स्राय का उपार्जन कर सकें जो उन्हें पहले प्राप्त हो रही थी, (४) केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा खाद्यान नियन्त्रण व राशनिङ्ग पर जो व्यय होता या उसमें

कमी आ गई। विनियन्त्रण से यदि कोई हानि हुई है तो यही कि सामाज नियन्त्रण और राशनिङ्ग विभाग के कर्मचारी वहुत गड़ी सख्या में वेरोजगार हो गये और मुनाफासोरों व चोरवाजारी करने वालों की आप का एक बहुत गड़ा साधन छिन गया।

खाद्य स्थिति विगद्रते जाने के फलस्वरूप १९५६ में चातल तथा गेहूं के मगदल (zone) निश्चित करके, उचित मूल्य पर वेचने वाली दूकानों द्वारा विक्री करके तथा पाद्यान्न के व्यापार एवम् लाने-ले जाने पर भतिवन्य लगा कर सीमित नियत्रण फिर से लागू किया गया। सरकारी प्रविकारिया का एक वर्ग पूर्ण नियत्रण के पन्न में है तथा योजना प्रायाग के प्रथंशान्त्रियों ने भी इस विचार का समर्थन किया। किन्तु, जैसा कि इम कण्य सकेत कर चुके हैं, पात्यान जीच कमेटी के नियत्रण के विरुद्ध सिफारिश की।

## **छध्याय** ६

# जमींदारी उनमूलन

त्राधिक दृष्टि से जमीदारी उन्मूलन का विशेष महत्व है। श्राखिल मारतीय काग्रेस क्मेटी की आर्थिक नीति का यह सदेव महत्वपूर्ण ग्रावार रहा है। विशेषज्ञों की श्रनेक समितियों ने मी समय-समय पर जर्मीटारी का उन्मूलन करने की सिफारिश की। १६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् कांग्रेस सरकार ने जमीदारी उन्मूलन को श्रपने ग्राधिक कार्य-कम का महत्वपूर्ण श्रग बना लिया ब्रोर धीरे-बीरे सभी राज्यों में इस नीति को लागू किया है। बहुत से राज्यों ने, जहाँ जमींदारी या दखी के अनुरूप कोई अन्य प्रधा प्रचलित थी, इन विशेषाबि-कारों का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाए है और उत्तर प्रदेश तथा विहार ने तो जमींटारी का उन्मूलन कर उन पर ग्रपना कव्का भी कर लिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात व्यान देने याग्य है कि इन मरकारों ने मुग्रावजा देकर जमींदारी-उन्मूलन करने की नीति श्रपनाई है श्रर्थात् सरकार ने जमींदार की उसकी जमीन के बदते उपयुक्त मुख्रावजा (Compensation) दिया है। ३१ मार्च १९५६ तक जमीदारी प्रथा उन्मूलन हो गया तथा ४,३६ करोड़ एकड़ श्रथवा राज्य की ६६.८ प्रतिशन कृषि जोतो पर भूमि सुवार के उपाय लागू किये गये।

उन्मूलन के पन्न में तर्क-जमीदारी उन्मूलन करने के समर्थन में श्रनेक तर्क दिए गए हैं। यह कहा गया है कि जमीदार किसानी का शोपक (Parasite) है श्रोर उसने श्रपने कब्जे की जमीन में कुछ सुवार नहीं किया, भूमि की चक-बन्दी (Consolidation of holding) करने में सदीव दशानट डाली है श्रीर किसान को जा जमीन जोतता बाता है भूम सुधार के लिये श्रपनी श्रनुमित नहीं टी है। यटि जमीदार को हटा दिया जाय तो भूमि में सुवार किया जा सकेगा, लाद्यान के उत्पादन में वृद्धि होगी ग्रोर भूमि सुवार योजना को कायान्वित किया जा सकेगा जिसकी बहुत समय से प्रावश्यकता प्रतुमव को जा रही है। यह तर्क वहुत अशों में सही है, फिर भी इस तथ्य को टाला नहीं जा सकता है कि कुछ ऐसी कठिनाइयाँ है जिन पर जमींदार का वश नहीं है त्रीर यदि वह वश में रखना

जमीदारी उन्मूलन का समर्थन करते हुए यह भी कहा गया है कि इससे भी चाहे तो सफल नहीं हो सकता। राज्य की भू-राजस्व (Land revenue) आय बढेगी । यह तर्क जिल्कुल सही है चयोंकि १६५१-५२ में राजों की मृ-राजस्य ने प्राय ४० ६६ करोड़ रुपये यो जो चढ़ कर १६५७-५ में (बजट के अनुसार) ६२ ५४ करोड़ रुपये हो जायगी। इससे चाज्य सरकार मुद्रावजे की किश्त चुकाने के बाद अपनी भूमि सुवार तथा आम-पुनर्निर्माण (Rural reconstruction) योजनात्रा को लागू कर सर्वेगी। परिणामहरूद देश के प्रति व्यक्ति की प्राय में वृद्धि होगी आर किसान की स्थिति में सुधार हो सकेगा।

जमीटारी उन्मूलन का प्रथन श्राधिक होने के नाथ ही राजनैतिक मी बताया गया है। देश के मतटाता श्रों में किसानों की सख्या बहुत श्रिथिक है। किसान वर्तमान स्थिति ते बहुत श्रिसन्तुष्ट हैं श्रीर उनका विचार है कि उनकों इस टयनीय स्थिति तक पहुँचाने के लिए केवल जमीटार हो उत्तरटायी हैं। यह सर्वविदित है कि जनतत्र प्रणाली में बहुमन का निर्णय ही मान्य होता है चारे उनका हिण्डकोण कुछ मा हो। इसलिए किसानों क श्रुसन्तीय को कम करके उनका मत श्रुस्त्वल करने के लिए जमीदारा उन्मूलन को एक साधन बनाया गया है। पिछले वैर-भाव की प्रतिक्रिया के रूप में किसान भविष्य में लागू की जाने वाली किसी मी भूमि सुधार योजना में जमीटारों के साथ सहयोग नहीं करेंगे इसलिए भूमि सुवार योजनाएँ तभी सफल हा सकती हैं जब किसानों तथा राज्य सरकार के मध्यस्तों का उन्मूलन कर दिया जाय।

जमीदारी उन्मूलन के चिरुद्ध तर्क—जमींदारी उन्मूलन के विरोध में भी अनेक तर्क दिये गये हैं परन्तु उनमें जान नहीं है! यह कहा गया है कि जमीदार के उन्मूलन से बहुत वही छएया में लाग वेरोजगार हो जायेगें, जैसे, जमीदार, उनके जिलेदार, कारिन्दे इत्यादि। इससे केवल जमीदारी की आय पर निर्मर करने वाला वर्ग वहुत कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कि उत्तर में यह कहा जा सकता है कि किसी भी परिवर्तन के साथ कुछ कि उन्मूल श्रीर अव्यवस्था का होना जरूरी है और इस कि जिलाई तथा अव्यवस्था से उरकर परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। वास्तव में महत्व तो इस बात का होता है कि परिवर्तन से क्या लाभ होगा अथवा उसका क्या परिणाम होगा। यह सही है कि अमीदारी का उन्मूलन कर देने ने जमीदारी को कि उनाहयों का समना करना पढ़ेगा परन्तु इसमें किसानों की दशा में सुधार भी होगा और दीर्घकालिक दृष्टिकाण से यह लाभदायक सिद्ध होगा। जमीदारों के कारिन्दे इत्यादि कर्मचारी आरम्भ में वेरोजगार हो जायेंगे परन्तु बाद में उन्हें रोजगार मिल सकता है क्यांकि सरकार को लगान वस्त करने के लिए नथा अन्य कायों के लिये कर्मचारियों की आग्रव्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमीदारों की कि ठिनाहयों का प्रश्न है चारियों की आग्रव्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमीदारों की कि ठिनाहयों का प्रश्न है चारियों की आग्रव्यकता पढ़ेगी। जहाँ तक जमीदारों की कि उनाहयों का प्रश्न है

सरकार जमींदारी के बदले उन्हें मुख्रावजा देगी और उन्हें ख्रपने जीवन निर्वाह के लिये स्वय ख्रम्य साधनों की खोज करनी चाहिए।

यह भी कहा गया है जमींदारी का उन्मूलन हो जाने से किसान को कई प्रकार से हानि पहुँचेगी। इस समय सामाजिक तथा ग्रन्य कार्यों के लिए जमींटार किसानों को ऋण देता है, लगान वस्ली में वह किसान की परिस्थितियों का ध्यान रखता है श्रीर उसे श्रदायगी के लिये समय देता है परन्तु सरकार के कर्म-चारी किसान को यह सुविधा नहीं देगे। केवल जमीदारी का उन्मूलन कर देने से ही भूमि सुधार सम्भव नहीं है, यदि सारी घटनायों को इसी प्रकार घटित होने दिया जायगा तो देश को लाभ होने की श्रपेत्रा श्रधिक हानि होगी। इसमें कुछ, सन्देह नहीं कि किसान की स्थित मे कुछ परिवर्तन ग्रवश्य होगा परन्तु यदि कार्य का सुचार-रूप से सचालन किया गया तो किसान की दशा श्रीर अधिक विगइ जाने की कोई सम्भावना नहीं। श्रावश्यक्ता पड़ने पर क्सान को कम सूद पर ऋग देने के लिये विशेष सस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं। यदि जमींदारी का उन्मूलन न किया गया तो जिस भूमि सुधार की बहुत समय से ख्रावश्यकता ख्रनु-भव की जाती रही है वह कभी लागून हो सकेगा । जभींदारी उन्मूलन से जो श्रव्यवस्था पैदा होगी उसका सामना करना पडेगा श्रीर जितना शीघ यह हो सके उतना ही ग्रच्छा है। इससे सुघार करने के लिये मार्ग खुल जायगा श्रीर कुछ समय तक ग्रस्यायी ग्रन्यवस्था के पश्चात् भूमि का उत्पादन बढेगा, किसान की दशा सुघरेगी श्रोर देश की श्रार्थिक समृद्धि बढेगी।

उन्मूलन योजना—जमींटारी उन्मूलन कार्य "श्रस्थायी बन्दोबस्त वाले चेत्र में श्रपंत्ताकृत सरल था, जैसे उत्तर प्रदेश श्रीर मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ श्रावश्यक लेखा तथा इस कार्य को करने याले श्राधकारी उपलब्ध थे। स्थायी प्रन्टोबस्त वाले चेत्रों में जेसे विद्वार, उड़ीसा श्रोर पिन्छमी बगाल तथा जागीरदारी चेत्रों पैसे राजस्थान श्रोर सोराष्ट्र में सब लेखा तैयार करना श्रीर नये सिरे से श्रिधकारियां की नियुक्ति श्रावश्यक थी। जो कुछ भी हो मध्यस्थों को हटा देने के कानून श्रिधकारा प्रदेशों में लागू कर दिये गये हैं"।

जमींदारी उन्मूलन में साधारणतया निम्न उपायो का प्रयोग किया गया है: (१) वे भूमि के भाग जो परती पडे थे, जगल, श्राबादी के चेत्र, त्रादि जो यध्यस्थों के ग्राविकार में थे, प्रवन्ध श्रीर सुधार के लिये सरकार के श्राधिकार में दे दिये गये। (२) खुट दाशत की भूमि तथा निजी फार्म के चेत्र, जिनकी देख-रेख स्यय जमींदार ही करते थे उन्हीं के ग्राधिकार में रहने दिये गये श्रीर वे काश्तकार जिन्होंने ऐसी भूमि पट्टे पर जमींदारों से ले रस्ती थी काश्तकार (tenant) की हैसियत से उन्हीं के अधिनार में छोड टी गई। (३) बहुत से राजों में प्रधान आसामी जिन्हें मध्यस्यों न सीवे भूमि प्राप्त थी सीवे राज्य की सरकारों से सम्बन्धित कर दिये गये। बम्बई, हैटराबाट और मेनर में इनामों से प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में यह बात नहीं लागू की गई थी। इन प्रदेशों में मध्यस्यों को ज्ञासामियों से लेकर कुछ भूमि टी गई। कुछ प्रदेशों में आसामियों को स्थायी तथा इस्ताँतरण का अधिकार प्राप्त था, इसलिये प्रव यह आवश्यक नहीं था कि उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किये जार्ये। उत्तर प्रदेश, मन्य प्रदेश, हैटराबाट, मैग्र फ्रांर दिल्ली राजों में आसामियों को भूमिधारा अधिकार प्राप्त करने के लिये उसका मूल्य ज्ञाने का अवसर दिया गया। आन्ध्र, मद्रास, राजस्थान, गौराष्ट्र (पाली चित्र) व मन्य मारत, हैटराबाट (जागीर चेत्र) आर अजमर में वा ता आसामियों के अधिकार बढा ।टये गये अथवा उनका लगान घटा दिया गया और उनसे कोई मूल्य नहीं वस्त्ला गया"।

''मन्यस्पों को दिये जाने वाले मुत्रावजे ग्रोर पुनर्यास में सहायता के रूप में दी जाने वाली रकम का श्रनुमान लगभग ४५० करोड़ रुपया लगारा गया है। इस रकम का ७०% के बल उत्तर प्रदेश ग्रोर निहार में दिया जाने वाला मुद्रावजा है।

मुख्यावजे का खिवकार-विभिन्न जमींदारी उन्मूलन कानूनों में मुख्यावजे के विभिन्न श्राधार दिने गये हैं।ग्रासाम, विहार, उदीसा ग्रोर मध्य प्रदेश में मुग्रा-वजे का त्राघार भूमि ने प्राप्त होने वाली 'वास्तविक त्राय' (net income) है। उत्तर प्रदेश में यह श्राधार 'वास्तविक सम्मत्ति' (net assets) श्रार मद्रास में मूल-भूत वाषिक ग्राय' (Basic annual sum) है । वास्तविक ग्राप ग्रोर वास्तविक सम्पत्ति के श्रावार लगमग समान ही हैं। जमींदारी की उन्न श्राय में से भूराजस्व उपकर (cess), प्रयन्य रा न्या, रैटयत के लाम के लिये किये गये कार्यों में च्यय श्रोर कृ।प ग्रायकर इत्यादि बटाकर ही वास्तविक ग्राय (net income) निकाली जाती है। प्रवन्य ग्रोर रैच्यत (ryot) के लाम के लिये किये गए कार्य में जो रकम व्यय की जाती है वह सभी राप्यों में समान नहीं है। वास्तविक स्नाय निश्चित करने के पश्चात् इमी श्राधार पर मुख्रावजा निर्धारित किया गया है। महास में 'मूलभूत वापिक ब्राप' निकालने के लिए रैय्यतवाडी से प्राप्त वार्षिक त्रान के एक विहाई भाग में स पाँच प्रतिशत कमचारियो पर व्यय करने स्रोर वस्ली न हो सकने के लिए अलग कर दिया जाता है ओर ३ व प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था को चलाने के लिये नाट लिया जाता है। इससे जो श्राय शेष रहती है वही 'मूलभूत वापिक स्राय' कहलाती है। यह दग स्रन्य राज्या से भिन्न है क्योकि सुय्रावजा जमींदार से प्राप्त होने वाली वर्तमान वास्तविक श्राय पर श्रावारित न होकर रय्यतवाड़ी प्रथा लागू होने के बाद भू-राजस्व के २५ प्रतिशत पर श्राघारित होगा।

उत्तर प्रदेश में मुत्रावजे की दर वास्तविक सम्पत्ति का श्राठ गुना है। इसके साथ ही जो जमींदार १०,००० रुपये से श्रिधिक भू-राजस्व नहीं देते उनको जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वास्तविक सम्पत्ति के २० गुने से लेकर एक गुना तक पुनर्वास श्रमुदान दिए जायँगे। यह श्रमुदान कम श्राय वाले जमींदारों के लिये सबसे श्रिधिक गुने होगे श्रीर श्रिधिक श्राय वालों के लिये कमशः कम होते जायँगे मध्यस्थों को दिया जाने वाला मुश्रावजा तथा पुनर्वास श्रमुदान का श्रमुमान क्रमशः ७५ करोड रुपया तथा ७० करोड़ रुपया है।

मुत्रावजे के चुनाने में सबसे श्रिषक विचारणीय बात यह है कि मुश्रावजा नकट दिया जाय या वेचे न जा सकने वाले वाएडों के रूप में। जमींदारों के दृष्टिकोण से यदि मुत्रावजा नकट दिया जाता तो सर्वोच्यम होता क्योंकि इससे वह कोई नया कारोबार खोलते या उत्रोगों में स्पया लगाते जिससे उन्हें बरानर श्राय होती रहती। परन्तु मुश्रावजे की रकम को नकद श्रदा करना समय नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें इतना श्राधक धन नकद देने की ज्यवस्था नहीं कर सकती है। उनके पास इसके मुगतान के लिए स्पया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहा जमींदार उन्मूलन कोष का निर्माण किया गया है, किसानों को श्रपने लगान का १० गुना जमा कर भूमिधारी श्राधकार लेने को पोत्साहित किया जा रहा है किर भी श्रभी तक बहुत कम स्पया इकटा हो सका है। मुग्रावजा वेचे न जा सकने वाले बायडों के रूप में दिया गया। परन्तु इस विधि से जमींदार के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं होता है क्योंकि जमींदारों को उनके मुग्रावजे की रकम श्रीर उस पर ज्याज का मुगतान काफी लम्बे समय में किया जायगा श्रीर इस बीच श्रपना वर्तमान खर्च चलाने में तथा कोई नया कारोगार स्यापित करने में जमींटारों को बहुत किटनाई होगी।

श्रान्य प्रगाली—नमींदारी उन्मूलन कर देने से दी सारी समस्या का इल होना सभव नहीं है। यदि इसके वाद भूमि सुघार लागू नहीं किए तो जमींदारी उन्मूलन का लाम नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य समस्याएँ यह हैं · (१) जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि पर श्रिषकार की व्यवस्था, (२) कृषि के रूप (form of cultivation). श्रीर (३) भू-राजस्व वसून करने के लिए श्रीर चरागाह, वंजन जैसी जमीन की देख रेख करने के लिए सरकार की श्रीर से निर्धारित उपयुक्त सस्था। श्रव तक भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृपक को स्वामित्व के श्रधिकार प्रदान करना था। भूमि के हस्तातरण के सम्बन्ध में भूस्वामी के श्रधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध इसिलये रखे गये हैं ताकि जोते बहुत बड़ी या बहुत छोटी न हो कॉय श्रौर भूमि गैर-कृषकों के हाय न चली जाय। "भूमि सुधार के उपायों के लागू होने के बाद जमींदारी श्रौर जागीरदारी चेत्रों से श्रधिकाश कृपकों के भूमि सम्बन्धी स्वामित्व के, श्रधिकार प्राप्त कर लिये हैं। इस प्रकार मीठि रैय्यत (occupancy raiyat), नियत लगान वाले रैय्यत श्रादि भू-स्वामी वन गये। गैर मीठिसी रैय्यत श्रीर रैय्यत के नीचे वाले किसान, सामान्यत मूल्य चुकावर ही मूस्त्रामी वन सकते हैं। यह सब तथा पूर्ववर्ती मध्यस्य जो श्रपनी सीर श्रौर खुदकाश्त के मालिक बने हुये हैं। श्रिविकतर राज्य के काश्तकार कहलाते हैं किन्तु वास्तव में वे श्रपनी भूमि के स्वामी है श्रीर उनके श्रधिकार रैय्यतवारी चेत्रों के भू-स्वामियो की तरह ही हैं।"

श्रिषकाश राज्यों में भूस्वामियों को श्रपनी भूमि वेचने का श्राधकार है यद्यपि इस पर कुछ प्रतिवन्घ श्रवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि घर, मध्यप्रदेश में भूमि स्वामी श्रीर भूमिधारी, विद्वार में भूस्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, पश्चिमी वगाल में रैय्यत, श्रासाम में भूस्वामी, विशेष श्रधकार प्राप्त रेय्यत, मैक्सी रैय्यत, लगान या सदैव के लिये निश्चित लगान देने वाले वाश्तकार, हैंदराबाद श्रीर बम्बई में भूमि वाले किसान, पजाब में भूस्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, उड़ीसा में भूस्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, उड़ीसा में भूस्वामी श्रीर मौक्सी काश्तकार, पण्यू में भूस्वामी, राजस्थान में खातेदार काश्तकार, मध्यभारत में पक्के काश्तकार इत्यादि सभी को श्रपनी भूमि वेचने के श्रिषकार प्राप्त हैं। भूमि वेचने पर इस प्रकार के प्रतिवन्ध श्रवश्य हैं जैसे (श्र) किस प्रकार के व्यक्तियों को भूमि वेची जा सकती हैं (ब) किस सीमा तक भूमि वेची जा सकती हैं, खरीदी भूमि के लिये श्रविकतम सीमा होती है तथा वेचने वाले के पास शेष भूमि के लिये निम्नतम सीमा होती है।"

"य्रनेक राज्यों में गैर-कृपको को भूमि वेचने की मनाही है। वस्बई हैटराबाद, मध्यभारत श्रौर सौराष्ट्र में कानूनन गैर कृपकों को भूमि वेचने की श्राशा नहीं है। वस्बई श्रौर पश्चिमी बगाल में श्रनुमित प्राप्त खरीदारों की प्राथमिकता का कम निश्चित है। प्राथमिकता में पहला नम्बर उन काश्तकारों का है जो भूमि पर वास्तव में काविज हैं। इसके वाद पड़ोसी कृपको का नम्बर हैं तथा इसी तरह लोगों का कम निश्चत है।"

"उत्तरप्रदेश में यद्यपि भूमिधार को अपनी जोतो को वेचने का अधिकार है किन्तु इस पर यह प्रतिवन्ध है कि घामिक संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर खरीदने वाले की जोत ३० एकड से श्रिधिक न हो जाय। वम्बई में यह सीमा १२ एकड़ से ४८ एकड (जो भूमि की किस्म पर निर्भर है) है। हैटराबाद में यह सीमा परिवारिक जोत की तीन गुनी है। मध्यमारत में यह ५० एकड़, पश्चिमी बंगाल में २५ एकड़ (जिसमे घर से सलग्न खेत नहीं शामिल हैं) दिल्ली में ३० स्टेन्डर्ड एकड, राजस्थान में ६० श्रिसिचत एकड़ या ३० सिंचित एकड़, श्रासाम में एक परिवार के लिये १५० वीघा (४६ ३ एकड़) तथा सोराष्ट्र में तीन श्रार्थिक जोत है।"

वस्वई, हैदराबाद थ्रोर मन्यभारत में ऐसी कोई भूमि नहीं वेची जा सकती जो वेचने वाले की जोत को निर्धारित सीमा में कम कर दे। उदाहरण के लिये वस्वई में कोई भी जोत वेचकर या किसी अन्य प्रकार इस तरह विभाजित नहीं की जा सकती कि उसके (एक गुटा या चार एकट सीमा भूमि पर निर्भर है) टुकडे हो जॉय। हैदराबाद में एक (स्टेन्डर्ड) निश्चत चेत्रफल निर्धारित करने की व्यवस्था किसी भी हालत में भूमि इससे कम चेत्रों में नहीं विभाजित की जा सकती। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में परका काश्तकार अपनी भूमि तभी वेच सकता है जब कि वह अपनी कुल भूमि वेचने से तैयार हो श्रथवा बेचने के बाद उसके पास प्र सिचित एकड़ या १५ असिचित एकड़ भूमि बच रही हो।"

इन सन प्रतिजन्धों के बावजूद भी, अधिकाश राज्यों में जमींदारी उन्मूलन के परचात् कृपकों का भू-स्वामित्व हो जायगा तथा प्रत्येक किसान अपनी जमीने जोतेगा। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी सीमा तक जमींदारी उन्मूलन के लाभ व्यर्थ हो जॉयगे। कृषक के पास अपनी भूमि में सुधार करने तथा कृषि के सुधारे हुये दगों का प्रयोग करने के लिये साधन नहीं है।

भूमि से उत्पादन की मात्रा तभी वढाई जा सक्ती है जब बहे चेत्री में खेती की जाय थ्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर मशीनों का उपयोग किया जाय। उत्पादन में वृद्धि होने से किसान की श्राय में भी वृद्धि होना स्वामाविक है। उत्तर प्रदेश कानून में दो तरह की सहकारी-कृषि प्रणालियों की व्यवस्था की गई है— (१) ५० एकड़ या श्रधिक के ऐसे छोटे फार्म जो १० या श्रधिक किसानों ने त्वेच्छा से समक्तीता करके बनाए हां श्रीर (२) श्राधिक हिंध्ट से श्रनुपयुक्त जमीनों को मिलाकर सगठित सहकारी फार्म। यदि दृषरे प्रकार के फार्म के सुल सदस्यों के दो तिहाई यह माँग करते हैं कि इन छोटे फामा को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया जाय तो शेष एक तिहाई को श्रनिशार्य रूप से यह माँग माननी पड़ेगी। परन्तु इससे समस्या नहीं सुलक्त सकती। सहकारी फार्म की प्रणाली लागू करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा।

## अध्याय ७

# ें भूमि की चकवन्दी

भाग्त में भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में विमक्त कर देने से गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मारत के किसान मूमि के छोटे छोटे यलग-यलग विखरे हुए हुनडों में खेती करते हैं जिससे खात्रान्न तथा अन्य सामग्री का उत्पादन कम होता है श्रार किसान की गरीबी बढ़ती जाती है। इसक श्रनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं, (१) भूमि पर जनसंख्या का दवान और मौक्सी इक सम्बन्धी कानून । परिवार के प्रधान के मरने पर जमीन उसके पुत्रों तथा ब्रान्य सम्बन्धियों में बॉट टो जाती है। वॉटने समय इस बात का व्यान नहीं रखा जाता है कि इन भूमि के छोटे-छोटे हिस्सा से हिस्सेदारी का जीवन-निर्वाह नहीं हो सकेगा, इनमे बो कुछ उत्पादन होगा उससे वह श्रपना भरण-पोपरा नहीं कर सकेंगे। (२) किसान क ऋगी होने तथा श्रन्य कारणों से भूमि का विक जाना। भारत के किसान भ्रम्ण के बोम से टब जाने के कारण ग्रपनी जमीन रेहन रख दंते हैं श्रीर मृरण न बुका सकने पर उस जमीन को ऋग्रदाता वेच देता है या स्वय ले लेता है, इससे जो जमान पहले से ही छोटे छोटे टुफडा मे यी श्रव श्रोर श्रिधक विमक्त हो जाता है। यदि किसान के संयुक्त परिवार के एक सदस्य का हिस्सा ऋग न चुका सकने श्रथवा श्रन्य किसी कारण में वेच दिया जाता है तो शेप भूमि कम हो जाती है श्रोर जब उसका विमाजन किया जाता है तो वह श्रीर छाटे छोटे दुकडों में वॅटती जाती है। (३) किसान इस बात से श्रनिमश है कि सूमिका छोटे-छोटे हिस्सों में बॅट जाना बुरा है। यह श्रमुमव किया गया है कि किसान भूमि की चकवन्टी क लिये शीम तैयार नहीं होता। इसके लिये उसे काफी समक्तना पहता है ग्रीर टवाव ढालना पहला है। मूमि की चकवन्दी से उत्पादन वढता है तथा कृपक का चिता भी कम हो जाती है इससे हम छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त होने की गम्मीर समस्या को ही इल नहीं कर लेते बल्कि याम योजना मे, खेल के मेदान, स्कूल, गढे त्रादि बनाने में भी सहायता मिलती है।

हानियाँ—भूमि का विभाजन और उसका छोटे-छोटे दुकड़ों में वट जाना एक गम्मीर दोप है। इससे अनेक हानियाँ होती हें (१) इससे भूमि में सुधार नहीं किया जा सकता। भूमि छोटे टुक्डों में वॅटी होने के कारण किसान अपनी खेती के लिये न कुआँ खोट पाता है, न मशीनों का उपयोग कर पाता है और न अन्य प्रकार के सुधारों को ही लागू कर पाता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ने पाती थ्रोर उत्पादन गिरता जाता है। (२) भूमि के छो-छोटे दुकड़ों में बंटे रहने के कारण बहुत सी जमीन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से थ्रलग करने के लिये मेढ़ वॉधने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है और भूमि के टुकड़े विखरे होने के कारण किसान थ्रपनी खेती की अच्छी तरह देख-भाल भी नहीं कर पाता है। इसस फसल में गहरी हानि होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। और (३) किसान को एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने मे ही बहुत सा समय नष्ट करना पड़ता है।

यह कहा गया है कि भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बॅटे रहने से किसान को लाभ है क्योंकि इससे गाँव के श्रनेक मागो में प्रत्येक किसान की कुछ न कुछ भूमि रहती है। यदि बाढ तथा टिड्डी इत्यादिका सकट आ जाय तो उसकी सारी भूमि नब्द होने से बच जाती है। यदि एक भाग इस संकट से नब्द भी हो जाय तो अन्य भाग दूर होने के कारण बचाये जा सकते हैं। दूसरा लाम यह बताया जाता है कि भूमि के इस प्रकार के बूँटवारे से गाँव की अधिकाश जनता के पास भूमि हो जाती है। यदि यह बॅटवारा न किया जाय तो बहुत से ग्रामीग बिना भूमि के रह जायंगे। परन्तु ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से पता चलेगा कि यह दोनो लाभ काल्यनिक हैं। ऐसा बहुत कम समन है कि प्रकृति के कीप से गाँव का एक ही भाग नष्ट हो थ्रौर शेप भाग बच जाय। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो इससे किसान को बहुत कम लाम होगा, वर्षों से छोटे-छोटे दुकड़ों में खेती करने से कियानों को जो हानि होती है वह इस सभावित लाम की अपेदा कहीं अधिक है। श्रीर जहा तक मृमि-विहीन मजदूरों का प्रश्न है यह भूमि के बॅटवारे या उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करने से इल नहीं किया जा सकता है। वास्तव में मुख्य समस्या यह है कि किसान को इस योग्य बनाया जाय कि वह रहन-सहन का एक उचित स्तर बनाये रख सके। कुल परिवार के पास समुक्त रूप से जितनी भमि हे यदि उसका उसके सदस्यों में विभाजन कर दिया जाय श्रीर प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ भूमि दे दी जाय तो इसमे रहन सहन का उचित स्तर नहीं रखा जा सकता। इन छोटे-छोटे भागों से किसान अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकने में ग्रसमर्थ होता है। यदि भूमि का इस प्रकार बॅटवारा न किया जाता तो शायद वह असमर्थ न होता। भूमि-विहीन मजदूरों की समस्या को इल करने के लिए सरकार को श्रन्य उपायो से काम लेना पडेगा।

यह खेद की वात है कि भूमि के बॅटवारे और उसके छोटे-छोटे भागों मे विभक्त हो जाने की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में कोई निक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि सम्बन्धी रायल कमीशन (Royal Commission on Agriculture) की रिपोर्ट से ववल यह सूचना मिलती है कि विभिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के पास ग्रीसतन कितनी जमीन है। इस सूचना से समस्या की पूर्ण जानकारी नहा होती। किसानों के पास ग्रोसत भूमि उत्तर प्रदेश, मद्राम, त्रिवॉक्टरकोर्च न ग्रीर हिमाचल प्रदेश में ग्रन्य दोत्रों की अपेन्ना कम है। उत्तर प्रदेश में भूमि प्राप्त कुल व्यक्तियों में से ८१२ प्रतिशत के पास ५ एकड से कम भूमि है श्रीर यह कुल काइत नी जाने वाली भूमि का उद्याद्वारात है।

मद्रास में ८२२ प्रतिशत के पास १० रुपया या इससे कम वापिक लगान की भूम है जो कारत की जाने वाली भूमि का ४१२ प्रतिशत है। त्रिवांकुर-कोचीन में ६४१ प्रतिशत के पास ५ एकड से कम भूमि है जो कुल कारत की जाने वालो भूमि ४४ प्रतिशत है। श्रान्य राज्यों में भी यह समस्या गम्भीर है। श्रीर इससे किसानों को श्राय में हानि सहनी पढ़ी है।

रीति (Methods)— भूमि की चक्क्चन्टी करने की टां मुख्य रीतियाँ हैं:
(१) स्वय किसानां में परम्परा स्वेच्छापूर्वक सहयाग की भावना के द्वारा छौर
(१) सरकार द्वारा चक्रबन्टी श्रानिवाय कर देने से। जहाँ तक स्वेच्छापूर्वक सहयोग करने का प्रश्न हैं इसम काफी देर लगती है श्रीर चक्रबन्टी का कार्य श्र श्रता में नहीं हो पाटा। कहीं क्हीं जमादार या महाजन चक्रबन्टी के कार्य में क्कावट पैदा कर देने हैं। इसके साथ ही किसानां का यह सममाना बहुत कठिन है कि चक्रबन्दी से उनका लाम होगा। किसान न तो श्रपनी भूमि छोड़ने के लिए तेयार होता है श्रार न इस काम में छाटा-मोटा व्यय करने को राजी होता है। परन्तु यदि भूमि की चक्रबन्टी श्रनिवार्य कर दो जाय तो किसान इसका विराध करता है। वह सममता है कि भूमि की चक्रबन्टी से उसके हितों को चोट पहुँचेगी। यदि चक्रबन्टी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी कमजोर श्रीर श्रक्तुशल हुए हुए तो श्रनेक काठनाइयाँ पेटा हो जाने की सभावना रहती है। परन्तु स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग करके भूमि को चक्रबन्टी कराने का परिस्ताम निगशाजनक ही रहा है इसलिए इस योजना को श्रनियार्य कर देने में हो श्रविक लाम हो सकने की समावना है।

इस दिशा में भूमि की चकवन्दी प्रथम प्रयास है। वास्तव में प्रयत्न इस बात का करना है कि भूमि का ब्रार बटवारा न हो अन्यया चकवन्दी से कुछ लाम समय नहीं। यदि भूमि छोटे हुन्छ। में ब्टती गई तो चकवन्दी का उद्देश्य ही विफल हो जायगा। भूमि का चकवन्दी के प्रश्न का इस बात में गहरा सम्बन्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रिधिक से श्रिधिक कितनी एक्ड भूमि रख सकता है। "उत्तर प्रदेश में कम से कम सीमा ६ है एकड़ भूमि प्रति न्यक्ति रक्खी गई है, मध्य भारत में यह सीमा स्विचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के लिये ५ एकड़ और जहाँ सिचाई की सुविधा नहीं प्राप्त है वहाँ १५ एकड़ निश्चित की गई है। आसाम में पचायत एक्ट के अनुसार पचायत को अधिकार है कि यदि उन लोगों म स जिनके लिये यह निर्माण किया जा रहा है है इस बात पर राजी हो जाय ता प्रत्येक किसान के लिये कम से कम भूमि की सीमा १२ बीधा निश्चित कर सकते हैं। बम्बई, पजाब और पेप्स में चक्वन्दी एक्ट ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे जितना भो उपयुक्त समक्ते प्रति किसान भूमि की सीमा निश्चित कर दे। बम्बई की सरकार ने इसलिये भूमि की विभिन्न न्यूनतम सीमाये १० गुन्ठे से लगा कर ६ एकड़ तक अपने विभिन्न जिलों में नियत कर दी हैं। इन सब राज्यों में ऐसे बटवारो पर रोक लगा दी गई है जिनके परिणाम स्वरूप बॅट कर न्यूनतम सीमा में कम हो जायगी"। यदि ये प्रतिबन्ध न लगाये जाय तो चक्वन्दी के लाम मिविष्य में होने वाले वेंटवारे के कारण न मिल सकते।

कान्न-नम्बई, मध्य प्रदेश, पजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, जम्मू श्रोर काश-मीर में चकबन्दी के सम्बन्ब में विशेष कानून पास किये गये हैं। देहली ने पजाब एकट को अपना लिया है भ्रोर उद्योग ने १६५१ के एग्रीकल्चर एकट मे कुछ चकबन्दी सम्बन्धी नियम जोइ दिये हैं। हैदराबाद, सीराष्ट्र, त्रिलासपुर श्रीर राज-स्थान मे इस सम्बन्ध में कानून विचाराधीन है। ब्रारम्भ में कानून ब्रनुमित प्रदान करने वाले (Permissive) ये श्रीर विशेष पदाविकारियों के द्वारा श्रदला बदली में सहायता तथा छुट ग्रादि का प्रवन्ध करते थे। बड़ौदा एक्ट इसी ढग का था। सहकारो समितियाँ किसानों के लिये स्वेच्छा से चकवन्दी कराने में विशेष सहायक हो सकती थीं। जो कानून पास किये गये हैं उन्हें हम दो वगी में रख सकते हैं (१) वे कानून जो किसानों को यदि उस गाँव में निश्चित प्रतिशत किसान राजी हों तो चकबन्दी के लिये वाध्य कर सकते थे स्त्रौर (२) वे कानून जो राज्यो को यह स्रधिकार प्रदान करते थे कि वे अपनी स्रोर से चकबन्दी की योजनास्रो को न्तागु करे। मध्य प्रदेश, जभ्मू श्रीर काश्मीर के कानून पहिले वर्ग में श्रीर पजाब पेप्स, देहली श्रीर बम्बई के कानून दूसरे वर्ग में श्राते हैं"। मध्य प्रदेश के बानून के अनुसार यदि किसी महाल, पट्टी अथवा गाँव के कम से कम आधे निवासी जिनके हिस्से में गाँव की दे मूमि ब्राती है मिलकर चकबन्दी की योजना के लागू कराने की प्रार्थना करें क्यार यदि चमजन्दी योजना पक्की हो चुर्सा है तो सब सुमि पर श्रिधिकार रखने वालों को चकबन्दी योजना स्वीकार करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। जम्मू श्रीर काश्मीर के एक्ट के श्रनुसार यदि दे किसान जिनके

श्रविरार में किसी गाँव के हैं नेत हैं त्रोर वे चरवन्टो की योजना स्वीकार करते हैं तो वह योजना पक्षी मान ली जायगी श्रार लागू वर वी जायगी। इन कानूनों क बारग जा योडे सं ब्यक्ति योजना को श्रस्वीकार रुरते हैं उन्हें भी योजना के श्रम्तर्गत लाकर उनकी सफलता निश्चित कर दी गई है।

वत्तर प्रवेश के कानून—' दंश में लागू किये हुये कानूनों की प्रवृत्ति के अनुसार ही उत्तर प्रदेश ने भी इस सम्बन्ध में एन नया कानून पास किया है जिसके अनुसार राज्य अपनी ओर ने अनिवार्य रूप में चकवन्दी लागू कर सकता है। यह नया नानून १९३६ के कानून के स्थान पर (जो चन्न्यन्दी अनिवार्य का ने लागू नरने की नभी अनुसति देना था जब कि किसी गाँव के एक विशेष प्रतिशत लाग चन्न्यन्दा के लिये अपनी स्वीकृति देते थे) पूर्ण का ने लागू कर दिया गया है १ १६५३ क उत्तर प्रदेश सृमि चकवन्दी एक्ट में अनिवार्य क्ष्म के उन लागू करने की अनुमति प्राप्त है। यह कानून उ० प्रवर्श मुमिनवार्य क्ष्म विश्वक्त चक्कवन्दी नमेटी नी लिफारिशों के आधार पर बनाया गया है आर पलाव के नित्रक की दी तरह मा है।

रस कानून के प्रावार भून सिद्धान निम्न हैं—(१) प्रत्येक पट्टेदार की निहा तद नम्मव हा सके वहीं पर भूमि दो जानगी जिस जेन में उसकी प्रधिकाश मूमि है, (२) प्रत्येक गाँव नी भूमि का वर्गीकरण निम्न ज्ञेनों में किया जायगा, जेन, (ग) वायल पटा नरने वाले जेन, (य) जायल गो छोड़ कर प्रन्य एक फसली दार को उस जेन भूमि दो जायगी जहा पर पहिले से ही उनकी भूमि है, (४) प्रत्येक पट्टेना को उतने ही चन दिये जायगी जितने कि गाँव में जेन एक हो पट्टेन (४) प्रत्येक पट्टेना को उतने ही चन दिये जायगी जितने कि गाँव में जेन एक हो छोड़ मर) बनाये गये हैं जम तक कि किसी गाँव में केनल पक हो जीन ने हो छोड़ मर) बनाये गये हैं जम तक कि किसी गाँव में केनल पिनार के पट्टेना को यथासम्भन एन दूसरे के पहोस में ही चन दिये जायगे, तो उन्हें चम देने ने इन नाता ना निशेष स्थान रम्बा जायगा, (७) यह कोई चम प्राप्त के पट्टेना जायगा आर न में ही पिन है तो यथासम्भन वह न तो उन्हों जम निया जायगा आर न में ही जायगा?। इन सिद्धान्तों से न्यूनतम जम्मान का प्रधिनतम लाम होने की तम्मानना है।

इस कानून के अन्तगत नरबन्दी के कार्य को करने ना एक विभव कम विना एम है। उसकी कार्यान्त्रत करने के पहिले प्रत्येक किसान क प्लार्टी का लिया उनके स्त्रेपलों के सम्म तथा प्रत्येक का लगान व मालगुजारी आदि के

सहित तैयार किया जायगा। एक ऐसी वालिका तैयार की जायगी जिसमे प्रत्येक पट्टेटार के कुल खेतों का चेत्रफल जो उनके पास विभिन्न प्रकार के ग्रासामी श्रिषकारों के श्रन्तर्गत है तथा उसे जितनी मालगुजारी श्रथवा उसका लगान देना पड़ता है, तैयार किया जायगा। जब यह हिसाब पक्के तौर पर तैयार हो जायगा तब किसानो को चक देन की शर्ते तैयार की जायगी जिसमे यह दिखाया जायगा कि कौन कौन से प्लाट प्रत्येक पटटेदार को उसके पुराने खेतों के बढ़ते में दिये जायॅगे तथा यदि नये सिरे से दिये हुये प्लाट उसके पुराने प्लाटा ती तुलना मे कम मूल्य के हैं तो क्या मुख्रावजा दिया जायना ख्रौर उसके कुच्चों, पेड़ो त्रीर इमारतों के बदले मे क्या मुत्रावजा दिया जायगा इत्यादि । इस प्रस्ताव पर किसानो को उजरदारी करने का श्रिधिकार होगा। परन्तु उजरदारी का जवान दिये जाने पर प्रस्ताव पक्का हो जायगा श्रीर चक्रबन्धी योजना लाग हो जायगी। इसके पश्चात् चक को दिये जाने का हुक्म जारी हो जायगा जिसमे यह दिखाया जायगा कि योजना के अनुसार कौन-कौन से नये खेत किसके दिस्से मे आगए हैं श्रीर उन्हें उन पर अधिकार दे दिया जायगा। इस बात का व्यान रक्ला जायगा कि किसानों को चक उसी चेत्र में दिया जाय जहाँ पर उनके श्रिषकाँश खेत हैं। भूमि पर श्रिधिकार के सम्बन्ध में निर्णय ऐसे निर्णायक द्वारा किया जायगा जिसे सरकार उन न्याय-कार्य सम्बन्धी श्राप्तसरों में से नियक्त करेगी जिन्हें कम से कम ७ वर्ष तक का श्रनुमव है। किसानों से भी राय ली जायगी त्रोर उन्हें श्रापत्ति करने का श्रिधिकार होगा परन्तु जब योजना पक्की हो जायगी तब सब को उसे मान लेना पढेगा । यह चकबन्दी योजना न्यायालयो के कार्य-चेत्र के बाहर इसलिए मानी गई है कि इस सम्बन्ध में मुकदमेवाजी न हो। एक्ट के अनुसार चकबन्दी का खर्चा ४ र० प्रति एकड़ नियत कर दिया गया है जो योजना मे सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों में वॅट जायगा ताकि सरकार को यह खर्च न उठाना पढें। जिनके खेतों की चकवन्दी की जायगी उन्हें पैमाइश तथा अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम वाले कार्य करने में सहयोग देना होगा श्रीर जो यह न कर सकेंगे तो उन्हें २ ६० ८ आना प्रति एकड़ के हिसाब से अम के बदले में खर्च के प्रति देना पढेगा। यह कानून मुजफ्फरनगर श्रोर मुल्तानपुर जिलो में लागू कर दिया गया है। थोड़ा अनुमव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पहिले यह २० जिलों में श्रौर लागू किया जायगा । आशा की जाती है उत्तर प्रदेश मे इस कानून के अन्तर्गत चकवन्दी का कार्य बहुत सुगम होगा।

किताइयाँ—चकवन्दी-कार्य बहुत कितनाइयों से भरा हुया है। इन्छ किताइयाँ तो मनोवैज्ञानिक हे श्रीर कुछ प्रयोगात्मक। (१) बहुत की जगहो पर भूमि श्राधिकारों का कोई लेखा प्राप्त नहीं है। पजाव में देश के वॅटवारे के पश्चात् सारे लगान सम्बन्धी लेखों के खो जाने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

- (२) चकबन्दी का कार्य छोद्यौगिक ढग का है। इसके करने वालों को वेमाइश, बन्दोबस्त, भूमि के वर्गीकरण, भूमि के मूल्याकन तथा पटटेदारी सम्बद्धी जान छावश्यक है। ऐसे कार्यकर्ताछों की कमी के कार्य चकबन्दी के कार्य में बाधा पड़ी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ प्रदेशों में ऐसे छफसरों को इस कार्य के लिये विशेष ट्रेनिंग देने जा छायोजन किया गया है।
- (३) इस कार्य में किसानों की विद्वादिता श्रौर पीढियों से श्रिधकार में स्थित भूमि के प्रति मोह के कारण भी बावा पढ़ी है। जमींदारों श्रौर श्रन्य श्रसामाजिक वर्गों द्वारा बाधा उपस्थित करने से भी काम में ककावट पहुँची है। शान्तिपूर्वक जनता में इस कार्य के प्रति प्रचार तथा जानकारी की वृद्धि द्वारा तथा जहाँ श्रावश्यक हो वहाँ श्रनिवाय कप से लागू करने से ही इन बाधाओं पर विजय पाई जा सकती है।

(४) चकनन्दी में रुपया खर्च होता है श्रीर रुपये के प्रवध के कारण मी इस कार्य में वाबा पहुँचती है। प्रादेशिक सरकारों के समज्ञ श्रमेक प्रकार की विकास योजनायें हैं हसिलये वे सदा इस कार्य के लिये पर्याप्त घन देने के लिये तैय्यार नहीं रह सकती। इस सम्बन्ध में खर्च पूरा करने के लिये तीन उपायों के काम में लाने की श्रनुमित दी गई हैं। (क) दिल्ली, मध्य प्रदेश श्रीर पजान में खर्च का एक श्रश किसानों से चकवन्दी फीस के नाम पर वस्तुल कर लिया जाता है। इस प्रकार कुछ श्रश तक व्यय सरकार द्वारा श्रीर कुछ श्रश तक किसान द्वारा पूरा कर लिया जाता है, (ख) बम्बई में सारा व्यय सरकार द्वारा सहन किया जाता है जहाँ पर किसानों के साथ रियायत के रूप में बिना फीस लिये काम किया जाता है, श्रीर (ग) उत्तर प्रदेश में जैसा कि कपर वताया जा चुका है पूरा खर्चा किसान से ४ ६० प्रति एकड के हिसान से वस्तूल कर लिया जाता है।

सफलता की मात्रा—चकबन्टी की सफलता विभिन्न प्रदेशों में कम ही रही है। केवल पनाव, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेप्सू छोर दिल्ली छादि ने कुछ सफलता इस सम्बन्ध में पात की है। पनाव में चकबन्दी का काम १६२० से श्रारम्म हुआ और उत्तर प्रदेश में १६२४ से। उत्तर प्रदेश में १६५३ के चकबन्दी एक्ट के पास होन पर इस काम की गति वढ गई छोर छाने चलकर एक्ट में भी उपयुक्त सुधार कर दिया गया। मार्च १६५५ तक पंजाब में ४० लाख एकड़, मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, पेप्सू में १० लाख एकड़ से अधिक भूमि

की चकवन्दी की गई। वम्बई और दिल्ली में १०६० और २१० गाँवों में क्रमशः यह योजना पूर्णतया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में २१ जिलो में यह योजना लागू है। अब भी विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्य को बढाने का अवसर है।

ययपि चमबन्दी का कार्य जरा घीमी गति से हुआ है और बहुत कम उन्नित इस ग्रोर हो पाई है फिर भी इससे लाटों की सख्या कम हो गई है और उनका ग्रोसत चेनफल बढ गया है। यदि प्लाटों की सख्या में कमी ग्रोर खेतों के उनका ग्रोसत चेनफल बढ गया है। यदि प्लाटों की सख्या में कमी ग्रोर खेतों के चेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से देखा जाय तो इम कह समते हैं कि सबसे ग्राधक उन्नित मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विलासपुर, रायपुर ग्रोर दुर्ग जिलों में प्लाटों उन्नित मध्य प्रदेश ने की है जहाँ विलासपुर, रायपुर ग्रोर दुर्ग जिलों में प्लाटों की सख्या प्रदेश कम हो गई है ग्रीर उनका श्रीसत चेत्रफल ४००% बढ गया है। की सख्या प्रदेश के स्वसं कम उन्नित की है ग्रीर वहाँ प्लाटों की सख्या में २०% इस ग्रोर मद्रास ने सबसे कम उन्नित की है ग्रीर वहाँ प्लाटों की सख्या में २०%

से मी कम कमी हुई है।
खेतो की चकवन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत
खेतो की चकवन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक किसान को श्रार्थिक जोत
(economic holding) प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि यि किसी किसान के ग्रियकार मे
गाँव के विभिन्न भागों में छिटके हुये हैं तो चकवन्दी से किसान के ग्रियकार मे
गाँव के विभिन्न भागों में छिटके हुये हैं तो चकवन्दी से किसान को ग्रार्थिक जोत देने
भूमि का चेत्रफल नहीं वढ सकता। इस लये प्रत्येक किसान को ग्रार्थिक जोत देने
के लिये बहुत वहें प्रयत्न की ग्रावश्यकता है।

#### श्रध्याय ५

# भृमि-क्षरण

प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रनुसार भूमिसरज्ञण से श्रमिप्राय केवल ज्ञरण को रोक पाना ही नहीं है परन्तु श्रपने न्यापक श्रर्थ में भूमि सरज्ञण के श्रन्तगंत वह सभी वार्ते शामिल हैं जिनका लक्ष्म भूमि की उत्पादन शक्ति को ऊँचे स्तर पर बनाये रखना है, जैसे भूमि की कमियों को दूर करने के उपाय, रासायनिक तथा देशी खाद का उपयोग, फसलों के बोने के कम का उचित सचालन, सिंचाई तथा नाली की न्यवस्या हत्यादि। इस कम में भूमि-सरज्ञण का प्राय: भूमि के उपयोग के दगों में सुवार करने से निकट सम्बन्ध है। भूमि सरक्षण के सम्बन्ध में मारत की प्रमुख्य समस्या भूमि-ज्ञरण को रोकना है। भूमि ज्ञरण होते रहने से भूमि का वहुत बढ़ा मांग कृषि के योग्य नहीं रहता।

कार्य्य — भूमि चरण के अनेक कारण हैं परन्तु उनमें से मुख्य निम्न-लिखित हैं .—-

- (१) वनों का काटना और वनस्रित का नष्ट हो जाना। जगल और वनस्पित हवा और पानी के वहाव को रोकते हैं जिससे भूमि का तल इनकी हानि-कारक शक्ति ने वच जाता है और उसका चरण नहीं हो पाता। यदि वन काट डाले जाय और वनस्पित नष्ट कर दी जाय तो भूमि पूर्ववत नहीं रहेगी, उसकी उत्पादन शक्ति घट जायगी। प्राय हैं घन या इमारतों के उपयोग के लिए वनों को काट लिया जाता है। यासाम, बिहार, उद्गीसा और मध्यप्रदेश के कुछ मागों में कवायली जनता (Tribal people) एक निश्चित स्थान पर खेती नहीं करती है। वह प्राय एक स्थान से दूखरे स्थान पर अपने कृषि चेत्र बदलती रहती है जिसके लिए उसे पेड काटते रहना पडता है और इससे वनों का विनाश हो जाता है। इघर जमीटारी उन्मूलन होते ही यनेक जमीटारों ने इमारती लकडी से स्पया पैदा करने के लिए अपने चेत्र के पेड काट डाले हैं।
- (२) पशुयों श्रौर विशेषकर मेड वकरियों का घास-पत्ती इत्यादि चर जाना । इससे भूमि के कण परस्पर गुथे नहीं (रहे जाते श्रौर उसका च्ररण होने लगता है। वनस्पति का इस प्रकार चर लिया जाना भारत के लिए एक गम्भीर समस्या वन गया है। १९५२ में भारतीय कृषि ग्रुनुसन्धान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) के तत्वावधान में उसके फसल श्रौर

भूमि विभाग (Crops and Soils Wing) की प्रथम वैठक में उस समय के खाद्यान मनी ने कहा कि मेड बकरियों को प्रथय देने का अर्थ है भूमि-च्ररण और महाविनाश। परन्तु गाय-भैंस को प्रथय देकर हम भूमि की सेवा कर सकते हैं और स्वय समृद्धिशाली वन सकते हैं। खाद्य मन्नी ने अधिक जोर देकर जरूर कहा है परन्तु यह सच है कि भेड वकरियों से भूमि को बहुत क्षति पहुँचती है। उचित यह होगा कि पशुत्रों को चारा दिया जाय और विना रोक टोक के इधर-उधर, विशेषकर उन चेनों में जो इस कारण पहले ही च्रतिप्रस्त हो चुके हैं, चरने न दिया जाय।

(३) जिस भूमि में उत्पादक तत्वों की पहले ही से कमी है उसका शोध चरण हो जाता है। यद भूमि उपजाऊ है और उसकी अब्छी तरह देखभाल की गई तो खराब भूमि की अपेज़ा इसमें भूमि-ज़रण कम होगा। काश्त की जाने वाली भूमि का भारत में पीढ़ियों से बिना किसी रोक टोक के बराबर उपयोग होता रहा है और उसकी उत्पादन शक्ति की पूर्ति करने के लिए खाद इत्यादि या तो नहीं डाली गई है या अपर्याप्त रही है। इससे देश के बढ़े-बड़े भाग भूमि ज्ञरण के सकट से अस्त हो जुके हैं।

भूमि-चरण ग्रनेक प्रकार का होता है परन्तु भारत में मुख्य प्रकार निम्न-लिखित हैं:---

- (१) तल च्ररण (Sheet Erosion)—पानी के तेज बहाब से या तेज हवा के बहने के कारण जब भूमि की ऊपरी उपजाक सतह बह जाती है तब तल-चरण होता है।
- (२) स्त्रन्त च्तरण् (Gully Erosion)—पानी के तेज बहाव के कारण् भृमि में गहरे नाले वन जाने से अन्तः च्तरण् होता है। प्राय अन्तः च्तरण् होने का कारण् यह होता है कि बहुत समय तक तल-च्तरण् होता रहे और उसे रोकने का काई उपाय न किया जाय। निव्यों के आस-पास की भूमि में अन्तः च्तरण् की अधिक सभावना रहती है क्योंकि बाढ आ जाने से तट की निकटवर्ती-भूमि का तल चरण् होता रहता है और धीरे-धीरे गहरे नाले बन जाते हैं।
- (३) वायु क्षरण (Wind Erosion)—वायु इरण देश के मरु प्रदेश में जैसे राजस्थान थ्रोर पूर्वी पजाब में होता है। तेज वायु बहने से मरु चेत्र की वालू उड़ती रहती है योर निकटवर्ती हिस्सों में बैठती रहती है जैसा राजस्थान के मरु प्रदेश के निकट होता है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति को गहरी हानि पहुँचती है।

भूमि ज्ञरण एक गभीर सकट है। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति कम होती

है, भूमि व्यर्थ हो जाती है ग्रीर जनता निर्धनता के चगुल में फस जाती है। इस देश के बढ़े बढ़े चित्र महस्थल में बदल नाते हैं। उन चित्रों में जहाँ नदी-घाटी योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे दामोदर घाटी, वहाँ पर भूमि च्ररण से निमित बाँघों को भय उत्पत्न हो जाता है। इस कारण इन बाँवा को देखमाल ग्रीर बचाव के लिए श्राधक व्यय करना पड़ता है। यह टुमांग्य की बात हैं कि हमें श्रपने देश में भूमि-इरण के प्रकार श्रीर प्रसार के सम्प्रक्ष में मही-मही गचना प्राप्त नहीं है इस स्चना के प्राप्त हो जाने पर भूमि-च्ररण को राकने के लिए प्रभावशाली उपायों को लागू किया जा सकता है। पिछले उद्ध वर्षों में भूमि सरझण के लिए कुछ काम किया गया है, वम्नई में छाटे-छोटे बांध बाँधने श्रोर टेक लगाने (Terracing) से श्रोर पजाब में बंगल लगाकर तथा पहाडी नाली में बाँग इत्यादि बाँघकर श्रोर उत्तर प्रदेश में नाली तथा उद्धों से पारपुर्वत भूमि पर कृषि करके भूम सरहण किया जा रहा है। बाँव बाधने श्रार टेक इत्यादि का निर्माण करने में श्रीर कटी फटी भूमि को स्मतल बनाने के लिए टैक्टरो तथा श्रन्य बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु ग्रमी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य करना शेप है।

राजस्थान के महस्थल का ममश उत्तर की छ।र विस्तार एक विशेष चिन्ता का विषय हो गया है छोर भारत सरकार ने उसकी रोकधाम के लिये निम उपाय किये हैं.—

- (१) "दस वर्ष के भीतर ही भीतर ४०० मील लम्बी और प्रमील भीतर को श्रोर चौड़ी जङ्गल की एक पट्टी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर लगा देना इसमें मेड, वकरी, गाय, देल, ठॅट, श्राट पर श्रो के चरने की श्राझ न होगी।"
- (२) मरुस्यल की भूमि में बालू के वर्णों को इतियाली द्वारा स्थिर करने में वैज्ञानिक उपायों की खोल करना।
- (३) ऐसे नख लरतानों की व्यवस्था करना जहाँ से पेड़-पौधे फीजी नाकों, रेल के स्टेशनों, पुलिस के यानों, तहसीलों श्रीर स्नूलों के हर्द-ागर्ट लें जाकर लगाये जा सके।
- (४) ऐसी चुनी हुई सबनों झौर रेल की लाइनो पर मनुष्यों की झाबादी में झावास का प्रवत्य करना जो वायु के बहाव को काटती हुई वटती हैं।
- (५) पौधों क लगाने वाली एकान्सवा को बील छोर पौधों के बाटने का प्रवन्य करना।
- (६) उपयुक्त चरागाहा की स्थापना का प्रवत्य करना को कि समय-समय पर श्रीर बारी-वारी से चरने के लिये सोले जायें।

इन उपायों से त्राशा की जाती है कि महत्थल की बाह दक जायगी त्रौर भूमि-च्रारण बन्द हो जायगा तथा भूमि की उर्वरता स्थिर रह जायगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—प्रथम पचवर्षीय योजना में भूमि चरण को रोकने श्रीर भूमि चरज्ञण की श्रावश्यकता पर विशेष रूप से महत्व दिया गया था। भारत चरकार ने विशेषज्ञों की एक तदर्थ-समिति (ad hoc Committee) बनाई थी जिसका कार्य पजान, पिटयाला सब उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र श्रीर कच्छ के निकटवर्त्ती उपजाक चेत्र में मरु प्रसार की समस्या का श्रम्ययन करना था। समिति ने एक विस्तृत कार्यक्रम की सिकारिश की है जिसमें यह सुक्ताव दिया गया है कि (१) राजस्थान की पिश्चमी सीमा पर वनस्पति का प्रमील चौड़ा किटबन्य लगाया जाय, (२) राजस्थान में वन चेत्र को बढाने के लिए नये वन लगाये जॉय, (३) मूमि के उपयोग के तरीकों में सुधार किया जाय। विशेष रूप से कुषक रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिय चृज्ञारोपण करें श्रीर रेगिस्तान को समस्या का श्रम्ययन करने के लिए श्रनुसवान केन्द्र (Research Station) स्थापित किया जाय। भारत सरकार ने इस समिति की सिकारिशें मान ली हैं।

प्रथम योजना में भारत सरकार द्वारा २ करोड़ रूपये भूमि सरक्षण पर व्यय करने का आयोजन था। "भूमि सरज्ञ्ण कार्य जैसे बाँघ बाँघने, खाई खोदने, नाले पाटने (gully Plugging), भूमि पर मेड़ बाँघने, पानी के बहाव पर रोक लगाने, नदी की घारा को तथा खड़ों के बनने को नियन्त्रित करने आदि उपायों के अन्तर्गत जो प्रदेशीय सरकारो द्वारा किये जा रहे हैं लगमग ७००,००० एकड़ भूमि आ गई है जिसका दो तिहाई भाग केवल बम्बई प्रदेश के भाग में आया है।

"प्रथम योजना में ही मूमि सरज्ञण कार्य नियमित रूप से आरम्भ हो गया या। लग-मग २५० कृषि और वन विमाग के अधिकारियों को भूमि सरज्ञण उपायों की विशेष शिज्ञा दी जा चुकी है। १६५२ में जोषपुर में रेगिस्तान में वृज्ञा-रोषण सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई यी और प्रथम योजना के पिछले वर्षों में ही पाँच अनुसन्धान तथा प्रशिज्ञण केन्द्रों की भी स्थापना हो गई यी। ग्यारह अग्रगामी योजना केन्द्र बम्बई, आन्त्र, उद्दीसा, पिछ्छमी बगाल, मद्रास, पजाब, सौराष्ट्र द्रावनकोर, कोचीन, अजमेर, कच्छ और मीनापुर में स्थापत किये गये हैं। द्रावनकोर, कोचीन तथा मद्रास की ये आदर्श योजनायें विकास योजना केन्द्र में परिणित कर दी गई हैं।

इस समस्या को समुचित रूप से मुलकाने के विचार से मारत सरकार ने छ: भूमि सरज्ञ्या सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रशिज्ञ्या केन्द्र देहरादून, कोटा, वसद

(उत्तरी गुजरात) वेलारी, कटाकामरह श्रौर जोघपुर में खोले हैं। इन केन्ट्रों ने बहुत लामपद कार्य किया है।

हितीय पचवपीय योजना—में तो श्रीर श्रिधक विस्तृत श्रायोजन किया गया है। भूमि सरच्य के लिये २० करोड़ रूपये की व्ययस्था की गई है। लगमग ३० लाख एकड भूमि जहाँ पर भूमि चरण बहुत बुरी तरह से हुश्रा है इस संरच्य योजना के श्रन्तर्गत लाने का हरादा है। इस ३० लाख एकड भूमि में से २० लाख एकड तो दल्श्रा ऊँची नीची खेती के योग भूमि, ३५०,००० एकड महस्थल तथा कटने वाले करार की भूमि, ३३०,००० एकड नदी की घाटी वाली भूमि, १७०,००० एकड पहाडी सूमि श्रीर १५०,००० एकड खडु वाला मूमि होगी।

मारत में सब से वड़ी कठिनाई यह है कि मूमि-चरण की समस्या की गम्भीरता का जनता को कुछ ज्ञान ही नहीं है। दुछ राज्य सरकारों ने मूमि सरज्ञा के लिए बहुत सीमित उपायों को लागू मिया है। जनता इस भारी सकट के प्रति विल्कुल उदासीन है और इस बात की छोर उसका न्यान नहीं जाता कि भूमि चरण को रोकने से कितना लाभ हो एकता है। इस सम्बंध में न्यवहारिक दृष्टि से विचार करके प्रथम श्रीर द्वितीय पचवर्षीय योजनाश्रों ने निश्चित प्रगति को है परन्तु इस कार्य के लिए जितना घन निर्वारित किया ग्या है वह श्रावश्यकता से बहुत कम है। इस कार्य में इससे कहीं श्रधिक रुपया व्यय होगा। राज्य सरकारों को श्रपनी वित्तीय कठिनाइयों के पश्चात भी इस कार्य के लिये श्राविक घन देना होगा । दीर्घकाल में इस ब्यय से श्रवश्य लाम होगा क्योंकि मृमि की उत्पादन शक्ति बढेगी श्रीर इमारी श्रनाज, कपास, ।तलहन इत्यादि की उपज में वृदि होगी जिससे उत्पादन तथा उनमोग के बीच की वर्तमान खाई को पाटने में महायता मिलेगी। केन्द्रीय भूमि सरज्ञण बोर्ड से यह आशा की जाती है कि भूमि सरज्ञण के उपायों के प्रयोग की प्रगति बढ़ाने में समर्थ होगा। यह बोर्ड "विभिन्न प्रकार की भीमयों के जो खेती, जड़ल लगाने तथा चरागाह बनाने के काम आ रही है सरस्त्य सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य का आरम्भ, सामजस्य तथा व्यवस्था करेगा श्रीर पादे। शक राप्यों को तथा नदी घाटी योजनाश्रों को भूमि सरहाण सम्बन्धी योजनाश्चों के बनाने में तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाने में सहायता प्रदान करेगा"। यह बोर्ड भूमि सरक्षण सम्बन्धी जानकारो की वार्तों के श्राटान-प्रदान का केन्द्र होगा तथा तत्सम्बन्धो शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा ताकि मृमि सरल्या सम्बन्ध में आवश्यक कुशल व्यक्तियों का पेमाइश श्राटि कार्यों के लिये पूर्ति की जा सके।

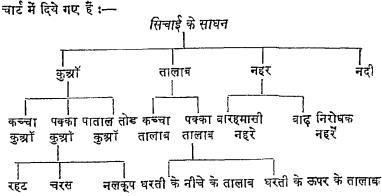
## श्रध्याय १० सिंचाई

वर्षा ही भारत में कृषि की भाग्य-विधात्री है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न मात्र में वर्षा होती है जिसमें काफी अन्तर रहता है। उदाहरणार्थ एक श्रोर तो चेरापूजी जैसे स्थान पर ४६० इन्च तक वर्षा होती है जिससे बाढ द्वारा फसलों इत्यादि की हानि होती है दूसरी श्रोर राजपूताना केवल ५ इन्च वर्षा होती हैं जहाँ पानी की कमी से फसलों नष्ट हो जाती हैं। चावल तथा गन्ने की खेती के लिये आवश्यक होता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में निरन्तर नियमित रूप से मिलता रहे। इसलिए प्राकृतिक सुविधा प्राप्त न होने के कारण भूमि के सिचाई के लिए श्रीर निहयों के पानी को उचित उपयोग में लाने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना पड़ता है।

मारत की निद्यों से प्राप्त १३,५६० लाख एकड़ फुट पानी में से श्रीसतन केवल ५ पित्र पित्र का उपयोग १६५१ के पिहले तक किया जाता था श्रीर शेष बाढ द्वारा प्रायः हानि पहुँचाता हुआ समुद्र में गिरता था। उसके पश्चात पानी का उपयोग बढ़ा है। आशा की जाती है कि १६५६ में लगभग १,३६० लाख एकड़ फीट जल अथवा कुल का १०% कार्य में आ जायगा। पानी की इस मारी चित्र को रोककर इसे सिचाई के कार्य में लाना चाहिए जिससे बाढ का प्रवाह घटे, भूमि की उत्पादन शक्त बढ़े और साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

सिचाई का स्रोत

मारत में सिचाई के मुख्य साधन कुन्नाँ, तालाव त्रौर नहरे हैं। कहीं-कहीं निद्यों से पानी खींचकर भी सिंचाई की जाती है। सिंचाई के यह सभी स्रोत निम्न



एक एकड जमीन को एक फुट गहराई तक भरने के लिए जितने पानी की
 श्रावश्यकता होती है वह एक एकड फुट पानी कहलाता है।

कुएँ—भारत मे िवाई के लिए कुएँ का प्राचीन काल से प्रयोग होता श्राया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण साधन हैं। कुएँ या तो कब्बे होते हैं या पक्ते। हमारे देश में कब्बे हुआ की सल्या बहुत श्राविक है क्यों कि इनका निर्माण करने में न तो श्राविक व्यय होता है श्रीर न विशेष कला के ज्ञान की ही श्रावश्य-कता है। इनसे पानी निकलने के लिये ढेक्ली का उपयोग होता है। पक्के कुएँ दो प्रकार के होते हैं, (१) ऐसे कुएँ जिनका पानी खीचने के लिए रहट या चरस का उपयोग किया जाता है श्रीर (२) नलकूप (Tube-wells) जिनका पानी खींचने के लिये विजली के या डिजिल पम्पों का उपयोग किया जाता है।

कुएँ श्रधिकतर मैदानी माग में श्रोर विशेषकर ऐसे मागों में वनाये जाते हैं जहीं पानी का तल बहुत गहरा नहीं होता है श्रीर जहाँ मूमि मुलायम होती है। पजाब, उत्तर प्रदेश, निहार, पश्चिम बगाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग श्रीर कपास की कृषि के योग्य काली भूमि में श्रधिकतर सिचाई के लिए कुश्चों का ही उपयोग किया जाता है। यह कुएँ निजी भी होते हैं श्रीर सरकारी भी। उत्तर प्रदेश में लगभग दो हलार सरकारी कुएँ है।

कुओं के पानी से िंचाई करना लाभदायक है क्यों कि कुएँ के पानी में सोडा, नाइट्रेंट, क्लोराईड श्रीर सल्फेट नाफी मात्रा में रहते हैं। इनसे मूभि की उत्पादन शांक म वृद्धि होती है। इसके साप ही कुश्रों से सिचाई करने का एक श्रीर लाम भी है। नहरों से सिचाई करने मे पानी एक स्थान पर एकत्र हो जाता है परन्छ कुश्रों के उपयोग से ऐसा होना सम्भव नहीं है। यदि कुपकों को तकाबी ऋण देकर और श्रिमक पक्के कुश्रों का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय तो श्रीधक उपयुक्त होगा। उन्हें कुएँ खोटने की सुविधा दी जानी चाहिए श्रीर विजली से चलने वाले पम्प लगाने के लिए गाँव तक विजली पहुँचानी ही। विजली के पम्प सस्ते होते हैं श्रीर श्रन्य साधनों की श्रपेशा श्रन्छे भी होते कारी सिमितियों के द्वाग किया जाना चाहिए।

तालाव—तालावं। के द्वारा छिंचाई करने का श्रिषक प्रचलन टिच्य में श्रीर विशेषकर महान तथा मैस्र म है। वेमे बङ्गाल, बिहार, उद्दीसा, उत्तर प्रदेश श्रीर मन्य प्रदेश में भी छिचाइ के लिये तालावं। का प्रयोग किया जाता है। कहीं यह तालाव काकी वड़े हैं जिन्हें क्तील कहना श्रीषक उपयुक्त होगा श्रीर कहीं छोटे-छोटे हैं जैसे प्राय: गाँवों में होते हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक हैं श्रीर कुछ का निर्माण किया गया है लो कच्चे-पनके दोनों प्रकार के हैं। एक्के तालाव भृिम के

नीचे और भूमि के ऊपर भी बनाए जाते हैं। यह तालाब वर्षा के पानी से भरते हैं और अन्य ऋतुओं में इनसे सिचाई के लिये पानी लिया जाता है।

कुश्रों के पानी की तरह तालाव का पानी भी उत्पादन शक्ति बढानेवाला है क्योंकि इसमें वर्षा का पानी श्रीर गन्दगी दोनों मिले होते हैं। यद्यपि तालाव सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन हैं परन्तु इनकी स्थित सन्तोषजनक नहीं है। इनकी गहराई मिट्टी भग्ने से घीरे-घीरे पटती जाती है। इसलिये श्रावश्यकता इस बात की है कि पुराने तालावों को गहरा किया जाय श्रीर श्रिष्ठिक नये तालाव खोदे जाय। चूंकि कृषक इस दिशा में श्रिष्ठिक कार्य नहीं कर सकता है इसलिये तालाव खोदने के लिये सरकार को श्रिष्ठिक सिंक्य होने की श्रावश्यकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में १६४८ से कार्य कर रही। यह कार्य पंचायतो, स्थानीय सरवाशों श्रीर सहकारी समितियों को सौपना चाहिये। पक्के तालावों का निर्माण करने में श्रिष्ठिक व्यय करना पड़ता है। परन्तु इनका श्रिष्ठिक सख्या में निर्माण करना श्रावश्यक है क्योंकि इनमें पानी काफी समय तक सुरिज्ञत रखा जा सकता है। कच्चे तालावों को तरह इनका पानी शीध सूल नहीं जाता। यदि इन तालावों से खेतो तक पछा नाली लगा दो जाय तो इससे पानी की पूर्ति में सुघार होगा श्रीर पानी व्यर्थ नहीं जायगा। जब यह तालाव खाली हो जाय तो सिंचाई की श्रावश्यकता न रहने पर नहरों के पानी से इन्हें मरा जा सकता है।

नहरें—नहर का पानी भारत में खिचाई का सबसे वड़ा साधन है। यजाब उत्तर प्रदेश, बगाल, विहार, मद्रास, मैस्र, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश श्रौर उड़ीसा में नहरों का जाल बिछा हुआ है। नहरें दो प्रकार की होती हैं (१) बारहमासी श्रौर (२) बार्टिनरोधक। बाँधों में पानी का सम्रह करके बारहमासी नहरों का निर्माण किया जाता है। इन नहरों से वर्ष भर पानी प्राप्त हो सकता है। वृस्ती श्रोर बाट निरोधक नहरों में निर्दियों का पानी एक स्तर से श्रिषक बट जाने के पश्चात् एकत्रित हो जाता है। बारहमासी नहरें श्रिषक श्रच्छी होती हैं क्योंकि मूखा पड़ने पर जब बाट-निरोधक नहरों का पानी स्त जाता है तो इन नहरों से सिचाई हत्यादि के लिये पानी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक निर्माण ज्यय का सम्बन्ध है बाट निरेधक नहरों के निर्माण में बारहमासी नहरों के निर्माण-व्यय की श्रपेक्षा बहुत कम व्यय होता है। बारहमासी नहरों का निर्माण करने में टेकनिकल कुशलता मशीनों श्रौर विभिन्न सामग्रियों की श्रावश्यकता होती है।

नहरों से सिचाई करने से कुछ हानियाँ भी होती हैं। इससे पानी एक स्थान पर एकत्रित रहता है श्रीर खेत में पहुँचने से पूर्व काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है। परन्तु यह नड़ी समस्यायें नहीं है। नहरों को पद्या कर देने से यह समाप्त हो जायेंगी।

सिचाई-कर—सिचाउँ । र की दर त्रीर उसकी वस्त् कि दग प्रत्येक फसल त्रीर प्रत्येक राज्य में भिन रहते हैं। नहर त्रार नलकृषों की सिचाउँ दर भी भिनन-भिन्न है। एक एकड़ भूमि में गन्ने की खेती में सिचाउँ करने की दर उत्तर प्रदेश में ५ क्षया श्रीर हैदरागद म ३३ क्षया है। क्षास के लिए पजान में ३१ क्ष्या श्रीर महास में १० क्ष्या है, चावल की प्रति एकड़ सिचाउँ दर ४ क्ष्ये से १८ क्ष्ये तक है श्रोर गेहूँ की दाई क्षये से १० क्षये तम है। इससे शात होता है कि व्यवसायी-कसल के लिए सिचाई कर की दर खादान की त्र्यंक्ता श्रीधक है। दर का यह त्रन्तर इस गत पर त्रावाग्ति है कि प्रति एकड़ व्यवसायी-कसल में खादान्न के प्रति एकड़ की श्रपेक्ता त्रिक्ष लाभ होता है। त्राजकल पानी की जो श्रनावश्यक चृति होती है उस बन्द कम्मा चाहिए श्रीर यदि श्रावश्यक हो तो व्यय किये गए पानी की मात्रा के ग्राघार पर सिचाई कर लगाना चाहिए।

ांपछले कुछ वपाँ में कुछ राज्यों ने नई विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अपनी सिचाई कर की दरों को बढ़ा दिया है जिससे कुपक पर भार ओर बढ़ गया है। सिचाई के कार्य को भी अन्य साधारण कार्यों की तरह चलाना चाहिए। सिचाई कर की दर केवल इतनी होनी चाहिए जिससे इस कार्य को चलाने में होने वाला न्यय निकल आए और योजना को कार्यान्वित करने में जो पूँजी लगाई गई है उसकी वसली होती रहे। सिचाई कर राज्यों क लिये आय का साधन न होना चाहिए, जेसा कि उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है, क्योंक इससे कुपक पर अमुचित भार पड़ता है और उत्पादन न्यय बहुत अधक बढ़ जाता है।

सगठन—१६१६ से िचाई व्यवस्था राज्य सरकारों के हाथ में आ गई है। प्रत्येक राज्य में एक िचाई विभाग है जो राज्य म िचाई के कार्यों के विकास के लिये उत्तरदायी होता है। अन्तर-राज्य िचाई व्यवस्था ना सचालन करने के लिए दो केन्द्रीय सस्थाएँ हैं। इनमें से एक केन्द्रीय जलवियुत, िचाई और जलयान सम्बन्धी आयोग है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने १६४५ में की थी। इसका उद्देश्य जल शक्ति पर नियत्रण रखने, उसका उपयोग और सरक्षण करने के लिए योजनाएँ बनाना और सभी नाया को सुसम्बद्ध करके उन्हें कार्यान्वित करना है। इसके साथ ही इसको यह भी कार्य सोपा गया है कि आवश्यकता पढ़ने पर सम्यन्धित राज्य सरकारों स परामर्श करके कोई नई योजना तेयार करें। दूसरी सस्था केन्द्रीय विचाई-परिषद् है। इसकी स्थापना १६३१ में हुई थी।

परिषद् को यह कार्य सीवा गया कि भारत के प्रमुखन्यान रेन्द्रों में सिंचाई तथा इसके सम्बन्धित यन्य विषया पर किये जाने यादी खाल कार्यों का समन्वय वरे। इन समन्यार्थों से सम्पर्क रसने वाली चिदेगी सस्यार्थों ने भी परिषद् श्रपना सम्भन्य बनाए रखती है। इनर पालाया पेन्द्रीय भीमिक जल सम (Central Ground Water Organisation) नाम की सत्या भी है जा १९४६-४७ मे

१९५४ ने भारत सघ रे फृषि तथा गाप मञ्जालय के पन्तर्गत नलकृत जल-स्रोती का ग्राप्यम कर रही है। योजनाम्ना के प्रशासक के निर्देशन ने एक नलक्ष्य विकास सब भी कार्य कर रहा है। यह सरवा नहीं सटा वर्षा कम होती है पहा उम दात का पता लगायेगी कि भूमि के जन्तस्तल में कितना पानी प्राप्त कर लेने की मध्यावना है।

शिचां की समस्या को दो दम की योजनायी द्वारा सुलकाने का प्रयक्ष किया गया है। प्रथम बहुनुस्ती नदी घाटी योजनाश्री ह्वाग तथा छोटे-छोटे विचार के साधना द्वारा । बहुमुर्जा नदी घाटी योजना जुन्य लामों के त्रातिरिक्त बहुत बले क्षेत्र को सिचार के लिए पानी देती है। उन्हें छोटे सिचाई के सावन यम्पि देराने में इतने श्राकर्षक नहीं है किर भी कृपकों को िधवाई के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक पानी देने हैं। यह प्राशा की जाती है कि जब छन नदी घाटी योजनामें पूर्ण हो जायँगी नो उनमें लगभग १६५ लाख एक्ट भूमि की खिचाउँ हो सरेगी।

कठिनाइयाँ—मारत में सिचाई की व्यवस्था का विकास करने में भूनेक

किताइयां का मामना फरना पड़ता है जिनका प्रवर्ण निम्नलिपित है :--(१) वित्त की समस्या—सिचाई योजनात्रों को लागू करने में सबमें पढ़ी कठिनाई नित्त की है। इनके लिए बहुत ग्रधिक रुपयों की ग्रामश्यकता पड़ती है। प्रथम पचवर्षीय शीतना में करी शिचाई योजनाश्ची के लिए प्रथू करीड श्रीर छोटी सिचार्ड योजनाश्री के लिए ४७ करोड़ रुपये का श्रायोजन किया गया था। इमके साथ ही कुश्री तथा तालावीं का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ग्रोर सहकारी समितियों को कुछ य्रातिग्ति धन की प्रावश्यकता होगी। यह धन प्राप्त करने के लिए पचवर्षीय योजना में भ्रमण लेने, राजस्य की श्राय से सहायता लेने, विशेष श्रनुद्रानों, जलपूर्ति यह प्रीर लगान में वृद्धि करने श्रोर विचाई तथा विकास कर लाग् करने की व्यवस्था की गई थी। परन्तु यह कर उसके भार की एमें समय में बढ़ा देते हैं जर्ज कि कर-मार स्वय काफी श्रधिक है। इसमें सन्देह नहीं कि इतना बन प्राप्त करने में जनता पर ग्रनुचित भार पड़ेगा जिससे श्रयन्तोप वेलन भी सम्मावना है।

(२) प्राविधिक (टेक्निकल) ज्ञान का स्त्रभाव—धन के ग्रभाव के

साय ही योजनाश्रो को कार्यान्वित करने के लिए श्रपेचित प्राविधिक कर्मचारियों का भी श्रभाव है। प्रायः सभी वहीं योजनाश्रों में विदेशी प्रविधिजों को नियुक्त किया गया है श्रीर इससे श्रनावश्यक रूप से श्रिधिक व्यय करना पढ़ रहा है। इसलिये यह श्रावश्यकता है कि देश में भारतीयों के लिए श्रनुसन्धान श्रीर प्राश्चित्र के स्वर होले जाय।

- (३) श्रावण्यक सामान की कमी—भारत में इन योजनाश्रों के लिए श्रावण्यक इस्पात श्रीर सिमंट की मी कमी है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि इन जा उत्पादन श्रीर बढाया जाय श्रीर जो कुछ सामान उपलब्ध हो सके उसको सबसे पहले सिंचाई के लिए निर्माण-कार्य में लगाया जाय।
- (४) पानी का अनुचित उपयोग श्रीर श्रुति—मारतीय कृपक पानी का उचित उपयोग नहीं करता। विभिन्न चेत्रों में विभिन्न फर्कलों के लिए श्रावश्यक पानी की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। परन्तु भारतीय कृषक पानी का बिना सोचे- समके उपयोग करता है। पानी की श्रायकता खेती के लिये उतनी ही हानिकारक है जितनी उसनी न्यूनता। एक समय में श्राधक पानी देने की श्रापेन्ता वार-वार पानी देना श्राधक लाभदायक खिद्र हुश्रा है। पानी की इस न्तृति को कुछ सीमा तक नहरों को पक्का बनाने श्रीर काम में लाये गये पानी की मात्रा के श्राषार पर सिंचाई कर लागू करने से रोका जा सकता है।
- (४) पानी का गलत वॅटवारा—भारतीय क्रथक बहुत समय तक अपने खेत वो सींचने के लए वर्षा के आगमन की प्रतीद्धा करता है। जब वर्षा से देर हो जाती है तब वह सिचाई के लिये नहरों और नल क्पों से पानी लेने के लिए दीइ-वृप करता है। परन्तु सब क्रपकों को एक ही समय में नहरों और नल क्पों से आवश्यक पानी मिलना सम्भव नहीं है क्यों कि भारत मे नहरों और नल क्पों का पानी क्रपक की श्रीसत आवश्यकता मे कम है। इस प्रकार की दीइ वृप से सिचाई की व्यवस्था पर बहुत भार पड़ता है जिसको कम करने के लिए किसानों को अपनी आवश्यकताये पहले से दर्ज करानी चाहिये और रजिस्ट्री के कमानुसार उन्हें पानी मिलना चाहिए।

यह कठिनाइयाँ ग्रसाध्य नहीं हैं। उचित प्रयत्नों से इनको इल किया जा समता है। यदि कृपक सहयोग दे श्रोर पानी की उचित रूप से ज्यवहार में लाने की श्रावश्यकता को समर्के श्रीर बहुमुखी नदी याटी योजनाश्रों के साथ-साथ फली- भूत होनेवाजी योजनाश्रों पर जोर दिया जाय तो देश की सिंचाई ज्यवस्था संभल जायगी।

# बहुउद्देशीय योजनाएँ श्रीर वाढ् नियंत्रण कार्यक्रम

िषचाई श्रोर शक्ति उत्पादन योजनायेँ प्रथम श्रीर द्वितीय पंचवपीय योजनात्रों के मुख्य श्रग हैं। इनमें विद्युत शक्ति के उत्पादन श्रीर सिंचाई की मुविधा में वृद्धि होगी जिनका श्रमाव उत्रोगों श्रोर कृषि की उन्नित में बावक रहा है। इन योजनाश्रों में बाद पर नियवण, मलेग्या के पेलने में रुजावट, तथा देश को अन्य श्रनेकों लाभ होंगे। प्रथम श्रार दितीय योजनाश्रों के श्रन्तर्गत तीन प्रकार की सिचाई योजनाश्रों की व्यवस्था है। (१) बहु उद्देशीय योजनायें, (२) बड़ी तथा साधारण सिचाई की योजनायें तथा (३) छोटी सिचाई की योजनायें।

इन नोजनात्रों की तीन विशेषतार्थे हैं। (क) उनमें ने श्रनेकों तो पचव-पींच योजना के श्रारम्भ होने के पूर्व ही से चल रही थी। "द्वितीय महासमर का त्रान्त होते ही बहुत सी परियोजनार्थे जिनमें कई बहुउद्देशीय योजनार्थे भी थीं श्रारम्भ कर दी गई थी। इनमें से छुछ तो ऐसी थीं जिनका कार्य तो बिना उनके सम्बन्ध में श्रावश्यक प्राद्यांशिक श्रीर श्राधिक छान बीन के ही श्रारम्भ कर दिया गया था। १६५१ में जन सिचाई श्रीर शक्ति उत्पादन की योजनाश्रों का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके पूर्ण होने में छुल व्यय ७६५ करोड़ रुपये होने का श्रनु-मान था" इसमें से १५३ करोड़ रुपया तो उन श्रपृर्ण योजनाश्रों पर व्यय हो चुका था क्योंकि ऐसा विचारा जाता था कि जितना शींघ हो सके उतना शींघ ये योज-नार्ये पूर्ण की जोय जिससे कि जो कुछ घन इन पर व्यय किया जा चुका है वह सार्थक हो श्रीर उसका यथा-सम्भव लाभ बढ़ी हुई मात्रा में श्रन्न की उत्पत्ति के रूप में शींघ मिल जाय।

(ख) प्रथम योजना के छान्तर्गत जिन परियोजनायों को छारम्म किया गया या उन पर पुन: विचार किया गया छोर िचाई तथा शक्ति उत्पादन की योजना पर व्यय ५५८ करोड़ रुपये ने बढ़ाकर ६०७ करोड़ रुपया कर दिया गया। जो छन्य मह्त्यशाली परिवर्तन किये गये वे निम्न हैं। (१) १६५१ में योजना निर्माण के समय सदा से कमी के चेच की छायर्यकताछो की छार विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इन चेत्रों की जनता के निर्धन होने तथा उनके छार्यिक कार्यों म निरन्तर प्राकृतिक बाधा की उपस्थित के कारण निरन्तर सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती थी। इस्र लिये १६५३-५४ में इन चेत्रों के स्थायी विकास के लिये कार्यक्रम निश्चित किए गए श्रोर इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के इल व्यय में ४० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। इन योजनाश्रों का ध्येय था कि वे जनता के पास धन की वृद्धि करेगी श्रोर वे मविष्य के विकास कार्यक्रम में उसमें सहायता दे सकेगे। (२) १६५४५५ में छोटी छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाश्रों इसमें सिम्मिलित कर लीं गई जिन पर २० करोट र० इस विचार से व्यय करने का निश्चय किया गया कि उनसे छोटे-छोटे करनों श्रोर गाँवों में जनता को कार्य पाने का प्रवस्तर प्राप्त हो ककेगा, श्रोर (३) बाढ पर नियत्रस रखने का १६५४-५५ में कम बनाग गया जिसपर १६३ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया।

(ग) इन योजना श्रों का कार्य इतना श्राधिक था छोर धन तथा श्रन्य श्रावश्वक माधनों का इतना श्रमाय था कि स्वकों कार्याविन्त करना सम्भव नहीं हो सका। इसलिए सम्पूर्ण कार्यक्रम को छाशों में विमाजित करना ध्यावश्यक हो गया। प्रथम योजना म यह निर्णय विया गया कि सम्बल, कोसी, कृष्णा, कोयना छोर रिह्न्ड योजना हो सम्पूर्ण योजना के श्रान्तिम काल में श्रारम्भ किया जाव।

इस प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना मे यह निर्णय किया गया है कि कुछ बड़े काम जैसे त्रान्त्र की वमसाधरा योजना, विहार की कन्साई योजना श्रीर वम्बई की उमाई नर्मटा, माही, खहरावासला, गिरना श्रोर बनस योजनायें, मध्य-प्रदेश की तावा योजना श्रीर पिन्छमी बगाल की कगसाबाती योजना सम्पूर्ण योजना काल के श्रन्तिम भाग में कार्यान्तित की जायेंगी।

योजना के श्रन्य कार्यक्रमों की ग्रिपेक्षा विचाई श्रौर शक्ति उत्पादन योज नाग्रों पर वजट में निश्चित व्यय कहीं श्रिधिक व्यय किया गया। यह एक सतो-पमद बात है, क्योंकि इसमें भारतवर्ष की श्राधिक स्थिति सुधरेगी श्रोर उद्योगों तथा कृषि में तीव्र गित से विकास सम्भव होगा। प्रथम योजना के तीन वर्ष व्य-तीत होने के पूर्व ही भारतवर्ष यदि ग्रज के लिये श्रात्म निर्भर हो सका है तो किसी सीमा तक इसका कारण सिंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायों हैं। प्रथम योजना के प्रथम चार वर्षों में ६७७ ररोड की व्यवस्था में से ४४५ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था। बहुउद्देशीय योजनाश्रों पर १८७ र४ करोड़ रुपया जो कि इल व्यय का ७६% हैं, शक्ति उत्पादन योजनाश्रों पर, ११२ ७५ करोड़ रुपया जो कि ६६% है, सिचाई योजनाश्रों पर (जिनमें कमी के सेन्नों का कार्यक्रम सम्मिलत हैं) १३३ ३७ करोड़ रुपया जो कि ६४% है, व्यय किया, जायगा। १९५४-५५ के श्रन्त तक कृषि के श्रन्तर्गत लाया गया श्रतिरक्त सेन्न ४० लाख एकड़ था ज कि लक्ष्य ५७ लाख एकड़ था। लम्बे शक्ति उत्पादन के सेन्न में

६६२००० किलोवाट शक्ति उत्पादन किया गया, जब कि ध्येय ८८१००० किलोवाट उत्पादित करने का था।

बहुत सी बड़ी योजनात्रों पर बहुत उन्नति की जा चुकी है, त्रीर यह श्राशा की जाती है, कि वे द्वितोय योजना काल में पूर्ण कर दी जायंगी। इन योजनात्रों में भाकड़ा, हीराकुएड, कोयना, चम्मल ग्रीर रिहेन्ड योजनाये श्राती हैं। इन सबते १७ लाख किलोगाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी।

## वहुउद्देशीय योजनाएँ

कुछ बहुउद्देशीय योजनाश्चों जैमे माकड़ा नागल, हिराकी, दामोटर घाटी श्रीर हीगकुरह ग्रादि ने पचनप्रिय योजना के प्रथम चार वर्षों में सतोषप्रद उन्निति की श्रीर योजना में निश्चित २८२०२ करोड़ वपए में से उन पर १६७२६ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है, इसके फलस्वरूप ६ लाख एकड़ ग्रतिरिक्त भूमि की सिचाई सम्भव हो सकी है, श्रीर २०२००० किलोबाट विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकी है।

भाकड़ा नागल याजना—गह योजना पजाब, पेप्स श्रोर राजस्थान को सुविधाये पहुँचायेगो। इसके ग्रन्तर्गत (१) सतलज नदी के श्रारपार भाकड़ा बॉय वनेगा, (२) नागल बॉध नदा में बहाव की श्रोर प्रभील तक बनेगा, (३) नागल नहर बनेगी, (४) दो नागल पावर हासउ बनेंगे श्रोर (५) भाकड़ा नहर व्यवस्था बनेगी। यह योजना १६४६ में श्रारम्भ की गई थी, श्रोर श्रव तक नागल बॉध नहर-नियामक (canal regulator), नागल जल द्वार तथा पजाब में भाकड़ा नहर की खुराई पूर्ण हो चुको है। हमारे प्रधान मत्री ने प्रजुलाई १६५४ को इस नहर व्यवस्था का उद्वादन किया था। भाकड़ा बॉध को चूने द्वारा ठोस करने के कार्य का उद्वादन १७ नवम्बर १६५५ में किया गया।

दामोदर घाटी योजना—योजना काल के प्रयम चार वन्ना में इस योजना पर प्रदःश्व करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था, श्रीर १.१ लाख एक्ट श्रति-रिक्त भूम की सिंचाई श्रीर १ प्र लाख किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादना होने लगा। दामोदरघाटी योजना एक ऐसे महत्वशाली श्रीयोगिक चेत्र को मुविधाये पहुँचाती है, "जहाँ से देश में प्राप्त कुल कोयले की मात्रा का ८०% अभक्त का ७०%, कोमाइट का ७०%, फायरक्के का प्र०%, लोहे का ६-%, ताँवे का १०० प्रतिशत श्रीर कामोनाइट का १००% प्राप्त होता है"। जन यह योजना पूर्ण हो जायगी तब यह देश के श्रीयोगिक तथा कुपि सम्बन्धी विकास में काफी मात्रा में सहयोग प्रदान करेगी।

हीरा कुएड योजना— नह योजना उद्दीसा राज्य को सुनिधा प्रदान करेगी, श्रीर इस योजना की प्रारम्भिक श्रवस्था में (१) महानदी की घाटी में एक बाँध ककड़ पत्थर श्रीर मिट्टी का, (२) दोनों किनारा पर मिट्टी के जल धरण (dykes) (३) दोनों किनारा पर नहर, (४) वाँध पर एक पावर हाउस १८३००० किलोबाट विद्युत उत्पन्न करने के लिये श्रीर (५) ट्रान्सिम्भन लाइन्स बनाई जायेगी। रोतों में नालिया को खुदवा देने से श्रिधकाधिक क्रेनों की सिंचाई की सुविधा हो सकेगी श्रीर इस प्रकार १६५८-५६ तक कुल ४५४ लाख एकड च्रेन सीचा जा सफेगा।

### विभिन्न प्रदेशों में योजनात्रों की प्रगति

राज्यों में खिचाड योजनायों नी प्रगांत बहुउद्देशीन योजनायों भी तुलना में कम हुई। १६५१ से ५५ तक चार वर्षों में वास्तिन काय १८८० ८ करोड़ क्यया हुया जब कि सम्पूण योजना के पुनरीच्चण के पश्चात् २०७६८ करोड़ क्यये के ज्यय करने की ब्यवस्था को गई थी। ख्रांतिरिक चेत्र जिसपर सिचाई की गई वह केवल ३५ लाख एकड था, जन कि योजना में ६४ लाख एकड़ ख्रांतिरिक भूमि पर सिचाई करने का त्येय था। इन योजनाख्रों की प्रगति 'क' राज्यों क कुछ भागों में तथा 'ख' राज्यों के खिकाश भागों में बीमी ही रही है। इसका कारण सगठन का ख्रभान, प्रशासनों ख्रोर काम करने वालों का ख्रभाव ख्रीर याजना में वार-वार परिवर्तन मरना रहा है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—द्वितीय पचवर्षीय योजना में सम्मिलित नई सिचाई योजनाश्रों का कुल ज्यय लगमग इद्भ० करोड रुपये हैं, इसमें से १७२ करोड रुपया द्वितीय योजना काल में ज्यय किया जायगा, रोप धन तीसरे तथा श्रम्य मिविष्य में होने वाली पचवर्षीय योजनाश्रों के काल में ज्यय होगा। वहें श्रीर साधारण श्रेणी के सिचाई सावनों पर द्वितीय पचवर्षीय योजना में कुल इद्भ करोड रुपये के ज्यय की ज्यवस्या की गई है। इसके श्रितिरिक्त ३५ करोड रुपये की श्रीर ज्यवस्या की गई है जिससे कि सिन्यु नदी नी योजनाश्रों तथा अन्य ऐसी योजनाश्रों से जिनके सम्बन्ध में श्रमी निर्णय नहीं हो पाया है, प्राप्त जल वा प्रयोग करने वे लिये अन्य नई योजनायें पूर्ण करवाई जा सकें। द्वितीय योजना काल में जो २८० लाख एउड सूमि सीचा जा सकेगी उसमें से लगमग १२० लाख एकड सूमि को छोटी सिचाई की योजनाश्रों से यह सिवा प्राप्त होगी।

श्रिषकांश अतिरिक्त विचाई (लगभग ६० लाख एकड) जो बडे त्रोर साधारण श्रेणो की योजनात्रों से होगी वह उन कार्यकर्मों की पूर्ति हो जाने के कारण होगी जो कि प्रथम योजना से ही चन्न रहे हैं | द्वितीय योजना में सम्मिलित नई योजनात्रों से लगभग ३० लाख एकड़ भूमि सींची जायगी। द्वितीय योजना के अन्तर्गत बड़ी ह्योर साधारण श्रेणी की योजनात्रों के पूर्ण हो जाने पर उनकी सीचने की शक्ति लगमग १६० लाख एकड़ होगी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत विद्युत-शक्ति उत्पादन के विकास-कायक्रम के तीन च्येय हैं: (क) वर्त्तमान पावर हाउसों पर बढे हुये सामान्य मार को वहन करना, (स्व) पूर्ति के तेत्रों के युक्ति सगत विकास के लिये आवश्यक विद्युत शिक्त का उत्पादन करना और (ग) द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवीन आरम्म किए हुए उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

# वाढ़ नियंत्रण का कार्यक्रम

सरकार ने समन्वित श्राधार पर बाढ की समस्या के निराकरण का अत्यन्त महत्वशाली निर्णय किया है। प्रथम योजना के श्रारम्भ में बाढ नियत्रण की कोई भी निरिचत न्यवस्या नहीं की गई थी। उस समय बाढ नियत्रण योजनाएँ नदी पाटियों के विकास सम्बन्धा बहुउद्देशीय योजनाओं के श्रन्वर्गत रखी गई थी। १६५४ की श्रपूर्व बाढों ने प्राण सम्पति तथा यातायात को विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी माग में, बहुत हानि पहुँचाई। इस कारण बाढ की समस्या पर स्विचाई श्रीर विद्युत शक्त उत्पादन कार्यकमें से श्रवण स्वतत्र रूप से विचार करना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया। प्रदेशों द्वारा वात्मालिक बाढ नियत्रण के लिये उपायों के प्रभावशाली सिद्ध न होन के कारण १६५४ में यह निर्णय किया गया कि एक न्यापक बाढ नियत्रण कार्यक्रम इस समस्या को उचित दग से सुख्याने के लिये बनाया जाय। १६५ करोड़ रुपये की योजना में इसीलिये १६.५ करोड़ रुप की व्यवस्था श्रोर कर दी गयी। बाढ नियत्रण के काय पर दितीय स्ववर्षीय योजना में श्रिधिक स्थान दिया गया है।

२ ३१ करोड रुपये का ऋणु प्रदेशों को १९५४-५५ में दिया गया श्रीर केन्द्रीय सरकार के १९५१-५६ के वजट में १० करोड रुग्ये को न्यवस्या इसके लिये कर दी गई है। जिससे कि ऋणु को सहायता प्रदान की जा सके। मार्च १९५५ कि विभिन्न प्रदेशों में जो सफलता मिली है, उसका विवरण निम्नलिखित है। पंजाब—निम्न कार्य पूरे किये गये (१) ४३ मील लम्बा डेरा बाबा नानक से आकर मन्ज तक रावीं नदी के किनारे आधार बाँघ का बनवाना, (२) देहली अदेश में जमुना नदी के किनारे जो पतली दारार पाई गई थी उनको बन्द कर-वाना और टकोला बाँघ बनवाना, (३) कर्नाल जिले में वाबैल से धानसीली तक जमुना नदी के दाहिने किनारे बाढ रोकने के लिये बाँघ बनवाना, और (४) जमुना नदी से ताजेवाला शीर्ष कम से नीचे की और बाँघ बनवाना, !

यह तो सर्व विटित है, कि वाद न तो सदा के लिये रोकी जा सकती है, श्रीर न रोक देना उचित ही है। इन बाढ़ों से बारीक मिट्टी वह कर श्राती है, जिससे पानी इब जाने वाले चेत्रों की उपज वह जाती है। उन वर्षों में जब कि बाढ ग्रसमान्य हो जाती है, उनसे बहुत हानि पहुँचती है ग्रीर जनता की कष्ट पहुँचता है। बाढ का प्राय ग्राना ग्रोर उसके द्वारा हानि को कम करने के लिये वाढों के घनत्व पर नियत्रण रखना ख्रावश्यक है। इसके लिये कमबद्ध कार्य-कम बनाने की आवश्यकता है। जिन उपायों से प्राय काम किया जाता है, वे निम्न हैं। (१) किनारे पर बॉब बॉधना (२) सम्रह जलाशय, विशेषकर सहायक धारात्रों पर (३) अवरोधन गढा बनवाना जहाँ पर बाढ का पानी एकत्रित करके थोडे समय के लिये रोका जा सके, (४) नदी की घारा को मोड़ देना जिससे कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँच जाय, (५) नदी का ढाल बढाना उसमें त्र्यारपार द्वार खुदवा कर, (६) निदयों तक ले जाने वाली धाराश्चों को जिनमें मिट्टी मर गई है, खुदवाना श्रीर उसकी मिट्टी निकलवाना, (७) स्थानीय रज्ञा के उपाय जैसे पक्की दीवार ग्रीर कॅचे टीले ग्रादि बनवाना ताकि भूमि कटने न पावें, श्रीर (८) वन लगाना श्रीर स्थान-स्थान पर बहाव की तीवता रोकने के लिये बाँघ बाँधना ।

सिंचाई श्रौर शिक्त मत्रालय द्वारा कुछ दिन पूर्व ही बाढ रोकने के कार्यक्रम की कररेखा बनाई गई है। इसके तोन भाग हैं। (क) तात्कालिक—इसके
श्रान्तर्गत ग्रन्वेपण योजना बनाना श्रोर समय का श्रानुमान करना होगा। दीवार
बनाना श्रीर वॉघ श्रादि भी विशेष स्थानो पर बनगये जा सकते हैं, (य) श्रव्यकालीन—इसके श्रान्तर्गत वॉघों श्रौर नालो श्रादि का सुधार किया जायगा।
इस प्रकार की रज्ञा के उपायों का प्रयोग उन चेत्रों में विशेष रूप से किया
जायगा जहाँ बाढ श्रिषक श्राती हैं, (ग) दीर्घ कालीन—इसके श्रान्तर्गत निदयों
तथा उनकी सहायक घाराश्रों के जल सचय का कार्य सिंचाई श्रौर विद्युत शिक्त
उत्पादन योजनाश्रों के कार्य के साथ किया जायगा।

द्वितीय योजना मे ६० करोड़ रुग्ये की व्यवस्था तत्कालीन और

श्रल्यकालीन योजनात्रों के लिये की गई है। इसमें ५ परोड़ रुपया परीक्ष तथा तत्सम्मन्धी स्चना सामग्री एकत्रित करने के लिये नियत किया गया है। वनों का लगाना श्रीर भूमि सरच्या के उपायों का कार्य में लाना, बाढ़ नियतण के महत्वशाली उपाय है, इनको बाढ़ नियत्रण के कार्यकम में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

वेन्द्रीय बाद निरोधक मंडल ने जून १६५५ को प्रापनी पाँचवीं सभा में १६ बाद नियत्रण योजनायों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें बाँघ वाँघना, नगरों की रत्ता के उपायों ग्रीर गाँवों की स्थिति के स्तर को ऊँचा करने के उपाय ग्रारि समितित है। इनमें से प्रत्येक योजना पर १० लाग रुपये से प्रधिक व्यय होगा, ग्रीर ७ ५ करोड़ रुपये का ग्रानुदान प्रादेशिक सरकारों को बाद रोकने के कार्य कमों को कार्यान्वत करने के लिये दिया गया है। बोर्ट ने यह मी सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रदेश के बाद रोकने के कार्यों को प्रदेशीन बाद निरोधक विभाग के नियत्रण में कर देना चाहिये। इससे कार्य में समन्वन ग्रार उसकी गति में तीवता होगी।

आलोचना-नाढ नियमण की यह योजना जनता के प्राण, सम्पत्ति ग्रीर फराल की हानि को रोन ने मे श्रभी तफ रफल नहीं हो पाई है। इसका कारण सरकारी कार्यक्रम के दोष हैं। सुख्य दोष निम्न हैं। (१) श्रमी तक जो प्रयत्न सरकार द्वारा किये गये हैं, वह सर्वथा अपर्याप्त है। योजनाएँ बनाने तथा प्रशा-सन कार्य करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं हो पाया है। जो व्यय नियत किया गया है, वह बहुत ही कम है। द्वितीय पाजना में भी केवल ६० करोड़ रूपये के व्यय की व्यवस्था की गई है, जब कि कम से कम इसका दुगना घन उपयुक्त होता। (२) जल विज्ञान सम्बन्धी जान के ग्रामाव के कारण योजनायें दोषपूर्ण हो वन पाती हैं। प्राय प्रयत्न विफल हो जाते हैं, ह्योर परिसाम प्रयत्न की तुलना में कुछ भी नहीं होता (३) वाढ़ों को रोकने के लिये श्रभी तक तटवेंघों पर श्रिधिक निर्भर रहे हैं। बाढ द्वारा लाई हुई मिट्टी तटवन्घों के किनारे जमा हो जाती है इससे तटबन्घों को ऊँचा करने का श्रथवा मिट्टी खुदवाने की समस्या सदैव बनी रहती है। श्रीर यदि बाट बहुत तीत्र हुई तो तटबन्धों के बह नाने का भी डर रहता है। श्रधिक श्रव्छा उपाय तो भूमि के संरक्षण का है, इससे बाढ की तीव्रता कम ही जायगी। इससे एक थ्रौर भी लाभ यह हागा कि वाढ पीडित स्थानों उपजाक भूम के वह जाने भी समस्या भी सुलमा जायगी।

कठिनाइयाँ—विचाई अरे विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाओं को कार्या-न्वित करमें में निम्नलिखित अनेक कठिनाइों का सामना करना पड़ा है।

- (१) दोषपूर्ण योजना श्रोर श्रकुशल प्रवन्न के कारण बहुत सा घन श्रीर 'प्रसाघन निष्फल हा गये। राव समिति में दामोदर घाटी कारपोरेशन के कार्य की परीचा की श्रोर इस परिणाम पर पहुँची कि केवल कोनार योजना के कुप्रवन्न के कारण १ ६४ करोड़ रुपये की हानि हुई। सिचाई श्रोर विद्युत शक्ति उत्पादन योजनाये जैसे बढ़े कार्य में घन का पोड़ा बहुत नष्ट होना तो श्रवश्यम्माची था क्योंकि कर्मचारीगण श्रनुभवहीन थे, श्रीर ऐसी स्थिति में मूल होना स्वामाविक या परन्तु वास्तविक हानि श्रनुमान से कहीं श्रिषक हुई इसलिये भविष्य में इस बात का ध्यान रखना पढ़ेगा कि जनता का घन न्यर्थ न जाय।
- (२) "स्थिरयत्रों श्रोर प्रसाधनों के क्रय के सम्प्रन्थ में निश्चित नीति के प्रभाव के कारण समय-समय पर विभिन्न प्रकार के यत्रों का क्रय किया गया। सिंचाई, शक्ति श्रौर योजना मत्रालय द्वारा १९५३ में नियुक्त प्लान्ट श्रौर मशीनरी कमेटी ने सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए मुख्य-मुख्य यात्रिक प्रसाधनों को एक ही प्रमाप का होना चाहिए।
- (३) अपेद्धित योग्यता और सनद प्राप्त इंजीनियर छोर विशेपओं के अमाव के कारण भारत की नटी घाटी तथा अन्य योजनाओं को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह समस्या दो प्रकार की है, (क) विशेषओं का अभाव तथा (ख) जो व्यक्ति टामोदर घाटी तथा अन्य योजनाओं का कार्य कर रहे हैं, वे अपने भविष्य के बारे में सशक हैं कि इन योजनाओं का कार्य जब समाप्त हो जायगा तब उनका क्या होगा। एक समय भारत सरकार अखिल भारतीय सिचाई तथा शक्ति विशेषओं का एक विशेष सेवा वर्ग बना रही थी, अथवा इसके स्थान पर ऐसे कर्मचारियों का जो विभिन्न प्रदेशों से आये थे एक सचय (deputation pool) बनाने का विचार कर रही थी।
- (४) िंचाई तथा शक्ति उत्पादन योजनायें मुधार-कर लगाने अयवा िंचाई की दर बढ़ाने को बाध्य करती हैं। मुधार कर एव िंचाई की बढ़ी हुई दर के कारण कुछ प्रदेशों के कृषकों को अधिक मार वहन करना पड़ा है। इसिल्ये यह आवश्यक है, कि इन करों के आरोपित करने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि कृषकों की कर क्षमता कितनी है। यदि राज्य सरकारें सिंचाई की दर, मुधार-कर तथा शक्ति की दर (Power rate) निश्चय करते समय कृषकों को देय-ज्ञुमता को भी ध्यान में रखें तो बड़ा ही अञ्छा हो।

#### श्रध्याय ११

# सामुदायिक विकास योजनाएँ

भारतीय क्रपकों की नि वनता श्रीर श्राधिक दृष्टि से विछ्टे होने का प्रमुख कारण है कि वे नई प्रणालियों श्रीर लीवन के नवीन उपायों के प्रति उदासीन हैं। उनके सम्मुख जो जटिल समस्याएँ हैं उन्हें इल करने के लिए वे सुसंगठित रूप में पयल भी नहीं करते। सामुदायिक विकास योजनार्था के कार्य क्रमों ग्रीर राष्ट्रीय विस्तार सेवाग्रों (National Extension Service) का उद्देश्य यह है कि उनके द्वारा "जनता के मानशिक दृष्टिकीण में पारवतन हो, उनमें जीवन के उच्चतर स्तर तक पहुँचने का महत्त्वाकाची श्रीर साथ ही साथ उस स्तर की प्राप्त करने के लिए इंढ निर्णय श्रीर इच्छाशक्ति उत्पन्न की जाय। ग्रामी में निवास करने वाले ७ करोड़ परिवारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, नवीन जान व जीवन के नवीन उपायां के प्रति उत्साह उत्पन्न करना श्रीर श्रेष्टतर जीवन व्यतीत करने के लिए उनके हृदय में श्रिमलापा व हृढ इच्छा-शक्ति का सचार--यह वास्तव में एक मानवीय समस्या है।" इस उद्देश्य के पूर्ण होने के लिए इस बात की श्रावश्य-कता है कि विकास कार्य-कम ग्रामीण जनता के अपर बलपूर्वक न लादे जायें, वरन् इस वात का प्रयास किया जाय कि उन लोगों में ही श्रात्मावश्वास का उदय हो श्रीर वे नियोजन के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले सकें । सामुदायिक विकास योजनात्रां के श्राधारभूत सिदान्त निम्न हैं :---

- (श्र) "विकास कार्य के लिए पेरक-शक्ति स्वय ग्रामवासियों से श्रामी चाहिए। श्रामों में विपुत्त शक्ति निष्कित रूप में विखरी पड़ी है लिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। श्रवण्व इस बात की श्रावश्यकता है कि वह शक्ति कियात्मक कार्यों के लिए नियोजित की जाय श्रोर प्रत्येक परिवार के सदस्य क केवल श्रपने हित के लिए कार्य करें वरन् सामुदायिक कल्याण के लिए भी समय दें।"
- (व) "सहकारिता के सिद्धान्त को विविध कर्षों में लागू होना चाहिए, जिससे आम्य-जीवन की श्रानेक समत्याएँ इल की जा सर्जे।"

सामुटायिक विकास योजनाश्चों के तीन उद्देश्य हैं. (१) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मछली-पालन श्चादि में वैद्यानिक विधियों को लागू करके श्लीर अन्य पूरक धर्घों व कुटीर-उद्योगों को प्रारम करके वेरोजगारी दूर की जाय श्लीर उत्पादन में वृद्धि की जाय (२) जनता के चह्योग से प्रत्येक ग्राम या कई ग्रामों को मिलाकर कम में कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्या होनी चाहिए जिसमें कृषि करने वाले लगभग सभी परिवारों के प्रतिनिध हो, (३) गाँव की सहकों, तालाबों, पाठ-राालाणों, स्वास्थ्य-नेन्द्रों थ्राटि सार्वजनिक हित के निर्माण-कार्यों के लिए सुसगठित प्रयास होना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त ग्रामोण जनता में प्रगतिशील हिटकोण उत्पन्न करने की भी थ्रावश्यकता है।

यह सामुदायिक विकास योजना २ श्रक्तूबर १६५२ को प्रारंभ की गई थी, जिसके अन्तर्गत ५५ केन्द्रों में सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रचालित की गई । इन योजनात्रों का कार्यचेत्र लगभग ३०,००० ग्रामों तक विस्तृत है जिनकी जनसंख्या लगभग १ करोड़ ६८ लाख है। कालान्तर में ग्रोर भी ग्रधिक सामदा-यिक विकास योजनाएँ चलाई गई श्रोर २ श्रक्त्वर १६५३ को राष्ट्रीय प्रसार सेवा के ग्रन्तर्गत प्रसार-महलों (Extension Blocks) का भी समारम किया गया । इस प्रकार इस समय दो योजनाएँ साथ-साथ चल रही हैं, जिनमें से प्रथम हैं सामदायिक विकास योजनाएँ श्रीर दितीय हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ। 'इन राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के भी नहीं उद्देश्य हैं जो सामुदायिक विकास योजनाओं के हैं। कृषि, पृश्-पालन, शिज्ञा, स्वास्थ्य श्रादि चेत्रों में दोनों के कार्य-क्रमों में पर्याप्त समानता है। उनमें यदि कोई मेद है तो यही कि सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्य-क्रम विस्तृत है श्रीर इसके श्रन्तर्गत स्थानीय कार्यों पर पर्याप्त धन-राशि भी व्यय की जायगी योजना में यह व्यवस्था की गई है कि जिन विकास-मंहलो की प्रगति पर्याप्त रूप से संवोपजनक होगी श्रीर जहीं जनवा का सक्रिय सहयोग श्रप्त होगा. उन्हें सामुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गत सुसगठित के लिए चन लिया जायगा।

संगठन—समुदायिक विकास योजना की न्यवस्था पचायतों और इसी उद्देश्य के लिए निर्माण की गई अन्य उच्च सस्थाओं द्वारा की जाती है। "जनता और उसके अनेक प्रतिनिधियों में नाफी विचार-विमर्श करने के उपरान्त विकास कार्य-क्रम निश्चित निया जाता है। गाँव के स्तर पर नियोजन का कार्य भार पचायत पर ही रहता है। वही विकास कार्यम को कार्यान्वित भी करती है। जिन चेत्रों में या तो पचायतें विल्कुल है ही नहीं या उनका अधिक प्रभाव नहीं है, वहाँ यह प्रयास किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए आमीण विकास समित्यों की स्थापना की जाय, जिन्हें आम-विकास महल, प्राम महल समिति, आम सेवा सब आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इन्हीं सस्याओं के द्वारा नियो- जन के कार्यन्क्रम को कार्यान्वित करने के लिए जनता का सिक्षय सहयोग प्राप्त

होता है। विकास मडल के स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाती है, जिसमें ग्राम समितियां के प्रांतनिधि, विवान-परिपद, विधान-समा व ससद के सदस्य, महकारी समितियों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषक आदि समिन लित होते हैं। यह परामर्शदात्री समिति ग्राम सस्थात्रों द्वारा तैयार की गई योज-नाश्रों पर विचार करती है। फिर इस परामर्शदात्री समिति द्वारा निर्माण की गई महल की विकास योजनाओं को जिला विकास समिति के द्वारा जिले की विकास-योजना के कार्य-मम में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस जिला विकास समिति में प्रमुख गैर सरकारी व्यक्ति श्रीर जिले के श्रनेक टेक्निकल विभागों के श्रध्यक र्साम्मलित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विकास योजना तैयार करने श्रीर उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकारी श्रीर गैंग्सरकारी सगठन साय-साय कार्य करते हैं"। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि "वर्तमान शासन-सम्बन्धी सरकारी ढाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है कि वह जन-कल्याय के टायित्व का भी ।नवांइकर सके, जिसका परिसाम यह है कि सामान्य प्रशासनयत्र से मिन्न एक पृथक जन-कल्याण विभाग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रशासन-यत्र (administrative machinery) की रचना राजस्व-समह (revenue collection) का निरीक्षण श्रीर नियम व न्यास्या की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी, उसने परि-वतित होवर वल्याणकारी शासन का रूप ग्रहण कर लिया है श्रीर सरकार के विकास-सम्बन्धी सभी विमागों के साधनों का उपयोग ग्राम-विकास की समस्याओं को इल करने के लिए किया जा रहा है।"

विकास-सम्बन्धी नीति के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास सिमित (State Development Committee) की स्पापना की गई है, जिसमें मुल्य मनी श्रीर विकास-कार्य ने सम्बद्ध अनेक विभागों के श्रध्यस्त सिमिति को है। डेवलपमेन्ट किमश्नर इस सिमिति का मनी होता है श्रीर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वह सरकार के विकास के सम्बन्धी अनेक विभागों के श्रध्यस्त श्रीर मिन्त्रयों के दल का प्रधान भी होता है। जिले, तहसील श्रीर महल के त्तर पर ऐसा ही समन्वय स्थापित करने के लिए डेवलपमेन्ट किमश्नर से समान ही कमश क्लास्टर श्रीर महल-विकास श्रिषकारी (Block Development Officer) को भी उसी प्रकार के कार्य सौपे गए हैं। विकास-सम्बन्धी शासन की इस भू खला में प्राम-सेवक श्रन्तिम कड़ी के समान होता है श्रीर जिले के शासन का एक श्रम समक्ता जाता है। श्रीर बहु-उद्देशीय कार्य करमें पड़ते हैं। शासन के दिने को निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि

श्रिधिकारी अधिक से अधिक कार्यज्ञमता मे काम कर स्त्रोग जनता से अधिकतर

योजना के अन्तर्गत-राष्ट्रीय विस्तार श्रोर सामुदायिक विकास योजनायें प्रयम पचवर्णीय योजना की देन है। कार्य की इकाई एक विकास मडल है, सहयोग उपलब्ध है। जिसके ग्रन्तर्गत लगभग १०० ग्राम भ्राते हैं, जिनकी जनसङ्या ३०,००० से लगाकर ७० ००० तक होती है, ग्रोर उनका चेत्रकल १५० में १७० वर्गमील तक हो सकता है, १६५२ में जब से यह कार्यक्रम ग्रारम्म हुआ है, समुदायिक विकास योजना के श्रन्तर्गत ३०० महल श्रीर राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के श्रन्तर्गत Eoo महल बना लिए गये हैं, श्रीर इस प्रकार १९५६ तक विस्तार महली का योग १२०० हो गया है। इसके अन्तर्गत तालिका नं०१ के अनुसार १२३००० माम श्रीर द करोड व्यक्ति श्रा जार्येने।

तालिका न० ?

H14 31.	तारि	नेका न०	?	. <del>सं</del> चारस्म <sup>(</sup>	केया गया
विकास मंडल का कार्य १६५२-	जो प्रथम <sup>प</sup>	। चवर्षाय १३.५४	शहपुष्ठ-पुष्	१६५५-५	६ जोड
SEX4.					३००
विकास भडल	२४७	પૂર	રૃષ્, ર	३९६	003
सामुदायिक विकास राष्ट्रीय विस्तार	<u></u>	२५१	२५3	386	१२००
जाइ	280	308			३२, <u>६५</u> ७
क्षामुद्राालच्या र र र	<sub>રપ્,</sub> રદ્દ૪	७,६ <u>६३</u> २५,१०	, २५, <sup>३०</sup>	० ३९६००	٤٥,000
राष्ट्रीय विस्तार जोड	२५,२६४			० ३६,६००	3333
					२०.४
जनसंख्या (दस साप्त सामुदायिक विकास	१६,४		४.० १६६ १६		1.8 AE 2 330 8.1
राष्ट्रीय विस्तार जोड	. १६.	X	२०६ १६	त्रम् करना	न्त्रीर प्रश्पूष्ठ प्राइन
	. * 200	oo नये <sup>२</sup>	स्कूला का अ		३५००० वयस्कों के

विकास चेत्र में १४००० नये स्कूलो को ग्रारम्म करना ग्रौर ५१५४ प्राइ-मरी स्कूलों को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, ३५,००० वयस्कों के लिये शिचा नेन्द्रों का स्थापित करना, जिनके द्वारा ७७,३०० वयस्क साचर किये गये हैं, तथा ४०६६ मील पक्की श्रीर २८००० मील कची सहक का बनवाना श्रीर ८०,००० शीचालयों का गाँवों में निर्माण करवाना स्थानीय विकास के उदा- इरण हैं। िलनका सामालिक प्रभाव बहुत ही महत्वशाली होगा। इस कार्य में बहुत श्रीविक श्रशा तक सहायता जनता तथा विस्तार योजनाश्रों को कार्यान्तित कराने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। यदि श्राम उद्योगा तथा सहकारिता के चेत्र में सकलता कम प्राप्त हुई हैं, इसका कारण यदि सम्पूर्ण देश के हिन्दकोण से ही देखा जाय तो सहकारिता तथा नवीन उन्नोगों की कार्य व्यवस्था का दोष है, जिसमें सुधार करना चाहिए।

"राष्ट्रीय विकास परिपद् ने सितम्बर १६५५ में यह स्वीकार कर लिया था कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में समन्त देश राष्ट्रीय विकास देवा योजना के प्रन्तर्गत ग्रा जायगा ग्रोर जा राष्ट्रीय विस्तार महल समुदायिक विकास महलों में परिणत कर दिये जायेंगे, ग्रार उनकी सख्या ४०% से कम न होगी। यदि पर्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हा सकेगी तो सम्मवत यह सख्या ५०% मी हो जाय। द्वितीय योजना म ३८०० नये विकास महल राष्ट्रीय विस्तार योजना के कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत ग्रारम्भ किये जाने वाले हैं श्रीर यह श्राशा की जाती है कि इनमें से ११२० समुदायिक विकास महलों में परिणित कर दिये जायेंगे। योजना के इस कार्य के लिए २०० करोड़ रुपयों का भी प्रवन्य प्रवन्य किया गया है।"

''सामुदायिक योजना प्रशासन के निश्चित किए हुये कार्यक्रम के श्रनुसार दितीय पचवर्षीय योजना में, प्रत्येक वप, राष्ट्रीय विस्नार महल तथा उनके सासु-टायिक विकास महलों में परिणान किये जाने का कार्य किया जाया करेगा।" जैसा कि तालिका न० २ में दिखाया गया है।

तालिका न० २ विस्तार मडलो की संख्या

वर्ष	राष्ट्रीय विस्तार सेवा	सामुदायिक विकास महलों में परिवर्तन	
१६५६-५७	५००	२५०	
<b>የ</b> Eሂ७-ሂ⊏	६५०	२००	
१९५८-५९	७५०	२६०	
<b>₹</b> ६५६-६०	- 003	300	
१६६० ६१	१०००	३६०	
	3500	११२०	

द्वितीय पचवर्षांय योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में यह भावना उत्पन्न करनी होगी कि अपने रहन-सहन के स्तर को सुधारना तथा एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करना और उसमें सहयोग देना उनका कर्चन्य है। यह आशा की जाती है, कि राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा और अन्य अनुपूरक कार्यक्रम द्वारा आगामी कुछ वर्षों में ही कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के श्रतिरिक्त निम्न अन्य चेत्रों में उन्नति होगी। (१) सहकारिता के कार्य में जिसमें सहकारी कृषि भी सम्मिलित है विस्तार होगा, (२) ग्रामोन्नति में सक्तय उत्तरदायित्व ग्खनेवाली संस्थाओं के रूप में ग्राम पचायतों का विकास होगा, (३) भूम की चकवन्दी, (४) ग्राम के छोटे उद्योगों का विकास होगा, (५) ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना हागा जिनमें गाँव के पिछड़ी हुई जनता को जैसे छोटे-छोटे कृषक, भूमिहीन कृषक, कृषि कार्य करने वाले मजदूर एवं शिल्पी इत्यादि, (६) छियों और नवयुवकों की उन्नति के लिये श्रीर पिछड़ी जातियों के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाये जार्येगे।

"देसे बहुमुखी कार्यक्रमो को कार्यान्वत करने के लिये जिसके अन्तर्गत उद्योग, सहकारिता, कृपि उत्पादन, भूमि सुधार, तथा सामाजिक सेवाये आवी हैं, जो चेत्र राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये चुने जायेंगे, उनके शीघ ही उन्नांत करने की बहुत श्रिधक सम्मावना होगी। जब इन कार्य-क्रमों को स्योजित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, स्रौर स्थानीय संस्थात्रा का सहयाग व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है, तो एक कार्य मे सफलता दूसरे में सफलता के लिए अवसर प्रदान करती हैं। और इस प्रकार सम्पूर्ण चेत्र में आपिक व्यवस्था दृढ हो जाती है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य-क्रम में क्रांव उत्पादन को सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। इसके पश्चात ग्राम की सबसे अधिक महत्वशाली आवश्यकता कार्य करने के पर्याप्त अवसरों का प्रदान करना है। सत्तलित ग्राम्य श्राधिक व्यवस्था में यह श्रावश्यक है, कि श्रीद्योगिक कार्यों के अवसरों की कृषि कार्यों को अपेद्या दृढतर गति से वृद्धि की जाये। हाल के प्राम तथा छोटे उद्योगो के विकास कार्य-कार्मो के सम्बन्व में जो अनुभव हुआ है उससे यह सकेत मिलता है, कि ऐसी विस्तार सेवा की श्रावश्यकता है, जिसका सम्पर्क ग्रामीस शिल्पकारों से हो श्रीर जो उन्हें श्रावश्यक पथप्रदर्शन कर सके. सहायता दे सके, उनकी सहकरिता के आधार पर व्यवस्था कर सके और अपने माल को गाँव में तथा बाहर वेचने में सहायता दे सके। इसका प्रारम्म २६ श्रमगामी योजनाश्रों को कार्यान्वित करके किया जा चुना है। यह त्रावश्यक है

कि ययासम्भव शीघ्र प्रत्येक विस्तार तथा सामुटायिक विकास चेत्र मे एक प्रवीस प्रशिक्षित इन ग्राम उद्योगो के कार्यक्रम को चलाने के लिये नियुक्त किया जाय।

वित्त की व्यवस्था—इन विकास कार्य कम के लिए वित्त की व्यवस्था समुदायिक योजना प्रशासन (Community Project Administration), रात्य सरकारों ख्रोर जनता के द्वारा की जाती हैं। सी० पी० ख्राधिक रूप से वित्त का प्रवन्ध तो करता ही है, इसके अतिरिक्त उस पर विशेष यन्त्रों व नत्सम्बन्धी अन्य साम्रायों को उपलब्ध करने का भी टायित्व है। इस विकास कार्य-कम को वार्यान्वत करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने पर जितना व्यय होगा, उसका ख्राधा धन राज्य सरकारों को चेन्द्रीय सरकार द्वारा आधिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार यह प्रयास भी कर रही है कि योजना की अवधि समात होने तक सहकारी अनदोलन और अन्य एजेन्सियों के द्वारा अल्पकालीन, श्रीसतकालीन और दीवकालीन श्रूण के रूप में कमश्र १०० करोड, और २५ करोड़ रुपये का धन प्रति वर्ष प्राप्त होने लगे। सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कम पर जो धन-राशि व्यय होती है उसकी लगभग १०% मारतीय-अमरीकी टेकनिकल सहयोग योजना द्वारा यन्त्रों और टेकनिकल परामर्श ख्राटि के रूप में प्राप्त होती है।

सामुटायिक योजनाओं श्रीर विकास महलों के लिए १६५२-५३ से लेकर १६५५-५६ तक कुल मिला कर ३२६० करोड़ रुपये घन का बजट में स्वीकृत हुत्रा है। इस प्रकार माच १६५४ तक प्रथम १८ महीनों में न्यय के लिए १६.३० करोड़ रुपये निर्धारित थे, किन्तु इस श्रविध में वास्तव में जो घन राशि न्यय की गई वह केवल ५६५ करोड रुपया थी। इसके श्रविग्क्ति इस श्रविध में नकट घन, श्रम, सामग्री श्रादि की ऐन्छिक सहायता के रूप में कुल मिलाकर २६३ करोड रुपया का घन प्राप्त हुत्रा, जो सरकारी न्यय के घन के श्राधे से योड़ा ही कम है। प्रारम्भिन काल की श्रनेक किनाउयों के कारण योजना की प्रगति घीमी रही, किन्तु जब हम इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कि जून १६५४ तक न्यय की कई घनराशि ८१० करोड़ रुपये तक पहुँच गई, तो भविष्य में श्रिधक जीव्र प्रगति होने की सभावना प्रकट होती है।

वीमी प्रगति के कारण्—सामुदायिक योजनायो की प्रगति का मूल्याक्त करने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से एक कार्य-मूल्याक्त संत्या (Programme Evaluation Organisation) की स्थापना की गई है। सामुदायिक योजनायों को कार्यान्वित करने के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ हैं—

(१) प्रारम्भिक अवस्या में प्रगति के अवस्य होने का कारण यह या कि

जनता उदासीन थी श्रीर श्रन्य लोकप्रिय व्यक्तियों ने भी योजना के कार्य-क्रम में सिक्य रूप से भाग नहीं लिया। इस स्थिति में किसी सीमा तक सुधार श्रवश्य हुआ है, किन्तु फिर भी शामवासियों का पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। प्रगति के धीमी श्रीर श्रानिश्चित होने का यह एक प्रमुख कारण था।

- (२) पचायतों श्रयवा विशेष कर इसी उद्देश्य से स्थापित की गई श्रन्य लोक प्रिय सस्थाश्रों से जो सहयोग प्राप्त हुया है, वह श्रपर्यात है। पचायतें सभी चेत्रों में नहीं हैं श्रीर जहाँ हैं भी, वहाँ उनमे गुटवन्दी के कारण प्राय: सवर्ष चलता रहता है। सहकारी सस्थाएँ उपयोगी हो सकती हैं, किन्तु विकास योज नाश्रों के सम्बन्ध में उनकी उपयोगिता सीमित ही है। उनके नियमों के श्रतुसार सामान्य रूप से सदस्य भी नहीं बनाए जा सकते, वर्योकि उनका चुनाव किया जाता है। सहकारी सस्याश्रों की रचना ही कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है जिससे उनके कार्य सीमित होते हैं। विकास कार्य-कम की सहायता के लिए श्रानेक परामर्श्यात्री सस्याश्रों की स्थापना की गई है जिनके मिन्न-भिन्न नाम हैं श्रीर जो कुशल श्रविकारियों के निर्देशन में सन्तोपजनक कार्य कर रही हैं। किन्तु फिर भी यह श्राश्यका बनी हुई है कि जब सरकारी श्रविकारी हटा लिए जायेंगे, तो समब है कि ये सस्थाएँ कार्य करना बन्द कर दे।
- (३) घीमी प्रगति के लिए उचित योजना का अभाव भी अधिक सीमा तक उत्तरदायी है। विकास की प्रगति इसलिए घीमी नही रही है कि आवश्यक वित्त का अभाव था, वरन् उसका कारण यह या कि प्रारम्भिक अवस्था में अधिकारियों-हारा बजट में कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की गई। इसके अतिरक्त अन्य कारण भी थे। बजट बहुत जल्दी में तथा अस्पष्ट विचारों के साथ तैयार किए जाते थे तथा धनराशि को मजूरी देने के पूर्व विवरण जानने में समय लगता था।

(४) कार्य-क्रम की इस धीमी प्रगति और श्रनेक भूलों के लिए प्रशिज्ञण-प्राप्ति कर्मचारियों का श्रमाय बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। किन्तु श्रव श्रधिक सख्या में कर्मचारियों को प्रशिज्ञण देकर यह श्रमाव शीवता से दूर किया जा रहा है।

पी॰ ई॰ श्रो॰ की तीसरी सफलताकन रिपोर्ट (Evaluation Report) ने कार्य को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में श्रानेक प्रयागात्मक सुकाव दिये हैं जो बहत ही महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्य-क्रम को आशानुकूल सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि (१) औद्योगिक विभागों को प्रत्येक दिशा में

श्रीर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में दृढ बनाया जाय । श्रनेक स्थानों पर प्रत्येक चेत्र तया जिला सम्बधी त्रोत्रोगिक विभागीय व्यवस्था की समता तथा सख्या में सुघार करना श्रावश्यक हो गया है, (२) इसके श्रतिरिक्त श्रन्वेपण के कार्य की मुविधात्रों का विस्तार किया जाय, भूमि के श्रास-पास के गवेपणागारों को विस्तत किया जाय श्रोर इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि खेतों से सब सूचनायें गवेषस्पारों तक पहुँच जॉय, (३) विमिन्न विषयों के विशेषजों पर चेत्र विकास वर्मचारी के नियन्त्रण (जो ग्रावश्यकता से ग्राधिक हो सकता है) तथा जिलों के श्रन्य पार्विधिक श्रिधिकारियों के दुहरे नियन्त्रण की व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है। (४) निर्माण कार्यों ने ग्रामों मे कार्य करने वाले कर्मचारियों का जिनका कृषि तथा कृषि विस्तार नी प्रारम्भिक शिच्चा मिली है श्रीर जिनका सबसे श्रधिक श्रावश्यक कर्त्तन्य कृषि उत्पादन बढाने का है, श्रधिकाश समय ले लिया है, (५) ग्राम पचायतों को श्रपने वृद्धिमान उत्तरदायित्व को जो कि उनके ऊपर डाल दिया गया है पूर्ण करने के लिये सदेव पथ प्रदर्शन तथा सिक्य सहायता मिलनो चाहिए, (६) कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने मे श्रावश्यकता से श्राधिक महत्व मोतिक श्रौर श्राधिक सफलताश्रो पर दिया गया है, जैसे निश्चित किये हुये कार्य के, व्यय श्रीर भवन निमाण के व्येत्रों को पूरा करना इत्यादि, श्रीर जनता को नये द्वग से कार्य करने की शिज्ञा देने तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सुघार श्रीर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के पूर्ण करने के लिये, जो राष्ट्रीय प्रादेशिक वोजना के श्रन्तर्गत है, एक प्रमावशाली साधन बनाने की श्रोर कम ऱ्यान दिया गया है।

कार्य करने मे त्रुटि—समुदायिक विकास योजनाश्चों ने प्रामीण जनता में श्रात्मविश्वास उत्पन्न करने में बहुत कुछ योग दिया है। उसने श्रामनिवासियों को इस बात का श्रामास दिया है कि ग्राम्य-जीवन में निश्चित रूप से कुछ गड़-वडी है जिसका पारस्परिक सहरोग के श्राधार पर ही सुधार किया जा सकता है। श्रामी इतना श्राधक समय नहीं हुश्रा है कि इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निकर्ष पर पहुँचा जा सके, किर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि सामुदायिक विकास योजनाशों ने उत्पादन बढ़ाकर श्रीर वेरोजगारी कम उरके श्रामों में रहन नहन का त्तर किंचा किया है। किन्तु जिस रूप में कार्य-कम को नार्यान्वित किया जा रहा है उसमें कई दोप हैं। (१) भूमिहीन खेनिहर मजदूरों के श्रम का उपयोग करने की समुचित ब्यवस्था नहीं है। इति के ज्ञेत्र में उत्पादन-वृद्धि श्रीर कुषकों के लिए कार्य के श्रवसर उत्पन्न करना ग्रह्मन्त महत्वपूर्ण है, किन्तु भूमिहीन मजदूरों को वसाने की ब्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब कभी विकास योजनाश्चों

के श्रन्तर्गत त्रास्थायी रूप से मजदूरी देकर कार्य करने की श्रावश्यकता पड़ती है तभी इन्हें थोडा-बहुत कार्य मिलता है। इसके अतिरिक्त वे नि:सहाय, वेरोजगार श्रोर उपेद्धित-से रहते हैं, (२) यदि दूसरे दिन्दिकीया से देखा जाय वो सामुदायिक निकास योजनात्रों के कार्य-कम मे एक और टोज प्रकट होगा। वह यह है कि खेतिहर मजद्रों को पूरक कार्य उपलब्ध कराने के लिए ग्राम्य-उद्योगों की स्थापना करने पर विशोध ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में पी० ई० स्रो० की यह धारणा है कि "प्रामीण उद्योग-घन्धो की ग्रानिश्चित सभावना के पीछे चाहे जो मी कारण हों, किन्तु तथ्य तो यह है कि सामुदायिक विकास योजनात्रों के वर्तमान स्वरूप श्रौर साधनों से भूमिहीन मजदूरो की वेरोजगारी की समस्या हल करने की थ्राशा नहीं की जा सकती"। किन्तु पीo ईo ब्रोo का यह दृष्टिकी ए गलत है। चिक सामुदायिक विकास योजनात्रो का उद्देश्य है कि उत्पादन कार्य ग्रीर ग्रामीख जनता की श्राय में वृद्धि हो श्रीर आमवासियों में नई श्राशा का संचार किया जाय, इसलिए गैर खेतिहर वर्ग की वेरोजगारी को समस्या को उपेजा की दिव्ह मे देखना उचित नहीं है ऐ. करने पर सामुदायिक विकास योजनात्रों की उपयो-गिता बहुत कुछ कम हो जायगी, (३) सामुदायिक यिकास योजना के अन्तर्गत भूमि की समस्या को सुलकाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। चकम्दी का कार्य एक अन्य सगठन द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इसने अभी श्रिषिक सफलता नहीं प्राप्त की है। बम्बई, उत्तर-प्रदेश श्रीर सीराष्ट्र को छोड़कर सहकारी कृषि के चेत्र मे श्रिधिक प्रगति नहीं हुई है ग्रीर इन राज्यों मे भी यह श्रान्दोलन श्रपनी प्रार्राम्मक श्रवस्था में ही है। बहुत से कुपकों के पास कृपि के लिये इतनी कम भूमि है कि उस पर कृषि करना ग्राधिक दृष्टि से लाभ-पूर्ण नहीं है। जब तक कृषि की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि का चेत्रफल नहीं बढाया जाता और निम्नतम लागत से श्राधिकतम उत्पादन नहीं होगा, तब तक किसान खेती की विकसित प्रणालियों का पूरा लाम नहीं प्राप्त कर सकेंगे, छोर (४) सामुदायिक विकास योजना के कार्य-कम में श्रव तक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे जन-सख्या की वृद्धि पर नियत्रण रखा जाय श्रौर परिवार-ग्रायोजन (Family Planning) का सुचार प्रबन्ध हो सके। जब तक यह कार्य नहीं हो जाता तव तक भारतीय प्रामीण जनता की जठिल समस्यायों को सन्तोपजनक रूप में इल करने की त्राशा करना व्यर्थ है। उत्पादन बढ़ाकर श्रीर जन-सख्या की वृद्धि को नियन्नित करके ही आमवासियों के रहन सहन का स्तर ऊँचा किया जा सकता है।

#### श्रध्याय १२

# सहकारी आन्दोलन

भारत में सहकारी श्रान्दोलन का विकास २० वीं शनाब्दी में हुशा। सहकारिता का अर्थ है किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयत्न
करना। समान उद्देश्य की दृष्टि से यह व्यक्तिगत प्रयत्न श्रीर सहायता से निल्कुल
भिन्न है। श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सब की परिभाषा के श्रनुसार सहकारी समिति ऐसे
व्यक्तियों की सस्या है जिनकी श्राधिक स्थिति श्रव्छी नहीं है श्रीर जो समान
श्रिषकार तथा उत्तरदायित्व के श्राधार पर स्वेच्छा-पूर्वक सगठित होकर श्रपनी
ऐसी समान श्राधिक श्रावश्यकताश्री की पूर्ति का भार एक सस्या को सीप देते हैं
जिनको वह श्रपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा पूर्णत सन्तुष्ट कर सकने में श्रसमर्थ
होते हैं। यह लोग श्रापस में मिलकर इस सस्या का प्रवन्ध करते हैं श्रीर समान
मौतिक एवम् नैतिक लाभ उठाते हैं। इस प्रकार सहकारी स्वित समान हितों का
सब है, यह समान श्रिषकार प्राप्त सदस्यों का स्वेच्छा से निमित एक ऐसा श्रायिक
सगठन है जो श्रपने सदस्यों की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करता है श्रीर उनके
समान हितों की रह्या करता है।

सहकारी समितियाँ दो प्रकार की हैं—(१) रेफिजेन (Raiffeisen type) श्रीर (२) शुल्ज हेलित्ज (Schulze Delitsch type)। इन दो प्रकार की सहकारी समितियों में जिन व्यक्तियां का नाम समितिलत है वह जर्मनी में सहकारी ग्रान्टोलन के प्रऐता थे। प्रथम प्रकार की सहकारी समिति के सिद्धान्तों का उपयोग प्राम में सगितित की जानेवाली समितियों में किया जाता है श्रीर दूसरे प्रकार की समितियों के सिद्धान्तों का उपयोग नगरों में किया जाता है। रेफिजेन-सिमितियों का कार्य चेत्र प्राय एक प्राम तक सीमित रहता है श्रीर इनके सदस्यों का उत्तरदायित्व श्रसीमित होता है। इन समितियों से केवल सदस्यों को ही ऋण विया जाता है श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी केवल उत्पादन के लिए। श्रुक्क-डेलित्ज समितियों का कार्य चेत्र श्रीर वह भी सेवल अत्यादन के स्थान उत्तरदायित्व भी सीमित है। इस प्रकार की सीमित सदस्यों में प्रवेश श्रुक्क वस्त्व करती है श्रीर विना श्राय वाला व्यक्ति इसका सदस्य नहीं वन सकता है।

वित्त, उत्पादन, वितरण इत्यादि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन समितियों को समिठित किया जा सकता है परन्तु भारत मे ऋण देने वाली साल समितियों का ही प्रमुत्व है। वास्तव में भारत में सहकारी श्रान्दोलन श्रारम करने का निश्चित उद्देश्य ग्रामों में श्रुण की भयानक समस्या को हल करना श्रीर ग्रामीणों को मुविधा जनक रीति से श्रुण देना था। भारत में जून १६५५ में सब प्रकार की २,१६,२८८ समितियों की तुलना में जून १६५६ में २,४०,३६५ सहकारी समितियों थीं। कृषि साख समितियों ही प्रमुख थीं। इनकी संख्या कुल समितियों की ६७६% तथा कृषि समितियों की ८०६% थीं। श्रान्दोलन श्रव भी साख-प्रधान है।

विकास—भारत में सहकारी आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम महत्व-पूर्ण घटना १६०४ का सहकारी साख-समिति अधिनियम है। इस नियम के बनने से पूर्व भी मद्रास में सहकारिता के सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण विकास हो रहा था। वहाँ साख-समितियों का कार्य 'निधियों' करती थी। देश में सहकारिता के विभिन्न पहों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम १६०१ में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब तक सरकार अधिनियम नहीं बनावी इस दिशा में विशेष प्रगति की सभावना नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सहकारी साख-समिति अधिनियम पास किया। इसमें केवल साख-समितियों की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार अन्य देशों की अपेद्धा भारत में सर्वप्रथम साख-समितियों का ही विकास हुआ। नियम लागू होने के परचात् यह अनुभव किया गया कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। साख-समितियों के पास माम में भ्रुण प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यकता से बहुत कम पूजी थी।

इस नियम के दोषों को दूर करने के लिए १६१२ में दूसरा सहकारी समिति श्रिमियम पास किया गया। इस नियम में क्रय-विक्रय करने वाली श्रान्य प्रकार की सहकारी सिमितियों का सगठन करने की न्यवस्था की गई। नगर श्रीर प्राम सिमितियों के अतर को मिटा दिया गया। सीमित उत्तरदायित्व और श्रासीमित उत्तर-दायित्व के श्राधार सिमितियों को अधिक वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया। नियम में यह निश्चित कर दिया गया कि जिन सिमितियों के सदस्य रिजस्टर्ड सिमितियों हैं वह सीमित उत्तरदायित्व वाली सिमितियों होंगी श्रीर साख-सिमितियों तथा ऐसी श्रान्य सिमितियों जिनके श्रीधकाश सदस्य कृषक हैं श्रासीमित उत्तरदायित्व साली सिमितियों होंगी। इस नियम से सहकारी श्रान्दोलन के विकास में सहायता मिली। उत्पादन के विकाय के लिए, पशु-बीमा, दूध की पूर्ति श्रीर खाद इत्यादि क्रय के लिए नई प्रकार की सिमितियों स्थापित की गई।

मैकलैगन समिति की रिपोर्ट के आवार पर सहकारी आन्दोलन के विकास

में एक और प्रयास किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के श्राघार पर १६१६ के सुधार अधिनियम (Reform Act) के द्वारा सइकारी श्रान्दोलन का कार्य राज्य-सरकारों को सीप दिया गया। राज्य सरकारों ने कुछ वर्षों तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की परन्त १६२५ में वम्बई की सरकार ने श्रलग से सहकारी सिति श्रिधिनियम नियम बनाया। इसके परचात श्रन्य राज्यों में भी श्रावश्यक कानून बनाये गये।

सहकारिता श्रान्दोलन के विकास का कुछ श्रनुमान इस बात से लग सकता है कि १९५१-५२ में समितियों की सख्या, सदस्या सख्या तथा कुल चालू पूँची क्रमशः १९८५ लाख, १३७ ६२ लाख तथा ३०६ १३४ करोइ ६० यी । १६५५-५६ में यह बढ़ कर कमश २४० लाख, १७६'२ लाख श्रीर ४६८ दर करोड़ ६० हो गई। विभिन्न प्रकार की समितियों के दृष्टिकी ग से अन्य समितियों की अपेता कृषि साख समितियों में वृद्धि श्रिषिक हुई है। पिछले वर्षों की बी तरह साख समितियाँ ही अधिक प्रधान रही और कुल चालू पूँजी का ७५% साख चेत्र में ही था। यह मानते हए कि मारतीय परिवार के सदस्यों की श्रीसत सख्या ५ है हम कह सकते हैं कि १९५५-५६ में ८८ करोड़ व्यक्ति प्रथवा जनसख्या के २३ प्रति-शत व्यक्ति सहकारी श्रान्दोलन के सम्पर्क में ग्राये। १६५१-५२ में ६६ करोड़ व्यक्ति श्रयवा १६ प्रांतशत जन सख्या सम्पर्क मे शाई थी। इसीप्रकार (प्राइमरी) मायमिक समितियों, जो स्नान्दोलन का प्राधार प्रस्तुत करती है, द्वारा १९५१-५२ में दिया हुमा ६७ ६५ करोड ६० था। १६५५-५६ में यह राशि वहकर १४० ७८ करोइ र० हो गयी। दिये गये ऋण की हस वृद्धि से भी प्रगति का कुछ श्रनुमान लगाया जा सकता है। चिन्ता का विषय तो यह है कि वकाया ऋगां के प्रतिशत के रूप में कालातीत ऋगों में कुछ कमी अवश्य हुई है किन्तु उनका अनुपात अव भी बहुत अधिक है।

प्रगति के इस सिक्स सर्वे जाए म इस टस निष्कप पर पहुँचते हैं कि (क) सहकारिता से जनसंख्या का बहुत छोटा खरा लाभ उटा रहा है, (ख) जनसंख्या की बृद्धि के अनुकूल अनुपात में सहकारिता का विकास नहीं हुआ है, (ग) यद्यपि गैर साल समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है, किर भी साख समितियों का ही अधिक विकास हुआ है। इसलिये सहकारिता आन्दोलन को ज्यापक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सहमारी समितियों में सादा के अतिरिक्त अन्य पह्नों पर भी आवश्यक न्यान देना चाहिये।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ— चहकारी आन्दोलन न तो सारे देश में समान रूप से फैला है आर न सभी जगह इसका सद्गठन समान है। सहकारी आन्दोलन ने खरह 'क' के कुछ राज्यों में विशेष प्रगति की है परन्तु अन्य राज्यों में इसका उपयुक्त विकास नहीं हो पाया है। खरह 'ख' और 'ग' राज्यों में से कुछ में इस आन्दोलन का विल्कुल विकास नहीं हुआ। सम्पूर्ण देश में कुल जितनी सहकारी सितियों हैं उनका ३८ प्रतिशत और प्रारम्भिक सितियों के लगभग ४६ प्रतिशत सदस्य केवल बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में हैं जबिक उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बङ्गाल, पञ्जाव तथा हैदराबाद में क्रमशः ६१ तथा ६५ प्रतिशत है। परन्तु देश में जहाँ जनसख्या तथा चेत्रफल में मारी अन्तर है सहकारी सितियों की प्रगति की जॉच करने के लिए सितियों की सख्या उपयुक्त नहीं है। यह जानना आवश्यक है कि इन सितियों से कितने प्रतिशत जनता लाम उठाती है। कुछ खरड 'ख' और 'ग' राज्यों में सहकारी सितियों का कार्य सन्तोप-जनक रहा है। रिजर्व बैक्क ने सुक्ताव दिया है कि शहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में सितियों के कार्य-चेत्र पर और खरड 'ख', 'ग' और 'घ' राज्यों में उनकी कार्य कुशलता पर विशेष महत्व दिया जाय।

सङ्गठन सहकारी समितियों का सङ्गठन वास्तव में शुडाकृति (Pyramid) के समान है। इस सङ्गठन का आधार वह प्रारम्भिक सहकारी समितियों हैं जिनको सङ्गठित करने के लिए कोई भी टस व्यक्ति सहकारी समितियों के रिजस्ट्रार को आवेदन पत्र दे सकते है। विभाग के निरीक्त द्वारा आवश्यक जॉच-पड़ताल के पश्चात् समिति स्थापित करने की अनुमित दी जाती है। इन समितियों की चालू पूँजी, प्रवेश शुलक, सरकारी ऋण, केन्द्रीय समितियों तथा राज्य वैद्वों से ऋण लेकर एकत्र की जाती है। इनमें से कुछ समितियों के पास शेयरों की पूँजी भी है। केवल साख समितियों को छोड़कर इन समितियों का उत्तरदायित्व सीमित है और सारी व्यवस्था प्रवन्धक समिति तथा आम-सभा के हाथ में होती है।

इन प्रारम्भिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय समितियां ऋौर राज्यीय सहकारी समितियों होती हैं। प्रारम्भिक समितियों के सङ्गठन से केन्द्रीय समितियों बनती हैं ऋौर इन (केन्द्रीय) समितियों के सङ्गठन से राज्यीय समितियां जन्म लेती हैं। सम्पूर्ण ऋगन्दोलन इसी प्रकार परस्वर गुँथा हुआ है। यनि केन्द्रीय साख-समितियों को ऋपनी पूँजी का ऋषिकाश भाग रिजर्व वैङ्क से ऋल्यकालीन ऋण के रूप में प्राप्त होता है किर भी इनकी ऋौर प्रदेशीय समितियों की व्यवस्था तथा वित्त की ऋगवस्थकता की पृति इत्यादि कार्य प्रारम्भिक समितियों को ही तरह होते हैं। पहले केन्द्रीय समितियों को रिजर्व वैङ्क से प्राप्त होने वाले ऋल्यकालीन ऋग्य की ऋविष्ट होने थी परन्तु ऋब इसे बढाकर १५ महीने कर दिया गया है। ऋग्य के

धन पर न्यान की दर छेड रूपया प्रतिशत है। यह दर बैह्न के न्यान की दर से दो प्रतिशत कम है।

सहकारी समितियों के शुहाकृति की व्यवस्था में शीर्ष पर सहकारी सह नाम की श्रिखिल भारतीय सस्या है। इस सस्या का प्रथम सम्मेलन करवरी १९५२ में बम्बई में हुआ था।

साख-समितियाँ—प्रारम्भिक कृषि साख समितियों की सख्या जो कि सहकारी ऋण व्यवस्था का मूलाधार है, जून १६५५-५६ में १ ने लाख यी श्रौर उनका सदस्यों की सख्या ७८ लाख यी।

तालिका नं० ३ प्रारम्भिक कृपि सास समितियों का कार्य ( अन्न वेंक श्रीर भूमिबंधक वेंकों को छोड़कर )

	१६५१-५२	१६५२-५३	१९५३-५४	<b>શ્દપ્ર</b> પ્રપ્
समितियों की सख्या	१,०७,६२५	१,११,६२⊏	१,२६,६५४	१,४३,३२०
सदस्यों की सख्या	४७,७६, <b>८१</b> ६	प्र१,२६,००२	५८,४६,३८०	६५,६५,४१६
वर्ष के ग्रन्तर्गत	(करोड़	र रुपये में)		
दिये हुए ऋगु जी				
घन राशि	२४ २०	२५ ६९	२६ ६४	३५.१८
वर्ष के भीतर				
ऋण में वस्ल की				
धनराशि	१८ ६७	२१ २१	२६ ४८	२८ ६१
वर्ष के श्रन्त में वस्त्	ī			
होने वाला ऋग	३३ ६६	३७ ६८	४१•५६	४८ ते ३
वर्ष के श्रन्त में				
शेष ऋग्	८ ५२	१० ४७	१२"०३	<b>१</b> ४°७०
निजी कोष	१७ ६७	१६ २७	૨ <b>१</b> •પ્રપ્	२३ <b>:</b> ६६
जमा धन	४ ४१	<b>४°</b> ४१	४६१	<b>५ ४</b> ४
ऋण में लिया हुश्राध	न २३१५	28 8E	२⊏ २४	३३ ५२
चालू पॅजो	४५ २२	8E.12	<b>48 88</b>	<b>६२</b> ६३
		~ -		

प्रारम्भिक साख समितियाँ श्रार्थिक हिन्दि से निर्वल हैं श्रीर इस कारण कुषक को उतना लाम नहीं पहुँचा पातीं जितना कि चाहिये। तालिका न• ३ सहकारी बैंकों के लिये वही कार्य करते हैं जो केन्द्रीय सहकारी बैंक छोटी सहकारी समितियों के लिये करते हैं। शीर्प बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं और अधिक आय वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आतिरिक्त आय से घाटे में चलने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करके सन्तुलन स्थापित करते हैं। लोगा को घन जमा करने की प्रेरणा देकर तथा ब्यापारिक बैंकों, रिजर्व बैंक और सरकार से ऋण लेकर यह द्रव्य बाजार और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच सबन्ध स्थापित करते हैं और इस धन से केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता करते हैं।

१६०४ के सहकारी समिति कानून में जो १६१२ में सशोधन किया गया उसके पश्चात् केन्द्रीय यूनियनों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों ख्रीर सर्वोच्च बैंको ने काफी प्रगति की है। १६०४ के कानून में सशोधन करके इन केन्द्रीय सहकारी सस्याख्रों को मान्यता प्रदान की गई। फिर भी इन केन्द्रीय सस्याख्रों की सख्या ख्रीर भारतीय कुषकों को इनसे मिलने वाली वित्त सहायता पूर्णत्या ख्रप्यांस है। सास्तव में इस बात पर जोर देना चाहिये कि इन सस्याख्रों की सख्या में वृद्धि हो, इनके साधन बढाये जाय जिससे ये कृषकों के लिये ख्रिषक लाभदायक सिद्ध हो सके।

शीर्ष वैक—सहकारी श्रिषिकोषण द्वारा की गई प्रगति का श्रनुमान इसी से लग सकता है कि १६५०-५१ से १६५५-५६ के बीच १० नई राज्यीय सहकारी वैकों की स्थापना की गई तथा ३० जून १६५६ को देश मे २४ ऐसी वैंके थी। केवल पाँच राज्यो—कच्छ, मनीपुर, पाँडुचेरी, त्रिपुरा श्रहमन श्रीर निकोबार,—मे श्रव तक राज्योय बैंक नहीं हैं। इन बैंकों की सटस्यता बढकर ३६,३६४ (जिसमे ११,७४३ व्यक्ति, श्रीर २४,६५१ बैंक तथा समितियाँ थी) तथा चालू पूँजी बढकर ६३ ३४ करोड़ र० हो गई।

शीर्ष सह कारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित और श्रामिश्रित। मिश्रित बैंकों के शेयर व्यक्ति तथा सहकारी सस्थायें दोनों ही लें सकते हैं परन्तु श्रमिश्रित में केवल सहकारी सस्यायें ही शेयर ले सकती है। यदि प्रत्येक शीर्ष वैंक श्रमिश्रित ढग के ही होते तो सहकारिता श्रान्दोलन की भावना के सर्वथा श्रनुक्ल होता। परन्तु श्रमिश्रित बैंक तो केवल श्रान्ध्र, पजान, पाच्छमी बङ्गाल श्रीर मैसूर ही में प्रचलित हैं। शेष सन राज्यों में मिश्रित बैंक ही हैं।

१६५५-५६ में शीर्ष वेकों की चालू पूँजी में (जो ६३.३४ करोड़ रुपए थी) निजी कोष १२.१%, जमा धन ५७ ६% तथा अन्य आतो से प्राप्त ऋगा ३०% था जब कि १६५१-५२ में यह प्रतिशत कमशाः ११४,५७७ और ३०.८ थे इन वैंकों के निजीकोष का इतना कम होना पड़ी चिन्ता या विषय है ययोंकि पिना निजी कोष में वृद्धि के इन में स्थिरता श्राना सम्भव नहीं।

ये वैंक वर्तमान समय में ऋण श्रीर जमाधन पर श्रपना नार्न चलाने के लिए निर्भर रहते हैं। १९५५-५६ में ३६ ६७ करोड़ का के जमान्वन में १८-८५ करोड़ का गैर-सहकारी स्रोतों से प्राप्त किया गया रिवर्व वैंक श्रीर सरनार से लिये नये ऋण की मात्रा क्रमश: २२'२ करोड़ का तया ७ करोड़ का गी। १९-२ करोड़ का की शन्य ऋण की राशि में व्यापारिक वेंगों से लिया गया ऋण १,०५१,००० का तथा सहकारी वैंकों से लिया ऋण ८८,००० था। इसमें व्यापारा वैंकों पर निर्भरता घटती श्रीर सरकार, रिजेंग वैंक तथा सहकारी नेंकों पर चढती दिखाई पड़ती है। इन वैंकों का लगमग १८'३६ करोड़ कपया सहकारी तथा श्रन्य प्रतिभृतियों (हस्टो सिक्योरिटीज) लगा हुश्रा था।

"गायीय सहकारी वैंकों द्वारा दिये गये श्राप्तम (advance) की माता १९५४-५५ के ५० १४ करोड़ कपया से नहकर १९५५-५६ में ६७ ६ रोड़ क० हो गई। यह वृद्धि वैंकों तथा समितियों को दिये गये श्राप्तम में श्राधक दर्शनीय थी। व्यक्तियों को दिये गये श्राप्तम की माता १९५४-५५ में घट गई थी किन्तु विपाद का विपय तो यह है कि १९५५-५६ में इसमें २३० नरोड़ क० की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों को दिये गए श्राप्तम की मात्रा बढ़नर ६ ७६ नराड़ क० हो गई।"

केन्द्रीय सहकारी चेंक—मेन्द्रीय वैं में की सख्या १६५४-५५ में ४८५ थी। १६५५-५६ में यह घटकर ४७८ हो गई। "यह कभी कुछ राप्यों में नेन्द्रीय विचीय एजेन्छियों के युक्तिकरण की नीति वरतने के परिणाम स्वरूप हुई है। उटाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश में राज्य की दो प्रविश्व वें किंग यूनियन राप्यीय सहकारी वैंक में विलयित हो गई। जम्मू श्रीर काश्मीर में तीन जिला वैंक जम्मू केन्द्रीय सहकारी वैंक में विलयित हो गई। केन्द्रीय वें कों की सख्या में कभी होने के वावजूद भी उनकी सदस्य सख्या १६५४-५५ के श्रत में २,७२,००० (१,३२,२७२ व्यक्ति तथा १,३६,७२८ समितियाँ) से बढकर १६५५-५६ में २६६, ५५५ (१,४४,००६ व्यक्ति तथा १,५५,५४८ समितियाँ) हो गई।" श्रान्ध्र, श्रासाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, हैटरावाद, जम्मू श्रीर काश्मीर, मध्यभारत, मैसूर, सीराष्ट्र श्रीर भोपाल में मिश्रित ढङ्ग के श्रीर त्रिवकुर कोचीन में श्रमिश्रित ढङ्ग के केन्द्रीय वैंक थे। शेष प्रदेशों में जैसे वम्बई, उड़ीसा, पञ्चाव उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वङ्गाल, पेप्स, राजस्थान, श्रजमेर, हिमाञ्चल प्रदेश में मिश्रित श्रोर श्रमिश्रित दोनों ढङ्ग के केन्द्रीय वेंक थे।

केन्द्रीय सहकारी वैकों के कुल सदस्यों में से पूर प्रतिशत वैक ग्रौर क्षमितियाँ हैं और ४८ प्रतिशत व्यक्ति हैं। इन वैकों की चालू पूँजी E२ ६७ करोड़ क्ष्यये हैं जिसमे से १६ ४ प्रतिशत निजी पूँजी हैं, ६० १ प्रतिशत जमाधन है, श्रीर २३५ प्रतिशत अन्य होतों से लिया गया ऋण है। १६५१-५२ में यह प्रतिशत क्रमशः १६ च, ६३ थ, २० १ थे । सर्वोद्य बैकों की तरह इन बैकों की निजी पूँजी का अनुपात पिछले वधों की अपेका कुछ बढ़ रहा है पर किर भी निजी पूँजी का अनुपात बहुत कम है। इससे इन बैकों का कार्य अस्थिर रहता है। मविष्य में इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी हिस्सा पूँजी और सुरिचत कोष की पूँजी बढ़ाई जाय जो इन बैको की निजी पूँजी होती है। १९५५ ५६ में नमाधन का ६७ प्रतिशत विभिन्न व्यक्तियों से स्रौर ३० प्रतिशत प्रारम्भिक सिमितियों से तथा ३ प्रतिशत सहकारी बैकों से प्राप्त हुआ। इन्होने ऋण अधिकतर सहकारी वैकों से प्राप्त किये। सहकारी वैका पर निर्भरता स्वामाविक ही है क्यों-कि जिन राज्यों में सर्वोच्च बैक हैं वहाँ केन्द्रीय सहकारी वैकों को सर्वोच्च बैंको के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से अपूर्ण लेने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता।

केन्द्रीय सहकारी बैका के कार्य की एक विशेषता यह थी कि व्यक्तियों को दिये जाने वाले अभिम में कमी आ गई। १९५५ ५६ मे बैकों तथा समितियों को दिये जाने वाला श्रमिम द्रद्र प्रतिशत तथा व्यक्तियों को दिया जाने वाला श्रमिम १२ प्रतिशत था जनिक इससे पहिले वर्ष के प्रतिशत क्रमशः ८१ तथा १६ थे। बुरे तथा सन्देहात्मक ऋगों का अनुपात अब भी अधिक है हालाँकि इस दिशा

समान विशेषताएँ—सर्वीच भ्रौर केन्द्रीय सहकारी वैंकों में बहुत कुछ में भी कुछ सुवार हुआ है। समानता पाई जाती है, (१) इन दोनों सस्याओं की हिस्सा पूँजी और सुरिहत निधि (अर्थात् निजी पूँजी) अपर्याप्त हैं। केन्द्रीय सहकारी बैकों को स्थिति कुछ अञ्च्छी है, परन्तु उनमें भी हिस्सा पूँजी आर सुरक्षित कोष का धन पर्याप्त नहीं है इसका एक कारण तो यह है कि इन वैंकों का जिन लोगों से सम्बन्ध रहता है वह निर्धन है और इनको लाभ भी बहुत कम होता है जिससे सुरचित कोष में पर्याप्त धन-राशि एकत्रित नहीं हो पाती । यह खेद का विषय है कि द्वितीत महायुद के समय त्रोर महायुद्ध के तुरन्त पश्चात् जब कृपकों की वित्तीय स्पिति सुघरी थी, इन वैंको की हिस्सा पूँजी बढाने का अवसर खो दिया गया। इन वेकों की हिस्सा पूँजी मे तभी वृद्धि की जा समती है जब कि कुषकों की वित्तीय स्थिति में सुघार हो प्रथम व हितीय पञ्चवर्षीय योजनास्रो की समाप्ति तक कृषको की वित्तीय स्थिति सुघर जायगी श्रीर तन वैंकों की हिस्सा पूँजी में वृद्धि को जा सकेगी।

(२) दोनों सस्याश्रों में कुछ मिथित तथा কुछ श्रमिथित वैंक हैं। श्रमिथित वेक सहपारिता के सिडान्त के अधिक अनुकूल होते हैं। परन्तु मिश्रित प्रकार के वेकों से यह लाम है कि इनका अधिक वित्त आप्त हो सकता है स्त्रोर साथ ही उन लोगों या ग्रविक सहयाग मिल सकता है जिनका कृषि से सम्बन्ध नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय कुषक श्रमी श्रविकिमित श्रवस्था में है यह वहत बढ़ा लाभ है। मिश्रित वेंकों से केवल यही हानि नहीं हैं कि इनका व्यवसाय सहकारिता के नियमों के श्रनुसार सामान्य नहीं होता बल्कि साथ ही इसका कमी-कभी हानिकारक परिग्राम भी होता है। विमिन्न व्यक्तियों को इन वैंकों के शेयरों को कय करने का अविकार है इसलिये इन वैंकों से ऋण लेने का भी श्रविकार है। व्यक्तियों को कृषि की उत्पत्ति के श्राघार पर भूग देना सहकारिता के नियमों के अनुकूल नहीं है क्योंकि इससे ये वैक उन दलालों की भी सहायता करते है निनको सहकारिता श्रान्डोलन समाप्त करना चाहती है। साथ ही इस प्रकार की सहायता से सहकारी विकय व्यवस्था के विकास में वाघा पहॅचता है। इसलिए यह उद्देश्य होना चाहिने कि 'मिश्रित' समितियों को कुछ समय तक रहने दिया जाय श्रीर बाट में कृपकों की श्रार्थिक स्थिति की सुधारने के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा इन सस्थात्रों को वित्तीय श्रावश्यकता पूर्ण हो जाने पर इन्हें श्रमिश्रित समितियों में बदल दिया जाय।

(३) वेन्द्रीय सहकारी वैक श्रविकतर निश्चित समय के लिये जमा श्रौर वचत को स्वीकार करते हें परन्तु सर्वोच्च वेक इनके अतिरिक्त चालू खाते में धन र्त्रीकार करते हैं। सर्गेच्च वैक ग्रीर कुछ सीमा तक केन्द्रीय सहकारी वैक साधारण व्यापारिक वेकों का व्यवसाम करते हैं। यह वैंक ड्राफ्ट देते हैं, हुएडी, चेक ब्रोर ऋ गपत्रों का नय-विकार करते हैं और सामान को सुरिह्मित रखते हैं। यह प्रश्न काफी विवाद प्रस्त है कि सहकारी सस्याय्रों का कार्य-चेत्र केवल सहकारी वैंकों के न्यवसाय तक ही सीमित रखा जाय या वे न्यापारिक वैकों का न्यवसाय भी करें। वर्तमान समय में सहकारी वैंकों का कार्य उनको न्यस्त रखने के लिये पर्याप्त नहीं है इसिलिये उन्हें न्यापारिक वेंकों का भी कार्य करना पड़ता है । यदि यह व्यवसाय न किया जाय तो वैकों की श्राय बहुत कम हो जायगी।

(४) इन सस्यात्रों को बहुत कम लाम होता है। इन सस्यात्रों का लाभ श्रीर सदस्यां का दिया गया लाभाश भारत के प्रन्य वैका का श्रपेका कम है।

व्याज दर-भाग्तीय रिजर्व वेक की हान की रिपोर्ट में वताया गया है कि अनेक राज्या में छाटी सहकारी समितियों के व्याज की दर काफी अधिक है। केवल वम्बई श्रोर मद्रास में जहा सहकारी श्रान्दोलन काफो सगठित हैं श्रीर काफी विकसित है व्याज की दर कुछ, कम रखना संभव हो सका है। अपनेक समितियों ने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि योग्य कुषकों को दिए जानेवाले ऋग पर अल्पकाल तथा मध्यकाल के लिए ६३ प्रतिशत से अधिक व्याज न लिया जाय श्रौर दीर्घकालिक ऋगु के लिए व्याज की दर ४ प्रतिशत होनी चाहिए। यह सिद्धान्त मद्रास श्रीर बम्बई में लागू रहा है। इन राज्यों की सरकारें घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देकर सहकारी वैकों को कम व्याज पर ऋण देने में सहायता कर रही हैं। इसके लिए सरकार बैक प्रशासन का कुछ भार स्वय वैंकों द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर श्रिधिक होने के कुछ कारण निम्न हैं—(१) सह मारी समितियाँ स्थानीय तीर पर पर्याप्त पूँ जी का सम्रह करने मे असफल रही हैं, (२) वम्बई श्रीर मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सहकारी बैक साधारणत छोटे हैं, इनके प्रवन्य का न्यय ग्रधिक है श्रीर त्र्यार्थिक दृष्टि से यह श्रनुपयुक्त हैं। यह श्रपना कारोबार तभी चला सकते हैं जब ऋगा लेने श्रीर देने की व्याज की दर में काफी श्रन्तर हो, ग्रीर (३) विभिन्न राज्य जो ऋण तथा त्रार्थिक सहायता से त्रान्दोलन की सहायता करते रहे हैं त्र्रव द्रव्य वाजार से <del>श्रावर्यक श्रृण ए</del>कत्रित करने में श्रीर परिणाम स्वरूप उसे कम व्याज पर विभिन्न सहकारी कार्यों में लगाने में विशेष कठिनाई श्रनुमन कर रहे हैं। रिजर्व वैक के मतानुसार निम्नलिखित प्रयत्नों से व्याज की दर कम की जा सकती है--(श्र) सहकारी त्रान्दोलन का दृढ बनाया जाय, उसकी कार्य कुशलता में सुधार किया जाय ख्रौर ग्राम्य चेत्रों की बचत को सम्रहीत करने पर जोर दिया जाय, (ग) श्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त इकाई का रूप देने के लिए सहकारी बैंकों श्रीर समितिया को एक में मिला दिया जाय ब्रौर समितियों के कार्यचेत्र का ज्यापक प्रसार किया जाय श्रौर (स) त्रारम्भ में राज्य सरकारें बम्बई की तरह आ्रायिक सहायता दें जिससे सहकारी वैकों को कम ब्याज लेने से जो घाटा होता है उसकी पृति की जा सके।

रिजर्व वैंक से ऋग् — रिजर्व बैंक एक्ट को घारा १७ (२) (ब) श्रीर १७ (४) (स) के श्रनुसार यह वैक सहकारी वैंको को कृषि उत्पादन श्रीर फसल वेचने के लिए विना घरोहर के श्रल्प कालिक श्रीर मध्य-कालिक ऋग देता है। घारा १७ (४) (श्र) के श्रन्तर्गत सरकारी प्रतिभृतियों श्रीर भृम वन्धक वैंकों के ऋग्यपत्रों की जमानत पर भी ऋग्य देता है। सन् १९५५ की फर्वरी से रिर्जव वैंक ने धारा

१ विस्तार पूर्वक अध्यन के लिये 'माम्य वित्त ध्यावस्था' का श्रध्याय देखिये

१७ (४) (ग्र) के श्रन्तर्गत तीन वर्ष की श्रविध के लिये मध्य कालीन भ्रमुण देना ब्रारम्भ कर दिया है। १६५३ के रिजर्व वैंक श्राफ इन्डिया एक्ट के संशोधन के कारगा यह सम्भव हो गया है कि १५ मदीने से लगाकर ५ वर्ष तक की श्रविध के लिये ऋगा दिया जा सके। इस नियम का प्रयोग करने के विचार मे ही वैंक ने तीन वर्ष की अवधि के स्थायी अपूरा, एक्ट की धारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत देना आरम्म कर दिया है, यद्यपि श्रिधिक लम्बी श्रविध श्रयीत् ५ वर्ष तक के श्रावेदनों पर श्रावश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता या। ऐसे श्राणों पर ब्याज कीर टर बैंक की दर से २% कम निश्चित की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा टी हुई गारन्टी श्रौर ऋगा लेने वाले पेन्द्रीय सहकारी वेंक श्रथवा समिति द्वारा लिये हुये प्रतिना पत्र ही इन ऋगों की जमानत थे। जिन कार्यों के लिये मध्य कालीन ऋगा दिये जा सकते थे वे वेकार भूमि को पुन. अधिकृत करना, बाँघ बनाना श्रथवा भूमि में किसी श्रन्य प्रकार का सुधार करना, वैल श्रादि जानवर परीदना, कृषि सम्बन्धी श्रीनार खरीदना तथा जानवरों की वींघने के वाडे श्रीर खेतों में गोदाम बनाना इत्यादि थे। रिजर्व बेक द्वारा राप्यीय सहकारी बैंक को दिये गये श्रमिम की राशि १६५१-५२ में ११ २६ करोड़ रु० थी। १६५७-५८ में यह बढ़कर ५७ १२ करोड़ ६० हो गई। इस ग्रायि के शन्त में देय भ्राणों की राशि ७ ८१ करोड़ र• मे बढ़ कर ३५ ११ करोड़ र० हो गई। १६५७-५८ में दिये गये ५७११ फरोड़ रु के कुल श्रिमिम में से ४१%१ करोड़ रु घारा १७ (४) (स) के श्रन्तर्गत, १२'७२ करोड़ ६० घारा १७ (४) (य्र) के श्रन्तर्गत तथा २ ६६ करोड़ ६० धारा १७ (४) (भ्र) के प्रन्तर्गत दिये गये।

श्रखिल भारतीय प्रामीण साख सर्वेच्चण समिति की सिफारिशों के श्रान-सार १० करोड़ ६० की प्रारम्भिक राशि से राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घंकालीन) कीप का निर्माण ३ फरवरी १९५६ को किया गया ताकि "राज्य सरकारी, (जिससे वे सहकारी समितियों की हिस्सा पूँजी में योग दे सकें) राज्यीय सहकारी वैंकों श्रीर भूमिवन्यक वैंकों को दीर्घ एवम् मध्यकालीन ऋगा दिये जा सकें।" जून १९५६ में इस कीष में ५ करोड़ ६० के वार्षिक अनुटान से वृद्धि की गई। मार्च १६५७ के श्चन्त तक २६८ करोड़ र० का ऋग् ११ राज्यों को टिया गया ताकि वे सहकारी सस्यात्रों की हिस्सा पूँजी में योग दे सके।

# ध्यध्याय १८

# कृपि नियोजन

मारत की प्रथम पद्मवर्णीय योजना ने कृषि नियोजन पर विशेष महत्व दिया था। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत २३५६ करोड़ रुपये के कुल ब्यय में से १५.१% (३५७ करांड़ रु०) कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनात्रों, तथा २८१% (६६१ करोड़ रुपये) सिंचाई तथा विद्युत शक्ति योजनात्रों पर ब्यय के लिये निश्चत कर दिये गये थे। द्वितीय पञ्चपन्पीय योजना के श्रन्तर्गत कृषि नियोजन का स्थान महत्वपूर्ण है, पर श्रिषक जोर श्रोद्योगिक विकास पर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम योजना में जो श्रस्तुलित होने का दोप श्रा गया था उसे दूर कर दिया गया है। द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ रुपये के कुल ब्यय में से कृषि तथा मामुदायिक विकास योजनात्रों को १६% (६१३ करोड़ रुपये) मिले हैं।

प्रथम योजना में कृषि पर विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में योजना श्रायोग न टो तर्फ टिये थे-(१) जा योजनाएँ पचलित है उनको पूर्ण करने की श्रावश्य-कता है ग्रार (२) जब तक खादान का श्रीर उद्योगों के लिये ब्रावश्यक खनिज पदाथा का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर लिया जाता श्रीचोगिक विकास के कार्यक्रम में विशेष प्रगति ला सकता सम्भव नहीं है। इसमे सन्देह नहीं कि उद्योगों का विकास करने के लिये खनिज पदायां श्रीर खायान्न की श्रावश्यकता होती है। यदि यह सामाग्रयाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जॉय तो भारतीय उद्योग को विकसित करने मे निश्चय ही सहायता मिल सकती है। इसके साथही भारत की अधिकॉश जनता कृषि कार्य करती है। कृषि में मुधार करने से इनकी श्राय में वृद्धि होगी श्रीर परिणाम स्वरूप रहन सहन में सुधार होगा। परन्तु इतने पर भी योजना श्रायोग द्वारा क्रांप को प्रधानता दिये जाने की कड़ी श्रालोचना की गई थी। भारत की श्राधिक व्यवस्था ग्रयन्तुलित है, क्योंकि उद्योगों का विकास करने की पूर्ण सम्भावना होते हुये भी श्रव तक उद्योग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। इस तथ्य की ऋोर ध्यान न देकर निरन्तर इस वात पर महत्व दिया जा रहा है कि कृषि का विकास करने की विशेष श्रावश्यकता है। पचवर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने पर इस ब्रसतुलित व्यवस्था के दूर होने की सम्भावना नहीं है। वास्तव मे

सम्भावना में इस वात की है कि योजना के परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था दृदतर हो जायगी। यदि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण करते समय उद्योगों पर श्रिषक ध्यान दिया गया होता तो इस टोप के दूर हो सकने की श्राशा थी श्रौर भारत का श्रौर श्रिषिक सन्तुलित विकास हो सकता था। यदि योजना श्रायोग उद्योगों के विकास पर महत्व टेता तो इससे कृषि के विकास की समुचित व्यवस्था करने में उसकी किसी बाधा का सामना नहीं करना पडता। दूसरे, पह बिल्कुल सहीं है कि भविष्य में ब्रीबोगिक विकास करने के लिए इंड श्राधार का निर्माण किया नाय परन्तु इस वात पर केसे विश्वास कर लिया जाय कि भारत की कृषि का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात् उन्नोगों का इस स्तर तक विकास कर लिया जायगा कि उसमें उस समय उत्पादित कच्चे माल श्रीर विजली इत्यादि का पृर्ण उपभोग हो सकेगा। यह बहुत सम्मव है कि उस समय तक भ्रन्य देशों ने उद्योग भ्राधक शक्ति शाली हो जार्येंगे श्रीर मारतीय उद्योग के लिये नवीन समस्याएँ उत्पन्न कर दें। योजना श्रायोग उद्योगों का श्रोर श्रविक विकास करने और मारतीय कृषि से उपलब्ध न हो सकने पर खात्राज तथा कच्चे माल का आयात करने की व्यवस्था कर सकता था जैसे जापान भ्रौर ब्रिटेन ने किया। यदि उद्योग श्रोर क्वांप दोनों का साथ साथ विकास किया जाय तो भारत का आर्थिक विकास ख्रोर श्रिधिक सन्तु ितत हो नायगा श्रोर उद्योग तथा कृषि के विकास का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो जायगा। योजना में कृषि पर श्रावश्यकता से श्रविक महत्व दिये जाने से कृपि तथा उद्योग के विकास में सन्तुलन स्थापित कर उनका सुनियोजित विकास करने में बाघा पहुँचेगी जब कि नित्रोजन का श्राघार ही सन्तुलित श्रीर कम वड विकास करना है।

प्रथम योजना—प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि की सर्वतोन्मुखी उन्निति का प्रवन्न किया गया था। उसके ग्रन्तर्गत कृषि उत्पत्ति के ग्रुतिरिक्त पशु-सुधार, सहकारी प्रादोलन का विकास, गन्यशाला, वन, भूमि सरक्ष्ण तथा पचायतों के विकास श्रोर सुवार की योजनाएँ सम्मिलित थीं। भारत को केवल खाद्यानों श्रीर उद्योगों के लिये कञ्चे माल के उत्पादन में ही श्रात्म निर्भर बनाने पर विशेष व्यान नहीं दिया गया था, वरन ग्रामीया जनता के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने तथा प्रति व्यक्ति वाधिक उत्पादन में भी वृद्धि करने का विचार किया गया था। प्रथम योजना में कृषि तथा सामुदायिक विकास योजनाश्रों पर व्यथ किये जाने वाले ३५७ करोइ दियो गंदी दिस्तार सेवाश्रों पर तथा सामुदायिक योजना चेत्रों पर, ६० करोइ दियो पश्रुप विस्तार सेवाश्रों पर तथा सामुदायिक योजना चेत्रों पर, २२ करोइ दिया पश्रुप पालन पर, १५ करोइ दिया या पश्रुप पालन पर, १५ करोइ दिया विस्तार सेवाश्रों पर तथा सामुदायिक योजना चेत्रों पर, २२ करोइ दिया पश्रुप पालन पर, १५ करोइ दिया

स्थानीय सुघार कार्यों पर, ११ करोड़ आम पचायतों पर, १० करोड़ बनो पर, ४ करोड मछली पकड़ने के कार्यों पर, ७ करोड़ सहकारिता पर छीर १ करोड़ रुपये ग्रन्य वार्तों पर न्यय करने के लिये नियत किये गये थे।

प्रथम योजना का िंचाई सम्बन्धी तथा विद्युत शक्ति के विकास का कार्यक्रम बहुत ही विशद था। यह कार्यक्रम उन योजनाश्चों पर श्राधारित था जो योजना के पूर्व से ही प्रचलित थीं। योजना में इन योजनाय्रो को ग्रागे बढाने का भवन्ध किया गया था। परन्तु इनकी सख्या इतनी आधक थी कि सम्पूर्ण योज-नाम्नों को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि कासी, कोयना, कृष्णा, चम्बल श्रोर रिहन्ड योजनाश्रों को योजना काल के श्रतिम भाग में लिया जायगा। ६६१ करोड़ रुपयो के कुल ब्यय में से ३८४ करोड़ सिंचाई के लिये, २६० करोड़ विद्युत योजना के लिये श्रीर १७ करोड़ बाढ नियत्रण तथा श्रन्य खोज कार्यों के लिये नियत किये गये। प्रथम योजना का लक्ष्य सोंची जाने वाली भूमि का चेत्रफल ५१० लाल एक ह से, जो कि १६५०-५१ में था, बढ़ा कर ६७० लाख एकड़ १९५५-५६ तक करने का ग्रोर विद्युत शक्ति का उत्पादन २३ लाख क्लोबाट से बढाकर ३४ लाख किलोबाट वर देने का था। यिंद इस विकास योजना को दीर्घ कालीन दिष्ट से देखा जाय तो यह त्राशा की जा सकती थी कि २० वर्षों के अन्तरौत ही ४०० लाख मे लगाकर ४५० लाख एकड़ तक अतिरिक्त भूमि िंचाई के अतर्गत आ जायगी और वर्तमान विद्युत शक्ति की मात्रा जो उत्पादित की जा रही है उसमें ७० लाख मिलीवाट की ग्रीर अधिक वृद्धि हो जायगी। यह कार्यक्रम का वटा ही श्रेष्ठ आदर्श है श्रीर यदि पूर्ण हो गया तो भारतीय ग्राम्य भ्रार्थिक व्यवस्था की रूप रेखा बदल जायगी।

प्रथम योजना में कृषि नियोजन की तीन प्रमुख विशेषताएँ थीं—(१) सम्पूर्ण कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा सचालित किया जायगा छोर उद्योगों के विपरीत निजी व्यवसाय का इसमें कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य में काफी दीर्घ श्रविष के पश्चात् लाम श्रजित किया जा सकता है श्रीर रुपयों के रूप में तुरन्त लाभाश प्राप्त नहीं होता। विगत वपो में निजी उत्योग इस प्रकार के कार्यों से पृथक रहा है। इसिलये स्वामाविक ही योजना श्रायोग ने इस कार्य का सचालन करने के लिये निजी उत्योगों को उपयुक्त साधन नहीं समक्ता। श्रायोग को निजी उद्योगों की कार्यच्चमता पर विश्वास नहीं हो सका। श्रायोग को श्रवसार राज्य सरकार सिंचाई तथा विद्युत योजना कार्यों का प्रवन्य करेगी श्रोर केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के इस कार्य में उचित सम्बन्य स्थापित करेगी तथा श्रन्थ सामान्य सहायता देगी, (२) दीर्घकालीन योजनाश्लो पर

विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार की योजनात्रों में होने वाले लाम का अनुभर १५ में २० वर्ष के पश्चात् विया जा सकेगा जब कि भारत की कृषि का पूर्ण विकास हो चुकेगा। यद्यपि दीर्घवालीन योजनात्रां पर महत्व दिया गया है, किर भी अल्पकाल में ताबान्न तथा उत्योग के लिये आवश्यक उच्चे माल के उत्यादन में वृद्धि करने जी भी समुचित व्यवस्था की गई है। जैसा कि 'कृषि उत्यादन से वृद्धि करने जी भी समुचित व्यवस्था की गई है। जैसा कि 'कृषि उत्यादन से स्वाद्य में बताया गया है, वह आशा भी जाती है कि तावाल के सम्बन्ध में भारत को याजना की अविध में ही स्वावलम्बी बनाया जा सकेगा आग क्यास तथा त्र के सम्बन्ध म मारत की विदेशों पर निर्मरता को कम किया जा सकेगा, (३) इस याजना का उद्देश्य केयल कृषि उत्यादन में वृद्धि ही नहीं विलक्त प्राप्य-जीवन का बहुमुनो विकास भी करना है।

दितीय योजना—प्रथम योजना का प्रमाव दितीय योजना में पूर्ण कर दिवा गया त्रार उत्रोगों को प्रमुण स्थान दिया गया है, जो कि न्यापपृष्य प्रोर उाचत था। इसने भारत के विकास की प्रसन्तित प्रयस्था सुघर जापनी श्रीर राष्ट्रीय प्राय में प्रधिक तीय गिन में वृद्धि हागी प्रोर कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्राप्त हो सकेंगे। दितीय योजना के प्रन्तर्गत ४=०० वरोड़ कपयों के विकास कार्य कमों पर नियत व्यय म में १८५% उत्योगों ग्रीर राान गाटने पर, २८६% सचार तथा याता गत पर, ११८% (५६= कगेड क०) कृषि तथा सामुदायिक विकास पर, ग्रार १६% (६१३ करोड कपये) सिचाई तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन पर व्यय किया जापना। यद्यपि दितीय योजना में उद्योगों श्रीर पातायात को प्रधिक महत्ता दी गई है पर कृषि तथा सिचाई को छोड़ नहीं दिया गया है। दिवीय योजना में किया नियन की मुक्त विचारसीय वार्ते नियन हैं—

(त्र) कृषि सुवार सम्बन्धो कार्य कमा ने यह आशा की जाती है कि बढ़ी हुई जनस्त्वा के लिये पर्याप्त पाटा सामग्री तथा विकसिन उद्योग व्यवस्था के लिये क्या माल दे सकेंगे प्रार इतनी कृषि उत्यक्ति वच रहेगे कि उसना नियांत मो किया जा सकेगा। इसलिये यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना ने प्रयम योजना की प्रयेना कृषि तथा श्रन्य उद्यागों के विकास कार्यक्रम में अविक पारस्परिक्त निर्मरता का श्रायोजन किया गया है। इन व्येगों को प्राप्त करने के कार्यक्रमा को निर्माण करत समय दीर्वकालीन दृष्टिकोण रखना श्रावश्यक है ताकि भोतिक साधनों प्रोर मानव अम का सर्वोत्तम प्रयोग, कृषि का सर्वतिनमुखी सत्रुक्ति विकास श्रार प्राप्त वास्ति सम्भव हो सके। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण करने में यह श्रावश्यक है कि ग्राम के सन्मुख एक ऐसा श्रादर्श उपस्थित कर दिया

नाय निसे प्राप्त करने में वे प्रयन्नशीन हो सकें। द्वितीय योजना निर्माण के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यह त्रादर्श १० वर्ष के श्रन्तर्गत ही उत्पादन को निसमें -खाद्यान, तिलहन, कपास, गन्ना, पशु पालन से प्राप्त वस्तुएँ इत्यादि सम्मिलित होंगी दुगनी कर देगा।

- (व) कृषि उत्पत्ति को अनेक-रूपता प्रदान करना आरे खाद्यात्र सम्बन्धी फसलों को अब तक जा प्रधानता दो जाती थी उसे बदलना आदर्श होगा। द्वितीय योजना मे ऐसी फसलों की वृद्धि भी है जैसे सुपाडी, नारियल, लाख, काली मिर्च, वृक्कफल इत्यादि जिन की ओर प्रथम योजना मे कोई विशेष व्यान नहीं दिया था।
- (स) क्रांप के चेत्रफल की वृद्धि करने की सम्मावना तो बहुत सीमित है। जो थोडी बहुत वृद्धि कृषि के चेत्रफल में सम्मव होगी उससे मोटे छन्न के ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती चलंगी वैसे-वैसे मोटे श्रन्न की माँग गेहूँ और चावल की माँग में बदल ही जायगी। ऐसी स्थित में कृषि उत्पत्ति में वृद्धि का मुख्य स्रोत अधिक कुशल, लाभटायक तथा धनी खेती ही होगा।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत कृषि नियोजन की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—(१) भूमि के प्रयोग का नियोजन, (२) दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों का निश्चित करना, (३) उत्पादन लक्ष्यों तथा भूमि प्रयोग योजनास्रों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देना, और (४) उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण करना।

द्वितीय योजना में ५६८ करोड़ रुपयो के न्यय में से १७० करोड रुपये कुषि कार्यक्रमों पर, २०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय विस्तार योजनात्रों पर, ५६ करोड़ रुपये पशुपालन पर, ४७ करोड़ रुपये वनो ह्यौर भूमि सरस्य पर, १५ करोड़ रुपये स्थानीय विकास पर, १२ करोड़ रुपये पचायतो पर, १२ करोड़ रुपये मछली पक-इने के न्ययवसाय पर, ४७ करोड़ रुपये सहकारिता पर जिसके श्रन्तर्गत भाएडागार तथा विक्रय सुविधाये भी सम्मिलित होगी, श्रौर ६ करोड रुपये श्रन्य विविध बातों पर न्यय किये जायेगे। इस प्रकार प्रथम योजना की तुलना में कृषि पर कुल न्यय कम हो गया है। स्थानीय विकास कार्यों तथा श्राम पचायता पर लगमग समान ही है श्रोर राष्ट्रीय विस्तार सेवार्श्रों तथा सामुदायिक योजनात्रों, पशुपालन, वन तथा भूमि संरच्या श्रीर सहकारिता पर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है।

कठिनाइयाँ—भारत में कृषि नियोजन को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं योजना को सफल बनाने के लिये सर्व प्रथम कृषक का स्वेच्छा से सिक्षय सहयोग आवश्यक है, परन्तु भारतीय कृषक अधिकतर रूढिवादी है और प्रत्येक बात पर परम्परागत दृष्टिकोण से ही विचार करता है। वह इस वात के लिये प्रस्तुत नहीं कि परम्परा की रूढि छोइकर कुछ नवीन प्रयोग किये जाँय। अतीत में कपकों की स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक प्रयक्त किये गये परन्त क्रमको की उदासीनता के कारण उनमें से अधिकाश असफल रहे। पचवर्षीय योजना में कहा गया है कि कृषि के चेत्र में विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये और निर्धारित लस्य तक पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि जनता सहयोग दे। जिना जन-सहयोग के समाज कल्याय की योजना सफल नहीं हो सकती। कपि विकास कार्यक्रम उसी सीमा तक सफलता पूर्वक कारान्तित हो सकता है जहा तक जनता उत्साह श्रीर त्वेच्छा से उसके लिये कार्य करने को प्रस्तुत हो। कृपकों का सिक्य सहयोग प्राप्त करने के लिये यह त्रावश्यक है कि (१) विभिन्न उपायों से क्रपकों को यह विश्वास दिलाया जाय कि योजना उपयुक्त है श्रोर इसके कार्नान्वित होने से उनका लाभ होना निश्चित है, (२) योजना लागू करके शीघ ही ऐने परिखाम निकाले जाने चाहियें जिनसे क्रवकों में विश्वाध उत्पन्न हो श्रीर उन्हें प्रेरणा मिले श्रीर जिनको वह स्वय श्रांंंंं ने देख श्रीर परख सकें। यदि योजना का उद्देश्य दीर्घकालीन लध्य की प्राप्ति करना हो तो क्रवकों में योजना की निश्चित उपयोगिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना कठिन हो जायगा। मूल्य श्रिधिक होने से, वेरोजगारी में वृद्धि से श्रीर व्यापक श्रापिक कठिनाइया के कारण वही योजनाश्रों को एफलता पूर्वक लागू करने में सरकार की समर्थता पर क्रवकों में विश्वास घटता जा रहा है, श्रीर (३) जनवा में योजना लागू करने के लिये उत्तरदायी पूर्ण श्रिषकारियों की ईमनाटारी और समता पर विश्वास उत्पन्न किया जाये। यदि जनता प्रशासन के इर त्तर पर भ्रष्टाचार देखे, उसे सब स्थानों पर कार्य में श्रनावज्यक देरी तथा श्रकुशलता का सामना करना पढे श्रीर यदि उसे यह मालुम हो कि समाज का शोपण कर समाज की हानि से लाभ उठाने वाले हानिकारक तत्वों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जा रही है तो जनता को उत्साहित कर उसका सिकय सहयोग पाप्त कर सकना श्रत्यन्त कठिन हो जायगा।

कृपि नियोजन की सफलता श्रन्य योजनाओं की तरह सम्बन्धित श्रांध-कारियों की कार्यक्षमता श्रोर ईमानदारी पर निर्मर करती है। योजना श्रायोग ने बताया है कि कार्यक्रम की सफलता की गति प्रशासन संगठन, उसकी कार्य-कुलता श्रोर उसके द्वारा प्रेरित जनता के सहयोग पर निर्मर करती है। प्रशासन को श्राल गत वर्षों की श्रपेक्षा श्रिषक बढ़ी श्रोर जाटल समस्ताश्रों का सामना करना पढ रहा है। यह समस्याएँ बढ़ी श्रोर जाटल श्रवश्य हैं, परन्तु श्राज इनके महत्व में श्रीत की श्रपेक्षा कहीं श्रिषक वृद्धि हो गई। योजना के कार्य का सफलतापूर्वक सचालन करने के लिये शिद्यित, कुशल श्रीर ईमानदार श्रिध-कारियों का श्रमान है। कार्य बहुत निशद है, परन्तु निभिन्न योजनाश्रों का कार्य सॅमालने के लिये शिक्तित कर्मचारी पर्याप्त सख्या मे नहीं हैं। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के श्रनेक जिला, राजस्व तया श्रन्य श्रधिकारी हैं, जिनमें से कुछ बहुत कुशल और परिश्रमी हैं, परन्तु खेट है कि इन श्रधिकारी मे से अनेक प्राचीन प्रया के अनुकूल चलते हैं ख़ौर कुपकों से ख़पने को काफी दूर रखते हैं। इन छाधि-कारियों की दृष्टि में रचनात्मक कार्य की श्रपेद्धा कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने का श्रधिक महत्व है, इससे यह श्रधिकारी योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपमुक्त सिद्ध नहीं हो सकते । 'ग्रधिक-ग्रन उपनात्रो' नथा ग्रन्य ग्रान्टोलनो के सम्बन्ध में अनेक ऐसी घटनायें प्रकाश में आई है जिनसे पता चलता है कि श्रिधकारियों ने बीज, खाद तथा रूपया कुपकों तक पहुँचाने को श्रेपेज्ञा केवल कागजा में खान। पूर्ति की श्रीर रुपयां को स्वय इड्प लिया। इससे योजना को सफल बनाने में सफलता नहीं मिल सकती और जनता का उस पर ने विश्वास उठ जाता है। पचवर्षीय याजना में इस बात पर महत्व दिया गया है कि सर्वप्रथम प्रशासन में निष्ठा, कुशलता, बचत श्रीर सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने की श्रावश्यकता है। याजना मे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये श्रनेक सुकाव दिये गये हैं। इनकी पृति मे अवश्य काफी समय लगेगा। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को छाँटने श्रीर उनको उचित ट्रेनिंग देने के साथ ही पचवर्षीय योजना में सम्बन्धित श्रिधिकारियों की कार्यज्ञमता, निष्ठा श्रीर ईमानदारी मे सुधार करने के लिये अनेक सुकाव दिये गये हैं इनमें से कुछ सुकाव इस प्रकार हें—(१) प्रशासन सम्बन्धी, राजनीतिक तथा अन्य पदों पर कार्य करने वाले श्रधिकारियों पर भ्रष्टाचार के श्रारोपों की जॉच करने के लिये उपयुक्त न्यवस्था की जाय । यदि अपराध स्पष्ट हो तो तथ्यों का पता लगाने और अपराध सिद्ध करने के लिये तुरन्त जॉच की जाय। (२) वर्तमान कानून में ऐसे मामलों के लिये व्यवस्था की गई है जिनमे सरकारी कर्मचारी त्राय के गैर कानूनी साधनों का उपमोग करता है श्रीर उन साघनों के सम्बन्ध में सन्तोपजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता । परन्तु वर्तमान कानून के अनुसार ऐसे मामलों की जाँच करने की व्यवस्था नहीं है जिससे यह जात हो कि अ्रमुक सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार एकाएक धनवान कैसे हा गये। इसिलये कानून के इस स्रभाव को पूरा करने के लिये श्रध्ययन किया जाय श्रीर उपयुक्त कानून बनाया जाय। (३) ऐसे श्रिधकारी को जिसकी ईमानदारी पर सन्देह किया जाता है बढे उत्तरदायित्व के पद पर नहीं नियुक्त करना चाहिये।

भारतीय ग्राम्य जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनमें कृषि नियोजन के वार्च में बाघा पहुँचती है। ग्रामों में श्रव्छी सबकों, सिचाई तथा अन्य सुवि-भाग्नों का त्रभाव है। कृपकों के इन ग्रभावों की शीव पूर्ति करने की श्रावश्य कता ई, परन्तु यदि इन कार्यों पर ऋधिक यान दिया जाय तो बहुमुखी ज्यापक कार्यक्रम को लागू करने में श्रानेक कठिनाइयाँ पेटा हो जायँगी। यदि टीर्धकालीन योजनायों पर श्रिविक व्यान दिया गया तो स्थिति में सुधार करने की शीघ फल-टायक योजनाएँ लागु करने की सम्भावना कम हो जायगी। यह सम्भव है कि दीर्घनालीन ग्रीर ग्रहरकालीन टोनो प्रकार की योजनात्रों पर व्यान दिया जाय परन्तु इससे प्रगति की गति मन्द हो जाती है और कार्य तजी से आगे नहीं वह पाता है। जमींदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की ग्रन्य प्रथाओं के उन्मूलन से अने क नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। ग्रामो से महाजनों श्रीर साहकारों के घीरे वीरे समाप्त हो जाने से नई कठिनाइयों मे वृद्धि हुई है। इससे एक खाई उत्पन्न हो गई है जिसको श्रमी तक नई न्यवस्था से पाटा नहीं जा सका है। भारतीय कृषक एक दुष्चक में फला हुआ है। वह निर्धन है क्योंकि अच्छे प्रकार का बीज, अन्छे पशु श्रौर खाद इत्यादि खरीदने के लिये उसके पास द्रन्य नहीं है, श्रीर जब तक वह घनी नहीं वन जाता तब तक वह इन वस्तुश्रो का कय कर सकने के साधन नहीं जुटा सकता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि कृपको की ऋ्र्य लेने की ज्ञमता नहीं है। वह जमानत न रख सकने के कारण सहकारी वैंकों तथा ऋण नहीं देने वाली श्रन्य सस्याश्रो से ऋण नहीं ले सकता है। ग्रौर जब नक कृपको को ग्राधिक व्यवस्था ग्रज्छी नहीं हो जाती वह इन सायनों को नहीं सुटा सकता है। यही कारण है कि शताब्दियों से भारतीय कृषक निर्धनता श्रौर दुखों में फला हुया है। कृपि नियोजन को सफल वनाने के लिये क्रपकां की इन कठिनाइयों को दूर करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

# श्रध्याय १६ वड़े पैमाने के उद्योग

मारत में श्रनेक बढ़े उद्योग हैं परन्तु श्रौद्योगिक च्रेंच में श्रमी ब्रिटेन में १८वीं शताब्दी में हुई श्रौद्योगिक क्रान्ति के समान श्रोद्योगिक क्रान्ति यहाँ नहीं हुई है। भारत में प्रति ब्यक्ति श्रौद्योगिक उत्पादन की मात्रा बहुत कम है श्रौर हन उद्योगों में देश की जन संख्या का बहुत कम माग लगा हुश्रा है। भारत के कारखानों में प्रदिदिन कार्य करने वाले श्रामकों की श्रौसत सख्या १६३६ में १६ लाख थी जो बढ़कर श्रव २५ लाख हो गई है। देश की ३८ करोड जनसख्या को देखते हुये यह बहुत कम है। देश में नवीन उद्योगों का विकास करने के लिये काफी बड़ा चेत्र खुला पड़ है श्रौर वर्तमान उद्योगों के उत्पादन में भी श्रिषक वृद्धि की जा सकती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय उद्योग की दो प्रमुख विशेपताएँ थी—
(श्र) कुछ उद्योगों में जैसे स्ती कपडा श्रीर चीनी उद्योग में बहुत श्रिवक श्रमिक कार्य करते ये श्रीर ये उद्योग श्रावश्यकता से श्रिवक उत्पादन करते ये, (व) इसके साथ ही वहें रसायनिक, इजीनियरिंग श्रीर इसी श्रेणी के श्रन्य उद्योग थे ही नहीं। युद्धोत्तर काल में कुछ सीमा तक इन दोपो को दूर कर दिया गया है। यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुश्रों के लिए भारत को श्रायात पर निर्भर करना पड़ता है फिर भी देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुश्रों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इन वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है श्रीर ऐसी सम्भावना है कि भविष्य में श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिये इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा। श्राशा की जाती है कि भाग्तीय श्रीद्योगिक विकास में जो ग्रभाव शेप हैं उनको पचवर्षीय योजना के श्रीद्योगिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करके पूर्ण कर दिया जायेगा।

## सूती कपडा उद्योग

भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका युद्ध के पश्चात् विशेष रूप से विकास हुद्या है। विश्वयुद्ध के पश्चात् कपड़ो की मिलो की सख्या में काफी वृद्धि हुई है। देश का विभाजन हो जाने से मिलो की सख्या १६४७ में ४२३ से गिरकर १६४८ में ४०८ रह गई थी परन्तु नवीन मिलों की स्थापना से ब्रौर प्रचीन मिलों में मशीन इत्यादि बढ़ा देने से भारतीय

स्ती मिला की उत्पादन शक्ति में काफी वृद्धि हो गई है। १६५१ में मारत में ४४५ मिलें यी जिनमें १ करोड़ १२ लाय ४० हजार तकुए (Spindles) श्रोर २,०१,४८४ वर्षे ये पर १६५७ के श्रन्तर्गत में ४६६ मिलें हो गई जिनमें १२६ लाख तकुए श्रोर २०६,१२६ कर्षे हो गये। कई नई मिलें स्थापित की जा रही हैं श्रोर श्राणा की जाती है कि इन मिलों द्वारा उत्पादन श्रारम्म होने पर मारतीय स्ती मिला की वाम्तविक उत्पादन शक्ति में मुख्यत कताई मिलों (spinnig mills) में, श्रीर वृद्धि हो जायगी।

क्छ मिलों में नेवल सत नाता जाता है श्रीर अन्य में सूत की कताई श्रीर वुनाइ टाना होती है <u>। युद</u> के पश्चात् काल की योजना समिति ने श्रनुमान लगाया कि अधिक दृष्टि से कताई-बनाई टाना कार्य करने वाली अनुकूलतम त्राकार की मूता मिल मे २५ हजार तकुए श्रार ६०० करघे होने चाहिये । परन्तु टभाग्यवश श्रिपनाश मिलें । अनमे कताई बनाई दोनों कार्य होते हैं श्रीर जिनमें केवल-कताई होती है श्रार्थिक हिन्द से श्रनुक्लतम श्राकार की मिलें नहीं कही जा सकती। स्त्री कपडा उत्रोग की वांकड़ पार्टी के अनुमान के अनुसार लगम्ग १५० मिली में अनार्थिक हैं। इसके साथ ही अधिकाश मिलों में पुरानी और विसी पिटी मशीनें हैं। बम्बई मिल-मालिक सच के अनुमान क अनुसार बम्बई की मिलो में ६०% मशीने २५ वर्ष से भी अधिक पुरानी है। सूती कपड़ा उद्योग के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान मिलो को श्रायिक दृष्टि से उपयुक्त स्तर पर लाया जान, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई श्राधनिक मशीनें लगाई जाय श्रीर उन्हें त्रावर्यक श्रोद्योगिक प्रसाधनों से सुसन्जित किया जाय। दूसरी भ्यान देने योग्य वात यह है कि देश के अन्य मागों जैसे मद्रास, मन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मन्त्र भारत में इस उद्योग का विकास हुत्रा परन्तु फिर भी यह उद्योग बम्बई में ही श्रिविक केन्द्रित है। कुल उद्योग में जितने तकुए श्रीर करचे उपयोग में लाये जाते हैं उनके ६० प्रतिशत केवल वम्बई में हैं। इसलिए भविष्य में विकास करते समय उद्योगों के स्थान-निर्घारण की समस्या पर विशेष ध्यान देना पडेगा। स्थानी करण की स्थिति में सुधार श्रावश्यक है।

उत्पादन की प्रवृत्तियाँ—१६४४ में सूती कपडे श्रीर १६४६ में सूत का उत्पादन श्रिषकतम श्रयांत क्रमश. ४८५२० लाख गाज श्रीर १६८५० लाख मीरह था। यह उत्पादन १६५० में गिरकर ६६६५० लाख गाज श्रीर ११७५० लाख पौरह हो गया। १६४६ श्रीर १६५० में उत्पादन के गिरने के मुख्य तीन कारण ये—(१) १६४७ में देश का विभाजन हो जाने से कच्चे माल की कमी हो गई श्रीर पाकिस्तान तथा श्रन्य देशों से रूई का श्रायात करने में श्रनेक कठिनाहयाँ

उत्पन्न हो गई, (२) उद्योगों में श्रमिकों के कागडे में वृद्धि हुई, श्रीर (३) विद्युत शिक्त पर्याप्त न होने के कारण बम्बई मिलों को दीं जाने वाली विद्युत कम कर दी गई। घीरे घीरे हन कठिनाहयों को दूर करके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। स्ती कपड़ा उद्योग में श्रमिक तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुघार हुआ, उत्पादन शिक्त में वृद्धि की गई श्रीर देश में कपास की उत्पत्ति में वृद्धि से कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप १६५१ में सूती कपडे और स्त का उत्पादन कमश: ४०७६० लाख गज श्रीर १३०४० लाख पीएड श्रीर १६५२ में ४५६८० लाख गज श्रीर १४५०० लाख पीएड हो गया। मिलों द्वारा कपास के क्रय पर से नियंत्रण के हटजाने के कारण, रई श्रीर कपड़ों के यातायात के लिये मालगाड़ियों के मिलने तथा माँग की वृद्धि से उत्पादन में श्रीर श्रधिक वृद्धि हुई है। इसके परि-णाम स्वरूप सूती कपड़ों श्रीर सूत का उत्पादन बढ़कर १६५७ में कमश: ५३१५० लाख गज श्रीर १७७६० लाख पीएड हो गया।

मारत की स्ती मिलों में पहले मोटे कपडे का ही श्रिधिकतर उत्पादन किया जाता या परन्तु प्रशुल्क मस्डल (टिरिक्नोर्ड) की सिकारिशों के श्रनुसार उत्तम प्रकार के कपंडे का उत्पादन धरीने के लिए रहर्य से रहर तक कांकी रुपया लगाकर श्रनेक टेकनिकल सुधार किये गये परन्तु उद्योग का पुनर्संक्षटन कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध श्रारम्भ हो गया। युद्ध के लिए सैनिक मागों तथा श्रन्य श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये उद्योग को फिर मोटे तथा माध्यम वर्ग के कपंडे का उत्पादन करना पड़ा। इसमें कुछ श्रीर रुपया लगाना पड़ा जिससे उद्योग पर कांकी मार पड़ा। परन्तु इधर कुछ वर्षों से मोटे श्रीर श्रन्युक्तम प्रकार के कपंडे के स्थान पर मध्यम श्रीर उत्तम प्रकार के कपंडों के उत्पादन में वृद्धि की गई। यह एक वान्छनीय प्रवृत्ति है श्रीर हम यह श्राशा कर सकते. हैं कि मिविष्य में देश की माग पूरी करने तथा निर्यात के लिए इस उद्योग को महीन श्रीर मध्यम श्रेणी के कपंडों की उत्पत्ति बढ़ानी पढ़ेगी।

कच्चा माल श्रिपनी पूर्ण वास्तविक उत्पादन शक्ति के बराबर उत्पादन करने के लिये मारतीय सूती का कपड़ा उद्योग को लगमग ५२ ५ लाख गाठ कपाच की श्रावश्यकता होती है। विभाजन होने से देश में कपाच का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। मारतीय मिलों को श्रावश्यकता पूरी करने के छाथ ही विदेशों को भी कपाच निर्यात किया जाता था जिससे उत्योग को कच्चे माल के श्रमाव की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। देश विभाजन के पश्चात स्थित में परिवर्तन हो गया। देश में कपास का उत्यादन गिर गया। १९४७-४८ में २२ लाख श्रीर १९४८-४६ में १० लाख गांठों का उत्यादन किया जा सका। हरसे

उद्योग के सम्मुख कन्चे माल के श्रमाव का गमीर सकट उत्पन्न हो गया। सामान्य स्थिति में कपास का श्रायात करके इस सकट को दूर किया जा सकता था परन्तु पाकिस्तान ने भारत को श्रावश्यकता के श्रनुसार कपास नहीं दिया। पाकिस्तान के श्रतिरिक्त श्रन्य देशों की कपास का भाव वहुत श्रिष्क था श्रीर भारतीय सती कपड़ा उद्योग के श्रनुकूल नहीं था। परन्तु १६५७-५८ में कपास का उत्पादन ५० लाख गाठें से कुछ ही कम था श्रीर इस प्रकार श्रमत कन्चे माल की कमी पूरी हो गई। द्वितीय पद्मवर्षीय योजना के श्रतगंत कपास के उत्पादन में श्रीर भी वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे स्ती कपड़ा उद्योग के कन्चे माल की कठिनाई का बहुत कुछ दूर किया जा सकेगा।

निर्यात—१६४८-४६ के विपरीत १६५०-५१ में स्ती कपड़े श्रीर स्त के निर्यान में श्रपेज्ञाइत वृद्धि हुई है। १६४८-४६ में ३४१० लाख गज कपड़ा श्रीर ७४ लाख पीयह स्त देश से बाहर मेजा गया। १६५०-५१ में १२६६५ लाख गज कपड़ा श्रीर ७४५ लाख पीयह स्त विदेश मेजा गया इस वृद्धि का कारण यह है कि भारतीय माल का मूल्य श्रपेज्ञाइत कम रहा श्रीर साय ही विदेशी वाजार पर श्रिष्कार जमाने के लिये भारतीय मिल मालिकों ने जोरदार प्रयक्ष किये।

परन्तु वाद में स्थिति फिर बटली श्रोर निर्यात की इसी स्तर पर स्थिर नहीं रखा ना सका। १९५२ ५२ में निर्यात की मात्रा घटनर ४२३७५ लाख गन कपडे ग्रीर ६२५ लाख पोयड सूत तक पहुंच गई। इस कमी के कारण निम्न-लिखित हैं -(१) स्ती कपटे श्रीर स्त के उत्पादन में कभी श्राजाने से श्रविक माल का निर्यात नहीं क्या जा सका ख्रीर सरकार ने क्पडे-के निर्यात पर प्रति-बन्घ लगा दिये। (२) निर्यात कर लगाने से भारतीय स्ती माल का मूल्य बढ गया। मारतीय स्ती उद्योग ने बरावर यह माग की है कि निर्यात की मान्ना वढ़ाने के लिये सरकार निर्यात कर को समाप्त कर दे। (३) मारतीय माल को विदेशों नापान, ब्रिटेन त्रीर छन्य देशों की बढती प्रतियोगिता का सामना करना पहा। भारतीय सूती मिलें सरकार की श्रनिश्चित नीति के कारण श्रपने निर्यात की मात्रा पूर्ण नहीं कर सकी श्रीर भारतीय माल की प्रकार, पैकिंग इत्यादि निर्यात की शतों के श्रनुक्ल नहीं हो सके। इसके परिणाम स्वरूप निदेशी बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति गिरती चली गई। निर्यात के बढ़ाने के सम्बन्ध में श्रनेकों उपायों का श्रनुसरण किया गया जैसे निर्यात कर की दरों में कमी करना, निर्यात किये जाने वाले कपड़ों के बनाने में काम आने वाली विदेशी रुई पर लगाये गये श्रायात कर में छूट देना, १ मार्च १६५४ से श्रायात-कर को ही वद कर देना श्रीर निर्यात पर नियत्रण कम करना इत्यादि। इनके परिणाम स्वरूप स्ती कपड़ों का निर्यात वह गया है। १६५६ व १६५७ में भारत ने क्रमशः ६८४० लाख गज तथा ८५४० लाख गज कपडे का निर्यात किया। किन्तु विश्वमाजार में प्रति स्पर्धा बहने तथा श्रायात करने वाले देशों में लगे प्रतिबन्धों के कारण १६५८ में निर्यात घटकर ६५०० लाख गज रह जाने की संभावना है। मुख्य प्रकार के कपडे जो भारत से निर्यात किये जाते हैं वे चादरें, कमीज श्रीर कोट के कपडे, वायल ननजेव श्रीर छीट श्रादि हैं।

कर—केन्द्रीय सरकार स्ती कपडे पर उत्पादन कर श्रीर निर्यात कर लगाती है। सितम्बर १९५६ में उत्पानकर में बहुत वृद्धिकर दी गई। इससे उत्पादन-लागत बढ़ गई। इसके श्रातिरिक्त राज्य सरकार स्ती कपडे श्रीर स्त पर विकी कर लगाती हैं। इससे उत्पादन लागत में श्राधिक बृद्धि हो गई है।

१९५२ में वेन्द्रीय सरकार ने इथकर्घा उद्योग श्रथवा बुनकरों की सहायता के लिये ६ करोड़ रुपये का कोष एकत्र करने के लिये मिल के बने सभी कपड़ों पर ३ पाई प्रति गज की दर से एक उप-कर लगा दिया। यह वास्तव में श्रपनी प्रकार का विल्कुल नवीन उपाय था। इसके अनुसार यह पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। क उद्योग को बहुत श्रधिक लाभ हो रहा है और वह इस नवीन कर का भार वहन कर सकने में समर्थ है। इन सभी प्रकार के करों से स्ती मिल उद्योग को श्रपना उत्पादन न्यय कम करने में श्रत्यन्त कठिनाई का सामना करना पद रहा है। इस-स्थिति में सुधार करने के लिये यह त्रावश्यक है कि कर कम किये जाय श्रीर मशीनों की टूट फूट के लिए जिस दर से घनराशि दी जाती है उसके प्रति उदार नीति श्रपनाई जाय जिससे स्ती मिल उद्योग पुरानी श्रीर टूटी मशीनों के स्थान पर नवीन मशीनें लगा सके श्रीर कारखानों में श्राधुनिक टैकनिकल सुविधाएँ प्रदान कर सकें। मशीनों की टूट फूट के लिये जो घनराशि निश्चित की गई है वह अपर्याप्त है। नवीन मशीनों को लगाने के लिये इस बात की श्रत्यन्त ग्रावश्यकता है कि सरकार कम ब्याज पर उद्योग को ऋण दे ग्रीर मशीनों की टूट फूट के लिये निश्चित धन के प्रति उदार नीति श्रपनाये। भारतीय स्ती कपड़ा उद्योग में युक्तीकरण की श्रात्यन्त श्रावश्यकता है। परन्तु यह निम्न वीन बातों पर निभर हैं, (१) श्रावश्यक धन की प्राप्ति, (२) श्रावश्यक मशीनों की प्राप्ति और (३) इस समस्या के प्रति अभिकों का विचार। फिर भी सरकारी कर नीति इस सम्बन्ध में सबसे श्राधिक विचारणीय है क्योंकि वही युक्तिकरण के लिये श्रावश्यक धन प्राप्त करने का श्रोत है।

एकत्रित सामग्री का संकट-१६५७ के प्रारम्भ से स्तीवस्त्र उद्योग गम्भीर सकट का सामना कर रहा है। लगमग २६ मिलॅं, जिनमें से १६ उत्तर प्रदेश में हैं, वन्द होगई है तथा ३७ मिले केवल अगत कार्य कर रही हैं। अप्रैल १६५८ के अन्त में मिलों के पास जिना जिके कराड़े की एकजित सामग्री ५०५३०० गाँठे थीं। अनेक मिलों को हानि उठानी पढ़ी है तथा, मिलों के अनेक मनदूर वेकार हो गये हैं। इस सकट के मुख्य कारण निम्न हैं (१) साद्यान्न तथा नीजन की अन्य आवश्यकताओं के मूल्य अत्यधिक केंचे होने के कारण लोगों की म्य शिक घट गयी जिसके फल स्वरूप पिकी कम होगई। साथ ही १६५८ में निर्यात में भी कमी आगई। (२) कपडे पर लगे उत्पादकर की कैंची टर के फलस्वरूप उत्पादन-लागत बरावर कैंची वनी हुई हैं। (३) उद्योग का मनदूरी-विल बहुत अधिक है। लागत के घटने का कोई सहज उपाय भी नहीं दिसाई देता क्योंकि मशीनें पिसी पिटी तथा पुरानी हैं तथा उत्पादन के युक्तीकरण में देर होती रहती है। उद्योग के बरवादी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन कर १६५५-५६ के स्तर पर कर दिया जाय तथा उत्पादन का युक्तीकरण किया जाय।

उद्योग के सम्मुख दो कठिनाइयाँ हैं। एक श्रोर उत्पादन पर नियत्रण लगा दिया गया है तथा दूसरी श्रोर इयकर्षा उत्पादकों के हित में मिल उद्योग पर १ ली दिसम्बर १६५२ से प्रतिवन्घ लगा दिये गये हैं जिनके श्रनुस्तर घोतियों के उत्पादन के १६५१-५० के मासिक श्रीस्त के ६०% पर मिलों का घोतियों का उत्पादन निश्चित किया गया है तथा साहियों का रगना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत—प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत स्ती कपड़ा उद्योग की उत्पादन शक्ति को १९५५-५६ तक ४७७=० लाख गब कपडे श्रीर १७२२० लाख पोड स्त तक बढ़ाने का श्रनुमान या श्रीर वास्तिविक उत्पादन ४७००० लाख गज कपडे श्रीर १६४०० लाख पोंड स्त का करने का या। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति को १५ गज कपड़ा प्राप्त हो सकने का या। प्रथम योजना के श्रन्त तक वास्तिविक उत्पादन श्रीर उत्पादन शक्ति दोनों ही लक्ष्य से श्रागे वढ गये।

दिवीय पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत यह प्रस्ताव किया है कि कुल कपढें के उत्पादन की मात्रा (भिल श्रोर इयक्षें श्रीर शक्ति चचालित करें से बने कपढें मिलाकर) को ६८५ करोड़ गज से, जितना कि १६५५-५६ में या, १६६०-६१ तक ८५० करोड़ गज कर दिया जाय श्रोर स्त का उत्पादन १६३ करोड़ पींड से १६५ करोड़ पींड कर दिया जाय। इसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति कपढे का उपभोग १८ गज तक बढा देने का है श्रोर लगमग १ श्ररव गज़ कपडे का निर्यात

करना है। द्वितीय योजना में कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दो मुत्य दोष हैं—(१)
मिविष्य की कपड़े की माँग का कम श्रुनुमान करना, क्योंकि धम्धई के मिल
मालिकों की एसोसियेशन के मतानुसार यह माँग ५५० करोड़ गज नहीं वरन्
१००० करोड़ गज होगी; ग्रौर (२) मिलां के विस्तार पर इस विश्वास से प्रतिन्य
लगाना कि इससे हथरघाँ के प्रयोग को सहायता मिलेगी। इथकर्षा उद्योग को
सहायता मिलों की उत्पत्ति को कार्वे कमेटी के श्रनुसार ५०० करोड़ गज तक
श्रिथवा किसी श्रन्य मात्रा तक मीमित कर देने में नहीं मिलेगी वरन् इथकर्ष से
बने कपड़े श्रिथक श्रन्छे बनाने श्रोर उसके मूल्य के घटाने से मिलेगी।

# जूट उद्योग

भारत में जूट की ११२ मिलें हैं जिनमें लगभग ७२,३६५ कर्घे चलते हैं। इनमें से ४५% कर्घे जूट के टाट छोर ५५% वोरे इत्यादि बनाने के लिये हैं। छनुमान लगाया गया है कि यदि उद्योग में केवल एक शिफ्ट में कार्य चलाया जाय छीर प्रति सप्ताह ४८ घटे उत्पादन किया नाय तो प्रतिवर्ष १२ लाख टन उत्पादन किया जा सकता है। जूट उद्योग छाधिकतर पश्चिमी बगाल में केन्द्रित है। मारत की कुल रिजस्टर्ड ११२ जूट मिलों में से १०९ मिलें पश्चिमी बंगाल ही में स्थित है। शेप मिलों में से ४ छान्छ में, ३ निहार में ३ उत्तर प्रदेश में छोर १ मध्य प्रदेश में हैं।

भारतीय जूट उद्योग श्रन्य सब उद्योगों से श्रिषक सुसगिठत है परन्तु दुर्भाग्यवश इसकी मगीन इत्यादि श्राधुनिक नहीं है श्रीर साथ ही यह मशीनें वनाये हुये माल की वर्तमान माँग के टिंटकोण से श्रिषक भी हैं। भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि करने के लिये यह श्रत्यन्त श्रावर्थक है कि उसकी पुरानी मशीनों के स्थान पर श्राधुनिक मशीनें लगाई जाँय श्रीर इस प्रकार उत्यादन व्यय घटाया जाय। परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि उद्योग का युक्तीकरण करने में ४० से ४५ करोड़ रुपये तक की पूँजी लगानी पड़ेगी श्रीर वर्तमान में उद्योग इतनी पूँजी लगा सकने की ज्ञमता नहीं रखता। "श्रिभनवीकरण (modernisation) के लिये राष्ट्रीय श्रीयोगिक विकास निगम द्वारा श्रम्ण दिये ला रहे हैं। मार्च १९५८ के श्रन्त तक ह मिल कम्पनियों के लिये श्र्ण स्वीकृत हो चुके हैं जिनमें से ७ को १.१६ करोड़ रु० दिया भी जा चुका है। वर्तमान स्थित यह है कि ८२ जूट मिल कम्पनियों में से ४४ ने ३० सितम्बर १९५७ तक कताई सम्बन्धी श्राधुनिक मशीनों को स्थापित कर लिया था। कुछ ने पूर्णतः तथा कुछ ने श्रातः श्रीमनवीकरण कर लिया था। पुराने तकुश्रों में से ४% के स्थान पर नये तकुये लगाये जा चुके तथा लगाये जा रहे हैं।

चत्पादन की प्रवृत्ति--जूट उद्योग में उत्पादन १६४५-४६ में उसस्तर तक पहुँच चुका था जनकि ११ ४ लाख टन माल का उत्पादन किया गया। इसके पश्चात् १६४६ तक उत्पादन दस लाख टन प्रतिवर्ष के लगभग रहा। परन्तु १६४६-५० में उत्पादन ८६ लाख टन तक गिर गया । इसके पश्चात् उत्पादन में कुछ सुघार श्रवश्य हुश्रा परन्तु फिर भी उत्पादन पूर्व स्तर तक नहीं पहुच पाया । १९५४-५५ में उत्पादन बढ़ कर १०, ४३,४०० टन हो गया था। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी थी वर्यों कि देश का विभाजन हो जाने के पश्चात् पूट का उत्पादन करने वाले ग्राधिकाश चेत्र पाकिस्तान में चखे गये। इस ग्रभाव को पूरा करने के लिये देश में ही जुट उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया। तब से देश में जुट के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिखाम स्वरूप जूट के माल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जूट उद्योग में प्रति सप्ताह केवल १२% धन्टे उत्पादन कार्य हो रहा या श्रीर उद्योग के कुल कर्षे के १२% प्रतिशत बन्द पढे हुये थे। परन्तु श्रवद्वयर १९५४ से ४८ घन्टे प्रति सप्ताह कार्य श्रारम्म हो गया श्रीर १९५६ के मार्च तक वन्द कर्षों में से ७३ प्रतिशत चालू हो गये थे। १९५६-५७ में उत्पादन १,०२५,२०० टन था तथा श्राशा की जाती है कि १६५७ ५८ में भी लगभग इतना ही होगा।

कचचा माल-उद्योग की इस समय सबसे बड़ी कठिनाई कच्चे माल की कमी है। यदि सब मिलें शक्ति भर कार्य करें तो भारतीय जूट उद्योग के लिये प्रतिवर्ष पटछन की ७५ लाख गाँठों की श्रावश्यकता है। परन्तु भारत में १६४७ ४८ में १५ लाख गाँठों से पुछ श्रधिक, १९४८-४९ में २० लाख गाँठ, १९४९-५० में २० लाख गाँठ श्रीर १९५० ५१ में २२ लाख गाँठ से कुछ श्रिषक का उत्पादन किया गता । भारत खरकार ने पाकिस्तान खरकार से समसौता कर पटसन के श्रायात की व्यवस्था की, परन्तु श्रायात का यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पाकिस्तान से बहुत थोड़ी मात्रा में जूट का श्रायात किया गया। फलस्वरूप भारतीय जूट उद्योग के कच्चे माल की श्रावश्यकता पूर्ण नहीं की जा सकी। इघर हाल के वर्षों में भारत में कच्चे जूट का उत्पादन वढ गया है। १९५६-५७ में इसका उत्पादन ४२ ५ लाख गाँठे थी। १९५७-५८ में इससे घट-कर ४० लाख गाठे (४०० पो० की एक गाँठ) रह नाने की श्रावश्यकता है। कच्चे जूट के विषय में आत्मिनिर्भरता प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले गहन प्रयत्नों के सदर्भ में १९५७-५८ में उत्पादन की यह कमी शोचनीय विषय है। द्वितीय योजना के अन्त तक भारत को पाकिस्तान से जूट मगाना ही पडेगा। किन्तु उन पर इमारी निर्भरता बहुत कुछ कम हो जायगी श्रोर यह सम्मव हो

सकेगा कि भारत में बूट उद्योग पाकिस्तान से जूट बिना पाये भी संतोधप्रद ढग

निर्यात—भारतीय नूट उद्योग अधिकतर भ्रयने माल के निर्यात पर निर्मर करता है। १६४८-४६ में भारत में ११ लाख टन उत्पादित माल में से में चले। ६३०,००० टन माल का विदेशों को निर्यात कर दिया गया। यद्यपि निर्यात की मात्रा पूर्व की अपेन्ना घटकर १९५६-५७ में इ५६००० टन हो गई है फिर मी यह

कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग है । कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग है । भारतीय जुट के टाट के टो बड़े बाजार यूनाइटेड स्टेटस तथा यू० के० हैं। १९५६-५७ में इन देशों को गये निर्यात में क्रमशः ५% श्रीर ५०% की कमी हुई। यद्यपि यूनाइटेड स्टेट्स को किये जाने वाले निर्यात की कमी से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरी अमेरिका में व्यापारियों ने टाट सामग्री कुछ कम कर दी थी; किन्छ यह पूर्ण सत्य नहीं है। अधिक महत्व की बात तो यह है कि १९५६-५७ में टाट के उपमोग में (गू॰ एस॰ में) १२% को कमी हुई । उपमोग की यह कमी येंले बनाने के लिये टाट का प्रयोग कम करने के कारण हुई । सन्तोष का विषय है कि श्रीद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जूट का प्रयोग बहता रहा । यू० के० में जुट के उपमोग में हुई मारी कमी वहाँ पर लागू जुट-नियन्त्रण के कारण हुई।

जूट से बनने वाले थैलों से यह लाभ होता है कि यह श्रपेचाकृत सस्ते होंते हैं और इनका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है जब कि पैकिंग के लिये कागज के मैलों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं का केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु जूट के येंलों के स्थान पर कागज तथा श्रन्य प्रकार की वस्तु प्रों के प्रयोग से जूट के माल की सौंग काफ़ी गिर गई है थ्रौर यह लूट उद्योग के लिये चिन्ता का कारण बन चुकी है। फिर भी यदि उचित प्रयत्न किये जाँय तो अन्य वस्तुष्ठों की अपेह्ना नट्ट का माल अपने लिये आवश्यक स्थान बना सकता है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जूट उद्योग का उत्पादन व्यय घटाया जाय, उत्पादन बढाया जाय श्रीर उत्पादित

मारत सरकार ने लूट के माल पर बहुत श्रिधिक निर्यात कर लगाया जिस माल की प्रकार में सुधार किया जाय। से कि माल के मारतीय तथा विदेशी मूल्य का श्रन्तर सरकारी खजाने में जमा हो जाय। यदि यह कर न लगाये गये होते तो उद्योग श्रपने श्राधुनिकीकरण तथा पुरानी विसी पिटी मशीनों के बदले नई मशीने लगाने के लिये पर्याप्त सुरिच्चत कोष का समह कर सकता था। निर्यातकर से बहुत हानि उठानी पढ़ रही थी। कोरिया युद्ध के कारण हुई महगी के काल में जूट के बने कपड़ों पर तो यह कर

(

१५०० ६० प्रति टन श्रीर बोरों पर ३५० ६० प्रति टन तक वह गया था। श्रगस्त १६५५ में पाकिस्तानी ६पये की विनिमय दर घटने पर यह कर हटा लिया गया। इटाते समय टाट पर यह कर १२० ६० प्रति टन श्रीर बोरों पर ६० ६० प्रति टन था। निर्यात कर के हटा देने का परिगाम यह हुन्ना कि मूल्यों में कमी हो गई श्रीर निर्यात वह गया तथा घरेलू माँग भी वह गई।

जूट जॉच आयोग-जूट जॉंच श्रायोग ने जिसके श्रध्यक्त के ० श्रार० पी० श्रायगर थे श्रपनी १६५४ में प्रकाशित रिपोर्ट में यह पाया कि ७५% मिलें लगमग १२ मैनेजिंग एजेन्सियों के हाथ में थी, जिनमें से चार के अन्तरर्गत ४५% कर्षे थे। मैंनेजिंग एजेन्टों के हाथ में सारे व्यवसाय के केन्द्रित होने श्रीर जुट उद्योग के भूतकाल में ऊँची दर पर श्राय प्राप्त करने के कारण इन मैने किंग एजेन्सियों के शेयर बहुत ही आकर्षक हो गए ये और उनके खरीदारों की सख्या बढ गई थी। चॅ्कि बूट उद्योग के वर्तमान सयत्र की उत्पादन शक्ति वर्तमान स्रौर भविष्य की सम्भावित माँग से कहीं श्रविक है इसलिये श्रायोग ने श्रीर नई मिलों की स्थापना को पसन्द नहीं किया । उसने मिलों को श्रपने सयत्रों को श्राधुनिक वनाने की सिफारिश की। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन की यह योजना होते हुए भी, चॅंकि इसका परिणाम विनाशकारी मतिद्वन्दिता श्रौर उद्योग की श्रव्यवस्या होगी, श्रायोग ने यह सिफारिश की कि काम के घरटों के सम्बन्ध में जो समकोता हुआ है जिसके अनुसार सप्ताह के अन्दर कार्य के घन्टे सीमित कर दिये गये हैं और मशीनों को अशतः चालु करना वन्द कर दिया गया है उसे आगे लागू नहीं रखना चाहिये। इस सममौते के श्रनुसार श्रक्रशल मिलें भी चलती रही हैं श्रोर कुशल मिलों को अपना उत्पादन ज्यय कम करने में वाषा पहुँची है। इससे पाकिस्तान तथा श्रन्य विदेशी मिलों को लाम पहुँचा है। श्रायोग की यह सिफारिश सर्वया युक्तिसगत है और इससे आशा की जाती है कि कुशल मिलें अधिक श्रच्छा कार्य कर सकेगी। श्रायोग ने सिकारिश की है कि भारत को कच्चे जूट की पूर्ति के लिये निरपेश के वजाय सापेशिक श्रात्मनिर्भरता का लक्ष्य सामने रखना चाहिये। हमें पाकिस्तान से उस प्रकार का ज्य श्रायात करना चाहिये जिसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता श्रीर श्रन्य मकार के जूट को स्त्रय उत्पादित करना चाहिये। जूट की विस्तृत खेती के बजाय गहन खेती तथा किस्म के सुघार पर ऋषिक जोर देना चाहिये।

श्रायोग इस परिणाम पर पहुँचा कि नियमित वाजारों में नियमों का लागू करना, सहकारी समितियों की व्यवस्था करना, तथा श्रन्य सिफारिशों को कार्या-न्वित करना दीर्धकालीन दृष्टि कोण्य से उत्पादकों के लिए श्रिषक लाभकारी सिद्ध होगा। मूल्य नियन्त्रण के उपायों के प्रयोग को श्रस्वीकार करते हुए भी निर्यात बढाने के लिए तथा घरेलू माँग बढाने के लिये श्रायोग ने मूल्य स्थिर रखने का

थोजना के अन्तर्गत-जूर उद्योग के सम्बन्ध में समस्य । उत्पादन शक्ति प्रयत्न करने की सलाह दी। बढ़ाने की नहीं है क्योंकि बाजार की माँग की तुलना में तो भारतीय जूट मिलों के साधन त्रावश्यकता से कहीं श्रिधिक हैं। वास्तिविक समस्या तो कब्चे माल की पूर्ति बहाने श्रीर उद्योग को उत्पादन में श्रपनी वर्तमान शक्ति के श्रतुक्ल वृद्धि करने की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसीलिये श्रीहोगिक प्रसाघनों की वृद्धि के बजाय उत्पादन में वृद्धि करने की सिकारिश की गई थी।

जूट उद्योग की (rated) प्रत्यिकत उत्पादन शक्ति १२ लाख टन पी परन्तु कच्चे माल के श्रभाव के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। प्रथम योजना में जूट के उत्पादन को ५१ लाख गाँठों तक ग्रीर जूट के बने माल का सम्पूर्ण पत्यिद्धित शक्ति भर श्रयीत् १२ लाख टन तक वढाने का प्रबन्ध किया गया था, जिसमें से १० लाख टन विदेशों को भेज दिया जायगा। परन्तु ये लक्ष्य

हितीय योजना में भी जूट मिलो की प्रत्यिकत शक्ति बढाने की तिफारिश प्राप्त नहीं किये वा सके। नहीं की गई है। केवल आधाम में १३ करोड़ क्पर्यों के व्यय से एक मिल खोलने का प्रस्ताव है। प्रयत्न यह होगा कि जुट के बने माल की १६५५-५६ की १,०४,००० टन की उत्पत्ति को बढाकर १६६०-६१ मे १,१००,००० कर दिया जाय। जट का उत्पादन ४० लाख गाँठों से जो कि १६५५.५६ में या बढ़ा कर १६६०-६१ में ५० लाख गाँठ कर दिया जाय। इस प्रकार भारतीय मिलो को आयात किये हुये जूट पर मिक्स में कुछ काल तक निर्मर रहना ही पढेगा।

निराकम्य ( Tariff ) सरवण तथा सरकारी नियोजन के फलस्वरूप भारत में चीनी की मिलों की सख्या १६३१-३२ में ३२ से बढ़कर १६५५-५६ में १६० हो गई । इनमें से १३६ तो १९५४-५५ में उत्पादन कार्य कर रही थीं श्रीर उन्होंने १६ लाख टन से कुछ ही कम चीनी का उत्पादन किया। १६५५.५६ मे १३७ मिले उत्पादन कार्य कर रही यी श्रीर उन्होंने १७ लाख टन चीनी का उत्पादन किया। १६४८ में सरकार ने चीनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया श्रीर नवीन मिलों की स्थापना की स्वीकृत दी। ५५ नई पैक्टरियों, जिनमें इद सहकारी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं, की स्थापना तथा वर्तमान ६६ मिलों की उत्पादनशक्ति के विस्तार के लिये अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) दे दिये गये हैं। लाइसेन्स दी हुई उत्पादन इकाइयों में चार ने १६५५-५६ में उत्पादन प्रारम्भ किया तथा पाँच ने १६५६-५७ में। १६५७ के श्रन्त में प्रत्यकित उत्पादन शक्ति २,०१०,००० टन थी। १६५७ ५८ में नी श्रीर इकाइयों ने भी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इसके परिण्य स्वरूप फैन्ट्री निर्मित चीनी की उत्पत्ति १६५६-५७ के २०३ लाए टन से बहुकर १६५७ ५८ में २१३ लाए टन होने की सम्भावना है।

चीनी उद्योग के विकास की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिएत एँ—(१) चीनी उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश श्रीर निहार में केन्द्रित है परन्त देश के श्रन्य भाग जैमे वम्बई, मद्रास, मैसूर ग्रीर हैदराबाद श्रादि भी चीनी उद्योग के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यहाँ गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन श्रिषक है श्रीर गन्ना परने का कार्य भी वहाँ श्रपेज्ञाइत श्रिषक समय तक किया जा सकता है। (२) प्रचलित कारखानों ने कभी भी श्रपनी पूर्ण शक्ति से उत्पादन नहीं किया। इनमें में कुछ तो निल्कुल वन्द रहे जिसके फलस्वरूप उत्पादन सदा वान्तिक उत्पादन शक्ति से कम रहा। (३) चीनी उद्योग में बहुत से ऐसे कारखाने हैं जो श्रमुक्ततम शक्ति से नीचे हैं। एक श्रीसत कारखाने को श्रपनी पूर्ण उत्पादन शक्ति का लाम उटाने के लिये प्रतिदिन ८०० टन गन्ना परना चाहिये परन्तु श्रमुमान लगाया गया है कि लगभग ८० कारखाने इस स्तर से नीचे हैं। इससे भारत में चीनी का उत्पदान व्यय श्रिषक होता है श्रीर श्राधिक हिन्द से श्रमुपयुक्त कारखानों का लाम भी कम हो जाता है।

खत्पादन की प्रवृत्तियाँ—भारत में चीनी के उत्पादन में काफी उतार-चढाव श्राता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीनी का उत्पादन गन्ने की पूर्ति की मात्रा, गना पेरने की श्रविध श्रोर गन्ने से प्राप्त चीनी के प्रतिशत पर निर्मार करता है। चीनी का उत्पादन, १६४८-४६ में १०'०६ लाख टन था जो गिरकर १६४६-५० में ६ ०६ लाप टन हो गया क्योंकि (श्र) १६४७ ४८ में मिलों के लिये गन्ने का भाव २ रुप्ये प्रतिमन से घटाकर १६४८-४६ में उत्तर प्रदेश में १ रुप्या १० श्राना प्रति मन श्रोर निहार में १ रुप्या १३ श्राना प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का मूल्य घटाने का उद्देश्य चीनी का भाव ३५ रुप्या ७ श्राना प्रतिमन से घटाकर २८ रुप्ता ८ श्राना प्रतिमन करना था। गन्ने के भाव में इस कमी से १६४६-५० में कारखानों के लिये गन्ने की पूर्ति में कमी हो गई श्रौर परिणाम स्वरूप उत्पादन भी गिर गया, (ब) गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १६४८-४६ में ६-६७ से गिरकर १६४६-५० में ६-६६ हो गई श्रोर गन्ना पेरने की श्रौसत श्रयिष मी १०१ दिन से घटकर ६१ दिन तक श्रागई। इस कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई जबिक कारखानों की सख्या १३४ से बढ़कर १३६ होगई थी।

परन्तु क्रमशः स्थिति बदली श्रीर उत्पादन बढकर १९५०-५१ में ११.०१ लाख टन श्रीर १९५१-५२ में १४'८३ लाख टन हो गया। १९५०-५१ श्रीर १६५१-५२ में चीनी का अधिक उत्पादन होने के तीन मुख्य कारण हैं. (१) मिलों को खुले बाजार में चीनी बेचने की छूट दे दी गई। इसके श्रनुसार कारखानों को १९४८-४९ या १९४९-४० में से जिस वर्ष का उत्पादन कम हो उसके १०७ प्रतिशत से स्रिधिक उत्पादित चीनी को खुले बाजार में उस समय के भाव के अनुसार विकय करने की अनुमित दे दी गई। इसके पूर्व कारखानों को श्रपना सम्पूर्ण उत्पादन नियन्त्रित भाव पर वेचना पहता था जिससे उन्हें श्रिधिक लाम नहीं हो पाता था। इस कारण उत्पादन वृद्धि की श्रोर उनकी प्रवृत्ति नहीं रही। खुले बाजार में श्रतिरिक्त चीनी का विक्रय करने की छूट देने के फलस्वरूप कारखाने ऋषिक उत्पादन का लाम उठा सकते थे इसलिए स्वामाविक ही उत्पादन में वृद्धि हुई, (२) चीनी के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की गई परन्तु गन्ने का माव १६४८-४६ के स्तर पर ही रहा। कारखाने से बाहर चीनी का नियन्त्रित भाव २८ रुपया ८ ज्ञाना स्थिर रखा गया परन्तु पहले यह डी॰ २४ नम्बर की चीनी का भाव था और अब ई० २७ नम्बर की चीनी इस माव से विकय होने लगी। चॅकि ई० २७ नम्बर की चीनी डी० २४ नम्बर की चीनी से घटिया प्रकार की है इसलिए यह कहना श्रुतिचत न होगा कि कारखानों ने गत वर्षों की श्रपेक्ता चीनी का श्रिषिक मूल्य वस्ल किया। उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में गन्ने का भाव २ ह्या • प्रतिमन बढाकर १ रुपया १२ ह्याना प्रतिमन निश्चित किया गया। कारलाने के बाहर ई० २७ नम्बर की चीनी का मान बढ़ाकर २६ रुपया १२ आ० प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसका मिल मालिको पर प्रतिकृत प्रमाव नहीं पड़ा क्योंकि एक मन चीनी का उत्पादन करने में १० मन गन्ना लगता है श्रीर इस त्राधार पर उत्पादन व्यय १ रुपया ४ श्राना प्रतिमन बढा श्रीर मुल्य भी इतना ही बढा. (३) गन्ना पेरने की अविध में भी वृद्धि की गई। १६४६-५० में गन्ना पेरने की श्रविध हर दिन थी जो १६५०-५१ में बढकर १०१ श्रीर १६५१-५२ में १३३ दिन हो गई। यद्यपि यह सत्य है कि गन्ने से प्राप्त चीनी की प्रतिशत मात्रा १० •०३ से घटकर ६ । प्रे परन्तु कारखानों को श्रिधिक समय तक चालू रखने के कारण चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई।

चीनी की उत्पत्ति १६५२-५२ में गिरकर १३.१४ लाख टन और १६५३-५४ में १०.०१ लाख टन हो गई। इसके कारण निम्न हैं, (१) उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों की सख्या जो कि १६५१-५२ में १३६ थी १६५२-५३ और १६५३-५४ में घटकर १३४ हो गई खीर कार्य करने के दिनों की खीसत सख्या १३३ से घटकर क्रमश∙ ११३ छीर ⊏६ हो गई, (२) १६५२-५३ मे कारखानों में पिछला बचा हुआ माल श्रिषिक मात्रा में या श्रीर श्रनेकों मिलें समय से कार्यारम्म मी न कर सकी जिसके फलस्वरूप जितना उत्पादन करने की उनमें शक्ति यी उतना मी उत्पादन न हो सका, (३) बहुत सी मिलों में यत्रादि विसे पिटे श्रीर प्राचीन ढग के थे जिनके कारण उत्पादन शक्ति का पूर्ण प्रयोग होना सम्भव नहीं या, श्रीर (४) श्रवैध सम से शाराव खींचने के कार्य में लाने के लिए बढ़ी हुई गुड़ की माग को पूर्ण करने के लिये कुछ गन्ने का प्रयोग गुड बनाने में कर लिया गया। १६५२-५३ की फछल के लिए गन्ने का मूल्य घटाकर १ रु० ५ ग्राना प्रति मन श्रीर चीनी का नियत्रित मूल्य २७ ६० प्रतिमन कर दिया गया। गन्ने का प्रतिमन मूल्य इतना कम हो जाने से कारखानो को पर्याप्त मात्रा में गन्ना ही न मिल सका। १९५३-५४, १९५४-५५ श्रीर १९५५-५६ की फसलों के लिये मारत की सरकार ने गन्ने का मूल्य १ ६० ७ ग्रा० प्रतिमन कर दिया। इस समय चीनी के मूल्य पर कोई नियत्रण नहीं हैं, केवल यह प्रतिबन्ध है कि फ़रुल की उत्पत्ति का २५% 'सुरज्ञित माल' सममा जाय जिसमें से सरकार चीनी पिछले नियत्रित मूल्य पर अर्थात् २७ र० प्रतिमन पर वेचती है। क्रपकों के दृष्टिकी स से गनने का १ र० ७ श्राना प्रति मन मूल्य श्रपर्याप्त है श्रीर इसी कारण फैक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में कचा माल मिलने में कठिनाई पड़ती है।

१६५६-५७ में चीनो की उत्पत्ति २०% लाख टन थी। १६५७-५८ में इससे बढकर २१३ लाख टन होने की सम्भावना है। इसका कारण वर्तमान फैक्ट्रियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि तथा नई फैक्ट्रियों की स्थापना है।

उत्पादन चमता—चीनी उद्योग की मुख्य समस्या उत्पादन व्यय की अधिकता है। उत्पादन व्यय अधिक होने से उपभोक्ता पर अनावश्यक भार पहता है और अन्य देशों की अपेक्ता भारतीय चीनी का मूल्य अधिक होने के कारण निर्यात की मात्रा भी नहीं बढ पाती। भारतीय चीनी का उत्पादन व्यय अधिक होने के अनेक कारण हैं। इसको कम करके चीनी का मूल्य घटाने के लिये काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। चीनी-उद्योग के सम्बन्ध में प्रयम किटनाई यह है कि कृषकों के हितों की रचा के लिये सरकार गन्ने का मूल्य अधिक निश्चित करती है और वेन्द्रीय तथा राज्य सरकार उद्योग पर अनेक कर लगाती हैं। गन्ने का अधिक मूल्य, अधिक मजदूरी और अधिक कर का फल यह होता है कि चीनी का उत्पादन व्यय कम होने की अपेक्षा बढता जाता है। चीनी के मूल्य को घटाने के लिये यह आवश्यक होगा कि गन्ने के मूल्य को घटाया जाय। चीनी उद्योग की जाँच करने वाले प्रशुक्क मणडल ने सुक्ताव दिया था कि

१६४६-५० में गन्ने के मूल्य में ३ श्राना प्रतिमन कमी की जाय, १६५०-५१ में भी इतनी कमी त्रोर की जाय जिससे भाव १ क्या ४ श्राना प्रतिमन तक श्रा जाय। यदि सुक्ताय को लागू किया जाता तो इससे प्रतिमन चीनी में गन्ने का मूल्य ३ काया १२ श्राना कम हो जाता। यदि प्रशुल्क मण्डल के सुक्ताय के श्रतु-सार माल तैयार करने की मद में भी २ काया ६ श्राना कि कमी कर दी जाती तो इससे १६५०-५१ में चीनी का भाव २२ क्या ४ श्राना प्रतिमन हो जाता। यह खेद की बात है कि सरकार ने प्रशुल्क मण्डल के सुक्तायों के श्रतुसार कार्य नहीं किया श्रीर गन्ने का भाव घटाने के बजाय बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप चीनी के मूल्य में श्रीर वृद्धि हो गई। १६५२-५३ में गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में घटाकर १ क्या ५ श्राना प्रतिमन कर दिया गया परन्तु इसके पक्षात् भारत सरकार द्वारा किर से बढ़ाकर १ क्या ७ श्राना प्रतिमन कर दिया गया।

गन्ने की उत्पत्ति—गन्ने के मूल्य की समस्या सन्तोषजनक ढक्क में तभी सुलमाई जा सकती है जनकि प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में वृद्धि की जाय। भारत में प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति ससार में सब से कम है श्रीर निरन्तर कम होती जा रही है। स्यूचा में प्रति एकड़ उत्पत्ति १७'१२ टन, मारिशस में १६'६३ टन, श्रास्ट्रेलिया में २१'३४ टन, प्युरटोरीको में २४'१६ टन, जाना में ५६ टन, श्रीर हवाई में ६२'०५ टन है। गन्ने के प्रत्यादान की प्रतिशत स्यूचा में १२'२५, मारिशस में १२'०८, ग्रास्ट्रेलिया में १४'३३, प्युरटोरीको में १२ २३, जावा मे ११'४६ श्रीर हवाई में १०'४६ है श्रीर भारत में १०% है। कृपक को तो भूमि से श्रपनी साधारण ग्राय चाहिये श्रीर यदि गन्ने का मूल्य घटा दिया जाय श्रीर यदि गन्ने ने प्राप्त प्रति एकड़ श्राय वढ जाय तो कृपक के लिये चिन्ता की कोई बात न होगी।

वर्तमान समय में चीनी तैयार करने के लिये कुछ कारखाने सल्फीटेशन मोसेस श्रीर कुछ कारबोनेशन मोसेस का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रकार के विधायन में गन्थक का उपयोग होता है जिससे चीनी के कारखानों का व्यय बढता है क्योंकि गन्धक का भारत बहुत प्रधिक मूल्य पर श्रायात करता है। कारबोनेशन प्रोसेस में ० • ० २ १ १ ९ तक गन्धक लगता है श्रीर सल्फीटेशन प्रोसेस में इसकी मात्रा • • • १ १ ९ तक है। इसिलये इन दोनों में से कारबोनेशन प्रोसेस का प्रयोग करना श्रावश्यक है क्योंकि इससे उत्पादन व्यय घटेगा। इखिडयन इन्स्टीट्यूट श्राव शुगर टेकनालाजी के सचालक श्री जे० एम० साहा ने बिना गन्धक का प्रयोग किये चीनी बनाने की नई प्रक्रिया खोज निकाली है। इस नई

प्रिक्तया से श्रिषिक मात्रा में चीनी उत्पन्न होती है श्रोर चीनी का प्रकार मी श्रपेद्धाकृत श्रच्छा है। पटना माइन्स कालेज के श्री ढी० एन घोष ने एक नई रीति
निकाली है जिससे बिना किसी रसायनिक या ताप की सहायता के जिजली के
द्वारा गन्ने का रस साफ किया जा सकता है। इन दोनों प्रणालियों का श्रमी तक
व्यवसायिक पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनसे
चीनी बनाने के व्यय में कमी श्रवश्य होगी। चीनी उद्योग में श्रच्छी मशीनों के
लगाने से भी उत्पादन व्यथ में कमी की जा सकती है।

स्थिति-उत्पादन व्यय ग्राधिक होने का एक कारण कारखानों का श्रातु-पयुक्त स्थानों पर स्थित होना भी है। यद्यपि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में श्रिधिकतर कारखाने स्थित हैं परन्तु यदि कारखाने बम्बई या दिख्या मारत में होते तो श्रविक उपयुक्त होता । वम्बई तथा दिल्ला के श्रन्य चेत्रों में गन्ने का पति एकड़ उत्पादन अधिक है और वहाँ गन्ने नी पिराई भी अधिक समय तक होती है। यदि उत्तर मारत की श्रवेज्ञा उद्योग दिज्ञण में ही विकसित होता तो चीनी का उत्पादन व्यय श्रवश्य कम होता। परन्तु श्रव यह है कि चीनी-उद्योग श्रिधि-कतर उत्तर प्रदेश श्रीर विहार में केन्द्रित हो गया है। १९५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन) कानून के अवर्गत नियुक्त लाइसेंसिन्ग समिति ने कुछ कारखानी को एक साथ नये स्थानों में ले जाने की सिफारिश की भी परन्तु यह समस्या का उपयुक्त हल विद नहीं हुया क्योंकि (१) यदि यह योजना लागू की जाय तो एक कारलाने को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाने में १० से १५ लाख रुपया व्यय हो जायगा श्रीर यातायात की व्यवस्था में व्यय होगा। इसके साथ ही कारखाने को इटाने की श्रवधि में उत्पादन बन्द रहेगा; (२) जिन चेत्रों से कारखाने इटाये जायंगे उनकी श्राधिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी श्रीर उनका श्रन्य चेत्रों से सम्बन्ध टूट जायगा। इसलिये उद्योग की स्थिति में सुधार करने का सबसे श्रव्छा उपाय यही है कि नवीन श्रीर उपयुक्त स्थानों में घीरे-घीरे नवीन कारखाने स्थापित किये जायँ श्रीर श्रुत्ययुक्त स्थानों में स्थित कारखाने जब पुराने पड़ जाय श्रीर पुनर्निर्माण की श्रावश्यकता हो तब उनका पुनर्निर्माण न करने दिया जाय।

निर्मात—श्रतीत में चीनी के लिये भारत विदेशों पर निर्मर था। १६२६-२० में भारत ने लगभग ६३ लाख दन चीनी का श्रायात किया। परन्तु हाल में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप श्रव श्रायात केवल नाम मात्रकों होता है। यह बहुत समव है कि भविष्य में भारत चीनी का श्रायात करने की श्रमेखा निर्यात करने लगेगा। हवायन श्रवर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन के कथनानुसार "बहुत

समय तक भारत को चीनी का निर्यात करने की अनुमित नहीं दी गई, यहाँ तक कि १६३६-४० में जब देश में चीनी का उत्पादन आवश्यकता से कहीं अधिक हुआ था, अतिरिक्त चीनी का भारत से निर्यात नहीं किया जा सका। कुछ समय से यद्यि भारत चीनी का निर्यात कर सकता है परन्तु निर्यात की मात्रा पर नियत्रण है। कुछ पड़ोस के देशों को भारत केवल कुछ हजार टन चीनी प्रतिवर्ष मेज सकता है।"

चीनी का निर्यात बढाने में सबसे बड़ी किटनाई मारवीय चीनी का अपेबाकृत अधिक मूल्य है। मारत में कारखाने के बाहर चीनी का भाव (ex-factory price) २७ रुपया प्रति मन है जब कि अन्य देशों में २१ से २३ रुपया प्रति मन है। इसिलए जब तक सरकार या तो चीनी के निर्यात के लिये आर्थिक सहायता नहीं देती या विदेशों को कम मूल्य पर निर्यात करने और घाटा पूर्ति के लिये देश में अधिक मूल्य पर वेचने की अनुमति नहीं देती तब तक चीनी का निर्यात बढ़ा सकना असमव है। परन्तु वर्तमान स्थिति में उक्त दोनों साम अव्यवहारिक हैं। इन कारखों से चीनी का निर्यात बहुत कम होता है और जब तक चीनी का उत्पादन व्यय नहीं घटाया जाता तब तक मविष्य में भी निर्यात में वृद्धि की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

योजना के श्रन्तर्गत—प्रथम पश्चवर्षीय योजना के श्रारम्म में चीनी के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि का कोई भी प्रवन्य नहीं किया क्योंकि यह श्राशा की जाती यी कि १५. प्र लाख टन की उत्पादन शक्ति का श्रनुमान श्रीर १६५५ ५६ तक १५ लाख टन का वास्तिवक उत्पादन उपयुक्त होगा। परन्तु १६५४-५५ में ही चीनी का उत्पादन १६ लाख टन के लगभग हो गया, श्रर्थात् योजना के लक्ष्य से १ लाख टन श्रिषक हो गया। इसिलए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसिलए प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का लक्ष्य १८ लाख टन कर दिया गया। इसि ध्येय से सरकार ने ३७ नई मिलों को श्रीर ४० प्रानी मिलों के विस्तार के लिये लाइसेन्स प्रदान किये। इससे ५३ लाख टन तक की उत्पादन शक्ति बढ़ने श्रीर वास्तिवक उत्पादन ३५ लाख टन वढ़ने की श्राशा है।

दितीय पञ्चवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादन शकि १७'४ लाख टन से जितने का १६५५ ५६ में अनुमान किया गया है, १६६०-६१ तक २५ लाख टन कर दी जाय और चीनी का उत्पादन १६५५-५६ के १७ लाख टन से बढ़ाकर १६६०-६१ तक २२ई लाख टन कर दिया जाय। उत्पादन की इस वृद्धि में से सहकारी चीनी के कारखाने ३ई लाख टन उत्पादित करेंगे। दितीय योजना में उत्पादन की बढ़ी हुई मात्रा का लक्ष्य उपयुक्त है। इस्डियन शुगर मिल्छ एसोसिएशन ने श्रपने स्मारकपत्र में जो उसने सरकार को मेना या यह लिखा था कि वर्तमान चीनी के कारखाने पहिले से लाहसेन्स प्राप्त कारखानों को सम्मिलित करते हुये १६६०-६१ तक २७ लाख टन तक चीनी का उत्पादन करने में समर्थ हैं नविक योजना का लक्ष्य केवल २२३ लाख टन ही उत्पादन करने का है। यदि भविष्य की कठिनाइयों जैमे वर्षा का न होना, बाढ का श्राना इत्यादि को विचाराधीन रख लिया जाय तब १६६०-६१ तक वर्तमान कारखाने पिहले से लाइसेन्स प्राप्त कारखानों को मिलाकर प्रति वर्ष २५ लाख टन चीनी का उत्पादन कर सर्केंगे जो कि लक्ष्य से २३ लाख टन श्रिषक होगा। इस बात को सोचते हुये सरकार के लिए यह श्रावश्यक है कि नई फैक्ट्रियों को लाइसेन्स देने में सावधानी करें नहीं तो भारतीय चीनी उद्योग में उत्पादन शक्ति का श्राधिक्य हो जायगा श्रीर सम्भवत उत्पादन मी श्रावश्यकता से श्रिषक होगा।

#### कोयला उद्योग

मारत में कोयले के उत्पादन में विशेष प्रगित हुई है। १६३० का २४० लाख टन का उत्पादन १६५७ में बढ़कर ४३५ लाख टन हो गया। सन् १६५० तक कोयले का उत्पादन लगमग ३०० लाख टन तक बढ़ पाया था पर १६५० में सर्व प्रथम उत्पादन बढ़कर ३२३३ लाख टन हो गया था। श्रागामी वर्षों में उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। १६५१ में ३४६ ६५ लाख टन, १६५२ में ३६३३४ लाख टन, १६५५ में ३८० लाख टन तथा १६५७ में ४३५ लाख टन हुआ था। उत्पादन में यह वृद्धि वर्तमान खानों की श्रिधक धनी खुदाई करने तथा कोयले की माँग में वृद्धि होने के कारण नई खानों की खुदाई का कार्य आरम करने के कारण हुई है।

स्ताद्न क्षमता—यद्यपि मारत में कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कोयले की खानों के उद्योग की उत्पादन इमता बहुत कम है। बहुत सी खानें इतनी छोटो हैं जिन्हें श्रार्थिक हिंदि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। खानों के यन्त्रीकरण में भी विशेष प्रगति नहीं की गई है। कोयला उद्योग में जितने श्रमिक कार्य करते हैं उनकी सख्या श्रावश्यकता से श्रमिक है। साथ ही श्रम्य देशों के निपरीत मारतीय खदान-श्रमिक की कार्य इमता कम है श्रीर प्रति श्रमिक उत्पादन भी कम होता है। उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की सख्या १६४१-५१ के मध्य ५८% बढ़ गई है परन्तु कोयले के उत्पादन में केवल ३२% की ही वृद्धि हो पाई है इससे श्रमिकों की उत्पादकता में हास प्रगट होता है। यह प्राविधिक (टैक्निकल) पिछड़ापन श्रीर कार्यक्षनता में कमी, कोयले के उद्योग की स्पर्ध शिक्त श्रीर लाम को नीचे स्तर पर रखने के लिये उत्तरदायी है। च्योलोजिकल, माइनिंग और मैटालर्जिकल सोसाइटी की २५ वी वार्षिक वैठक में यह बताया गया कि भारत में प्रति श्रमिक आठ घटे की एक शिफ्ट में २'७ टन कोयले का उत्पादन होता है जब कि ब्रिटेन में ६'२६ टन, जर्मनी में ८६६ टन और अमरीका में २१'६८ टन कोयले का उत्पादन होता है। इसका तालर्य यह है कि उत्पादन ब्याय कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थिति तालर्य यह है कि उत्पादन ब्याय कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थिति तालर्य यह है कि उत्पादन ब्याय कम करने के लिए और उद्योग की वित्तीय स्थिति तालर्य यह है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो किंदनाइयो का सामना श्यकता है। कोयला उद्योग का यन्त्रीकरण करने में दो किंदनाइयो का सामना श्यकता है। कोयला उद्योग का वित्रोध करते हैं क्योंकि इस योजना को लागू और (२) अमिक इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं क्योंकि इस योजना को लागू करने से भूनेक अमिक वेरोजगार हो जायँगे। उद्योग की उत्पादन-द्यमता में सुधार करने के लिए इन दोनों किंदनाइयो को दूर करना आवश्यक है।

परिरक्ष्य (Conservation)—वर्तमान समय में घातुशोधन के कार्य में आने वाले उत्तम श्रेगी के कोयले की काफी चृति हो रही है। इस कोयले का कुल जितना उत्पादन होता है उसका ४० प्रतिशत माग रेलवे के कार्य में आता है, २१ प्रतिशत के लगमग लोहे और इस्पात उद्योग में और १३ प्रतिशत का निर्यात और जहाजों में प्रयोग होता है। इस्पात उद्योग में इस प्रकार के कोयले की बहुत आवश्यकता होती है इसलिये इस उद्योग के उपयोग के लिये इसका सरस्य करना पड़ेगा। मेटालर्जीकल कोल कमेटी (१६४६) अपनी जांच पहताल के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँची कि प्रत्येक वर्ष पूर्व की कुल खपत में से (उद्योग को बिना कुछ हानि पहुँचाये) आगामी ५ वर्षों में बीरे धीरे १० प्रतिशत की कमी की जा सकती है स्रीर इस प्रकार घातुशोधन के कार्य में स्राने वाले उत्तम श्रेगी के कोयले का उत्पादन घटाया जा सकता है। इस समिति ने सुमाय दिया है कि (ग्र) किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के कीयले की खानें न खोली जायें। यदि पुनः प्रचलित करने में अधिक धन न लगे तो उत्तम श्रेणी के कोयले की कुछ खानों को वन्द किया जा सकता है, (व) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने ग्रीर धोने को कान्ती रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, भ्रौर (स) खराव कोयला छोड़कर श्रन्छ। कोयला निकालने की रीति को बन्द कर देना चाहिए। योजना श्रायोग ने सुम्माव दिया है उत्तम श्रेगी के कीयले का सरक्षण किया जाय और कीयले तथा कोयला समिति से सम्बन्धित सभी विषयों पर परस्पर उचित संबन्ध स्थापित करने वाली नीति श्रपनाई जाय । सरकार ने वातु शोवन के कार्य में श्रानेवाले कोयले के उत्पादन की अधिकतम मात्रा निर्घारित कर दी है। १६५३ उत्पादन की अविकतम मात्रा १५१ द लाख टन, १६५४-५५ में १४३ द लाख टन, १६५६ में १५४ र लाख टन तया १६५७ में १६० लाख टन कर दी गई।

सरकार की इस नीति की दो आधारों पर आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि (अ) उत्तम प्रकार के कोयले के उत्पादन की मात्रा पर प्रतिवन्ध लगाना समस्या ना उचित हल नहीं है। सरच्या करने का अर्थ है रोकी जा सकने वाली च्रित होने की सारी संभावनाएँ समाप्त करना, उत्पादन में अधिक उपयुक्त साधनों तथा उपायों का प्रयोग करना और कोयले के व्यय में वचत करना इत्यादि। इसके साथ ही सरकार की नीति को व्यापक होना मी आवश्यक है, (व) कोयले के चट्टे लगाने, मिलाने और घोने में और सरच्या की नीति को लागू करने में अतिरिक्त व्यय करना पहला है जिसका उत्पादन व्यय पर प्रभाव पहला है। सरकार न तो उद्योग को आवश्यक वित्त की सहायता देती है और न अतिरिक्त व्यय करने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करने देती है। उद्योग पर उक्त प्रतिवन्ध लगाना सरवार की न्यायसगत वार्यवाही नहीं कही जा सकती। इस अभाव की पूर्ति किये विना सरकार की कोयला सरच्या नीति से उद्योग को और अधिक हानि होने की सभावना है।

परिवहन—कीयला उद्योग की एक सबसे बड़ी किटनाई परिवहन के साधनों का अभाव है। कीयले को अन्यन्न में जने के लिए पर्याप्त सख्या में गाड़ियाँ या मा लगाड़ी के डिक्वे नहीं मिलते हैं। गाड़ियाँ मिलने में बहुत देर होती है जिससे खानों के समीप कोयले के ढेर लग जाते हैं। इससे खानों के कार्य में बहुत किटनाई होती है। वेंगाल और विहार के कोयले की खानों के चेन्न में (जो देश के ८०% कोयले के उत्पादन के लिये उत्तर टायी है) प्रतिदिन लादी जाने वाली मालगाडियों के डिब्वे की श्रीसत सख्या १९५७ में ३६६७ थी, जब कि १९५६ तथा १९५२ में यह सख्या क्रमशः ३४०५ तथा ३१६३ थी। इससे उन्नित की प्रवृत्ति प्रदिश्त होती है परन्तु खेद है कि कोयले की खानों को उपलब्ध माल गाड़ियों की सख्या न तो आवश्यकता के अनुक्ल ही रही है और न रेल विभाग की शिक्त के ही अनुक्ल।

कोयले के लिये मालगाहियों के हिन्बों की पृति में वृद्धि आवश्यक है ताकि उद्योग द्वारा मोयला श्रीव्रता में श्रीर मम मृल्य पर वेवा जा सके। मालगाड़ी के हिन्बों की पृत्ति में वृद्धि के लिये रेलवे के प्रसाधनों में वृद्धि आवश्यक होगी। इसमें निश्चय ही समय लगेगा। परन्तु कुछ श्रन्य भी उपाय हैं जिनसे कोयले की खानों के लिये मालगाड़ी के डिन्बों की पृत्ति में विद्ध की जा सकती है। वर्तमान मालगाड़ी के डन्बों के आवेटन की प्रणाली वड़ी ही जटिल है जिससे देर भो लगती हैं श्रीर खानों पर अत्यधि अवेपला भी एक ति हो जाता है। दूसरी समस्या ढोने की दर की है। भारत सरकार ने कोयले के माड़े की दर में ३० प्रतिशत वृद्धि कर दी है। भाड़े की वृद्धि कोयला उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त की गई वर्किंग पार्टी के सुकाव के अनुसार की गई है। इस वृद्धि से कोयले के परिवहन व्यय में वृद्धि हो गई श्रौर इस प्रकार कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों का उत्पादन व्यय भी वढ गया। भारतीय उत्योगों का विकास करने के लिए कोयले का परिवहन व्यय कम करने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है।

कोयले के निर्यात में कमी की समस्या भारत सरकार ने १६५४ में नियुक्त एक कमेटी के सम्मुख रक्खी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि भारत के कोयले के मुख्य बाजार पड़ोसी देशों में ही हैं। इस लिये बरमा, लका, पाकिस्तान, दिज्ञणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों को ही भारत को अपना स्वाभाविक बाजार समक्ता चाहिये। १६५१-५२ में जो यूद्व को अधिक निर्यात हुआ। या वह यूद्व में कोयले के अभाव, दिज्ञणी अफीका में यातायात की कठिनाईयों, आस्ट्रे लिया में नियित्रत उत्पादन और कीरिया के युद्ध जिनत कारणों से था। १६५३ में ये १६५१-५२ की अपवादी स्थित समाप्त हो गई ओर जो नवीन बाजार भारत को प्राप्त हो गये थे वे सामान्य स्थित होने पर फिर समाप्त हो गये। कोयले का निर्यात बढ़ाने के विचार से कमेटी ने निम्न सिफारिशें कीं: (१) कोयले का सरकारी कय विकय बन्ट होना चाहिये, (२) कोयले की विभिन्न प्रकारों पर जो नियत्रण लगा हुआ है उसे कम करना चाहिये, (३) कोल अदिग बोर्ड को वे ही ग्रेड बनाने चाहिये जो कन्ट्रोल आर्डर में दे दिये हैं, और (४) कलकत्ते के बन्टरगाह पर अधिक सुविधाओं के देने के उपाय करने चाहिये।

योजना के अन्तर्गत — द्वितीय पच वर्षीय योजना में कोयला उद्योग को प्रमुख स्थान दिया गया है। घीरे घीरे इसे सरकारी चेत्र में ले आया जायगा। कोयले का उत्पादन ३६७.७ लाख टन से जो कि १९५४ में था बढ़ाकर १६६०-६१ में ५६७.७ लाख टन कर दिया जायगा।

१६४८ के श्रीद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह कहा गया या कि प्रत्येक कोयले की नवीन खान सरकारी चेत्र में ही श्रारम्भ होगी, ऐसी स्थिति के श्रातिरक्त नहीं कि राष्ट्रीय दृष्टिकीण से सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों का सहयोग श्रावश्यक सममती है। श्रारम्म में इस नीति के व्यवहार में कुछ शिधिलता दिखाई गई परन्तु श्रव यह निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में कोयले के उद्योग के नवीन उपक्रमों को सरकारी चेत्र में ही रखने का प्रयत्त किया जायगा श्रीर बढी हुई माँग को पूर्ण करने के लिए श्रातिरक्त कोयले का उत्पादन द्वितीय योजना काल में श्रिधिकतम स्तर तक सरकारी चेत्र में ही किया जायगा।

# लोहा ख्रौर इस्पात उद्योग

भारतीय लोहे श्रीर इस्पात उत्योग के चेत्र में तीन मुख्य उत्पादक हैं, टाटा श्रायरन एउड स्टील कम्पनी, इिएडयन ग्रायरन एउड स्टील कम्पनी (इसमें स्टील कारपोरेशन श्राफ बगाल भी सम्मिलित हैं) श्रीर मेस्र श्रायरन स्टील वर्मा हम कारखाना में कच्चे लोहे का इस्पात बनाया जाता है श्रीर इस्पात से श्राय-श्यक वस्तुर्ये तैयार की जाती हैं। इनके श्रातिरिक्त लगमग ६४ छोटे कारपोने हैं जो ब्यर्थ लोहे से श्रीर लोहे के छड़ों से जो उत्पादकों द्वारा प्राप्त होते हैं या श्रायत होते हैं, इस्पात तेयार करते हैं।

भारतीय इस्तात उद्योग एशिया में सबसे वड़ा है श्रोर ससार के सवाँतम इस्तात उद्योगों में मे एक है। १६२४ में सरच्या मिलने के पश्चात् इसने महत्व- पूर्ण प्रगति की है। उद्योग की उत्पादन इमता में इतनी नृष्टि हुई कि १६४१ में सरच्या की कुछ श्रावश्यकता नहीं रही। इस्तात का उत्पादन १६४७ में दृष्ट लाख टन था जो बढ़कर १६५२-१६५५ तथा १६५७ में नमशः ११ लाख टन, १२ लाख टन श्रोर १३ लाख टन हो गया। १६५६ में उत्पादन की मात्रा ४५ लाख टन श्रात्र की श्रपेचा कम हो गया। इसका कारण किसी सीमा तक तो श्रमिकों के कारवे थे श्रीर किसी सीमा तक यन्त्रों के श्रमिनवीकरण के कारण उत्पादन १६५२ की श्रपेचा कम हो गया। इसका कारण किसी सीमा तक तो श्रमिकों के कारवे थे श्रीर किसी सीमा तक यन्त्रों के श्रमिनवीकरण के कारण उत्पाद वह श्रव्यवस्था थी जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए कारखानों को मन्द रखना श्रावश्यक हो गया था। इसके श्रमन्तर उत्पादन में वृद्धि हुई श्रीर भविष्य में इसके श्रीर श्रमिक बढ़ने की समावना है। मारत के इस्पात श्रीर लोटे के उद्योग की मुख्य समस्याएँ (श्र) इस्तात के उत्पादन में वृद्धि करना, (व) ढले हुए लोटे के उत्पादन को फाउन्ट्रीयों के लिये बढ़ाना है।

लोहे श्रोर इस्पात उद्योग के लिए श्रावश्यक कच्चा माल भारत में ही प्राप्त है। जितना कच्चा माल वर्तमान समय में प्राप्त है उतने से ही उद्योग के लिए इस्पात वढ़ा लेना सम्मव है।

इस्पात का मूल्य—देशी इस्पात का मूल्य श्रायात किये हुये इस्पात से बहुत कम है। मूल्यों में समानता लाना बहुत श्रावश्यक है। यह मूल्य के नियत्रण द्वारा ही ( युद्धकाल से श्राज तक ) सम्मव हो सका है। १ श्रवट्टवर १६३६ से ३० जून १६४४ तक युद्ध के लिये क्रय किये जाने वाले इस्पात के मूल्य पर नियन्त्रण था। परन्तु इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं था। इस्पात के व्यवसायिक मूल्य पर से नियन्त्रण १ जुलाई १६४४ से श्रारम्म हुश्रा। इस सम्पन्य में सरकार जिस प्रणाली का श्रवसरण करती है उसके

श्रनुषार प्रलारच्य मूल्य (retention price) नियत कर दिया जाता है जिस पर मुख्य-मुख्य उत्पादक इस्पात विकय करते हैं, ग्रीर उपभोक्ताश्रों के लिये मृल्य की एक श्रन्य कॅची दर नियत होती है जिस पर वे क्रय करते हैं। होनों मृल्यों के श्रन्तर से प्राप्त घन समानता स्पापित करने वाले कोप (equalisation method) में जमा कर दिया जाता है जिसमें से इस्पात के ग्रायात में सहायता प्रदान की जाती है श्रीर इस्पात उत्पादकों के ग्रामिनवीकरण तथा विकास के कार्यक्रमों में ग्राधिक सहायता दी जाती है। एक जुलाई १९४४ श्रीर ३१ मार्च १९४६ के मध्य इस्पात के हो प्रत्यारच्या मृल्य निर्धारित किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय हस्पात के हो प्रत्यारच्या मृल्य निर्धारित किये गये थे। एक युद्ध के लिये क्रय हस्पात के हो प्रत्यारच्या मृल्य निर्धारित किये गये थे। एक पुद्ध के लिये क्रय हस्पात के किये श्रीर दूसरा ज्यवसायिक प्रयोग के लिये, परन्तु १ श्रमेल १९४६ से केवल एक ही प्रत्यारच्या मृल्य निर्धारित है। परिस्थित के परिवर्तन के साथ प्रत्यारच्या मृल्य श्रीर विकय मृल्य वदलते रहते हैं।

प्रशुक्त मराइल की विकारिशों के अनुचार सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि १६५५-५६ से १६५६-६० तक की अवधि के लिये ३६३ ६० प्रति टन के प्रत्यारज्ञण मूल्य की एक ही दर टाटा कम्पनी और इन्डियन आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिये नियत की जानी चाहिये। इस पुनर्निश्चित मूल्य के लागू करने के लिये सरकार का प्रस्ताव फरवरी १६५६ में पास हुआ। इसी समय १६५४-५५ के लिये पुनर्पारिज्ञित प्रत्यारज्ञण मूल्य ३४३ ६० प्रति टन का टाटा आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिए शारे ३८६ ६० प्रति टन का इन्डियन आयरन एएड स्टील कम्पनी के लिए नियत किया गया। इस बात को सव ने स्वीकार कर लिया कि १६५४-५५ का समायोजित प्रत्यारज्ञण मूल्य और ३६३ ६० प्रति टन के समान प्रत्यारज्ञण मूल्य का अन्तर प्रत्येक कम्पनी अपने विकास कीष में दे देगी।

भूतकाल में इस्पात का मूल्य व्यव्हें, कलकत्ता, मद्रास, जमशेदपुर श्रीर वरनपुर में ५०० रुपये प्रति टन या, श्रीर श्रन्य स्थानों पर उपमोक्ताश्रों को उसके साथ परिवहन व्यय मिला कर देना पढ़ता था। इसका श्र्म यह था कि (१) उत्तर प्रदेश, पजाब श्रीर उत्पादन केन्द्रों तथा बन्टरगाहों से दूर स्थित नगरों के उपमोक्ताश्रों को श्रिषक मूल्य देना पढ़ता था, श्रीर (२) बन्दरगाहों के निकट उद्योग केन्द्रित होते जा रहे थे स्थोंकि उन्हें वहीं इस्पात सत्ता मिलता था। सरकार की चृत १६५६ की नई नीति के श्रनुसार इस्पात का एक ही मूल्य (५२५६० प्रति टन) जिसमें रेल का किराया सम्मिलित होगा रेल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा। इस प्रकार कपर बताये हुए पंची स्थानो पर उपमोक्ताश्रों को २५ ६० प्रति टन श्रतिरिक्त मूल्य देना पढ़ेगा श्रीर उन उपभोक्ताश्रों को जो श्रमृतसर श्रीर कानपुर ऐसे स्थानों में हैं लगमग ३५ ६० प्रतिटन कम देना पढ़ेगा। पहले मूल्य

में समानता लाने के लिये सिद्धान्त का प्रयोग केवल इस्पात के सम्बन्ध में ही लागू किया गया था। यन यह सिद्धान्त ढाले हुए लोहे के सम्बन्ध में भी लागू किया जायगा। इस नई नीति के कारण इस्पात छोर लोहे के मूल्य में भारत के उत्तरी माग में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कमी हो जायगी प्रोर दुर्लम वस्तुयें प्रत्येक को युक्ति सगत मूल्य पर प्राप्त हो सर्केंगी।

इस्पात के मूल्य पर सरकारी नियन्त्रण उपभोक्तात्रों के लिये लाभकारी िस हुत्रा है क्यों कि निना इस नियन्त्रण के उन्हें ये वस्तुय अधिक मूल्य पर प्राप्त होती। परन्तु कम प्रस्थार ज्ञण मूल्य के नियत किये जाने से उत्पादकों को हानि हुई हैं। यदि उत्पादकों को उँचा मूल्य मिला होता तो वे अवश्य उत्योग के विस्तार करने में तथा श्रमिनवीकरण में व्यय किया जाता। अन्य उन्हें इस काय के लिये सरकार से ऋण लेना पड़ा है श्रीर सरकार ने मूल्य समीकरण कोप (equalisation fund) से यह ऋण दिया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने टाटा कम्पनी श्रीर स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल को तथा अन्य इस्पात के उत्पादकों को वह धन ऋण के रूप में दिया है लो कि न्यायत उन्हीं का था। यदि इस्पात कम्पनियों को ऐसे श्रयसर पर जब कि इस्पात का मूल्य वढा हुशा है श्रीधक मूल्य का लाम न उठाने दिया जायगा तो आर्थिक मन्दी के समय जब मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है वे हानि का सामना कैसे करेंगे।

भविष्य की मोंग — लोहा श्रीर इस्पात मेजर पेनेल ने १६४६ में श्रमुमान लगाया कि मारत में २० लाए टन इस्पात की खपत है, जब कि युद्ध के
पूर्व केवल दस लाख टन की खपत थी। परन्तु १६४० में परामर्शदात्री नियोजन
परिषद ने श्रमुमान लगाया कि देश में सामान्य स्थित में १५ लाख टन इस्पात
की खपत है। कृषि तथा श्रीद्योगिक विकास पर विचार करते हुये योजना श्रायोग
ने श्रमुमान लगाया कि १६५२ में कुल ३२ लाख टन की श्रावश्यकता होगी ग्रीर
१६५७ तक २८ लाख टन की श्रावश्यकता हो जायगी। लोहा श्रीर इस्पात पेनल
ने श्रमुमान लगाया है कि भारत को फाउन्ड्रियों के लिये प्रतिवर्ष ३ लाख टन ढले
हुये लोहे की श्रावश्यकता होगी। वाणिज्य मन्त्रालय के छोटे श्रीर बढे इजीनिरिंग
उद्योग के जाँच करने वाले पेनेल ने १६५१ में बताया कि मारत को ४ लाख
से ४.२ लाख टन तक ढले हुये लोहे की श्रावश्यकता थी। द्वितीय पचवर्षीय
योजना का श्रमुमान है कि १६६०-६१ में इस्पात की माँग लगभग ४५ लाख टन
की श्रीर फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की माँग लगभग ७५ लाख टन की होगी।
मुख्य उत्पादकगण ढला लोहा श्रपने प्रयोग के लिये तथा फाउन्ड्रियों के लिये ही

उत्पादित करते हैं। इसलिये फाउन्ड्रियों के लिये ढले लोहे की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये प्रमुख उत्पादकों को अपने उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी।

योजना के अन्तर्गत — दितीय पचवर्षीय योजना ने भारत में इस्तात के उत्पादन के विकास पर विशेष महत्व दिया है। उद्योगीकरण की वर्तमान बढ़ी हुई प्रगति को बनाय रराने के लिये थ्रीर भारत में यन्त्रों के निर्माण करने वाले उद्योग को स्थापना करने के लिये यह श्रावश्यक होगा कि इस्तात के उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाय। दितीय योजना में १६६०६१ तक ४३ लाख टन इस्पात के उत्पादन का प्रवन्व किया गया है। इसमें से वर्तमान तीन प्रमुख उत्पादक श्रपने विस्तार के कार्य कम को पूर्ण कर लेने के पश्चात् लगभग २३ लाख टन की पूर्ति कर सकेंगे। सरकारी चेत्र में तीन नये स्थापित प्रमुख उत्पादक लगभग २० लाख टन का उत्पादन १६६०-६१ तक कर सकेंगे यद्यपि उनके उत्पादन की चरम सीमा कहीं श्रिषक होगी।

लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन को प्रधानता देने के निर्ण्य के श्रनुकृत द्वितीय पचवर्षीय योजना में सरकारी चेत्र के श्चन्तर्गत तीन इस्पात के कारखानी की स्थापना का निश्चय है जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन होगी, श्रीर इन तीन में से एक को ३०५ लाख टन फाउन्ड्रियो के प्रयोग में श्राने वाला ढला हुश्रा लोहा तेयार करने की सुविधार्ये पाप्त होंगी । रूरकेला में खोले गये कारखाने में १९५६-६१ में १२८ करोड़ रुपये के विनियोग का श्रनु-मान है। यह त्राशा की जाती है कि ७.२ लाख टन इस्पात की चपटे श्राकार की वस्तुत्रों का उत्पादन करेगा। दूसरा कारखाना, जो कि मध्य-प्रदेश में भिलाई स्थान पर स्थापित किया गया है, उस पर लगभग ११० करोड़ रुपया व्यय किये जाने का श्रनुमान है। उससे हम श्राशा करते हैं कि ७'७ लाख टन विकय योग्य इस्तात तथा वजनी श्रीर मध्य श्रेणी की वस्तुत्रों का उत्पादन हो सकेगा जिसमें १.४ लाख टन पत्रक का भी रि-रोलिङ्ग उद्योग के लिये उत्पादन सम्मिलित होगा। तीसरा कारसाना दुर्गपूर में, जो कि पश्चिमी बगाल में स्थिति है, खोला गया है जिसमें लगभग ११५ करोड़ रुपये के व्यय होने की आशा है। यह कारखाना ऐसे प्रसाधनों से युक्त होगा कि वह इल्की श्रीर मध्य श्रेणी की इस्पात तथा पत्रक की वस्तुत्रों का निर्माण ६.६ लाख टन तक प्रतिवर्ध कर सकेगा।

सरकारी चेत्र के समान ही न्यक्तिगत चेत्र में भी हस्पात श्रौर लोहे का स्थान श्रोद्योगिक योजना में एक बहुत वही महत्ता रखता है। हस उद्योग पर न्यक्तिगत चेत्र में लगभग ११५ करोड़ रुपये के विनियोग का विचार किया गया है। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत न्यक्तिगत चेत्र में लोड़े श्रौर हस्पात उद्योगों के

विस्तार सम्बन्धी विनियोग तथा जो कुछ व्यय द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत किया गया है उस सन का फल १६५६ के मध्य से मिलना प्रारम्भ होगा जबकि टाटा श्रायरन एएड स्टील कम्पनी तथा इिएउयन श्रायरन एएड स्टील कम्पनी की समुक्त उत्पादन शक्ति वर्तमान १२५ लाग दन के स्थान पर २३ लाख दन के लगभग हो जायगी।

दितीय पचवपीय योजना ने इस्वात ख्राँर लोहे के उत्पादन के बढ़ाने पर उचित ही ध्यान दिया है। इस्वात प्रधिक मात्रा में ख्रौदोगीकरण का ख्राधार है ख्रौर इस्वात के उत्पादन की वृद्धि ख्रौदोगिक उज्ञति के लिये ख्रत्यन्त ख्रावश्यक है। लोहे का उत्पादन बढ़ाने में सरकारी चेत्र पर बहुत ख्रधिक विश्वास है। रूप्त मई, १९५५ को वेन्द्रीय सरकार ने लोहे ख्रीर इस्वात के लिये एक मञ्चालय की नियुक्ति की जिस पर लोहे ख्रीर इस्वात के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी कार्यों का तथा सरकारी फाउन्ड्रीयों की दैरामाल का भार राया गया। कुछ लोगों के मत में यह ख्रधिक ख्रन्छा होता यदि इस्वात के उत्पादन में वृद्धि करने का भार मुख्य रूप चे वर्तमान उत्पादकों के अपर ही छोड़ दिया गया होता बयोकि उन्हें इस बात का ख्रायश्यक ख्रनुभव था ख्रीर सम्भवत. वे ख्रियक ख्रीकता से ख्रीर कम लागत पर उत्पादन की वृद्धि करने में सफल भी हुये होते।

#### सीमेन्ट उद्योग

सीमेन्ट के उत्पादन में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १६४८ में केवल १५ लाख टन का उत्पादन या जो १६५७ में बढ़ कर ५६ लाख टन हो गया। १६५२ में भारत में केवल २३ फेनिट्रयाँ थीं, जिनकी उत्पादन शक्ति ३७ ६ लाख टन थी। १६५७ में २६ फैनिट्रयाँ थी जिनकी स्थापित सामध्य ६६३ लाख टन थीं। भारतीय सीमेन्ट उद्योग की वास्तिवक उत्पादन शक्ति में नह फेनिट्रयाँ की स्थापना तथा पूर्व की फैनिट्रयों के विस्तार के कारण वृद्धि हुई है। सीमेन्ट उद्योग को ज्ञनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, (१) मृतकाल में उत्पादन की मात्रा उनकी वास्तिवक उत्पादन शक्ति से बहुत कम थी और १६५० में जब कि वास्तिवक उत्पादन शक्ति ३१ २ लाख टन थीउस समय उत्पादन केवल २६ १ लाख टन था। परन्तु इधर हाल में इस टोप का किसी सीमा तक निराकरण कर दिया गया है, (२) बहुत फिन्ट्रयाँ ज्ञनुकूलतम उत्पादन शक्ति से बहुत नीचे स्तर पर हैं, नवीन फैन्ट्रयाँ उपगुक्त ज्ञाकार की हैं और अेव्डतम यन्त्रों का प्रयोग कर रही हैं। (३) सीमेन्ट उद्योग को ज्ञावश्यक सख्या में मालगाड़ी के डिक्वे नहीं प्राप्त होते जिनसे कच्चा माल लाया जा सके और तेयार सीमेन्ट उपभोग केन्द्रों को शीवता पूर्वक मेजा जा सके, और (४) सीमेन्ट का नियन्नित मूल्य सब फैक्ट्रियों के

हिष्टिकोण से न्यायोचित नहीं रहा है, नयों कि अन्य फैक्टिनों में तन्तनाय जो अधिक व्यवस्थित थीं कुछ फैक्टिमों का उत्पादन व्यय अधिक रहा है ।

टघर हाल में स्थित में घोर परिवर्तन हुआ है। मीमेन्ट दुर्लभ ही नहीं वरन् वहुत महगा भी हो। गया है। इस बात को विचाराधीन करते हुये सरकार ने सीमेन्ट का क्रय विकय अपने हायों में ले लिया है और उसके लिये एक विकय मूल्प १ जुलाई १९५६ से लागू कर दिया है। मब सीमेन्ट के उत्पादकों को अब अपना सीमेन्ट स्टेट ट्रेडिझ कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राहवेट लि०) के हाथ फेन्ट्री के बाहर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचाने में लगे रेलवे के किराये के आधार पर नियत मूल्य पर वेचना होगा। यह कारपोरेशन सीमेन्ट १०२ ६० प्र आने प्रति दन के मूल्य पर वेचता है। मई १९५७ में सीमेन्ट पर लगा उत्पादन कर ५ ६० प्रति दन के मूल्य पर वेचता है। कई १९५७ में सीमेन्ट का मूल्य भी इतना ही बढ गया।

देश के विभाजन के फलस्यरूप कुछ सीमेन्ट की फैरिट्रयाँ पाकिस्तान में चली गर्छ । यही कारण था कि १६४७ में उत्पादन घट कर १५ लाख टन हो गया जब कि १६४५ में २२ लाख टन था। परन्तु देश ने बहुत शीघ ही विभाजन के प्रभावों से मुक्ति पाली श्रीर उत्पादन में वृद्धि श्रारम्भ हो गई जो श्राज तक निरन्तर चल रही है। युद्रोत्तर काल में सीमेन्ट उद्योग की विकास सम्बन्धी उल्लेखनीय विभेषताएँ यह हैं, (१) १६३६ में सीमेन्ट उन्नोग प्राय मध्य प्रदेश श्रीर मध्य मारत मे ही केन्द्रित था। परन्तु एसोशियेटेड सीमेन्ट प्रम्पनी द्वारा युक्तिकरण की योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप कुछ फैक्ट्रिया को नये स्याना पर स्थापित किया गया। युद्रोत्तर काल में इस उद्योग का विकास स्रधिक **य**न्तुलित ढग पर हुया श्रीर नवीन स्थानो पर कारसाने स्थापित हुये। इसका परिणाम यह हुआ कि सीमेन्ट के कारपाने सम्पूर्ण देश में फेले हैं। इससे देश के विभिन्न भागों मे प्राप्त होने वाले करूचे माल का भी उचित प्रयोग सम्भव हो गया है। साथ ही यातायात में बहुत सा व्यर्थ व्यय जो उत्रोग के किसी एक स्थान पर केन्द्रित होने के कारण करना पड़ता वह भी बच गया। (२) भृत काल में सिमेन्ट उद्योग व्यक्तिगत उपक्रम था, परन्तु यत्र रास्तार ने भी इस उपक्रम में भाग लेना यारम्म कर दिया। मैस्र राज्य की फैन्ट्री के यतिरिक्त, जिसकी उत्पादन शक्ति ३६ हजार टन से बढ़ा कर ६० हजार टन कर दी जायगी, उत्तर प्रदेश की राजकीन फेन्ट्रो पिपरी में स्थापित की है जिसकी उत्पादन शक्ति रई लाख की है। (३) भूतकाल मे अधिकाँश कारसाने ८००० टन ही के स्रनाधिक से भी कम उत्पादन वाले थे। परन्तु हाल में जो कारपाने स्थापित किये गये हैं वे ब्राधिक

दृष्टि से उपयुक्त हैं श्रीर प्राय सभी कम मात्रा में उत्पादन करने वाले कारखानों ने अपनी उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है।

चीमेन्ट की श्रान्ति साँग उसकी पूर्ति से श्रिषक होगई। देश में उत्पादन की वृद्धि के श्रालावा १६५६ के प्रारम में यह निश्चय किया गया कि उस वर्ष विदेशों से ७ लाख टन चीमेन्ट का श्रायात किया जाय। राज्य-ज्यापार निगम (State Trading Corporation) ने इस मात्रा के श्रायात के लिये टढ ज्यवस्था कर रखी थी किन्तु बीच में स्वेज का सकट उपस्थित हो जाने पर १६५६ में केवल १००,००० टन चीमेन्ट हो श्रा सका। १६५७ में ३२१,००० टन चीमेन्ट श्रीर श्राया। १६५० में श्रायात श्रीर कम होगा। इसका कारण विदेशी विनियम का सकट तथा देश में उत्पादन का तीत्रता से बढना है।

योजना के श्रन्तर्गत-प्रयम योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि सिमेट के कारखानों की सख्या १६४०-५१ में २१ से बढ़ाकर १६५५-५६ में २७ कर दी जाय। साथ ही इनकी ३३ लाख टन की उत्पादन शक्ति तथा २७ लाख टन उत्पाटन बढाकर १६५५ ५६ में क्रमश ५३ लाख टन ख्रौर ४८ लाख टन कर दिया जाय। मध्य प्रदेश, मध्यभारत ग्रौर ट्रावनकोर कोचीन में सिमेंट के कारखानों को प्रतुर्गाखत शक्ति में वृद्धि का कोई नियोजन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा श्रीर बम्बई में नवीन कारखाने खोले जाने वाले थे। बिहार, राज-रथान ब्रोर मद्राप्त के कारखानों की शक्ति में वृद्धि करना श्रस्यन्त श्रावश्यक था जो पूर्व के कारखानों में श्रांतिरिक्त नवीन मशीनों के प्रयोग से ही सम्भव था। इस कार्य के करने में प्रधान कठिनाई घन के भ्रमाय की थी। कारखानों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने श्रोर उन्हें १३ लाख दन प्रति वर्ष उत्पादन करने योग्य बनाने के लिए बहुत श्रधिक मात्रा में घन की श्रावश्यकता है। उत्तर पदेश की चिमेंट फीद्री की स्थापना में, जो कि मिर्जापुर जिले में चुर्क में है, ४३ करोड रूपये की लागत लगी थी। उसकी उत्पादन शक्ति २५२ लाख टन प्रतिवर्ष की है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री का कुल व्यय सरकारी कर्मचारियों की श्रनुमवहीनता के कारण बहुत श्रधिक हो गया है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की वह चर्नोचम फैक्ट्रियों में से एक है।

प्रथम योजना में श्रनुगियत उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये थे, परन्तु काफी हद तक सफलता श्रवश्य मिली थी। १६५५-५६ में टीमेंट की उत्पादन शक्ति श्रीर उत्पादन कमश्र ४७४ लाख टन श्रीर ४४ लाख टन थी जबिक प्रथम योजना में क्रमशः ५३ लाख टन श्रीर ४८ लाख टन का लक्ष्य था। देश के श्रीयोगीकरण में उन्नति हो जाने पर सीमेंट

की माँग मे वृद्धि होगी। इसिलये दितीय योजना ने १६६०-६१ तक उत्पादन शिक्त को १६० लाख टन तक (जिसमें से भू लाए टन सरकारी चेत्र में बढेगा) त्रोर वास्तिविक उत्पादन को १३० लाख टन वढाने का लक्ष्य वनाया है। त्रव तक भारत सरकार द्वारा ५४ स्कीम जिनमे २५ नई हैं तथा २६ वर्तमान उत्पादन इकाइया के विस्तार से सम्बन्धित हैं, मज्द की गई हैं। यह स्कीम प्रगति के विभिन्न स्वरों पर हैं। इनमें से १५ स्कीम ( ४ नई तथा ११ विस्तार सम्बन्धी ) जिनकी कुल उत्पादन शिक्त १९ छोर स्कीम पूरी हो जाँयगी तथा छाशा की जाती है कि इस समय तक कुल उत्पादन शिक्त १०४ लाए टन हो जायगा। शेय स्कीम १६६० ६१ तक पूरी होगी।

### कागज उद्योग

वर्तमान समय में भारत में कागज की १६ मिलें हैं जिनकी स्थापित उत्पादन शक्ति २५०,००० टन है। कागज उन्त्रोग को १६२५ में १६४७ तक सर्जाण दिया गया था। इस उद्योग ने नि:सन्देह उल्लेखनीय प्रगति की। १६५२ में भारत में केवल ६ मिलें थीं जिनकी उत्पादन-शक्ति २७ इज़ार टन थी। १९५६ में २१ मिलें थी तथा उनकी उत्पादन शक्ति २१९,६०० टन थी। १६५७ में मिलों की सख्या घटकर १६ होगई क्योंकि उत्पादन की दो इकाइयाँ जो बन्द सी ही थीं सूची में से हटा टी गई। किन्तु विस्तार की योजनाश्रों के पूरी हो जाने के कारण उद्योग की स्थापित उत्पादन शक्ति बढकर २३ लाख टन हो गई है। कागज उद्योग की तीन श्रेणियाँ हैं (१) कागज ख्रीर पटा, (२) श्रखनारी कागज की सूखी दफ्ती तथा श्रन्य प्रकार की दिफ्तयाँ। कागज तथा पह के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूली दिक्तयों तथा भ्रन्य पकार की दिक्तयों के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। परन्तु देश में श्रखनारी कागज का बहुत श्रभाव है। भविष्य में कागज उद्योग का विकास करते समय श्रखनारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने की सस्मया पर विशेष ध्यान देना पडेगा । युद्ध के उत्तर काल में (श्र) यह उद्योग नवीन स्थानों पर भी श्रारम्म हो गया है श्रीर श्रधिकांश प्रदेशों में श्राज कागज बनाने वाली मिल हैं, (ब) श्रव श्रनेक प्रकार के कागज तथा दिक्तियों का उत्पादन होने लगा है यहाँ तक की इन्ले स्त्रोर ट्रिग्ले टिम्तयों तथा काफ्ट लपेटने के कागज के उत्पादन में तो विशेष प्रगति हुई है।

कागज उद्योग की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उत्पादन शक्ति की बहुत श्रिधिक प्रतिशत मात्रा का उत्पादन हुआ है। १६४८, १६४६ और १६५० में कमशः ६७,००० टन, १०३,२०० टन और १०८,६१२ टन का उत्पादन हुआ था जो कि उत्पादन शक्ति का लगभग द्र %, ६४% और दर % होता है। १६५७ मे २१०,१२५ टन का उत्पादन हुआ जो कि उत्पादन शक्ति का द्र ३% था। यह सब होते हुये भी कागज उद्योग को अभिकों के मनाडे तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल के न्यायोचित मूल्य पर न मिल सकने की किठनाइयों का सामना करना पड़ा है और निम्न स्तर के कोयले का जिसके लिये इन्जनों के बायलर अनुपयुक्त हैं, प्रयोग करना पड़ता है। बीस और घास के मैदानों के न्यायोचित मूल्य पर दीर्घमालीन पट्टों पर न उटाये जाने के कारण हानि उटानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त जब से रेल विमाग ने अपनी अधिमान्य पद्धति (Preferential System) को माल के यातायात सुविधा के सम्बन्ध में परिवर्तित कर दिया है कागज उद्योग को जो प्रधानता मिलनी थी उसका अन्त हो गया है और अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ उसे भी यातायात सुविधा पाने में प्रतीह्या करनी पढ़ती है। इन किठनाइयों के कारण ही कागज उद्योग की उत्पादन लागत तथा उत्पादन मात्रा कम हो गई है।

कचा माल-कागज श्रीर पट्टा श्रयवा टक्ती उन्नोग श्रपने कन्ने माल के लिये बाँस छोर सबई घास का उपयोग करता है। इसके श्रतिरिक्त कुछ कार-खाने चियहे, रही कागज, चोनी की सीठी इत्यादि का उपयोग करते हैं। भारत में ऐसे कच्चे माल का कुछ ग्रभाव नहीं. परन्तु उद्योग के उपयोग के लिये इनकी प्रित का सगठन करने की ब्रावश्यकता है। कागज उद्योग में ब्रनेक रसायनों जैसे चूना, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, न्लोरीन, गधक श्रादि का भी उपयोग किया जाता है। गधक को छोड़ कर श्रन्य सब रसायनिक भारत में ही मिल जाते हैं। कुछ सीमा तक कास्टिक सोहा और सोडा ऐश का विदेशों से आयात करना पहता है। मन्य प्रदेश के नागज के कारखाने सवाई की लकडी का प्रयोग करते हैं। परन्तु इसके साथ ही चीड़, देवदार, श्रीर एक प्रकार के सरो के वृज्ञ की कोमल लक्डी का भी उपयोग किया जा सकता है जिसकी भारत में बहुतायत हैं। यदि मुलायम लक्ड़ी के वनों का विकास किया जान, लकड़ी को कारखानों तक पहुँचाने के लिये यातायात की उचित व्यवस्था की जाय श्रीर एक कारखाना त्रखबारी कागज श्रौर केमिकल पल्प बनाने के लिये स्थापित किया जाय तो श्रखवारी कागज उद्योग के लिये ग्रावश्यक वच्चे माल की पूर्ति को बढ़ा सकना सम्भव है। कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुक्ताव दिये थे, (१) कागज उद्योग के काम ल्राने वाले पेडों के वनों की सुरज्ञा की जाय ल्रौर इनका उपयोग कर सकने के लिये उद्योग को दीर्घकालीन पट्टे के अधिकार दिये जॉय (२) बॉस श्रीर सबई घास के सारे देश में एक तर्क सगत आधार पर मूल्य

निर्धारित किये जाँय जिससे उत्योग को फच्चा माल निरतर प्राप्त हो सके। राज्य सरकारों के हितों की रक्षा करने के लिये कच्चा माल एक निश्चित मूल्य पर उनोगों को दिया जाय श्रोर इस के साथ ही उन के तैयार माल की विकय मूल्य से सम्बन्धित प्रन्यानि (premium) की कोई मात्रा लाभाश में से उनसे वसूली नाय, (३) यातायात की सुविधा के लिये जगलों में सहके बनाई जींय, श्रोर (४) कपटों की कतरन, पटसन भ्रोर जूट तथा रही कागज का निर्यात विल्कुल बन्ट

यह खेट की बात है कि वन विकास के सबन्ध में राप्य सरकारों की कोई सुसाद नीति नहीं है श्रोर कागज की मिलों को जगल पट्टें पर देने में बहुत श्रविक कर टिया जाय। मूल्य वसूल करती हैं। रेल परिवहन के भाडे की दर भी श्रधिक है। मारत सर-कार पुराने श्रखवारों की रही के त्रायात पर मारी श्रायात कर वस्ल करती है श्रीर ग्रपनी रही का स्टाफ िना किसी बात का व्यान किये ठेकेदारों को वेच देती है, जो उसे पैकिंग इत्यादि के लिए बाजार में वेच देते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की नीति में परिवर्तन करने से उद्योगी को कचा माल पर्याप्त मात्रा

योजना के अन्तर्गत - विभिन्न कागज की मिलों के प्रधार कार्यक्रम को में दिया जा सकता है। लागू फरने से यह आशा की जाती है कि प्रथम योजना काल में उद्योग की उत्या-टन शक्ति २११,००० टन कागज श्रीर दिक्तयाँ श्रीर ३०,००० टन श्रखनारी कागज की हो जायगी श्रीर १९५५-५६ तक २००,००० टन कागज श्रीर दिक्तयाँ श्रोर २७,००० टन श्रखवारी कागज का वास्तविक रूप से उत्पादन हो जायगा। भूसे इत्यादि से बनने वाली दिक्तयों के उत्पादन सवन्ध में श्रनुमानतः १६५५-५६ क उद्योग को वार्षिक उपादन शक्ति ५८,५०० टन हो जायगी श्रीर वारतिवक

काराज श्रोर काराज की दिम्तयों के उद्योग के सबन्ध में प्रथम योजना के उत्पादन ५२,००० टन होगा। लक्ष्य लगभग पूरे हो गये । श्रखनारी कागज का उत्पादन करने वाली सर्वप्रथम मिल ने १९५५ में कार्य भ्रारम किया। यद्यपि इसका उत्पादन श्रमी बहुत कम है पर श्राशा की जाती है कि जम यह मिल शक्ति भर उत्पादन करेगी तब ३०,००० टन अखनारी कागज का उत्पाटन सभव हो सक्ता। द्वितीय योजना मे यह प्रस्ताव किया गया है कि १९६०-६१ तक स्थापित उत्पादन शक्ति तथा कागज श्रीर कागज की दिपनियों का वास्तविक उत्पादन बढ़ा कर कमश ४५ लाख टन और ३५ लाल टन कर दिया जाय श्रीर श्रखनारी कागज के स्थापित उत्पादन शक्ति तथा वास्तविक उत्पादन वढाकर ६०,००० टन तक कर दिया जाय । द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण कर सकने के लिये यह आवश्यक होगा कि (१) कागज उद्योग के कार्य को उरलता से चलाने के लिये देश का आर्थिक वातावरण अनुकूल बनाया जाय, (२) कच्चे माल तथा तैयार माल के यातायात के लिये मालगाडी के डिट्नों की पूर्ति बढाई जाय, और (३) कच्चे माल की पूर्ति बढाई जाय। मारत में चीनी उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में होने के कारण गन्ने की सीठी का कागज बनाने के लिए प्रयोग बडे लाम के साथ किया जा सकता है। १६५५ के अन्त में जर्मनी के विशेषजों का एक दल मारत में इस विषय का परीच्या करने तथा रिपोर्ट देने के लिये आया था। पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म से सीठी पर आधारित १०० टन प्रतिदिन का उत्त्यादन करने वाली उत्पादन इकाई की स्थापना पर बातचीत चल रही है।

श्रन्य उद्योगों की भाँति कागज उत्योग के उत्पादन के प्रकार तथा उत्पादन व्यय कम करने के लिये उपाय करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। योजना श्रायोग ने यह श्रिमस्ताव किया है कि कागज उद्योग को श्रपने उत्पादन की प्रविवि को श्राधुनिक बनाना चाहिये जिससे वह निम्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, (१) ईंधन तथा कच्चे माल के प्रयोग में कभी करके कागज की उत्पादन लागत में कभी, श्रीर (२) विभिन्न प्रकार के कागजों, विशेषकर रेपिंग श्रीर काफ्ट कागज, की प्रकार में उन्नति। यदि यह सुधार सम्भव हो सके तो कागज उद्योग में स्थायित्व श्रा जायगा।

# छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले तथा कटीर उद्योग

मारत की श्रीयोगिक व्यवस्था में छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले ग्रीर कुटीर उद्योगों का स्थान सदा से ही महत्वपूर्ण रहा है। शिल्पकारों की एक बहुत बड़ी सख्या सदैव इन उद्योगों पर ही अपनी जीविका के लिये निर्भर रही है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने छोटी मात्रा में उत्पाटन करने वाले तथा कुटीर उन्योगों को भारत में वेकारी की कठिन समस्या को इल करने के साधन के रूप में रत कर इनकी श्रोर श्रधिक घ्यान श्राकिषत किया है। इसके पूर्व कि द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत इन उत्रोगों के विकास कार्यक्रम पर विचार करें यह श्रावश्यक होगा कि इन उद्योगों की कठिनाइयों का परी इण किया जाय।

उद्योगों को प्राय: तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, (१) वडे पैमाने पर उत्पादन करने वाले ग्रथवा बडे उत्रोग, (२) छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले ग्रयवा छोटे उद्योग, (३) कुटीर उत्योग। इन उद्योगो को विभिन्न प्रकार से परिमापित किया गया है। एक मत के अनुसार कुटोर उन्योग वे उद्योग हैं जो शिल्पियों द्वारा स्वय ग्रापने ग्राप ही ग्रायवा किसी कारखानेदार के निर्देशन में वर पर ही किये जाते हैं। यदि कार्य छोटे कारखाने में किया जाता है छौर उसका निर्देशन उत्योगपित द्वारा किया जाता है तो उसे इक छोटा उत्योग कह सकते हैं चाहे शक्ति सचालित मशीनों का प्रयोग न मी किया जाय। एक भ्रन्य मत के ग्रनुसार घरेलू उद्योग वह है "जो ग्रमतः मुभवा पूर्णतः परिवार के ही सदस्यों की। सहायता से चलाया जाता है चाहे वे सम्पूर्ण दिन कार्य करें या थोड़ी देर ही। नित्य कार्य करें"। श्री चिन्तामणि देशमुख के मतानुसार "घरेलू छद्योग" प्रायः हम उन सन उत्पादन के उपक्रमों को कहते हैं जो वडे-वडे व्यवस्थित कारखानो के श्रविरिक्त हैं। जो व्यक्ति इन उपकर्मों में लगे हुये हैं मुख्यतः श्रपने ही प्रयत्न ग्रीर कीशल पर निर्मर रहते हैं, सीध-सादे ग्रीजारों का प्रयोग करते है ज्रोर श्राने घर पर ही कार्य करते हैं। विशिष्ट ज्यावश्यमता क्रों के कारण इस प्रकार के कुछ उद्योग हाल में आरम्भ हुये हैं। ये उद्योग प्रधानत परम्परागत हैं स्रोर वर्तमान उत्पादन प्रविधि से स्पर्धा करते हुथे श्रापनी रह्या में प्रयक्षशील है। छोटे पेमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग "घरेलू तथा प्राम्य उद्योगों से इस ग्रथ म भिन्न हैं कि उनको सचालित करने वाले उद्योगपति होने हैं जो पारिश्रमिक पर रक्से हुये अमिकों से कार्य लेते हैं।"

उपर्वक्त परिभाषात्रों को विचाराधीन रखते हुये इम यह कह सकते हैं कि वरेलू उन्नोग की निन्न विशेषतार्थे हैं, (१) ऐसे उन्नोगों को घर पर ही बिना श्रीमकों की सहायता के स्वय चलाया जाता है, (२) इनमें परम्परागत टग का ही श्रनुसरण किया जाता है, श्रौर (३) इनका स्वतंत्र तथा पूर्ण समय का कार्य होना त्रावश्यक नहीं हैं, ये कृषि तथा किसी श्रन्य व्यवसाय के सहायक हो सकते हैं। छोटे उत्रोग श्रथवा योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की मुख्य विशेषता यह है कि ये कार्य करने वालों के घर में नहीं चलाये जा सकते श्रौर कार्यक्त्तां के श्यावश्यक स्रोत नितान्त सीमित होते हैं। योड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों के कार्य करने वाले अमिकों की सख्या १० से ५० तक सीमित है। हमारे देश में उपर्युक्त दोनों वर्गों में म्रानेवाले म्रानेक उद्योग हैं जैसे कर्घा, कन, रेशम, गुड, राब, तेल पेरने, ताले बनाने के कार्य इत्यादि। इन उद्योगों में काम में सहायता देने वाले परिवार के सदस्यों श्रीर समय पर इनमें कार्य करने वाले उन व्यक्तियों की सख्या को छोड़कर को कृषि श्रादि श्रन्य मुख्य व्यवसाय में सलग्न है, लगभग २० लाख व्यक्ति कार्य करते हैं। इन दोनों प्रकार के उद्योगों का ग्रामों श्रीर नगरों टोनों में ही पूर्ण श्रयवा श्राशिक समय के लिये श्रनुसरण किया जाता है। हैएडी कैंफ्ट का उन्रोग जैसे वेल-त्रूटे काढने का कार्य, पीतल का कार्य, रेशम बनाने का कार्य इत्यादि पूर्ण समय के कार्य है श्रीर इन कार्यों में सलम व्यक्तियों ने उत्कृष्ट ज्ञमता भी प्राप्त कर ली है।

लाभ मि (१) घरेल् उद्योग श्रोर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्योगों का धवसे बड़ा लाम तो यह है कि वे बहुत बड़ी सख्या में कार्य का श्रवसर प्रदान करते हैं। कितने व्यक्ति कुटीर श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों में कार्य करते हें श्रीर वे कितना कितना उत्पादन करते हें इस सम्बन्ध में ठीक ठीक श्रॉकडे प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय श्राय धमिति ने यह श्रनुमान लगाया था कि १६५०-५१ में छोटे उत्योगों का उत्पादन ६१० करोड़ रुपये का हुश्रा या श्रीर लगभग ११५ लाख व्यक्ति उनमें कार्य करते ये जबकि फैक्ट्रियों में लगभग ३० लाख व्यक्ति कार्य करते ये श्रीर उनके कुल उत्पादन का मूल्य लगभग ५५० करोड रुपया था। इन छोटे उद्योगों में कुटीर उत्योग भी सम्मिलित थे पर वे छोटे छोटे कारखाने जो फैक्ट्री एस्ट के श्रवर्गन श्राते थे। इनमें सम्मिलित नहीं किये गये थे। समिति ने उन्हें फेक्ट्रियों में सम्मिलित किया था। यदि इम इन छोटे छोटे कारखानों को भी घरेलू श्रीर छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्येगों में सम्मिलित कर लें श्रीर हाल में जितने लोग इनमें कार्य कर रहे हैं उनकी बढ़ी हुई सख्या को भी वचाराधीन रख लें तो कुल कार्य करने वालों की सख्या लगभग २०० लाख श्रीर

कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगभग १२०० करोड़ रुपये के हो जायेगा। पर यह एव गणना अनुमान मात्र है इसिलये विश्वस्त नहीं कही जा सकती। इन आँकड़ों से घरेलू और छोटे उद्योगों के विस्तार और मावी सम्भावना का ही कुछ अनुमान ही मिल सकता है।

- (२) कुटीर उद्योग की यह विशेषता है कि इसमें मूल्यवान् मशीने नहीं लगाई जाती हैं, इसके लिये किसी बड़ी इमारत इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है इसलिये इसको चलाने में अधिक पूँजी नहीं लगानी पड़ती। मारत में पूँजी का अभाव है और इमें कुछ ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जिनमें पूँजी कम लगे और अमिक अधिक।
- (३) इसके विपरीत बहे पैमाने के उद्योग में वैज्ञानिक श्रौर टेकनिकल ज्ञान की विशेष श्रावश्यकता होती है। परन्तु वर्तमान समय में (टेकनिशियन) प्राविधिनों का भारत में श्रमाव है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में यही लाभ है कि इनमें श्रविक प्राविधिक (टेकनिकल) ज्ञान श्रौर प्रविधिनो की श्रावश्यकता नहीं होती है।
- (४) छोटे पैमाने के और कुटार उद्योग बढे पैमाने के उद्योगों की तरह किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण देश में विस्तृत हैं। इनमें इमारत, सफाई, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिनका बढे पैमाने के उद्योगों को सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही युद्ध के समय इनके विनाश का मय भी कम रहता है। बढे पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों का तुल-नात्मक अध्ययन करते समय और इनके लाम-हानियों का विवेचन करते समय हमें उक्त सामाजिक व्यय का भी विचार करना चाहिये।
- (५) बढे पैमाने के उद्योगों की अपेचा छोटे पेमाने और कुटीर उद्योगों में रोजगार में अस्थिरता बहुत कम होती है। इमारे देश के आमीण व्यक्तियों का मुख्य उद्यम कुषि करना है और वे सहायक व्यवसाय के रूप में रस्ती बनाने, गुड़ बनाने, कपड़ा बुनने इत्यादि कायों को करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन सहायक उद्योगों में मंदी आ जाय तो अमिक अथवा कारीगर को उतनी श्रिषिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पढ़ेगा जितना किसी श्रीद्योगिक अमिक को मदी के कारण नौकरी छूट जाने पर करना पड़ता है।

कुटीर श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों से बड़े पैमाने के उद्योगों की श्रपेद्धा कुछ श्रिक लाभ होते हैं। श्रव प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों को कोन सा स्थान देना चाहिए। वित्त श्रायोग (१६४६-५०) के श्रनुसार इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर विचार करना श्रावश्यक है;

- (१) उद्योग के प्रकार,
- (२) उद्योग में टेकनिकल व्यवस्था,
- (३) उद्योग के संगठन के लिए आवश्यक अम और पूँजी,
- (४) त्र्यायिक दृष्टि से उत्पादन का किस सीमा तक उचित इकाइयों में विकेन्द्री करण किया जा सकता है केवल व्यक्तिगत व्यय को ही नहीं वरन् सामाजिक व्यय को भी विचाराधीन रखते हुए।

जहाँ तक उद्योग के प्रकार का प्रश्न है उसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, (१) ऐसे उद्योग जिनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ निश्चित लाम है श्रोर जिनको छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे लोहा श्रोर इस्पात उद्योग, सीमेंट, भारो रसायनिक श्रीर खदान उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों को कुटीर में श्रयवा छोटे पैमाने पर नहीं चलाया जा सकता है इसिलए इस चेत्र में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता है, (२) ऐसे उद्योग जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादन करके कुछ निश्चित लाभ उठाया जा सकता है, जैसे ताला मोमवत्ती, बटन, चप्पल, खाद्याज इत्याद उद्योग। इनमें से कुछ में छोटे पैमाने पर उत्पादन करने में उत्पादन व्यय कम होता है। खाद्याज के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जब वस्तुएँ हाथ से तैयार की जाती हैं तो उनमें पौष्टिक तत्व श्रिषक रहते हें, (३) ऐसे उद्योग जिन्हें बड़े श्रीर छोटे पैमानों पर चलाया जा सकता है। इन उद्योगों के सम्बन्ध में चुनाव का प्रश्न उठता है।

टेकिनिकल व्यवस्था के ग्राघार पर उद्योग को निम्नलिखित भागों में विमालित किया जा सकता है—(१) ऐसे उद्योग जिनमें बढ़े पैमाने के उद्योगों श्रीर कुटीर तथा छोटी मात्रा के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं हैं, जैसे मधु मक्खी पालन, गुरू बनाना तथा श्रन्य दस्तकारी के कार्य इत्यादि। (२) ऐसे उद्योग जिनमें छोटी मात्रा के श्रीर कुटीर उद्योग बढ़े पैमाने के उद्योगों के सहायक हैं, इनमें उन वस्तुश्रों का उत्पादन किया जाता है जिनकी बढ़े पैमाने के उद्योगों को श्रपनी उत्पादन प्रक्रिया को श्रागे बढ़ाने के लिये श्रावश्यकता होती है। बढ़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ श्रशों का उत्पादन हों उद्योगों के उत्पादन में सहायता देते हैं या उत्पादन की लम्बी प्रक्रिया में कुछ श्रशों का उत्पादन छोटे उद्योगों में किया जाता है, श्रीर (३) ऐसे उद्योग जिनमें बढ़े पैमाने के श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जैसे, कहाँ में बुना कपड़ा, खायहसारी चीनी, चमहे का सामान इत्यादि। प्रथम वर्ग के श्रतर्गत श्राने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है परन्तु दूसरे वर्ग के श्रन्तर्गत छोटे तथा वढ़े पैमाने के उद्यागों में परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके इनकी किसी भी

समस्या को सुगमता पूर्वक सुलक्षाया जा सकता है। तीसरे वर्ग के उद्योगों के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

#### कठिनाइयाँ

कच्चे माल, उत्पादन की प्रविधि, वित्त, विकय, कर इत्यादि के सम्बन्ध में कुटीर श्रीर छोटे पैमाने के उद्योगों को नहीं कठिनाइयों का सामना करना पहता है। इन उद्योगों को प्रायः उन वस्तुश्रों की श्रावश्यकता होती है जिनका बहे उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। क्ष्मी उद्योग पूर्णत्या स्ती मिल द्वारा उत्पादित स्त पर निर्भर करता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्त मिलने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जितने स्त का उत्पादन किया जाता या उसका श्रिषकाँश मिलों की ही श्रावश्यकता पूर्ति में लग जाता था। उस समय श्रिषकतर मिलों में कताई श्रीर द्वनाई साथ-साथ होती थी। केवल कताई करने वाली मिलो को सख्या बहुत कम है। क्ष्मी उद्योग को श्रिषक स्त उपलब्ध कराने के लिए स्त की कताई करने वाली कुछ श्रीर मिलों की स्थापना की गई हैं श्रीर इनमें उत्पादित स्त का कुछ प्रतिशत कर्षा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दलालों के कारण कुटीर उद्योग को श्रावश्यक कच्चे माल का श्रिषक मूल्य चुकाना पहता है। इस कठिनाई को सहकारी समितियों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

प्रविधि और प्रमाली—इन उद्योगों में जिस ढग से श्रीर जिन साधनों से उत्पादन किया जाता है वह प्राचीन हो चुके हैं श्रीर वर्तमान में उनकी उपयोगिता बहुत घट गई है। खोज कार्य करने श्रीर कारीगरों के शिच्या की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उत्पादन के प्रकार में बहुत श्रति हुई हैं। श्रमिकों को उचित शिच्या देने श्रीर उत्पादन के प्रकार में सुधार करने के लिए बहुत योड़ी ऐसी सस्याएँ हैं जो श्रच्छा कार्य कर रही हैं, जैसे श्रखिल मारतीय प्राम उद्योग संघ, श्रिखल मारतीय कताई संघ, खादी प्रतिष्ठान श्रीर हाल ही में स्थापित खादी श्रीर श्राम उद्योग विकास बोर्ड।

श्रन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने, जिसको कोई फाउन्डेशन ने नियुक्त किया था, जिसने छोटी मात्रा में उत्पादन करने नाले तथा कुटीर उद्योगों का श्रष्ययन करने के लिये तथा उनके पुनरुत्थान के सुमाव देने के लिये भारत का टौरा किया, १९५४ में श्रपनी रिपोर्ट दी जिसमें उसने यह सिफारिश की कि चार शिल्प कला ज्ञान सम्बन्धी सस्थायें स्थापित की जानी चाहिये जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिये कि वे सम्पूर्ण भारत की सेवा कर सकें। भारत सरकार ने यह

विकारिश स्वीकार करली है। पर खोज का कार्य करेंगी श्रीर श्रपनी जोज के परिणामों को तथा नई उत्पादन विवियों, नये श्रीजारों, श्रीर नई प्रविधियों की स्वना उत्पादकों तक पहुंचायेंगी।

कार्य करने वालों को प्रोत्साइन देने की श्रावश्यकता है जो कि उचित शिक्षा प्रचार तथा प्रत्येक टस्तकारी के लिये स्थानीय परिषद के स्थापित करने से सम्भव हो सकता है।

वित्त व्यवस्था—छोटे उयोगों ग्रीर उद्योगपितयों की नहीं किटनाइयों में वित्त को किटनाई प्रमुख है। मशीन श्रीर श्रावश्यक श्रीजार कय करने के लिए उसे टीर्थकालीन पूँजों की ग्रावश्यकता होती है। इसके साथ ही कच्चा माल क्रय करने के लिए श्रीर पारिक्षमिक इत्यादि चुकाने के लिए श्राटायालीन पूँजी की श्रावश्यकता होती है। छोटे उत्पादकों में श्रिषकतर निर्धन हैं श्रोर श्र्यण के लिए श्रावश्यक प्रतिभृति नहीं दे पाते। साथ ही ऐसे उपाटका की श्रावश्यकताएँ भी कम होती हैं, इन्हें श्रिषक धन की श्रावश्यकता नहीं होती है इसलिए बटे उयोगों को विचीय सहायता देने वाले व्यवसायी वैक इनको श्रूण इत्यादि देने में कुछ लाम नहीं सममते। बहुत कम ऐसी सस्याएँ हैं जिनसे इन उत्पादकों को विच की सहायता मिल सकती है। इन्हें श्रिषम्तर नामीण साहुकारों ग्रोर कारप्वानादारों पर निर्भर करना पड़ता है। कारखानेटार इस सर्त पर श्रूण देते हैं कि उत्पादित माल उनको वेचा जायगा। उत्पादित माल का मूल्य श्रूण देते समय निश्चत कर लिया जाता है। इससे उत्पादक को श्रपने माल का उचित मृत्य नहीं मिल पाता।

श्रन्तर्राष्ट्रीय योजना टीम ने यह सिफारिश की कि (१) व्यापारिक वैंकी को प्रपनी शाखात्रों को श्रिधिक श्रृण देने की श्रनुमित देकर इन्हें टिये जाने वाले श्रृण की मात्रा वढा देना चाहिये, (२) सहकारी वेंकों को इन उद्योगों की विच सहायता करने की श्रोर श्रीर श्रिधिक ध्यान देना चाहिये, (३) प्रत्येक प्रदेश में एक राज्यीय विच्च निगम स्थापित किया जाना चाहिये जिसके कीय को इन छोटे उद्योगों की ही सहायता के लिये सुरिच्चत कर देना चाहिये, श्रीर (४) वास्तविक सम्पत्ति की प्रतिभृति पर श्रृण देने की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिये।

व्यक्तिगत चेत्र की वित्त सहायता के लिये शीफ कमेटी ने भी रिजर्व वैक को जून १९५४ में टी हुई श्रपनी रिपोर्ट में उन छोटे उद्योगों के विषय में विचार फिया है जिनकी सम्पत्ति १० हजार कार्ये श्रीर ५ लाख क्पये के श्रन्दर है। कमेटी ने कृषि के सहायक उद्योगों को श्रपनी परीत्त्या परिधि के श्रन्टर समितित नहीं

किया। चालू पूँजी के सम्बन्ध में फमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन उद्योगों से सरकार द्वारा क्रय किए गये माल के मूल्य का मुगतान करने में देर नहीं होनी चाहिये। इसके ऋतिरिक्त कमेटी ने यह भी सिकारिश की कि न्यक्तिगत सस्याश्रों द्वारा लिखे हुये इकरारनामों की रजिस्ट्री की कीस भी कम कर देनी चाहिये ताकि उनको वैंकों से ऋगा लेने में श्रधिक सुविधा मिले । दीर्घ कालीन पॅजी की श्रावश्य-कताश्रों के लिये यह सिफारिश की कि पादेशिक सरकारों को इन उद्योगों को 'स्टेट एड टु इग्डस्ट्रीज एक्ट' के अन्तर्गत अधिकाधिक सहायता देनी चाहिये। इसलिये इन उद्योगों को श्रिधिक ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये यह ग्रावश्यक होगा कि प्रादेशिक वजट में इस पर न्यय करने के लिये ग्राधिक धन का श्रनुटान किया जाय श्रीर भूगा देने की प्रणाली को श्रधिक सरल बनाया जाय। कमेटी ने यह सुकाव दिया है कि 'पादेशिक वित्त कारपोरेशन' को छोटे उद्योगों को भारण देना चाहिये। इसके साथ ही उसने यह सिफारिश की कि छोटे उद्योगों की सहायतार्थ एक विशिष्ट विकास निगम की भी स्थापना होनी चाहिये जिसकी प्रारम्भिक शेयर पॅजी ५ करोड़ रुपया हो जो कि भारत के रिजर्व वैंक, व्यवसायिक वैंको, बीमा कम्पनियों, तथा व्यक्तिगत लोगों द्वारा प्राप्त होनी चाहिये।

वाजार-दितीय युद्ध के समय ग्रीर युद्ध के पश्चात् कुछ वर्षी तक बहुत से उद्योगी द्वारा उत्पादित माल के विकय की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि माँग पूर्ति से श्रिधिक थी परन्तु फिर भी दलालां के कारण श्रीर उत्पादित माल घटिया होने के कारण उत्पादक को श्रपने परिश्रम का उचित मुल्य नहीं मिलता था। इघर कुछ वर्षों से इन उत्योगों की विकय समस्या गमीर होती जा रही है। काश्मीर का शाल श्रीर बनारस की सिल्क जैसे मूल्यवान सामानों का उपभोग नहीं हो पा रहा है क्यों कि राजाओं तथा जमींदारों की श्रव पहले जैसी स्थिति नहीं रही। राजाओं की गद्दी ग्रीर जमींदारी का उन्मुलन हो चुका है। जनता की क्रयशक्ति में कभी होने के कारण माँग घट गई है। समस्या यह है कि बाजार मे उत्पादित माल की माँग बढ़ाई जाय श्रीर उचित मूल्य वस्ता जाय। माँग में वृद्धि तभी की जा मकती है जब या तो निर्यात किया जाय या वहे उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के बदले इनका उपभोग किया जाय। कुटीर उद्योगों मे उत्पादित माल का उपभोग कनाडा, श्रमरीका, न्यूजीलेगट, श्रास्ट्रेलिया श्रीर मध्य पूर्वी देशों में बढाया जा सकता है। यह देश पूर्व से ही माल कय करते रहे हैं श्रीर दस्तकारी की वस्तुत्रों, कलापूर्ण कपड़ो, लाख तथा खेल के सामान इत्यादि के विषय में पूछताछ करते रहे हैं परन्तु इन देशों को वड़ी मात्रा में एक साथ श्रीर नमूने के

अनुरूप माल की आवश्यकता है। उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में श्रीर ठीक नमूने के अनुरूप निर्यात करने के लिए विकय समितियों का विकास करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार छोटे पेमाने के श्रौर कुटीर उद्योगों पर कर कम लगाने की नीति श्रपनाती हैं। उदाहरणस्वरूप खरडसारी चीनी पर कारखानों द्वारा उत्पादित चीनी की श्रपेक्षा कम उत्पादन कर देना पबता है। इस समस्या का एक दूसरा पक्ष भी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सुक्ताव दिया गया है कि छोटे पैमाने के श्रौर कुटीर उद्योंगो का विकास करने के लिए बढ़े पैमाने के उद्योगों पर कर लगाया जाय। कर्षा उद्योग का विकास करने के लिए ६ दें करोड रूपया एक करने के लिए स्त्री मिलों में तीन पाई प्रति गज के हिसाब से यह कर लगा भी दिया गया है। बढ़े पेमाने के उत्योगों पर पूर्व ही से बहुत कर लगे हुए हैं यदि यह नया कर श्रौर लगा दिया गया तो इससे उद्योग के विकास में वाधाए उत्यन्न हो जार्येगी। सभी प्रकार के बढ़े, छोटे श्रौर कुटीर उद्योगों के विकास का उद्येश्य इस प्रकार की कर-नीति से पूर्ण नहीं हो सकता है।

छोटे ग्रीर कुटीर उद्योगी के सामने वित्रुत ग्रीर यावायात के ग्रभाव की मी समस्या है। इनकी स्थिति सुघारने के लिए सस्ती वित्रुत ग्रीर सस्ते यातायात की सुविधा देना ग्रावञ्यक है।

कार्वे कसेटी रिपोर्ट—योजना आयोग ने कार्वे कसेटी, श्रयवा आस्य उद्योग श्रोर छोटे उद्योग कसेटी, की नियुक्ति जून १६५५ में इन उद्योगों की समस्याओं का परीच्चण करने और एक ऐसी योजना प्रस्तुत करने के लिए की जिससे (१) द्वितीय योजना काल में उपमोग की वस्तुओं की वढी हुई मांग का अधिकाश इन्हीं उद्योगों से पूर्ण किया जा सके, (२) उनसे उत्तरोत्तर कार्य करने के अधिक श्रवसर प्राप्त हो सकें और (३) उत्पादन और विनिमय की व्यवस्था सहकारिता के श्राधार पर व्यवस्थित हो सके।

कमेटी को यह स्पष्ट हो गया था कि ग्राम्य तथा छोटे उद्योगों की उपेह्या बहुत दिनों से होती ग्रा रही है। प्रथम योजना में जो उनके प्रति ध्यान दिया गया था वह पर्याप्त न था। प्रथम योजना के परिणामस्वरूप इन उद्योगों के विकास के लिये छ॰ विशिष्ट बोडों की स्थापना है। इन बोडों ने १६५१-५२ में १४ ३२ लाख रुपया ज्यय किया था जो कि १६५४-५५ में बढ़कर ६ ७३ करोड़ रुपया हो गया ग्रीर १६५५-५६ में १५-४२ करोड़ रुपया, परन्तु यह भी ग्रपर्याप्त सिद्ध हुन्ना। किमिटी ने २६० करोड़ रुपये के विनियोग की सलाह दी श्रप्यांत् द्वितीय योजना काल में प्रति वर्ष ५२ करोड़ रुपया ज्यय किया जाय।

कार्वे कमेटी ने उन छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले थ्रोर कुटीर उत्योगों के विकास की सिफारिश की थी जो नित्यकार्य में थ्राने वालो वस्तुश्रों का उत्पादन करते ये जैसे सूनी कपदे, ऊनी कपढ़े, हाथ के कुटे चावल, वनस्पति तेल, गुइ श्रोर खरदशारी, चमटे के जुते ग्रोर दियासलाई इत्यादि । साथ ही रेशम के कोडे पालना, रेशम चुनना, इपकर्षा उत्योगों की नारियल की जटा का कातना श्रीर खनना, थ्रादि उत्यागों की श्रोर कमेटी ने प्रपना च्यान दिया। कमेटी द्वारा दितीय याजना के प्रनार्गत प्रस्तावित कुल २६० करोड रुपए के व्यय से श्राशा की जाती है कि श्रविक समय के लिये, योजे समय के लिये श्राशा की जाती है कि श्रविक समय के लिये यह उत्योग ५० लाख व्यक्तियों को कार्य करने का श्रवस प्रदान करने। कपड़े के उत्योगों को कमेटी ने सब से श्रविक महत्ता दी । इनमें विकेन्द्रित सून कातने श्रीर विनने का काम मी सिम्मिलित है। इस उद्योग पर लगमग कुल व्यय का ४४% ध्रयांत् ११३ करोड़ क्या व्यय किया जायगा। श्राशा को जातो है कि यह उद्योग लगमग ३० लाख व्यक्तियों को कार्य प्रदान कर सकेगा।

कमेटी ने तीन मुख्य ध्येय अपने समज्ञ रक्खे थे। (१) द्वितीय योजना काल में यपासम्भव श्रीद्योगिक वेरीज्यारों में हृद्धि न होने देना जो कि प्राय परम्परागत अम्य उद्योगों में हुआ करती है; (२) अधिक से अधिक सख्या में लोगों को योजना काल में आम्य श्रीर छोटे उद्योगों द्वारा कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना, श्रीर (३) विकेन्द्रित समाज की स्पापना के लिये एक श्रापार प्रदान करना तथा वृदि-मान गति से श्राधिक विकास करने की सुविधा देना। कमेटी ने समृद्धिका जो काल्पनिक चित्र श्रपने मन में रक्खा था उसकी प्राप्त कर लेने के विचार से निम्न समाव दिये हैं—

- (१) प्रादेशिक सरकारों को सहकारों समितियों को धन तथा प्रत्याभृति द्वारा सहायता देनी चाहिये जिससे वे भाम्म श्रोर छोटे उद्योगा की श्रीघक सहायता कर सकें। कमेटो ने रिजर्व वैंक श्रोर स्टेट वैंक ग्राफ इण्डिया को भाम्य श्रीर छोटे उद्यागों की सहायता देने के श्रानेक ढगों का सुमाव दिया। उसने यह भी सिका-रिश को कि जा तक इन उद्योगों के लिये एक नई सपूरित सस्थागत श्रृण की न्यवस्था न हो जाय तब तक श्रांसल भारतीय बोडों, प्रादेशिक वित्तीय निगमों तथा राजकीय विभागों को ग्रावश्यक सहायता देते रहना चाहिये।
- (२) प्रादेशिक सरकारा हारा दिने हुये श्रनुदानों का श्राम्य श्रोर छोटे उद्योगों की सहायता करने के स्थान पर कमेटी ने यह श्रधिक श्रन्छा समक्ता कि सरकार द्वारा सहकारिता के श्राधार पर उत्यादित कुछ वस्तुश्रों का निम्नतम

मृल्य निश्चित कर दिया जाय जिस पर वे वेची जाय । मूल्य मे कम पर वेचने में जो घाटा हो उसे राष्य को पूरा करना चाहिये।

- (३) ग्राम्य और छोटे उन्नोगों को विस्तार का श्रवसर प्रदान करने के विचार से कमेटी ने यह विचिन सुकाव दिया कि फेन्ट्री उन्नोगों के श्रधिकतम उत्पादन की मात्रा नियत कर देनी चाहिये श्रीर जितना भी माँग इसके उपगन्त बढ़ें उसे पर्यात. श्रथवा श्रशत ग्राम्य उन्नोगों से पूर्य करना चाहिये।
- (४) समा फेक्ट्री उत्रोगों के सम्बन्ध में कमेटी ने एक उपकर श्रारोपित करने की सिफारिश की निसंका प्रयोग प्राम्य और छोटे उत्रोगों के विकास श्रीर उत्पत्ति के लिये किया जाय ।
- (५) कमेटी ने सुक्ताव दिया कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में एक पृथक मत्री प्राम्य ग्रोर छोटे उन्योगों के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये । इस मत्री को सहयोग देने के लिये मित्रमण्डल के सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिये जिसका काम मारत सरकार की श्रीद्योगिक नीति में सामजस्य स्थापित करना होगा।

समालोचना-कार्वे कमेटी की सिकारिशों में निम्न गमीर टोप हैं।

- (थ्र) कमेटी ने आम्य श्रोर छोटे उद्योगों का श्राप्तिकीकरण तथा श्रमिनवी करण तमी करने की छिकारिश की है जब कि उससे वेकारी न बढें परतु यह श्रसम्भव है।
- (व) मिल उद्योगों के उत्पादन की श्रधिकतम सीमा निर्धारित करने का श्रर्थ यह है कि शाम्य श्रीर छोटे उद्योग उपयोग की वस्तुश्रों की वही हुई माँग को पूर्ण करने में समर्थ होंगे, जो कि जनसख्या के बढ़ने तथा राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि के कारण होगी '। जिन व्यक्तियों को शाम्य श्रीर छोटे उद्योगों का जान है वे यह श्रव्छी प्रकार जानते हैं कि श्रसम्भव है।
- (स) कार्वे कमेटी का अन्तर्हित विचार यह है कि ग्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों की मिल उद्योगों की स्पर्वा से रज्ञा होनी चाहिये श्रीर उनको श्रपने माल को वेचने की त्वतन्त्रता मिलनी चाहिये। परन्तु इस सम्प्रन्य में केवल देश के मिल उद्योग का ही विचार नहीं करना है वरन् विदेशी मिले भी स्पर्धा करेंगी।
- (द) कमेटी की इस सिफारिश के फलस्त्ररूप कि राज्य सहकारिता के सिद्धान्त पर उत्पादित वस्तुत्रों के कय त्रोर विकय मूल्य का श्रन्तर सहन करे श्रीर एक नया मन्त्रालय स्थापित करे, माग्त में राज्यों का व्यय बढ जायगा । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक राज्यों के इतने बडे व्यय तथा त्राय स्रोतों को देखते हुये इस सुमाव को व्यवहारिक नहीं माना जा सकता।

योजना के अन्तर्गत-यह वहे सीभाग्य की वात है कि योजना श्रायोग

श्रीर सरकार ने कार्वे कमेटी की सब सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया विवाद अस्त प्रश्न मिल उन्नोगों के उत्पादन की श्रीधकतम मात्रा नियत करने का था, उस पर श्रमी निर्णय नहीं किया गया है। यह वहे दुर्माग्य की वात है कि उपकर कुछ उद्योगों पर तो लगा ही दिया गया है श्रीर श्रम्य पर लगाये जाने की सम्मावना है। परन्तु श्रमी तक तो कार्वे कमेटी की शिफारिशे उस सीमा तक स्वीकार नहीं की गई हैं कि भारतीय श्राधिक व्यवस्था को श्रसाध्य हानि पहुँच जाय।

प्रथम पचवर्षीय योजना में दस उन्नोगों के लिये एक योजना निर्माण की गई यी—गाम्य तेल उन्नोग, नीम के तेल का साबुन बनाना, घान क्रमा, खजूर का गुड़ बनाना, गुड़ श्रीर खग्डसारी उन्नोग, चमडे का उन्नोग, जन के कम्बल बनाना, हाथ से श्रच्छे प्रकार का कागज बनाना, शहद की मक्सी पालना श्रीर क्रिटीर दियासलाई उन्नोग। यह योजना इस विश्वास पर निर्माण की गई थी कि इन उन्नोगों के विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार १५ करोड़ रुपया श्रीर प्रादेशिक सरकार १२ करोड़ रुपया श्रीर प्रादेशिक सरकार १२ करोड़ रुपया व्यय करेगी। प्रयम योजना काल में जो धनराशि वास्तव में इन उन्नोगों पर व्यय की गई है वह ३१२ करोड रुपये है। इसमें से ह्यक्षां उन्नोग पर ११२ करोड़ रुपये श्रीर छोटे उन्नोगों पर ५२२ करोड़ रुपये व्यय हुये।

टो बढे मह्त्वपूर्ण कार्य प्रथम योजना काल में किये गये। उनमें से एक तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों के विकास के लिए एक नहीं मात्रा में घनराशि का अलग निकाल देना या श्रीर दूसरा विभिन्न उद्योगों के लिये अलिल मारतीय बोडों की स्थापना था। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण, तथा अलिल भारतीय बोडों की कार्य परिधि के विस्तृत हो जाने के कारण, अनेकों उद्योगों का उत्पादन तथा उनमें कार्य करने वालों की सख्या मे वृद्धि हुई है।

तीसरी महत्वपूर्ण बात सरकार द्वारा स्टोर्स परचेज कमेटी की उन सिकारिशों की स्वीकृति हैं जो स्टोर्स की कुछ प्रकार की वस्तुय्रो का केवल ग्राम्य श्रीर उद्योगों से ही खरीटा जाना श्रमिवार्य करते हैं, श्रीर बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की तुलना में उन वस्तुत्रों के मूल्य के य्रन्तर को ग्राम्य उत्योगों को देने के लिये बाध्य करते हैं।

दितीय पंचवर्षीय योजना मे प्रथम योजना की श्रिपेद्धा छोटे उद्योगो पर श्रिषिक घन मुख्यतः इसिलये व्यय किया जायगा कि उससे भारत में वेकारी की समस्या इल होगी। कार्वे कमेटी की २६० करोड इपया व्यय. किये जाने की िषफारिश के विपरीत द्वितीय योजना ने केवल २०० करोट रुपयों के व्यय की व्यवस्था की है। त्राशा यह की जाती है कि जब प्रादेशिक योजनात्रों का पुनर्परीक्य होगा तो यह धनराशि श्रवश्य वह जायगी।

२०० करोड़ रपया के विनियोग में से वेन्द्रीय सरकार २५ करोड़ रपये व्यय करेंगी और प्रादेशिक सरकार १७५ करोड़ रपया व्यय करेंगी। योजना में ग्राम्य श्रोर छोटे उद्योगों के लिये निश्चित किये हुए २०० करोड़ रपयो के श्रातिरिक्त ११ करोड रपया कुटीर ग्रीर मध्यवर्ती उद्योगों के विकास के लिये श्रीर श्रीद्योगिक श्रुण के लिये, श्रीर ७ करोड़ रपया विभिन्न लोगों के पुनवास के कार्यक्रम के श्रुन्तर्गत श्रोद्योगिक तथा व्यवसायिक शिद्या के लिये निश्चित किया गया है। समुदायिक विकास चेत्रों के वजट में ऐसे उद्योगों के लिये प्रत्येक चित्र में १५ लाए रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है। पिछड़ी जातियों की सुध सुविधा के लिये बनाये कार्य-क्रम में भी कुछ चुने हुये उद्योगों से सम्बन्धित व्यवसायिक श्रीर श्रोद्योगिक शिद्या का प्रवन्ध किया गया है।

दितीय पचवर्णीय योजना के पहले दो वर्णों में छोटे पैमाने के उत्योगों तथा कुटीर उद्योगों में कुछ प्रगित हुई है। इन पर पृष्ट करोड़ क्या व्यय हो चुका है श्रीर श्राशा की जाती है कि तीवर वर्ष की समाप्ति तक यह ह१ करोड़ क्या हो जायगा। इस व्यय का ४० प्रतिशत खादी श्रीर त्रामोद्योगों के लिये, २५% से कुछ श्रीषक छोटे पेमाने के उद्योग तथा श्रोद्योगिक वस्तियों (Industrial estates) के लिये तथा २०% के लगभग हाय के कर्षे तथा शक्तिचालित कर्षों के लिये था। पहली दो योजनाश्रों में की गई व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र की अनुमानित व्यय-समता पर श्राधारित थी। १६५८-५६ एक श्रन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण हो गया। केन्द्र श्रीर राज्यों के पास योजनाश्रों को लागू करने के लिये धनराशि सीमित थी।

६२ श्रीचोगिक वस्तियों में से, ११ पहले दो वर्षों में पूरी हो गई तया श्रन्य १६ के १६५८-५६ तक पूरी होने की श्राशा है। १६५७-५८ के श्रन्त तक छोटे उद्योगों का प्राविधिक तथा विकय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये, ४ प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा सस्यान (Small Industries Services Institutes), १३ बढे सस्यान, २ उप सस्यान तथा २७ प्रसार-केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। १६५८ ६६ के एक श्रीर प्रादेशिक लघु उद्योग सस्यान तथा ३३ प्रसार वेन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

१९५६-५७ में इयक्षे का उत्पादन १६००० लाख गज या जो १९५५-५६ के उत्पादन से १३०० लाख गज अधिक था। १९५७-५८ में श्रनुमानित उत्पादन १६५००लाख गज था। श्रव तक की प्रगति लक्ष्य से कहीं कम है। १६५७ के अन्त तक श्रम्बर सूत से उत्पादित कपड़ा ७० लाख गज था। ऐसा प्रतीत होता है कि १५०० लाख गज का सशोधित लक्ष्य योजना काल के अन्त तक पूरा नहीं होगा। पुरानो ढग की खादी का उत्पादन ३५० लाख गज के आवार भूत उत्पादन से ५० लाख गज प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। खादी उत्पादन के लिये कई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया था। शक्तिचालित कर्षां की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त लक्ष्य भी श्रव तक नगएय हैं।

#### ऋध्याय २१

## श्रोद्योगिक उत्पादन श्रोर नियोजन

प्रथम पचवर्षीय योजना मे राजकीय तथा निजी उत्रोग चेत्र में स्त्रीद्योगिक उत्पादन में वृद्धिकरने की व्यवस्था की गई थी। ऋतर केवल इतना था कि राजकीय उद्योग चेत्र में उत्पादन मे वृद्धि करने का सम्पूर्ण उत्तरटायित्व सरकार ने ग्रापने कपर ले लिया था परन्तु निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के लक्ष्य निर्घारित कर दिये गये थे। यह श्राशा प्रकट की गई यी कि निजी उद्योग योजना की श्रविध समाप्त होने तक इन लक्ष्यों तक पहुँच जाँयेगे । पुर्नपरी ज्ञित योजना को कार्यान्यित करने के लिये निर्घारित २३५६ करोड़ रुपयों में से १७६ करोड़ रुपया श्रर्थात् कुल व्यय का ७.६% उद्योगों स्त्रीर खान खोदने पर व्यय करना या जिसमें से बडे स्त्रीर मध्यम श्रेगी के उद्योगों पर १४८ करोड़ रुपया, खानों के सुधार पर १ करोड़ रुपया श्रीर छोटे उद्योगों पर ३० करोड़ रुपया व्यय प्रस्ता या। इक्षन बनाने के चितरजन कारखाने ह्यौर रेल के लिये इस्पात की कोच बनाने के कारखाने में जो कुछ घनराशि लगाई गई वह रेलवे विकास योजन का एक अग थी। इस प्रकार श्राघार भूत उद्योगों श्रीर यातायात के लिये निर्घारित ५० करोड़ की धनराशि पृथक करके सम्पूर्ण राजकीय विकास कार्य क्रम मे ५ वर्ष के अन्दर ६४ करोड़ रुपया निर्घारित किया गया। राजकीय औद्योगिक चेत्र मे जो रुपया लगाया गया उससे लोहे तथा इस्पात के नये कारखाने, इखन बनाने के चितरक्षन कारखाने, मैसर में मशीन श्रीजार बनाने के कारखाने, सिन्द्री के रसायनिक खाद के कारखानों त्रीर पेनिसिलिन, डी॰ डी॰ टी॰, यन्त्र, टेलीफोन इत्यादि बनाने के कारखाने की विभिन्न योजनाम्नों को कार्यान्वित किया गया। जितने उद्योगों की सरकार सरलता से व्यवस्था कर सकती थी उन पर श्रिधकार कर लिया गया श्रौर शेष निजी चेत्र के लिये छोड़ दिये गये। इस मिश्रित श्रर्थं व्यवस्था से यह लाभ है कि राजकीय उत्योग चेत्र का उस सीमा तक प्रसार किया जा सकता है जितना न्यवहारिकता दृष्टि से सम्भव है और निजी उद्योग को श्रपने साधनों, कुशलता एवम् श्रनुभव के द्वारा देश का श्रीयोगिक विकास करने का अवसर मिलवा है।

योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया था कि योजना में उत्पादन के निर्घा-रित लध्य तक पहुँचने के लिये निजी उद्योग च्रेत्र में पाँच वर्ष के श्रन्दर कुल २३३ करोड़ रुपया लगाना पढेगा। यदि इसमें मशीनों को परिवर्तन तथा उद्योग का श्राधुनिकीकरण करने के लिये १५० करोइ श्रोर चालू पूँजी के लिये ३२४ करोड़ की धनराशि समिनित कर दी जाय तो पाँच वर्ष में निजी उद्योग चेत्र में कुल ७०७ करोड़ रुपया लगाया जायगा। मारतीय उद्योगपितयों ने इस योजना की श्रालोचना की । उनका कहना या कि (श्र) उद्योग के श्रायुनिकीकरण के लिये १५० करोड़ रुपया श्रपर्यात है क्योंकि श्रधिकाश उद्योगों की मशीनें प्राय व्यर्थ हो गई हैं। योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये श्रावश्यक मशीनों का प्रवन्ध करने में इससे कहीं श्रधिक रुपयों की श्रावश्यकता होगी, (ब) सम्कार ने केवल श्रावश्यक धन की मान्ना बता दी है, परन्तु उसकी प्राप्ति की व्यवस्था नहीं की है। उद्योगों के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिनसे यह कार्य किये जा सकें, भारतीय पूँजी बाजार की ऐसी स्थित नहीं है कि इतना धन प्राप्त किया जा सके श्रीर विदेशी पूँजी मो प्राय. उपलब्ध नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से जात होता है कि निजी उद्योगों का योजना में निर्धारित उत्यादन के लक्ष्यों को पूरा कर सकना सम्भव नहीं है।

योजना में उत्योगों को जिस कम से प्रायमिकता दी गई थी उससे स्पष्ट है कि प्राधारमृत एवम् प्रमुख उद्योगों के साथ ही ऐसे उद्योगों को श्रिषक महत्व दिया गया जिनका श्रिपेज्ञाकृत नहुत कम विकास हुश्रा था। यदि राजकीय तथा निजी उत्योग चेत्रों को एक साथ मिला कर देखा जाय तो यह ज्ञात होगा कि कुल ज्यय का रह प्रतिशत धातु शोधन उद्योगों के लिये, २० प्रतिशत पेट्रोल शोध-शालाश्रों के लिये, १६ प्रतिशत इजीनियरिंग उत्योगों के लिये, प्रतिशत स्ती उद्योगों के लिये, ५ प्रतिशत सीमेंट श्रीर लगभग ४ प्रतिशत कागज, पट्ठे तथा श्राखनारों कागज उद्योग के लिये निर्धारित किया गया था। इसका श्राय यह या कि जिन उत्योगों का स्त्रमी विकास नहीं हो पाया था उन पर श्राधक व्यय किया जाय। वर्तमान उद्योगों को छोड़ा नहीं गया था बल्कि उनके लिये कम बनराशि निर्धारित की गई थी। ऐसा उचित मी था। देश के सभी उपलब्ध सावनों का श्रच्छे से श्रच्छा उपयोग करने के उद्देश्य से ही यह व्यवधा की गई थी। श्रीद्योगिक विकास कार्यक्रम के लिये योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम दिया गया है।

- (१) जूट श्रीर प्लाइइड जैसे उत्पादक वस्तु उद्योग श्रीर स्ती कपडे, चीनी, चाबुन, बनस्पति, रग श्रीर वानिश जैसे उपभोग की वस्तुश्रों के उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाय।
  - (२) लोहे तथा इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रसानिक खाद, भारो

रसायनिक, मशीनों के श्रीजार इत्यादि उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति की बहाया जाय।

- (३) जिस उद्योग को श्रारम करने के लिए कुछ पूँजी लगा दी गई है उसे पूरा किया जाय।
- (४) देश के श्रौद्योगिक ढाँचे को श्रधिक शक्तिशाली बनाने के लिए श्रपने साधनों को ध्यान में रखते हुए नये कारखाने स्थापित किये जायँ जैसे जिप्सम से गन्थक का उत्पादन किया जाय।

प्रथम योजना में उद्योगों के तीन वर्ग किये गयेथे। (१) जूट श्रोटोमाँबाइलस्, मशीन व ग्रीजार कपडे की मशीन तथा चुड़ी के उद्योगों के सम्बन्ध में जिनकी उत्पादन शक्ति प्रयोप्त थी, इस बात पर महत्व दिया गया कि वे श्रपना उत्पादन वढाकर श्रपनी श्रनुमानित शक्ति के स्तर पर ले श्रावें जो बटली नहीं जायगी, ढलें हुये लोहे, इस्पात, चीनी, सीमेंट, कागज श्रीर कागज के पट्टे, दियासलाई तया कुछ रसायनिक वस्तुत्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग जिनके सम्बन्ध मे यह निर्णय किया गया या कि उनकी अनुमानित शक्ति बढाई तो जायगी पर १०० प्रतिशत से कम । इनके अन्तर्गत सीमेंट, सलफ्युरिक ऐसिंड, दला हुआ लोहा, तैयार इस्पात, कागज श्रौर कागज के पटटे, दियासलाई, स्टोरेज वैटरी ग्रौर विजली के पखे बनाने वाले उद्योग भी सम्मिलित कर लिये गये थे. (३) बिजली से चलने वाले पम्पों, डिज़िल इननों, सीने की मशीन, बाइसिकिलों इत्यादि उद्योगों का जिनकी वास्तविक उत्पादन शक्ति माँग के अनुपात में कम है काफी पसार करने की योजना बनाई गई थी। इसी श्रेणी में अन्य उद्योग भी आते हैं जैसे काटन लिन्टर्स, केमिकल पल्प, कुछ दवाइयाँ इत्यादि जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता या परन्तु श्रव इनके उत्पादन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार पचवर्षीय योजना में देश के श्रौद्योगिक विकास की कमी को पूरा करने का प्रयन्न किया गया था।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक श्रोर खनिज पदार्यों के विकास को प्रथम योजना की श्रपेद्या श्रिषक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वास्तव में द्वितीय योजना श्रौद्योगिक विकास पर केन्द्रित है। द्वितीय योजना में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से ८६० करोड़ या १८५% उद्योगों पर व्यय किया जायगा जब कि प्रथम योजना के कुल २,३५६ करोड़ रुपयों के व्यय में से उद्योग पर १७६ करोड़ रुपये या ७६% व्यय किया जाना था। द्वितीय योजना प्रथम की श्रपेद्या श्रिषक विस्तृत है श्रीर इसमें व्यय मी बहुत श्रिषक किया जा रहा है। उद्योगों को श्रिषक महत्व देने का कारण देश

के श्राधिक विकास की श्रधिक सतुलित करना, राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि श्रीर वेकारी ब्राटि को कम करना है। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत कार्यक्रम मे प्रायमिकता निम्न प्रकार दी गई है।

- (१) लोहे और इस्पात तथा भारी रखायनिक उद्योगों का निर्माण करना जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद श्रीर इन्जीनियरिंग तथा मशानो के निर्माण सम्बन्धी उद्योग सम्मिलन है।
- (२) विकास सम्बन्धी वस्तुओं तथा उत्पादन में कार्य श्राने वाली वस्तुओं, जैसे श्रलमोनियम, सीमेंट, रसायनिक पल्प, रग, फास्फेट युक्त खाट श्रीर श्रत्यन्त श्रावश्यक दवाईयाँ श्रादि की उत्पादन शक्ति में विस्तार करना।
- (३) महत्वशाली राष्ट्रीय उद्योग, जो स्थापित हो चुके हैं, जैमे जुट ग्रौर स्ती कपढे बनाने तथा चीनी उद्योग ग्रादि, उनके प्रसाधनों की वृद्धि ग्रौर उनका ग्राभिनवीकरण।
- (४) उन उद्योगो की उत्पादन शक्ति में जिनकी उत्पादन शक्ति श्रीर वास्त-विक उत्पादन में श्रन्तर है वृद्धि करना।
- (५) साधारण उत्पादन के कार्यक्रमों तथा उद्योगों के विकेन्द्रित ग्रश के उत्पादन लक्ष्य के श्रनुसार उपभोग की वस्तुश्रों के उत्पादन में वृद्धि करना।

श्रौद्योगिक विकास के कार्य क्रम के दृष्टिकोण से द्वितीय योजना की अनेकों विशेषतायें हैं :—

(१) इसमें राजकीय चेत्र को व्यक्तिगत चेत्र से श्रिधिक महत्ता दी गई है। दितीय योजना की नवीनता इस बात में है कि राजकीय चेत्र में श्रौद्योगिक श्रौर खिन उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को प्रधानता दी गई है। भारत में कृषि, विद्युत शक्ति, यातायात, तथा सामाजिक सेवाश्रों के विकास के सम्बन्ध में राजकीय चेत्र के श्रन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगों श्रौर खिनज सम्बन्धी योजनाश्रों को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुत्रा था। प्रथम योजना में राजकीय चेत्र के श्रन्तर्गत किये गये विनियोग में उद्योगों श्रौर खिनज सम्बन्धी योजनाश्रों को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त हुत्रा था। प्रथम योजना में राजकीय चेत्र में बढे उद्योगों की स्थापना के लिये केवल ६४ करोड़ रुपयों के विनियोग का प्रबन्ध किया गया था, जबिक व्यक्तिगत चेत्र में २३३ करोड़ रुपयों के विनियोग का श्रनुमान किया गया था। दितीय योजना के श्रन्तर्गत राजकीय चेत्र में बढे उद्योगों श्रीर खिनज के विकास के लिये (वैज्ञानिक श्रन्वेषण्य कार्य पर व्यय सिम्मिलत करते हुये) ६६० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जब कि व्यक्तिगत

त्तेत्र में उद्योगो श्रोर खानों पर न्यय किये जाने के लिये केवल ५७५ करोड रुपयों का ही प्रवन्ध है। न्यक्तिगत त्तेत्र को यद्यपि देश के श्रौद्योगिक विकास में एक बहुत वहा भाग लेना है फिर भी यह प्रत्यक्त है कि राजकीय त्तेत्र की योजनाश्रों पर न्यक्तिगत त्तेत्र की योजनाश्रों पर न्यक्तिगत त्तेत्र की योजनाश्रों से श्रोपेक्षाकृत श्रिषक महत्व दिया गया है।

(२) योजना की दूसरी विशेषता यह है कि मुख्य श्रीर श्राधार उद्योगों का विकास उपमोग की वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की श्रपेद्धा श्रिषक किया जायगा। प्रतिष्ठापित उत्पादन शक्ति के श्रायोजित विकास तथा प्रस्तावित उत्पादन सम्बन्धी १६६०-६१ के श्रांकडे यह प्रकट करते हैं कि लोहे श्रीर इस्मत, इन्जीनियरिंग तथा रसार्यानक उद्योगों के श्रिविकतम प्रधार का श्रायोजन किया गया है। भारत में प्रथम वार मशीन निर्माण उद्योग के विकास का श्रायोजन किया गया है। सत तथा जूट विनने की मशीनों के तथा सीमेंट श्रीर चीनी बनाने की मशीनों के श्रीर छोटे छोटे श्रीजारों के उत्पादन के उद्योग तो भारत में पिहले से ही स्थित हैं, पर उनका बहुत श्रिषक विस्तार कर दिया जायगा। कागज तथा छपाई उद्योग के उत्पादन का मूल्य १६६०-६१ तक क्रमशः ४ करोड़ रुपये तथा २ करोड़ रुपये तक हो जायगा। वर्तमान समय मे तो इन वस्तुश्रों का उत्पादन नगरय ही है।

वहें उद्योगों श्रोर खनिज उद्योग पर जो ६६० करोड रुपया व्यय किया जाने वाला है वह लगभग पूर्ण रूप से मूल उद्योगों के विकास के लिये हैं, जैसे लोहा इस्तात, कोयला, खाद, इन्जीनियरिंग तथा बड़े वहें विजली के प्रसाधन इत्यादि। योजना में तीन इस्पात स्थनों को स्यापना रूरकेला, मिलाई, श्रोर दुर्गपुर में होगी जिनम से प्रत्येक की उत्पादन शक्ति १० लाख टन इस्पात प्यर्डों की होगी। इसके श्रातिरिक्त इनमें से एक स्थन्त्र ती ३५०,००० टन ढला हुआ लोहा विकी के लिये उत्पादित करेगा। राजकीय चेत्र के श्रन्तर्गत सब योजनाश्रों से श्राशा की जाती है कि कुल इस्पात की उत्पादित मात्रा लगभग २० लाख टन दितीय योजना के श्रन्त तक हो जायगी।

इन्जीनियरिंग के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम में चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री में एक बड़ी इस्तात फाउन्ड्रों की स्थापना भी सम्मिलित हैं। इस बात का प्रवन्ध किया जा रहा है कि बड़े बड़े बिजली के प्रसाधनों का निर्माण राजकीय चेत्र में हा। इसलिये चित्तरन्जन लोकोमोटिव फैक्ट्री का विस्तार होना परमावश्यक है ताकि वर्तमान समय के १२५ इन्जिनों के वार्षिक उत्पाटन के स्थान पर ३०० इन्जनों का प्रतिवर्ष उत्पादन हो जाय। दि इन्टीगरल कोच फैक्ट्री जिसने उत्पादन कार्य १६५५ में आरम्म किया लगमग ३५० कोच प्रतिवर्ष १६५६ तक उत्पादित कर सकेगी। एक नई मीटर गेज कोच फैक्ट्रो की स्थापना का भी प्रबन्ध कर दिया गया है।

(३) द्वितीय-योजना में प्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को प्रथम योजना की श्रपेचा श्रिषक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है श्रीर यह प्रत्नाव किया गया है कि उन पर प्रथम योजना के ३० करोड़ रुपये के व्यय के स्थान पर श्रव २०० करोड़ रुपया व्यय किया जाय । श्राम्य श्रीर छोटे उद्योगों को इतना महत्व देने का मुख्य कारण यह है कि देश की श्रार्थिक व्यवस्था के विकेन्द्रित भाग में कार्य करने के श्रिषक श्रवसर प्रदान कर सर्केंगे।

समालोचना—दितीय योजना प्रथम योजना की श्रपेता अधिक विचार पूर्ण है। इस योजना में यह उचित ही है कि कृषि की तुलना में श्रीद्योगिक विकास पर अधिक महत्व दिया गया है। इससे देश का सतुलित विकास सम्भव हो सकेगा और जो देश की आर्थिक व्यवस्था में अभाव रह गए थे वे पूर्ण हो जायेंगे। यह भी बहुत उपयुक्त है कि बड़े मूल और मशीनों के निर्माण के उद्योगों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। इन्हां के आधार पर भारत का भावी श्रीद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा। यह सब होते हुए भी द्वितीय योजना में श्रनेकों गम्भीर दोष रह गये हैं।

- (१) राजकीय चेत्र का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है। यदि स्मार के पास धन के स्नात, अद्योगिक ज्ञान, उत्योगों के आरम्म करने की च्रमता आदि होतो तव तो इसमें कोई हानि की सम्मावना न होती, परन्तु सरकार के पास तो ये पर्याप्त मन्ना में नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेकों उद्योग जो राजकीय चेत्र के अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैं उनमें राजकीय चेत्र से जितना साहस प्राप्त हो सकता है उसकी अपेचा अधिक जोखिम उठाने और साहस की आवश्यकता है। अन्त में यह भी कहा जाता है कि राजकीय चेत्र को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर देने से ज्यक्तिगत चेत्र के लिये सुगमता पूर्वक कार्य करते रहने के लिये जितने साहस की आवश्यकता है उससे बहुत कम का अवसर छोड़ा गया है। इसमें सम्बद्ध रूप से यह भय लिच्चित होता है कि राजकीय चेत्र अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण न कर सकेगा।
- (२) यद्यपि व्यक्तिगत च्लेत्र पर कुछ वस्तुश्रों की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन करने का उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, परन्तु इसके लिये न ती पर्याप्त मात्रा में जित्त की उपनिका का कोई प्रवन्य किया गया है छीर न ऐसी सुविधाये ही प्रदान की गई है जैमे अवच्चयण के लिये वृद्धि अपना करों से छूट आदि, जो कि व्यक्तिगत चेत्र के सरनता से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक

हैं। राष्ट्रीय श्रीनोगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) जिसकी १९५४ में स्थापना की गई थी व्यक्तिगत जैन में उद्योगों के विकास में सहुत सहायता पूर्ण कार्य कर रहा है। दितीय योजना में भी यह सस्या व्यक्तिगत सेन में सहायता का गार्न परती रहेगी। यह सन होते हुये भी यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत सेन को निस्त सकट उठाना पढ़ रहा है, जिससे श्रीदोगिक विकास में नाधा पढ़ रही हैं।

(३) भारत के श्रोयोगिक चगटन में महत्यपूर्ण स्थान रराने के कारण यह सर्वया उपयुक्त है कि मान्य श्रीर छोटे उपोगों के विकास का प्रयत्न किया जाय, परन्तु यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि करें उपोगों पर उपकर श्रारोपित किया जाय श्रयवा उनके उत्पादन की मान्ना पर प्रतिगन्ध लगा दिया जाय, निसत्ते कि मान्य श्रीर छोटे उद्योगों की रक्ता हो मके। एवं कार्याण्म्म का माहस नष्ट हो जाता है श्रीर कोई प्रभावशाली सहायता भी ग्राम्य श्रयवा छोटे उपागों को नहीं मिलती। इन उपोगों की समस्या को उनके हारा उत्पादित पर्तुश्र के गुणों की उनके हारा उत्पादित पर्तुश्र के गुणों की उनकि करके, तथा उनके मूल्य को घटा कर करना चाहिये न कि वर्ष उपोगों पर प्रतिन्य हारा।

हितीय योजना के योजोगिक विकास काउमम में उपर्युक्त दोवा के होते हुये भी यह याचा भी जाती है कि इससे योजोगिक विकास की गति में प्रवस्य बुटि होगी, तथा श्रोचोगिक विवास सगटन के प्रभावां को पूर्ण करके यह योजना संगुलन स्थापित करेगी योर ससार में भारत का पाजोगिक स्तर सँचा उठायेगी।

योजना की प्रगति—"१९५७ प्रत तक पहली योजना में प्रारम्भ की गई अनेक जोशोगिक योजनाएँ पूर्ण हो गई। इन योजनाओं में श्रलवये का डी॰ डी॰ टी॰ का कारखाना, दिल्ली के डी॰ टी॰ टी॰ कारखाने का विस्तार, हिन्दु-रतान एन्टीवायोटिय (कारखाने) का विस्तार, मेसूर में सरकारी पोर्स्तीन फैन्द्री की पोर्सतीन इन्सुलेटर्स स्कीम, मेसूर श्राहरन एएड स्टील वर्कस का spun-pipe का कारखाना, विद्यार की सुगर फासफेट फैन्द्री तथा NEPA कारखाने में समुलन उपस्कर की व्यवस्था श्रादि सम्मिलत थे। इन योजनाशों के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप डी॰ डी॰ टी॰ निर्माण करने की शक्ति में २१०० टन की, दिन्छि॰ लीन के सम्बन्ध में १६२ लाख मीगा इकाइयों की तथा सुपर फास्फेट की उत्पादन शक्ति में ३३,००० टन की वृद्धि हो गई। NEPA ने प्रतिवर्ष ३०,००० टन श्रखारी कागज का उत्पादन करने की श्रपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया। २५०० टन इन्सुलेटर्स के निर्माण की शक्ति श्रथवा सामर्थ्य की भी स्थापना हुई। द्वितीय योजना में इन स्कीमों पर ३ करोड ६० व्यय करने की व्यवस्था थी।"

आशा की जाती है कि १६५८-५६ में निम्न औद्योगिक स्कीम पूरी हो जॉयगी।

जाँयगी।			
योजना	नयी श्रयवा श्रतिरिक्त शक्ति या सामर्थ्य		
1. सिन्द्री (खाद) कारखाने का विस्तार	४७,००० टन नाइट्रोजन		
2. मिलई ऋौर रुरकेला में पहली	७००,००० टन प्रतिवर्ष दला सोहा		
महियाँ (Blast furnaces)	(pig iron)		
3. दुर्गापुर, की योजना (Coke-	२८५,००० टन कोक		
oven project)	(hard coke)		
4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्म, ( milling			
machines or lathes) के उत्पादन में वृद्धि।	drilling machines)		
5. Hindustan cables Co axial	५३० मील केबिल श्रीर ३०० मील		
cables project	co axial cables.		
	गमग २१ करोड ६० है तथा १२ करोड़		
रु का विदेशी विनियम श्रपेश्वित है।	the Court of the court of the court		
	। योजना काल मे पूरी हो जॉयगी।		
योजना	नई ग्रयवा ग्रातिरिक्त सामर्थ्य		
१ मिलाई, रुरकेला, श्रीर दुर्गपुर	२२ लाख टन स्टील, तथा ६००,०००		
स्टील वर्केस	टन ढला हुआ लोहा (pig Iron)		
२ नागल खाद योजना	७०,००० टन नाइड्रोजन ( fixed )		
३. लिग्नाइट योजना उत्खनन सम्बन्धी	३५ लाख दन लिगनाइट		
४. इिन्दुस्तान एन्टीवायोटोनिस की	४५००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन		
स्ट्रेप्टोमाइसीन योजना	4		
५. मैसर श्राइरन श्रीर स्टील वर्क्स का	१५००० टन फैरो-सिलीकन		
फेरो-छिलकिन का विस्तार	2		
६ विद्वार की पोर्शकति इन्सुलेटर्स की	२००० टन इन्सुलेटर्स		
योजना	८-१२ जहाज प्रतिवर्ध बनाने की इसता		
७. हिन्दुस्तान शिपयार्ड	के लिये विस्तार,		
द, यू• पी० सरकार की सीमेन्ट फैक्ट्री	२३१०० रन सीमेन्ट,		
का विस्तार			

## अध्याय २२ सरकार की श्रोद्योगिक नीति

### भारत सरकार की लोगोगिक नीति का श्राघार १६५३ के श्रोगोगिक (विकास श्रोर नियमन) स्वाधन कानून द्वारा स्वाधित १६५१ का श्रोधोगिक (विकास श्रोर नियमन) कानून है। सरकार की नीति 'मिश्रित श्राधिक व्यवस्था' पर श्राधारित है जिसमे राजकीय उद्योग तथा निजी उद्योग टोनों का स्थान है। इस कानून मे भारत सरकार ने जिस श्रोग्रागिक नीति का निरूपण किया है वह भारत सरकार के उस क्कव्य से बिल्कुल भिन्न है जो उसने समद द्वारा स्वीकृत

प्रस्ताव के रूप में ६ अप्रैल १६४८ को दिया था।

श्रोत्रोगिक नीति का उद्देश्य देश के श्रोत्रोगिक साधनों का यथा सम्भव गित ने चन्तुलित विकास करना होना चाहिये। यदि यह कार्य पूर्णतया निनी उन्होगों को ही समर्पित कर दिया जाय तो यह उद्देश्य पूर्णत: प्राप्त नहीं किया जा चकता न्योंकि पॅजी का ग्रमाव. उन्रोग के लिये ग्रावश्यक सामान श्रीर मशीनों का श्रमाव, श्रीयोगिक कुरालता का श्रमाव श्रीर उद्योगपति की शीघ लाम उठाने की श्रमिलापा इस दिशा में बाघक बन जाते हैं। इस कारण श्रव तक उपमीग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उन्नोगों पर मशीनों इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्यागों की ग्रपेक्षा अविक महत्व दिया जाता रहा है इसीलिए निबी उद्योगों पर नियत्रण रखा जाना और साथ ही राज्य के त्तेत्र में उद्योग पर सचालन तथा प्रजन्म त्रावश्यक प्रतीत होता है। बहुत समय से इस नीति का समर्थन किया जाता रहा है कि राज्य को निजी उद्योगों पर नियनण रखना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि निजी उद्योगों को सहायता दी नाय, उनको विकास के लिये प्रोत्साहित किया नाय, राजकीय उद्योग का चैत्र निश्चित किया जाय, निजी उन्योग को अनुचित कठिनाइयों और उलक्तनों में न पढने दिया जाय श्रीर एक श्रीदोगिक सत्या को दूसरी श्रीदोगिक संस्था का शोषण न करने दिया जाय। परन्तु भारत सरकार की भ्रीयोगिक नीति इसके विपरीत है। इससे मारत के उपयुक्त श्रौदोगिक विकास की सम्मावना नहीं है। इस नाति को नद्रारात्मक नीति कहा जा सम्ता है। इसमे निजी उद्योगों के सम्बन्ध में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिनको करने के लिये राज्य श्रनु-मित नहीं देगा। इसमें यह निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि राज्य निजी उद्योगों को सहायता देने के लिए क्या करेगा। यह नीति यथार्थवादी नहीं है क्यों कि

इसमें भारत में निजी उद्योग की वर्त्तमान स्थिति और उसके सगठन तथा आकार-प्रकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत निजी-उद्योग चेत्र में कुछ ऐसी वाते लागू की गई हैं जिनकी उपयोगिता पर सन्देह प्रगट किया जा सकता है, जो देश के औद्योगिक विकास में सहायक होने की अपेन्ना वाधक हो सकते हैं।

६ अप्रैल १६४८ का श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव— १६४८ में घोषित ऋौद्योगिक नीति में 'मिश्रित' ग्रार्थं व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। परन्तु राष्ट्रीयकरण का विषय इसमे विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। वास्तव में 'मिश्रित ग्रर्थ व्यवस्था' के सिद्धान्त में ही 'राष्ट्रीयकरण' का विचार निह्त है। परन्तु सरकार ने अपनी घोषणा में इसकी चर्चा करके इसे त्रिषिक स्पष्ट कर दिया। इस घोषणा में उद्योगो को तीन श्रेणियों में विमाजित किया गया था। (१) प्रथम श्रेगी के उन्त्रोगों में इथियारों ऋौर गोला-बारूद का उत्पादन, श्रग्ण-शक्ति का उत्पादन श्रीर नियत्रण श्रीर रेलवे परिवहन का प्रवन्ध तथा स्वामित्व सम्मिलित किये गये थे। इन उद्योगों पर राज्य को पूर्ण एकाधिकार दिया गया । इस न्यवस्था से विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि ये उद्योग पहले से ही राज्य के अधिकार में अरीर इस बात की बहुत कम सम्मावना है कि भारत में निजी उद्योग इनमें से किसी एक को भी ग्रपनाने के लिये तैयार होगा। वास्तव मे द्वितीय श्रौर तृतीय श्रेणी के उद्योगों पर ही इस श्रौद्योगिक नीति का महत्व निर्भर करता है। (२) द्वितीय श्रेग्री के उद्योगों में कीयला, लोहा, इस्पात, विमान-निर्माण जलयान-निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार के तार के यत्रों का निर्माण और पेट्रोल इत्यादि खनिज तेल सम्मिलित किये गये हैं। इन उन्योगों के सम्बन्ध में यह कहा गया या कि इस श्रेगी के नवीन कारखानों को स्थापित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल राज्य पर होगा और जो वर्तमान समय में चालू कारखाने हैं उनकी दस वर्ष में पुन जॉच की जायगी श्रीर यदि श्रावश्यक हुश्रा तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा । इस व्यवस्था का निजी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे उनका भविष्य ऋनिश्चित हो गया। उद्योग में सुवार करने के लिये जो कुछ रुपया लगाया जायगा उसका लाम उठा सकने के लिये १० वर्ष का समय बहुत कम है। श्रीर चूँकि नये कारखाने स्यापित करने ना पूर्ण भार राज्य ने स्वीकार कर लिया, इससे इस श्रेणी के उद्योगों में निजी उद्योग के मालिको की रुचि कम हो गई इस चेत्र मे उनका सम्पूर्ण उत्साह समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप श्रीद्योगिक उत्पादन घट गया, पूँजी निर्माण की प्रक्रिया बीमी पड़ गई स्त्रीर स्त्रीद्योगिक चेत्र में कुछ सीमा तक मन्दी स्त्रा गई। यदि

राज्य नवीन कारगाने स्थापत कर उत्पादन कार्य ग्रारम्भ कर देता तो इससे विशेष हानि की समावना नहीं थी। परन्तु मारत सरकार ग्रीर राज्य सरकारों के पास इस कार्य के लिये ग्रावश्यक बन, साहस लोर कुशल कर्मचारियों का ग्रमाव है। फल स्वरूप देश भी ग्रोधोगिक स्थिति प्रगति करने की श्रपत्ता ग्रवनत होती गई। (३) शेष उत्योगों को तीमरी श्रेणी में रगा गया। यत्यपि इस श्रेणी के उद्योगों को निजी उत्योग दोन के लिये छोड़ दिया गया परन्तु यह भी कहा गया कि राज्य इस चेन में भी गमश भाग लेगा। परन्तु सापनो के श्रभाव के कारण राज्य इस चेन में सिहन नहीं हो सका।

नवीन औद्योगिक नीति—३० श्रप्रैल १६५६ को घोषित नवीन श्रोवोगिक नीति १६५८ के श्रोवोगिक नीति सम्मन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा से मिलती जुलती है, श्रोर उद्योगों को राज्य द्वारा उनमें भाग लेने के श्रावार पर ३ वर्गों में विभाजित करती है। प्रथम वर्ग में १७ उद्योगों की गणना की गई है जिनमें कोयला, लोहा श्रोर इस्पात, गनिज-तेल, सामान्य श्रोर विद्युत इन्जीनियरिंग के उस्त्र श्रीर परिवहन सम्प्रन्धी कुछ ऐसे उद्योग श्राते हैं जिनके भावी विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के कार है। द्वितीय वर्ग में लगभग एक दर्जन उद्योग सम्मिलत किये गये हैं, जेसे मशीन के यन्त्र, श्रलमुनियम, खाद, सहक श्रीर समुद्री परिवहन इत्यादि जिनमें व्यक्तिगत श्रोर राजकीय उपक्रम साथ साथ चलेंगे परन्तु यह कमश राजकीय श्राधिकार में श्रा जायेंगे, इस लिये इन में नवीन उपक्रमों के स्थापित करने में राज्य श्रयगणी होगा। शेप उद्योग जैसे स्ती कपड़े, सीमेंट, चीनी इत्यादि तीसरे वर्ग में रक्ये गये हैं। इनका भावी विकास सामान्यत व्यक्तिगत स्त्रेत से उपलब्ध कार्यारम्भ साहस पर निर्मर करेगा। राज्य की यह भी श्राधकार होगा कि इस वर्ग के उद्योगों को भी श्रारम्भ कर सके।

उत्योगों के इस विवर्गीय विभाजन में कोई दोष नहीं है। १६४८ के श्रीद्योगिक नीति प्रस्ताव के श्रनुसार सतोष प्रद दग से कार्य हुया है। परन्तु नवीन श्रीद्योगिक नीति के विवर्गीय विभाजन में कुछ दोष श्रा गये हैं।

(१) राजकीय चेत्र के विस्तार में बहुत छाधिक वृद्धि कर दी गई है ज्योर व्यक्तिगत चेत्र को अत्यधिक सकुचित कर दिया गया है। इससे हानि यह होगी कि छौद्योगिक जान वाले कर्मचारिया, सगठन करने की चमता, पूँजी तथा अनुमव के अमाव में राज्य उन उत्योगों का प्रवन्ध न पूर्णत और न अधिकाँश ही कर सकेगा जिन्हें उसने अपने लिये सुरिच्त कर रक्ष्ला है। व्यक्तिगत उपक्रम इस कठिनाई को सुवार सकने में असमर्थ होगा क्योंकि नवीन नीति के अनुसार उन्हें यह कर सकने का कोई अधिकार ही न होगा और यदि सरकार उन्हें आमन्त्रित

भी करेगी तों उनमें इतना श्रात्म विश्वास न होगा कि वे ऐसा कर सके। इस नीति के निर्माता इस कठिनाई से अनिमन नहीं थे। जो न्यक्ति न्यक्तिगत उप-क्रमों की कार्य प्रणाली और १६४८ के श्रोद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रमाय से परिचित हैं वे समक सकते हैं कि इस प्रयोगात्मक परिस्थिति में व्यक्तिगत उपक्रम सम्मुख त्राने का साइस न कर सकेंगें। प्रथम दोनों वर्गों में सम्मिलित व्यक्तिगत उद्योगों को सरलता से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक वातावरण का आभाव है। यदि गत पाँच वर्षों के अनुभव का भरोसा करे तो यह आशा करना कि यदि राजकीय उपक्रम वाञ्छित लक्ष्य को पूरा न कर सके तो उनका स्थान व्यक्तिगत उपक्रम ले लेंगे, युक्ति सगत नहीं है। यदि प्रथम वगो में गिने गये कुछ उद्योगो को तीसरे वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता, जिसमें कार्यारम्म का मार व्यक्तिगत उपक्रमों पर है, तो निश्चित रूप से यह सम्मव होता कि वे किसी न किसी प्रकार श्रीद्योगिक ज्ञान, पूँजी तथा श्रमुभव के श्रमाव को पूर्यो कर सकते जैसा कि गत २०० वर्षों से देखने में त्राया है। यह कोई तर्क नहीं है कि त्रोद्योगिक इमता, पूजी, अनुमव आदि का सर्वथा अमाव है, ज्योर इस लिये राजकीय उपक्रम अधवा व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा इस समस्या को सुलमाने में कोई श्रन्तर नहीं पडता बहुत बझा श्रन्तर तो यह है कि व्यक्तिगत उपक्रमो के पास उत्साह श्रीद्योगिक चमता श्रीर कार्य करने की शक्ति है श्रीर राजकीय उपक्रमों के पास इनका श्रमाव है। नवीन श्रीद्योगिक नीति के कारण विकास की गति वहने के स्थान पर अवरुद्ध

- (२) १९४८ की ख्रोद्योगिक नीति में वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये वर्ष की ख्रविध निश्चित की गई थी, ख्रोर तीसरे वर्ग के उद्योगों के लिये यह एक से कह दिया गया था राज्य उन्हीं उद्योगों को इस्तगत करेगा जिनकी प्रगति सतीषपद नहीं रही है। इसके व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ ख्राद्या करी। प्रगति सतीषपद नहीं रही है। इसके व्यक्तिगत उपक्रमों को कुछ ख्राद्या करी। परन्तु ख्रव राज्य को ख्रात्यिक ख्रिषकार देकर व्यर्थ में व्यक्तिगत उपक्रमों की परन्तु ख्रव राज्य को ख्रात्या कर लिया गया है। यह राज्य के विचार ख्रयवा सुरज्ञा की मावना का ख्रवहरण कर लिया गया है। यह राज्य के विचार ख्रयवा सुरज्ञा की मावना का ख्रवहरण कर लिया गया है। यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में ख्रविचार से कार्य करने का प्रश्न नहीं है वरन् यह तो व्यक्तिगत उपक्रम में ख्रविचार ख्रीर सदेह की भावना उत्पन्न करती है तो उससे हम सतोषपद परिणाम की ज्याना क्रां कर सकते।
  - की ग्राशा नहीं कर सकते ।

    (३) व्यक्तिगत उपक्रम को बहुत ही संकुचित चेत्र प्रदान किया गया है

    (३) व्यक्तिगत उपक्रम को बहुत ही संकुचित चेत्र प्रदान किया गया है

    जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते । मारत की ग्रीद्योगिक नीति में

    जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते । मारत की ग्रीद्योगिक नीति में

    जिस प्रकार राजकीय चेत्र का निश्चित स्थान है वैसे ही व्यक्तिगत चेत्र का मी

    जिस प्रकार राजकीय चेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भी प्रयन्न का स्वामाविक

    है। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को कम करने के किसी भी

परिशाम मारत के श्रीद्योगिक विकास को कम करना है। वर्तमान समय में प्रचितत आय और सम्पत्ति के अन्तर की कम करने, व्यक्तिगत एकाधिकार की रोकने श्रोर श्रायिक शक्ति को थोढे से व्यक्तियों के हाथ मे केन्द्रित होने से बचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह तर्क ग्रासगत है। इस बात को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत में राज्य को जो श्राधकार श्राज प्राप्त हैं उनके द्वारा उद्योगों के व्यक्तिगत दोत्र में रहने पर भी वह एकाधिकार तथा श्रार्थिक शक्ति का केन्द्रित होना न रोक एके। जहाँ तक श्राय के श्रन्तर का सम्बन्ध है वह तो आर्थिक तथा अन्य उपायों रे पहिले ही काम किया जा चुका है। फिर यह कैसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उद्योगों की राजकीय त्रेत्र में रखने से श्राधिक शक्ति केन्द्रित न होगी। प्रन्य देशों के श्रनुभव के अनुसार इसका परिगाम श्रिधिक हानिकारक होगा। दूसरा कारण जिसके श्राघार पर वड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उपक्रमों का विस्तार व्यक्तिगत जेत्र में सकुचित किया गया है वह कुटीर, ग्राम्य श्रीर छोटे उनोगों की वहें उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिवन्ध लगाकर श्रौर भिन्न करारोप द्वारा श्रयवा प्रत्यन्न श्रवदानों द्वारा सहायता करना है। मारत में प्राप्य और छोटे उन्नोगों को प्रोत्साहन देने में कोई दोष नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि इनका मारत की श्रौद्योगिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु बढ़े उद्योगों को हानि पहुँचाकर छोटे उद्योगों की प्रगति करना सर्वथा अविचारपूर्ण है। मारत की राष्ट्रीय आय श्रीर श्रौद्योगिक विकास में वृद्धि वहे उद्योगों से ही सम्भव है। द्वितीय योजना का ध्येय प्रति न्यक्ति चाषिक स्राय बढाना स्रीर वेकारी घटाना है। यदि वहे उद्योगी का काल्पनिक ग्रादर्शों के लिये उत्सर्ग कर दिया गया तो वह ध्येय कमी पूर्ण नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत चेत्र के विस्तार को सकुचित कर देने का परिणाम यह होगा कि व्यक्तिगत उपक्रम उचित रीति से कार्य न कर सकेंगे।

नवीन श्रीधोगिक नीति में वे गुण तो नहीं है जो कि १६४८ के श्रीशोगिक नीति प्रस्ताय में थे, परन्तु उसके सब टोप उसमें वर्तमान हैं। १६४८ की
नीति नकारात्मक थी श्रीर उसमें व्यक्तिगत उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्ध का
ही केवल वर्णन था। राज्य से उन्हें क्या यहायता प्राप्त होगी इसके प्रति कोई
सकेत नहीं था। यही दोप नवीन श्रीशोगिक नीति में जनता को महान प्रतीत
होने वाले निर्यंक श्रादशों के सम्मक्ष्य के रूप में है। व्यक्तिगत उपक्रम की
श्राद्यिक कर, श्रायकर के नियमों के श्रमुक्ल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में
श्रवस्थिष कर, श्रायकर के नियमों के श्रमुक्ल उनके लिये पर्याप्त मात्रा में
श्रवस्थिष वृत्ति का प्रवन्ध, श्रीर सरकार की श्रम श्रीर मृत्य नीति के कारण सदैव
बढते हुये उत्पादन व्यय से रहा श्रावश्यक है। राज्य को इस हिटकोण से

व्यक्तिगत उपक्रमों को निश्चित सहायता प्रदान करनी चाहिये जिससे वे सफलता-पूर्वक ग्रपना कार्य कर सकें। सहायता का क्या रूप होगा ग्रीर वह किस विधि से दी जायगी आदि वाते सरकार की औद्योगिक नीति का एक आवश्यक अग बन जानी चाहिये जिससे कि वे सम्भव हो सके ।

१६४१ का उद्योग कानून-११५१ का उद्योग (विकास और नियमन) कातून प्रथम अनुसूची में दिये गये उन ३७ उद्योगों पर लागू होगा जिनमें १ लाख से अधिक पूँजी लगाई गई है। यह व्यवस्था की गई है कि इन समी भौद्योगिक संस्थानों को भ्रानिवार्य रूप से ग्रापनी रिजस्ट्रो करानी पढेगी। कोर्ड नवीन कारखाना स्थापित करने के लिये ग्रथवा वर्तमान कारखानों का प्रसार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करना पढेगा ।

कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अनुस्चित उद्योग की जाँच करा सकती है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। इन निर्देशी का पालन न करने पर वेन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण उद्योग को या उसके किसी भाग को एक निश्चित काल के लिए किसी व्यक्ति, बोर्ड या विकास-परिपद् के हाथ में सींप सकती है। परन्तु यह अविध ५ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यह व्यवस्थाएँ श्रस्पष्ट श्रीर विस्तृत हैं। यह खेद का विषय है कि ससद ने जिस दितीय प्रवर-समिति को यह विधेयक विचारार्थ सौपा उसने प्रथम प्रवर-समिति की रिपोर्ट में दी गई उन शतों को रह कर दिया जिनके त्राघार पर राज्य हस्तत्त्रेप कर सकता था। प्रथम प्रवर सिमिति ने विकारिश की थी कि यदि उद्योग के प्रवन्त में अधिक अन्यवस्था फैली हो, वस्तुओं के माव में अनुचित उतार-चढाव हो, वस्तुत्रों का अभाव हो, अभिको में अशाति एवम् त्रसन्तोष हो ग्रौर यटि सम्बन्धित उद्योग के कार्य मे स्थाने वाले कन्चे माल का श्रमाव श्रीर उसकी शीप्र समान्ति को रोकना राष्ट्र हित में हो तमी राज्य को अपने नियत्रण और इस्तचेष के अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इन शर्तों से निजी उद्योग सन्तृष्ट था और यदि विषेषक देखी रूप में स्वीकार कर लिया जाता तो योद्योगिक विकास को हानि न उठानी पडती परन्तु दितीय प्रवर-समिति द्वारा इन निश्चित शतों को रिपोर्ट में से निमाल देने के कारण फिर वही अनिश्चितता फैल गई जो सरकार की स्तपूर्व भी गोगिक नीति से फैली थी।

इस कानून में केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद श्रीर विकास-परिषदे स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् में उद्योगपतियो, कर्मचारियों श्रौर अनुमूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के उपमोक्ताश्रों के प्रति-निधि होगे | इनके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति मी इस परिषद् में समिलित किए जा सर्केंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समक्तेगी। श्रध्यज्ञ को छोड़ कर परिषद् की सदस्य सख्या ३० मे श्रधिक नहीं होगी । केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् श्रमु-सूचित उत्योगों के विकास श्रोर नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सुकाय देगी।

किसी भी श्रनुसचित उद्योग श्रथवा उत्योगों के समूह के लिए विकासपिष्टिं स्थापित की जा सकती हैं। विकास परिषद में उद्योगपतियों, कर्मचारियों
श्रार उन उत्योगों द्वारा उत्यादित माल के उपभोक्ताश्रों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें
ऐसे उर्याक्त भी सदस्य बनाये जा सकेंगे जिन्हें सम्पन्यित उत्योग श्रथवा उद्योगों के
त्रारे म विशेष टेम्निकल शान हो। विकास-परिषद् का कार्यचेत्र बहुत व्यापक
बनाया गया है। मुख्यत विकास परिषटें उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करेंगी,
उत्पादन-कार्य में सामजस्य स्थापित मरने के लिए सुक्ताय देंगी श्रोर समय समय
पर उद्योग श्रथवा उत्योगों की प्रगति की समीक्ता करेंगी, इसके साथ ही चृति
रोकने के लिए कुशलता के मान निर्धारित करेंगी, श्रधिकतम उत्पादन करने,
उत्पादन व्यथ करने श्रोर उत्पादित वस्तु मी प्रकार में सुधार करने के लिए सुक्ताव
देंगी। विकास परिषदें उत्पादित वस्तु मी प्रकार में सुधार करने के लिए सुक्ताव
करेंगी श्रोर विकय की व्यवस्था करेंगी श्रीर ऐसे उपाय सुक्तावेगी जिनसे श्रमिकों
की उत्पादन-शक्ति में सृद्धि हो। जैसा पहले कहा जा चुका है सरकार उत्योग की
पूर्ण व्यवस्था श्रथवा उसका कुछ भाग श्रियक से श्रधिक १ वर्ष के लिए इन
विकास परिपदों के हाथ सौष सकती है।

विकास-परिपटो से यह श्राशा की जाती है कि वह निजी उद्योग के लिए एक परिचारिका का कार्य करेंगी। १९५३ में ऐसी दो विकास परिपटें स्थापित की गई। वाद में श्रन्य विकास परिपटें स्थापित की गई। १९५७ के श्रन्त में १२ विकास परिपटें निम्न उद्योगों के लिये काम कर रहीं थीं।

- (१) भारी विद्युत् उद्योग,
- (२) इलका वियुत् उद्योग
- (३) Internal Combustion Engines तथा शक्तिचालित पग्प

<sup>3</sup> ८ मई १६५२ को कान्न लागृ होने के साथ ही केन्द्रीय परामर्शदात्री परिपद् स्थापित की गई, वाणिज्य तथा उद्योग-सन्त्री इसके श्रध्यक्ष है। १६५४ में इसका पुर्नसगटन किया गया श्रीर इसके सदस्यों की सख्या २६ कर दी गई जिनमें से १४ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि (श्रनुस्चित उद्योग के), ५ कर्मचारी, ५ उपमोक्ता, श्रीर ५ श्रन्य व्यक्ति जिनमें प्रारम्भिक उत्पादक सम्मिलित है। इससे यह परिपद् पूर्ण रूपेण प्रतिनिधि परिपद् वन गई है।

- (४) साइकिल
- (५) ग्रम्ल (acid) ग्रीर उर्वरक
- (६) द्वार (alkalı) तथा सम्बन्धित उद्योग
- (७) टवाइयॉ
- (८) जनी कपहा
- (E) कलापूर्ण देशमी कपड़ा
- (१०) चीनी (शकर)
- (११) ग्रालीह धातुये श्रीर मिश्रित घातुये, तथा

ूर्न परिपटों का कार्य श्रपने-ग्रपने उद्योगों की समस्याग्रों पर विचार करना। इनका ध्येय है उत्रोगों को अपनी पूर्ण शक्ति मर उत्पादन कर सकने की सुविधाये प्रदान करना, उनकी (रेटेड) ऋकित शक्ति को स्रावश्यक स्तर तक बहाना, ग्रीर उत्पाटन व्यय को कम करना है।

विकास परिपदों की सत्या इस लोगों ने ब्रिटेन से अनुसरण की है जहीं पर इनकी स्थापना ग्रानेको उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में की गई थी। वहाँ ये परिषद असफल सिद्ध हुये पर हम लोग अब भी इनको अपनाए हुए हैं। व्यक्तिगत उपक्रमों के सफलता पूर्वक कार्य करने के लिये यह ग्रावश्यक हैं कि उन्हें नित्य प्रति के कार्यों में प्रबन्ध कर्ता से पर्याप्त मात्रा में स्वतत्रता प्राप्त हो । उपक्रमो को कार्यारम्म करने का साइस श्रीर उत्साह होना चाहिये। यही एक श्राधार है जिस पर व्यक्तिगत उपक्रम से हम सफलता की आ्राशा कर सकते हैं। प्रक्रव करने में स्वतन्त्रता की मात्रा में कमी करने के मय, इन परिषदों की कार्यप्रणाली की अनिश्चितता तथा किसी उपक्रम के भ्रावश्यकता पहने पर सरकारी प्रबन्ध में ते लिये जाने की ग्रानिश्चित शर्ते (जैसे विकास परिषद के निर्टेशों का किसी उप-क्रम द्वारा उलान) ये उपक्रमी वर्ग के मन में सदेह की मावना भर दी है। इसके श्रातिरिक्त परिषद एक ही प्रकार की संस्थायें तो है नहीं जो अपने अपने उद्योगो में से विकिषत हुई हो, इसिलिये वे मनोवािह्यत विकास नहीं कर सकती। यह भी सम्मव है कि विकास परिषद का इस्ता चेप सरकारी नियन्त्रणों से ग्रस्त उपक्रमों के

१६५३ का उद्योग (विकास और नियमन) संशोधन कानून-भारत-विनाश का ग्रन्तिम कारण सिद्ध हो। सरकार को १६५१ के उत्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून की लागू करने के एक वर्ष पश्चात ही सशोधन कानून का आधार लेना पड़ा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मात की ब्रोबोशिक नीति कितनी ग्रानिश्चित है। ऐसी स्थिति किसी प्रकार भी लामकर नहीं कही जा सकती है। सशोधन कातृन का विश्लेषण करने से जात होगा कि उसकी व्यवस्थाएँ पूर्व की अपेचा अधिक टोषप्ण हैं। सशोधन कातृन के अनुसार किसी भी उत्योग पर सरकार परामर्शदात्री परिपद् से पूछे बिना अधिकार कर सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सरकार निर्देश दे और उत्योग को स्पष्टीकरण का अवसर है। सरकार के इन नवीन अधिकारों को प्राप्त करने से व्यापारों में उत्योगों के सम्बन्ध में और अनिश्चितता फैली है और इससे देश की औत्योगिक प्रगति अवस्छ हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं।

श्रव यह कानून ४२ उद्योगों पर लागू है, जिनमे श्रवली रेशम, नकली रेशम, रग बनाने की बस्तुये, साबुन, प्लाईबुड, फेगेमेगेनीज ग्रादि ६ नवीन उद्योग भी सम्मिलित हैं। सथाधन द्वारा सरकार को यह श्रिष्ठकार प्राप्त है कि वे यि चाई तो ५ वर्ष के पश्चात् भी (जो श्रविध एक्ट में दी हुई यी) किसी उपक्रम का प्रवन्ध श्रपने हाथों में रख सकती हैं। इसके लिये यह श्रावश्यक होगा कि नियश्रण की श्रविध बढ़ाने की एक विजित पार्लियामेट के समन्न उपस्थित कर दी जाय। स्वारी उपक्रमों को नई बस्तुश्रों के उत्पादन के लिये लाइसेन्स लेने से छूट दे दी गई है, यद्यि एक्ट मे दी हुई प्रथम तालिका में श्रनुस्चित उपक्रमों को लाइसेन्स लेना श्रिनवार्थ है। सरकार को यह श्रिष्ठकार है कि वह जिन उद्योगों को श्रपने श्रिष्ठकार में ले उनके सगठन की सात श्रीकार है कि वह जिन उद्योगों को श्रपने श्रिष्ठकार में ले उनके सगठन की सात श्रीकार है कि वह जिन उद्योगों को यि चाई तो कार्य कर सकती है। इस श्रिष्ठकार से हिस्सेदारों के सामान्य श्रिष्ठकारों को श्राधात पहुँचता है।

इन संशोधनों से उद्योग (विकास श्रीर नियमन) कानून बहुत कड़ा कानून बन गया हैं। श्रव केवल यह श्राशा की जाती है कि कानून को लागू करने वाले श्रिधिकारी सन्द्रलित दृष्टिकोण से कार्यवाही करेंगे श्रीर भारत के श्रोद्योगिक ढाँचे को सदैव के लिए नष्ट हो जाने से बचाएंगे।

राष्ट्रीयकरण की नीति—राष्ट्रीयकरण की नीर्ि अप्रत्यन्न रूप से भारत सरकार की श्रीयोगिक नीति का एक अग है। इसका सकेत उद्योग (विकास और नियमन) कानून की उस व्यवस्था से मिलता है जिसके अनुसार सरकार दुछ स्थितियों में निजी उद्योगों पर अपना श्रिषकार कर सकती है।

राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर जनता का श्रिधिकार हो। राज्य या तो श्रपने उत्योग स्थापित कर सकता है या चालू निजी उद्योगों को अपने अधिकार में ले सकता है। राष्ट्रीयकरण का देश की सामाजिक, राजनैतिक, अाथिक स्थितियों से निकट सम्बन्ध है। राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाय यह उस देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है।

सिद्धानत रूप में राष्ट्रीयकरण की नीति ना कई आधारों से समर्थन किया जा सकता है। प्राय यह कहा जाता है कि निजी उद्योग देश के सभी उपलब्ध साधनों का न तो पूर्ण उपयोग करना चाहता है और न वह ऐसा कर सकने में समर्थ ही है, इसिलए बिना राजकीय उद्योगों में तीवता से प्रगतिशील श्रीद्योगी-करण नहीं किया जा सकता। निजी उद्योगों द्वारा उद्योग के श्राधुनिकीकरण और युक्तिकरण (Rationalisation) की श्रोर ध्यान न देने की प्रवृत्ति की श्रालोचना करके भी राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है। आलोचना करके भी राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया जाता है। यह कहा जाता है। कि राष्ट्रीयकरण हो जाने से श्रीमक-मालिक के सम्बन्धों में सुधार होगा और श्रीमकों के दूने उत्साह से कार्य करने के कारण उत्पादन भी बढ़ेगा। राष्ट्रीयकरण के समर्थका का यह भी विश्वास है कि उद्योगों पर सरकार का श्राधकार हो जाने से बेरोजगारी की समस्या भी इल हो जायगी।

परन्तु यह तर्क सन्तोपजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय करण की किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व यह त्रावश्यक है कि राज्य के पास पर्याप्त पँजी हो श्रीर उसे प्रशासन तथा सभी कुशल प्राविधिक सेवाऍ प्राप्त हो। राष्ट्रीय करण के परचात् श्रमिक ग्रौर उद्योग के प्रबन्धको के सम्बन्धों में ग्रौर तनातनी होने की सभावना हे क्योंकि वर्तमान में इन दोनों के बीच राज्य सतुलन स्थापित करता है ्रे श्रौर जब कमी इनके बीच कगढे उत्पन्न होते हैं राज्य उनमे हस्तत्तेप करता है। परन्तु यदि राज्य ही उद्योग का अधिकारी हो तो इस प्रकार के क्रगडों में राज्य स्वय एक पत्त हो जायगा श्रीर इस कारण मन्यस्थता नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय-करण हो जाने से श्रीद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने का सिद्धान्त इस वात पर श्राधारित है कि जनतन्त्र में अमिक यह सममता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसी के हाथ मे है । इसलिए उसका राज्य से कोई फगड़ा नहीं होगा। परन्तु यह केवल सिद्धान्त की वात है। यह विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है कि केवल राष्ट्रीयकरण हो जाने से ही श्रमिकों का स्वमाव बदल जायगा श्रीर वह श्रिघिक कुशलता से श्रिधिक परिश्रम कर उत्पादन वहा देंगे। <u>उत्पादन तमी</u> बढ़ सकता है श्रीर वेरोजगारो को तभी कम किया जा सकता है जब राज्य जालू उदागों को ग्रपने प्रधिकार में करने की ग्रपेक्षा नुये उद्योगों को ग्रारम्भ करे।

राष्ट्रीयकरण की श्रपनी उपयोगिता होनी चाहिए। उसकी श्रपनी विशेष-ताएँ होनी चाहिए। केवल निजी उद्योगों में दोष होने के कारण ही राष्ट्रीयकरण की नीति श्रपनाना उचित नहीं है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध श्रनेक तर्क दिये जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यह वहा जाता है कि अग्रोगों पर राष्य का ग्रिधिकार हो जाने से प्रबन्ध की कुशलता में ग्रमाय ग्रा जाता है स्वांकि राजकीय श्रिधकारी उतने सतर्क श्रीर उत्साही नहीं होते हैं जितना निजी उद्योगपितयों ते श्राशा नी जाती है। राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में प्रबन्धनों को सरकार कर्मचारी होने के कारण उत्योग से निजी लाभ उठाने की समायना ही नहीं होती, इसलिए उन्ह न तो व्यवसाय बढाने की इच्छा होती है श्रीर न इस श्रोर कोई ग्राम्पेण होता है। जिन उगयोगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनका विकास करने के लिए ग्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने में ग्रियक कर लगाने की श्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने में ग्रियक कर लगाने की श्रावश्यक प्रकती है श्रीर यह समय है कि श्रायिक हिए से श्रिवक्तित देश की जनता 'कर' के इस श्रीविक्त भार का बहन करने में श्रममर्थ रहे।

भारत में वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारें कुछ उन्नोगों की अधिकारिणी हैं श्रीर उन्हें चलाती हैं जिनमें रेलवे, डाक-तार, प्रतिरह्मा सम्प्रन्थी कारराने, टेली-फोन कम्पनियाँ श्रोर कुछ निजली की कम्पनिया सिम्मिलित हैं। गत कुछ वर्षों से श्रोद्योगिक चेत्र में राज्य का प्रवेश वटता गया है। प्रीफेन्रीकेटेड हाउनिंग फेक्टरी १६४६ में स्थापित की गई श्रोर अगस्त १६५० से इसका उत्पादन कार्य प्रारम्भ हुआ, चितरन्जन लोकामादिव फेक्ट्री ने १६५० ने कार्य आरम्म किया, सिन्द्री खाड के कारराने ने अक्ट्रवर १६५१ से उत्पादन श्राम्म किया। यह सभी राजकीय उद्योग हैं। इनके श्रतिरिक्त हिन्दुस्तान विमान निर्माण उत्योग, प्रिसीजन इन्स्ट्र्मेट फेक्टरी, नेशनल न्यूजपिन्ट श्रोर पेपर मिल्स लिमिटेड मी राजकीय उत्योग हैं। राज्य ने कुछ वर्तमान उद्यागां को भी अपने अधिकार में कर लिया है। १६५३ के विमान निगम कान्त के अन्तर्गत सरकार ने विमान उद्योग पर श्रिषकार कर लिया है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। राष्ट्रीयकरण होने से कम उत्पादन व्यय पर श्रिषक श्रीर श्रव्छा उत्पादन होना चाहिए। परन्तु भारत सरकार की राष्ट्रीकरण की नीति से यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुश्रा है। इसके विपरीत इन उत्योगों में जनता के धन की श्रपार स्ति हुई है श्रीर उत्पादन में श्रनुचित देरी हुई है। इस सम्बन्ध में सिन्द्री खाद कारखाने का उदाहरण दिया जा सकता है। पहले यह श्रनुमान लगाया गया पा कि १० ५३ करोड़ रुपये में कारपाना स्थापित हो जायगा परन्तु श्रन्त में इस पर २३ करोड़ स्पया व्यय किया गया श्रोर स्थापित होने के सात वर्ष परचात् इसमें उत्पादन कार्य श्रारम्भ हो सका प्रोफेप्रीकेटेड हाउसिंग फैक्टरी द्वारा उत्पादित माल देश

ाप्त कच्चे माल के भार को निर्मित वस्तु के भार से विभाजित करने ने प्राप्त होता है। यदि 'माल का इन्डेक्स' किसी उद्योग के सम्बन्ध में बड़ा है तो इसमें इस सम्मना चाहिये कि कच्चे-माल की प्राप्ति का स्थान श्रीधक प्रभावशाली हारण है श्रीर उद्योग की स्थापना के लिये वह स्थान श्रीधक उपयुक्त होगा परन्तु दि 'माल का इन्डेक्स' छोटा है तो उससे यह समम्मना चाहिये कि कच्चेमाल ही प्राप्ति कोई विशेष महत्यशाली बात नहीं है श्रीर उद्योग की स्थापना श्रव्छी । कार बाजार के निकट की जा समती है।

परन्तु जैसा इस सिद्धान्त में बताया गया है उसके अनुसार जहाँ न्यूनतम ारिवहन व्यय हो वहाँ सर्वदा उद्योग स्थाणित नही किये जाते । इसके कई कारण ं, जैसे (१) उद्योगपितयों को कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोतो ख्रौर बाजारो का र्[ण जान नहीं होता कि वे ठीक-ठीक आवश्यक अनुगणन कर सके। होता यह है कि ग्रौसत दर्जे का व्यवसायी वर्तमान उद्योगों की स्थिति का श्रनुमान लगा तेता है ग्रीर जहाँ पर उसकी समक्त में यह ग्राता है कि वह ग्राधिकतम लाभ उठा सकेगा वहीं अपना कारखना खोल देता है। सामान्यतः वे उद्योग जो किसी थापन विशेष में केन्द्रित हो गये हैं कुछ ऐसी लामकारी स्थिति वहाँ उत्पन्न कर ते हैं जिनके कारण नवीन कारखाने वही स्थापित होने लगते हैं जिससे वहाँ छीर प्रविक स्थानीयकरण हो जाता है, (२) उद्योगपितयो के समज्ञ स्थान निर्धारण मे ादा श्रार्थिक ही कारण नहीं रहते। वे सामाजिक सुविधाये तथा जीवन की अन्य अविधायों की प्राप्ति का भी विचार करते हैं जो नगरो में सुगमतापूर्वक प्राप्त ं। इस कारण से भी वे बहुघा बड़े-बड़े नगरों में या उनके श्रासपास श्रपने गरायानों के खोलने का निश्चय करते हैं चाहे ऐसा करने में उन्हें प्राम में गरपाना खोलने की ग्रपेद्धा लाभ कुछ कम ही क्यों न प्राप्त हो, ग्रीर (३) युद-गल में इवाई इमला से रच्चा का भी व्यान रखना द्यावश्यक होता है इसलिये बहुषा उद्योगों की स्थापना खुले हुये नगरों से दूर तथा नदी के किनारो से दूर रेश के ब्रान्तरिक भाग में करना पहता है चाहे इसमें ब्रार्थिक हानि ही क्यों न उटानी पडे ।

प्रवृत्ति—भारत में उद्योगों का स्थान-निर्धारण त्रृटिपूर्ण है। एक ब्रोर मि कि वस्वई, पश्चिम वगाल ब्रीर विहार में ब्रिपेद्याकृत ब्रिधिन ब्रीधोगीकरण ज्या है तो दूसरी ब्रोर ब्रन्य राज्यों में ब्रीधोगीकरण के प्रायः सभी साधन होते ए भी विशेष विकास नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दूर ब्रामों की ब्रिपेद्या पर के पढ़ीस में ही उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से भारत के वढ़े नगरों का निर्वित प्रसार हो गया है।

तातिका १ भारत के छाँछोगिक श्रमिकों की कुल संख्या का श्रतिशत

प्रदेश	१६२१८३	१६:६क्ष	\$EX3\$	१६५१
बगाल श्रोर बग्बई	६२१	पृह् २	५७ ६	48 =
बगाल, बम्बर्ड, महास, उत्तर प्रदेश ग्रार विहार	⊏३१	<b>二</b> ዟ ይ	<i>ፍ</i> ሪ•ሄ	55 Y
शेप भारत में	१६ ६	<b>\$</b> 8.\$	१५ •६	<b>११</b> ६

क्षत्रित्रिमााजत भारत के ग्राँकडे

तालिना १ के अनुसार १६५१ म भारत के कुल श्रोद्योगिक धिमकों ने ५४'३ प्रातशत बंगाल श्रोर त्रमंद्र के दा राज्यों में नार्च करते ये श्रीर व्याप्त प्रार त्रमंद्र के दा राज्यों में नार्च करते ये श्रीर व्याप्त है कि श्रीद्योगिक विनास की दृष्टि से सन्य चित्र विदृष्ट हुए हैं जिनमें कुल श्रीद्योगिक श्रीमर्श के वेचल ११'६ प्रतिगत कार्य घरते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि तम्पई श्रीर बगाल चेत्र में कुल श्रीद्यागिक श्रीमकों की मरुया ४६२१ में ६० १ प्रतिशत थी जो घटकर १६५१ में ५४'३ प्रतिशत हो गई जब कि महास, उत्तर प्रदेश श्रीर निहार में इनकी मख्या १६२१ में कुल श्रीमकों के २१ प्रतिशत से बढ़नर १६५३ में २६'द श्रीर १६५१ में ३४'१ प्रशित हो गई। शेष भारत के श्रन्य चेत्रों में कुल श्रीद्योगिक श्रीमकों की सख्या १६२१ में १९६ प्रतिशत यी जो घटनर १६४३ में १५'६ प्रतिशत श्रीर १६५१ में १९'६ प्रतिशत यी जो घटनर १६४३ में १५'६ प्रतिशत श्रीर १६५१ में १९'६ प्रतिशत हो गई। इसका यह शर्थ है कि बगाल श्रीर बम्बई तथा देश के श्रन्य चेत्रों की श्रीम्हा महास, उत्तर प्रदेश श्रीर निहार में उद्योग श्रीपक केन्द्रित हुवे हैं।

तालिका २ भारत के कुछ नगरों की जनसंख्या (लायों में)

	१६३१	१६४१	१६५१
कलकत्ता	33.48	₹₹ ०€	રૃપ્ ૪٤
वम्बर्ड	११ ६१	१६·६५	२८ ३६
कानपुर	२'४४	<b>۲</b> ۰5 <b>७</b>	<b>৬</b> •०५
महाम	६४७	७ ७७	१४ १६
दिल्ली	₹ ४७	<b>५</b> •२ <b>१</b>	દ શ્પ્

तालका २ के ऑकडों को देखने से पता चलता है कि १६२१ से १६५१ के बीच के ३० वर्षों में मारत के बहे नगरों कलकत्ता और वम्बई की जन-सख्या में बहुत श्रिधिक वृद्धि हुई है। कलकत्ता श्रीर वम्बई की जन-सख्या श्रपने दो गुने से भी अधिक हो गई है जब कि कानपुर की जन-सख्या तीन गुनी हो गई है। इसका एक कारण तो यह है कि अन्य नगरो की भाति गाँव से लोग आकर इनमे इसते गये हैं अगेर साथ ही इन चेत्रों में उद्यागों के वेन्द्रित हो जाने से भी

हानियाँ—नगरो श्रीर वहे कस्वीं में उद्योगों के केन्द्रित हो जाने से श्रमेक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। हानियाँ हातो हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं .—(१) इससे जन-संख्या स्थान के अनुपात में बहुत अधिक वह जाती है आरे इससे मोड एकम् धिन-पिच हो नाती है। इसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है, सफाई नहीं रह पाती, रहने के लिए घरों का अभाव हा जाता है और इन चेत्रा में अनेक सामा-...., जिस्ती कि वृद्धि श्रीर उनका प्रधार होने लगता है। यदि उद्योगा को उचित रूप से विभन्न उपयुक्त स्थानों में स्थापित किया जाता तो इनमें से बहुत सा बुराईंथों से बचा जा सकता था; (२) उद्योग केवल बडे कस्यो श्रीर नगरों में दी विन्द्रत नहीं हुए हैं वरन् कुछ मुख्य प्रकार के उद्योग खास-खास राज्यों में केन्द्रित हुए हैं। चीनी उद्योग श्रधिकतर उत्तर प्रदेश श्रीर बिहार में, स्ती उद्योग बम्बर्ड, मत्य-प्रदेश ग्रोर उत्तर प्रदेश म, लोहा श्रीर इस्पात उद्योग विहार में, जूट बगाल में और कायले की खदानों की उद्याग बगाल और बिहार में केन्द्रित हैं। इसका एक कारण तो यह है कि इन देत्रों में अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल और विजली मिल जाती है और दूसरा कारण उद्योगपितयों की रुचि भी कहा जा सकता है। इस प्रकार को स्थिति से यह झानि होती है कि यदि इनमें से किसी उद्योग में मदी आ जाये तो उसका उस चेत्र पर बहुत तुरा प्रभाव पहता है। यह चीनी के उद्योग में मटी ग्रा जाय तो इससे उत्तर प्रदेश ग्रीर विहार की जनता पर विपात्त का पहाइ टूट लायगा श्रीर स्ती उद्योग में मदी श्राने से वम्बई, मध्य प्रदेश और उत्तर-प्रदेश की जनता सकट में पड़ जायगी। यदि उद्योग देश में चारी श्चीर वितरित हुए होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। यह विल्कुल संभव है कि एक उद्योग में मदो त्राते ही दूसरे उद्योग में भी मदी नहीं त्रा जाती है क्रीर यिद उद्योगों को उचित शीत से सम्पूर्ण देश में फैला रखा हो तो मंदी त्राने से उद्याग को चृति अपेजाकृत कम होगी, (१) इन्हीं कुछ चुने हुए चेत्रों में उद्योग। के केन्द्रित हो जाने से अन्य चेत्रों की प्रायः उपेक्षा की गई है। यह हो सकता है कि ग्रान्य चित्र इनके समान उत्तम सिंद्ध न हो फिर भी उनमें उद्योगों की स्थापना से कुछ श्राधिक लाभ होने को सभावना है। इन चेतों को सामाजिक सुविधारों श्रोर उत्योग के लिए प्रावश्यक प्राकृतिक साधनों का प्राच विल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। इन चेता की जनता श्र्मेक्षाकृत श्रधिक वेरोजगार है श्रीर जीविका की उपयुक्त व्यवस्था न होने से उनके रहन-सहन का स्तर भी निम्न है। यदि इन चेता में उद्योगों का चाल किया जाता, जैमे उत्तर प्रदेश के पूर्व जिले, दिस्स्स् भागत प्रोर पजान के कुछ स्थान, तो देश म उपलब्ध गावनों का श्रीर प्रज्ञा उपयोग किया जा सकता था, (४) हमारे देश में उत्योगों की जैभी व्यवस्था है वह युद्धकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। यद के समय अमर्या में इमरी भारी चिति होने की सभावना है। यदि उत्याग कुछ स्थानों पर केन्द्रित होने की श्रमेस्ता नहें जेत्र में वितरित हाता तो इस प्रकार का भय प्रपेनाकृत कम रहता।

श्राध्निक प्रवृति-यविष स्थानीकरण की दृष्टि में भारतीय उद्योग में प्रनेक टोप हैं परंन्तु इधर कुछ वर्षों से स्थिति में नुधार होने की समावना दिगाई देती है। स्ती उद्योग के लिए छारभ में प्रमाई नगर छोर उसका समीपवर्ती चैप विशेष महस्वपूर्ण समका जाता था परन्तु धीरे-घीर मन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश श्रीर ग्रन्य स्थानों में च्ली उरोंग के नने कारमाने नोले गये हैं। इसमें बम्बई का महत्व कमश कम होता गरा। यद्यपि वस्तर्द ग्रान भी नहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है अन्य स्थाना ने भी श्राना महत्त्र पटा लिया है। चीनी उद्योग ने सम्प्रध मे यव भी उत्तर प्रदेश योर बिहार प्रमुख हैं परन्तु मद्रास, बस्बई श्रीर भृतपूर्व रियासतों में भी इस उद्याग की श्रोर श्राकर्पण बढ़ा है। १६३१-३२ में कुल ३२ चीनी के कारसानों मे २६ कारसाने उत्तर प्रदेश श्रीर विदार में वे परन्त १६४२-५१ में कुल १३४ कारखानों मे ने इन दोनो राज्यों मे चेवल ६३ कारपाने ये। १६३१-३२ श्रोर १६५२-५३ के बीच मद्रास मे चीनी के कारसानों की संख्या २ से वढकर १३, वम्पई में १ से बढकर १४ श्रोर खण्ड 'ख' राज्यों में जहाँ एक मी कारलाना नहीं या १२ हो गई। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश श्रीर निहार श्रव भी महत्वपूर्ण राज्य हैं परन्तु श्रन्य राज्यों में भी चीनी के कारखाने खुल गये है स्रोर उनका भी महत्त्व कुछ बढ गया है।

जहाँ तक कागज के उद्योग का प्रश्न है इसके कारखानों की स्थापना सर्व-प्रयम बगाल में हुई जिसका मुख्य कारण कोयले की पूर्ति की सुविधा थी। कारखानों में कागज बनाने के लिए हिमालय के पहाड़ी चुत्रों से प्राय ६०० मील दूर से सबाई घास लाई जाती थी परन्तु चूंकि एक टन कागज बनाने में २३ टन घास श्रीर ५ टन कोयले की श्रावश्यकता होती थी इसलिए कोयले को प्रायमिकता दी गई। कोयले के चेत्र के निकट कारखाना स्थापित करना श्रिषक उपयुक्त सममा गया। परन्तु वीरे-धीरे वॉस श्रीर विजली का प्रयोग होने लगा। इससे कागज के कारखाने श्रान्य स्थानों को हटाये गये। सिमेट उद्योग सर्वप्रथम मन्य-प्रदेश श्रीर राजपूताना में स्थापित किया गया परन्तु धीरे-धीरे सिमेट उद्योग के कारखाने उन चेत्रों में स्थापित होने लगे जो या तो सिमेट का उपभोग करनेवाले चेत्र हैं या सिमेट का उपभोग करनेवाले चेत्रों के निकट पडते हैं।

उद्योगों की स्थाग्ना में उपर्युक्त वितरण के अने क कारण है जैसे (१) स्वदेशी वाजार का महत्व बढ़ना, परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि तथा देश के आन्तरिक भागों में इव्य बाजार की सुविधाओं की प्राप्त, (२) उत्पादन प्रविधि में विकास जैसा कि कागज के उत्पादन के स्वयम म हुआ, (३) उत्पादकों का विनाशकारी स्पर्धा नीति का सविचार त्याग तथा उद्योगों की स्थापना में सुधार की प्रवृत्ति जैसा कि सिमेन्ट के उद्योगों में दिखाई पढ़ा है, (४) देशी रियासतों का जो कि 'ल' राज्य कहलाते हैं उद्योगों को अपनी श्रोर आकृष्ट करने की नीति का अनुसरण करना जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की सुविधाये प्रदान करना जैसे अम सम्यन्वी उदार-कानून बनाना, तथा उनकी पूँजी में भाग लेना आदि, श्रोर (५) हाल में लागू की हुई उद्योगा को इन्डस्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाने की सरकार की नीति इत्यादि।

सरकार की नीति १६५१ के उद्योग (विकास एवम् नियम) कानुन के अनुस्तर भारत सरकार का उद्योग के स्थान-निर्धारण पर पूरा नियमण रखने का अविकार है। कारखानों को अपनी रिजस्ट्री करनी पड़ती है और अपना उत्पादन या उत्पदान शक्ति में वृद्धि करने से पूर्व आवश्यक अनुमित लेनी पड़ती है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई अथवा कारखाने के पास लाइसेन्स होता है। लाइसेन्स देने-वाली समिति लाइसेंस देते समय उद्योग कानून के अतर्गत कारखानों के आकार-प्रकार और स्थान इत्यादि का निश्चित विवरण देती है। चीनी के कुछ कारखानों को अनुक्ल स्थानों पर इटाने के लिए यह समिति पहले ही अनुमित दे चुकी है और स्ती मिलों को कपड़े की बुनाई के लिए वहीं नयी शाखा खोलने की अनुमित देना अस्वीकार भी कर चुकी है।

कुछ उद्योगों का लाइसेन्स इसिलये श्रस्थीकार रर दिया गया है कि जहाँ नम कारखाना खोलने का निश्चय था वहाँ पहले से ही श्रिषक कारखाने या तो रियत ये श्रथवा जो स्थान ग्रावेटन पत्र में कारखना खोलने का बताया गया था लाडसेन्स देने वाली समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समक्ता गया। लाइमेन्स देने में उन श्रावेदनो की प्राथमिकता दी जाती है जो किसी नये उपयुक्त स्थान

पर कारखाना नोलने के लिये होती है। उद्यागों के स्थान-निर्धारण की सहकारी नीति का उद्देश्य बड़े करवों श्रोर नगरों में उद्योगों के श्रधिक जमाव की पटाना है। सरकार या उद्देश्य है कि जिन राख्यों में पहले ही श्रपेन्नाकृत श्रधिक कारखाने खोले जा चुके रें वहां श्रीर श्राधिक कारखानों को स्थापित न होने दिवा जात । इसके विपरीत नये कारग्यानों को उन चेत्रों की ग्रोर ग्राप्ट किया जाय जिनका ग्रभी विशास नहीं हुया है। परन्तु भारतीय उर्जागों के उचित स्थानीय-करण की ममस्या केवल लाइनेन्स देने की व्यवस्था में ही इल नहीं की जा सकती है। उद्योगपति पिछडे हए श्रीर कम विकसित चेत्रा में नए कारपाने पोलना नहीं चाहते हैं इसना एक कारण तो उनकी पूर्व धारणा हो मकती है परन्तु वास्तव मे बात यह है कि इन चेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए न निजली की मुविवा मिलती है, न कच्चे माल की श्रीर न उपयुक्त अम की। इन पिछ्टें श्रीर विरिष्ठत चेत्रों ती श्रान उपोगों को श्राकृष्ट करने के लिये यह श्रावश्यक है कि (१) इन च्रेनों रा विकास किया जाय जिसमें उद्योगपति इनकी श्रोर श्राकृष्ट हो सर्के स्रीर (२) स्रारम्भ में उद्योगपितयों का कम से कम कुछ सुविवार्ये दी जार्य, जैसे भूमि रियायती टर पर दी जाय, रेलवे का माझा कम किया जाय. म्त्रीर जहीं त्रावश्यक हो नकट द्रव्य ने गहायता की जाय। भारत में उन्होंगों के स्थान-निर्वारण की समस्या तभी इन की जा सकती है जन सरकार इन सन बातीं की व्यान में रखनर एक उत्तरोत्तर निकासमान नीति श्रपनाये।



# युक्तिकरण

युक्तिकरण उद्योग की कार्यज्ञमता मे वृद्धि करने श्रीर उत्पादन व्यय को घटाने की लम्बी प्रक्रिया है। किसी उद्योग के युक्तिकरण से श्रमिप्राय यह है कि कारखाने में पुरानी मग्रीनो के स्थान पर श्राधिनक मशीने लगाई जाएँ, नए टेविनकल मुघार किए जाएँ, अमिकों की मख्या कम करने के लिए अम बचाने के उपायों तथा स्वचालित मशीनो का उपयोग किया जाए ग्रीर उद्योग को व्यर्थ की प्रतियोगिता से बचाने के लिए उसके सगठन में सुधार करके तथा उसकी व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर सर्गाठत करके उत्पादन कार्य की गति में वृद्धि की जाय। "युक्तिकरण का यर्थ यह है कि कार्य करने की प्राचीन परिपाटी, निश्चित क्रम तथा श्रतुमविक नियमो श्रीर शोधनो के स्थान पर ऐसे ढग का प्रयोग होने लगे जो कि वर्षों के वेज्ञानिक अव्ययन के परिखाम हैं श्रीर जिनका ध्येय साधनों को साध्यों के साथ ग्राधिकतम उपयुक्तता के साथ सयोजित करने का है जिससे कि उत्पत्ति के प्रयत्न की प्रत्येक इकाई का श्रिषकतम लाभकारी परिसाम हो।"

युक्तिकरण का उद्देश्य उत्पादन-न्यय घटाना, उत्पादित वस्तु की प्रकार में मुघार करना श्रीर उत्पादक की हानि उठाने से बचाना है। यदि उद्योग का प्रबन्ध उचित रीति से किया जाय तो युक्तिकरण उपभोक्ता तथा श्रमिकों श्रीर उत्पादकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परन्तु वास्तव में यह देखा गया है कि युक्तिकरण से प्राप्त लाभ को उत्पादक स्वय ले लेते हैं ग्रीर वस्तुन्रो की पकार म सुधार करके तथा मूल्यों मे कमी करक उपमोक्ताश्रो श्रीर पारिश्रमिक बढाकर श्रमिको को लाभ नहीं उठाने देते। श्रमिक युक्तिकरण का विरोध करते हैं, इसकी योजना से उनमे असतीय फेलता है क्योंक इसका परिणाम वेरोजगारी होता है। अमिक यह नहीं चाहते कि स्वचालित मशीनों से तथा अम बचाने के अन्य प्रयत्नी को भ्रपनाकर भ्रीर पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीन भ्राधुनिक मशीनों का उपयोग कर अनेक श्रामको को वेरोजगार कर दिया जाए। इसी कारण श्रमिको ने प्रायः युक्ति प्रस्म का विरोध किया है। श्रमिकों की यह माँग बहुत कुछ न्याय सगत है क्योंकि अतीत में युक्तिकरण का वह पूर्ण लाभ नहीं उठा छके हैं। परन्तु षदि उन्योग के युक्तिकरण से पारिश्रमिक बढना है श्रीर उपभोक्ताश्रों को कम मुल्य पर वस्तु मिल सन्ती है तो फिर श्रमिकों द्वारा इस प्रक्रिया के विरोध होने का कोई कारण नहीं रह जाता। बढे पैमाने के उद्योग केवल युक्तिकरण के द्वारा ही उन्नति कर सकते हैं और तभी श्रामकों तथा उपभोक्ताओं की स्थिति सुघर सकती है। बह सत्य है कि युक्तिकरण की योजना लागू करने से ब्रारम्भ में कुछ वेरोज-गारी फैलतो है परन्तु उत्पादन व्या स्त्रीर वस्तु का मूल्य कम हो जाने से भविष्य में उपभोक्ताश्रों की मॉग में वृद्धि होगी। इस माग की पूर्ति के लिए उद्योग में ग्रीर ग्राधिक लोगों को रोजी मिलेगो। इससे सफ्ट है कि युक्तिकरण योजना लागू होने से फैलने वाली वेरोजगारी अल्पकालीन होती है और उद्योग के उन्नति करने क साथ इसे ट्र किया जा सकता है। समस्या वास्तव में अमिक की आय और रहन-सहन के स्तर की है। यदि युक्तिकरण के साथ पारिश्रमिक में भी वृद्धि होती है तो इससे अभिनो की त्राय में वृद्धि होती है ग्रीर रहन-सहन के स्तर में भी सवार होता है। इस रूप में इस प्रक्रिया का उद्योग च्लेत्र में स्वागत करना चाहिए। ज्ञत में यह एक महत्वपूर्ण एवम् विचारणीय प्रश्न है कि यदि भारतीय उद्योग का युक्तिकरण न किया गना तो विश्व बाजार की प्रतियोगिता मे यह विदेशों की सुसगठित उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकेगा। यदि श्रीमक युक्तिकरण का विरोध करते हैं तो इसका एक ही परिणाम हो मकता है कि ग्रनेक कारखाने नष्ट हो नाऍगे, उनका वन्द करना पढ़ेगा श्रोर इससे श्रनेक अमिक वेरोजगार हो जाएँगे। वास्तव मे हमारे सम्मुख दो स्थितियाँ हैं कि या तो इम इस बात का समर्थन करें कि युक्तिकरण की योजना लागू कर अमिका हो सनियोजित एवम् नियत्रित श्राधार पर नौकरी से पृथक किया जाए श्रीर क्रमश नवीन कार्यों ने स्थान दिया जाए या कडी प्रतियोगिता का सामना न दर सकने के नारण अनेक कारखाने बन्द करके बड़ी सख्या में अमिको को वेरीजगार होने दिया जाए। हमारे सम्मुख समस्या रोजगार ऋोर वेरोलगार की नहीं विलक्त एक प्रक्रिया लागू करने से योडे श्रमिकां की योडे समय के लिए वेरोजगारी श्रीर दूसरी प्रक्रिया द्वारा प्राय सभी श्रमिको भी ऋषिक समय तक वेरोजगारी की है। इमें इन दो प्रक्रियात्रों में से एक को चुनना है।

भारत में जब तक उत्पादित माल की खपत समव यी श्रीर पूर्ति के श्रमाव के कारण उपभोक्ताश्चों को विभिन्न वस्तुश्चों के लिये श्रधिक मूल्य देना पड़ता या तब तक युक्तिकरण की समस्या सम्मवत. इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यदि वस्तुश्चों का मूल्य श्रधिक रहता तो मिल मालिकों को युक्तिकरण की श्रावश्यकता का श्रमुमव नहीं होता। मिल मालिकों ने प्रति मशीन श्रधिक व्यक्तियों को कार्य में लगाया श्रीर पुरानी तथा व्यर्थ हुई मशीनों से कार्य लेकर भी लाम उठाया। परन्तु जब से बाजार में वस्तुयां की पूर्ति में वृद्धि हुई है यीर उपमोक्ता वस्तुयां का श्रिक मूल्य देने को प्रस्तुत नहीं है तम से शुक्तिकरण की आवश्यकता में वृद्धि होती जा रही है। मिल मालिक अपना आवश्यकता से अधिक श्रीमकों को माग दे सकने में अममर्थ में श्रीर श्रीमकों के स्थान पर मशानों का उपयोग श्रीनार्थ है। यदि उपभोक्ता वस्तुश्रों का अधिक मूल्य देने को प्रस्तुत होते तो यह स्थित उत्पन्न नहीं होती परन्तु उपभोक्ता उसके लिए प्रस्तुत नहीं है इसलिए उत्पादित वस्तु का मूल्य कम करने के लिये उत्पादन-व्यय कम करने श्रीर अपने लाभ के अश्र में वृद्धि करने की हिए से उत्पादक को श्रुक्तिकरण् का सहारा लेना पड़ता है।

श्रीद्योगिक विकास सिमिति की योजना—श्रीद्योगिक विकास सिमिति ने १६५१ के श्रारम्भ म युक्तिकरण की समस्या पर विचार किया श्रीर इस बात की स्वीकार किया कि उत्पादन व्यय घटाने श्रीर भारतीय उद्योग की कार्य ज्ञमता में वृद्धि करने के लिए युक्तिकरण श्रावश्यक है। परन्तु समिति ने इसके साथ ही इस बात की भी माना कि श्रमिकों के दितां की रच्चा करना श्रावश्यक है तथा युक्तिकरण की प्रक्रिया की तीव गित से नहीं लागू किया जाना चाहिये। समिति ने निम्नलिसित निग्य किए:—

- (१) युक्तिकरण योजना लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इससे वेरोजगार होन वाले अभिकों को सख्या यथासम्भव कम करने के लिए कार्यवाही की नावे। युक्तिकरण के फलस्वरूप होने वाली छटनी छोर वेरोजगारी को कम करने के लिए समिति ने यह सुमाव दिये हैं कि (छा) कर्मचारी को मृत्यु, पद-निवृति इत्यादि के कारण रिक्त स्थानों का पूर्ति कुछ समय के लिए स्थिगत कर दो नाय, (व) अन्य निभागों म कार्य करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को बिना वेतन में कभी किये हुये श्रीर निना गत नौकरी के कम को तोहे हुये कार्य दिया जाये, (स) स्वेच्छा से कार्य छोड़ने वाले कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया जाये, (स) टेक्निकल सुधारों के कारण बेरोजगार हुये अभिकों को खपाने के लिये अहीं समय हो कार्य में वृद्धि की जाय।
- (२) प्रति इकाई उत्पादन की स्टैन्डर्ड मात्रा निश्चित की जानी चाहिये श्रीर श्रमिकों का प्रमाणीकरण होना चाहिये। यदि किसी प्रकार का मतमेद हो तो उसकी जाँच होनी चाहिये श्रोर स्टेन्डर्ड होनो पत्तों के विशेषशोद्धारा निश्चित किया जाना चाहिये।
- (3) सम्मन्वित उद्योग की रिथात स्रोर कार्य की मात्रा इत्यादि को स्रोर समान उत्योगों के स्रनुभवों को ध्यान में रखते हुये नई प्रकार की मशोनों को

लगाने से उत्पन्न टेकनिकल परिवर्तनों का कुछ समय तक परीच्या किया जाना चाहिये।

- (४) जिन श्रमिको की छुटनी की जाय उनके पुनर्वास के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। श्रमिकों को ट्रेनिंग देने श्रीर ट्रेनिंग की प्रविध में जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करने की योजना मालिकों तथा श्रमिकों द्वारा संयुक्त रूप से निर्माण की जानी चाहिए।
- (५) वेतन श्रयवा पारिश्रमिक में वृद्धि करके श्रमिक को भी युक्तिकरण के लाभ में से भाग देना चाहिए।

इस योजना में युक्तिकरण के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है परन्तु उसके दुष्परिणामी जैसे वेरोजगारी, श्रीमको का शोपण श्रीर प्रधिक कार्य लेकर भी वेतन में वृद्धि न करने की समस्या को टालने ना प्रपत्न किया गया है। मालिकों तथा श्रीमनों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। विभिन्न राज्य सरकारें श्रपने-श्रपने होत्रों में उद्योगों के युक्तिकरण नी पोजनाश्रों का परीक्षण कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस समस्या पर त्रिदलीय श्रम सम्मेलनों में विचार किया गया है श्रीर स्ती तथा चीनी उद्योग के युक्तिकरण का विशेषजों ने वैद्यानिक श्राधार पर श्राध्ययन किया है।

श्रपील पंचन्यायालयों के निर्णय—भारत में श्रम श्रपील पचन्यायालय के निर्णायों में दिये गये सिदान्तों के श्राधार पर ही भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की छटनी की जाती है। इन्हीं सिद्धान्तों के श्रानुसार यह निश्चय किया जाता है कि किस प्रकार त्रोर क्तिने अभिकों की छुटनी की जाय। पचन्यायालय के निर्णयों मे कहा गया है कि छटनी करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के व्यवस्थापकों पर है। यदि उद्योग के व्यवस्थापक युक्तिकरण श्रथवा बचत करने या श्रन्य पर्याप्त कारणों के आवार पर यह सिद्ध कर देते हैं कि छटनी की जानी चाहिए तो इसके परचात् इस प्रश्न पर विचार करना श्रावश्यक है कि किसी सीमा तक छटनी की जायगी, इस विषय में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि नमा व्यवस्थापकों द्वारा श्रमिको की छटनी न्यायसगत कार्यवाही है, वहीं वह श्रपने अनुचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो छटनी नहीं कर गहे हैं। छटनी करने के परिशाम स्वरूप बचे हुये कार्य करने वाला पर प्रार्व भार बहाना मिल मालिकों की श्रमिकों के प्रांत श्रनीति श्रोर श्रन्याय तथा स्वार्थ का एक उदाहरण है। छटनी करने की श्रनुमित केवल तभी दी जाती है जब यह सिद्ध हो जाता है कि व्यवस्था-पकों की मोंग न्यायसगत है, उसका उद्देश्य अनुचित स्वार्थ साधन नहीं है श्रीर किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए छटनी नहीं की जा गद्दी है।

इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि छटनी लागू करने में व्यवस्थापकों को दो महत्वपूर्ण सिद्धान्ता को मानना पडेगा — (१) नई मर्ती के अमिक की छटनी पहले की जायगा और (२) यदि उद्योग में नई मर्ती हो और यटि छटनी में निकाले गये योग्य अमिक प्राप्त हो सके तो नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जायगी। अपील पचन्यायालय के निर्णयों में यह िखान्त प्रतिपादित । कया गया है कि कोई कम्पनी केवल लामाश कम हो जाने के कारण श्रपने श्रमिकी की छटनी नहीं कर सकती है यदि वाजार में उत्पादित माल की माँग कम है या कच्चे माल के ग्रमाव के कारण व्यापार में ग्रल्पकालीन गतिरोध श्रा जाय वो ऐसी स्थिति में मालिक को श्रमिको की छटनी कर उनकी श्राय छीन लेने की अनुमित नहीं दी जा सकती है। यदि उद्योग अथवा कम्पनी के स्थायी आदेशों में व्यवस्था हो तो मालिक ऐभी स्थिति में मास में कुछ दिन कारखाने में बैठकी करा सकता है। स्थायी आदेशों के अनुसार वैठकी कराने से ३३ वीं घाग का उल्लघन नहीं होता है। घाटे पर चलने वाले कारखाने को बन्द कर देने का मालिक को पूरा त्राविकार है परन्तु यदि पचन्यायालय के सम्मुख मामला प्रस्तुत होने की अविध में ऐसी स्थिति आ जाय तो कारखाना वन्ट करने के लिए न्यायालय से श्रनुमित लेनी श्रावश्यक है।

श्रपील पचन्यायालय के निर्णायों के आधार पर विकित प्रणाली काफी सितोषजनक रही है परन्तु श्रमिकों की शिकायत है कि (श्र) मालिक अपनी स्पिति का दुरुपयोग करते हैं और श्रावश्यकता न रहते हुए भी श्रमिकों की छटनी की काती है श्रीर (व) इससे काफी बड़ी सख्या में श्रमिक वेरोजगार हो गये हैं। इसके जाती है श्रीर (व) इससे काफी बड़ी सख्या में श्रमिक वेरोजगार हो गये हैं। इसके विपरीत मालिकों की शिकायत है कि उन पर श्रमेक ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिससे उत्पादन न्यय को कम नहीं किया जा सका है श्रीर श्रावश्यकता न रहते हिए भी उन्हें श्रिषक श्रमिकों को कार्य पर लगाये रखना पड़ता है।

सरकारी नीति—मारत सरकार की नीति युक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की है (अ) यदि किसी उत्पादन इकाई के मालिक और अमिक टोनो परस्पर इस बात को स्वीकार करते हैं अपवा (ब) श्रीचोगिक विकास समिति की योजना इस बात को स्वीकार करते हैं अपवा (ब) श्रीचोगिक विकास समिति की योजना के अनुसार युक्तिकरण श्रावश्यक है और अपील पचन्यायालय के निर्णयों के अग्रनक्ल है। इन निर्णयों में यह भी दिया हुआ है कि अमिक को श्रल्पकाल के श्रानुक्ल है। इन निर्णयों में यह भी दिया हुआ है कि अमिक को श्रल्पकाल के लिये कार्य से प्रथक कर देने के बदले में अथवा छटनी कर देने के बदले में लिये कार्य से प्रथक कर देने के बदले में अथवा छटनी कर देने के बदले में अथवा हिना पड़ेगा। जब तक कोई मिल मालिक श्रावश्यक हरजाना देता है हरजाना देना पड़ेगा। जब तक कोई मिल मालिक श्रावश्यक हरजाना देता है श्रीर दी हुई सपूर्या बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई श्रापित नहीं की श्रीर दी हुई सपूर्या बातों को स्वीकार करता है तो युक्तिकरण में कोई श्रापित नहीं की जा सकती। मार्च १९५४ में लोक सभा के तरकालीन विच मन्त्री श्री चिन्तामणि जा सकती। मार्च १९५४ में लोक सभा के तरकालीन विच

देशमुख ने पेन्द्रीय गरकार के प्रजट पर वार्टायवाद का उत्तर देते हुय कहा था कि ---

"सगीत उद्योगा में २५ लाए में कुछ थाड़े ने श्रविक व्यक्ति लगे हुये हैं जिनक सम्यूष में युक्तिकरण मा प्रश्न उठाया जाता है। यह तो सर्विदित है कि उद्योगों में रोजगान के प्रमुखां की पर्याप्त मृद्धि किये बिना मुगल व्यवस्था की प्रवृत्ति पढ़िने के नारण तथा जन सख्या की वृष्ट क फलस्वस्त श्रिमकों की निरन्तर बढ़ती हुई सत्या मा कार्य देना सम्मव न हा सकेगा। इसके श्रतिरिक्त प्राप्य श्राधिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत श्रर्थिक सख्या में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हे पूर्ण शाक्त भर कार्य करने का श्रवसर नहा प्राप्त है। इस नात से तो सभी सहमन होगे कि प्राधागिक विकास के प्रति अदूरदर्शिता का परिचय देते हुये कार्य करने के श्रवसर में वृद्धि करना उचित न होगा। मेरा ऐसे विश्वास है कि युक्तिकरण द्वारा श्रद्धायी रूप से स्थानान्ति व्यक्तियों का जो ज्ञति हाती है यह जनता के हित के लिये श्रार्थिक व्यवस्था के प्रसार को नीति द्वारा पूर्ण हो जाता है। यह सम बात का एक श्रीर उटाहरण है जिसमें सामाजिक न्याप की बांछनीयता को श्रार्थिक महत्ता के श्रारे सुरुमना पहता है"।

"समासदों का यह ता शात होगा ही कि हाल में ऐसे कानून बना दिये गये हैं जिनके श्रन्वर्गत श्रीमरों का ग्रायकारा प्राप्त करने पर सदायता तथा कार्य करने के काल में यदि श्रस्पायी रूप में काय से प्रयक्त होना पहें तो भी उसका हरजाना दिया जायगा। सभा सदों को स्मरण होगा कि एक उद्याग निरोप में ऐसी स्थिति उलन हो गइ थी कि सरकार ने लाक सभा की वेठक का समय न होने के कारण श्रध्यादेश द्वारा इन कानूनों का प्रचलित कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे श्रमिकों के हित की रच्चा के लिये जो छटनी के श्रन्तगत श्रा गये हैं बहुत श्रिषिक महत्व देती हैं। मने पहिले भी कहा है कि श्रास्थायी रूप से श्रापने कार पर से इटाये हुये अभिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये जा उन्छ सम्भव हो, किया जाना चाहिये, पर मेरा मत है कि हमें ऐसी नीति का श्रनुसरण न करना चाहिये जिससे पीद्योगिक विकास श्रवस्द हो जाय श्रीर कार्य करने के त्रवसरों का विकास भी कक जाय। किसी भी समय इर उद्योग में विभिन्न ज्ञमता चाले अनेक उपक्रम उत्पादन-कार्य करते रहते है। उनमे से कुछ तो हाल में ही श्रारम्भ भिये हुये होते हैं या श्रारम्भ होते रहते हैं, दुछ मे प्रसरण श्रीर कुछ मे चकुचन की प्रवृति लिइत होती है स्रीर कुछ की ऐसी हिथति होती है कि उनका अन्त होता रहता है। इसलिये उद्योग के समुचित विकास भ्रीर वृद्धि के लिये यह श्रावरपक है कि प्रत्येक उपकम द्वारा श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार नियुक्त श्रमिकी की सख्या के सम्बन्ध में कुछ लोच श्रवश्य रहे। हमें कुल कार्य करने के श्रवसरी के योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वह नीति जो श्रपने श्राश्वासनों द्वारा छटनी श्रसभव करती है नये ढगों से श्रन्य उपक्रमों द्वारा उत्पादन के विकास श्रीर वृद्धि को निश्चयं ही रोक देगी श्रीर समयत उसके द्वारा देश की श्रार्थिक व्यवस्था को जिसमें श्रमिक श्रवश्य सम्मिलित हैं उस ज्ञति की तुलना में जिसे बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है कहीं श्रिषक ज्ञति पहुँचावेगी"।

मारत के विस मन्त्री द्वारा स्थिति का यह ऐतिहासिक वर्णन इस बात को स्पन्ट करता है कि हमें एक या दो उपक्रमो में छटनी किये जाने से चिन्तित नहीं होना चाहिये, वरन् हमें सम्पूर्ण स्थिति को विस्तृत हिन्दिकोण से देखना चाहिये। यदि हम ऐसा करेंगे तो युक्तिकरण हमारे लिये (१) बढती हुई जन-सख्या के लिये कायं के श्रवसर प्रदान करने का, (२) श्रमिकों की श्राय तथा उनके रहन-सहन के स्तर को बढाने का श्रीर (३) उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने तथा प्रौद्योगिक विकास निश्चय करने का साधन होगा। परन्तु यह श्रावश्यक है कि व्यक्तिगत श्रमिकों की श्रावश्यक कठिनाइया से रच्चा की जाय। इस सबन्य में कार्य से प्रथक किये जाने पर हरजाना देने का कानून द्वारा ही प्रवन्य कर दिया है श्रीर उस श्रमिक विशेष के लिये श्रन्य कोई कार्य द्व ढ लेने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये।

सूती मिल उद्योग—१६२६-२७ में प्रशुक्त मण्डल ने इस श्रोर ध्यान श्राकिपित किया कि सूती मिल उद्योग में श्रावश्यकता से श्रिषक पूँजी एकत हो रही है श्रीर उसमें श्रावश्यकता से श्रिषक श्रीमक लगे हुए हैं। बोर्ड के कथनानुसार १६१७ श्रीर १६२१ के मध्य उद्योग की कुल पूँजी २० ८४ करोड़ से बढ़कर ४० ६८ करोड़ हो गई जो उस समय उद्योग की मशान इत्यादि सपित को देखते हुए बहुत श्रिषक थी। बोर्ड इन सब बातो का श्रध्ययन कर इस परिणाम पर पहुँचा कि भारतीय स्ती मिलों में श्रम का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। भारत में एक श्रीमक १८० तकुश्रों में कार्य करता है जन कि जापान का श्रीमक १४० में, इक्क्लैंड का श्रीमक ५४० से ६०० में श्रीर श्रमरीका का श्रीमक ११२० तकुश्रों में कार्य करता है। मारत में प्रत्येक बुनकर के पास श्रीसत न कर्च हैं । इन दोषो के कारण भारतीय सती मिलों में उत्पादन क्यय श्रीषक होता है। प्रशुक्त महल की सिफारिशो के श्राधार पर सती मिल उद्योग ने बबई की कुछ मिलों में लाग करने के लिए श्रीककरण की एक योजना निर्माण की। इस योजना की विशेषता यह थी कि एक व्यक्ति एक के स्थान पर दो कातने की मशीन चलाएगा श्रीर

एक बुनकर टो के स्थान पर ३ या ४ क्यें चलायेगा। परन्तु श्रमिकों ने इस योजना का विरोध किया श्रीर इसे लागू नहीं किया जा सका। १९३२ में जाँच करने के परचात् प्रशुल्क मरहल ने पता लगाया कि यदि यह योजना लागू की गई होती तो उत्पादन न्यय में १७ से २० प्रतिशत तक कमी हो जाती। स्ती मिल उद्योग ने उत्पादित वस्तु के प्रमाणीकरण, कय श्रीर विक्रय, न्यवसाय के पुर्नसगठन श्रीर श्राधिक हिंद्र से श्रमुपयुक्त मशीनों को प्रलग करने के लिए ७ मेनेजिंग एजेन्सियों को एक में एकत्रित करने की योजना निर्माण की। इन एजेन्सियों के पास ३४ मिल थीं। इस योजना में यह न्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक मिल को पूर्व निर्धारित मूहन पर ले लिया जायगा, मूहन साधारण शेयरां में दिना जायगा, न विके हुये माल का स्टाक बाजार भाव पर क्रय कर लिया जायगा श्रीर नाम के निए कुछ धनराशि नहीं दी जायगी। परन्तु वित्त के श्रमाव के कारण योजना कार्यन्वत नहीं की जा सकी।

इन योजनार्थ्यों के विफल हो जाने पर भी स्ती मिल उद्योग ने निरन्तर युक्ति नरण योजना लागू करने का प्रयन्न किया है। बम्पई श्रम समिति द्वारा प्रचलित की गई प्रश्नावली के उत्तर में बम्बई मिल मालिक सघ ने इस बात पर महत्त्व दिया कि भारतीय उत्रोग ने उत्पादन मे सभी श्राधुनिक उपायों को ग्रपनाया है। श्रनेक स्ती मिलों की पूँजी भी घटाई गई ख्रौर १६२७ श्रौर १६४० के बीच स्ती मिल उद्योग ने प्रशुलक मग्रहल के सुकाव के श्रनुसार मोटे श्रीर घटिया प्रकार के कपडे के स्थान पर श्रच्छे प्रकार के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की नीति श्रपनाई। परन्तु इस सुघारों के होते हुये भी स्ती कपड़ा उद्योग की उत्पादन च्मता कम है श्रीर उसके युक्तिकरण की श्रावश्यकता है। स्ती मिल उद्योग सम्बन्धी वर्किंग पार्टी ने १९५२ में यह पता लगाया था कि लगभग १५० वर्तमान सूती मिलें जो कि कुल मिलों की सख्या की लगभग ३३६% थीं, आर्थिक दृष्टि-कोण से श्रनुपयुक्त श्रीर हीन इमता वाली मिलें थीं। व्लोरूम के वाहन्डिंग विभाग में तथा रगाई विभाग मे जिन मशीनों का प्रयोग हो रहा है वे अनुपयुक्त थीं। इस प्रकार कर्घों की सख्या के सम्बन्ध में जो प्रत्येक श्रमिक की देखरेख में था वर्किंग पार्टी ने पतालगाय। या कि दिक्षीकी एक मिला में श्रीर मद्रास की दो मिलों में स्वचालित कर्षे ही लगाये गये हैं ग्रौर एक एक दिनने वाला अमिक ४, ६, ८ स्रौर १६ कघों पर कार्य करता है। स्रहमदाबाट-की एक मित्त में १८ कर्षों पर एक अभिक और वम्बई की एक अन्य मिल में ६ कर्षे पर एक अमिक कार्य करता है। फिर भी श्रधिकाश मिलें उत्पादन ज्ञमता में हीन हैं श्रीर पुरानी मशीना का प्रयोग करती हैं।

वर्किङ्ग पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि उन मिलों का कार्य जो स्वचालित कर्षों का प्रयोग कर रही है सतोषननक हैं। श्रन्य मिलों में भी स्वचालित कर्षों के 'श्राधुनिक श्रीर मशीनों के प्रयोग किये जाने तथा उत्पादन का युक्तिकरण करने की श्रावश्यकता स्पष्ट हो जाती है। सितम्बर १९५४ में कान्नगो कमेटी ने यह सिकारिश की यी कि उत्योगों के सभी विभागों जैसे मिलों, शिक्त स्वालित कर्षों, हाथ कर्षों श्राटि का युक्तिकरण १५ वपा के श्रन्तगंत हो जाना चाहिये। वर्किंग पार्टी ने युक्तिकरण की श्रविष केवल १० वर्ष ही रक्खी थी।

उत्तर प्रदेश में कानपुर की मूती-मिलों को विशेष कठिनाइयों का समना इसलिये करना पड रहा है कि उन्होने श्रपनी श्रावश्यकता से श्राधिक श्रमिकों को लगा रक्ला है। इससे यहाँ की मिलों का उत्पादन व्यय देश के श्रन्य भागों की भिलों की श्रपेचा बहुत श्रधिक है। यदि इनमे युक्तिकरण न किया गया तो इन मिलो के बन्द हो जाने का भय है। यह बड़े सीभारत की बात है कि श्रमिक श्रोर मालिक दोनो ही ने जून १६५४ में नैनीताल में हुई त्रिदलीय समा में इस बात को स्वीकार किया था कि कानपुर की सुती मिला के उत्पादन का युक्तिकरण किया जाना चाहिये। इसका श्रर्थ यह होगा कि प्रत्येक श्रीमक, जैसा कि बम्बई में हो रहा है, दो कर्यों के स्थान पर चार कर्यों पर कार्य करेगा ब्रोर कार्य भार की मात्रा में भी सामान्यत. बृद्धिहो जायगी। इससे मिलों का बन्द होना एक जायगा श्रीर श्रमिकों को बरवस वेकार न रहना पहेगा। इस योजना के सम्बन्य में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अम मत्री सम्पूर्णानन्दजी ने कहा था कि, "हाल में सेन्द्रल हिस्पृद्ध एक्ट में जो सुधार हुआ है उछने मालिकों के लिये श्रतिरिक्त अमिकों की छुटनी करना हरजाना देकर श्रपेज्ञाकृत प्रधिक सरल कर दिया है। श्रनेकों 'मिल मालिक इसमें श्रपना लाभ देखेंगे कि वे छटनी करके हरजाना देकर ग्रपने मिल में स्थायी बचत कर लें। हमारी समस्या उन श्रीमकों की किसी प्रकार रक्षा करने की है जिनके छाँट दिये जाने का भय है। सरकार की युक्तिकरण की ऐसी योजना बनाने के निर्णय पर, जिसके अन्तर्गत ५००० और ६००० के मध्य <sup>1</sup> श्रानुमानित छाट दिये जाने वाले अमिकों को कार्य करने का अवसर पाप्त हो सके, इस प्रष्ठभमि के समज्ञ विचार करना चाहिये"। कानपुर की अनेक मिलें जो अभी तक वहीं कठिनाई से दो शिफ्ट में कार्य कर पा रही थीं अब तीन शिफ्ट में कार्य कर सकेगी जिससे कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेगे। इसके अतिरिक्त युक्तिकरण की यह योजना कानपुर के सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की श्रीसत पारिश्रमिक जिसमें मेहगाई भी सम्मिलित होगी, द्यु रु से बढाकर ११५ रु प्रति मास ग्रीर विशेष जमता वाले श्रमिकों के लिये १५० रु प्रति मास कर सकेगी।

जूट उद्योग—जूट उद्योग भारत का सर्वाधिक सुसगठित उद्योग है श्रोर श्रारम्भ में ही इस उपाग ने यह नीति श्रपनाई है कि मर्राानी का प्रयोग रोक कर तथा प्रति सप्ताह कम घन्टे कार्य कर उत्पादन की मात्रा को श्रावश्यकता श्रिषक न होने दे ताकि जिना जिका माल स्टाक म एकपित न होने पाव । द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जूट उद्योग के पास श्राद्योगिक सावन बाजार की सुल सेमींग ने कहां श्रिषक थे। यह श्रातुमान लगाया गया था कि जाजार की सुल मान को जूट उद्योग प्रयन। सुल मशोनों में से कवल एक चीपाई का उपयोग करके पूरा कर सकता है। परन्तु वर्तमान स्थिति जिल्कुल मिन्न है। यह श्राशा की जाती है कि भविष्य में जूट के सामान की मींग में वृद्ध होगी पर्रार जूट मिलों में इस समय जितनी मशीने है उन सन का उपयोग करना पड़िया। परन्तु योजना श्रायोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना में जूट उद्योग का श्रीर प्रसार करने की कोई व्ययस्था नहीं की है। वार्षिक वास्तविक उत्पादन शक्ति १६५५-५६ में भी १२ लाए उन ही रहेगी। १६५०५१ में भी उत्पादन शक्ति इतनी ही थी। यदि उद्योग श्रापनी पूरी शक्ति से उत्पादन करे तो सारा उत्पादित माल घरेलू माँग श्रीर निर्यात करने में स्थ जायगा।

१६४२ की गमियों में भारत सरकार ने भारतीय जुट मिल मालिक सप को सुकाव ।दया या कि वोयले तथा परिवहन का सरज्ञाण करने के लिए उद्योग का युक्तिकरण श्रावश्यक है। सरकार के कथनानुसार रेलवे विभाग जूट उद्योग के क़ल वास्तविक उत्पादन को पश्चिमी मागो तक ले जाने की व्यवस्था कर सकने में ग्रमभर्य था। जींच करने पर पता चला कि जुट की वस्तुश्री की कल माग, जिनमें देश के अन्दर का उपभोग भी समिलित है, लगभग ५५ हजार टन प्रति मास होगी जब कि कुल ६५ हजार टन माल का उत्पादन किया जा रहा था। इससे स्पष्ट था कि उत्पादन में कमी की जानी चाहिए। मारत सरकार ने सुक्ताव ।दया कि उत्पादन कम करने के लिए केवल उन्हीं मिलों में उत्पादन कराया जाय जिनमें विद्युत सवालित मशीने हैं। भारतीय झूट मिला ने इस सुकाव को स्वीकार नई। किया ब्रीर युक्तिकरण की एक नवीन योजना लागू कर टी जिसके अनुसार बाय की बचत करने के लिए कायले के केन्द्रीय स्टाक स्थापित किए गये श्रौर कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। तदपश्चात् एक 'समह योजना' लागू की गई जा १ जुलाई १९४४ से ३१ मार्च १९४६ तक प्रचलित रही। युक्तिकरण नी इस योजना से उद्योग कोयले के ब्यय में बचत करने में चफल हुआ स्त्रीर कुछ मिलों को युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर जो हानि उठानी पदी उसका और श्रिविक समान वितरण किया जा सका ।

वर्तमान समय में श्रपनी पुरानी श्रौर घिसी हुई मशीनों को परिवर्तन करने के लिए श्रौर श्रन्यदेशों के उद्योगों की मॉित उत्पादन के विल्कुल श्राधुनिक उपायों का उपयोग करने के लिए जूट उद्योग को युक्तिकरण की योजना लागू करने की श्रत्यन्त श्रावश्यक्ता है। चूँ कि भारत के जूट उद्योग को विदेशी उत्पादकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए श्रन्य देशों द्वारा प्रयुक्त प्राविधिक कुशलताश्रों का यहाँ भी उपयोग किया जाना चाहिए। भारत की कुछ मिलों ने श्राधुनिक मशीनों का उपयोग श्रारम्भ कर दिया है। उत्पादन व्यय कम करने के लिए श्रन्य उद्योगों को भी ऐसा करने की श्रावश्यकता है। इन योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में दो सब से बड़ी कठिनाहयाँ यह हैं कि (१) इनके लिए ४० से ४५ करोड़ रुपये की श्रावश्यकता है, जो वर्तमान समय से उपलब्ध कर सकना कठिन है श्रीर (२) इन योजनाश्रों के कार्यान्वित हो जाने से लगभग ४० हजार श्रमिक वेरोजगार हो जायेंगे।

कोयला उद्योग—कोयला उद्योग में कोयले की छोटी-छोटी श्रीर श्रार्थिक हिन्द से अनुपयुक्त खानों को सम्मिलित कर एक बड़ी इकाई का रूप देने, विभिन्न उपायों से धातुशोधन के कार्य श्रानेवाले बिद्धया कोयले का सरज्ञ्या करने श्रीर कोयले की खानों में मशीनों का उपयोग करने के लिए युक्तिकरण की योजना लागू करना श्रावश्यक है।

कोयला उद्योग में मशीनो का उपयोग करने से श्रिमियाय यह है कि खान में कोयला काटने श्रीर उसे नियत स्थान तक ले जाने के लिए मशीनो का प्रयोग किया जाय श्रीर कोयला निकालकर नियत स्थान तक ले जाने की दोनों कियाएं एाथ-साथ हों। भारत में मशीनों का प्रयोग श्रमी बहुत कम हुआ है। १६४४ में कोयला निकालने की २१० मशीनों थीं जिनसे २१ लाख टन कोयला निकाला जाता था। १६३६ में इस प्रकार की केवल १८६ श्रीर १६३५ में केवल ६५ मशीनों थीं। १६५१ के मध्य तक भारत में ३७४ मशीनों से प्रति मास लगभग ५ लाख ६० हजार टन कोयला (श्रयांत् ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष) निकाला गया जो श्रीसत मासिक उत्पादन का लगभग १९६ प्रतिशत था। भारतीय कोयला-खान समिति ने १६४६ में सिफारिश की कि मारतीय कोयले वी खानों में मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि मशीनों के उपयोग से ही उत्पादन शीन बहाया जा सकता है जो कि भविष्य के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। वर्तमान में मशीनों के उपयोग के प्रति थोड़ी प्रतिकृत्वता होने के कारण शायद सत्ते श्रम की उपलब्धि है। जब श्रम महँगा पड़ने लगेगा, पारिश्रमिक बढ़ने लगेगा तो श्रवश्य ही इस प्रतिकृत्वता में परिवर्तन होगा श्रीर तब मशीन श्रीर श्रम के बीच

उपयोगिता की दिष्टि से विचार कर उपयुक्त साधन छाँटने के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा। कोयला उद्योग के सम्बन्ध में १६५० में विकिक्स पार्टी ने सुक्ताव दिया कि खानों में मशीनों का उपयोग करने से ही सुनियोजित उपाय से शीव उत्पादन बढाया जा सकता है और मविष्य में देश के श्रौद्योगीकरण की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति को जा सकती हैं । सम्पूर्ण व्यवस्था का सन्तुलित विकास करने के लिए सानों में शीव ही मशीने नहीं लगानी चाहिए। इसके लिए एक अविध निश्चित की जानी चाहिए। यह उचित नहीं है कि एक साथ समी खानों में मशीनों की सहायता से उत्पादन आरम्म कर दिया जाय। इसके लिए एक एक खान करके प्रगति करनी होगी। क्रमशः मशीनों का उपयोग बढाने पर भी कोयले की खान के श्रमिकों में वेरोजगारी फैल सकती है। विकद्ग पार्टी इस परिसाम पर पहुँची कि खानों में मशीनों का उपयोग करने में वेरो गगारी के भय मे वावा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मशीनों के उपयोग से हानियों की श्रपेन्ना लाभ वहीं श्रविक हैं। इसकी सफलता के लिए वर्किक्स पार्टी ने सुमाव दिया है कि (१) छोटी छोटी कोयले की सानों को कम से कम १० हजार टन प्रति मास उत्पादन करने वाली इकाई के रूप में सगठित कर दिया जाय ग्रीर (२) कोयले की खाना में लगाई जानेवाली मशीनों का भारत में ही निर्माण किया जाय !

भारत के श्राधिकाश उद्योगों में कम ने कम तीन चेत्रों में युक्तिकरण की योजना लागू करना अत्यन्त आवश्यक है (१) कारखानों के स्थानीयकरण में सुधार, जैसे चीनी ग्रोर कुछ सीमा तक लोहे तथा इस्पात के कारखानों में। १९५१ के उद्योग (विकास एवम् नियमन ) कानून के ग्रन्तर्गत स्थापित लाइ-से।न्संग सिमति ने पूर्व मे ही चीनी के कुछ कारखानों को अधिक अच्छे स्थान पर हटा लेने की अनुमित दे दी है। लोहे श्रीर इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में श्राशा की जाती है कि नये लोहे और इस्पात के कारखानें नये स्थानों पर स्थापित किए जार्येगे, (२) उत्पादन के उपायों में सुधार, जैसे गन्धक का व्यय कम करने के लिए चीनी उद्योग में, घातुशोधन के काम आने वाले विद्या कीयले की बचाने के लिए लोहे तथा इस्पात के उद्योग में श्रीर उत्पादित माल का प्रकार सुधारने तथा उत्पादन व्यय घटाने के लिये उत्पादन के ढग में सुघार करने की त्रावश्यक्ता है, (३) कारखानों का स्त्रार्थिक दृष्टि से उपयुक्त दाँचा निश्चित करने ने लिए प्रति मशीन पीछे कार्य करने वाले अमिकों की सख्या मे कमी करने की यावश्यकता है। भारत के लोहे तथा इस्पात, चीनी, सूती, कपहा, जूट तथा श्चन्य उद्योगा में प्रत्येक मशीन पर श्रावश्यकता से श्रधिक श्रमिक नियुक्त किये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन न्यय श्रिषिक होता है श्रीर उद्योग की

#### अध्याय २८

# वेरोजगारी की समस्या

यह त्राश्चर्यजनक बात है कि श्रार्थिक हिंदर से बहुत कम विकित देश में वस्तुश्रों श्रीर विमिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के श्रमाव के साथ वेरोजगारी हो श्रीर बहुत बड़ी मात्रा में श्रम-शिक श्रम्युक्त पड़ी हो। मारत श्रार्थिक हिंदर से बहुत कम विकास कर सका है परन्तु यहाँ वेरोजगारी भीषण रूप धारण किए हुए है। इस कारण मारत की राष्ट्रीय श्राय बहुत कम है, रहन-सहन का स्तर बहुत निम्न है श्रीर जनता दुखी तथा श्रसन्तुष्ट है। मारत में केवल शिच्चित लोगों श्रीर उद्योगों तथा कृषि चेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही वेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ रहा है वरन नागरिक एवम् ग्रामीण चेत्र की प्रायः सम्पूर्ण जनता इसके चगुल में फॅसी हुई है। पाश्चात्य देशों में भी वेरोजगारी है परन्तु उसका कारण व्यापार में मन्दी श्रा जाने से कुछ समय के लिए वस्तुश्रों के माँग की कमी है। इसके साथ ही वहाँ कुछ ऐसे कारखाने हें जो वर्ष में कुछ मास चलने के पश्चात् शेष मास बन्द रहते हैं श्रीर इन मासों में वहाँ वेरोजगारी फैल जाती है। प्राय एक कार्य छोड़ने के पश्चात् तुरन्त दूसरा कार्य नहीं मिल पाता श्रीर इस बीच की श्रवधि में भी एक प्रकार की श्रस्थानी वेरोजगारी रहती है तथा श्रन्य प्रकार की श्रत्थालीन वेरोजगारी होती है।

मारत में वेरोजगारी तथा श्राशिक रोजगारी श्रिधिकाश जनता के जीवन का स्थायी श्रग वन चुके हैं। इसका कारण यह है कि देश की जन-सख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है श्रोर देश के श्रार्थिक साधनो का बहुत कम विकास किया गया है। गत कुछ वर्षों से इस समस्या ने गम्मीर स्थिति उत्पन्न कर ली है। प्रथम पचवर्षाय योजना मे इसके निम्निलिखित काग्ण बताए गए हैं.—

(त्र) जन-संख्या की तीव गति से वृद्धि,

- (व) शास्य उद्योगों का नष्ट हो जाना जिनमें त्रामों के बहुत से व्यक्तियों हो स्राशिक व्यवसाय प्राप्त हो जाता था,
- (स) व्यवसाय की दृष्टि से कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादन चेत्रों का पर्याप्त विकास (यद्यपि गत ४० वर्षों में काफी विकास हुआ है फिर भी १६११ प्रचात् कृषि चेत्र में व्यवसायों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ३ प्रतिशत रही है),

(द) देश-विभाजन के परिगाम स्वरूप जन-सख्या ना बहुत बड़ी सख्या में विस्थापित होना।

श्राकडा के श्रभाव मे यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि भारत में वेरोजगारो या श्राशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की सख्या कितनी है। कुछ अधिकारियों का अनुमान है कि प्राम्मों में जन-सख्या का लगभग ३० प्रतिशत वेरोजगार है श्रीर ऐसे व्यक्तियों की सख्या वहुत श्राधिक है जो श्राशिक रूप से रोजगार पाए हुए है। श्रन्य श्रनुमानों के श्रनुसार देश की कुल जन-सख्या आमीण एव नागरिक दोनों चित्रों में वेरोजगार श्रीर श्राशिक व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों की सख्या ५ या ६ करोड़ के बीच में है। यह वेरोजगारी की बहुत बड़ी सख्या है। पश्चिम के कुछ काफी विकसित देशों में समृद्धि के समय कुल जितने व्यक्तियों को व्यवसाय प्राप्त है उनके एक से तीन प्रतिशत से भी कम व्यक्ति वेरोजगार रहे हैं। परन्तु भारत की स्थिति विल्कुल भिन्न है। भारत के समृद्धि काल में व्यवसाय प्राप्त व्यक्तियों के श्रनुपात में वेरोजगारों की सख्या पाश्चात्य देशों के श्रिधकतम मन्दी के काल की तुलना में कहीं श्रिधिक है।

"भारतीय समस्या का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण द्रार्थिक व्यवस्था की प्रकृति से हैं। इसिलिये इस पर विचार इसी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये। शिज्ञित वर्ग की वेकारी की विशेष महत्ता के प्रदर्शन से, जो कि स्वामाविक मी है, इस वर्ग के विशेष मुखरित होने और राजनैतिक प्रभाव डालने की ज्ञमता रखने के कारण हम भ्रान्ति में पढ़ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक हानि उठाने वाले भूमि हीन रूपि तथा गैर-कृषि प्राम्य अमिक, नगर में रहने वाले समयिक अमिक, ग्राम्य तथा नगर के छोटे-छोटे उद्योगो में कार्य करने वाले अमिक, तथा फुटकर कार्य करने वाले दस्तकार हत्यादि हैं। इन सब से वे अमिक जो आर्थिक तथा समाजिक हिंदकोण से हीन हे सबसे अधिक हानि उठाते हैं। सामाजिक हिंदकोण से पद्दिलित जातियाँ, आदिवासी तथा निकृष्ट दस्तकारी का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं"।

पाश्चात्य देशों मे बेरोजगारी एक ग्रस्थायी समस्या के रूप में होती है श्रोर सरकार तथा मिल मालिकों द्वारा ठीक समय पर कार्यवाई कर देने से उसके हल हो जाने की श्राशा रहती है परन्तु पाश्चात्य देशों में प्रयुक्त उपायों द्वारा भारत की समस्या का हल नहीं किया जा सकता। भारत में इस समस्या को दीर्घ कालीन दृष्टिकोण से हल करने के लिए यह श्रावश्यक होगा कि कृषि की भूमि का चेत्रफल बढ़ाने के साथ ही जनता को सुनियोजित करने श्रौर उस पर नियन्त्रण रखने, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने तथा श्रीद्योगिक सम्भावनाश्रों को विकसित

करने की आवश्यकता है। किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रतिवर्ष १३ प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली जन सख्या को व्यवसाय दे सकेगी जब कि व्यवसाय के साधनों में भी इसी गित से वृद्धि नहीं होती। चूँ कि प्रवास के द्वारा जन सख्या को समस्या को सुलक्ताया नहीं जा सकता है इसिलए मभी को व्यवसाय का न्याय सगत अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि पर और औद्योगिक साधनों पर जन सख्या के दबाव को कम करने के लिए जनसख्या से वृद्धि को रोका जाए। परन्तु इस व्यवस्था वो लागू करने में अधिक समय लगेगा और वेरोजगारी की समस्या को इतने समय तक बिना इल किए छोड़ देना समय नहीं है।

प्रथम पचवर्षीय योजना ने कुछ नये व्यवसाय के श्रवसर प्रदान किये थे। परन्तु योजना के तीसरे वर्ष से निरन्तर वेकारी के बढ़ते रहने के कारण आयोग को यह स्पष्ट हो गया कि देश के श्रोद्योगिक श्रीर श्रार्थिक विकास द्वारा इस समस्या वे सुलमाने के उपाय को सर्व-प्रधानता देनी श्रावश्यक है। इसी हिष्टकोण से प्रथम योजना पर व्यय की जाने वाली धन राशि श्रवद्वार १६५३ मे १८० करोड रुपया बढ़ा दी गई जिससे कि नवीन विशेष योजनाओं के लिए, जो कि व्यवसाय के श्रवसरों की वृद्धि करेंगी श्रीर बढती हुई वेकारी रोकेगी, पर्यात वित्त प्राप्त हो सके। इसके ग्रांतिरिक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम को १९५३-५४ के गत निर्णय के अनुसार अन्त कर देने के स्थान पर पूर्ण योजना काल तक चालू रखने का भी निर्णय किया गया। बेकारी की समस्या को इल करने के पुनपरी ज्ञित कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि (१) राज्य-वित्त निगम स्थापित किये जॉय, (२) केन्द्र से राज्यों को देश की दरिद्रता कम करने के लिए नई योजनायों के चालू करने के लिए विचीय सहायता दी नाय, (३) सहकों के निर्माण के लिए तथा छोटी-छोटी शक्ति उत्पादन की योजनाश्चों को कार्यान्वित करने के लिये अनुदान दिये जाँय ख्रीर (४) द्रौद्योगिक शिद्धा की सुविधायों का विस्तार किया जाता। पर जैसा भय था उसके अनुसार वह समस्या सुलक्ताने का याशिक प्रयत्न यसकल रहा। यामो श्रीर नगरा दोनीं स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों की सख्या जो श्राशिक व्यवसाय प्राप्त या वेरोजगार है निरन्तर वढती जा रही है। यह श्राशा की जाती है कि इस समस्या को वास्तविक रूप से सलमाने का प्रयत्न किया नायगा निसमें देश के ब्रीहोगिक विकास पर ग्रिधक महत्व टिया जायगा श्रीर साथ ही साथ जन सख्या की वृद्धि पर कुछ. नियत्रण भी रक्ला नायगा। यही उपाय द्वितीय योजना का मुलाघार है।

यदि भारत के कारखानो द्वारा निर्मित वस्तु के उत्पादन श्रीर विकय मे

वृद्धि हो तो श्रीवोगिक वेरोजगारी को कम किया जा सकता है । यह तभी सम्मव है जब प्रति हकाई उत्पादन ज्यय कम किया जाए । बहुत से उद्योगों में पारिश्रमिक उत्पादन ज्यय का एक महत्वपूर्ण ग्रग है । गत १० वर्षों में भारत के श्रमिकों के पारिश्रमिक में पूर्व स्तर से ३१ से ४० गुना श्रिविक वृद्धि हुई है परन्तु इस वृद्धि के खाय ही श्रमिक की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है । इसका स्वामाविक परिगाम यह हुशा कि कुछ कारखाने बन्द कर देने पढ़े जिससे अमिकों में वेरोजगारी फेली । यह स्थिति बहुत समय पूर्व ही श्रा गई होती परन्तु युद्ध के समय वस्तुयों का श्रमाव हो गया था श्रीर वह श्रमाव युद्ध समाप्त हो जाने के परचात भी रहा । वस्तुश्रों का उत्पादन ज्यय श्रधिक होते हुए श्रीर भावों का स्तर श्रधिक रहते हुए भी श्रपने समान का विक्रय कर सकने में उद्योग सफल रहे । परन्तु श्रव उपभोक्ता इस स्थिति का श्रागे निर्वाह कर सकने में ग्रसमर्थ हैं । इसिलए वेरोजगारी को कम करने के लिए या तो भारत के श्रमिकों को कम पारिश्रमिक लेने के लिए परन्तु रहना होगा या उन्हें कार्य ग्रधिक करना पड़िगा ।

इसके साथ ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाने से, विभिन्न सरकारी नियन्त्रणों ख्रौर निजी उद्याग में अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देने से भारतीय उद्योगों के उत्यादन व्यय में वृद्धि हो गई है। भारत के ख्रीद्योगिक चेन्न में लग-भग निजी उद्योगों का ही नोल बाला है। इसलिए ख्रीदिक उत्पादन करने के लिए ख्रीर उद्योगों में व्यवसाय की सभावना में वृद्धि करने के लिए निजी उद्योग चेन्न को सभी संभव सुविधाएं और उसके मार्ग में सरकारी प्रतिबन्धों द्वारा बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि सरकार ख्रपनी कर, अम तथा उद्याग सम्बन्धों नीतियों में ऐसा परिवर्तन करे जिससे उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए उद्योगों को प्रीत्साहन मिल सके तो उद्योग चेन्न में बेरोजगारी बहुत ख्रशों में कम की जा सकती है।

यह सुक्ताव दिया गया है कि भारतीय उद्योग चेत्र में युक्तिकरण की योजनाओं को लागू करने की अनुमति न दी जाय वयों कि इससे उद्योग चेत्र में वेरोजगारी मेवृद्धि होती है। यदि यह सुक्ताव मान लिया गया तो ओद्योगिक चेत्र में वेरोजगारी घटने की अपेद्धा और अधिक बढेगी। जब बाजार में पृति माँग से कम हैं तो इस बात का विशेष महत्व नहीं है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु की मित इकाई का उत्पादन व्यय कितना है। परन्तु चूं कि अब खरीबार अपनी व्यय शक्ति के अनुकूल कय करना चाहता है जिसके कारण बाजार की स्थित उसी हाथ में है, उद्योगों की परस्पर प्रतियोगिता शक्ति विशेष महत्व की बात हो हो गई है। यदि किसी कारखाने का उत्पादन व्यय भारत या विदेश में अपनी

प्रतिह्नी कारताने के उत्पादन व्यय मे अिक है तो वह कारताना अवस्य नष्ट हो नायमा युक्तिकरण उत्पादन वाय को कम करने का एक उपाय है। पि युक्तिकरण की योजनाओं को लागू किया नायमा तो उसमें कुछ वेरोजगारी अवस्य कैलेगी परना यदि युक्तिकरण योजनाओं को लागू ही न किया गया तो यह सम्भव हो सक्ता है कि कारताना सदे के लिए बन्द कर देना पढ़े और पूर्व की अपेना कहीं अधिक सख्या में व्यक्तियों को वेरोजगारी का सामना करना पड़े।

मुख्य व्यक्तियों का मत है कि भारत सरकार ने जून १६४४ में जो योजना प्रमातित की यो त्रोर जो त्राप्त तक वैकल्पिक रही है उसे त्रानिवार्य कर देना चाहिए। इस योजना के श्रमुक्तार वरोजनार व्यक्ति को त्राप्त वेरोजनारी मास के पूर्वार्द्ध में पाल्शिमक की साधारण दर का ७५ प्रतिशत मिलेगा त्रीर उत्तरार्ध में ५० प्रतिशत। इस योजना में पहले ही मान लिया गत्रा है कि भारतीय उत्रोग दम श्रातिरिक्त परिश्लिमक के घन भार वहन कर सकने में समर्थ हैं, परतु वास्त्रविक स्थिति इसके निपरीत है। भारतीय उद्याग को जितना लाम होता था उसकी मात्रा घट गई है त्रोर यदि उत्योग पर श्राधक भार पढ़ा तो वह बदन कर सकने में असमय सिंद होगा। भारत के श्रानेक कारणाने पहले ही बन्द हो चुके हैं। यदि यह योजना श्रानिवार्य की गई तो कुछ त्रोर कारखाने भी बन्द हो जायेंगे।

'प्रथम योजना काल के श्रनुभय से यह श्राप्तश्यक हो गया है कि वेकारी को समस्या पर केपल सामृहिक रूप में ही नहीं वरन् श्रामीण त्रीर नागरिक च्रेनों के द्रष्टिकोण से भी निचार करना चाहिये। इस समस्या के विस्तार का, जा कि ग्रागामी कुछ वर्षों में होगा, ठीक-ठीक ग्रनुमान करने के लिये यह श्रावश्यक है कि देश के विभिन्न भागों के श्रामीण श्रीर नागरिक च्रेनों में इसकी वास्तिनिकता को समक्त लिया जाय। यह भी श्रावश्यक है कि शिच्चित वर्ष की वेकारी को श्रन्य लोगों की वेकारी से श्रलग कर लिया जाय?'।

"प्रथम योजना के आकड़ों के परी चुण से यह जात होता है कि आघी
योजना कार्यान्वित होने पर वेकारी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। प्रथम योजना
काल मे रिजिस्टर किये हुये वेरोजगार लोंगों भी सख्या निरन्तर बढ़ती रही यह
मार्च ८६५१ में ३३० लाख के तथा दिसम्बर १६५३ में बढ़कर ५२२ लाख
हो गई और १६५६ म मार्च म ७.०५ लाख हो गई। योजना आयोग की सिकारिश के अनुमार नेशनल सैम्पिल सर्वे ने जो प्रारमिक परीक्षण नगरवासियों में
वेरोजगारों का किया या उसके परिणामों के हिस्टिनी सु से यदि इन आंकड़ां को

देखा जाय तो इनसे वि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पहता है। इस सर्वे के अमुसार नागरिकों में वेरोजगारा जी (१६५४) सख्या २२ ४ लाख आँकी गई थी। इस सर्वे ने वेकार लोगों की सख्या आर जिनका नाम रिक्टर किया जा चुका या उनकी सख्या के बीच अनुपातिक मम्बन्ध मी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सर्वे का अनुमान था कि लगभग २५% वेरोजगार व्यक्ति एक्सचेन्ज के दपतर में अपना रिजस्टर करवाने हैं। इस आधार पर नगरवासियों में बेरोजगारी की सख्या वर्तमान काल में २८ लाख के लगभग आती है। यह अनुमान सामान्यंत देश के विभिन्न भागों के नगर्रा में किये गये परोज्ञणों की रिपोर्टों के समान है। समियक वेकारी, को जो कि विकासमान आर्थिक व्यवस्था में अवश्यमभावी है, खूट देते हुये हम यह कह सकते हैं कि नगरवासियों में वेकार लोगों की सख्या २५ लाख के लगभग अनुमान की जाती है। इस सख्या में नगर के अमिकों की सख्या चाहिये। यह अनुमान किया जाता है कि आगामी ५ वपा में लगमग ३८ लाए व्यक्ति इस कारण वेकारा में जोड़ दिये जायगे।

श्रागामी ५ वर्षों मे श्रिमको की गणना मे वृद्धि श्राने वाले नवागन्तुकों की सख्या १ करोह श्रनमान की गई है। इस सख्या में से नागरिक श्रिमकों में नवागन्तुकों को श्रनमानित ३८ लाख सख्या घटा कर १६५६-६१ के मध्य ग्राम्य श्रिमकों की गणना में वृद्धि करने वाले नवागन्तुकों की सख्या ६२ लाख के लगमग श्रावेगी। निम्न तालिका यह बतलाती है कि द्वितीय योजना काल में यदि वेकारी की समस्या की समाप्त करना है तो कितने व्यवसायों के श्रवसर प्रदान करने पहुँचे .—

	(१० लाख में सस्थार्ये)		
	नगरों के चेत्र में	ग्रामी के चेत्र में	योग
श्रमिकों में नवागन्द्वकों के लिये वर्त्तमान श्रमिकों मे	३'द	६•२	₹•'٥
वेरीजगार व्यक्तियों के लिये	<b>ર</b> 'પ્	₹'⊏	प्•३
योग	६६	6.0	१५ ३

याद इस प्रकार रोजगार के अवसरों को पैदा करना सम्भव भी हो सके तो भी आशिक रोजगार की समस्या को जो वेकारी की समस्या की ही तरह महत्व शाली है सुलुक्ताया नहीं जा सकता। द्वितीय योजना का ध्यान प्रधानतः वेरोजगारी श्रोर ग्रांशिक वेरोजगारी की समस्या पर है। इसलिये द्वितीय योजना में एक श्रोर वड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले समुक्त पूँजी वाले उपक्रमों के विकास के प्रति श्रीर दूसरी श्रोर मान्य तथा छोटे उद्योगों के विकास के प्रति इस श्रांशा से प्रधानता दी गई है कि ये किसी सीमा तक वेकारी की समस्या को मुलमा सकेंगे। सरकारी चेत्र में दुल व्यय लगभग ४८०० करोड़ रुपये का श्रामान किया गया है, जिसमें में केवल ३८०० करोड़ रुपये विनयोग दिसाने हैं। इसके श्रांतिरक्त व्यक्तिगत चेत्र में विनयोग की मात्रा २४०० करोड़ रुपये श्रामान की गई है। राज्यों एय वेन्द्रीय मन्नालयों द्वारा पूरित श्रामहों तथा व्यक्तिगत चेत्र के लिए उत्पादन शक्ति में वृद्धि सम्बन्धी मान्यतात्रों को विचाराधीन रसते हुए जो ध्येय निश्चित किए गए हैं उनके श्राधार पर द्वितीय योजना द्वारा प्रदत्त रोज़ी के ग्रांतिरक्त श्रवसरों मा श्रामान लगाया जा सकता है। निम्न तालिका में इन परिगामों का निष्कर्ष दिया गया है।

(१० लास न	ही सख्या में)			
अनुमानित श्रविरिक्त रोजी (वृत्ति) किृषि को छोड़ कर				
१. निर्माण	२ १∙			
२ विचाई तथा विद्युत योजनाऍ •	*0¥			
३ रेलवे	•રપ્			
४ भ्रन्य यातायात भ्रीर सचार	' <b>१</b> ८			
५ उद्योग तथा खनिज	৬५			
६ कुटीर तथा छोटे उद्योग	¥Ч			
७ वन, मछली पकड़ना, राष्ट्रीय विकास				
योजना, तथा सम्मन्धित श्रन्य योजनाएँ	8\$			
८ रिज्ञा	3 8			
६. स्वास्थ्य	<b>•</b> १२			
२० श्रन्य सामाजिक सेवार	१४			
११ सरकारी नौकरियाँ	<b>.</b> 83			
योग (१ से ११ तक)	५.५०			
१२ "श्रन्य" जिनमें वाणिच्य श्रीर व्यापार				
जो कुल का ५२% है सम्मिलित हैं	२.७०			
कुल योग	७६०			

🚁 🖟 द्वितीय पचवर्षीय योजना द्वारा कितने नवीन व्यवसायों को श्रवसर प्रदान किया जा सकेगा उसका ठीक-ठीक श्रनुमान लगाना श्रभी तक सम्भव नहीं हो सका है। "ग्रायोग द्वारा परीचा करने से यह शात होता है कि प्रथम योजना काल में जो प्रत्यज्ञ व्यवसाय के श्रवसर सरकारी श्रीर व्यक्तिगत चेत्र में प्रदान किये गये उनकी सख्या ४५ लाख के लगभग थी। इस अनुमान में वाखिल्य श्रीर व्यापार श्रादि के चेत्र के श्रन्तर्गत श्रातिरिक्त व्यवसाय सम्मिलित नहीं किये गये हैं। विकास सम्बन्धी भयत्न को द्विगुणित करके जा द्वितीय योजना में अतिरिक्त न्यवसाय के अवसरों के प्रदान करने का ध्येय बनाया गया है वह कुछ विशेष श्रिधिक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि द्वितीय योजना में विकास सम्बन्धी व्यय प्रथम योजना काल के व्यय से कोई विशेष श्रिषक नहीं हो पायेगा, क्योंकि सन्कारी चेत्र में योजना का ज्यय १६५५-५६ में ६०० से ६२० करोड़ रुपयों के लगमग निश्चित किया गया है, जब कि विकास योजनाश्रों पर १९५०-५१ में २२४ करोड रुपया ही ब्यय किया गया था। प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में सरकारी चेत्र में व्यय की मात्रा १६५०-५१ के व्यय की मात्रा से लगभग ४०० करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है। यह भी सम्भव है कि प्रथम योजना के य्रन्तिम वर्ष की तुलना में विकास योजनाश्चों पर व्यय में वृद्धि द्वितीय योजना के श्रन्तिम वर्ष में लगभग ६०० करोड़ रुपया हा। इसके श्रतिरिक्त द्वितीय योजना में विनियोग के ढग को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारी उद्योगों श्रीर यातायात पर, जो कि श्रल्पकाल में बहुत कम व्यवसाय के श्रवसर प्रदान कर सकते हैं, बहुत श्रिषक धन न्यय किया जाने वाला है।" इसका श्रर्थ यह है कि परम सीमाग्य होते हुये भी ८० लाख से आधिक व्यक्तियों के लिये (कृषि को छोड़ कर) द्वितीय योजना के उपायों द्वारा व्यासाय प्रदान करना सम्भव न हो सकेगा जब कि वेकारी की समस्या को पूर्ण रूपेण इल करने के लिये १५२५ लाख व्यक्तियों के लिये व्यवसाय प्रदान करना श्रावश्यक है।

मई १९५० में योजना ह्रायोग द्वारा जारी की गई पुस्तिका 'द्वितीय पच-वर्षीय योजना की सम्भागनायें मूल्यांकन' के श्रनुसार "पहले दो वर्षों में कृषि के बाहर रोजी के २० लाख श्रवसर प्रदान किये गये। लगमग १० लाख श्रम-शक्ति १९५८-५६ में रोजी पा सकेगी। यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना में ७९ लाख व्यक्तियों के कृषि के बाहर तथा १६ लाख व्यक्तियों के कृषि के श्रन्दर रोजी पाने की सम्भावना है। विभिन्न योजनाश्रों की लागत में वृद्धि हो जाने के फल-स्वरूप कृषि के बाहर सरकारी चेत्र में ४८०० करोड़ र० के व्यय के श्रनुमान पर लगमग ७० लाख व्यक्तियों को रोजी मिल सकेगी। यदि यह व्यय ४५०० करोड़ र० हो तो रोजी पाने वालों की सख्या ६५ लाख के लगभग होगी। यह श्रानुमान बिल्कुल सही नहीं है किन्तु इनसे इतना तो पता चलता ही है कि हमारी श्रार्थ व्यवस्था में श्रम-शक्ति की वार्षिक वृद्धि के श्रानुरूप विनियोग नहीं हो रहा है।"

### रोजगार के दफ्तरों का कार्य

मारत में रोजगार के दफ्तरों का एक जाल सा विछा हुआ है जो वेरोजगार व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार करते हैं और उन रिक्त स्थानों के लिये उन्हें मेज देते हैं जो सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विज्ञाप्ति किये जाते हैं। इसमें सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तर वेरोजगारी कम करने में सहायक हैं, क्योंकि वे वेरोजगार व्यक्तियों का सम्बन्ध व्यवसाय प्रदान करने वालों से स्थापित कर देते हैं परन्तु ये रोजगार के दफ्तर ही मनुष्य की अप्रयुक्त शक्ति की समस्या को सुलक्तान के सफल उपाय तो नहीं हैं। इनका कार्य चित्र प्रचलित आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अन्तर्गत ही सुविधार्य प्रदान करना है। ये दफ्तर नवीन व्यवसायों को तो उत्यक्त कर नहीं सकते। वे तो केवल वेरोजगार व्यक्तियों को जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं और करना चाहते हैं निर्देश मात्र ही दे सकते हैं। वे उन व्यवसावों के लिये जो निचापित हैं और जिनके लिये स्थान रिक्त हैं उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं हुढ सकते।

यह सब होते हुए भी वेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त स्थानों के लिये निर्देश देना भी वेरोजगारी की समस्या के मुलक्ताने में एक बड़ी सहायता है। इसके अितिरक्त यद्यांप रोजगार के दफ्तर में नाम रिजस्टर कराये हुए वेरोजगार व्यक्तियों से हमें वेकारी की समस्या का पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होता, पर उसते नि.सदेह वेरोजगारी की वदलती हुई प्रवृत्ति ज्ञात होती है। यह बड़ी चिन्ता की विषय है कि रोजगार के दफ्तरों में राजस्टर किये हुये व्यक्तियों की सख्या १६५६ में केवल १,५८,५०३ यी। १६५७ में यह वढ़ र १,२२,०६६ हो गई। १६५६ में केवल १,६८,५०३ के जगह दी गई। १६५७ में यह सख्या बढ़ कर १,६२,६३१ हो गई।

रोजगार के दफ्तरों को आधक प्रभाव शाली बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उनका पुर्नसगठन किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रशिक्तण और व्यवसाय व्यवस्था समिति ने जिसे पाय बी० शिवा राव कमेटी कहते हैं भारत सरकार, की अप्रैल १६५४ में दी हुई रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की:—

(१) रोनगार के दफ्तरों की व्यवस्था का विस्तृत करके उसे राष्ट्रीय सेवा का एक स्थायी व श्रिषक श्रिषकार प्राप्त विमाग बना देना चाहिये,

(२) प्रशासन विकेन्द्रित होना चाहिये। इसका यह अर्थ है कि नीति

चाहे सरकार द्वारा क्यों न निर्धारित की जाएँ पर उनका नित्य प्रति का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होना चाहिये,

- (३) केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार के दफ्तरों को जो अनुदान सहायतार्थ दिया जाता है वह चालू रहना चाहिये, पर उसकी मात्रा को चेत्रीय प्रधान कार्यालयो तथा राज्यों के रोजगार के दफ्तरों के कुल व्यय के ६०% तक सीमित कर देना चाहिये, और १६५३-५४ के बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई हो अथवा १६५२-५३ में जो वास्तविक व्यय किया गया हो, इन दोनों राशियों में से जो राज्य की सरकार के द्षांटकोगा से उसके लिये अधिक लाभकारी हो, उसे अनुदान की अधिकतम मात्रा नियत कर देनी चाहिये,
- (४) रोजगार के दफ्तरों के कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिये श्रीर उनके कार्यों में निम्न कार्यों को भी धम्मिलित करना चाहिये (क) मालिकों श्रोर कार्य करने वाले वर्गों के साथ बहुत श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये; उनको चाहिये कि व्यवसाय चाहने वालों के श्रावेदनों को स्वीकार करें श्रीर तब तक उनसे श्रपना सम्बन्ध रक्खें जब तक कि उस पर नियुक्ति न हो जाय, (ख) नाम रिजस्टर कराये हुये व्यक्तियों का निरीक्षण तथा सहायता करें श्रीर उनकी श्रावश्यक परीक्षा लें, (ग) रिजस्टर कराये हुए व्यक्तियों की फाहलें निर्माण करें, श्रीर योग्य श्रावेदकों के प्रार्थना पत्रों को कार्य देने वाले व्यक्तियों के पास मेर्जे श्रीर उनकी निर्मुक्त का लेखा निर्माण करें श्रीर सुरिक्त रक्खें, (व) व्यवसाय के श्रावस्य का तथा लगावें श्रीर व्यक्तियों तक इसकी सूचना पहुँचाने की सुविधायें प्रदान करें ताकि वेरोजगारों को व्यवसाय प्राप्त हो सके श्रीर मालिकों को उपयुक्त कार्य करने वाले इन दफ्तगे को चाहिये कि वे व्यवसाय सम्बन्ध श्रीक कार्य करने वाले इन दफ्तगे को चाहिये कि वे व्यवसाय सम्बन्ध में श्रपना मत भी श्रकाशित करें श्रीर कीन सा कार्य कब तक चलेगा इसके सम्बन्ध में श्रपना मत भी श्रकाशित करें.
- (५) अदस्र श्रमिकों को न तो रिजस्टर करने की आवश्यकता है और न उनके आवेटनो की। जो व्यक्ति ऐसे श्रमिकों की सेवाये चाहते हैं उनको घोषणा द्वारा या किसी अन्य रूप से सूचित कर देना ही पर्याप्त होगा। इसके पश्चात जो कार्य करना चाहते हैं उन्हें सीचे मालिकों के पास पहुँच जाना चाहिये। ऐसे व्यक्तिया के सम्बन्ध में जो प्रतिदिन रोजगार के दफ्तर पर इकटा होते हैं तथा घोषणा द्वारा जिन रिक्त स्थानी की स्वना दी जाती है उनके आके तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, और

(६) सरकारी तथा अर्घ सरकारी सस्याओं द्वारा नियुक्त किये जाने के

सम्बन्ध में ये दफ्तर जो सिफारिशें करें उनके परिणाम की कुछ दिन तक जाँच करने के पश्चात् व्यक्तिगत चेत्र में भी इन दफ्तरों की सिफारिशो पर नियुक्त करना त्रनिवार्य कर दें।

सरकार ने बी॰ शिवाराय कमेटी के ग्रामिस्तावों को ग्राशिक रूप में स्वीकार कर लिया है त्र्योर रोजगार के टफ्तरों को क्रिधिक प्रभावशाली बनाने के लिये निम्न उपायों को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने का निर्णय किया है. (१) रोजगार दिलाने के विभाग को १२५ नये रोजगार के दफ्तरों की स्थापना करके विस्तृत करना ताकि अन्य बहुत से व्यवसाय के केन्द्र इनके अतर्गत आ सर्कें; (२) ब्यवसाय मी सूचनाओं के एकत्रित करने तथा लोगों तक पहुँचाने की योजना निर्माण करना, (३) चुने हुये व्यवसाय के दफ्तरों मे नवयुवक रोजगार सेवा सस्था की स्थापना करना तथा वयस्को के लिये व्यवसाय की सलाह देना तथा 'केरियर पेम्फलेट' श्राटि उपयुक्त तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करना, (४) रोजगार सम्बन्धी विश्लेषण तया खोज के कार्य-क्रम बनाना ताकि विभिन्न व्यवसायों के नाम तथा परिमापा मान्य स्तर की वनाई जा सके, ऋौर (५) रोजगार के दफ्तरों मे व्यवसायिक परीच्चा सम्बन्धी कार्यक्रम बनाना । इन उपायों से भारत की व्यवसाय दिलाने वाली सेवात्रों की कार्य कुशलता श्रधिक बढ जायगी परन्तु यह तमी सम्मव है जब कि रोजगार के दफ्तर राष्ट्रीय सेवा विभाग के रूप मे विकित्व हो जाँय ग्रौर तमी उनके लिये वेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसाय दूढना ग्रौर दिलाना मी सम्मव हो सकेगा। कमेटी ने प्रशासन को विवेन्द्रित करने नी िकारिश की है क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकारों को भी इस सस्या के प्रति चहानुभृति उत्पन्न हो जायगी श्रीर वेरोजगार के दफ्तरों का राज्य की सरकार तया राज्य के त्रन्तर्गत व्यक्तिगत मालिकों से सम्बन्ध स्थापित करने में भी यह सहायक भी सिद्ध होगी । विकेन्द्रियकरण से प्रान्तीयता के बढने तथा श्रन्तरप्रान्तीय जनसङ्य के आवागमन में बाधा पड़ने का मत्र निर्मूल है क्योंकि इन रोजगार के दफ्तरों की नीति तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्घारित होगी। इन सस्याय्रों के कार्यों के प्रसार के सम्बन्ध में जो सुक्ताव दिये गये हैं उनसे मालिकों तथा रोजगार के दफ्तरों के बीच श्रीर वेरीजगार व्यक्तियों श्रीर रोजगार के टफ्तरों के वीच श्रव्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो सकेगा। श्रदत्त श्रमिकों के सम्बन्ध में उनकी रिनस्ट्री न करने की सलाह देने में ऐसा लगता है कि कमेटी इस कार्य के विस्तार तथा सम्भावित श्रधिक व्यय से विशेष प्रभावित हो गई थी। पर ऐसा करने से इसमें सदेह नहीं कि रोजगार के दफ्तरों की वेरोजगारी की समस्या सुलक्काने के सम्बन्ध में उपयोगिता श्रनश्य कम हो जायगी।

### श्रन्याय २६

## श्रौद्योगिक गृह निर्माण

श्रोत्रोगिक यह निर्माण की समस्या श्रामका को कम किराये पर उपयुक्त श्रावास प्रदान करने की है। द्वितीय महायुद के पूर्व भी बढ़े-बड़े करगे श्रीर नगरों मे, विशेष कर द्रोद्योगिक नेन्ट्रों मे, रहने के लिये घरों का श्रभाव था। श्रमिक लाग चील तथा वस्तियों में बडे श्रम्वास्थ्य वातावरण में रहते हैं। गत कुछ वर्षों से जन सख्या में वृद्धि होने, पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने तथा व्यक्तिगत लोगो द्वारा कम सरूपा में नये घरो के निर्माण के कारण दशा ह्योर भी ह्यधिक शोचनीय हो गई है। १६३१, १६४१ छोर १६५१ की जनगणना के छनुसार जनसख्या मे कमण ११, १४३ श्रीर १३४ प्रतिशत दक्षि हुई परन्तु नागरिक चेत्रों में यह वृद्धि क्रमशर् २१, ३२ श्रीर ५४ प्रांतरात हुई। पाकिस्तान से लगमग प्त्र लाख शरणार्थिया के श्रा जान से नागरिक होत्रों मे जनसख्या का दवाव वढा जिसके प्रभाव से रहने की व्यवस्था ज़ीर जटिल हो गई। शरणार्थिया ने गाँव की श्रपेता वहे करनां श्रीर नगरां मे ही रहना अधिक पसन्द किया। इसमे नगरों श्रोर कस्त्रो में रहने के लिए घरों की माँग बढ़ी परन्तु पूर्ति न हो सकने से यह श्रमाव की खाई चोड़ी होती गई। मॉग के श्रनुसार घरों की पूर्ति न हो सकने का कारण यह है कि इमारत बनाने के सामान का श्रधिक मूल्य होने के कारण श्रीर बाजार में सामान के श्रभाव के फलस्वरूप नई इमारती को पर्याप्त मात्रा मे नहीं बनाया जा सका। इसके साथ ही मकानों को किराये पर देने श्रीर किराये की दरों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाने से भी इम दिशा में प्रतिकृल प्रभाव पड़ा श्रीर इसी कारण बढ़ती जनसख्या के साथ मकानो की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

गृह निर्माण की प्रवृत्ति—वर्तमान में मुख्य गृह निर्माण एजेन्सियाँ निम्निलिखत हैं:—(१) सरकारी अथवा अन्य एजेन्सियाँ, (२) उद्योगपित, (३) सहकारी सिमितियाँ, (४) अपने उपयोग के लिए मकान बनाने वाले व्यक्ति, और (५) निजी उद्योग। निजी उद्योग के मालिकों की अरे अपने उपयोग के लिए गृहिन्मीण कराने वाले व्यक्तियों की अब गृहिन्मीण की और गिति मन्द हो गई है। गत कुछ वर्षों में इस दिशा की और सरकारी तथा अन्य मिली-जुली एजेन्सियों, उद्योगपितयों और सहकारी समितियों की गिति में विशेष रूप से वृद्धि हुई है।

प्रथम योजना काल मे ७६,६७६ किराये के वरों के निर्माण के कार्यक्रम

को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से १६,१६५ वम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैटराबाद में, ५,१८१ मध्यप्रदेश में, ३,४४४ मध्यभारत में तथा इसमें कम सख्या में श्रन्य राज्यों में बनवाये जाने वाले थे। जितने किराये के घरों का निर्माण प्रथम पचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पूर्व किया जा चुका था उनकी सख्या ४०,००० के लगभग थी। जितने किराये के घरों के निर्माण की श्रनुमति दी गई है उनमें से ६८,२०० श्रयना ८५% के लगभग राज्य सरकारी द्वारा, १०,१६१ स्रथना १३% अभिकों के निजी उत्रोग द्वारा स्त्रीर १,३१८ या १.५% उद्योगों में काम नरने वालों की सहकारी समितियों द्वारा बनवाये जा रहे हैं। जन यह योजना निर्माण की गई थी उस समय सहकारी समितियों छौर मालिकों के सहयोग की ग्रधिक आशा की यी। योजना के इस पद्म पर विचार किया ना रहा है श्रीर ऐसे उपाय सोचे जा रहे हैं जिनसे कि मालिकों श्रीर कारखानों के अमिकों की सहकारी समितियों का अधिक सहयोग प्राप्त हो। इनके श्रतिरिक्त पुनवास, रज्ञा, रेलवे, लोहा श्रीर इस्पात, उत्पादन, यचना, निर्माग, यह निर्माण तथा पूरि श्रादि मत्रालयों द्वारा भी गृह निर्माण के समुचित कायक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें श्रीर कुछ स्थानीय श्रधिकारियों के श्रपने निजी यह निर्माण के कार्यक्रम भी चालू हैं। यह श्रनुमान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पुनर्वास मन्त्रालय ने नगरों में ३,२३,००० किराये के घर वनवाये श्रीर राव्य सरकारों तथा केन्द्रीय मनत्रालयों ने, निर्माण, गृहनिर्माण तथा पूर्ति के मन्त्रालयों को छोड़ कर लगभग ३००,००० गृहीं का निर्माण करवाया। श्चन्य गृहनिर्माण की योजनाश्चों को, जिनका कपर वर्णन किया जा चुका है, सम्मिलित करते हुए सरकारी विभागों ने प्रथम योजना काल में लगमग ७,४२,००० यहों का निर्माण करवाया । व्यक्तिगत लोगों ने कितने गृहों का निर्माण कराया उसकी सख्या नानना कठिन है। कर नौंच श्रायोग के इस सम्बन्ध में परीज्ञा करने से ज्ञात हुआ कि नगरों में गृहनिर्माण के सम्बन्ध में कुल विनियोग १६५३-५४ में लगमग १२५ करोड़ रुपया या। यदि इसे हम पाँच वर्षों की अविध का श्रीसत मान लें श्रीर एक घर के बनवाने में श्रीसत व्यय १०,००० र० के लगमग मान लें तो यह शात होगा कि प्रथम योजना काल में लगभग ६००,००० गृहों का निर्माण ल्यक्तिगत चेत्र में हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना त्वाल में लगभग १३ लाख घर नगरों में बनवाये गये।

प्रथम योजना काल में ग्रामों में भी रहने की स्थिति में सुधार के कुछ उपायों का प्रयोग किया गया है। सामुदायिक विकास योजना चेनों से ५८,००० ग्राम्य शीचालय, १६०० मील लम्बी नालियाँ श्लोर २०,००० कुँचे बनवाये गये हैं न्त्रोर लगभग ३४,००० कुँग्रां का जीखोंदार किया गया है ग्रोर राष्ट्रीय विकास चेन्ना में ८०,००० माम्य शीचालय, २७०० मील लम्बी नालियाँ, ३०,००० नये कुँये श्रोर ५१०० पुराने कुँश्रों का जीगोंद्वार किया गया है। राष्ट्रीय विकास तथा सामुदायिक विकास योजनाश्चों के होत्रों म लगभग **२६००० घरों** का निर्माण हुआ है श्रीर लगभग उतने ही पुराने घरों का जीखोंदार किया गया है। अनेकों राज्यों में प्रामों में ईट क भटटे स्थापित किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं पर सहकारी समितियों भी सहायता इस कार्य में ली जा रही है। उदाइरणार्थ उत्तर प्रदेश में १६५०-५१ में १६ सहकारी ईंट के भट्टें खोले गये थे, १६५४-५५ तक उनकी सख्या बढकर ७५२ हो गई श्रीर भट्टों के श्रास-पास के मानों में श्रिविकाधिक नये दग के पर्के मकान बनने जा रहे हैं। बहुत से राज्यों में इरिजनों के श्रावास की स्थिति को, विरोप मृमि न्नेत्रों को उनके लिये नियत करके तथा सहकारी यहनिर्माण समितियों की स्थापना द्वारा, सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के श्रन्तर्गत निर्माण, पूर्ति तथा गृहनिर्माण मन्त्रालय ने श्राम्य यहिनमांग श्रागार की स्थापना की है जिसका ध्येय इस होत्र की विभिन्न समस्यात्रां का श्रध्ययन करना श्रीर एहों के नये-नये श्राकारों, श्रिभन्यासों, निर्माण के दगों तथा स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग करने के उपायों की खोज करना है।

कठिनाइयाँ—- ग्राधिक मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं:

(१) ग्राम श्रीर नगर में भूमि, इस्पात, ईट, खिमेंट, लकड़ी की चीखट इत्यादि के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई। यह सभी चीजे मकान बनाने के लिए बहुत श्रावर्यक हैं। इन वस्तुश्रों के मूल्य श्रिषक होने पर भी गृह-निर्माण समय या परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसके लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। दूसरी श्रोर यदि श्रिषक ब्यय पर मकान बनाया जाय तो उसका किराया भी श्रिषक होना चाहिए परन्तु गृह निर्माण का कार्य तीन्न गति से करने का मुख्य उदेश्य यह है कि श्रामकों तथा श्रन्य निर्धन श्रोर मध्यम श्रेणी के लोगों को सस्ते किराये पर मकान दिये जा सकें। इसलिए समस्या यह है कि मकान बनाने के सामान का मूल्य घटाया जाय, महँगे सामान के स्थान पर सस्ते मूल्य का कोई दूसरा उपयुक्त सामान लगाया जाय श्रीर श्रमकों हत्यादि के लिए सुखदाई परन्तु कम ब्यय में मकान बनाने के लिए मकान के श्राकार-प्रकार श्रीर उसके ढाँचे इत्यादि के सम्बन्य में खोज कार्य किया जाय। परन्तु यदि गृह निर्माण के ब्यय में पर्याप्त कमी भी कर दी जाय तब भी। गृह निर्माण योजना को कार्यन्तित करने के

लिए रुपये की आवश्यकता होगी और जब तक पर्याप्त घन, जो कम से कम १०० करोड़ रुपया होगा, प्राप्त नहीं होता तब तक सभी आवश्यकताप्रस्त लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाजार में रुपये की तगी है और जनता के पास पर्याप्त घन नहीं है। इसलिए घर बनाने के इच्छुक लोगों को कम व्याज पर रुपया देने के लिये कुछ उपाय खोज निकालना अत्यन्त आवश्यक है।

(२) मजानों का किराया बढ़ाने पर राज्य सरकारों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। सरकार तथा अन्य एजेन्सी, उद्योगपित और सहकारी समितियाँ लाम की चिन्ता किये विना यह निर्माण कार्य में वृद्धि कर सकनी है। परन्तु किराये पर नियत्रण लग जाने से और नगरों तथा कस्बों में मजानो का एलौटमैन्ट करने की व्यवस्था से निजी उद्योगों के मालिक नये मजान बनवाने की और से लगभग निराश हो चुके हैं। कुछ राज्यों मे ऐसी व्यवस्था है कि एक निश्चित तिथि के पश्चात् बने नये मकानों पर यह नियन्त्रण लागू नहीं होते हैं इससे नये मजान बनवाने के कार्य को प्रोत्साहन मिला है।

१६५२ मे एशिया श्रीर सुदूर पूर्वी श्रार्थिक सम्मेलन का गृह निर्माण विषयक श्रिष्वेशन दिल्ली में हुश्रा था। इस सम्मेलन में सुक्ताव दिये गये थे कि (१) श्रादर्श योजनाएँ चालू की जॉय जिनमें इस्पात श्रीर इमारती लक्बी के स्थान पर बांस तथा श्रन्य लकिवों के उपयोग की जॉंच की जाय श्रीर (२) इसी प्रकार की श्रन्य योजनाश्रों द्वारा ईट इत्यादि बनाने के लिए उपयुक्त चिक्तनी मिट्टी की मी जॉंच की नाय। इस प्रकार की श्रादर्श योजनाश्रों के द्वारा इम श्रमिकों तथा श्रन्य लोगों के लिये सस्ते श्रीर सुबदाई मकानों का निर्माण करने के उपाय खोज सकते हैं।

सरकारी योजनाएँ—श्रौद्योगिक शाित प्रस्ताव में सुक्ताये गये गृह निर्माण कार्य कम के श्राधार पर भारत सरकार ने १६४६ में एक गृह निर्माण योजना तेयार की। इस पोजना में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारों तथा कर्मचािरयों इत्यादि के द्वारा बनाये जाने वाले मकानों में जितना रूपया लगेगा उसका हो तिहाई केन्द्रीय सरकार व्याज मुक्त श्रूण के रूप में देगी, परन्तु इसके लिये मािलकों को भी कुछ शतें माननी पहेंगी। इस योजना के श्रनुसार मािलक तथा राज्य सरकारों को एक तिहाई व्यय की स्वय व्यवस्था करनी पहती है। केन्द्रीय सरकार से उन्हें केवल इतना ही लाम प्राप्त है कि श्रावण्यक पूंजी का हु श्रश व्याजयुक्त श्रुण के रूप में प्राप्त हो जाता है।

परन्तु इस योजना के असमल हो जाने पर भारत सरकार ने यह अनुभव

किया कि यह निर्माण कार्य को प्रोत्छ। हन देने के लिये राज्य सरकारों ग्रीर कारखाने इत्यादि के मालिकों को इसके लिये नकद आयिक सहायता देनी पडेगी। इसी विचार से एक योजना निर्माण की गई श्रीर उसे पायः सभी राज्यों की सरकारों के पास विचारार्थ मेजा गया। इस योजना मे यह प्रस्ताव रखा गया था कि गृह निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों तथा निजी उद्योगपतियो को भूमि के मूल्य का अधिक से अधिक २० प्रतिशत केंद्रीय सरकार सहायता के रूप में देगी। परन्तु इसके लिए यह शर्ते लगाई गई कि (१) मकान वास्तव मे श्रिमको को किराये पर दिया जायगा, (२) किरायेटार से घर की कुल लागत का, जिसमें म्मि का मूल्य भी सम्मिलित है, केवल ढाई प्रतिशत ही वस्त किया जायगा परन्तु यह किराया श्रमिक की श्राय के १० प्रतिशत से श्रविक नहीं होना चाहिये. (३) घर वेन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशेष स्नाकार प्रकार के बनने चाहिएँ स्नीर (४) घर का निरीच्चण करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के निरीच्चको श्रोर यह-निर्माण बोर्ड को सभी श्रावश्यक सुविधार्ये दी जानी चाहिएँ। इस योजना का कार्यचेत्र सीमित था श्रीर राज्य सरकारो ने इस श्रीर विशेष व्यान नहीं दिया। इसलिये भारत सरकार ने १९५२ के अत मे एक अधिक व्यापक योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत यह ब्यवस्था की गई कि केन्द्रीय सरकार ग्रहनिर्माण कार्य को पोत्छान देने के लिये राज्य सरकारो श्लीर यहनिर्माण बोर्ड को कुल व्यय का, ५० पितशत तक सहायता के रूप में देगी। इसमें भूमि का मूल्य मी सम्मिलित किया 🦯 जायगा। शेष ५० प्रतिशत के लिये सरकार ४३ प्रतिशत व्याज पर ऋग देगी। जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध मे यह अयवस्था की गई कि गृह निर्माण के कुल व्यय का २५ प्रतिशत सरकार सहायता के रूप में देगी और साथ ही कुल निर्माण-न्यय का ३७ई प्रतिशत धन ४ है प्रतिशत वाषिक ब्याज पर ऋगु देगी जिसे १५ वर्ष के अन्दर चुकाया जा सकता है। उद्योग के मालिको को सरकार कुल लागत का २५ प्रतिशत श्राधिक सहायता के रूप में और कुल न्यय का ३७3 प्रतिशत तक ४३ प्रतिशत वाधिक व्याज की दर से ऋग्ण देगी। यह ऋग्ण १५ वर्ष के श्रन्दर चुकाना होगा। इन सब के सम्बन्ध ने ऋणा तथा अनुदान की मान्ना स्टेन्डर्ड लागत के आधार पर श्रनुगिष्ति मात्रा पर ही सीमित कर दी जायगी। बम्बई श्रीर कलकता के सम्बन्ध में १ कमरे वाले कई मजिले मकानों की स्टेन्डर्ड लागत ४५०० रुपया श्रीर श्रन्य स्थानों में २७०० रुपया आँकी गई है। दो कमरे वाले कई मिलले मकानो की बम्बई श्रीर कलकता में लागत ४५३० रुपया (जो कि श्रव बढाकर ५६३० रुपया

कर दी गई है) श्रोर श्रन्य स्थानों में ३४६० रुपया श्रॉकी गई है। एक मिलले मकानों के लिये स्टेन्डर्ड लागत का श्रनुमान कम धन राशि है।

इस पुर्नपरोज्ञित योजना की दो मुख्य विशेषतायें हैं (१) सहकारी समितियों को न्यय की ५०% तक ऋण रूप से सहायता मिल सकेगी जबिक मूल योजना के अन्तर्गत केवल ३७ है ही मिल सकती यी और १५ वर्षों में ऋण के सुकता करने के स्यान पर श्रव २५ वर्ष का समय भी मिल जायगा, और (२) स्टेन्डर्ड किराया विभिन्न प्रकार के मकानों के लिये वम्बई तथा कलकत्ता में १० रुपये में लगाकर ३० रुपया तक और अन्य नगरों और कस्वों में १० रुपये से लगाकर १६ रुपया तक नियत कर दिया गया है। इससे योजना अधिक पूर्ण बन गई है। यह आशा की जाती है कि एह निर्माण कार्य को इस योजना के अन्तर्गत अधिक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

त्रार्थिक सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना के श्रन्तर्गत, जो सितम्बर । १९५२ में लागू हुई, १९५७-५८ केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूर की गई घनराशि २५ ७६ करोड़ रु॰ थी जिसमें १३-२८ करोड़ रु॰ श्रृण के रूप में तथा १२-५१। करोड़ रु॰ श्रार्थिक सहायता के रूप में थे। इसके श्रन्तर्गत ११,२५० घर थे। । नवन्तर १९५७ तक पूर्ण हुये मकानों की सख्या ६६,७०० थी तथा शेष निर्माण के निमिन चरणों में थे।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक तथा अन्य गृह निर्माण् योजनाओं के लिये अधिक धन सहायता में देने का निश्चय किया गया है। प्रथम योजना में अद्भ करोड़ रुपयों की सहायता का प्रवन्य किया गया था परन्तु द्वितीय योजना में १२० करोड़ रुपयों की सहायता का निम्न तालिका के अनुसार प्रवन्य किया गया है —

सहायता प्राप्त श्रीयोगिक गृह निर्माण	४५ ३	करो <b>ड</b> ़	दपये
निम्न त्राय-वर्ग के लिये गृह निर्माण	80	,,	"
प्राम गृह निर्माण	१०	37	"
विस्तियों की सफाई श्रोर भगियों के लिये गृह निर्माण	२०	27	"
मन्य वर्ती अथय वर्ग के लिये गृह निर्माण	ą	77	57
रोपणोद्योग के लिये यह निर्माण	ર	"	"
योग	१२०	"	77

द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय की योजना अधिक विस्तृत है और अनेकों नये व्यय के शीर्ष उसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जो कि प्रथम योजना में नहीं ये और कार्य का व्यय निम्न है •—

जिनमें भगी भी सम्मिलित हैं— १ ४. मध्य वर्ती ब्राय वर्ग के लिये घर ५. रोपण उद्योग के श्रमिकों के लिये घर	ग्रहों की सख्या १२⊏,००० ६⊏,००० वेघर	२. निम्न श्राय वर्ग के लिये घर	₹. ₹.
	११०,०० <i>०</i> ५,०००	जिनमें भगी भी सम्मिलित हैं- ४. मध्य वर्ती आय वर्ग के लिये घ ५. रोपण उद्योग के श्रमिकों के हि ६. आमीण गृह निर्माण योजना	પ્ર

श्रन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा, राज्य सरकारो तथा स्थानीय श्रधिकारियों द्वारा तथा कोयले की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये गृह निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनवाये वरो के श्रितिरिक्त ७५३,००० गृहों का (जिनकी सख्या ८००,००० के लगमग द्वितीय योजना काल में श्रांकी गई है) निर्माण होगा। इस प्रकार द्वितीय योजना में कुल १६ लाख घरों के निर्माण का श्रनुमान है जबिक प्रथम योजना काल में केवल १३ लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।

Ĺ

द्वितीय योजना के पहले तीन वर्ष में ग्रह निर्माण के ऊपर किये जाने वाले कुल व्यय का श्रनुमान ४० करोह है। "श्राधिक सहायता प्राप्त श्रीयोंगिक ग्रह निर्माण योजना के श्रन्तर्गत १६५६-५६ हन तीन वर्षों में ४२,६०० हकाहयों के निर्माण की व्यवस्था है। निम्न श्राय वर्ग के श्रन्तर्गत २२,००० हकाहयों के निर्माण की तथा भगियों के ग्रह निर्माण के श्रन्तर्गत २२००० हकाहयों के निर्माण की व्यवस्था है। प्रामीण ग्रह निर्माण योजना १६५८-५६ में प्रमावपूर्ण ढग से लागू की जा रही है। चूं कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में काट-छाँट हो रही है श्रतएव ग्रहिनर्माण के लिये सशोधित राशि १०० करोड़ र० होगी जो प्रारम्भिक राशि से २० करोड़ र० कम है। ४५०० करोड़ र० के ऊल व्यय में ग्रह निर्माण पर किया जाने वाला व्यय ८४ करोड़ र० है। इसमें ६४ करोड़ र० राज्यों के लिये है तथा रि० करोड़ र० केन्द्र के लिये है।"

## श्रद्याय ३० श्रम की कार्यच्मता

यह लाक प्रसिद्ध है कि भारतीय श्रमिक निपुण नहीं है। उसकी प्रति घटा उत्पादन शक्ति भी बहुत कम है। यदि पाश्चात्य देशों के उसी प्रकार के श्रमिकों की उत्पादन शक्ति से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारतीय श्रमिकों का उत्पादन बहुत गिरा हुआ है। जापान, ब्रिटेन और श्रम्रीका के श्रमिक की अपेद्धा उतने ही ममय में भारतीय श्रमिक बहुत कम कार्य कर पाता है।

स्ती मिल उन्नोग सनन्वी प्रशुल्क मगडल (१६२६-२७) ने वताया कि भारतीय श्रमिक श्रयवा श्रापरेटर ने १८० तकुत्रों पर कार्य किया जब कि इतने ही समन में जापान के अमिक ने २४०, इगर्लंड के अमिक ने ५०० से ६०० के वीच श्रीर श्रमरीकी श्रमिक ने ११२० तकुश्रों पर कार्य किया। मारतीय वुन कर श्रीसतन २ कर्षे चलाता है जब कि जापान का बुनकर २३, ब्रिटेन का ४ से ६ तक थ्रोर अमरीका का ६ कर्षे चला लेता है। इससे मारतीय अमिक की सापेखिर कार्यज्ञमता का श्रामार मिलता है। यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि गत ऊछ वर्षों से कतिपय स्ती मिलों में कार्यच्चमता में काफी वृद्धि हुई है। स्ती उद्योग सम्बन्धो वर्किङ्ग पार्टी (१९५२) ने जाँच करके पता लगाया कि दिल्ली की एक श्रीर मद्रास की दो मिलों में एक बुनकर ४, ६, ८ श्रीर १६, श्रहमदाबाद की एक मिल में १८ श्रीर वम्बई नी एक मिल में ६ कर्षे चला लेता है। कार्यज्ञमता में इस वृद्धि का कारण यह है कि इन मिलों में स्वचालित आधुनिक मशीनें लगी हुई है जिससे अभिक अधिक काम कर सकता है परन्त कार्य मे इतनी प्रगति होते हुए भी आज तक यह बात सय माना जातो है कि मारतीय श्रमिक ब्रिटेन या जापान के अपने ही प्रकार के अमिक ने कम निपुण है। कायला-खदान उद्योग के सम्बन्ध में मारत की जिश्रोलोजीक्ल, माइनिंग श्रीर मेटालर्जीकल सोशाइटी के रूप वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के भाषण में बताया गया कि भारत में एक श्रमिक का उत्पादन २ ० टन है जब कि ब्रिटेन के मजदूर का ६ र्ट टन, नर्मनी के श्रमिक का ८ ६ टन और अमरोका के अमिक का २१ ६८ टन है। मारतीय अमिक का प्रतिषरटा उत्पादन गत कुछ वर्षों में गिरा है। योजना श्रायोग ने बताया है कि कोयला खदान उद्योग में कार्य करने नाले अमिकों की छल्या १६४१ में २, १४, २४४ से बढ़कर १६५१ में ३,४०,००० हो गई है जब कि इसी अवधि में कोयले

का उत्पादन २ करोड़ ५८ लाख ६० हजार टन से बहुकर ३ करोड ४० लाख टन हो गया। इस प्रकार जब अमिकों की सख्या में ५८ प्रतिशत बृद्धि की गई तो उत्पादन केवल ३२ प्रतिशत बढ़ा है परन्तु अमिक का प्रतिघरटा उत्पादन १२७ टन से गिरकर लगभग १०० टन हो गया।

यद्यपि सभी उद्योगों के सम्बन्ध में विम्तृत स्वना प्राप्त नहीं है फिर भी शह्म में प्रकाशित कतिपय उद्योगों की उत्पादकता और अर्जित आय के परिवर्तनों से निम्न वार्ते जात होती हैं:

- (1) कोयला उद्योग में १९५१-१९५४ के बीच खोदने तथा लादने वालों की उत्पादकता में • • ०७६ प्रति माह वृद्धि हुई जबकि प्रति सत्ताह नकद ग्राय में • • २६ की वृद्धि हुई।
- (11) कागज उद्योग में, १९४८-१९५३ के बोच मजदूरों की श्रीसत श्राय में तो चृद्धि हुई किन्तु इनकी उत्पादकता बढ़ने का कोई चिन्ह नहीं था।
- (111) जूट उद्योग में १६४८-१६५३ के बीच उत्पादकता की वृद्धि २६ प्रतिवर्ष थी जबिक श्रार्जित श्राय की वृद्धि ३७ थी तथा,
- (1v) स्ती वस्त्र उद्योग में उत्पादकता की वृद्धि की वार्षिक दर १९४८-१९५३ के बीच २ २ २८ थी नविक स्त्रिक्ति स्त्राय की वृद्धि १ १४ थी।'

इसके विपरीत श्रमरीका श्रीर ब्रिटेन के श्रमिक की कार्यज्ञमता में निरन्तर चृदि होती जा रही है। श्रमरीकी श्रमिक की प्रतिषयटा उत्पादन ज्ञमता में १६१० तया १६४० के बीच = ३ प्रतिशत वृद्धि हुई । विगत १५ वर्षों में इसमें श्रीर श्रधिक वृद्धि हुई है। यह बताया गया है कि यदि उत्पादन ज्ञमता इसी श्रमुपात में बढ़ती गई तो ३० वर्ष में टोगुनी हो जायगी । उत्पादन शक्ति की जाच करनेवाली एक श्राग्ल-श्रमरीकी परिपद ने ब्रिटेन के लोहे श्रीर इस्पात के कारखाने के कुछ विमागों की जाच की । परिषद की रिपोर्ट में बताया गया है कि १६१६ से १६५२ के बीच स्टील फोडिंग में १५ से २० प्रतिशत की श्रीर ड्राय-फोडिंग में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे ही श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। श्रनेक कारणों से भारतीय श्रमिक की कार्यज्ञमता निरन्तर घटती जा रही है। यहाँ यह बता देना श्रमुचित न होगा कि कार्यज्ञमता में कमी होने के लिये केवल भारतीय श्रमिक ही उत्पद्धायी नहीं है। इसका बहुत कुछ कारण खराब मशीनें श्रीर दोप पूर्ण क्रियोगिक सगठन है। परन्तु इसका परिणाम यह श्रवश्य हुआ है कि भारतीय अधिक की प्रतियोगिता शक्ति घट गई है श्रीर विश्व बाजार में श्रपने माल की निकाली करने में उसे अत्यन्त कठिनाइयो का समना करना पड़ रहा है।

कार्य-अमिक की कार्यच्मता अथवा उसकी निपुण्ता की परिभाषा करना बहुत फाँठन है और यह अनेक बातो पर निर्भर करती है। अमिक की कार्यज्ञमता की जाँच करने का एक व्यवहारिक दुग श्रमिक के प्रतिघएटा उत्पादन की जाँच करना है। एक श्रमिक की एक शिफ्ट के कुल उत्पादन के हिसाब से भी कार्यज्ञमता का पता लगाया जा सकता है। एक शिफ्ट में ७३ या ८ घण्टा कार्य होता है। इसके साथ ही अमिक के वार्षिक उत्पादन की मात्रा को भी इसका साधन बनाया जा सकता है। श्रमिक की कार्यज्ञमता केवल श्रमिक के श्रम पर ही निर्मर नहीं रहती है। कच्चे माल के प्रकार, मशीनों के प्रकार और उनकी हिषति श्रीर सम्पूर्ण श्रोद्योगिक सगठन का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रकुशलता ग्रयवा निपुरा न होने के लिये सारा दोप भारतीय श्रमिक पर ही नहीं मढा जा सकता। कुछ दोष ग्रवश्य श्रमिक का भी है परन्तु जिस प्रणाली के श्रन्तर्गत वह कार्य करता, है उसे इस श्रारोप से वंचित नहीं किया जा सकता। जब इम भारतीय श्रमिक की कार्यचमता श्रीर ब्रिटेन, श्रमरीका या श्रन्य देशों के श्रमिकी की कार्यज्ञमता की तुलना करते हैं तो हमें दोनो देशों के कारखाने मे लगी मशीनों श्रीर कार्य की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। परन्तु फिर भी इन सभी बातो पर विचार करने के बाद भी यह सही है कि भारतीय श्रमिक की कार्यज्ञमता श्रमरीकी तथा बिटिश श्रमिक की कार्यचमता से कम है।

मारतीय श्रमिक के श्रकुशल होने के ग्रनेक कारण वताये गये हैं: (१) श्रमिक की श्रस्वस्पता, (२) कुशलता का ग्रमान, (३) उसका प्रवाजी स्वभाव, (४) जलवायु, (५) श्रामिक का कम वेतन, (६) मारतीय उद्योग द्वारा प्रयोगरमें लाये जाने वाले कच्चे माल का घटिया प्रकार, (७) टूटी-फूटी ग्रीर पुरानी मशीनें श्रीर बहुत से कारखानों मे दोष पूर्ण श्रमिन्यास ग्रीर (८) श्रकुशल श्रीद्योगिक सगठन।

दुर्वल शरीर तथा बुरा स्वास्थ्य—इसमें कुछ सन्देह नहीं कि भारतीय अमिक का स्वास्थ्य विटिश या ग्रमरीकी अमिक की ग्रपेचा गिरा हुग्रा है। प्रश्न मारतीय अमिक ग्रोर ब्रिटिश श्रथवा ग्रमरीकी श्रमिक को काम करता है वह उस काम के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि वह उस काम के लिये उपयुक्त है या नहीं। यदि वह उस काम के लिये उपयुक्त है तो यह कहना उचित नहीं कि ब्रिटिश श्रथवा ग्रमरीकी श्रमिक की श्रपेचा स्वास्थ्य श्रिषक खराब होने के कारण भारतीय श्रमिक की कार्यच्याता श्रपेचाकृत कम है। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर ब्रिटिश, श्रमरीकी प्राय. सभी श्रमिको का उत्पादन गिर जाता है, उनकी कार्यच्यमता कम हो जाती है। इसलिये भारतीय श्रमिक की श्रकुशलता का कारण उसकी बीमारी या दुर्वलता नहीं हो सकते हैं।

- (11) प्रवासी प्रवृत्ति—भारतीय श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति से भी उसकी श्रकुशलता नहीं सिद्ध की जा सकती क्योंकि जनतक श्रमिक काम करता है तनतक श्रीयोगिक केन्द्रों में रहता है श्रीर इस बीच वह श्रपनी सम्पूर्ण योग्यता के श्रनुकृल कार्य कर सकता है। बीच-बीच में गाँव चले जाने से एक निश्चित लाभ यह होता है कि कारखाने के काम से कुछ दिन का श्रवकाश ले कर कारखाने के नियमित कार्य से श्रजा हो जाने के कारण एक नई शक्ति प्राप्त करता है इससे पुन. कारखाने लीटने पर वह पहले की श्रपेशा श्रिवक कार्य कर सकता है।
- (111) कुशलता का प्रभाव—इसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि कुशलता न होने के कारण ही उसकी कार्यच्रमता कम है, क्यों कि यदि श्रमिक एक विशेष कार्य करता है तो इसका कारण ही यह है कि वह इस कार्य को श्रन्य कार्यों की श्रपेचा श्रन्छी प्रकार कर सकता है। कुशलता का श्रमाय तभी होता है जब कुशल टेकनीशियनों का श्रमाय हो। परन्तु जहाँ कुशल टेकनीशियन काम करते हैं वहाँ उनकी कार्यच्रमता उतनी ही शिक्षा पाये हुए श्रन्य देशों के टेकनीशियनों से कम नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक ऐसे कार्य का सम्बन्ध है जिसको करने में विशेष कुशलना की श्रावश्यकता नहीं होती है वहाँ कुशलता के श्रमाय का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (1v) कम मजदूरी यह कहा जाता है कि पारिश्रमिक कम होने के कारण ही अमिक की कार्यज्ञमता कम है। इसके समर्थन मे यह तर्क दिया जाता है कि कम पारिश्रमिक होने से श्रमिक ग्रपना श्रीर ग्रपने परिवारका ठीक से भरण-पोषण नहीं कर पाता है। इससे उसकी कार्यज्ञमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह जानना चाहिए कि इन सब बातो का कारण पारिश्रमिक कम होना नहीं है वरन् मूल्य स्तर की तुलना मे पारिश्रमिक का श्रमाव है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक कम हो ग्रीर जिन वस्तुग्रों पर वह ग्रपना पारिश्रमिक व्यय करता है उन के मूल्य और भी कम है। तो उसे अपने परिवार का भरख-पोषख करने में कुछ कठिनाई नहीं होगी। वह अपनी आवश्यकता पृति के लिए सभी वस्तुएँ क्रय कर सकता है। वास्तव में मुख्य समस्या यह है कि पारिश्रमिक वस्तुत्रों के मूल्य की श्रूपेचा कम है। इसी कारण श्रमिक श्रवने परिवार को पेट भर भोजन नहीं दे पाता है स्रीर उसकी सन्य स्रावश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पाती। इससे उसकी कार्यज्ञमता की चति होती है। प्रश्न पर्याप्त भोजन न पाने श्रोर जीवन को सुखी बनाने के प्रसाधनों को न पाने का नहीं है। वास्तव में श्रमिक वस्तु श्रों के मूल्य की श्रपेक्षा पारिश्रमिक कम होने के कारण परिवार का ठीक तरह से प्रबन्ध भी नहीं कर् पाता । इससे उसे सदैव चिन्ता लगी रहती है जिससे श्रत में उसकी कार्यच्यमता

पर प्रभाव पहला है। इस प्रकार एक दुष्चक स्थापित हो जाता है; उसकी कार्यच्रमता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यच्रमता घट जाती है श्रीर उत्पादन कम हो जाता है। पारिश्रमिक होने से कार्यच्रमता नहीं बढ़ पाती है श्रीर जब तक कार्यच्रमता में वृद्धि नहीं होती पारिश्रमिक नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि भारतीय श्रमिक इतने वर्षों के परचात् भी श्राज निर्धन ही बना हुश्रा है। यदि श्रमिक का पारिश्रमिक बढ़ जाय श्रीर इसके फलस्वरूप उसकी कार्यच्रमता में भी वृद्धि हो तो वह भविष्य में श्रीर श्रमिक कमा सकता है। जहाँ तक पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, दितीय महायुद्ध से श्रमकों की स्थित में सुधार हुश्रा है। १६४२ से १६५२ के बीच भारतीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई परन्तु दुर्माग्य से पारिश्रमिक बढ़ने के साय-साथ वस्तुश्रों के मृत्यों में भी वृद्धि हुई । १६४२ श्रीर १६५२ के बीच मजदूरी की श्रपेच्चा बहुत श्रमिक वृद्धि हुई। १६४२ श्रीर १६५२ के बीच मजदूरी की श्रमेचा बहुत श्रमिक वृद्धि हुई। जब तक वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं होती श्रर्थात् श्रपने द्राज्यिक पारिश्रमिक से वस्तुश्रों श्रीर सेवाश्रों को श्रमिक मात्रा में नहीं खरीद पाता श्रमिकों की कार्यच्यमता में वृद्धि नहीं हो सकती श्रीर यह दुष्चक नहीं दूट सकता।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय अमिक की मजदूरी कम हैं। यद्यपि हाल में द्राञ्यिक तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ भारतीय अम की क्षमता में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। अम-मजालय के अम-कार्यालय द्वारा १६५६ में फैनद्री की अर्जित आय सम्बन्धी प्रकाशित विवरण से निम्न रोचक निकर्ष निकलते हैं:—

१—मारत मे फैन्ट्री में काम करने वालो की कुल श्रांजित श्राय (रेलवें वर्कशाप सिम्मलित नहीं हैं) १६४७ में १३७३ करोड रु० यी जो १६५५ श्रोर १६५६ में बढकर कमश. २४५ करोड़ रु० २६६ ५ करोड़ रु० हो गई। स्थायी उद्योगों में लगे तथा २०० रु० प्रति माह से कम पाने वाले व्यक्तियों की वार्षिक श्राय १६४७ में ७३७ रु० थी। १६५५ श्रोर १६५६ में बंढकर यह क्रमश. १,१७४ रु० तथा १२१३ रु० हो गई।

र-१६४७ से १६५६ तक दस वर्षों मे भारतीय उद्योगों में मजदूरों की वापिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चमड़ा उद्योग में ४% तथा सीमेन्ट उद्योग में १६३% हुई है। सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुये कहा जा सकता है कि प्रति मजदूर वार्षिक आय में ६३% की वृद्धि हुई है।

३—श्रम कार्यालय द्वारा प्रकाशित श्रॉकडे वास्तविक श्राय श्रथवा रहन-सहन के स्तर में कोई सुधार नहीं प्रकट करते। १६४७ से १६५६ के बीच में अमिक वर्ग से सम्बन्धित मूल्यों में २१% की वृद्धि हुई है तथा सामान्य मूल्य स्तर में ३१% की वृद्धि हुई है जब कि श्रौसत द्राव्यिक मजदूरी में ६३% की वृद्धि हुई है। इससे रहन-सहन के स्तर में होने वाली वृद्धि का श्रमुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि द्राव्यिक एवम् वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हुई है किन्तु भारतीय श्रम की उत्पादकता में उस श्रमुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

- (v) जलवायु—श्रमिक की कार्यज्ञमता में कमी होने का एक महत्वपूर्ण कारण भारत की जलवायु है। वर्ष के श्रिष्ठकाश भाग में न केवल श्रौद्योगिक श्रमिकों को वरन सभी लोगों को श्रालस्य श्रौद् शिथिलता वरे रहती है। इससे कठिन परिश्रम का काम एक प्रकार से श्रसमय हो जाता है। ब्रिटिश तथा जापानी श्रमिक की श्रपेज्ञाकृत श्रिष्ठक कार्यज्ञमता का एक कारण उन देशों की जलवायु भी है। भारत में भी विभिन्न चेत्रों के श्रमिकों की कार्यज्ञमता में जलवायु के श्रनुरूप श्रतर है।
- (v1) भारतीय उद्योगो द्वारा घटिया माल का उपयोग—मारतीय श्रमिक की कार्यचमता कम होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी हैं कि भारतीय उद्योग पटिया प्रकर के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कारखानों मे पुरानी श्रौर विसी टूटी मशीने हैं, मिलो के नियोजन में टोप हैं श्रौर श्रौद्योगिक सगठम लराव है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मिल-मालिको पर है। यदि वह श्रुच्छे प्रकार का कच्चा माल दें ख्रीर कारखानो मे ख्रच्छी मशीनें लगाये तो भारतीय अमिक की कार्यज्ञमता बढ़ेगी और श्रमिक के प्रति घएटा उत्पादन की मात्रा भी पहले की श्रपेचा श्रिषिक होगी। कारखानों में पुरानी मशीनो के स्थान पर श्राधिनिक मशीनों को लगा सकना वर्तमान में सुभव नहीं हो सका क्योंकि (१) इसके लिए त्रावश्यक वित्त का श्रभाव है, (२) मशीनों इत्यादि श्रोर टेकनिकल सामान का उपलब्ध हो सकना कठिन है, (३) मारतीय मिल-मालिक आधुनिक मशीनों के लाभ से ऋपरिचित हैं श्लोर (४) कारखानों के युक्तिकरण का श्रमिकों द्वारा विरोध किया जाता है। मारतीय अमिक मशीनों के युक्तिकरण का स्रोर पुरानी घिसी मशीनों को वदलने का तीव विरोध करता है। श्रमिकों का कहना है कि इससे वेरोजगारी होती है। भारतीय अमिक की कार्यज्ञमता कम है क्योंकि कारखानों की मशीनें पुरानी और विची-पिटी हैं इसलिए जब अमिक इन मशीनों को बदलने का विरोध करता है तब वास्तव में वह अपनी कार्यक्रमता में सुधार को रोकता है। युक्तिकरण के श्रव्याय में बताया गया है कि मशीनों के युक्तिकरण से वेरोजगारी फैलना आवश्यक नहीं है, यदि वेरोजगारी फैलती है तो सभी लोगों की तरह श्रमिकों को भी प्रगति के लिए यह कष्ट मेलना ही पडेगा। यदि मशीनो

में मुधार होने से वेरोजगारी फैलती है श्रीर श्रिमकों की कुछ ज्ञति होती है तो दीर्घ काल मे श्रिमक की कार्यज्ञमता में वृद्धि होने से श्रीर श्रिमिक पारिश्रमिक मिलने से यह हानि लाम में बटल जाती है।

श्रमिक की कार्यच्चमता की कमी बहुत कुछ उसकी मान्सिक स्थिति पर निर्भर करती है। कार्यच्चमता में कमी होने के सभी कारणों में प्रमुख यह है कि मारतीय श्रमिक विलास प्रिय है श्रीर उसमें श्रनुशासन का श्रभाव होता है। जब तक श्रमिक श्रपने उत्तरदायित्व को नहीं समक्तता श्रीर जब तक मिल-मालिक के श्रीर श्रपने हितों को समान नहीं समक्तता तब तक वह श्रपनी पूर्ण योग्यता एवम् च्याता से कार्य नहीं करता है। उत्पादन शक्ति रखते हुए भी श्रपनी कार्यच्यता में कमी बनाये रहता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद श्रमिकों की विचार घारा में पहले की श्रपेचा श्रीर बुराई ग्रा गई है। श्रमिकों ने कारखानों में काम धीरे करने की नीति ग्रपना ली है जिसका श्रर्थ यह है कि कार्य करने के लिए निर्धारित समय में श्रमिक उचित परिश्रम करने के स्थान पर कार्य श्रत्यन्त धीरे-धीरे करके श्रपना समय नष्ट करता है। श्रमिक द्वारा 'काम बीरे-धीरे करो' नीति श्रपनाने का एक कारण मालिकों को श्रपनी माँगें मानने के लिए मज़वूर करना है। परन्तु इस उद्देश्य के पूरे होने के स्थान पर इसके विपरीत उत्पादन कम हो गया है ग्रीर इससे उसकी स्थिति श्रीर भी विगइ गई है।

मारतीय श्रमिकों में श्रनुशासन के श्रभाव को गत कुछ वधों में (१) उत्पादन के श्राधार पर नहीं विलिक केवल उपस्थित के श्राधार पर महगाई भत्ता, वोनस हत्यादि देने से वहावा मिला है। महगाई भत्ते को श्रमिक के रहन-सहन के व्यय में सम्मिलित कर दिया गता है। श्रमिक चाहे श्रपना कार्य पूर्ण करे या न करे उसे महगाई भत्ता मूल्य के देशनाँ कों के श्रनुक्ल श्रवश्य मिलता है। इस कारण श्रमिक श्रपने उत्पादन श्रयवा श्रपने कार्य की किचित् मात्र भी चिन्ता नहीं करता है। यदि महगाई भन्ते को उत्पादन पर श्राधारित कर दिया जाता तो श्रमिक ऐसा नहीं करता। साथ ही निर्धारित मात्रा से श्रमिक उत्पादन करने पर श्रमिक का नोनस श्रीर महगाई भत्ता बहता श्रीर उत्पादन बहता, (२) इन्हिस्ट्रयल हिस्प्यूट्स एक्ट के पास होने के पहिले तक श्रीनोशिक क्तास्त्रों पर समक्तीते श्रीर पन्चिनर्श्य प्रणाली के श्रन्तर्गत उद्योग श्रथवा कारखाने के मालिक को श्रपने कर्मचारी को निकालने का श्रथिकार नहीं था, चाहे कर्मचारी श्रकुशल हो या काम लापरवाही से करता हुशा पाया गया हो। ऐसे मामलों में नौकरी से ग्रलग करने का निर्णय समकीता बोर्ड, श्रम न्यायालय, या श्रीसोगिक न्यायालय करते

थे । इसके परिखाम स्वरूप कार्यज्ञमता को ज्ञित पहुँची है श्रीर अभिक के प्रति <sub>घन्टे</sub> उत्पादन की मात्रा गिरी है।

दोष दूर करने के उपाय-भारत में श्रमिकों की कार्यचमता की स्थिति बहुत विगड़ चुकी है श्रीर इसको सुधारने के लिए सरकार को, मिल-मालिकों श्रीर श्रमिक नेता श्रों को बहुत श्रधिक परिश्रम करने की श्रावश्यकता है। यदि इस टिशा मे पूरी शक्ति से प्रयत्न नहीं किया गया अप्रीर केवल ग्राशिक प्रयत्न किए गये तो समस्या सुलक्तने की सभावना कम है। भारतीय अभिक की कार्यज्ञमता बढ समती है। इसके लिए यह ग्रावस्थन है कि (१) महगाई भता, बोनस इत्यादि उत्पादन के ग्राधार पर दिए जार्चे। यह श्रावश्यक है कि अमिक का न्यूनतम पारिश्रमिक श्रीर उसके कार्य की मात्रा निश्चित कर दिए जॉय। श्रमिको के लिये एक न्यूनतम पारिश्रभिक इस शर्त पर निश्चित कर दी जाय कि वह एक निश्चित मात्रा में कार्य करे। इसके उपरान्त पारिश्रमिक मे वृद्धि हो सकती है पर वृद्धि का अनुगणन ऐसे सूत्र के आघार पर होगा जिसमे रहन सहन की लागत श्रीर श्रमिक की उत्पादकता दोनों ही बातों का विचार सम्मिलित हो। इससे अमिकों के हित की रज्ञा यदि रहन सहन के ब्यय में वृद्धि हो गई तो होगी श्रोर साथ ही साथ यदि उनकी उत्पाटकता घट जायगी तो मिल मालिकों का मी हित उपेज्ञित न हो सकेगा, (२) काम धीरे करों नीति को श्रीचोगिक मत्राडे के श्रन्तर्गत समम्तना चाहिए। यदि श्रमिक 'काम घीरे करो' नीति श्रपनाऍ तो ऐसी ज्यवस्था होनी चाहिए कि मिल-मालिक सममीता बोर्ड इत्यादि के द्वारा श्रपनी शिकायत दूर करा सकें, (३) यदि श्रीमक अन्छी प्रकार कार्य न करें अरीर निर्धा रित मात्रा में उत्पादन न करे तो उद्योगपित ग्रथवा मिल-मालिक को उन्हें निकालने का ग्रिधिकार दिया जाना चाहिए, (४) त्र्यालस्य, उत्तरदाथित्व को टालने की भावना श्रीर अनुशासन के श्रमाव को दूर करने के लिए सरकार को श्रीर श्रभिक नेताथ्रो स्रादि को निरन्तर प्रचार कार्य करते रहना चाहिए। यदि उसका ध्यान बारम्बार इस दृश्य की स्रोर श्राकिषत किया जायगा कि उसकी कार्यवाही से वह उद्योग नष्ट हो सकता है जिस पर उसकी समृद्धि निर्मर करती है तो अवश्य ही अमिक की स्थिति में सुघार होगा और उसका हिन्टकोण बदलेगा। यद्यपि यह कार्य बहुत घीरे-घीरे होगा परन्तु दीर्घकाल मे श्रमिक की कार्यज्ञमता ग्हाने में इसका बहुत अधिक प्रभाव पहेगा, (५) श्रमिक की उत्पादन शक्ति का अन्ययन करने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के ब्रिटिश पोढिनिटविटी कौंसिल के समान एक विशेष सगठन भारत में भी स्थापित करना चाहिए। ग्रन्तर्राष्ट्रीय अम सघ के उत्पादन शक्ति का श्रध्ययन करने वाले दल ने वम्बई स्ती मिल उद्योग में जो कार्य किया है उससे मारतीय स्ती उद्योग का उत्पादन बढ़ने की समावना है। इस दल ने सुक्ताव दिया है कि कारखानों में सभी कार्य श्राधुनिक रीति से किया जाय श्रीर वर्तमान स्थित का गंभीर श्रध्ययन करने के बाद उद्योग के सगठन की योजना बनाई जाय। श्रीद्योगिक कार्यज्ञमता में वृद्धि करने के लिए श्रावश्यक सुक्ताव देने को विभिन्न उद्योगों में तत्सम्बन्धी श्रस्थयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

#### अध्याय ३१

#### श्रोद्योगिक सम्बंध

श्रीयोगिक उत्पादन यहाने, श्रीमकों की श्रार्थिक स्थित को सुघारने श्रोर देश को श्रार्थिक दृष्ट में समृद्रणाली बनाने के लिये श्रीयोगिक शांति का श्रत्यन्त महत्य है। यदि दृदतालें होती हैं, मिलो-कारपानों में तालाबन्दी की जांती है श्रीर श्रीयागिक शांति भग की जांती है तो उत्पादन घटने लगता है, उत्पादन व्यय में वृद्धि होने लगती है श्रीर श्राय कम हो जाने से श्रमिकों को श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पहता है। बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति नियमित रूप से न होने या उनकी पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा श्रा जाने से उपभोक्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पहता है। श्रीयोगिक चेत्र में श्रशांति होने ने सम्पूर्ण देण की शांति भग हो जाती है श्रीर इससे किसी को लाभ नहीं होता। पूर्जीबादी व्यवस्था में तालाबटी का होना श्रावश्यक नहीं है। यदि उचित ध्यान रपा जाय श्रीर व्यवस्था ठीक हो तो हन बाधाश्रों को पूरी तरह समाप्त न भी किया जा सके तो रम से कम टाला श्रवश्य जा सकता है।

श्राधुनिक प्रवृत्तियाँ-भारत के श्रीद्योगिक देत्र में शांति बनाये रखना सदैव सभव नहीं रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में श्रीदा। गिक मागड़ों की **ग**ण्या श्रीर इन कगड़ा के कारण नष्ट हुए कार्य के दिनों की गंख्या काफी कम रही है। र्झांकड़ो से प्रकट होता है कि १६४३ में जब कि युद्ध श्रपनी चरम सीमा पर था हड़ताल एवम् तालाबन्दियों से फेवल २३ लाख कार्य के दिन नष्ट हए। १६४४ में यह सख्या नढकर ३४ लाख दिन श्रोर १६४५ में ४१ लाख दिन हो गई। यह सख्या फिर भी श्रपेद्धाकृत कम रही, इसको अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। युद्ध के समय ग्रीन्त्रोगिक सम्बन्ध काफी ग्राच्छे रहे क्योंकि (१) श्रमिक ने सरकार को लड़ाई में सहयोग देने का यचन दिया स्त्रीर वह यह नहीं चाहते थे कि उत्पादन में किसी प्रकार की वाधा पड़े श्रौर युद्ध का सकल सचालन कर सकने में किसी प्रकार की बाधा पड़े। (२) उस समय वस्तुत्रों के भाव में तथा रहन-सहन फे न्यय में वृद्धि की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। इसी समस्या से ही बाद में ख्रीद्योगिक मगडे उत्पन्न हुए। १६ श्रगस्त १६३६ को समाप्त होनेवाले सप्ताइ को आधार मानते हुए १६४१-४२ श्रीर बाद के चार वर्षों में सामान्य मूल्य के देशनाक क्रमशः १३७ ०, १७१ ०, १३६ ५ २४४ २ श्रोर २४४ ६ रहे। वस्तुत्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी परन्तु इसी समय वेतन में भी त्राशिक वृद्धि हो गई थी। इसमें मालिक तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध विशेष खराब नहीं हुए, (३) युद्ध के समय भारतीय प्रतिरच्चा नियम की घारा दश-ए लागू थी जिसके श्रमुसार श्रौद्योगिक सगर्डों का निपटारा करने के लिए सरकार को सकट कालीन श्रिष्ठकार दिये गये थे। सरकार श्रशाति के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने को स्वतत्र थी।

परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही, श्रीर विशेषकर स्वतन्नता प्राप्त होने के पश्चात श्रीद्योगिक मगडों की खख्या वही श्रीर उत्पादन में कमी श्रा गई। १६४६ श्रीर १६४७ में क्रमश १ करोड़ २७ लाख श्रीर १ करोड़ ६८ लाख कार्य के दिन नष्ट हो गये जब कि १६४५ में केवल ४१ लाख कार्य के दिन नष्ट हुए । श्रीद्योगिक क्तगड़ों मे इतना वृद्धि होने का कारण यह था कि (ग्र) स्वतन्त्रता प्राप्त होने के परचात् श्रमिक के दिल में नई आशाएँ जगी थीं। श्रमिक अपनी आर्थिक स्पिति को सुघारना चाहते थे त्रौर इसी के परिणाम स्वरूप इहताले हुई। सरकार की थम नीति ने मी जिसका उद्देश्य श्रमिकों का पारिश्रमिक बढाना ग्रौर कार्य की स्थिति में सुघार करना था, इसमें काफी योगदान दिया, (ब) युद्ध काल की ऋषेज्ञा चीजों के माव में श्रधिक वृद्धि हुई। १६४५-४६ में योक विकी के माव का देशनाक २४४′६ या परन्तु १६४६-४७ में वह कर २७५ ४ ग्रोर १६४७-४⊏ में ३०७ हो गया। वस्तुर्जों के मूल्यों में तो वृद्धि हुई परन्तु वेतन ऋथवा प।रिश्रमिक में इसी श्रनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इससे अमिक को श्रनेक कठिनाइयों का मामना करना पड़ा । परिगामस्वरूप अमिकों ने वेतन ऋयवा पारिश्रमिक बढवाने के लिए इडताले कीं, (स) भारतीय प्रतिरत्ता नियम के लागून रहने से अमिको ने एक छूट का अनुमव किया। अब श्रमिकां की इच्छा भी युद्ध के समय की तरह कटोर परिश्रम करके उत्पादन वढाने की नहीं रही थी।

स्थित काफी गभीर रूप धारण करती गई और १६४७ के दिसम्बर में मारत सरकार नो श्रौद्योगिक शांति सममीता कराने के लिए हस्तद्येप करना पड़ा। इससे भारत में श्रौद्योगिक सम्बन्ध सुधारने में वाफी सहायता मिली। श्रीमक के श्रान्दोलन और सरकार के हस्ताचेप करने में पारिश्रमिक में वृद्धि हुई, में हगाई भत्ता, बोनस और लामाश में श्रीमकों के माग में भी वृद्धि हुई। यह कहा गया कि द्रव्य में श्रीमक का पारिश्रमिक बढ़ने ने श्रीमक का वास्तविक पारिश्रमिक नहीं बढ़ा और यदि स्पये को क्रय शक्ति की हिंदि से देखा जाय ता ज्ञात होगा कि श्रीमकों की स्थित युद्ध ते पूर्व के वर्षों की श्रपेन्ना कहीं श्रीधक विगड़ गई। इस तर्क में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गमा है कि मूल्य बढ़ जाने से केवल श्रमिक को ही नहीं बिल्क सभी वर्गों की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रश्न यह नहीं है कि असिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या नहीं; धास्तव में विचारणीय बात यह है कि क्या श्रमिकों को समाज के ग्रन्य लोगो की अपेदा अधिक कष्ट सहने पडे १ यद्यपि अमिकों के कुछ वर्ग ने अधिक वेतन ग्रथवा पारिश्रमिक की मांग करते हुए श्रान्दोलन जारी रसा परन्तु जहाँ तक पूरे श्रीमक वर्ग का प्रश्न है वह सन्तुष्ट रहा ग्रीर हहतालों की संख्या भी घट गई। मिल मालिकों ने तालाइन्दी घोषित नहीं की क्योंकि पारिश्रमिक में वृद्धि होने के साथ ही उत्पादित माल के मूल्य में भी वृद्धि हुई ग्रीर बाजार विकेता के श्रमुक्ल दृढ होने के कारण भिल मालिकों को श्रिधिक हानि नहीं उठानी पडी। इसके साथ ही श्रीद्योगिक मगडे सम्बन्धी कानून के ख्रन्तर्गत मगडे सुलमानेवाली उस्था क्रमश: अधिक प्रभावशाली बनाई गई श्रीर समसीते तथा अनिवार्थ पचिनर्शय के द्वारा श्रनेक होने वाले श्रीद्योगिक मगर्डी को जो श्रवश्य उत्तन होते रोक लिया गया । १६५० में कुल नष्ट हुए अम-टिनो की सख्या १२८ १ लाख हो गई परन्तु इसका कारण सर्वत्र श्रीद्योगिक सम्बन्धां का विगड़ना नही बल्कि सूती मिल उद्योग की लम्बी इंडताल थी। कुल नष्ट हुए १२८ १ लाख दिनों में से १३ लाख दिन अकेले स्ती उद्योग में ही नष्ट हुए। श्रीद्योगिक समझौते के पश्चात् से मारत में श्रीद्योगिक शांति श्रविक मग नहीं हुई है श्रीर उक्त तालिका के श्रमुसार नष्ट हुये श्रम-दिनों की सख्या घटकर १६५१ मे ३८२ लाख, १६५२ में ३३ ४ लाख, १६५३ में ३३ 🖛 लाख और १६५४ में ३७ २ लाख हो गई। १६५६ में ६६ ६ लाख अम दिन निष्ट हुवे । श्रीद्योगिक मत्त्रहो की सल्या १,२०३ तथा उनसे सम्बन्धित श्रमिको की सख्या ७१५,१३० यो। १६५७ मे ६४ लाख अमदिन नष्ट हुये तथा श्रीद्योगिक मगडों की सख्या २,०५६ तथा उनसे सम्बन्धित असकी की संख्या १,०१८,६२५ थी। नष्ट हुये ६४ लाख अस-दिनों मे स्ती वस्त्र उद्योग मे १५ लाख दिन, कोयला तथा अन्य खदान उद्योगो में लगभग १० लाख, रोपण तथा जूट उद्योग मे लगमग ५ लाख अम दिन नष्ट हुये।

कानूनी ज्यवस्था—एक जनतत्रवादी देश में जहाँ उद्योग स्वतत्र हैं
ज्ञपनी माँग के अनुसार उचित वेतन अथवा पारिश्रमिक न मिलने पर श्रमिक
को अन्य उपाय असफल रहने के पश्चात अत में हडताल करने का आधकार है
को अन्य उपाय असफल रहने के पश्चात अत में हडताल करने का आधकार है
और यदि मालिक अमिकों के कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो तो उस भी तालावन्दी
प्रीपत करने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि जनतत्री शासन व्यवस्था में यह
घोषित करने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि जनतत्री शासन व्यवस्था में यह
अधिकार निहित हैं फिर भी जिना सार्वजनिक हित पर विचार किये इन अधिकारों
अधिकार निहित हैं फिर भी जिना सार्वजनिक हित पर विचार किये इन अधिक जोने
का प्रयोग नहीं करना चाहिये। हड़ताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने
का प्रयोग नहीं करना चाहिये। हड़ताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने
का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इड़ताल होने से या तालावन्दी घोषित की जाने
के उपभोक्ता को भी अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। अभिक तथा मिल

मालिकी द्वारा कमश इइताल श्रीर तालावन्दी के श्रपने मूलभूत श्रिषकारों के प्रयोग के प्रति जनता श्रीर सरकार उदासीन नहीं रह सकते । उचित रीति में समक्तीता वार्ता चलाने श्रीर एक दूसरे की किनाइयों को समक्ती हुए श्रीयोगिक क्ष्मांडे को सुलक्ताना सदैव सभय है। श्रीयोगिक क्षमांडे सम्बन्धी कानून का उद्देश्य यह है कि कमांडा होने पर मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच समकीता करने के लिए साधन खोजा जाय। इस कानून में विभिन्न परिस्थितियों के श्रानुक्ल भिन्न भिन्न साधनों की न्यवस्था की गई है श्रीर किसी भी श्रीयोगिक कमांडे में समक्तीते तथा पचिनिर्णय में जितना समय लगना चाहिए उसकी श्रविध भी निश्चित कर टी गयी है। इसमें मामले पर विचार करने की पूर्ण विधि विस्तार से दी गई है। भारत तथा ससार के श्रनेक देशों में यह देखा गया है कि कार्य की श्रविषट रूपनेखा के कारण श्रम उत्पन्न हो जाता श्रीर इससे श्रीयोगिक मतभेंद हो जाता है। श्रम कानून का यह उद्देश्य है कि इस प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न हो जाता है। तो उसे दूर किया जाय।

१६२६ का भारतीय व्यापारिक विग्रह कानून—इस कानून में सार्व-निक उपयोगिता की सेवायों तथा श्रन्य उद्योगों के लिए पृथक व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें जैसे रेलवे डाक तथा तार, विजली श्रीर जल पूर्ति विभाग के कर्मचारियों तथा भगियों इत्यादि की इन्द्रतालों पर प्रतिवन्घ लगाया गया या। ये कर्मचारी मालिक को १४ दिन पूर्व नोटिस देने के पश्चात् ही हडताल कर सकते थे। ग्रन्थ उद्योगों में इडताल श्रयना तालावन्दी को घोषित किया बी सकता था परन्तु इन कगर्दों को सुलकाने के लिए एक निश्चित साधन नियुक्त किया गया था। श्रीयागिक कगडों के सम्बन्ध में तदर्थ जाँच समिति श्रीर समकीता परिपद् नियुक्त करने भी भी व्यवस्था की गई थी। जाँच समिति में एक या एक से श्रधिक निष्पद्म व्यक्ति रखे जायँगे। यह समिति मामले की जाँच करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट नियुक्त करने वाली सरकार के सामने पस्तुत करेगी। समसोता परिषद् इस बात का प्रयक्ष करेगी कि दोनों पद्म साथ बैठकर श्रं<sup>पने</sup> मतमेदों को दूर करके सममीता कर लें। सममौता न हो सकने पर मामले नी रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी जाती थी। इस कानून में श्रुनि<u>ब</u>्रार्थ पचनिर्णय की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अनुसार सरकार ने केवल यही प्रयत्न किया कि दोनो पद्म एक दूसरे के और अधिक निकट आ जाएँ और मामले तथा उर भगडे के कारणो को जनता को बतावे जिससे सममोता करने के लिए जनता क राय का भी बल प्राप्त हो। जनहित की सुरज्ञा के लिए कानून की दृष्टि में वे इड़तालें श्रीर तालावन्दियाँ गैर कानूनी थी (क) जिनका उद्देश्य उन्योग के श्रान्य मगडे का प्रधार करने के श्रतिरिक्त कुछ श्रीर भी हो या (ख) जिनका उद्देश्य जनता पर श्रनेक कठिनाइयाँ लादकर सरकार की विशेष कार्यवाही करने की मजबूर करना हो।

यह कानून उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। श्रीयोगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं या क्योंकि (१) समकीता श्रिधकारी श्रयवा कगड़े का श्रीम निपटारा करने वाली श्रान्य सस्याश्रों के स्थान पर तदर्थ सार्वजनिक जॉच को श्रिधिक महत्व दिया गया श्रीर (२) स्याई श्रोद्योगिक न्यायालय की स्थापना के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई।

बम्बई मे १६३४, १६३८ श्रीर १६४६ मे श्रीचोगिक विग्रह कानून बनाकर उक्त कानून के दोपों को कुछ सीमा तक दूर कर दिया गया। इन कानूनों के श्चन्तर्गत मालिको द्वारा श्रमिक सघो को मान्यता दी जाने की व्यवस्था की गई थी। इन कानूनों में क्तगढ़ों को मुलकाने की पूरी विधि ह्योर निश्चित ह्यविध दी गई थी। केवल सार्वजनिक जॉच करने की अपेद्धा समकौते श्रीर कगडा सुलकाने पर प्रधिक महत्व दिया गया। इस बात का निशेष ध्यान रखा गया कि कार्य की शर्ते श्ररपण्ट श्रीर श्रनिश्चित न हो क्योंकि इससे कगडे उत्पन होते हैं। इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि सममौते की शर्ते छोर स्थायी सभायें लिखिन छीर रजिस्टर्ड हो । स्त्रन्य प्रभावशाली साधनों के साथ ही स्थायी स्त्रीद्योगिक न्यायालय का विकास हुन्ना है। पहले के कानूनों में न्याय का मानना ऋनिवार्य नहीं था परन्तु इडताल अथवा ताले-नन्दी से पूर्व सम्पूर्ण मामले शातिपूर्ण उपाय से मुलक्ताने के लिए प्रस्तुत करने श्रावश्यक थे। परन्तु बम्बई के १६४६ के कानून मे पचिनर्गाय के लिए मामला प्रस्तुत करना श्रनिवार्य कर दिया गया श्रीर श्रपील करने के लिए एक अप्रालत की व्यवस्था की गई। वास्तव मे बम्बई ने इन कानूनों का बनाकर भविष्य में श्रक्षिल भारतीय पैमाने पर श्रिधिक उपयुक्त कानून बनाने के लिए मार्ग दर्शाया।

भारतीय प्रतिरत्ता नियम के अन्तर्गत कार्यवाही—पहले कहा जा चुका है कि युद्ध काल मे आयोगिक मगडो को हल करने के लिए सरकार ने सक्कट कालीन आधिकार प्राप्त कर लिये थे। भरतीय प्रतिरत्ता नियम की धारा दृश् (ए) के अन्तर्गत, जो जनवरी १९४२ में लागू की गयी थी, यह व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत की प्रतिरत्ता के लिए, सार्वजनिक सुरत्ता के लिये, शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये युद्ध का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिये समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक सामान की पूर्ति जारी रखने के लिये सामान्य अपवा विशेष आदेश द्वारा वेन्द्रीय सरकार तालावन्दी तथा हडताल पर रोक

लगा सकती है श्रोर श्रोत्रोगिक सगटों को सममति या श्रदालती कार्यवाही के लिये मेज सकती है श्रोर श्रदालत के निर्णय को लागू कर सकती है। उस कानून में यह भी व्यवस्था की गई थी कि हदताल श्रथवा तालवन्दी की पहले से सूचना दी जाय। सममति की कायवाही की श्रविय में हदताल श्रथवा तालेक्टी पर रोक लगा दी गई थी। स्थोकि सरमार को श्रदालती निर्णय श्रिनवार्य का से लागू कर देने का श्रिषकार प्राप्त था इसलिये हम कह सकते हैं कि इस नियम के द्वारा पचनिर्णय श्रिनवार्य कर दिया गया था।

१६४७ का छाँचोगिक विश्वह कानून - फरवरी १६४७ में बेन्द्रीय सरमार ने श्रोत्रोगिक विश्वह कानून स्वीकृत किया। इस कानून ने बम्पई के श्रात्रभव का लाम उठाकर १६२६ के श्रोत्रोगिक निश्वह कानून के कुछ दोपों को दूर कर दिया। इस कानून में कार्य समिति, नमकीता श्राधकारी, समकीता बोर्ड श्रीर जाँच-श्रदालत नियुक्त करने की व्यवस्था है। इसके श्रितिरूक्त करने की व्यवस्था की गई है जिसमें उच क्यायालय के न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें उच न्यायालय के न्यायाशिश होंगे। इस कानून में परस्पर ममकीता करने पर श्रिक महत्व दिया गया है। पहले कानून में केवल जाच कार्य को ही महत्व दिया गया था। कार्य समितियां का कार्य परस्पर वातचीत करके मालिक तथा कर्मचारी के तीच का मतमेत दूर करने श्रोर समकीता पटाधिकारियों तथा समकीता बोर्डों का कार्य दोनों पन्नों में समकीता कराना है। परन्तु यद्दि यद्द प्रयत्न सफल न हो तो मामले को श्रोत्रोगिक न्यायालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। सरकार को इन न्यायालयों का न्याय पूर्ण या श्राशिक रूप में लागू करने का श्राधकार श्रात है। उस प्रकार इस कानून में भी श्रीनवार्य पचित्रण्य की व्यवस्था है।

१६५१ मे श्रीशोगिक विग्रह (संशोधन) ग्रध्यादेश जारी वरके इस कानून की कुछ कियों ने दूर कर दिया गया। इस श्रन्थादेश के द्वारा वे श्रीशाणिक इकाइयाँ मी श्रदालती नार्यवाही के त्रेत्र में श्रा गई जिनमें श्रा तक कोई मनादा नहीं हुश्रा था परन्तु भविष्य में होने की समाजना थी। भविष्य में एक ही बात पर श्रन्थ श्रीशोगिक इकाइयों में मनाइन न होने देने के लिए यह श्रद्धादेश श्रावश्य क सममा गया। १६५० के श्रीशोगिक विग्रह (श्रम श्रपील न्यायालय) वानून से श्रम श्रपील न्यायालय स्थागित करने की व्यवस्था थी गई है जिसमें श्रिमिन्नों श्रोशोगिक पच न्यायालयों, श्रोशोगिक श्रदालतों, वेतन परिपत्नों इत्यादि के फैसले पर की गई श्रपीलों की सुनवाई होगी। श्रम श्रपील न्यायालय के किसी श्रदालत फैसले श्रयवा निश्चय के विष्ट की गई श्रपीलों पर विचार करने का श्रधिकार है परन्तु इसकी दो शर्ते हैं (१) फैसले श्रयवा निश्चय में कोई विशेष कानूनी पैंच

हो या (२) उसका धवन्ध वेतन, वोनस, छटनी इत्यादि से हो। विभिन्न राज्यों में त्र्योद्योगिक न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी फैसले दिये जाने के कारण जिसस देश में त्रोद्योगिक सबन्ध अधिक जटिल होते जाते ये श्रम त्रप्रील न्यायालय स्थापित करने की त्रावश्यकता श्रनुभव हुई। इसके साथ ही श्रपील करने के लिए कोई न्यवस्था न होने के कारण यह श्रीद्योगिक श्रदालते उदार निरक्कश शासक की तरह ग्राचरण करने लगी थीं। इस प्रकार की निरक्रशता और स्वच्छन्दवा जन-तत्री शासन प्रणाली के अनुकृत नहीं है। मूल कानून की ३३ वीं घारा मे यह व्यवस्था की गई थी कि समसौते के लिए किसी भी सगडे के विचाराधीन होने के काल में कोई मालिक समभौता अधिकारी, बोर्ड अथवा पचन्यायालय की लिखत ग्रनुमित प्राप्त किये विना न किसो कमचारी को दरह दे सकता है ग्रीर न निकाल सकता है, साथ ही मामला प्रस्तुत होने के ठीक पहले की नौकरी की हालत में वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस धारा की च्यवस्थात्र्यो को धारा ३३ (ए) जोडकर ग्रीर बढा दिया गया है। घारा ३३ (ए) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मालिक धारा को भग करता है तो उससे पीड़ित कर्मचारी विधिनत लिखित रूप में अपनी शिकायत उस पच अदालत के सामने पेश कर सकता है जिसमें मामला विचाराधीन है। वह पचश्रदालत उस शिकायत पर उसी रूप में विचार करेगी जैसे वह कानून की व्यवस्था के अनुसार पच श्रदालत में पेश किया गया श्रीद्योगिक क्तगडा हो। इस सशोधन के श्रनुसार पीड़ित कर्मचारी को मामले के विचाराधीन होने के काल में नौकरी की हालत मे परिवर्तन, छटनी, दगड इत्यादि के मामलों को सीधे पचन्यायालय में विचारार्थ अस्तुत कर सकने का श्रविकार पाप्त है। इससे पचन्यायालय मे प्रस्तुत होनेवाले क्तगड़ों की सख्या भी श्राधिक बढ़ने से बच जायगी श्रौर निर्णय भी शीघ हो जायगा।

श्रा बी० वी॰ गिरि का दृष्टिकोग्र —भारत के श्रम-मन्नी श्री गिरि ने अवदूवर १६५२ में नैनीताल में हुए भारतीय श्रम-सम्मेलन के १२ वे श्रिष्वेशन में, फरवरी १६५३ में नई दिल्ली में हुए राज्य श्रम-मन्नी सम्मेलन में श्रीर श्रनेक सार्वजनिक भाषणों में बराबर इस बात पर जोर दिया है कि श्रीद्योगिक क्तगड़ों को वर्तमान न्यवस्था के श्रमुसार श्रमिवार्य पचिनर्णय के द्वारा नहीं बल्कि परस्पर समक्तीता करके स्वेच्छिक पचिनर्णय से इल करना चाहिए। इस योजना के अन्तगत सार्वजनिक उपयोग सेवाश्रो के सबन्य में श्रमिवार्य पचिनर्णय लाग् रहेगा परन्तु ग्रन्य सस्याश्रों या उद्योगों में समक्तीता श्रथवा स्वेच्छिक पचिनर्णय लाग् रहेगा। परन्तु सकटकाल में श्रीर वेन्द्रीय सरकार से पहले विचार विमर्श कर लेने के बाद राज्य सरकारों को श्रीद्योगिक मामला श्रमिवार्य पच-

निर्ण्य के लिए सीपने का अधिकार होगा। श्री गिरि का मत या कि अम अपील न्यायालय को समाप्त कर दिया जाय क्यों कि कागड़ों को ग्रापस में सुलका लेने के पश्चात् इस न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं गृह जाती। श्री गिरि द्वारा मुक्ताई गई योजना के अन्तर्गत मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच के सभी मताड़ों पर स्वेब्छ। से समसीता करना होगा। समसीता वार्ताक समन्य मे भगडे से सबन्वित कोई भी पन्न सममीता श्रिषकारी की सहायता लेने को स्ववत्र होगा श्रोर दुसरे पन्न को यह स्वीकार करना पडेगा। यदि इस प्रकार की समझीता वार्चा असफल हो जाती है और दोनों पत्त मामले को पचनिर्णय के लिए सीपने को प्रस्तुत हों तो पचा का निर्णय दोनों पत्तों को मानना पड़ेगा। पटि पच परस्पर सहमत नहीं हो तो फगडे से सबन्यित पार्टियाँ एक निर्णायक छॉट सकती हैं जिसका फैसला दोनो पत्नों को मान्य होगा। यदि दोनो पार्टियों में निर्णायक छाँटने के प्रश्न पर मतमेट हो तो वह दोनों एक गय से मामला पच ग्रदालत को साप सकते हैं। सममीते की इन विभिन्न हिथातियों के लिए ग्राविध निश्चित होगी। राज्य सरमार्चे केवल सकट काल में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर गेर सार्वजनिक उपयोग के उद्योगों के मामलों को श्रुनिवार्य पच-निर्णय के लिए सोप सकती हैं। परन्तु यह श्रविकार श्रन्य उद्योगों पर लागू नहीं होगा । गिरिन्योजना के अन्तर्गत शमिक समितियाँ, सममीता श्रविकारी, सममीता बोड. श्रीचोगिक न्यायालय श्रीर पच श्रदालत पूर्ववत् रहेंगी परन्तु क्षम श्रपील-न्यायालय खत्म हो जायगा ।

इससे दो मुख्य प्रश्न उठते हैं (१) वया श्रनिवार्य पचनिर्ण्य हो या स्वैिच्छक पचनिर्ण्य श्रोर (२) क्या श्रम श्रपील न्यायालय रहना चाहिए या नहीं ?

श्रमिनार्य पंचितिर्ण्य—यह कहा जाता है कि श्रमिनार्य पचितर्णय श्रीयोगिक चेत्र में शानित बनाए रखने में सहायक नहीं है। स्थायी तौर पर शानित तमी रह सकती है जब परस्पर ब्रार स्वैन्छिक समीते किये जायें। यह भी बताया गया है कि श्रमिनार्य पचितर्ण्य से श्रीयोगिक कमाई को प्रोत्साहन मिला है श्रीर भारत में इससे श्रमिक सब कमजोर हो गए हैं। "श्रमिक सब की व्यवस्था पर इससे कुठाराबात होता है। श्रमिक सब के सदस्यों में एकता निजी स्वार्थ का ही परिणाम है। यदि श्रमिकों की समक्त में यह श्रा जाय कि एकता के सूत्र में बँध जाने से ही उनके स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है तो उनके समुक्त होने के लिये श्रन्य किसी प्रेरणा की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। श्रमिनार्थ पचितर्ण्य उनको उस बात के लिये कोई कारण नहीं उपस्थित करता कि उनमें इस प्रकार की एक ता हो '। श्रमिनार्य पंचिनर्ण्य, श्रार्थिक व्यवस्था को एक ऐसी कठोरता

प्रदान करता है जिससे श्रन्तर्राम्ट्रीय बाजार में विकने वाली वस्तुश्रों के लिये

परन्तु ग्रुनिवार्य पचिनिर्णय का समर्थन भी किया गया है। कहा गया है बहुत फाठनाई उपस्थित हो जाती है। कि अर्थिक दृष्टि से कम विकसित देश में श्रीद्योगिक मनाडों के कारण यदि उत्पादन वक जाता है तो इससे राष्ट्र के हितां की हानि होने की सभावना है। उत्पादन में गिरावट रोकने के लिए श्रीर परिणामत: राष्ट्रीय श्राय कम न होने देने के लिए प्रनिवार्य पचनिर्णय को लागू किया जाना चाहिए। पचनिर्णय की सफलता के लिए यह त्रावश्यक है कि (१) मालिकों तथा अमिकों के कुशल सगठन हो श्रीर (२) सममौते की कार्यवाही में उत्तरदायित्व सममने वाले ग्रनुमवी नेता श्रों को भाग लेने दिया जाय। चूँ कि भारत में श्रीमक सगठन ग्रव भी बहुत कमजोर है, ग्रीर समसीते तथा पचित्रग्य के लिए निष्पत्त व्यक्तियों का श्रमाय है इसलिए यह समय है कि स्वैन्छिक पचनिर्णय से सन्तोषजनक परिसाम

इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस परिग्राम पर पहुँचते है कि यद्यपि सर्विजनिक उपयोग के उद्योगों के लिए अनिवार्य पचितर्ग्य आवश्यक है न निकले। श्रीर स्कट काल मे भी यह लाभवायक साधन सिद्ध हो सकता है परन्तु श्रीचोगिक मगड़ों को सुलमाने का यह सन्तोषजनक दम नहीं है। इससे प्राय श्रीशोगिक क्ताडे उत्पन्न होते रहते हैं, अमिक संगठन कमजोर होते जाते हैं ग्रीर देश की

परन्तु श्री गिरि का श्रपील न्यायालय को समाप्त कर देने का सुमाब ग्रार्थिक व्यवस्था कठोर होने लगती है। पूर्णतया सत्य नहीं है। देश के विभिन्न भागों में समान अम स्थिति उत्पन्न करने में ग्रापील न्यायालय विशेष सहायक रहा है। वेतन, बोनस, कार्य की स्थिति इत्यादि प्रश्नों पर अपील न्यायालय के पैसलो से श्रीशोगिक पच अदालतों को काफी लाभ पहुँचा है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि परहार सममीता करके या स्वेन्छिक पर्चानर्गीय द्वारा मामला तय करके ऐसी स्थिति श्रा सकती है कि मविष्य में श्रपील न्यायालय की श्रावश्यकता न रहे परन्तु जब तक श्रीद्योगिक पच-ग्रदालत हैं तब तक देश के विभिन्न भागा में अम सम्बन्धी समान स्थिति लाने ग्रीर विमिन्न उद्योगों में भी एकरूपता लाने के लिए ग्रपील त्यायालयों को समाप्त

१९४६ का औद्योगिक विम्रह कानून—एक बिल अमिकों के सम्बन्ध विषयक संसद में १९५० में रक्खा गया, पर उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी, न किया जाय। क्योंकि मिल मालिकों अरीर श्रमिकां के नेताओं ने उसका बहुत विरोध किया। शह्मभू के खितम्बर में पुनर्पगिनित रूप में एक विधेयक १९४७ के श्रीयोगिन विमह कानून का खरोधन परने के लिये लोक सभा में मन्तुत किया गया श्रीर १९५६ में श्रीयोगिक निमह (संशोधन तथा निभन्न सर्तों के खाय) कानून पास किया गया। यह बढ़े तुर्भाग्न की बात है कि इस जानून में श्री गिरि के विचारी को बहुत ही सीमित मात्रा में सिमलित किया गया है। ऐसा लगता है कि उसमें श्रोयोगिक कागहा में विस्तार होगा श्रीर समझीता पठिन होगा। इस कानून के मुख्य प्रनिधान, जो कि बम्बई के १९४७ के कानून के श्रानुरूप रें, निम्न हैं —

- (१) अमिकों की परिमापा विस्तृत कर दो गई है, खोर छव छी योगिक कर्मचारी तथा देख रेख करने वाले पदाधिकारी भी जिनका वेतन ५००) माधिक से अभिक नहीं है अमिकों के अन्तर्गत रिमलित कर लिये गये हैं। नर्गिक बहुत से इस प्रकार का कार्य करने वालों को गोपनीय और सगठन सम्बन्धी कार्य दिया जाया है छीर वे अभिकों की अपेक्षा मालिकों के हो विशेष छन है, इससे यह भय है कि मालिका को नई कठिनाइयों का सामना करना पढ़िया।
- (२) १९५० के यांचागिक निगद (श्रावील न्यायालय) कानून का प्रत्यानयन कर दिया गया है श्रीर श्रीमकों के प्रपील न्यायालय को समाप्त कर दिया गया है। इस न्यायालय के कारण देश के निभन्न भाग में श्रीमकों की स्थित में समानता आ गई थी श्रीर इसने अनेकों ऐसे लाभदायक सामान्य नियम बना दिये थे जिनके विरान्डन से मविष्य में गभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे इम केवल एक ही अञ्छाई की आशा कर सकते हैं कि अपील न्यायालय के अभाव में सम्भवत मालिकों और श्रीमकों को स्थित की वास्तिनिकता पर विचार करने की प्रेरणा मिले।
- (३) इस कार्न के अनुसार तीन प्रकार के मीलिक न्यायालय वर्नेंगे। (अ) अम न्यायालय, (३) ओनोगिक न्यायालय श्रीर (स) राष्ट्रीय न्यायालय। अम न्यायालयों को ऐसे श्रीद्योगिक मनाडों के निर्णय करने का श्रिषकार है जो मालिकों की ऐसी श्रीश्राओं के सम्बन्ध में उत्पन्न हुये हैं जिनका श्रोबित्य तथा नियमानुक्-लता सिंदम्ब है और जो स्थायी आशाआं के अन्तर्गत है तथा कर्मचारियों को निमाले जाने के सम्बन्ध में श्रीर हइताल अथवा तालावन्दी के सम्बन्ध में हैं। श्रीयोगिक न्यायालय ऐसे मनाबा मा निर्णय करना जो कि पारिश्रिमक, कार्य के अन्दे, बोनस, युक्तिकरण और छड़नी क सम्बन्ध में हैं। राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे मनाहों का निर्णय करेगा जो कि सरकार के मत मे ऐसे मामले हैं जिनकी राष्ट्रीय इिनकोण से महत्ता है, अथवा ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध एक से श्रीषक

राज्यों से है। इन तीन न्यायालयों के निर्णय पर अपील करने का कोई अवसर नहीं है इसिलये इनके कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी योग्यता पर विशेष न्यान दिया गया है। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय न्यायालय अपील न्यायालय का स्थानापन नहीं है।

- (४) यह कानून स्यायी आज्ञाओं के सम्बन्ध में आपित्तनक परिवर्तन करता है। मालिको की चिन्ही विशेष मामलों में कार्य करने की स्थिति के सम्बन्ध में बिना उन अभिकों को, जिनसे इसका सम्बन्ध है, २१ दिन पूर्व अपने विचारों की स्वना दिये परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह कानून औद्य गिक रोजगार (स्थायी आज्ञात्रां) कानून का संशोधन करता है और प्रमाण पत्र देने वाले विशेष पदाविकारी को तथा अन्य अधिकारियों को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वे प्रमाण पत्र देने के पूर्व स्थायी आज्ञाओं की युक्तिसंगतता तथा न्याय पूर्णता पर विचार कर ले। पहिले केवल मालिक को ही स्थायी आजाओं में परिवर्तन करने के लिये आवेदन देने का अधिकार प्राप्त था। यह कानून अभिकों को भी मालिकों के ही समान प्रमाण पत्र देने वाले अधिकार प्रदान करता है।
- (५) मालिकों के साथ एक विशेष रियायत की गई है, जिसे इम रियायत के स्थान पर यदि न्याय का प्रदर्शन कहें तो श्रिषक उपयुक्त होगा। इसके श्रन्तर्गत मालिक को किसी कर्मचारी को, जब कि क्षगड़ा, निर्णयार्थ विचाराधीन हो, इस क्षगड़े से श्रसम्बद्ध किसी दुराचार के लिये निकाल देने श्रयवा सजा देने का श्रथिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मालिक को श्रांमशुक्त श्रीमक को एक मास का पारिश्रमिक देना पड़ेगा श्रीर श्रपनी श्राज्ञा के लिये श्रधिकारियों की श्रमुक्ति लेनी होगी। इससे कारखानों में श्रमुशासन ठीक रहने की श्राज्ञा को जाती है।

इस कानून का सबसे बड़ा दोष यह है कि सरकार को श्रीबोगिक निर्णया को परिवर्तित कर देने का श्रिषकार दे दिया गया है। बड़ी कठिनाइयों के पश्चात् मालिकों श्रीर श्रिमकों के पारस्परिक विरोधी हितों पर सममौता हो पाता है श्रीर यदि ऐसे सममौतों को बदल देने का श्रिषकार सरकार को प्राप्त है तो इससे मामलों के श्रीर श्रिषक उलम जाने का भय है। कानून में ऐसा प्रबन्ध है कि सरकार को परिवर्तन सम्बन्धी श्राज्ञाश्चों को ससद के समज्ञ १५ दिन की श्रवधि तक के लिये रस्खा जाय जिसके मीतर प्रस्ताव द्वारा ससद उसे स्वीकार करे श्रयवा श्रस्वीकार कर दे, इससे स्थिति के सुवार की श्राधा नहीं की जा सकती। वास्तिविक वात तो यह है कि यह जानते हुये कि संरकार को अपने इच्छातुकूल निर्णय वदल देने का अधिकार प्राप्त है मगड़ा जिन पत्नों के बीच है वे अपनी बात पूरी-पूरी व्यक्त न करेंगे और जल्दी सममोता न करेंगे। कानून की अच्छी बात यह है कि अब मगड़े में पड़े हुये दोनों पत्नों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे किसी सममौते के निर्णय पर इस्तान्तर कर सकते हैं। इस मगड़े को किसी पत्त निर्णायक को फैसला करने के लिये सौंप सकते हैं। इस प्रवन्ध के अतिरक्त यह कानून गिरी द्वारा प्रस्तावित संयुक्त रूप से सममौता करने की योजना को कोई स्थान नहीं देता। यदि गिरी के अभिस्ताव इसमें समिलत कर लिये गये होते तो अभिक और मालिक के हितों को बिना कोई हानि पहुँचाये ही पारस्परिक सममौते की सुविधा कुछ अधिक ही सम्भव हुई होती।

श्रीचोगिक श्रनुशासन संहिता (Code)—१६५७ में मारतीय श्रम कान्फ्रेन्स की स्थायी श्रम-क्षमित ने 'श्रीचोगिक श्रनुशासन सहिता' श्रपनाई जिसे कर्मचारियो तथा नियोक्ताश्रां के सघो ने भी स्वीकार किया। इससे भारत में श्रीयोगिक सम्बन्धों के सुधारने की श्राशा की जाती है। इसके श्रनुसार कर्मचारी तथा नियोक्ता भविष्य में होने वाले क्तमहों को पारस्परिक पत्र-त्यवहार, सममौता तथा श्रपनी इच्छा से बीच-बचाव करवा के हल करने के लिये वाष्य हैं। इसके श्रन्तर्गत श्रमिक तथा नियोक्ता 'धीरे काम करो' की चाल, तालाबन्दी, विना नोटिस के इहताल, धमकी तथा श्रनुशासन हीनता के श्रन्य रूप (जो प्राय-श्रीचोगिक क्तमहों के कारण होते हैं) को नहीं श्रपनार्येंगे।

मार्के की बात तो यह है कि सहिता में इन्हें लागू करने तथा इसके परिग्राम आकने की व्यवस्था भी है। १६५८ में केन्द्र में लागू करने तथा आँकने के लिये एक छोटी सस्या का निर्माण क्या गया। यह सस्या विभिन्न समूहों से अशतः या न लागू होने, निर्ग्य, अधिनियम तथा सममौता आदि के दोषपूर्ण ढग से या देर से लागू होने के सम्बन्ध में विवरण एक करेगी। सघ के अम मन्नालय ने राज्य सरकारों से २० फरवरी १६५८ तक तथा भविष्य म प्रतिमाह की दस वारीख तक प्रश्नावाल के उत्तर के रूप में स्वना देने की प्रार्थना की थी। अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने की दिशा में यह एक प्रभावपूर्ण कदम है। अधिनियम पास करने तथा सहिता स्वीकार करना ही काफी नहीं है। भविष्य में इसके अनुसार काम होने के लिये यह आवश्यक है कि उसके लागू करने तथा लागू न होने के वार्रणों पर कठोर हिन्ट रखी जाय।

## ष्ठभ्याय ३२

# ट्रेड यूनियन

भारत में अभिक ख्रान्दोलन बहुत पुराना नहीं है। यद्यपि २० वीं शताब्दी के ख्रारम्भ में भारत में ट्रेड यूनियन थीं परन्तु उनका कार्यचित्र बहुत सीमित था ख्रीर वह उन कार्यों को नहीं करतो थीं जिनकी एक ट्रेड यूनियन से ख्रेपेंचा की जाती है। भारत में इनका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ ख्रोर जो कुछ प्रगति हुई भी है वह ख्रनेक कारणों से सन्तोपजनक नहीं कही जा सकती। अभिकों में किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सगठित होने की भावना होने के लिए यह ख्रावश्यक है कि उन्हें इस प्रकार के सगठन की ख्रावश्यकता प्रतीत हो। १८ वीं सदी में ब्रिटेन में ख्रीचोगिक क्रान्ति हुई ख्रीर उसके पश्चात् कुछ देशों में उसकी पुनरावृत्ति हुई। परन्तु भारत ने ख्रव तक हस प्रकार की ख्रीचोगिक क्रान्ति का ख्रनुभव नहीं किया है। यदि ख्रीचोगिक क्रान्ति हुई होती तो उससे अभिकों के सगठन की ख्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती ख्रीर एक अभिक सगठन वन जाता। ख्रीचोगिक क्रान्ति से ख्रनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती जिनकी पूर्ति के लिए अभिको का सगठित होना ख्रावश्यक हो जाता। भारत के ख्रोचोगिक विकास से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं परन्तु यह समस्याएँ उतनी तीव नहीं हैं जितनी ख्रीचोगिक क्रान्ति होने पर होती।

श्रनेक कारणों से भारत में श्रीमक श्रान्दोलन का विकास नहीं हो पाया है,
(१) यह पहले कहा जा चुका है कि भारत की श्रधिकतर श्रीमक जनता निरहर
है और उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी है। श्रीमक भाग्य पर विश्वास करता है और
यह मानता है कि स्वय प्रयत्न करके वह श्रपनी स्थिति नहीं सुधार कर सकता है।
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थिति नहीं सुधार कर सकता है।
इस भावना से प्रेरित होने के कारण वह श्रपनी स्थिति सुधारने की श्रावश्यकवा प्रतीत होती श्रीर उसे यह जात हो जाता कि स्वय प्रयत्न करके वह श्रपनी
स्थिति कोबहुत सीमा तक सुधार सकता है। ऐसा श्रनुभव कर वह इस उद्देश्य
की पूर्ति के लिए श्रपने श्रन्य श्रीमक साथियों को सगठित कर सकता था। यदि
भारतीय श्रीमक भी पाश्चात्य देशों के श्रीमकों की तरह भौतिकवादी होता तो वह
निरह्नर होते हुए भी सगठित हो सकता था परन्तु भारत में निरह्नरता श्रीर भाग्यवाद के कारण ही श्राज तक श्रीमक का प्रभावशाली सगठन नहीं हो पाया है।

श्रमिक प्रान्दोलन सम्बन्धी श्रनेक कार्यवाहियों के होते हुए भी भारतीय श्रमिक की व्यक्तिगत भावना कम नहीं हो पाई है।

- (२) भारत का श्रीय गिक श्रीमक केवल काररानों पर ही निर्भर नहीं है। बीच-बीच में वह गाँव जाता रहता है श्रीर फिर काम करने कारखानों में त्रा जाता है। समान हितों की पूर्ति के लिए सगठित होने में उनके स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति सब से बड़ी बावक रही है। इधर चुछ वपों से स्थिति में कुछ परिवर्तन हुशा है श्रीर शुद्ध श्रीयोगिक श्रीमक के एक वर्ग का उद्भव हो रहा है।
- (३) श्रमिकों के पारिशमिक में वृद्धि हुई है परन्तु इसके साथ ही रहन-सहन के व्यय म भी वृद्धि हुई है। श्रमिक श्रवीत की तरह प्राव भी ट्रेट यूनियन के लिए योड़ा स चन्दा देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। यदि उसे सगठन का लाभ मात्म होता तो ट्रेट यूनियन की सदस्यता के लिए प्रावश्यक चन्दा देने से वह पीछे नहीं हरता।
- (४) भारत के उद्योगपित भी प्रीद्योगिक विकास के प्रारम्भ काल के प्रत्य देशों के उत्योगपितयों की तरह ट्रेंड यूनियनों का विरोध करते हैं जोर यह श्रमुभव करते हैं कि ट्रेंड यूनियन उनकी प्रतिह्न्ही शक्ति है। यदि उद्योगपित कुछ श्रोर विचारपूर्ण दिष्टकीण श्रपनाते तो इस श्रान्दोलन की बहुत प्रगति हो गयी होती। इसर कुछ वर्षों से उद्योगपितयों ने श्रीद्योगिक क्तगड़ों के निपटार के लिए श्रीर उत्योग में शांति बनाये रखने के लिए ट्रेंड युनियनों का महत्व समक्ता है।
- (५) वर्तमान में मारतीय अिमक खंबों पर स्वय श्रीमकों का नहीं विलक्ष वाहरी लोगों का नियत्रण है। यदि द्रेड यूनियनों का नेतृत्व स्वय अिमकों के हाय में होता तो वह श्रीमकों के हित में ट्रेड यूनियनों का सगठन करने का महत्व समस सकते श्रीर इससे श्रीमक श्रान्दोलन तेजी से वह सकता या। परन्तु नेतृत्व स्वय अिमकों के हाय में नहीं है श्रीर वाहरी लोग ट्रेड यूनियनों का उपयोग श्रपने राजनीतिक स्वायों की पूर्ति में करते हैं। उनकी दृष्टि में श्रीमकों की स्थिति में सुवार करना गीण विषय होता है। इसीलिए श्रीमक सोचते हैं कि ट्रेड यूनियनों का संगठन करने से विशेष लाभ नहीं है। भारतीय ट्रेड यूनियन संगठन में यह दोष होने से ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र विकसित नहीं हो पाया है श्रीर श्रीमकों में शिचा-प्रसार श्रीर स्वास्थ्य स्वन्धी कोई कार्यवाही नहीं की ला सकी है। भारतीय ट्रेड यूनियनें श्रीषकतर स्वर्धिण प्रवृत्ति की है। यह एक प्रकार से इन्द्रताल करने की श्रीर भालिक या सरकार के विरुद्ध श्रान्दोलन करने की एजेन्सी के रूप में कार्य करती हैं। इस नीति के कारण भारतीय ट्रेड यूनियनों का कार्यचेत्र बहुत सकी श्रीर गाया है।

१६५५-५६ में (जिस अद्यंतन वर्ष के आँकडे प्राप्त हैं) भारत में ७८६ अभिक सब थे जिनके सदस्यों की सख्या २२% लाख थी। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा कि १६५२-५३ से रिजिस्टर्ड अम-सब तथा उनकी सदस्य सख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सबों के इस विकास के होते हुए भी रिजिस्टर किये हुये अभिक सबों के कुल सदस्यों की सख्या उद्योगों में कार्य करने वाले अभिकों की कुल सख्या का अश्च मात्र ही है।

रजिस्टर्ङ	श्रम-संघ	तथा	उनको	सदस्य-सख्या
-----------	----------	-----	------	-------------

वर्ष	श्रमसघ का सख्या		दस्यों की कुल संख्या
	 रजिस्टर्ड	 सूचना देने वाले	
१६५० ५१	३७६६	२००२	१७,५६,६७१
१६५१-५२	४६२३	२५५६	१६,६६,३११
१६५२-५३	४६३४	२७१८	२०,६६,००३
१९५३ ५४	६०२६	<b>३</b> २९५	२१,१२,६९५
१९५४-५५	६६४८	<b>३११</b> ३	२१,७०,४५०
१९५५-५६	७८४६	9 हे ३ €	२२,२५,३१०

### कानूनी व्यवस्था

ट्रेड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने का उद्देश्य ट्रेड यूनियन की व्याख्या करना, उसके कर्तव्यों छोर उत्तरदायित्व को निश्चित करना छोर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में उनकी रक्षा करना है। कानून यह निश्चित करता है कि उद्योगपित ट्रेड यूनियन को मान्यता देंगे छोर ट्रेड यूनियन सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने पर किसी श्रदालत में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा। ऐसा कानून न होने पर उचित कार्यवाही भी श्रन्य श्रयों में श्रवेध घोषित की जा सकती है।

१६२६ का भारतीय ट्रेंड यूनियन कानून—१६२६ के भारतीय ट्रेंड यूनियन कानून में १६२८, १६४२ और १६४७ में सशोधन किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन इसी कानून द्वारा सचालित होती हैं। १६२६ के कानून के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन की यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी सगठन चाहे अस्यायी हो या स्थायी यदि अभिक और उद्योगपित या मालिक और कर्मचारियों के बीच अध्वा कर्मचारियों के बीच पारस्परिक उचित सम्बन्ध बनाये रखने के लिए बनाया गया

हो, या वाणिज्य-व्यापार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिए बनाया गया हो या दो या दो से श्रिधिक सवा का सगठन हो तो उसको भी ट्रेड यूनियन ही कहा जायगा। इस प्रकार ट्रेड युनियन की श्रेणी में श्रिमिकों श्रीर मालिकों टोनों के सगठन सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी यूनियन के ७ या उससे अधिक सदस्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त रिजस्ट्रार के पास यूनियन की रजिस्ट्री कराने के लिए आवेटन पत्र भेज सकते हैं। परन्तु इसके लिए यह स्रावश्यक है कि यृनियने निर्धारित शर्ते पूरी करती हो। यह भी व्यवस्या की गई है कि रजिस्टर्ड यूनियन के पटाधिकारियों में से आधे वास्तव में उस उन्नोग के कर्मचारी हों जिसके श्रमिको की यह यृनियन हैं। इससे बाहरी व्यक्तियों को ट्रेड यूनियन सगठन में काफी स्थान मिल जाता है। यदि यूनियन के कान्त समात उद्देश्य को आगे बढाने के लिए किये गये समक्तीते के सम्बन्ध में क्तासा हो तो यह कानून युनियन के पटाविकारियों श्रीर सटस्यों की फीजदारी के टावे से सुरचा करता है। इसके साथ ही यदि मालिक श्रीमकों के क्यांडे के बारे में कोई कार्य किया गया है और शिकायत केवल यह है कि इस प्रकार के कार्य से अन्य श्रमिक द्वारा काम छोड़ दिये जाने की सम्मावना है या यह न्यापार में ग्रथवा किन्हीं लोगों की नियुक्ति में इस्तचेष करना है तो इस कान्न की वजह से यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों पर दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है।

इस कानून द्वाग रिजर्टर्ड ट्रेड यूनियन के कीय पर प्रतिवन्य लगाया गया है। इस कीय का केवल उन्हीं कार्यों में उपयोग किया ना सकता है जिनका कानून में विवरण दिया गया है परन्तु एक पृथक् कीय का निर्माण करने की अनुमति दे कर यूनियन के सदस्यों के नागरिक एवम् राजनीतिक हितों की भी रन्ता की गई है। प्रत्येक ट्रेड यूनियन का प्रतिवर्ष अपना हिसाब छुपे कार्मों में मरकर राजस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ ही आय-व्यय का आदिट किया हुआ विवरण भी मेजना पड़ता है। यदि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन क (१) आधकतर सदस्य आन्यमित इड़ताल में भाग हो, (२) यूनियन का कार्यकारिणी अनियमित इडताल की सलाह दे, उससे सहयोग करे या उसे महत्वार, या (३) यूनियन का अधिकारी गत्वत वक्तव्य प्रकाशित कराए, तो कानून के अनुसार ये कार्यवाहियाँ अनुचित सम्मी जाँयगी और इसके लिए दण्डस्वरूप यूनियन की मान्यता वाग्स ले लेन की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर यदि उन्योगित या मालिक (अ) अपने अमिनों के ट्रेड यूनियन सगठित करने के अधिकारों में इस्तचेप करे या पारस्परिक सहायता एवम् सुरज्ञा के उद्देश्य स की जाने वाली कार्यवाही में गड़वड़ी पेदा कर, (व) किसी ट्रेड यूनियन के

बनने या उसके प्रशासन में हस्तान्तें करे, (स) किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के अधिकारी को ट्रेंड यूनियन का अधिकारी होने के कारण नौकरी से निकाल दे या उसके साथ मेद-भाव की नीति वरते, श्रीर श्रमिकों को कानून के श्रन्तर्गत चलने वाली किसी जाँच इत्यादि कार्यवाही में गवाही देने पर या श्रारोप लगाने पर ाकाल दे, या (द) मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ सममीता वार्ती करने से न्कार कर दे या कानून में दो गई सुविधाओं को देने से इन्कार कर दे तो उद्योगपित श्रथवा मालिक की यह कार्यवाही कार्त की हिष्ट मे श्रनुचित समकी जायगी। अनुचित कार्यवाही के लिए उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करने की व्यवस्था की गई है।

इस कानून से ययापि ट्रेड यूनियनों को मान्यता मिली श्रोर उनको कानूनी श्चाचार दिया गया फिर भी इससे भारत में ट्रेड यूनियन सगठन का विकास करने का उद्देश्य पूर्या न हो सका । इसमे अनेक दोप हैं: (१) इस कान्त्र के अनुसार ट्रेंड यूनियन केवल मजदूरों के सगठनों तक ही सीमिन नहीं है, जैसा कि होना चाहिए था, परन्तु इसमे मालिको और उद्योगपितयों के सगठन मी शामिल किये गये हैं। इससे अनावश्यक गहवड़ी पेदा हो जाती है, (२) कानून के अतु-सार ट्रंड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना श्रानिवार्य नहीं है। इस कानून में उन यूनियनों को भारतीय दगड विधान के अन्तर्गत फीजदारी के मुकदमें से छूट नहीं दो गई है जिनकी रजिस्टा नहीं हुई है, इससे ट्रेंड यूनियन सगठन कमजोर पड़ जाता है, श्रीर (3) कानून क अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के सामान्य कोष श्रीर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित कोष मे श्रवैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सामान्य कोप से व्यय करने के लिए श्रत्यन्त सकीर्षा

श्चाचरण-सहिता (code of conduct)—यद्यपि भारत में अम सर्वा की बाहुल्यता है तथा विभिन्न सवो (federations) के सामजस्य सहित काम व्यवस्था की गई है। करने की कोई आशा नहीं है फिर भी मई, १९५८ में नैनीताल में भारतीय-श्रम-काफ़िल्स में माग लेने वाले अम सगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये

इस सहिता के श्रनुसार "(1) किसी उद्योग श्रथवा इकाई के कर्मचारी श्राचरण सहिता से श्राशा का सचार होता है। को श्रपनी इच्छा की यूनियन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता होगी। इस सबव में कोई दवाव नहीं डाला जायगा। (11) यूनियन की दोहरी सदस्यता नहीं होगी। प्रतिनिधि-यूनियनो के सम्बन्ध मे यह तय किया गया कि उपर्युक्त नियम की स्त्रीर क्योच्या की जाय। (111) श्रम-संघों के प्रजातत्रीय दग पर कार्य करने को स्त्रीकार किया जाय तथा त्रादर की दृष्टि से देखा जाय। (iv) ट्रेंड यूनियन के पदाधिकारियों तथा प्रशासकीय निकायों के चुनाव नियमित तथा प्रजातत्रीय उग पर होने चाहिये। (v) श्रमिकों की श्रज्ञानता और पिछडेपन का कोई सगठन कायदा नहीं उठायेगा। कोई सगठन श्रनावश्यक माँगे नहीं पेश करेगा। (v1) हर एक सब जातीयता व प्रान्तीयता से दूर रहेगा। तथा (v11) श्रम संघीं के बीच कोई हिसा, दबाव, धमकी तथा व्यक्तिगत वटनामी श्राटि नहीं होगी।" यह सब बढे ही श्रच्छे प्रस्ताव हैं किन्तु इनकी सकता इस पर निर्भर करेगी कि ट्रेड-यूनियन उन्हें कहाँ तक श्रपनाती हैं।

अस सुघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई वेन्द्रीय श्रिधिनियम नहीं है। भारतीय श्रम-काफ़ोन्स ने द्रेड यूनियन के मान्यता देने के सम्बन्ध में निम्न कसौटियाँ प्रस्तावित की । "(1) जहाँ एक से श्रधिक यूनियन हो वहाँ मान्यता प्राप्त करने वाली यूनियन रजिस्ट्री के बाद कम से कम एक वर्ष तक काम करती रही हो किन्तु जहाँ एक ही युनियन हो वहीं यह शर्त लागू नहीं होगी । (11) सस्थान के कम से कम १५% श्रामक उसके सदस्य हों । (111) किसी स्थानीय चेत्र में एक युनियन को किसी उद्योग का प्रतिनिधि युनियन भाना जा सकता है वशर्ते कि चेत्र में उद्योग के २५% अमिक टसके सटस्य हों। (1v) यूनियन को मान्यता मिलने पर, दो वर्ष तक स्थित में कोई सुधार नहीं होना चाहिये। (v) जन किसी उद्योग श्रथवा संस्थान में श्रनेक यूनियन हो तो सबसे श्रधिक सदस्य-सख्या वाली यूनियन को मान्यता देनी चाहिये। (v1) किसी चेत्र में विसी उद्योग की प्रतिनिधि यूनियन को देश भर के सस्थानों के श्रमिकों का प्रति-निधित्व करने का अधिकार है। विन्तु यदि किसी सस्थान के श्रमिकों की यूनियन में उसके ५०% श्रमिक सदस्य है तो उसे केवल स्थानीय हित के मामलों पर कार्य-वाही करने का श्रिषकार होना चाहिये। (v11) प्रतिनिधित्व का रूप निर्ण्य करने के लिये छानवीन करने के ढग को श्रीर श्रधिक पर्याप्त कर देना चाहिये। जब इस सम्बन्ध में वैमागिक छान-वीन के परिणाम दलों को मान्य न हों तो चेन्द्रीय अम सम के प्रतिनिधियों से निर्मित एक सिभित को इस प्रश्न की जॉच कर इसे हल करना चाहिये। इस कार्य के लिये केन्द्रीय अस सगठन विभिन्न मागों के लिये ग्रावश्यक धन श्रीर व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। यदि इससे काम नहीं होता तो प्रश्न का निर्णय न्यायालय के सुपुर्ट कर देना चाहिये। (v111) सिर्फ वे युनियन मान्यता पा सर्वेगी जो श्रौद्योगिक श्रनुशासन सहिता को मानेगी। (1x) उन श्रम-सर्घों के सम्बन्ध में जा श्रम के चार वेन्द्रीय सगठनों से सम्बन्धित नहीं है, इस प्रकार श्रलग से विचार करना चाहिये।" यह कसौटियाँ

विस्तृत तथा सुविचारित हैं। यदि इनका अनुसरण किया गया तो ट्रेड यूनियनो की नींव दृढ हो जायँगी। प्राप्त अनुसव के आधार पर वे इस विषय पर अधि-नियम बनाने का आधार भी बन सकती हैं।

भविष्य की योजना-वर्तमान में भारतीय श्रमिक श्रान्दोलन में कुछ श्राघारभूत दोष हैं श्रौर स्थिति सुघारने के लिए इन दोषो को दूर करना बहुत श्रावश्यक है। इस समय एक ही उद्योग मे एक ही दोत्र से अनेक ट्रेड युनियनें हैं। बहुत ग्राधिक ट्रेंड यूनियन होने से श्रमिक का पत्त कमजोर पढ़ जाता है श्रीर श्रीमक के श्रिधिकारों की रच्चा में भी वाधार्ये श्रा जाती हैं। इसलिए ट्रेड युनियनो के सगठन को सगठित करने श्रीर इनको एकता के सूत्र में बॉधने की श्रत्यन्त त्रावश्यकना है। यह त्रावश्यक है कि एक त्रेत्र में स्थित किसी मुख्य उद्योग में अभिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक मे श्रिधिक ट्रेंड युनियन न हो। यदि एक दोत्र के विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले सभी श्रामको का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ट्रेड यूनियन होती तो सर्वोत्तम होता । परन्तु यह समव नहीं है क्योंकि कभी-कभी विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की समस्याएँ भिन्न होती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अमिक एकता के सूत्र मे नहीं वंघ पाते हैं जब कि ट्रेड यूनियन ऋान्दोलन की सफलता इनकी एकात्मकता पर निर्भर करती है। भारत के ट्रेड यूनियन चगठन में दूसरा बड़ा दोष यह है कि यह अपनी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः हस्ताल मे और मालिको से सामूहिक माँगे करने में लगा देते हैं। बहुत कम ऐसी यूनियने हैं जिन्होंने अपने कार्यचेत्र को व्यापक बनाया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सामृहिक रूप से मॉग करना और इड़ताल करना ट्रेंड यूनियनो का महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु इसके साथ ही अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में ट्रेड यूनियन का कार्यक्रम और विस्तृत करने की, श्रावश्यकता है। इसमे वयस्कों की शिचा, सहकारी-श्रान्दोलन का गठन, जनसेवा कार्यं इत्यादि भी सम्मिलित निये जाने चाहिये। इससे ट्रेड युनियनों की उपयोगिता बढ जायगी।

ट्रेड यूनियन श्रान्दोलन का एक बहुत बड़ा दोष वेन्द्रीय सगठनों का बाहुल्य है। कुल १५३१ यूनियनों में से श्राई० एन० टी० यू० सी, ए० श्राई० टी० यू० सी० हिन्द मनदूर समा श्रीर यूनाइटेड टी० यू० सी० से संयोजित यूनियनों की सख्या क्रमश. ६१७, ५५८, ११६, श्रीर २३७ श्रीर उनके सदस्यों की सख्या क्रमश: ६७२ लाख, ४२३ लाख, २.०४ लाख, श्रीर १५६ लाख १६५६ के श्रन्त में थी। इन केन्द्रीय सगठनों को एक शक्तिशाली सस्या में सगठित करना सम्मव है। इसमें सदेह नहीं कि इन केन्द्रीय सगठनों के राजनीतिक

## श्रध्याय ३४

रेल यातायात भारतीय रेलों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १८५३ में भारतीय रेलवे लाइन की लम्बाई केवल २० मील थी, १६०० में यह २४,७५२ मील हुई ग्रीर १६५१ ५२ में इसका प्रसार ३४,११६ मील श्रीर १६५६ ५७ में ३४,७४४ मील हो गया, जिसमें ३४,२६१ मील सरकारी प्रवन्य के म्रान्तर्गत या। १६०० म भारतीय रेलों से १७ करोड़ ५० लाख यात्रियों ने यात्रा की, ४ करोड़ ३० लाख टन सामान दोया गया । १९५६-५७ में यात्रियों की संख्या १३८ करोड़ ३० लाख ग्रीर ढोये जाने वाले माल की मात्रा १२ करोड़ ५० लाख टन हो गई । १६ ग्रप्रैल १९५३ को भारतीय रेलों ने ग्रपनी उपयोगी सेवाग्रों के १०० वर्ष पूरे किये। ठीक १०० वर्ष पूर्व १६ अप्रेल १८५३ को प्रथम भारतीय रेल ने बम्बई शहर से याने तक २१३ मील की दूरी तय की थी। यद्यपि रेलवे सगठन में कुछ भुटियाँ हैं श्रीर कुछ दाव भी है परन्तु फिर भी जिस गति से उसने प्रगति की है उस पर भारतीय

मुख्य विशेषताऍ-भारतीय रेलवे के विकास में कुछ उल्लेखनीय विशेष-रेलवे गर्व कर सकती है। ताएँ हैं। (१) भारत में रेल का कार्य निजी उद्योग के रूप में प्रारम्भ किया गया। रेल-उत्प्रीग करने वालो को सरकार ने कुछ सुविघाएँ दीं जैसे इन्हें भूमि सुफ्त दी गई ग्रीर पूँजी की वस्ली की गारन्टी दी गई। इससे रेलवे निर्माण के व्यय में वृद्धि हुई ग्रीर सारे देश को इसका भार वहन करना पड़ा। ऐसे समय में जब रेलों का निर्माण करने के लिए उद्योगपित पूँकी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये यह सुविघायें देना समवत ग्रात्यन्त ग्रावश्यक या परन्तु यदि इस ग्रोर किचित् सावधानी से कार्य लिया जाता तो इनको काफी कम भी किया जा सकता था। रेलो का प्रवन्ध निजी उद्योगपितयों के हाथ में होने से इसकी काफी त्रालोचना की गई है। ग्रालोचकों ने प्रबन्धकों द्वारा पत्तपात किये जाने ग्रीर कच्चे माल के निर्यात तथा तैयार माल के श्रायात के भाड़े में रियायतें देने की शिकायतें कीं, क्योंकि बन्टर-गाही से देश के भ्रन्द्र सामान लाने और बन्दरगाहों तक सामान पहुँचाने के लिए रेल के भाडे की दर अन्य दरों की अपेक्षा कम रखी गई थी। एकवर्थ समिति (Acworth Committee) ने सुम्ताव दिया कि राष्ट्रीय हित में रेल के निजी उद्योग को क्रमश. राष्य को श्रपने हाय में ले लेना चाहिए। इस दिशा में १६२५ में प्रथम प्रयास किया गया। सरकार ने ईस्ट इिल्डिया श्रीर जी, श्राई, पी, रेलवे को श्रपने श्रधिकार में ले लिया परन्तु इस प्रक्रिया को पूरा होने में २० वर्ष लगे ग्रार नहीं तक विटिश भारत का सम्प्रत्य है १९४४ में निनी उत्योग समाप्त कर राज्य ने इसको पूर्णतया श्रपने श्रधिकार में ले लिया। १९५० में सघीय वित्तीय एकीकरण के पश्चात् भूतपूर्व रियासतों की रेलों को भी भारत-सरकार ने श्रपने हाय में ले लिया श्रोर श्रव रेलवे एकमाश राजकीय उद्योग पन जुका है।

रेल उद्योग निजो उद्यागपितयों के द्राय में होने की श्रापेक्षा सरकार के द्राय में होने से श्रानेक लाम हैं—(श्र) इसने साधनों की श्रानाप्रथम द्रानि श्रीर विभिन्न रेलवे-प्रक्वों में प्रतियोगिता समाप्त हो। जाती है। (व) राजकीय उद्योग दोने के कारण देश के श्रोद्योगिक श्रीर कृषि साधनों के कितास के महत्व को हाँ के रणते हुए रेल के माडे की उचित दर निश्चित की जा। सकती है श्रीर (स) इस उप्योग से जो लाम द्रोगा वह केन्द्रीय धन कोष में जमा हा सकता है।

- से जो लाम होगा वह देन्द्रीय धन कांप मे लमा हा सरता है।

  (२) दो विश्वयुद्धी के कारण, १६३० की श्राधिक मटी श्रीर १६४७ में देश के विभाजन में रेलों पर बहुन भार पड़ा है श्रीर उसरा परत्पर सम्बन्ध भी देश के विभाजन में रेलों पर बहुन भार पड़ा है श्रीर उसरा परत्पर सम्बन्ध भी विच्छिल्ल हो गया। युद्ध के कारण रेलों की वार्य समता पर श्राधिक भ्यान नहीं दिया गया, पुराने कल-पुजा इत्यादि को नहीं बटला गया श्रीर नई मशीनें लगाने की योजना स्थिगित कर टी गई। दितीय पिश्वयुद्ध के समय ⊏ प्रतिशत मीटर-गेंज के इखन, १५ प्रतिशत मीटर-गेंज के बैगन, ४ हजार मील लग्भी पटरियाँ श्रीर ४० लाख स्लिपर मारतीय रेलां से लेकर मध्यपूर्वी देशों को मेजे गये। युद्ध के समय रेलों के सामान का श्रीर पर्टार्था का श्रत्यधिक उपयोग किया गया, उनको न बटला जा सका श्रीर न नया सामान लगाया जा सका। इनमें रेलों श कार्य- स्थान पाकिस्तान के मार्ग चेला गया श्रीर गरणाथियों को लाने-पहुचान के कार्य में रेलों पर श्रीर श्राधिक भार पढ़ा। यत कुछ वर्षों में रेला पर श्रावश्यकता में श्रिधिक भार कुछ कम किया गया है, पुराने सामान को बदला गया है श्रीर मामान की मात्रा बढ़ाई गई है परन्तु इस दिशा में सभी बहुत कुछ करना शेप है।
- (३) श्रतीत में इसनी, वायलरों, हिन्मों इत्यादि के लिए भारतीय रेलों को श्रायात पर निर्भर करना पड़ता था। इससे देश का बहुत-सा धन विदेश चला जाता या श्रीर देश को निदेशा विनिमय साधनों को गम्भीर ज्ञित होती थो। परन्तु इधर कुछ वर्षों से स्थिति में सुधार हुआ है श्रीर श्रम देश में ही इस्रम हिन्ने इत्यादि बनने लगे हैं। भारतीय कारखानों में हिन्मों का उत्पादन बढ रहा है श्रीर रेलवे की श्रावश्यकता की श्रिधिकाधिक पूर्ति की जा रही है। चित्त-रखन के इस्रम बनाने के कारखाने में इस्रम के लगभग ७० प्रतिशत कल पुर्जी

का उत्पादन किया जाता है श्रीर नेवल ३० प्रतिशत का श्रायात करना पहता है।

- (४) भारत में अनेक रेलें थीं परन्तु पुनर्वर्गी-करण योजना लागू करके इनको ७ चेत्रों में सगठित किया गया है। एकीकरण से पिहले मारत में ३५ रेलवे थीं जिनमें से २२ सरकार के अधिकार में थीं। रेलवे बोर्ड की जॉच करने के लिये नियुक्त समिति (१६५०) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भारतीय रेलों को ६ चेत्रों में सगठित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया। दिल्ला रेलवे का १४ अभेल १६५१, पिश्वमी और केन्द्रीय रेलवे का ५ नवम्बर १६५१ को और शेप तीन उत्तरी, उत्तरी पूर्वोत्तर और पूर्वी रेलवे का १४ अभेल १६५२ को उद्वाटन हुआ। पहली अगस्त १६५५ से सातवें चेत्र का निर्माण पूर्वी रेलवे को दो चेत्रों में विभाजित करके किया गया: (१) पूर्वी रेलवे जिसमें पुरानी ई० आई० आर० का मुगलसराय तक का भाग (सियालदह हिवजन को लेकर) सम्मिलत थी, और (२) दिल्ला पूर्वी रेलवे को निम्न सात चेत्रों में विभाजित कर देया गया।
- (१) दिल्ला रेलवे—इसमे एम० एनड एस० एम०, एस० आई० और मैस्र राज्य रेलवे सम्मिलित है।
- (२) पश्चिमी रेलवे इसमें भ्तपूर्व बी० बी० सी० आई०, सौराष्ट्र, राजस्थान तथा जैपुर रेलवे और जोधपुर रेलवे का कुछ भाग सम्मिलित कर दिया गया है।
- (३) केन्द्रीय रेलवे—इसमें जी० आई० पी०, एन० एस०, सिन्ध्या नाज्य और घौलपुर राज्य रेलवे सम्मिलित हैं।
- (४) उत्तरी रेलवे—इसमे ई० पी०, जोधपुर श्रीर बीकानेर रेलवे, ई० श्राई० श्रार० के इलाहाबाद, लखनऊ श्रीर सुरादाबाद दिवीजन श्रीर बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे का दिल्ली रेवारी-फजिलका चेत्र सम्मिलित है।
  - (५) दिक्क्णी पूर्वी रेल वे—इसमें बी० एन० श्रार० शामिल है।
- (६) उत्तरी पूर्वी रेलवे—इसमे श्रो० टी० एन्ड श्रासाम रेलवे, ई० श्राई० श्रार० का कुछ भाग श्रीर बी० बी० एन्ड सी० श्राई० रेलवे का फतेइगढ चेत्र है।
- (७) पूर्वी रेखवे—इसमें पुरानी ई० त्र्याई० का मुगलसराय तक का माग त्रीर सियालदृह हिवीजन सम्मिलित है।
- ७ चेत्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हुन्ना है कि जिसमें विभिन्न चेत्रों का कार्य कम न्यय के साथ चलाया जा सके स्त्रीर विभिन्न चेत्रों में यातायात की

उचित मुविधा प्राप्त हो। विभिन्न च्रेनों के रेल पधों का विस्तार २३३१ मील से लगाकर (जो कि पूर्वी रेलवे का है) ६३३६ मील तक है। (जो कि उत्तरी रेलवे का है) इस बात का ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम हटाना पढ़ें और केवल ईस्ट इडिया और बीo बीo एन्ड सीo आईo रेलवे को छोड़कर जहाँ तक सम्भव है वर्तमान रेलवें व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए एक या दूसरे माग में सम्मिलित कर लिया जाए।

रेलवे के पुनवंगीकरण योजना की श्रालोचना की गई है। कहा गया है कि (अ) पुनर्वर्गीकरण से एक रेलवे के कर्मचारियों को दृसरी रेलवे में परिवर्तित किया गया, उनमें श्रानेक को नोकरी से श्रालग कर दिया गया, (व) इससे कम से कम टो रेलवे—ईस्ट इन्डियन श्रीर बी० बी० एन्ड ० सी० श्राईं० गेलवे—तोड़ी गर्ड जिसमे अनेक जिंटल समस्याएँ उत्पन्न हो गई, श्रीर (स) इससे भारतीय न्यापार एवम् उद्योग को प्रनेक कठिनाइयाँ हुई हैं। रेलवे के पुनर्वर्गीकरण जैसे बढे परिवर्तन में योदा-बहुत सम्बन्ध विच्छेत होना श्रीर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से ऋलग कर दिया जाना श्रमियार्थ था। उसमे बचा नहीं जा सकता था। परन्तु इतने से ही पुनर्वर्गीमरण भी योजना श्रवाछनीय श्रीर त्रानुपयुक्त सिद नहीं होती क्यांकि इस योजना के लागू हो जाने से जो लाभ होंगे वह इससे होनेवाली हानियों की अपेना नहीं अधिक हैं। यह भी कोई तर्क नहीं, जैसा कि कुछ सम-तियों ने मुक्ताव दिया था, कि यह योजना पाँच वर्ष बाद लागू की जाय श्रीर सरकार को इस समय इसे स्थागत कर देना चाहिए था। यदि पनवीगीकरण की नीति स्वीकार कर ली गई है तो इसे जितना शीष्र लागू किया जाय उतना ही अञ्चा है। इस योजना के लागू करने से तीन निश्चित लाम हैं --(क) इससे वह सभी लाभ पास हो सर्केंगे जो प्रबन्य ब्यारस्था बढे पैमाने पर सगठित करने म होते हैं। (ख) इससे एक ही काम श्रनेक बार करने से छुटकारा मिल जायगा और हानिकारक प्रतियोगिता मी नहीं हो सकेगी और (ग) इससे रेलवे वी श्रार्थिक स्थिति दढ होगो श्रीर कार्य के स्तर में सुधार किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के पञ्चात् रेल के भाडे श्रीर किराये की दर, यात्रियों की सुविधाश्री, मजदूरों के वेतन श्रीर सुविधाश्रों इत्यादि के सम्बन्ध में सारे देश में समान नीति लागू नी जा सकेगो। यह कोई छोटी सफलता नहीं।

(५) भारतीय रेलवे की कार्यचमता अभी भी बहुत नीचे स्तर की हैं। युद्ध आरभ होने के पूर्व की कार्यचमता के स्तर तक भी अभी भारतीय रेलवे नहीं पहुँच सकी है। इस बात का प्रमाण माल के दिव्यों का चक्कर लगाकर अपने स्थान पर पहुंचने में दस श्रमवा श्यारह दिन के समय का लगना है जर कि युद के पूर्व के राल नी दिन लगते थे। रेल के सामान के श्रमान के श्रतिरक्त कार्य प्रवन्ध में देर लगना भी माल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर से पहुँचने का प्रधान कारण है। समय की पाउन्दी तथा माल के हिन्मों के प्रयोग स्वक सुक्त नहुत नीचे स्तर पर हैं। छोटी लाइन की स्थिति श्रीर भी विगदी हुई है।

भारतीय रेलवे में कोयले का व्यय भी बहुत अधिक है। वर्तमान समय म रिष्म लाख उन कोयला ३०३ करोड़ रुपये की लागत का प्रयोग में आता है। रेलवे प्यूल बाच कमेटी ने विभिन्न उपायों द्वारा २०% बचत करने का सुकाव दिया था। यदि यह सम्भव हो सका तो ग्लवे को प्रति वर्ष ६ करोड़ रुपये वी बचत अगले पाँच वर्षों में सम्भव हो संग्रेगी। इसक अतिरिक्त अन्य मितन्यायता क बचत अगले पाँच वर्षों में सम्भव हो संग्रेगी। इसक अतिरिक्त अन्य मितन्यायता क उपायों का पूरी जाँच होनी चाहिए और इनका प्रयोग होना चाहिये जिसमें रेलवे अन व्यय रम हो जाय तथा आय में वृद्धि हो जायगी।

रेलचे की वित्त ज्यवस्था—एकपर्णं समिति के सुमान पर १६२४ न रेलवे की जित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से भिन्न कर टी गई। १६२४ के प्रथक्करण समसीते में यह व्यवस्था की गई थी कि रेलवं में लगी हुई पूँजी पर न्याज के साथ ही न्यवसाय में लगी पूँजी का एक प्रतिशत. श्रुतिरिक्त लामीश का दे भाग श्रीर रेलवे के सुराज्ञत कीए में ३ करोड़ चपया जमा कर देने के बाट बचे श्रास्यधिक श्रातिरिक्त लामीया का है भाग राजस्व के नाम में जमा करेगा। महत्वपूर्ण रेलों की हानि का भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। रेलवे के सुरित्तित कीय में से सामान्य राजस्व दिया नायगा श्रीर यदि ग्रावश्यकता पदी तो हुर-फूट फे लिये पूँ जी ग्रोर रेलचे की ग्रार्थिक स्थिति को टढ बनाने के लिए भी इसमें से धन लिया जायगा। रेलव के सामान को बदलने श्रीर नया सामान मंगाने के लिए १ प्रपंत १६२४ में हूट-फूट के लिए एक भिन मुरिक्ति कीप बनाया गया है। केन्द्रीय सरकार की सामान्य वित्त व्यवस्था से रेलवे की वित्त व्यवस्था को भिन्न फरने क दो लाम हुये हैं (अ) स्रतीत में सामान्य वित्त की कठिनाइयो श्रीर श्रिनिश्चतता पर ही रेलवे का भित्रष्य निर्मर करता था। इस कारण वह पहले से ही श्रपने विकास की योजना निर्माण नहीं कर पाते ये। अनुमान है कि पृथनकर्ण समसीते के अनुसार वित्त व्यवस्था थकपृ कर देने में रेलवे की स्थिति अधिक सुरक्षित हो जायगी श्रीर इसके प्रसार करने के लिये तथा इसमें सुधार करने के लिए निश्चित घन राशि प्राप्त हो जायगी। (य) श्रतीत में यह निश्चित नहीं या कि वेन्द्रीय राजस्य को रेलवे से कितनी श्राय होगी परन्तु पृथककरण समकौते के श्रनुसार इसके श्रन्तर्गत धन राशि निश्चित

प्रयक्करण सममौते में सशोधन किया गया जो १ अप्रैल, १६५० से लागू हुद्र्या । इस संशोधन के ग्रनुसार (१) जनता को रेलवे का हिस्सेदार माना गया है ग्रौर जो ऋण ली गई पूजी रेलवे में लगाई गई है उस पर सरकार को (श्रर्यात् जनता को) ४ प्रतिशत का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा । यह धन रेलवे की श्राय में से केन्द्रीय सरकार को दिया जाता है। पहले १६२४ के समसीते के ब्रनुसार सामान्य राजस्व में दी जाने वाली घन राशि की कोई निश्चित निर्धारित मात्रा नहीं थी पर इस सशोधन से यह निश्चित कर दिया गया कि रेलवे में जो कुछ पूँजी लगी है उसका एक निर्घारित प्रतिशत सामान्य राजस्व में दिया जायगा। (२) समस्तोते में रेलवे विकास कीप स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस कोष से (श्र) नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने में वित्तीय सहायता दी जायगी। इन नई लाइनों से श्राय होना श्रावश्यक नहीं है, (व) यात्रियों की सुविधा के लिए न्यय किया जायगा श्रोर (स) श्रम कल्याग कार्य इत्यादि में व्यय किया जायगा । (३) सममौते के सशोधन के श्रानुसार प्रथम पाँच वर्षों में रेलवे के टूट-फूट कोष में कम से कम १५ करोड़ रुपया सम्रह किया जाना चाहिए और शेष म्रतिरिक्त म्राय से एक ऐसे कोप का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे श्रार्थिक सन्तुलन रखा जाय। रेलवे का सामान अधिक महँगा होने के कारण १९५० के प्रथक्करण समझौते के पश्चात् से टूट-फूट के कोष में ३० करोड रुपये की नियत घनराशि सप्रह कर दी गई है।

पुराने समसौते में सामान्य राजस्व के अन्तर्गत जमा की जानेवाली धन-राशि निश्चित नहीं यी परन्तु नये समसौते में यह रकम निश्चित कर दी गई है। इससे रेलवे का योजनावद विकास किया जा सकता है, सुरिच्चित कीप का निर्माण किया जा सकता है और पुनर्वास तथा प्रसार का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा सकता है। टूट-फूट के कीप में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली धनराशि में इस आधार पर वृद्धि कर दी गई है कि कल पुजों, मशीन, इखन इत्यादि बदलने के ज्यय का मूल ज्यय से और उपयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के जीवन काल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अब तक इन्हीं दो आधारों पर टूट-फूट के कीप में योगदान निर्धारित किया जाता था। नये समसौते के अनुसार ज्यय का भार बढ़ाने का उद्देश्य रेलवे को अत्यधिक पूँजी सप्रह करने से गेकना है। विकास कीप की स्थापना के समय यह बात मान ली गई है कि भविष्य में रेलवे का विकास केवल ज्यवसायिक दृष्टिकोण से सीमित नहीं रखा जा सकता है। देश के आर्थिक विकास में रेलवे को जिसका राष्ट्रीकरण किया जा चुका है एक महत्वपूर्ण अौर निश्चित योगदान देना है।

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् रेलवे की वित्तीय स्थिति में निरन्तर सुधार हुआ है। वास्तविक आय जो कि १६४८-४६ में ४२३४ करोड रुपये थी १९५१-५२ में बढ़कर ६१ ७५ करोड़ रुपया हो गई है श्रीर १९५८-५९ के वजट के अनुसार ७६ ६२ करोड़ रुपया अनुमान किया गया है। १९५१-५२ में सामान्य श्राय के प्रति ३३'४१ करोड़ रुपया टिया गया या श्रीर १६५८-५६ में ४६ ५८ करोड़ रुपयों के टिये जाने का श्रनुमान किया गया है जब कि १६४८-४६ मे केवल ७ ३४ करोड़ रुपये ही दिये गये थे। इतने पर भी रेलवे की अतिरिक्त आय जो कि १६४८-४६ में १६.६८ करोड़ रुपये थी १६५१५२ में बढकर २८३४ करोड़ रुपये और १९५८-५९ के बजट अनुमान के अनुसार २७ ३४ करोड़ रुपये मानी गई हैं। यह सारी रकम विकास कीय में जमा कर दी गई है जब कि १६४८ ४६ में केवल १० करोड़ रुपये ही इस कीष में जमा किये गये थे। रेलवे की वित्त स्थिति में इस सुघार का कारण यह है कि (१) यात्रियों की सख्या में श्रीर माल के यातायात में वृद्धि हुई है श्रीर (२) रेलवे के किराये तथा भाडे में भी चृदि हुई है। देश के ग्रोद्यागिक विकास में वृदि होने से श्रीर श्राधिक कारोबार बढाने से रेलों द्वारा यातायात भी बढा है। वास्तव में रेलें बढते यातायात की माँग पूरी कर सकने में असमर्थ रही हैं, यातायात बढने के साय ही रेल का किराया भी बढ़ा है। १६४८ ४९ में रेलवे को यात्रियों से ८४ करोड़ रुपयों श्रीर १६५१-५२ में १०६ ८८ करोड रुपयों की स्त्राय हुई। १६५८-५६ के बजट में लगाये हुए श्रनुमान के श्रनुसार यह श्राय १२४.७३ करोड़ र० होगी। इसी प्रकार माल होने से आय जो कि १९४८-४९ मे १०८-२६ करोड़ रुपये थी, १६५१-५२ मे बढकर १५६ ७६ करोड़ रुपये हो गई श्रीर १६५८-५६ में श्रनुमान है कि २५० ५० करोड़ रुपये हो जायगी।

रेल से यातायात कम होने का वास्तविक कारण १९५१-५२ और १९५५-५६ के बीच यह था कि १९४८ से रेल के किराये में और माढे में अत्यिवक वृद्धि हुई है। युद्ध के तुरन्त पश्चात् रेल के किराये और माढे में इतनी वृद्धि नहीं हुई जिसका यातायात पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ता परन्तु १९५१ में रेल के किराये तथा भाढे में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से यात्रियों और माल से होनेवाली आय कम हो गई।

	यात्रियों से होनेवाली त्र्राय (करोड़ रुपयों में )	माल ढोने का श्राय (करोड रुपयों मे )
\$EX5-8 <b>E</b>	EX 00	१०८ २६
१९४९-५०	<b>८६</b> २६	१३० ३७
१९५०-५१	६७ ८४	१४३.०१
<b>શ્દપ્ર</b> -પ્ર <b>ર</b>	१०६ दप	<b>१</b> ५६ <i>७६</i>
<b>શ્દપ્ર-પ્ર</b> ર	१००′३८	१४६'१२
<b>१</b> ६५३-५४	₹ <i>0</i> 0°00	१४७ १८
<b>{</b> E५४-५५	१ <b>०२'</b> ६२	१५८८६
१९५५-५६	१०७ ७१	<b>१८०°</b> २८
१ <b>९५</b> ६-५७	११६′३३	२०३ ६६
१९५७-५८ (सशोधित)	१ <b>२०</b> ′६ <i>०</i>	२३१ ००
१९५८-५९ (वजट)	१२४ ७३	२५०•५०

पिछले तीन वर्षों मे यात्रियों तथा माल के यातायात में श्रीदोगिक विकास के कारण वृद्धि होने से स्थिति में उन्नति हुई है।

रेलवे के किराये और भाडे की दर सम्वन्धी नीति—रेलो के किराये श्रीर माढे का उद्योग, ज्ञीप, ब्यापार श्रीर वाणित्य के विकास में श्रीर स्वय रेलों की विचीय स्थित को रह बनाने में बहुत महत्व है। यदि माड़ा श्रीधक होगा तो उससे उत्पादन व्यय पर प्रमाव पहेगा श्रीर उत्पादन व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के श्रीबोर्गाकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि भाडे की दर निश्चित करने में शुंट रह गई है तो उससे उद्योगों के स्थाननिर्धारण पर श्रीर श्रीद्योगीकरण के ढाचे पर बुरा प्रमाव पड़ता है। रेल का किराया श्रीर भाड़ा श्रिषक होने से यातायात को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, यातायात रेलों के द्वारा न होकर ग्रन्य साधनों से होता है जिसमे रेलवे को र्ज्ञात पहुँचती है। यह भाडा कम है तो इसमे श्रीचोशिक तथा कृषिक विकास में ग्रवश्य सहायता मिलेगी, परन्तु यदि इससे रेलवे को हानि पहुँचती है श्रीर वह श्रपना व्यय पूरा करने के पश्चात उचित लाम नहीं उठा सकती है तो यह न्यावसायिक सिद्धान्तों के प्रतिकृत तथा श्रन्यित है। इस लिए रेल के विराये तथा भाडे की दर सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे रेलवे के हित में और उद्योग तथा कृषि के हितो में सन्तुलन स्यापित किया जा सके श्रीर जिससे देश में प्राप्त साधनों के श्राधार पर देश का कृषि तथा श्रीद्योगिक विकास पूरी तीवता से किया जा सके, पचवर्षीय योजना में

निर्घारित लच्य पूरे किये जा सर्के ग्रोर रेलवे का वित्ताय स्थिति पर्याप्त सुदृढ रखी जा सके।

१६४८ से पहले भारत में रेलवे के किराये तथा भाडे की दरे इसके अनुकूल नहीं भी ग्रीर उसकी कड़ो ग्रालोचना की गई है

- (१) भारतीय रेलवे मे किराये तथा भाडे की दर निर्धारित करते समय दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। इससे लम्बी यात्रा करने वालों को या काफी दूर सामान मेजने वालों को बहुत श्रिषक भाडा देना पड़ता था। इससे माल की खपत के लिए बाजार की स्थित तथा श्रन्य कारणों के श्रनुकुल रहते हुए भी उत्योगों को कच्चे माल के खोतों से दूर स्थापित करने को प्रोत्साहन न मिला। उद्योग के लिए रेलों के भाडे की दर कुछ कम थी, साथ ही विशेष स्टेशनों के बीच रियायतें भी दी गई थों परन्तु इससे ब्यापार श्रीर उद्योगों को विशेष लाभ नहीं हुआ।
- (२) भारत से कच्चे माल को विदेशों को निर्यात छौर विदेशी माल के आयात को सस्ता करने के लिए रेलवे ने देश के किसी भाग से बन्दरगाहों तक छौर बन्दरगाहों से देश के अन्य उपयोग के केन्द्रों तक का किराया कम रखा। भारत में विदेशी सरकार की इस घुटिपूर्ण नीति से भारतीय उद्योग को चांत पहुँची छौर विदेशी उद्योगों को छिषक प्रोत्साहन मिला।
- (३) मारतीय रेलवे के कुछ मार्गों में किराये की दरें मीलों के आधार पर निश्चित की गई श्रीर ब्लाक रेट की प्रणालो श्रपनाई गई श्रर्थात् एक रेल द्वारा कम दूरी तक माल ढोने पर प्रांत मील श्रिधिक किराया वस्ल किया गया। इसका उद्देश्य यह या कि माल कुछ दूर ढोने के बाद दूसरी रेल से न ढाया जाय बिलक लम्बी यात्राश्चों में उसी रेल का उपयोग करें। इसके परिणामस्वरूप ब्लाक-रेट नीति से बचने के लिए सामान को आयश्यकता से श्रधिक दूर तक ले जाना पड़ता था। इससे लागत बढती थी श्रीर यातायात क साधनों पर भी श्रमुचित भार पड़ता था।
- (४) एक ही नामान के लिए विभिन्न रेला की विभिन्न दरे थीं। इनसे व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। इसके ग्रातिरिक्त विभिन्न सामनों के भाडे की दरों में भी काफी ग्रातर था।

१६४८ में रेल के किराये तथा भाडे की दरो की कुछ त्रुटियाँ दूर कर दो गई। किराया प्रति मील की दर से निर्धारित किया गया, साथ ही अनाज, दाल, आटा श्रीर बीज इत्यादि की दरें निश्चित कर दो गई। इसके लिए सर्वप्रयम दूसरे समूह की रेलो—श्रासाम, ईस्ट इन्डिया, जी० श्राई० पी० श्रीर श्रो० टी० रेलवे—

में टर निश्चित की गई ब्रोर तत्पश्चात् पहले समूह की रेलों में। दोनो समूहों में इस ब्रातर का कारण यह था कि दूसरे समूह की रेलों की दरें पहले समूह की रेलों की श्रपेक्षा पहले से ही कम यीं ब्रीर यिंट दोनों समूह की रेलों की टरें एक साय बढ़ा टी जातीं तो इससे श्रिषक कठिनाई होती है।

रेल के किराये तथा भाडे की दरों में इस प्रारम्भिक परिवर्तन के पूरे हो जाने के बाद र अप्रैल १६५२ को कुछ और परिवर्तन किये गये। दूरी के आधार पर किराये की दर निर्धारित करने की नीति त्याग दी गई। शेष दरों का प्रमाणी-करण हुआ और इस प्रक्रिया में उनमें वृद्धि की गई। लोहे और इस्पात उद्योग के लिए निश्चित विशेष दरों को खत्म करके नई संशोधित दरें लागू भी गई जो स्टैन्डर्ड तटकर की दर से कम रखी गई। दिख्य को चीनी के यातायात की रियायती दरें खत्म कर दी गई। कोयले के भाडे में ३० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई अप्रेर यह कहा गया कि पहले की दर व्यय से बहुत कम थी। १६५५-५६ के बजट में भाडे की दरों में अन्य परिवर्तन किये गये। अन्न तथा खाद का प्रति गाइी भाड़ा कम कर दिया गया तथा विभिन्न श्रेणियों का जात्रियों के लिये किराया ६०० मील से अधिक दूरी के लिये कम कर दिया गया और प्रथम ३०० मील की वात्रा का किराया बढा दिया गया पर ३०१ से ६०० मील की दूरी के किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इससे रेलवे को श्रनावश्यक हानि उटानी पड़ी जब कि रेलों द्वारा कुल जिवने सामान का यातायात होता है उसका ४० प्रतिश्वत कोयला होता है। यह सुक्काव दिया गया कि कोयले के माड़े की दर श्रिषक होने से रेलवे को लाम होगा इससे रेलवे के हितों की रज्ञा होगी।

रेलवे भाडा पर जाच कमेटी—जो कमेटी जून १६५५ में नियुक्त की गई पो उसने १६५८ के श्रारम्भ में सरकार को श्रपनी रिपोर्ट दी। सरकार के विचाराधीन होने के कारण श्रमी तक वह कार्यान्वित नहीं की गई है। कमेटी यह सिपारिश की है कि किराये की दरे निम्मतर श्रेणी से-उच्चतम श्रेणी तक वृद्धिमान श्राधार पर होनी चाहिये। इस विचार, को कार्यान्वित करने के लिये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सबसे सरल श्रीर सतीपमद ढग श्राधार रूप में एक दर निश्चित करना श्रीर अन्य दरें इसी पर के प्रतिशत वृद्धि के श्राधार पर नियत करना होगा। इसके लिये कमेटी ने एक सामान्य दर जो कि मान द्यड होगा नियत किया है जिसे (Class 100 rate) वर्ग १०० दर कहा जायगा। कमेटी ने वर्तमान वर्ग ६ को सबसे श्रिषक सुविधाजनक समान्य (Norm) श्रीर श्रन्य वर्गों को इसके ऊपर तथा नीचे माना है। इसी प्रकार गाड़ी भर माल की दरे

भी १०० के नये वर्ग के श्राधार पर प्रतिशत श्रकों में व्यक्त किये गये हैं। प्रत्येक वर्ग कित ने प्रतिशत होगा व्यक्त कर दिया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिये गाडो- भर माल के श्राधार पर वर्गोकरण किया जाना चाहिये श्रीर साथ ही साथ छोटी मात्राश्रो (smalls) का भी वर्गीकरण होना श्रावश्यक है। कमेटी ने छोटी मात्रा में माल की टरों में गाड़ी भर माल की टरों की श्रपेता १५ से लगाकर ३६ प्रतिशत वृद्धि करने की श्रमुर्मात दी है।"

कमेटी ने यह मत दिया था कि (1) सीमा कर रह कर दिये जाने चाहिये पर नयं दरों के बनाते समय इस बात को विचाराधीन रखना चाहिये, (11) थोड़ी दूरी के लिये श्रतिरिक्त भागा वस्ताना श्रनुचित समका जाना चाहिये, (11) घाट सम्बन्धी श्रीर स्थानान्तरस्स सम्बन्धी वम्ली बन्दी कर दी जानी चाहिये। (11) भाडा वस्त्रने की न्यूनतम दूरी २५ मील तक बढ़ा दी जानी चाहिये। चोड़े माल एक रेल श्रयवा रहे रेला द्वारा ले जाया जाय एक ही बार उसकी बुकिंग होनी चाहिये, (11) माल गादियों द्वारा भेजे जाने के लिये न्यूनतम वजन २० सेर होना चाहिय, श्रार (11) जो १ २० १२ श्रा० प्रति गाडो माल पर न्यूनतम सम्मिलत वस्ती की जाती है बन्द कर दी जानी चाहिये।

कमेटी ने यह भी सिवारिश का है नि ३०० मील नी द्री की प्रथम चीढी की भांड की दर नियत नरने के लिये चार भागी में बाट देना चाहिये, जैसे १ से २५ मील तक, २६ से ७५ मील तक, ७६ से १५० मील तक, ग्रीर १५१ से ३०० मील तक। स्पष्ट रूप में उसने यह सिवारिश की है कि "कर्मचारियों की यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो सके योड़ी योड़ी दूरी के लिये रेल का प्रयोग न किया जाय वरन् श्रन्य परिवहन के साधनों का उसके स्थान प्रयोग बढ़े।"

इस बात को विचाराधीन रखते हुये कि (१) दरे लम्बी दूरी तक लेजाने वाले माल पर भार स्वरूप न हो, (२) उनमं सीमा सम्बन्धी तथा श्रन्य सम्बन्धों में जा वसूली की जाती है सम्मालत हो, (३) श्राय श्रीर व्यय के बीच जो ३०० कराइ रुपयो का व्यवधान है उनसे पूरा हो जाय। कमेटी ने निम्न दरों के लागू किये जाने की सिपारिश की है.—

	मील	प्रतिमील प्रतिमन पाइयो की इकाई में दरे
₹	से २५ तक	३६०
२६	से ७५ तक	१ <b>.</b> ४०
७६	से १५० तक	१ २०
१५१	से ३०० तक	,

मील	प्रतिमील प्रविमन पाइयो की इकाई से दरे
३०१ से ५०० तक	০ দে
प्०१ से ८०० तक	0,00
<b>८०१</b> से १२०० तक	03.0
१२०१ से आगो तक	० ५०

कमेटी की सिपारिशें (1) रेलवे की माडे की दरों को सरल श्रोर सुगम बना देगी श्रीर इस प्रकार उनकी श्रनेकों जिटलतायें श्रोर श्रसगतायें दूर हो जायेंगी, (11) उनसे रेलवे की श्राय में वृद्धि होगी जिसकी बहुत श्रावश्यकता है, (111) रेलवे को इसमें श्रावश्यक सुविया प्राप्त होगी श्रीर सहक द्वारा छोटी दूरी क परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु उद्योगों का उत्पादन लागत पर रेल के विराये का श्रत्यिक श्रोर श्रनुचित भार पडेगा। वर्तमान मूद्रा स्फीति की दशा में इससे हानि होगी। बाहर भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में तो किराये की बही हुई दरें भारतीय माल की विदेशी बाजारों में स्पर्धा शक्ति ज्ञीण कर देगी जिससे विदेशी विनिमय वी कठिनाहयों के श्रीर भी श्रिषक बढ़ जाने का भय होगा।

जनवरी १९४८ में यात्रियों के लिए भारतीय रेलों में प्रति मील किराये की समान दर निश्चित की गई। परन्तु कुछ रेलों में किराये की दर कम थी। उसे भी अन्य रेलों की किराये की दर के समान ही कर दिया गया। १९५१ में रेल का किराया २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

१९५५-५६ के वजट में किराये की दरें निम्न प्रकार निश्चित की गई हैं

	पाइ प्रांत माल प्रति यात्री			
~	१ -१५० माल	१५१३०० माल	३०१ मील ग्रौर इसमे ग्रिधिक	
एथर वन्होशन श्रेणी	38	38	32	
प्रथम श्रेणी	१ <b>=</b>	१६	<b>१</b> ५	
दितीय श्रेणी (मेल/एउसप्रेस)	११	<b>₹</b> ०₹	<b>٤</b> ٦	
,, ,, (साधान्स्)	3	E	۳ <sub>۹</sub>	
त्रितीय श्रेणी (मेल/एउसप्रेम)	) ६ <u>१</u>	६	પ્	
,, ,, (साधारण)	પ્	પૂ	¥3	

रेलों का पुन मगटन रुग्ने में गेल के किराये तथा शांडे में जो सुधार किया जा सका उससे (१) रेल का किराया निर्वारत करने का ख्राधार सरल हो गया, (२) रेल की दरों में जा ख्रव्यवस्था फैनी हुई थो वह दूर हो गई, ख्रीर (३) रेलवे का विकास कर मकने के लिए श्रिधिक धन भी प्राप्त हुया। रेल के किराये के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सुधार करने से किराये श्रीर भाडे में कुछ वृद्धि कर दी गई है। इससे उन्होंगों का उत्पादन च्यय वहा है श्रीर यात्रियों तथा सामान के यातायात से प्राप्त होनेवाली श्रीय घटी है।

रेलों की कार्य प्रगाली में टोप—फेडरेशन श्राफ इन्डियन चेम्बर्फ श्राफ कामर्छ ऐड इन्डस्ट्री ने श्रपने स्मारक पत्र में भारतीय रेलवे कार्य प्रणाली के श्रनेकों टोपों श्रोर मुटियां की श्रोर प्रान श्राकृत्य कराया था, जैसे गाड़ी के डिब्बों का न मिलना, पहुत दिनों तक माल के यातायान में प्रतिवन्य का लगाना, यातायात में श्रिव स्मय लगना, थांडे सामान के यातायान की सुविधा में श्रामान, माल के डिब्बों की माँग करने श्रीर प्राप्त करने में समय का लम्बा न्यवधान, कुछ जरशनों में लाइनों का श्रमाव, बड़ी श्रीर छोटो लाइनों में परस्पर श्रयला पटली की मुविधाशां का श्रमाव, कुछ रास्तों में लाइनों का श्रमाव, मार्ग में माल का चोरी होना श्रोर पों जाना या चोरी हुए माल की हानि निश्चित फरने में श्रीधक देर लगना, श्रीर कर्मचारियों को कार्यन्नमता में सामन्यत श्रमाय रत्यादि। इस स्पन्य में मुख्य समस्या तो यह है कि कृषि श्रोर उद्योगों की श्रावश्यकता के श्रमुसर रेलवें की सुविधा कम है। इस देश में श्राधिक व्यवस्था विकासोनमुद्ध है, यहाँ कृषि एच उद्योगों के उत्यादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है श्रीर वर्तमान यानायात मुनिधाय पूर्ण्क्षिण श्रपर्यान्त हैं। फेडरेशन ने इस सम्बन्ध में निम्न सिफारिश की है।

- (१) रेल वे के विस्तार त्रोर सुगर के लिए ४०० करोड़ रुपयों का प्रथम पंचवर्णीय योजना में नियत करना अपर्याप्त था श्रीर कम से कम १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष श्रीर ग्राधिक नियत करना चाहिये था। इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्तर्गत १४८० करोड़ रुपये व्यय किये जाने की माँग रेल वे बोर्ट ने की थी जिमे योजना आयोग ने घटा कर ११२५ करोड़ रुपये कर दिया है। यह घन भारतीय रेल वे की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त न होगा।
- (२) प्रथम योजना में रेलवे के वर्तमान सामान की मरम्मत पर श्रधिक जोर दिया गया था जो गन बीस वर्गों में बदले भी नहीं गये। यद्यपि यह बहुत श्राप्तर्यक है, फिर भी श्रव श्रधिक ध्यान रेलवे के विस्तार पर दिया जाना चाहिये। विस्तार इतना होना चाहिये कि न केवज यातायान की श्रावश्यकतायें ही पूर्ण हो सर्के, वरन् भविष्य में बढ़ी हुई श्रावश्यकता को भी पूरा कर लेने की पर्याप्त शिक्त हो। यद्यपि द्वितीय योजना में श्रिधिक जार विस्तार पर दिया गया है फिर भी यह श्रयांत है।

- (३) रेलवे के कार्य करने की इत्सता में वृद्धि होनी चाहिए। देश के श्रीद्योगीकरण में प्रोत्साहन देने के लिये श्रावश्यक है कि रेल द्वारा यातायात की सुविधा सस्ती हो। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि रेलवे का चालू व्यय कम हो। भारतीय रलवे की कुल किराये भाडे से प्राप्त श्राय १६४८ को २१३ करोड़ रुपयों से बहकर ४०७४८ करोड़ रुपये १६५८-५६ के इला में श्रतुमान की गई है। कुल व्यय १७३ करोड़ से बहकर २६८ ३५ करोड़ रुगये हो गया है। इससे वह पता लगता है कि वही हुई श्राय का श्राधकाश व्यय की वृद्धि में प्रयुक्त हुश्रा है श्रीर यह सम्भव है कि किराया श्रीर भाड़ा घटाया जा सन।
- (४) माल के यातायात में सुविधा प्रदान करन के लिए ऐसे श्रस्थायी उपायों से कार्य लेना चाहिए जैसे मुकामा घाट, श्रागरा ग्रार कोनरमती श्रीर श्रम्य स्थानों पर मशीनों द्वारा माल को स्थानान्तिक करना, कन्वयर प्रणालो का प्रयोग करना श्रीर मुगलसराय वाल्टेयर, भागलपुर श्रादि जक्शानों पर माल की गाड़ियों की श्रदला-बदली की गति में तीव्रता लाना नयों कि इन स्थानों पर वड़ी भीड़ रहती है। जिन रास्तों पर लाइनों के श्रभाव के वारण किटनाई हो जाती है वहाँ श्रिषक लाइनों का खेलना श्रोर विशेष प्रकार के माल के दिन्हों की सख्या बढ़ाना।
- (५) व्यापारियों को मार्ग में माल के चोरी हो जाने छोर तो जाने छोर बहुत देर में हानि मिलने के कारण बहुत किटनाई उठानी पढ़ती है। रेलने व्यवस्था को इस प्रकार की सभी हुई चोरियों ने रोकने छोर रेलने नर्मचारियों की श्रसावधानी छोर चरित्रहीनता के नारण गड़ी में माल के जाने नी रोक थाम के लिये विशेष प्रयक्षशील होना आवश्यक है। हानि जल्टी चुकाने के उपायों को भी सोचना आवश्यक होगा। विभाग का विकेन्द्रीय करण नरना, कुल माल के खो जाने पर हानि हरन्त चुकाना, इस दशा पर कि यदि एक वर्ष के भीतर ही भीतर माल मिल गया तो पाया हुआ हर्जा रेलने को नापिस हे देनें। ऐसी क्ले मस एडवाइसरी कमेटी नी स्थापाना करना जिसने सटस्य उन उद्योगों और न्यापारों के प्रतिनिध हो जो क्लेग्स विभाग के नर्मचारी से सम्मन्धत है आदि कुछ ऐसे उपाय है जिनके प्रयोग में लाने से रेलने के दोप मिट सकते हैं।

रेलवे के कर्मचारी इस बात का प्रयन्न कर रहे हैं कि रेल के कार्य प्रगाली की समता बढ जाय श्रीर सुविधार्ये भी बढ जॉय, माल की सधी चोरियों श्रीर उनके खोने पर रोक याम करने के लिए रेलवे करपशन इनक्वारी कमेटी की नियुक्ति की गई है जो शीम ही श्रपनी रिपोर्ट सरकार के समझ उपस्थित करने वाली है। रेलवे के चालू व्यय पर रोक थाम में सहायता करने के लिये श्रीर रेलवे का विकास करने के लिए, विकास में वैज्ञानिक ढग का प्रयोग करने के लिये तथा वड़ी-बड़ी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिये, जिन्हें पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत रेलवे को पूर्ण करना है, रेलवे बोर्ड की सदस्य सख्या चार के स्थान पर पाँच कर दी गई है।

योजना के अन्तर्गत-प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड रुपये के व्यय का प्रस्ताव रेलवे के नये सामान के क्रय करने तथा पुराने की मरम्मत के के लिये किया गया था। वास्तव में यह श्राशा की जाती है कि प्रथम योजना के समाप्त होने तक लगभग ४३२ करोड़ रुपया व्यय हो जायगा। गन्त्रयानाटि श्रीर श्रीर खर्चाग स्यत्र पर न्यय प्रस्तावित धन से बहुत श्रिधिक हो गया है। गन्त्रया-नाटिपर अधिक न्यय होने के कारण यात्रा श्रीर दलाई १९५३-५४ श्रीर १९५४ ५५ के बीच साढे श्राट प्रतिशत बढ़ गई श्रीर त्राशा की जातो है कि योजना के श्चान्तम वर्ष में नौ प्रतिशत वह जायेगी। प्रथम योजना के ग्रारम्भ के समय रेलदे के पास ८२०६ इन्जन, १६२२५ यात्रियों क डिब्बे ग्रौर २२२४४१ माल के हिन्वे थे। इनमे से २११२ इन्जन, ७०११ यात्रियो क डिन्वे श्रीर ३८५८४ माल के डिब्वे पुराने थे। प्रथम योजना में १०३८ इन्जनो स्रोर ५६७४ यात्रियों के डिब्वे श्रीर ४६१४३ माल के हिन्नों के क्रय करने का प्रवन्ध किया गया था। वास्तव में उपर्युक्त सख्या से कुछ श्रधिक इन्जन श्रीर माल के डिव्वे श्रीर कुछ कम यात्रियो के ।डब्वे प्रथम योजना के अन्तर्गत क्रय किए जा सकेंगे। इतनी अधिक मरम्मत त्रीर नये सामान के क्रय किए जाने के पश्चात भी भारतीय रेलवे का सामान बहुत पुराना श्रीर पुराने ढग का है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के श्रारम्भ मे ६२६२ इन्जन, २३७७६ यानियों के डिब्बे श्रीर २६६०४६ माल के डिब्बे काम मे श्राते हुये होंगे जिनमें से २८१३ इन्जन श्रीर ५३०५ यात्रियो के डिव्वे श्रीर ४६५६⊏ माल के डिब्बे बहुत पुराने विसे हुये होंगे श्रीर उनकेस्थान पर नये लाने श्रावरयक होंगे। इससे यह पता लगता है कि रेलवे के विस्तार की इतनी श्रावश्यकता होते हुये भी उनकी मरम्मत श्रीर उनके स्थान पर नये सामान लाने की जरूरत बहुत बड़ी है।

दितीय योजना के छन्तर्गत ११२५ करोड़ रुपया भारतीय रेलवे पर व्यय किया जायगा जिसमें से ७५० करोड़ सामान्य छाय में से, २२५ करोड़ रेलवे के छ्रवज्ञरण कोष से, १५० करोड़ रेलवे की छाय से प्राप्त होगा। रेलवे बोर्ड के १४८० करोड़ रुपये के व्यय किये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर १११५ रु० का व्यय किया जायगा।

द्वितीय योजना में १६०७ मील के रकाय के दुगने किये जाने का, २६५

द्योटी लाइन को बढी लाइन में परिवर्तित कर देने का, लगभग ८२६ मील तक विजली पहुँचान, १२६३ मील तक पीडप्वाल्स सुविधा देने का, ८४२ मील नई लाइन निछाने, २००० मील लाइन की मरम्मत करवाने श्रीर २२५८ इन्जनों को किन करने तथा ११३६४ यात्रियों के डिब्बों श्रीर १०७,२४७ माल के डिब्बों को त्रय करने ना श्रायोजन किया गया है।

मारतीय रेलवे १२ करोड़ टन माल के ढोने के स्थान पर १६५५-५६ में ११ करोट ५० लाख टन माल ढोयगी और इस प्रकार ५० लाख टन माल के द्वाये जाने की कमी रह लायेगी। यटि इतीय पोजना के ख्रन्त तक जो ६ करोड़ २ लाय टन माल के ढोये जाने की ख्रावश्यकता बह जायेगी उसका विचार किया जाय तो इम बह मबते हैं कि १६६०-६१ तक १८ करोड़ ८ लाख टन के ढोये जान की ख्रावश्यकता होगी। ऐसा मय है कि जितना धन रेलवे के विकास प्र लिये नियंत कर दिया गया है उसके प्रयोग से रेलवे इतना माल न ढो सके ख्रीर जिन मुविवाओं के प्रवान करने का इराटा किया गया है वे ख्रावश्यकता मे १०% गन्त्रयानाटि क सम्बन्ध में ख्रीर ५% श्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में कम कर देनी पड़े।

हितीय पचवर्णीय योजना के झाधार पर योजना झायोग के मतानुसार (मर्ड १६५८) "नो प्रायंक्रम १८९५ करोड़ रुपयों के व्यय का बनाया गया था उमने अप मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण १०० करोड रुपयों के झीर श्रिषक व्यय होने का श्रनुमान किया गया है। इस समय ११२५ करोड़ रुपयों की मात्रा व्हाट जा नहीं सकती। इसिलये रेलवे को योजना के श्रन्तर्गत पुछ विकास योजना यो को स्थित करना पड़ेगा। विदेशी विनिमम की किटनाइयाँ भी इसका एक प्रारण्ण होगी। जिन विकास योजना आर्थों को स्थितत करने का उराटा है वे (१) तम्यागम तिल्लुएम जेत्र तथा कलकत्ते के श्रन्तर्गत सियालदा चेत्र में बिजली पहुँचाने की भाजना, (२) मीटर गेज कोच फेक्ट्री (३), इन्टीगरल कोच फेक्ट्री के प्रसाधन विभाग तथा (४) गुना और उटजेन के बीच नई रेल के लाइन बिछाने की योजनार्य हैं।"

"ग्राने न्येय को पूरा पर लेने के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है यह श्राणा की जाती है कि १९६०-६१ तक रेल वे ४२० लाज टन माल ढोकर श्रातिरिक्त ग्राप्त प्राप्त कर संकर्ण। पर क्या पर्धाप्त पर्याप्त होगी। निश्चित कर से कहा नहीं जा सकता। विदेशी विनिमय तथा ग्रन्य कि कारण विकास योजना को कार्यान्वित करने में दील देने के कारण दुलाई की मात्रा योजना के श्रान्तिम वर्ष तक श्रारम्भ में किये गये श्रमुमान से जो कि ६१० लाख टन था म्म

हो जायगी पर हो सकता है कि ४२० लाख टन से अधिक हो। कुछ भी हो योजना में की गई रेल द्वारा माल ढोने की मात्रा के प्रतुमान में कुछ परिवर्तन तो ग्रवश्य ही होगा। जहाँ तक यात्रियों के ढोने के त्येय से सम्बन्ध है-स्थर्यात् 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि — यह सम्भवतः पूरी हो जायगी। १६५५.५६ की अपेक्षा श्ह्यूइ-पूछ मे रेल के यात्रियों मे प्रतिशत वृद्धि इ-७ हुई थी। अगर यहाँ रही तो

नेल में भीड़ की समस्या श्रीर भी श्रधिक खराब हो जायगी।" द्वितीय योजना मे भारतीय रेलवे की माल ढीने ग्रीर यात्रियों के ग्राने-जाने की शक्ति में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। परन्तु वृद्धि देश की आवस्य कता से बहुत कम सम्मव हो सकेगी। केवल सरकार को ही नहीं वरन् जनता को भी अधिक मात्रा में यातायात की सुविधा की आवश्यकता पडेगी। प्रथम योजना में भी जनता को यातायात की सुविधा में कमी का ऋतुमव हुआ था। द्वितीय योजना में तो स्थिति त्रोर भी खराब होगी। रेलवे के सम्बन्ध में यही सर्व प्रधान श्रालीचना है। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों तथा मूल्यों में वृद्धि होने पर भी योजना में रेलवे के विस्तार के प्रति व्यान श्रिषक रखना चाहिये था श्रीर व्यय के लिये अधिक धन नियत करना चाहिये था।

#### श्रध्याय ३४

### सहक यातायात

मारत में सहको का बहुत श्रमाव है। १६०० में सहकों की लम्बाई कुल १,७६,००० मील थी श्रोर १६५२ में २,५६,००० मील थी। प्रथम योजना के श्रन्त तक कुल सहकों की लम्बाई बढ़कर ३१६,००० मील हो गई जिसमें से १२१,००० मील पक्की सहके हैं श्रीर शेष कच्ची। एक ऐसे देश में निसका चेत्रफल १,१३६,००० वर्गमील है, जिसकी जनसङ्या लगभग ३५ करोड ७० लाख है श्रीर जिसके उत्योग तथा कृषि का काफी विकास हो सुका है २६५,००० मील सहके बहुत कम हैं। भारत में प्रति वर्गमील में बहुत ही कम सहकें हैं, श्रन्य देशा की नुलना में यह स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय है। भारत के प्रति वर्गमील चेत्रफल में सहको को लम्बाई ०२ है खब कि हन्गलैएड में २०, वेलाजयम में ३३, फ्रास में २४ श्रीर श्रमरीका में ११ है।

। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देश के श्राधिक विकास में सहकों का विशेष महत्व है। सडकें होने से ही ग्रामो से कच्चा माल ग्रोर कृषि उत्पादन कारखानो कस्त्रों श्रीर नगरों तक पर्द्वाया जाता है श्रीर बन्दरगाहों तथा कारखानों से माल आमी तक मेजा जाता है। देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियां के लिए सहकें यातायात की सुविधा पदान करती हैं। सब्कों की सुविधा से ही व्याक्त एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान काल में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए यातायात के द्रुतगामी साधनों की ख्रोर ख्रच्छी सडकों की ख्रत्यन्त ख्राव-रएकता है। रेलों तथा विमाना की सहायता से देश के वहे-महे नगरों श्रीर व्यापारी केन्द्रा से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है परन्तु देश के दूर-दूर के स्थानों तक पहुँचने के लिए श्रौर उनका लाम उठा सकने के लिए श्रन्छी सडकों का होना अत्यन्त आवश्यक है। युद्ध के समय यदि सडकें आरुछी हैं तो सेना नो शीब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है, युड़-सामग्री स्रावश्यक स्थानों तक पहुँचाई जा सकती है स्रौर इस प्रकार देश की शत्रु ने त्राक्रमण से रज्ञा की जा सकती है। नास्तव में भारत की कुछ पाचीन बडी सबकें इसी उद्देश्य से बनाई गई थों। यदि देश में अच्छी सबकों का जाल विछा हो तो उसका शाविकाल में तथा युद्ध के समय हर स्थिति में विशेष महत्व होता है।

श्रतीत में दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ते से मद्रास, मद्रास से वम्बई श्रीर चम्बई से दिल्ली को मिलाने वाली चार वही सहकों के चारों श्रोर छोटी बढी सहकों का जाल फैला हुआ था। इन चार बड़ी सहकों को वारहो मास कार्य में नहीं लाया जा सकता है। पुल न होने के कारण श्रीर टूट-फूट तथा सामान्यतथा स्थित खराब होने से इन सहकों का वरसात में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन बड़ी सहकों को देश के ग्रामों से मिलाने वाली प्रदेशीय सहकों तथा अन्य छोटी-छोटी सहकों की स्थित श्रीर भी खराब है।

देश की आन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सड़कें बढ़ाई जायं।

राष्ट्रीय सड़कें वर्तमान समय की भाँति केवल पूर्व से पश्चिम तक के च्रेत्र में ही

न फैलें वरन इनका प्रसार उत्तर से दिन्निया तक भी किया जाय। इसके साथ ही

इन सड़कों को और प्रदेशीय तथा अन्य छोटी सड़कों को सभी आहुतुओं में कार्य

में लाने योग्य बनाने की आवश्यकता है। मोटर यातायात के लिए भी कुछ

सड़कों का होना आवश्यक है। इसके लिए सड़कों के मोड सुगम होने चाहियें,

जहाँ से सड़क निकाली जाय वह भूमि पक्की होनी चाहिए और सड़कों को ककर

तया डामर या सिमेंट के प्रयोग से पक्का बनाना चाहिए। इन सड़कों की सतह
को चिकना होना चाहिये। इसके साथ ही वैलगाडियो तथा यातायात के अन्य

साधनों के लिए भी ऐसी सड़के होनी चाहियें जो मोटर की सड़क की भाँति अधिक

व्ययशील तो न हो परन्तु ऐसी हों जिनको वर्ष भर प्रयोग में लाया जा सकता

है। यह बहुत आवश्यक है कि सड़कों के निर्माण की सुसम्बद्ध योजना निर्माण

की जाय जिसमें बड़ी राष्ट्रीय सड़कों, प्रदेशीय सड़कों और आमों इत्यादि को

मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों को विशेष महत्व दिया जाय।

भारत में सड़कों के विकास की ख्रोर बहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके कई कारण हैं -—(१) सरकार ने छौर स्थानीय सस्था छों ने सहकों के विकास का महत्व नहीं समका। नगर पालिका छों छौर जिला बोडों की देख-रेख में अनेक सड़के हैं परन्तु इन सस्या छों ने सड़कों के विकास की ख्रोर उचित ध्यान नहीं दिया। प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने भी अन्य विकास कायों को इसकी अपेन्हा प्राथमिकता दी है। इघर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की आवश्यकता और इसके महत्व की ख्रोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान गया है और दोनों सरकारों ने इसके लिए योजनाएँ बनाई हैं, (२) सड़कों के निर्माण के लिए ख्रावश्यक बहुत प्रकार के सामान और मशीनो का भारत में अभाव है और इनका आयात करने के लिए हमें विदेशों पर निर्मर करना पड़ता है। अब भारत में सिमेंट तथा सड़क-निर्माण के अन्य सामानों का उत्पादन होने लगा है साथ

ही महक कूटनेवाले, भाप से चलनेवाले इखनों तथा हिजिल इखनों का भी भारत म उत्पादन श्रारम्भ हो गया है परन्तु फिर भी एउफाल्ट के लिए विदेशों पर ही निर्भर करना पडता है। श्राशा है कि पेट्रोल शोधशालाओं का निर्माण पूरा हो लाने पर देश की श्रावश्यकता पूर्ण करने के लिए एउफाल्ट प्राप्त हो जायगा; (३) देश मे ।वत्त का श्राभाव है। नगर पालिकाओं श्रीर जिला बोडों की देख-रेख में जो सहकों है वह वित्त के श्राभाव के कारण श्रव्छी दशा मे नहीं रह पातों। राज्य सरकारों के पास विकास के लिए कीय है परन्तु उनका उपयोग सहकों के निर्माण में कम श्रीर अन्य कार्यों में श्रिषक किया गया है। यही स्थित वेन्द्रीय सरकार की भी है।

संद्रक कोय—सडक दिकास समिति (१६२७) की सिफारिश पर १६२६ में सटक विकास कीय स्थापित किया गया और प्रति गैलन पेट्रोल पर कर ४ आने ते वढ़ाकर ६ आने कर दिया गया जिसमें से प्रति गैलन दो आना सडक विकास कीप में जमा किया गया। बाद में पेट्रोल पर आतिरिक्त कर लगाकर सडक विकास कीप में दो आने की जगह ढाई आना जमा किया गया। परन्तु दुर्माग्यवश सड़क विकास कोप के घन का उचित उपयोग नहीं किया गया है। सड़क विकास कीय स्थापित हो जाने के बाद राष्ट्र सरकारों ने अन्तर-राष्य तथा अन्तर-जिला सडकों के विकास में स्वय अपने वजट से व्यय कम कर दिया। इसके साथ ही आमों को मिलाने वाली छोटी-छोटी सटकों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार सटक विकास कीप निमाण का उद्देश्य ही न्यर्थ हो गया। सडकों का विकास करने के लिए उपलब्ध साधनों में अपनी आर से सहायता देने की अपेना राष्ट्र सरकारों ने अपने व्यय स्थानी श्रीर से सहायता देने की अपेना राष्ट्र सरकारों ने अपने व्यय में कटौती कर दी।

भारत सरकार ने सहक विकास की प क धन को व्यय करने में कुछ प्रांतवन्त लगा दिये। सरकार ने यह व्यवस्था की कि (१) इस कोष का धन सहकां के निर्माण तथा सुधार में व्यय किया लाय परन्तु इस कोप का वर्तमान सहकों की मरम्मत श्रीर देखभाल में उपयोग नहीं किया जा सकता है, श्रीर (२) सहक विकास कीप में राज्य के योगदान का कम से कम २५ प्रतिशत छोटी छोटी सटकों में व्यय किया जाय श्रीर टन सहकों पर २५ प्रतिशत से श्रीधक व्यय न किया जाय जो रेल मार्ग की प्रतियोगी हैं। यह सब होते हुए भी यह सत्य है कि सहक विकास कोप से प्राप्त होने वाला धन श्रावश्यकता से इस है श्रीर १६५०-५१ के अब तक २० करोड़ रुपये के व्यय की याजनाश्रा को स्वीइति प्रदान की जा चुकी यी श्रीर १७ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था। १६५१-५२ से दिसम्बर १६५५ तक २७ करोड़ रुपये के व्यय की

योजनास्त्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी स्त्रीर माच १९५५ तक लगभग १२ करोड़ रुपया उनके कार्योन्वित करने में व्यय किया जा चुका था।

सरकार अपनी वर्तमान श्राय मे से सङ्कों के निर्माण में पर्याप्त ब्यय नहीं कर सकती है साथ ही इस कार्य के लिए सहकों का उपयोग करने वालो पर लगाए गये करों से भी पर्याप्त आय नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सहको के निर्माण के लिए ऋण लिया जाय। यह सोचना बिल्कल निरर्थक है कि सडकों पर व्यय किये जाने वाले रुपयां से प्रत्यज्ञ रूप मे ऐसी आय नहीं होती है जिससे इस कार्य के लिए उपलब्ध भूगण का ब्याज चुकाया जा सके, इसलिए यह व्यय अनुत्पादक है ज्ञोर इसको नही करना चाहिए। यह समव है कि सहको के विकास से प्रत्यज्ञ रूप में कोई आय न हो परन्तु इससे निरसन्देह देश की आर्थिक समृद्धि बढती है और साथ ही जनता की कर देने की शक्ति मे वृद्धि होती है। भारतीय सडक एवम् यातायात सघ ने कुछ वर्ष पहले एक जॉच की जिसमें पता चला कि एक विशेष चेत्र में सहक का विकास करने से १२ लाख रुपये का वाषिक लाभ हुआ जब कि सहक निर्माण में तथा उसकी देखभाल में केवल ४३ लाख रुपया वार्षिक व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि सडकों पर व्यय किये गये प्रति १०० रुपयों पर जनता को २७७ रुपये का लाभ होता है। सहका के विकास से जनता समृदिशाली बनती है, सरकार की आय में वृद्धि होती हे, इसलिए भ्राग लेकर सहकों पर निर्माण करने में किसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं होनो चाहिए।

नागपुर योजना—१६४३ में विभिन्न राज्यों के मुख्य इक्षीनियरों की नागपुर में एक वैठक हुई श्रीर देश की न्यूनतम श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए एक सडक निर्माण-योजना निर्माण की गई। इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि इसके पश्चात भारत में सडका के निर्माण की सभी योजनाश्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। नागपुर योजना में सडको को चार श्रे (ख्यों में विभक्त किया गया है •—(१) राष्ट्रीय सडके, (२) राष्य की सडकें, (३) जिलों की बड़ी छोटी सडकें ग्रीर (४) प्रामा का सडकें। योजना में इन चार प्रकार की सडकों का १० वर्ष के श्रन्दर सुनियो।जत श्रीर सुसम्बद्ध श्राधार पर विकास करने का समाव दिया गया था जिससे पक्की सडकों की लम्बाई लगभग ६६,४०० मोल से १,२२,००० मील तक श्रीर श्रन्य सडकों की लम्बाई १,१२,००० से २,०७,५०० मील तक बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही योजना में वर्तमान सडकों में सुधार करने का भी सुक्ताव दिया गया। नागपुर योजना का उद्देश्य यह या कि विकसित कृषि चेत्र का कोई भी ग्राम मुख्य सडक से ५ मील से श्रिषक दूर न पड़े श्रीर कोई

भी गाँव चाहे कहीं हो सडक से २० मील से श्राधिक दूर न पड़े। इस योजना के अनुसार युद्ध पूर्व के मूल्या में ५० प्रतिशत वृद्धि के श्राधार पर निर्माण-कार्य में ३७२ करोड रुपया लगेगा जिसमें से ६६.५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय सडकां पर श्रीर ३०५ ५ करोड रुपया श्रन्य सहकों पर व्यय किया जायगा। यदि मूल्य युद्ध पूर्व के स्तर से २०० प्रतिशत बढ़े मान लिये जावें जिससे व्यय का श्रनुमान वर्तमान समन के मूल्य के श्रिधिक निकट श्रा सके तो, जैसा कि योजना-श्रायोग ने बताया है, नागपुर योजना को कार्यान्वित करने में कुल ७४४ करोड रुपया व्यय होगा जिसमें से १३३ करोड रुपया राष्ट्रीय सडकों के लिए श्रोर ६११ करोड़ रुपया श्रन्य सटकां पर व्यय किया जायगा।

रेल मार्ग से सम्बन्ध—भारत में सहकें अपर्याप्त होने श्रीर सहकों की हियति टोप पूर्ण होते हुए भी १६३० के श्रास्पास सहक यातायात से रेलवे को गहरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। निजी बस सविधां की श्रोर रेल की श्रपेद्धा श्रिषक यात्री श्राक्षित हुए निसमें श्रिषकतर कम श्राय वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही हलके सामान को लाने लेजाने के लिए भी मोटरों को सुविधाजनक समक्ता गया। मोटर यातायात प्राय श्रीर सुगमता से हो जाता है इससे रेल को गहरी हानि उठानी पड़ी। श्रनेक रेलवे जॉच समितियों ने रेलवे तथा सहक यातायात की प्रतियोगिता पर विचार किया श्रीर रेलवे को सहक की प्रतियोगिता में रज्ञा करने के अनेक सुक्ताव दिए। रेलवे ने सस्ते वापसी टिकटों के रूप में रियायत देनी श्रुक्त कर दो, कुछ विशेष समय के लिये टिकट टिये, श्रच्छी सर्विस श्रोर कम किराये की व्यवस्था की। परन्तु इससे प्रतियोगिता का जोर कम नहीं हुआ श्रीर यह श्राशंका की जाने लगी कि सहक यातायात से रेलवे को गहरी ज्ञांत पहुँचेगी।

रेलवे के हितों की रह्मा करने के लिए सरकार ने श्रनेक उपायों का श्राश्रय लिया श्रीर १६३६ में मोटर गाडी कानून लागू किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सभी मोटरों तथा बसों के लिए लाइसेन्स लिया जाय। कानून में बसों को रखने तथा श्रविक यात्री न बैठाने श्रोर बसों की चाल इत्यादि पर नियत्रण की शर्ते माननी श्रविवार्य कर दी गई। वसों का बीमा श्रावश्यक कर दिया गया। इस कानून से यात्रियों के हितों की रह्मा के साथ ही हानिकारक प्रतियोगिता को रोकने का प्रयत्न करके रेलवे के हितों की रह्मा की भी व्यवस्था की गई। परन्तु सहक यातायात की श्रोर से प्रतियोगिता प्रचलित रही श्रीर १९४६ में इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक त्रिटलीय सगठन का निर्माण करने की नीति श्रपनायी गई। इस सगठन में मोटर मालिकों, राज्य सरकार श्रीर रेलवे

के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परन्तु इस योजना को आशा के अनुक्ल सफलता नहीं मिली । बाद मे भारत सरकार ने सड़क यातायात कार्पेरिशन कार्त (१६४८) लागू किया जिसके स्थान पर १६५० में एक श्रीर व्यापक कानून लागू किया गया।

वर्तमान में रेल श्रौर सइक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है क्योंकि (१) यातायात का श्रमाय है श्रीर वर्तमान समय में रेल श्रीर मोटर यातायात को साथ साथ कार्य करके लाभ उठाने का काफी अवसर है, (२) कुछ तो सरकार के प्रतिबन्धों के कारण और कुछ मोटरों के तथा उनके विभिन्न कल-पुजों के मूल्य श्राधिक होने से सड़क यातामात का न्यय बढ़ गया है, ग्रीर (३) अनेक राज्यों मे यातायात का राष्ट्रीकरण कर देने से रेलवे तथा रोडवेज में अधिक

राज्य द्वारा संचालित सङ्क यातायात के चेत्र निश्चित है छौर मोटरे उचित सम्बन्ध स्थापित हो गया है। यात्रियों तथा सामान को उसी चेत्र के अन्दर लाती ले जाती है। इस बात पर महत्व दिया गया है कि यातायात इस प्रकार सचालित किया जाय जिससे रेल-सहक यातायात का सुसम्बद विकास हो । यातायात इस प्रकार नियोजित हो कि यात्रियो तथा सामान को रेलवे केन्द्रो तक पहुँचाया जाय जहाँ से छागे का यातायात रेलवे समालेगी। जहीं तक रोडवेज का सम्बन्ध है यात्रियों को दी जानेवाली सुविधाएँ बढी हैं, श्रिधिक मोइ-भाइ पर नियत्रण रखा गया है श्रीर

यह योजना १६४६ में वम्मई में प्रारम्भ की गई ग्रीर १६४८ से १६५० गाहियाँ श्रब्छी दशा में रखी गई हैं। तक ढाई वर्ष में यातायात के मार्गों की सख्या द से ४६५ तक बढ गई । श्रारम्म में २४० मील तक यातायात की व्यवस्था यी । १६५० में यह व्यवस्था १५,०३६ मील तक फैल गई और १६४८ से १६५० तक क्रमशः कुल १,०८,७७२ और २,६१६,२४७ मील के बीच यातायात किया गणा। इसके बाद के वर्षों में इस दिशा में प्रगति घीमी रही है परन्तु समी इष्टिकीणों मे रोहवेज ने उन्नति की है। उत्तर प्रदेश में १६४७-४८ में ३१ सरकारी रोडवेज सर्विसे चाल हुई जो १६५५-प्रमें २३७ हो गईं। यह यातायात व्यवस्था ६,००० मील तक फेली हुई है। यह श्रतुमान लगाया गया है कि कुल १०,००० मील के चेत्र में यात्रियों के यातायात का राष्ट्रीकरण करने मे २,३०० यसो की आवश्यकता होगी। द्वितीय •योजना के ग्रन्तगत इस यातायात सुविधा का विस्तार ६६६४ मील हो जायगा ग्रौर उसमे १६०० वसे होगी।

वम्बई में राजकीय रोड़वेज ने प्र से ६ पाई प्रति मील किराया वस्ल

विया। इसमे पहले इस चेत्र में किराये की यही दर वस्ली गई थी, परन्तु गुजरात में मोटर मालिकों ने रेलवे की प्रांतयोगिता में किराया कम वस्ला था। वस्वई में यर्राप किराया कम नहीं किया गया है परन्तु रोडवेज की सविस में निस्सन्देह काफी सुधार हुआ है श्रीर जनता को राष्ट्रीकरण से पहले की अपेदा अधिक सुविवाऍ प्रदान की गई हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है रोडवेज का ग्रपर तथा लोग्रर वलास का किराया श्रवटूबर १९५२ में क्रमशः ६ पाई श्रीर ७ई पाई से बढ़ानर १०३ पाई श्रीर द्रपाई प्रति मील कर दिया गया। किराये में वृद्धि करने का उद्देश्य मीटर इत्यादि के कल-पुजा तथा श्रन्य सामाना की बढी मृल्या को पूर्ण करना था। परन्तु चॅ्कि केन्द्रीय कारखाने स्थापित कर देने से मरम्भत इत्यादि में पहले की श्रपेता कम ज्यय वरना पड़ता है इसलिए १६५३ में क्रियों में कमी कर दी गई। अब क्रियों की दर अपर क्लास के लिए १०३ पाई र्मात मील से घटाकर ६ पोई प्रति मील कर टी गई ग्रीर लोग्नर यलास के लिए किराये का टर पाई से घटाकर ७३ पाई कर टी गई । श्रयत्वर १६५२ से पहले किराये की यही दर थी। लोश्रर क्लांस का विराया श्रव भी रेल के तीसरे दर्जे के किराये से श्राविक है। रेल में तीसरे दर्जे का १५० मील का किराया याद डाकगाड़ी या एवसप्रेस से सफ़र किया जाय तो ६० पाई प्रति मील है ऋौर यदि सामान्य गाही से सपर विया जाय तो दर ५ई पाई प्रति मील है परन्तु श्राशा की जाती है कि भविष्य में रोहवेज किराया और घटायेंगी।

राजकीय रोडवेज प्रणाली सन्तोषजनक रीति से चल रही है परन्तु (१) गाहियों को रखने तथा मरम्मत इत्यादि करने का ज्यय श्राधक है श्रीर रोडवेज को उतना लाम नहीं होता है। जतना की श्राशा थी। (२) श्रमी कुछ दिशाश्रों में यात्रियों को श्रीर श्राधक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। परन्तु इसमें कुछ सन्देह नहीं कि रोडवेज ने सड़क यातायात की श्रवस्था मे काफी सुधार किया है श्रीर भारत मे रोडवेज यातायात व्यवस्था का प्रसार करने के लए कोई वाधा नहीं है।

निजी उद्योग की किटिनाइयाँ—भारत वे सडक यादायात के विकास में अनेका कारणों से वाधायें पहुँची हैं (१) मेंटर गाड़ियों को बहुत अधिक कर देना पड़ता है जिससे व्याक्तयों की इस कार्य को करने की शक्ति टूट जाती है। मोटर गाड़ी कर जीच कमेटी ने यह बात वही थी कि भारत में मोटर गाड़ियों का प्रयोग करन वाले व्याक्यों पर ससार भर में सब से अधिक कर कार्या जाता है। इसी रिपोर्ट वे अनुसार प्रत्येक लारी पर प्रति वर्ष कुल कर मद्रास में ६,०७७ स्पये, बम्बई में ५,००० स्पये से लगा कर ५,२५८ द० तक

श्रीर श्रन्य राज्यों में श्रीसत कर लगभग ५,१३४ रु० था। इस कमेटी ने यह मी श्रनुमान लगाया था कि माल ढोने वाली लाग्यिं केन्द्रीय श्रीर स्वदेशीय राज्यों को जितना कर देती हैं, (स्थानीय करों को छोड़ कर) यदि वे २० हजार मील से अधिक थात्रा करती हो तो वह रेल द्वारा प्रति टन प्रत मील दुलाई के ग्रीसत किराये से सी प्रतिशत भ्रधिक था। पिछले तीन वर्षों में लारियों पर यह भार वास्तव में अनेको राज्यो मे और श्रधिक बढा ही है।

- (२) प्रादेशिक सरकारों ने सहको पर बहुत कम धन ब्यय किया है ज्रोर उनकी देख-रेख भी ठीक नहीं होती। इससे व्यक्तियों को वस चलाने के कार्य मे बड़ी कठिनाई पड़ती है। "मोटर गाडी कर जॉच कमेटी ने पता लगाया था कि (क) राज्यों को १९४६ में रिलस्टर की हुई मोटर गाहियों और वस्तुओं से प्राप्त २३'२६ करोड़ रुपयों के लगमग यी जब कि सहकों की मरम्मत पर नेवल ११'७ करोड़ रुपया व्यय किया गया था जो कि वमूल किये हुये कर के स्त्राचे से भी कम है। यह स्थिति वड़ी विचित्र है कि सड़ क यातायात पर कर इतना अधिक है कि यात्रियो ख्रीर माल ढोने में उनका प्रयोग करने मे बाधा पड़ती है, पर फिर भी मोटर गाडियो से वस्ल हुये कर के धन का पूरा प्रयोग सहकों के बनाने में नहीं किया जाता। " सडक की ठीक मरम्मत न होने से सडक यातायात के ब्यय मे नी वृद्धि हो जाती है। कमेटी ने श्रतुमान लगाया था कि एक वस साधारण खराव श्रीर बहुत खराव सहको पर एक वर्ष में ३५००० मील चलाने में व्यय ग्रुच्छी सहक में चलाने मे न्यय की ग्रुपेचा २६०० ६० ग्रुधिक होगा।
  - (३) १६३६ में मोटर गाड़ी एक्ट ने उन लग्नी यात्रास्त्रों पर जो उस समय वम्बई ग्रीर कलकत्ते, वम्बई ग्रीर देहली, वबई ग्रीर पेशावर ग्रीर वम्बई ग्रीर महाउ ग्रादि के बीच प्रचलित घी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इस एस्ट की योजना है कि सङ्क यातायात को राज्यों के छोटे-छोटे चेत्रों में ही सामित कर दिया जाय जिसमे कि कोई मोटर राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक जिना अनेको यातायात अधिकारियों की आशा के न जा सके। ऐसी आशा बहुत ही कम दी जाती है। ऐसी स्थित में अन्तर प्रदेशीय यातायात की कोई सम्मावना ही नहीं हो सकता। मोटर गाहियों के चलाये जाने के द्वेत्र को सीमित करने के ग्रातिरिक्त दोत्रों के कर्मचा-रियो को यह अविकार भी प्रदान किया हुआ है कि वे अपनी उच्छा के अनुसार विभिन्न होनों में चलाई जाने वाली मोटर वसों की सख्या भी सीमित कर धकते है। मोटर गाडी एक्ट ने छोटे छोटे चित्रों में अनेको अविकारियों को बनाकर सहक के यातायात की छोटे-छटे भागों में विभाजित करके तथा प्रतिक्च लगा

कर निहित स्वाथ का श्रवसर प्रदान कर दिया है । इसके परिखाम स्वरूप सङ्क यातायात के वैज्ञानिक ढग पर विकास में वाषा पड़ी है।

(४) जिस प्रकार सहक यातायात का राष्ट्रीयकरण विभिन्न राज्य द्वारा किया गया है उससे राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत अधिक महत्वराली योजनाओं पर जो घन व्यय किया जाना चिहये था वही नहीं रोका गया वरन् व्यक्तियों को यह कार्य करने में वड़ी भारी वाघा भी पहुँची है। इस दोप को रोकने के लिये योजना आयोग ने १६५३ में प्रादेशिक राज्यों से अपनी-अपनी लाइसेंस देने की नीति को सुधारने की आजा दो थी न्योंकि वह व्यक्तियों को सहक यातायात का कार्य करना आरम्भ करने में बहुत वाघक थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक राज्यों ने इस आजा को अनसुनी कर दिया है क्योंकि कि इनके सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के कार्य कम में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अपनी आजा को मनवा सकने के लिये योजना आयोग को अपनी आजा निश्चित शब्दों में निश्चित निर्देशों सहित मेजनी चाहिये थी। स्थिति के अपने अनितम परीज्ञण में योजना-आयोग केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से इस परिणाम पर पहुँचा है कि द्वितीय योजना में माल ओर यात्रियों के सम्बन्ध में कुछ सिदान्तों का अनुसरण आवश्यक है।

माल की दुलाई के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त निम्न हैं:-

- १ सडक द्वारा ढोने वाली सस्याओं के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना १९६१ तक अर्थात् द्वितीय योजना के अन्त तक नहीं सोची जानो चाहिये।
- २ १६३६ के मोटरगाड़ी एउट के श्रनुसार कम से कम तीन वर्ष के लिये ऐसी सस्याओं को जो पनप सकती हैं परिमट स्वतन्त्रता पूर्वक देना चाहिये। मोटरगाड़ी एक्ट के अन्तर्गत श्रिषिक से श्रिषिक पाँच वर्ष तक का परिमट देकर प्रोत्साहन देना चाहिये।

यात्रियों के यातायात के लिये निम्न सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है-

- (१) जो प्रादेशिक राज्य यात्रियों के यातायात सेवा सस्याश्रों का राष्ट्रीय-करण करना चाहें उन्हें योजना श्रायोग के समक्ष क्रिमक कार्य-क्रम बनाकर विचार करने के लिये रखना चाहिये जिससे वह कार्यक्रम को योजना में सम्मिलित कर सके। इस कार्य-क्रम को उन्हें १६६० ६१ तक जिन चेत्रों में राष्ट्रीयकरण करना है उनका निश्चित रूप से विवरण दिया जाना चाहिये। इसका विचार श्रायोग द्वारा तभी हो सकता है जबिक शर्ते प्रादेशिक राष्यों द्वारा स्वीकार कर ली जायं।
  - (२) राष्ट्रीयकरण योजना के बाहर की सङ्कों पर<sub>मे</sub>यातायात के लिये

परमिट कम से कम तीन वर्षों के लिये १६३६ के मोटर गाड़ी एक्ट के श्रनुसार दिया जाय।

- (३) उन चेत्रों में जो स्वीकृत राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत आते हैं परिमट श्रिधिक से अधिक समय तक के लिये, जो कि विस्तार के कार्य-क्रम के अन्तर्गत मोटरगाड़ी एक्ट की सीमा के अन्दर ही है, दिये जाने चाहिये।
- (४) जहाँ पर सरकार के सहयोग की सम्मायना है एक त्रिदलीय सस्था स्थापित की जानी चाहिये जिसमे प्रादेशिक सरकारें, रेलवे और इस कार्य में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हों।
- (५) उन च्रेत्रों में जिन्हे पूर्णतया व्यक्तिगत लोगों के श्रिधकार मे छोड़ दिया जाय प्रतिस्पर्धा दलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

राज्यों में सदकों के विकास में बाधा डालने वाली श्रानेक कठिनाइयों मे से एक तो निर्देशन करने वाले उपयुक्त कर्मचारियों का श्रभाव है जिनका कार्य मोटर द्वारा परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान देना, सहकों के नियोजित विकास की अपेत्ता विशेप हो । १६५८ के आरम्भ में भारत सरकार ने एक कमेटी इस मामले की जाँच करने के लिये श्री० एम० ब्रार० मनानी की ब्रध्यन्नता में नियुक्त की थी। सरकार ने १६५८ के श्रारम्भ में एक श्रन्तर-राज्य यातायात श्रायोग की भी नियुक्ति की थी जिसको मोटरगाड़ो ( सशोधित ) एक्ट की ६३ ए घारा के श्रनुसार नियन्त्रसा तथा निर्देशन के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त है श्रीर जिससे यह श्राशा की जाती है कि (१) वह परिवहन की गाहियों के सचालन तथा उनके विकास सम्बन्धी योजनात्र्यों को तैयार करे श्रीर श्रपनी योजनात्र्यों में माल लादने वाली गाड़ियों का जो कि अन्तर्राज्यों में यह कार्य कर रही है विशेष ध्यान रक्खें, (२) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी मतगढे श्रथवा मतमेद उत्पन्न हो उन सन को निवटों यें श्रीर उन पर निर्णाय लें, (३) श्रीर दो श्रथवा दो से श्रधिक राज्यों में पड़ने वाले मार्गो पर मोटर गाड़ी चलाने, नये परिमट देने, पुरानों को फिर से चालू करने तथा रह करने के सम्बन्ध में राज्य विशेष के यातायात श्रिधिकारी को श्रयवा त्रेत्र विशेष के यातायात श्रधिकारी को निर्देश दे।" इस श्रायोग से आशा की जाती है कि यह अन्तर राज्य यातायात की सुविघाओं का प्रभावशाली रूप से विकास करने में सफल होगा।

योजना के स्नन्तर्गत — जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना स्नारम हुई भारत में १७५४६ मील पक्की सहकें स्नौर १५१००० मील कच्ची सहकें थी । योजना के स्नन्तगत पिरेले ११० करोड़ रुपया व्यय करने के लिये रक्खा गया या जो कि बाद में बढाकर १३५ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसमें से प्रथम योजना काल में लगभग १३४६ करोड़ रुपये वास्तव में रार्च कर दिये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप २४००० मील नयी भूमि के समतल सदरें. श्रीर ४४००० मील नीची सदरें बनवाई गई श्रोर इस प्रकार सदरों की लग्नाई १२१००० मील पर्का श्रीर १९५०० मील कच्ची श्रायंत् कुल ३१६००० मील हो गई जन कि नागपुर योजना का ध्येय देवल १२३००० मील पर्का तथा २०८००० मील कच्ची श्रायंत् कुल ३३१००० मील सदर्भों का ही था।

इसके ग्रातिरक्त श्रमेकों सहकों के बीच के व्यवधानों को मिलाने तथा पुलों के बनाने की भी व्यवस्था की गई थी। "पहली श्रमल १६४० का नव कि भारत सरकार ने राजाय कही जाने वाली सद में क विरास तथा बनाये रखने का वित्ताय दायित्व श्रपने कपर लिया उस समा लम्बी लग्बी दूरी तक सदमों के व्यवधान पढे हुये थे तथा मुख्य-मुख्य स्थानों पर श्रानेकां सहकों पर पुल नहीं थे। प्रथम योजना क श्रारम्भ तक ११० मील महर्के दो सहकों के बीच के व्यवधान को जाडन के लिये तथा तान गडे-पडे पुल बनवाये गये ग्रार १००० मील सहकों का मरम्मत करवाई गई । प्रथम योजना फाल के छारम्भ में ही वेन्द्रीय सरकार न सहकों के विशास तथा सुवार हा कार्य कम ग्रारम्भ किया जिसके श्रन्तर्गत १२५० मील वाच की गायन सहजी तथा ७५ बडे-बडे पुली का बनवाना तथा ६००० माल सहकों की मरम्मत करवाना निम्म लत था। इसमें से योजना काल में ६४० मोल बीच की गायब सडके तथा ४० पुल तथा २५०० मील पुरानी सडकों की मरम्मत पूरी हो जाने की स्नाशा की गई थी। योजना के खत्म -हाते-होते ६३६ मील वीच की गायन सडके, ३० बडे-बडे पुल श्रोर ४००० मील पुरानी सहकों की मरम्मत हो पाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी वीच की गायव सबको के बनवाने का ध्येप बनाया गया था यह लग भग पूरा हो गया श्रोर वर्तमान राजवयां की मरम्मत का काम सोची हुई मात्रा से लगभग दुगना कर लिया गया। पोजना में २७ ८० करोड़ रुपये राजपयों पर न्यय के लिये नियत किये गये ये जिसमें से २७६२ करोड़ रुपये ब्यय पर दिसे गये।

प्रथम योजना में सहको द्वारा यातायात पर १२३ करोड़ रुपये व्यय किये गये। राज्यों ने ३००० मोटर गा। ह्यों छोर वहाई विससे कुल मोटर गाड़ियों की सख्या जो सरकार की छार से यातायात की सेवा में लगी हुई थी ११००० हो गई। प्रथम योजना वे छन्त तक मोटर द्वारा जनता की यातायात सेवा का २५% सरकारी विभाग द्वारा किया जाने लगा था। माल परिवहन व्यक्तिगत एजेन्सियों के ही छाधिकार में रहा।

द्वितीय योजना में (सदकों के विकास के लिये) २४६ करो रुपयों के

च्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से ८२ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रीर १६४ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा व्यय किया जायगा । यह रक्षम केन्द्रीय सङ्क कोष से प्राप्त होने वाले १५ करोह रुपयों के ग्रांतिरिक्त है। दिनीय योजना के पूरे होने पर यह अशा की जाती है कि परकी सहके बढ़ कर १४३,००० मील स्त्रीर कच्ची सहके २३५,००० मील श्रर्थात् कुल योग ३७८,००० मील हो जायगा।

यह मात्रा नागपुर योजना से कही ग्राधिक है। हितीय योजना का कार्यक्रम पहिली योजना ही की तरह चडे-वडे पुली का निर्माण तथा बड़े-बड़े राजायों का मिला देने वाली सहकों के निर्माण का और पुरानी सद कों को मरम्मत का ही है। इस योजना के अन्तर्गत आर म किये हुये निर्माण कार्य पर कुत व्यय लगभग ८७५ करोड़ क्यये का है। यह व्यय निम्न प्रकार का है।

णुकाय पर कुण गा			
र का है।  प्रथम योजना के श्रपूर्ण निर्माण कार्य प  प्रथम योजना के श्रपूर्ण निर्माल कार्य प  जिसमें विनहाल टनल सम्मिलित है—	₹ •	\$0°0	करोड रपया
न्ने जाल पर्यों की मिलाप पर		१०५	<b>37</b>
2 /6 AD HIVI /		२००	>>
र के कर्ज के जिमारा पर (रेरे	_	Ä.0	53
イン・プラ 中型 上 はれば		<b>6</b> 0	**
हाट-छाट पुरा पुरानी सहको की मरम्मत पर			
- 1 3 CD C C C C C C C C C C C C C C C C C		१५ ०	•
कराने पर (३००० मील)	TT	50.7	
The second secon	कुल ज्ञाम	पुप्र करो	इ रुपये का श्रन

द्वितीय योजना काल य वास्तविक व्यय लगमग ५५ करोड़ रुपये का श्रनु-मानित किया गया है। राष्ट्रीय राज्यवधा के श्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ महत्वशाली सहको का निर्माण प्रथम योजना में करवाना आरम कर दिया था। वह कार्य इस योजना मे प्रचलित रहेगा श्रीर लगमग ६ करोड़ रुपया इस पर व्यय हो जायगा। कुल मिला कर केवल १५० मील नई सड़क बनाई जायेंगी श्चीर लगभग ५०० मील सङ्को को उन्चस्तल कर दिया जायगा।

द्वितीय योजना में १३६ करोड़ रुपयों की राज्यों की सङ्क्र यातायात सबन्धी विकास काय-क्रमों के लिये व्यवस्था की गई हैं। १६५० के रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एकट के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कारपोरेशन स्थापित करने की सलाह दी गई है ग्रीर रेलवे योजना के झन्तर्गत १० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है कि रेलवे इन कारपोरेशनों में सम्मिलित हों। इसके श्रितिरिक्त यातायात मन्त्रालय की योजना में देहली ट्रान्सपोर्ट सरविस के लिये एक ३ करोड़ रुपये का कार्य-कम भी स्वीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार सरकारी सड़क यातायात पर कुल विनियोग द्वितीय योजना में १७ करोड़ रुपयों के लग मग होता है।"

१६५६-५७ में कुल सदकों के कार्य क्रम पर न्यय ४२ ७१ करोड़ कप्या या श्रीर १६५७-५८ के लिये सशोधित श्रनुमान ४४ ३२ करोड़ कप्यों का है इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों से कुल न्यय १२६ २६ करोड़ काया होता है। बचे हुये हो वर्षों के लिये ११६ ८६ करोड़ रुपया रह जायगा। श्रन्तिम हो वर्षों के लिये ११६ ८६ करोड़ रुपया रह जायगा। श्रन्तिम हो वर्षों के लिये वजट में इस रक्षम की न्यवस्था सम्भव हो सकेगो इसमें सदेह मालूम पद्भता है। इसके श्रतिरिक्त लोहे की कमी के कारण पुलों के निर्माण में वाघा पद्भने का भय भी है। इस्र्लिये इस यह कह सकते हैं कि योगना के विकास कार्य-क्षम में सुछ कमी श्रवश्य ही श्रायेगी।

## ऋध्याय ३६

# जल यातायात

भारतीय यातायात अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। द्वितीय महायुक् के पूर्व भारत के पास १२,५०० जी० ग्रार० टी० (ग्रास रजिस्टर्ड टनेज) के जलयान थे। प्रथम योजना के श्रारम्भ में भारत के पास ३,६०७०७ जी० श्रार० टी० के जलयान ये जिनमें से २,१७,२०२ जी० ग्रार० टी० भारतीय तटों पर ग्रौर १,७२,५०५ जी० ग्रार० टी० के जलयान विदेश में ज्यापार कार्य में ज्यस्त थे। प्रथम योजना के अन्त में कुल टनेज ४,50,000 जी० आर० टी० था जिसमें से २,४०,००० जी० श्रार० टी० तटीय ज्यापार तथा समीपवर्ती देशों से ज्यापार का था और २४०००० जी० भ्रार० टी० दूर विदेशी ज्यापार का। लायह के जलयान के रिजस्टर के श्रनुसार ३० जून, १६५७ को समस्त ससार का उन्ल टनेज १,१०२ करोड़ जी० श्रार० टी० या जनिक १६५५ के श्रन्त मे १,००६ करोड़ जी० श्रार० टी० ही था। इस प्रकार भारत का दुल टनेज ससार के टनेज के ३% से कुछ श्रिधिक था जब कि भारत का विदेशी व्यापार ससार के कुल व्यापार का ३% से अधिक था । श्रन्तराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा भारतीय जलयान भारत के समुद्री न्यापार का केवल ५०% न्यापार कर पाते हैं। इसका यह अर्थ है कि भारतीय जल यातायात के विकास में श्रमी बहुत लम्झा मार्ग पूर्ण करना है।

भारत के लिए जिसका समुद्री तट ४,१६० मील (श्ररडमन द्वीप सम्मिलित करके) तक विस्तृत हुआ है और जो बहुत बड़ी मात्रा मे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है वास्तव में जलयान का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमारे पास अपने जलयान हो तो भारतीय उद्योग का यातायात व्यय कम हो जायगा ख्रोर विदेशी बाजारों में उसकी प्रांतयोगिता गांकि में वृद्धि हो जायगी। यदि सामान का भार-तीय जलयानी के द्वारा यातायात किया जाय तो इम उतनी विदेशी विनिमय मुद्रा बचा सकते हैं जिसको श्रान्यथा इन जलयानों में व्यय करना पहता है। इसके साय ही भारत को श्रापने समुद्रतटीय चेत्र की रज्ञा करने के लिये श्रीर युद्ध के समय अपने व्यापार की सुरचा के लिए एक शक्तिशाली जल सवा की आवश्य-कता है। सकट के समय ज्यापारी जलयान प्रतिरचा की दूसरी पंक्ति का कार्य देते हैं। यह सहायक सेना के रूप में ही सहायक नहीं होते बल्क इनसे नी-सेना को शिचा दी जा सकती है और युद्ध के समय आवश्यक सामान समुद्र पर पहुँचाने के लिए इनकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता पड सकती है।

मुख्य विशेषताएँ—भारतीय जल यातायात के विकास की कुछ उल्ले-स्वनीय विशेषताएँ हैं —

- (१) भारत में श्रॅमेनी शासन के समय भारतीय जलयानों को ब्रिटिश तथा विदेशी जलयानों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा श्रीर उमे विकास करने का श्रवसर ही नहीं दिया गया । १६२० के लगभग श्रनेक जलयान कम्पनियाँ बनी परन्तु प्रतियागिता का भामना न कर सकने के फलस्वरूप नष्ट हो गई। इन कम्पनियों के नष्ट होने म विदेशी जलयान कम्पनियों की भाड़े की दर सम्बन्धी नीति का भी बहुत योगटान रहा है। इन विदेशी कम्पनियां ने भारतीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के कारण भाडे को दर घटा टी ग्रीर जन यह वम्पनियाँ वन्ट हो गई तम भी भाड़े को टर मे पुन वृद्धिकर ली। इसके माप इन कर्पानयां ने यह व्यवस्था की कि यदि किसी व्यापारी ने एक निश्चित समय तक नियमित रूप से इनके जलवाना के द्वारा ही सामान भेजा श्रीर मैंगाया तो उस ग्रविध में यह जितना भाइ। देगा उसका एक ग्राग उने वापिस कर दिया जायगा । इन विदेशी कर्णनया की प्रतियोगिता का केवल सिधिया स्टीम नेवी-गेशन कम्पनी ही सामना कर सर्जा। विदेशी कम्पनियों ने इसे नष्ट करने की श्रनेक बार चेण्टा की परन्तु वह सफल नहीं हो सके। इससे सिंधिया कम्पनी को भारी चृति उठानी पडी । विधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के हुढ रहने पर १६२४ में एक सममीता हुन्ना जिसके अनुसार हुने ७५ हजार टन सामान प्रतिवर्ष ले जाने की श्रमुमित दी गई। भारतीय जलयान कम्पनियों के नष्ट हो जाने का एक कारण यह या कि निदेशी कर्णानयों वी प्रातयागिता शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी त्रोर दृषरा कारण यह या कि भाग्तीय कम्पनियों के पास वित्त की उपयुक्त व्यवस्था नहीं यी श्रीर इनका कुल व्यय भी बहुत ग्रिविक था। थोडे बहुत परि-वर्तन के साथ यह प्रतियोगिता स्वतन्त्रता मिलने तक चलती रही श्रीर स्वतन्त्रता मिलने से भारतीय जल यातायात का भारत के तटीय व्यापार में महत्व बढ गया है क्योर साथ ही विदेशी व्यापार में भा एक सीमा तक इसने क्यपना विशेष स्थान बना लिया है।
- (२) ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने भारतीय जल यातायात की कुछ भी सहायता नहीं दी श्रीर स्वतन्त्र न्यापार नीति का बहाना लेकर भारतीय उद्योग को टाल दिया गया त्रीर श्राप्तने लिए स्वय मार्ग बनाने की छोड़ दिया गया। इसका यह परिणाम हथा कि इस त्रविध में भारतीय जल यातायात ने विशेष प्रगति नहीं की। स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् भारत सरकार ने इस श्रीर ' स्यान दिया है। भारत सरकार ने जलयान उत्योग को भ्रमुण तथा श्रन्थ श्रायिक

सहायता दी। सरकार ने जलयान निर्माताओं से जिस मूल्य पर जलयान क्रय किए मारतीय जलयान कम्पनी को उससे कम मूल्य पर वेचे स्प्रीर श्रन्तर को श्रपने कोष से दिया। लाइसेन्स की प्रधा लागू करके १९४८ में भारत के तटीय न्यापार पर नियत्रण स्थापित किया गया भ्रीर १६५० में तटीय व्यापार केवल भारतीय जलयानो के लिये सुरिच्चत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप मारतीय समुद्र तट पर १६४८ में जितने टना के जलयान व्यापार करते थे उसमें पूर मितशत की वृद्धि हो गई और १९५२-५३ तक व्यापार मे १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक जल यातायात बोर्ड स्थापित किया गया है जिसका कार्य जल यातायात के कार्य का सचालन करना है। सरकार की सहायता प्राप्त करके अब भारतीय कम्पनियाँ विश्व जल यातायात सम्मेलन की सदस्य हैं।

१६४७ में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि तीन जल यातायात कार्पी-रेशन बनाये जायँ, पत्येक के पास १० करोड़ रुपये की पूँजी हो छौर तीनों कार्पोरंशन तीन मार्गों से ज्यापार इत्याद करे। परन्तु १६५५ तक मार्च १६५० में १० करोड रुपये की अधिकृत पूँजी का केवल एक कार्पोम्शन, पूर्वी कार्पोस्थन लिमिटेड, स्थापित किया जा सका था। सरकार ने दो करोड राये की नियमित पूँजी का केवल है भाग दिया भ्रीर शेव पूँजी मैनेजिंग एजेन्टों ने लगाई। जून १९५६ में दूसरे कार्पोरेशन (पिश्चमी शिविंग कार्पोरेशन) की स्थापना हुई। यह

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ईस्टर्न शिषिग कार्पोरशन से ग्रागामी पृर्ण रूप से राज्य के श्राधिकार में है। गींच वर्षों के अन्दर यह आशा की जाती थी कि ४०,००० जी। आर० टी० व्यापार श्रीर श्रविक कर सकेगा। परन्तु वह केवल २१,६०० जी० श्रार० टी० व्यापार प्रथम तीन वर्षों मे वढा पाया । सरकार ने जलयान उद्योग की श्रीर ग्राधिक वित्तीय तथा ग्रन्य प्रकार की सह'यता दी है। इसिलये यह त्राशा फरना सर्वया युक्ति सगत होगा कि कुछ समय में भारतीय जल यातायात उन्नति की चरम सीमा पर

(३) प्रारम्भ में देश-विदेश व्यापार में मारतीय जनयानी ने भी भाग लिया। परन्तु उनमें से अधिकतर छोटे थे ग्रीर अधिकतर सेलिंग वेसिल, टम्स, पहुँच जायगा। नाम्जेज, कोस्टर्स इत्यादि थे। अतीत में एक सबसे वही कठिनाई यह थी कि देश

में जलयान उद्योग नहीं था जिससे जलयाना का व्यय श्रत्यधिक हो गया था। अत्र विणाखापट्टम् में जलयान कारखाना है। यह जून १६४१ में स्थापित किया गया था। यह ग्राशा की जाती थी कि २,१५,००० जी० ग्रार० टी० में से जो कि प्रथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राप्त कर लेना चाहिए या हिन्दुस्तान

शिपयार्ड १ लाख जी० श्रार० टी० की पूर्ति करेगा। परन्तु शिपयार्ड की उन्नति वडी घीमी रही है श्रीर प्रथम तीन वर्षों में वह केवल ३५,८०४ जी० श्रार० टी० ही की पूर्ति करने में समर्थ हो सका है। भारतीय जल यातायात कम्पनियों को विशाखापट्टम् शिपिङ्क यार्ड से श्रिधिकाधिक संख्या में जलयान के पाने की श्राशा की जा सकती है। इसमे सबसे कठिनाई जलयान के विभिन्न कल-पुजों की प्राप्ति में कठिनाई है जिन्हें विदेशों से मॅगाना पहता है। जैसे ही यह कठिनाई दूर हो जायगी श्रीर शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो जायगी, भारतीय जलयानों के टनेज के विस्तार में वास्तविक सहायता पहुँच सकेगी।

(४) मारतीय जल यातायात के विकास में सबसे नडी कठिनाई यह है कि हमारे देश में जलयानों को वन्टरगाह की उचित सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। भारत के पाँच बढ़े बन्दरगाहों, क्लक्ता, बम्बई, महास, कच्छ श्रीर विशासापट्टम म पेट्रोल, जलयान में जलानेवाला कोयला इत्यादि को छोडकर केवल दो करोड टन सामान प्रतिवर्ष उतारा लाटा वा सकता है। १६४६-५० में पेट्रोल तथा जलयान में जलने वाले कोयले को सम्मिलित करके इन बन्दरगाहों में दो करोड़ टन सामान लादा उतारा गया। प्रथम योजना के श्रन्तर्गंत विकास के कारण माल लादने उतारने की शक्ति बढ़ कर दो करोड़ पचास लाख टन हो गई है। वन्दरगाहों पर ययाशक्ति कार्य हो रहा है। जलयानों को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माल डॉक में पड़ा रहता है इसके पूर्व कि लादा जा सके। यह मस्ताव किया गया है कि बन्दरगाह की सुविधाओं का विस्तार किया जाय श्रीर कारहला ब्रीर मगलीर के हो नये चन्दरगाह बनाये जा रहे हैं। बन्दरगाहों पर त्रावर्यक सामान, श्राकाशदीप तथा अन्य सुविधायें बढाई जा रही हैं।

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति—पुननिर्माण नीति उपसमिति (१६४७) ने भारतीय जल यातायात की पूर्णतया जाँच की श्रीर निम्नलिखित विकारिश की —

- (१) मारत को प्रति वर्ष १ करोड़ टन मामान लाने ले जाने के लिये श्रीर ३० लाख यात्रियों का ले जाने के लिये छोटे जलयानों को छोड़कर २० लाख टन के जलयानों की त्रावश्यकवा होगी।
- (२) हमारा उद्देश्य है कि १६५७ तक मारत के तटीय व्यापार का १०० प्रतिशत, भारत-वर्मा लका तथा श्रन्य पड़ोसी देश से व्यापार का ७५ प्रतिशत, दूर देशों से भारत के व्यापार का ५० मितशत और धुरी राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले व्यापार का ३० प्रतिशत सॅमाला जाय।
- (३) भारत सरकार की नीति का उद्देश्य भारतीय जल यातायात का प्रसार होना चाहिए श्रीर दरों में कमी श्रीर वृद्धि होने से इसकी रच्चा की जानी

चाहिए। इन उद्देश्यां को पूरा करने के लिए, जल यातायात वोर्ड को पूरे ग्राधिकार देने चाहिए।

पुनर्निर्माण नीति उपसमिति ने जो लक्ष्य निर्धारत किये ये भारतीय जल यातायात का स्तर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। यह निजी उद्योग तथा भारत सरकार के लिए श्रात्यन्त खेद की बात है। वर्तमान मे भारतीय जल यातायात का टनेज केवल ५ लाख टन है जब कि समिति ने २० लाख टन का सुमाव दिया था। भारतीय जलयान कुल विदेशी व्यापार का केवल ५ प्रतिशत पूरा करते हैं जब कि समिति ने सुमाव दिया था कि भारतीय जलयानों को श्रपने कुल विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत स्वय करना चाहिये। केवल तटीय व्यापार के सम्बन्ध मे समिति की श्रमिलाषा पूर्ण हुई है।

मारतीय जल यातायात के प्रसार एवम् सगठन के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये जल यातायात के मालिको की परामर्शदात्री समिति की १६५२ के मध्य में एक बैठक हुई। समिति ने अनेक सुक्ताव दिये। समिति ने सुक्ताव दिया है कि भारत में जलयानों की सख्या बढाई जानी चाहिये परन्तु पचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए जितने घन की व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है। सरकार को अधिक से अधिक २ प्रतिशत वार्षिक व्याज पर मारतीय जलयान कम्पनियों को ऋग्ण देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूँजी सरलता से चुकाई जा सके। समिति ने यह भी सुक्ताव दिये कि (१) पुराने जलयानों के स्थान पर नये जलयानों को खरीदने के लिए जो लाभाश जमा किया गया है उस पर आय कर न लगाया जाय, (२) भारतीय जलयानों में जलने वाले तेल पर चुङ्की न लगाई जाय और (३) जलयानों का सामान वेचने वाले स्टोरों पर विकी-कर न लगाया जाय।

यह भी सुक्ताव दिया गया है कि तटीय व्यापार करनेवाला जलयान वेहा सन्द्रिलित होना चाहिये। इसमें विभिन्न श्राकार प्रकार के जलयान होने चाहिये जो तटीय व्यापार की विशेष वस्तुश्रों जैसे नमक, कोयला श्रौर तेल लाने ले जाने के उपयुक्त हों। कुछ लोगों का बिचार है कि नमक श्रौर कोयला ले जाने के लिए ६,००० से ८,००० ही॰ डब्लू॰ टी॰ के जलयान श्रीषक उपयुक्त होते हैं श्रीर खाद्यान की सामग्री इत्यादि का यातायात करने के लिए छोटे श्राकार के जलयानों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस समिति ने बताया कि भारतीय वन्दरगाहों में सामान लादने श्रौर उतारने की श्रन्छी न्यवस्था नहीं हैं। विशेषकर कीयला लादने के लिए वर्धों (जलयान खंडे होने का स्थान) का श्रभाव है श्रौर कुछ टूटी-फूटी स्थिति में हैं श्रीर उससे कार्य श्रन्छ। प्रकार नहीं लिया जा सकता है। समिति ने सुफाव दिया कि बन्दरगाहों में माल लादने श्रीर उतारने इत्यादि का कार्य तीव गित से करने के लिए मर्शानें लगाने की श्रीर वर्तमान सामान को श्रीर बढाने की श्रावश्यकता है।

पंचवर्पीय योजना के खन्तर्गत-प्रथम पचवर्पीय योजना में भारतीय जलयानों की संख्या बढ़ाने पर श्रीर बन्दरगाही हत्यादि की सुविधाएँ बढ़ाने पर जोर दिया गया था। योजना में कहा गया था कि तटीय व्यापार में जो पुराने श्रीर विसे-19टे जलयान प्रयुक्त किये जा रहे हैं जलयान कम्पनियों को उन्हे बदलने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशाखापटनम में जलयानी के निर्माण हेत रुपया लगाया है। श्राशा की जाती है कि पचवर्णाय योजनाकाल में ही विशाखापट्टम के कारखाने में कुल १ लाख जी० श्रार० टो० के जलयान प्राप्त किये जा सकेंगे। इनमें से ६० इजार जी० छार० टी० के जलयानों से पुराने धिस-पिटे जलयानां को बदला जायगा ग्राप् शेष जलयान विशेष पर तटीय व्यापार में प्रयुक्त किये जायंगे। विशाखापटनम कारपाने ने जलयान कम्पनियों के हाथ जलयान उचित मृल्यों पर वेचे जायेंगे। याट निर्माण व्यय में स्रोर विक्री मूल्य में कुछ अन्तर रहेगा ता उसके लिए सरमार जलयान निर्माण उद्योग को आर्थिक सहायता देगी। इस प्रकार जलयान निमाण कार्य का प्रसार करने का विशाखा-पटनम कारसाने के विकास से गहरा सम्बन्ध है जिससे विशासापटनम की उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके। योजना ने श्रनुसार तटीय व्यापार को सुरिच्चत बनाए रखने के लिए कम से कम ३ लाख जी० श्रार्० टी० के जलयानों का होना ग्रत्यन्त श्रावश्यक है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि पाँच वर्ष के श्रन्टर भाग्तीय जलयान कम्पनियों को ४ करोड़ रुपया ऋगु दिया जायगा ग्रीर जलयान कम्पनियाँ श्रपने साधनों से शेप २ करोड़ क्पया एकत्रित करेंगी। श्रनुमान या कि इस ६ वरोड़ रुपये से भारतीय जलवान कम्पनियों के पास पर्यात जलवान हो जायँग। पचवर्षीय योजना के ब्रान्तर्गत चिदेशी व्यापार के लिए १,००,००० डी० डब्लू० टी० के जलयाना की ख्रोर ख्रावश्यकता समक्ती गई थी जिसमें ईस्टर्न शिपिग कार्पोरेशन के लिए श्रावश्यक ६० ६ जार डी० डब्लू० टी० के जलयानी वो सम्मिलत नहीं किया गया था जिसके लिए सरकार ने अपने भाग के ४४ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी थी।

मथम योजना में १९५५-५६ तक ६ लाख जी० छार० टी० तक जलयानी के बढाने का विचार किया गया था। पर बास्तव में योजना काल के छन्त तक कुल ४,८०,००० जी० छार० टी० का कार्य किया जा सका। जो ध्येय ६,००,००० जी श्रार टी का सोचा गया या वह तो तभी पूरा हो सका जब कि योजना काल मे ही मंगाये हुये नहाज प्राप्त हो सके ।

जल यातायात उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रथम योजना के श्रन्तर्गत व्यवस्था की गई है उसकी लोगों ने निम्न श्रालोचना की है (१) सन् १६५६ तक 5,00,000 जी० श्रार० टी० के जलयानों की वृद्धि पुनिनर्माण नीति-उपसमिति की उफारिश की तुलना में बहुत कम है। समिति ने रिफारिश की थी कि १६५- तक ्० लाख टन के जलयान हो जाने चाहिए परन्तु इस काथ में अनेक कांटनाइया का सामना करना पढ़ा है। वित्त के साथ ही आवश्यक सामान का ग्रामाव है ग्रोर ब्यवहारिक दृष्टि से पचवर्णीय योजना समिति के कार्यक्रम को ग्रपना लक्ष्य नहीं बना सकती थी। योजना में व्यावहारिक हिन्टकी स के श्राघार पर लक्ष्य निर्घारित किये हैं। (२) मारतीय जलयान समिति ने सुमाब दिया है कि सरकार तटीय एवम् विदेशी व्यापार में जो रुपया ब्यय करेगी वह जलयाना ग्रीर ग्रन्य सामान के बढ़े हुए मूल्यों का देखते हुए बहुत कम है। एचवर्षीय योजना में जो लस्य ानवीरित किया गया है उसको पूरा करने मे भा कही श्रिधिक रुपया लगेगा, (३) सरकार अस्य दी गई पूँजा पर फितना व्याज वस्ल रही है थ्रोर ऋण के साथ जो शर्ते लगी हैं उनसे ऋण तेना उद्योग के लिए ग्रसुविचाजनक हो गया है। उद्योग को यह ऋग भहगा पड़ता है। यह सुमाव दिया गया है कि सरकार को २० वर्ष के लिए ऋण देना चाहिए और पहले ५ वर्षों मे उस पर कुछ ब्याज नहीं लेना चाहिए। छठे वर्ष से ३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज बसूल किया जा सकता है श्रीर इसी समय से भूगा ली गई पूँजी भी किश्तों में चुकानी श्रारम्म हो जायगी, (४) योजना की अन्य सुविधाओं की कुछ चर्चा नहीं की गई है, जैसे जलयान मे जलने वाले तेल पर से चुक्नी हटाना, जलयान सामान के स्टोर पर से विकी कर हटाना ग्रीर ग्राय-कर पर रियायत देना । जल यातायात उद्याग ने इन सुविधात्री की माँग की है। इनके विना भारतीय जल यातायात की तेजी मे प्रगति नहीं की जा सकती है।

हितीय योजना मे यह प्रस्ताव किया गया है कि ६० इजार जी० ग्रार० टी० के विसे-पिटे जलयानों को निकाल कर ३० लाख जी० श्रार० टी० के जल-यानों की वृद्धि की जाय। इस प्रकार दूसरी योजना के भ्रन्त तक कुल टनेज ६ लाख जी० आर० टी० हो जाना चाहिए। योजना का व्यय है (१) तटीय न्यापार की श्रावश्यकताश्रों को रेलवे द्वारा प्राप्त माल श्रोर यात्रियों की मात्रा को ध्यान मे रखते हुए पूर्ण करना, (२) मारत के विदेशी ज्यापार का अधिक से अधिक भाग भारतीय जलयानों के लिए प्राप्त करना, (३) टैकों का बेड़ा तैय्यार करने के लिए केन्द्र स्थापित करना।

नीचे लिखे निश्चित ध्येय को पूरा कर लेने के पश्चात् भारत का १२ से १५ प्रतिशत समुद्रपार देशों से न्यापार और श्रास-पास के देशों से न्यापार का ५०% भारतीय जलयानों के भाग में श्रा जायगा जब कि वर्तमान में इन न्यापारों का केवल ५ ग्रीर ४० प्रतिशत उनके भाग में हैं।

जी० ग्रार० टी०

	योजना के पहले	प्रथम योजना के श्रन्त में	द्वितीय योजना के श्रन्त में
तटीय श्रीर निकटस्य	<b>२१</b> ७२०२	₹ <b>१</b> २२०२	४१२२००
समुद्र पार	१७३५०५	र⊏३५०५	४०५५०५
ट्रेम्प			<sup>1</sup> ६००००
टैन्कर्स		५०००	<b>' २३०००</b>
सेलवेज टग			१०००
कुल	७०७०३६	६००७०७	<i>७०७</i> १० <i>३</i>

प्रथम योजना में १६ ५ करोड व्यया जल यातायात के लिये नियत किया गया था। बाद में यह धन बढ़ा कर २६ ३ करोड रुपया कर दिया गया। योजना काल में वास्तिविक व्यय १८ ७१ करोड़ रुपये किया गया। द्वितीय योजना में जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जल यातायात के विकास के लिये ४५ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था यद्यांप की गई है फिर भी क्योंकि पिछली योजना का ८ करोड़ रुपया बचा हुआ है इसलिये केवल ३७ करोड़ रुपया ही इस योजना में विकास कार्यों के लिये प्राप्त होगा।

योजना श्रायोग के द्वितीय पचवर्षीय योजना के कार्यो तथा यानी सफलता के मत के श्रनुसार (मई १६५८) जितने न्यय की द्वितीय योजना में न्यवस्था की गई है उसका न्यय तो हो ही चुका है श्रीर उसके फलस्वरूप जो जल यातायात का कार्य होगा (टनेज मिलेगा) वह लगभग १८०००० जी० श्रार० टी० होगा जबिंक योजना का ध्येय ३६०,००० जी० श्रार० टी० टनेज प्राप्त करने का था, जिसमें ६०००० जी० श्रार० टी० टनेज पुराने जहाजों के स्थान पर नये प्रयोग में ले श्राने के कारण प्राप्त होने वाला था। श्रपने त्येय को पूरा कर सकने के जिये जगभग ४५ करोड़ रायों की श्रोर श्रावश्यकता होगी।

बन्दरगाह-प्रथम योजना की रूपरेखा जब उपस्थित की गई थी उसमें वन्दरगाहों के विकास अथवा सुवार का कोई स्थान नहीं था। इस अभाव की पूर्ति की महत्ता समक्ती गई ग्रीर जब योजना की संशोधित रूपरेखा बनाई गई तो उसमें ३३ करोड़ रूपयों की व्यवस्था की गई थी। बाद में यह मात्रा वढा कर ३६ १९ करोड़ कर दी गई थी। चूंकि बन्दरगाहों के सुवार का कार्यक्रम देर से श्रारम्म हुश्रा, इसलिये योजना-काल में व्यय की मात्रा केवल २७ ५७ करोड़ क्पयों की हो पाई । कुछ भी हो यह विकास कार्यक्रम जो श्रारम्भ किया गया बडे महस्त का था। काण्डला के नये बन्दरगाह के बनवाने के प्रातिरिक्त जिस पर < दिश् करोह क्पयों की व्यवस्था की जा चुकी थी, इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गत मुख्य योजनाएँ बम्बई श्रीर फलकत्ता में थी जिनके लिये योजना में ११ तथा द करोड़ इपयो की व्यवस्था क्रमशः की गर्ड थी। योजना के श्रन्त तक काराहला पर ५५ करोड़ रुपये वम्बई पर ११ करोड़, श्रीर कलकत्ता पर ३'५ करोड़ रुपये ब्यय किये बा चुके थे।

"मुख्य मुख्य बन्दरगाहीं की चुमता प्रथम योजना काल में २०० करोड टन से बढ़ कर २५० करोड़ टन हो गई। १६५०-५१ में कुल माल जो इन मुख्य बन्दरगाहों द्वारा छतारा श्रथवा चढाया गया १८० २ कराइ टन या जिसमें ११२ ५ करोड़ टन आयात का माल श्रीर ६७ ७ करोड़ टन निर्यात का माल सम्मिलित था। १६५५-५६ में श्रनुमान है कि उतारे स्त्रीर चढाये जाने वाले कुल माल की मात्रा २२० करोड़ टन थी जिसमें १३० कराड़ टन श्रायात श्रीर ६० टन निर्यात

लगमग २२६ छोटे-छोटे बन्दरगाह २६०० मील के तट पर फैले हुये हैं जिनमें १५० बन्दरगाहों से माल त्राता-जाता है। १९५१-५२ में इन बन्दरगाहों का भाल था।" द्वारा २७६ करोड़ टन माल उठाया गया, श्रीर १६५४ तक यह माला वढ कर ४१ प् करोड़ टन हो गई। प्रथम योजना में इन छोटे-छोटे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में मद्रास, सौराष्ट्र, बम्बई, उडीसा आदि मुख्य स्थान सम्मिलित किये गये थे। कुल व्यय जो किया गया था वह २ करोड़ रुग्यों से कुछ ही कम था।

द्वितीय योजना का साधारण ध्येय है कि प्रथम योजना में जो कार्य आरम्भ किया जा चुका है उसे पूर्ण कर दिया जाय और सर्व सुविचार्त्रों का प्रवन्ध करके डॉकों को आधुनिक रूप प्रदान कर दिया जाय ताकि देश के आर्थिक और अत्रौद्योगिक विकास के कारण जो श्रावश्यकतार्य हो पूर्ण की जा सर्के । ४० करोड़ क्यये की व्यवस्था बहे-बडे बन्द्रगाहों के सुघार कार्य कम के लिये को जा चुको है। जो निर्माण कार्य श्रारम्म किये जार्येगे, जिनमें प्रथम योजना के श्रवूरे कार्यों को पूर्ण करने का कार्य मी सम्मिलित होगा, उनमें लगभग ७६ करोड रुपया व्यय होगा। योजना में व्यवस्थित ४० करोड रुपये के श्रांतिरिक्त कुछ घन बन्दर-गाहों के श्रपने निजी कोषों से भी प्राप्त होगा। योजना में निर्धारित धन सरकार की श्रोर से कारहला में लगाया जायगा श्रीर पोर्ट ट्रस्ट की सहायता ने लिये दिया जायगा। वर्तमान रियायती श्रुण की पोर्ट ट्रस्ट के लिये सुविधा दूसरी योजना काल में भी रहेगी। दितीय पचवर्षीय योजना के बड़े-बड़े बन्दरगाहों के सुधार के नार्यक्रम में कलकत्ते मे १६६ करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, बम्बई में २६ ३ करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, कोचीन में ४० करोड रुपया व्यय किये जाने वाली, योजनाएँ हैं।

मारत में लगभग १५० छोटे वन्दरगाह हैं जिनमें से १८ विशेष महत्व के हैं। उनका सुघार श्रत्यन्त श्रावश्यक है। प्रथम योजना में छोटे छोटे वन्दरगाहों के सुघार की योजनाएँ सम्मिलित की गई थीं जिनका कुल व्यय २४१ करोड स्पया नियत था, इसमें से १ करोड केन्द्रीय कीप से प्राप्त होना था श्रीर शेष वन्दरगाहों के कर्मचारियों को श्रपनी श्रोर से एकत्रित करना था। द्वितीय योजना में छोटें-छोटे बन्दरगाहों के सुधार के लिए ५ करोड स्पया नियत किया गया है।

### अध्याय ३७

### हवाई यातायात

वर्तमान युग में देश के श्रीद्योगिक,श्राधिक ग्रीर श्रन्य कार्यों का मूलाधार 'गति' है श्रीर यातायात के मूलाधार हैं यात्रियों एवम् सामान का तीव्र गति से यातायात कर सकने वाले साघन । भारत जैसे विशाल देश में हवाई यातायात का विशोष महत्व है। विमानों द्वारा यात्रा करने से समय की बहुत बचत होती है, अनेक असुविधाओं से बचा जा सकता है, न्यापारी, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य लोग बड़ी कुशलता से कार्य कर सकते हैं, ग्रंपने कारखानों से सम्पर्क रख सकते हैं, दुर-दूर स्थित कार्यालयों से सम्बन्ध वना रह सकता है श्रीर नियत्रण के साथ ही साथ उनका श्रव्छी प्रकार निरीक्तण किया जा सकता है। सकटकाल में, बाढ श्रयवा भूकम्प के समय हवाई यातायात का महत्व श्रीर भी श्रिषिक हो जाता है। इसके श्रातिरक्त शातिकाल में नागरिक उद्भयन के कर्मचारी जो श्रनुभव प्राप्त करते हैं उसका युद्ध के समय सद्दुपयोग किया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और देश विभाजन के पश्चात् भारत की हवाई कम्पनियों ने यात्रियों तथा सामान का यातायात करने में, निरीक्षण करने में श्रीर सरकार के निर्देश पर शरणाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में प्रशसनीय कार्य किया। हवाई यातायात का यथासभव विकास करने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है, इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते हैं।

विकास—यह खेद का विषय है कि मारत में हवाई यातायात अभी अपनी प्राप्तिक अवस्था में है। यद्यपि मारत में १६११ ते ही विमानों का उपयोग आरम्म हो गया था और प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस दिशा में कुछ प्रगति मी की गई थी परन्तु भारतीय हवाई यातायात में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उसके पश्चात् ही विशेष प्रगति की जा सकी। भारत के हवाई यातायात के विकास में कुछ उल्लेखनीय वात हुई हैं: (१) १६२७ में नागरिक उड्डयन विमाग स्थापित किया गया और १६२८ में दिल्ली, कलकत्ता, अम्बई और कराँची में 'फ्लाइग क्लब' खोले गये। विमान-चालको और टेकनीशियनों के शिच्चण की ज्यवस्था की गई और इम्पीरियल एयरवेज सर्विस का १६२६ में दिल्ली तक प्रसार करने का प्रबन्ध किया गया। मारत में हवाई यातायात के विकास का यही प्रारमकाल था, (२) १६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद,

कलकत्ता और कोलम्बों के मध्य हवाई यातायात आरम किया श्रीर तत्पश्चात् कराँची श्रीर मद्रास तक इसका प्रसार कर दिया । देश के कुछ मार्गों पर इण्डियन नेशनल एयरवेन ने भी यातायात कार्य शुरू कर दिया, (३) १६३८ में एम्पायर एयरमेल योजना लागू की गई जो युद्ध प्रारम्म होने पर स्पगित कर दी गई परन्तु तत्पश्चात् बहत सीमित पैमाने पर इसे फिर लागू किया गया; (४) १६४६ में कुछ सुमगठित विश्वासनीय निजी व्यवसायिक सस्पात्रों को ग्रावश्यक सरकारी सहायता देकर देश के श्रन्दर तथा विदेश से इवाई यातायात की सुविधा का विकास एवम् प्रधार काने को प्रोत्धाइन देने के लिए भारत सरकार ने एक निश्चित उद्भयन नीति निर्धारित की । १६४६ में इवाई यातायात लाइसेंसिंग बोर्ड स्थापित किया गया। यह निश्चित किया गया कि लाइसेन्स देते समय बोर्ड इन बालों पर पर विचार करेगा (अ) कम्पनी की विच स्पिति, (व) कार्यक्रमता का उचित स्तर, (स) यातायात की माँग ग्रोर (द) जनता की ग्रावश्यकता के श्रनुकुल कम्पनी की इवाई यातायात का विकास कर सकने की समता। वार्ड को लाइसेन्स-प्राप्त कर्म्यानयों के किराये तथा भाडे की श्राधकतम तथा न्यूनतम दर निर्धारत करने का श्राधिकार दिया गया। नोर्ड ने श्रपने कार्यकाल में श्रनेक कम्पानयों को लाइसेन्स दिये। इसका परिखाम यह हुआ कि इवाई यातायात में बहुत सी कम्पनियाँ चाल हो जाने से जटिलत। या गई श्रोर इनमें परस्पर हानिकारक प्रतियोगिता चलने लगी। इससे कम्पनियों को चति भी उठानी पड़ी, (५) मारत सरकार ने टाटा के सहयोग से विदेशी हवाई यातायात के लिए एयर इशिहया इन्टरनेशनल की स्थापना की। टाटा के साथ यह समसीता किया गया कि इस नई कम्पनी में ४६ प्रतिशत शेयर सरकार लेगी जो ५१ प्रतिशत तक बढाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ५ वर्ष तक यदि घाटा हुआ तो इस घाटे की भी सरकार पूर्ण करेगी।

ह्वाई यातायात जॉच सिमिति (१६४२)—हवाई यातायात जाँच सिमिति
ने, जो राजाव्यस् कमेटी के नाम से श्रिषक प्रसिद्ध है, भारतीय हवाई कम्पनियों
की स्थिति श्रीर उनकी समस्याश्रों की पूर्य जाँच की श्रीर इस परिणाम पर पहुँची
कि हवाई यातायात लाहसेन्सिय बोर्ड ने श्रपना कार्य सन्तोष-जनक रीति से नहीं
किया श्रीर बिना किसी प्रकार का मेद किये कम्पनियों को लाइसेन्स दिये, जिसका
परिणाम यह हुआ कि दो वर्ष के श्रन्दर ११ कम्पनियों को लाइन्सेस मिल गये
जब कि सपूर्य कार्य केवल चार कम्पनियाँ श्रच्छी प्रकार चला सकती थीं। इतनी
श्रिषक कम्पनियाँ होने से उन्हें हानि उठानी पढ़ी, इसके साथ ही हवाई कम्पनियों
ने सतकता से कार्य नहीं किया श्रीर कम्पनी के सङ्गठन इत्यादि में बहुत श्रीषक

रुपया न्यय किया जब कि यातायात की स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं या। कम्पनियों का उत्पादन न्यय भी पेट्रोल के मूल्य १ रुपया १४ श्राना प्रति गैलन (१९४६) से बढकर १९४९ में २ रुपया ९ श्राना प्रति गैलन हो जाने से, बढ गया।

या कि इवाई कर्म्यानयों के राष्ट्रीयकरण के पन्न में नहीं थी। समिति का मत या कि इवाई यातायात के चेत्र में समय के अनुकूल परिवर्तनशील नी।त की और साहस-पूर्वक नयी योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता है परन्तु यदि इवाई कम्पनियों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो इसकी सभावना कम हो जायगी। इस कारण समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान कम्पनियों का चार कम्पनियों में एकीकरण किया जाय और वम्बई, क्लकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में उनके अद्भे स्थापित हों। इससे हानिकारक प्रतियोगिता कम हो जायगी और कम्पनियों में कार्य का वितरण भी वैज्ञानिक तथा चेत्रीय आधार पर किया जा सकेगा। सिमित ने सुकाव दिया कि उड़ान के घरटों में कमी करने के लिए वर्तमान कम्पनियों की मार्गों को निर्धारित कर दिया जाय, विमानों की सख्या घटा दी जाय, अतिरिक्त कमेचारियों की छटनी की जाय, और इवाई यातायात के सचालन-व्यय, उचित लाभाश और विमानों का प्रयोग करनेवाले यात्रियों की स्थाल पर विचार करके किराये तथा भाडे की दर में वृद्धि की जाय। सिमित ने सिफारिश की कि स्टैन्डर्ड-व्यय के आधार पर इवाई कम्पनियों को सरकार आर्थिक सहायता दे।

राष्ट्रीयकर ग् — हवाई कपनियाँ स्वेच्छा से एकीकर ग के लिए प्रस्तुत नहीं हुई जैसी कि हवाई यातायात जाँच समिति को आशा थी। हवाई यातायात में अव्यवस्था के कार ग कम्पनियों की भारी ज्ञति उठानी पड़ी और उनकी स्थिति हाँवाडोल होने लगी। यद्यपि जाँच समिति ने राष्ट्रीयकर ग के विषद अपनी राय प्रकट की थी परन्तु हवाई कम्पनियों की विगवती दशा को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय कर ग करने का निश्चय किया। यह तर्क किया गया कि (१) राष्ट्रीयकर ग हो जाने से उड़ान में जो समय व्यर्थ नष्ट होता है वह कम हो जायगा, एक ही कार्य अनेक वार नहीं करना पढ़ेगा और हानि भी कम हो जायगी, (२) राष्ट्रीयकर ग से समुक्त प्रवन्ध होने से हवाई यातायात की कार्य ज्ञमता बढ़ेगी और (३) नागरिक उद्धयन का अच्छा सङ्गठन किया जा सकेगा जिससे युद्ध जैसे सकट काल में विमान चालकों, टेकनीशियनों हत्यादि के अभाव का सामना नहीं करना पढ़ेगा।

हवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये ससद ने १६५३ का हवाई यातायात कार्पोरेशन कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत १ अगस्त १६५३ को दो कार्पोरेशन स्थापित किये गये जिनमें से एक देश के अन्दर के हवाई यातायात श्रीर दूसरा विदेशी यातायात सर्विसं का प्रान्ध करेगा। मुश्रावजे के सम्बन्ध में बहुत विवाद चला। यह कहा गया कि मुश्रावजा मूल मूल्य में से टूट-फूट का व्यय घटाकर नहीं वरन् विमानों, विमान के श्रातिरिक्त कल-पुनों इत्यादि के वर्तमान बाजार-भाव के श्राधार पर दिया जाय। श्रानुमान था कि मुश्रावजे के वर्तमान श्राधार पर डेकोटा विमान लगभग ५०,००० चपये में लिया जा सकता है जन कि उसका बाजार-माव तीन लाख रुपया है, श्रीर स्काई मास्टर विमान ४ से ६ लाख रुपये में लिया जा सकता है जनिक वाजार में उसकी वर्तमान कीमत ३० लाख रुपया है। कानून में 'गुड़विल' के लिए, कपनियों द्वारा कर्मचारियों की शिक्ता में श्रीर नवीन मार्ग पोलन इत्यादि में व्यय किए गए वन का उचित मुश्रावजा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु यि इन सब के लिए मुश्रावजा दिया जाय तो व्यय बहुत बढ जायगा श्रीर राष्ट्रीयकरण से हवाई यातायात में सुधार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सक्गा। साथ ही राष्ट्रीयकरण से उस घाटे की पूर्ति नहीं की जा सकेगी जिससे वर्तमान कपनियों पीइत हैं।

मुद्रावजे की समस्या १६५५ में ६०१ करोड़ रुपया देकर सदा के लिये निश्चित कर दी गई। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के पिग्णामस्वरूप वेकारी का प्रश्न था, यह निश्चित कर लिया गया कि वे सब कमेंचारी जो ३० जून १६५२ के पूर्व कम्यानयों द्वारा नियुक्त किये गये थे उनकी बदली कारपोरेशन में कर दी गई श्रीर इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है कि कमेंचारियों को पुर्नव्यवस्था श्रोर विस्तार के कार्य-कम में लपा लिया जान।

वर्तमान स्थिति—१६५३ के ग्रारम्भ में भारत में ६ इवाई कपनियाँ थीं जिनके पास २१६ कराइ रुपये की ग्राधकृत पूँजी ग्रीर टूट-फूट के कोष में ३ करोड़ रुपये से कुछ कम थे। इन कम्पनियों के निमान कुल २८,००० मील के चेत्र में चलते थे। जून १६५२ के ग्रन्त तक भारत में ६७७ र्राजस्टर्ड विमान थे, जिनमें २०३ विमानों को यायता के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके थे। इवाई श्रद्धों पर कार्य करने वाले लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ५५७ यी तथा ए लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या ५६२, ए-१ के लाइसेंस-प्राप्त विमान चालकों की संख्या ४२६ थी। इसमें पहले वर्ष की तुलना में इझीनियरों तथा 'ए' लाइसेन्स-प्राप्त विमान चालकों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु ए-१ चालकों श्रीर बी. लाइसेन्स प्राप्त चालकों की संख्या घट।।

रहपर श्रीर ५३ में इवाई यात्रा की स्थिति में श्रवनति होती रही श्रीर यात्रियोंकी सख्या श्रीर यातायात के माल की मात्रा में कमी श्राई जिसके कारण रहप ३ में यात्रियों की सख्या घटकर ४०४ लाख श्रीर ढुलाई के माल की मात्रा घट कर प्र'प्त लाख पौड हो गई जबिक यह सख्या १६५२ में कमशः ४'३ लाख एव प्र'प्त लाख पौड थी। इसका कारण कुछ तो जनता के पास धन की कमी श्रीर कुछ भारतीय हवाई सर्विस की दुर्ज्यवस्था थी। यद्यपि ढाक की मात्रा १६५२ में बढकर प्र लाख पौंड श्रीर १६५३ में प्र लाख पौंड हो गई फिर भी यात्रियों श्रीर यातायात के माल की कमी का घाटा इससे पूर्ण न हो सका।

भारत में हवाई कम्पनियों के कार्य के असतीषजनक होने के अनेक कारण हैं: (१) हवाई कम्पनियों के कार्य-एचालन का न्यय बहुत श्रधिक है। इसमें विमानों में प्रयुक्त होनेवाले पेट्रोल श्रीर विमानों की देख-रेख इत्यादि का व्यय सम्मिलित है। कुल सचालन व्यय का ५० प्रतिशत पेट्रोल, विमान के कल-पुर्जी श्रीर स्टोर में व्यय होता है स्रोर ४० प्रतिशत पारिश्रमिक तथा वेतन में । श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पारिश्रमिक श्रीर वेतन अविक निर्धारित किये गये हैं झौर पेट्रोल, स्टोर इत्यादि के व्यय में वृद्धि हवाई कम्पनियों की शक्ति के बाहर है। सचालन व्यय श्रधिक होने का एक कारण तो सरकार की नीति का दोप है श्रीर कुछ दोष उन परिस्थितियों का है जिन पर हवाई कपनियों का कोई नियत्रण नहीं श्रीर इसके लिए कम्पनियों को दोषी मी नहीं ठहराया जा सकता है. (२) इवाई कम्पनियों की सख्या यातायात को देखते हुए श्रावश्यकता से श्रधिक है, इस कारण किसी भी कम्पनी को पर्याप्त कार्य नहीं प्राप्त होता। इस दोष के लिए हवाई यातायात लाइसेन्सिंग बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड ने श्रनेक कम्पनियों को उद्योग चालू करने की श्रनुमित दी श्रीर श्रावश्यकता का ध्यान रखे बिना विमानो की सख्या बढाने दी, (३) कम्पनियों की कार्यज्ञमता को देखते हुए कार्य पर्यात नहीं है परन्तु यह व्यवसाय ऐसा है जिसमे कुछ विमान चालको, इङ्जीनियरों और टेकनीशियनों को नियुक्त करना पडता है। इसके फलस्वरूप कम्पनियों को स्रावश्यकता से स्रधिक कर्मचारियों का भार वहन करना पड़ता है, (४) किराये स्त्रोर माडे की जो न्यूनतम स्त्रौर अधिकतम दरे सरकार ने निश्चित कर दी हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। प्रति यात्री से प्रत्येक मील के लिए श्रिधिक से श्रधिक ४ श्राना किराया वस्त्ल किया जा सकता है परन्तु रात मे चलनेवाली डाक सर्विस के लिए किराये की दर २६ आना प्रति मील है । यह किराया भार-तीर्य वायुयान कम्पनी के व्यय से बहुत कम है। यदि एकं विमान पूर्ण वर्ष में १५०० घरटे चलाया जाय तो प्रति घरटे का स्टेन्डर्ड न्यय ५८६ रुपया होता है। इसिलिए प्रत्येक सीट का प्रति मील का किराया विमान की ७ प्रतिशत जगह भरने

तालिका नं० १ श्रमुस्चित भारतीय दवाई सेवायों के श्राकडे

	0 %			كالمنتب بنبيا المتالية للمتلكسية
वर्ष	यात्रा गीलो ग (दस- लारा गें)	यानियो की सम्दर्भ	यातायात मारा वी माना (दग साना विक मे)	हार की मापा (इंग्र लाग पीट में।
1878	844	* 67 54 4	- ==	F0°4
१६४७	६३६	२५४८६०	чч	₹*¥0
\$£4≃	१२६५	₹ <b>٧</b> , ८८६	\$1 ق ع	१ ४८
3×35	१५.६०	3468\$4	ं द्वपूर	: ५० <b>३</b>
१९५०	₹5 €0	४५२८६६	, =0 + <b>t</b>	· =======
१९५१	<b>6E 170</b>	YYE (EZ	<b>८</b> ७६६	, ot=
१९५२	१६ ५६	Atax=0	<b>⊏</b> 8.0⊀	<b>ت</b> ٠٤٦
१९५३	१६ २०	803563	E ( E ?	ביבוז
<i>1E</i> 4¥	15.20	४३१४६५	, EE.A\$	10 60
े १९५५	२१ २७	¥\$£000	₹= २०	₹₹ <b>*</b> ¥≒
१६५६	२३.४८	4्4्६००•	६६ २३	१२.६६
१६५७	₹3.3¥	4EX000	£4.0€	13.E.A.

के श्राघार पर ४३ श्राना होना चाहिए। चूँ।क किराया यम है इसलिए इवारे कम्पनियों को हानि होना स्वाभाविक ही है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् हवाई सेवाजो की स्थित में घट्टत मुधार हुजा है। उड़ने का विस्तार १९५४ को १९८ फरोड़ मी० से बढ़ कर १९५७ में २३३४ फरोड़ मील हो गया। मेल तथा यात्रियों की सख्या भी बढ़ी है। मेल की मात्रा १९५४ में १०६७ करोड़ पींड यी जो कि १९५७ में बढ़ कर १२९४ करोड़ पींड हो गई ज़ीर यात्रियों की सख्या जो कि १९५४ में ४११५६५ थी बढ़ कर १२५७ में

प्रध्या के शर्म । लादने वाले माल की मात्रा १६५६ में ६६२३ करोड़ पौंड थी जो कि १६५७ में थोड़ा घट गई और ५५०६ करोड़ पौंड हो गई। इस उम्नित का अशतः कारण आपसी विनाशकारी प्रतिद्दन्द्विता का समाप्त हो जाना तथा कुशलता संगठन रहा है जो कि कारपोरेशन की व्यवस्था के कारण समव हो सका है, और अशतः श्रीद्योगिक और आधिक विकाश रहा है जिसके कारण हवाई सेवाओं की अधिक माँग की गई हैं।

टोनों एयर कारपोरेशनो ने बहुत ही सन्तोपजनक उन्नित की है। उन्होंने कार्य-चेत्र बढाया है श्रीर जनता का बहुत सी सुविधार्ये प्रदान को हैं। "ये कारपोशन श्रपनी वायुयान सबन्धी कायों के एकीकरण तथा उनक कुशल सगठन में व्यस्त रहे हैं। हाण्डयन एश्रद लाइन्स श्रपने हु३ हवाई जहांजों, ६७ डकोटा, १२ वाहिकग, ६ स्काई मास्टर श्रीर द हेरीन्स के द्वारा देश के प्रमुख वेन्द्रों को सम्बन्धित करते हैं श्रीर उसके हवाई मागों का विस्तार १६,६८५ मील है। दि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल श्रपने वायुयानों द्वारा जिसमें ५ सुपर कान्सटेलेशन्स, ३ कान्सटेलेशन्स श्रोर १ डकोटा है १५ देशों तक श्रपने कार्यों को प्रसारित किये हुये हैं। उसके हवाई मार्ग का विस्तार २३,४८३ मील है।"

इिएडयन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन का कुल कार्य-चेत्र तीन मागो में विमाजित कर दिया गया है। प्रत्येक माग एक मैनेजर के श्रिषकार में है श्रीर वम्बई, कलकत्ता श्रीर देहली के किसी न किसी श्राइ हे से नियत्रित होगा। श्राई • ए० सी० को निरन्तर घाटा हो रहा है। १६५४-५५ में इस घाटे की रकम ६०१५ लाख रुपया, १६५५-५६ में ११६-४० लाख र० श्रीर १६५६-५७ में १०८० ७६ रुपया थी। परन्तु इसके विपरीत एयर इन्डिया इन्टरनेशनल को निरन्तर लाम होता रहा है। श्राई ० ए० सी० के घाटे का कारण श्रधतः कर्मचारियों को श्रत्यिक सख्या का होना है तथा श्रधतः सेवा की श्रत्यिक लागत श्रीर वे कठिनाइयाँ है, जो इसे उन प्राइवेट कम्पनियों से मिली थी जिन्हे इसने ले लिया था।

ह्वाई भाड़ा—अपनी आयिक स्थिति को सुधारने के लिये तथा हानि बचाने के लिये ए० आई० सी० ने अपने भाडे की दर में वृद्धि की घोषणा १५ ज्न, १६५८ से एअर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की सलाह के अनुसार की। किसी-किसी मार्ग के भाडे में वृद्धि १०% हुई है और अब बम्बई से कलकत्ते का किराया बनाय २२० र० के २४२ र० हो गया है। इस माडे की वृद्धि से ए० आई० सी० को ३० लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। इससे हवाई सेवा पर लगाये टेक्स के कारण तथा पेट्रोल पर लगाये टेक्स तथा श्रन्य टेक्सों के कारण इवाई सेवा की लागत में वृद्धि का प्रभाव घटाया जा सकेगा—

ए० त्राई० सी० के लिये एम्रर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल ने हवाई माडे में वृद्धि की सिपारिश की श्रीर निम्न दरों का सुक्ताव दिया .

मील		प्रति मील प्रति यात्री भाइा
		श्राना पाई में
१ से ३० तक		<i>०</i> —६ <b>—</b> ६
३१ से १०० तम	•	o-4-0
१०१ से २०० तक		<i>3—</i> 8—0
२०१ से ५०० तक		•—४ <del>—</del> ६
५०१ से ६०० तक	•	o-8-3
६०० से ऊपर		o80

काउन्सिल की सिफारिश का श्राधार—"श्रार्थिक एिट कोण से श्राधिकतम सख्या में यात्रियों को श्राधिक काम में श्राने वाले मागों की सेवा का प्रयोग करने का प्रोत्साहन देना था ताकि कम प्रयोग में लाये जाने वाले मागों से होने वाले घाटे के कारण जो सेवा की लागत श्रीर ग्राय में श्रन्तर होता या वह न रहे श्रीर हवाई यात्रा के लामों के कारण लोगों के मन में हवाई यात्रा करने की इच्छा स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाय।" श्राधिक श्रच्छा होता यदि सरकार टेन्सों की मात्रा कम करके उनकी सहायता करती श्रीर कारपोरेशन श्रपना खर्च कम करने का प्रयत्न करते। हवाई यात्रा के माढे के बढ जाने से उसकी सर्विप्रयता के घट जाने का मय है। एयर ट्रान्सपोर्ट काउन्सिल की श्रत्यसख्यक रिपोर्ट ने भी यह सकत किया है कि, "मारत में हवाई यात्रा की किंची दरों के कारण हवाई यात्रा के प्रति श्राकर्पण के नष्ट होने का भय है श्रीर इस बात की श्राशका है कि लोग बहुत बढी मात्रा में हवाई जहाजों द्वारा यात्रा के स्थान पर रेल द्वारा यात्रा करना श्रीयक पसन्द करने लगेंगे।"

योजना के श्रन्तर्गत—प्रथम योजना के श्रन्तर्गत वायुयान कारपोरेशन के निमित्त ६ ५ कराइ रुपयों का व्यय नियत किया गया था। पर वास्तव में प्रथम योजना में १५ ४ करोइ रुपया व्यय किया गया था जिसमें ६ करोइ रुपयों की रकम एयर काफ्ट खरीदने के लिये सम्मिलित थी। कुछ धन की मात्रा भूमि पर यातासाद के साधन खरीदने, वर्तमान दफ्तरों के सुधार तथा नये दफ्तरों के खोलने पर भी व्यय की गई थी।

दितीय योजना में ३० ५ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें से १६ करोड़ रुपया तो इन्डियन एग्रर लाइन्स कारपोरेशन पर श्रीर १४५ करोड एयर इन्डिया इन्टरनेशनल पर व्यय किया जायगा। व्यय के मुख्य शीर्षक निग्न हैं:—

	करोड़ रुपये में
मुग्रावजे का चुकाना	५ १४
एश्चर जाफ्टो का कय	<b>१५</b> ३४
इन्डियन एथ्रर लाइन्छ के कार्य में हानि	9 00
इन्डियन एश्रर लाइन्स के दक्तर श्रीर क्रमंचारियों के श्रावास	০ৠ০
एश्रर इन्डिया इन्टरनशनल के कारखाने का विस्तार	१•६५
टन्डियन एग्रर लाइन्छ के श्रावण्यक सामान	० ५०
एग्रर इन्डिया इन्टरनेशनल के ऋणपत्रों का चुकाना	30 0
कुल	३०५५३

इन्डियन एश्रर लाइन्छ के बेढे को श्राधुनिक बनाने के निमित्त ब्यय का प्रमन्ध किया जा रहा है। कारपोरेशन ने ५ वाई काउन्टों के क्रय करने के लिए प्रथम योजना में ही त्रार्टर दे रक्खा था श्रोर श्राशा की जाती है कि १६५७ के मध्य तक वे श्रा जायेंगे श्रोर श्रन्य जहाजों के क्रय करने के लिये श्रार्डर दिये जाने के सम्पन्म में छान भीन की जा रही है। इन्डिया इन्टरनेशनल के लिए यह क्यवस्था की गई है कि कुछ टवों-प्राप या जेट एश्रर काफ्ट बढी हुई माँग को पूर्ण करने के लिये तथा श्रितिक सेवा के लिये क्रय किए जाये। इवाई सेवाश्रों के विस्तार के कार्यक्रम को निश्चित करते समय श्रनेकों वातों का ध्यान में रत्यना श्रावश्यक होगा जैसे कि क्रय किये जाने वाले एश्ररकाफ्टों के प्रकार, उनको चलाने का व्यय, किराये-भाडे की दर, सगठन की छश्शलता, हानि रोकने की सम्भावना, सेवाशों की सुरज्ञा, श्रीर देश के सभी भागों को कुशल हवाई सेवा झारा एक दूसरे से सम्मन्वत कर देने की श्रावश्यकता इत्यादि।

## अध्याय ३८

# यातायात का परस्पर सम्बन्ध और नियोजन

भारतीय यातायात व्यवस्था में सुमम्बन्ध स्थापित करने श्रीर उसका नियोजन करने की दृष्टि से यातायात की सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए, यातायात के विभिन्न साधनों में होने वाली अनुचित प्रतियोगिता को रोकना चाहिए श्रीर उपमोक्ता के लिए यातायात के न्यय को कम किया

भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यातायात के वर्तमान साधन पूर्णतया श्रपर्यात हैं। यदि प्रति न्यक्ति को प्राप्त यातायात की मुनिषा की भारत के वरावर चेत्रफल श्रीर जनसंख्या वाले श्रन्य देशों से तुलना की जाय तो जान होगा की भारतीयों को श्रन्य देशों के नागरिकों की श्रपेक्षा यातायात की वहुत कम सुविधा प्राप्त है। यदि रेलवे श्रीर इवाई मार्ग की लम्बाई दूनी कर दो जाय और जलयानों की माल दोने की शक्ति को चार गुना बढा दिया जाय तब भी इसे बहुत श्रिषक नहीं कहा जा सकता है, हाँ इससे देश की आवश्यकता अवश्य पूर्ण हो सकती है।

किसी मी देश के यातायात की सुविधा में वृद्धि का उसके श्रीद्योगिक श्रीर श्राधिक विकास से निकट सम्बन्ध होता है। देश के श्राधिक विकास के लिए यह त्रावरयक है कि उसमें यातायात की सुविधा पर्याप्त हो, सस्ती हो श्रीर यातायात की गति तीव हो। उद्योगी के लिए यातायात व्यय उत्पादन का महत्वपूर्ण त्रम है इसलिए उद्योगों का न्यय घटाने के लिए यातायात का न्यय घटाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यावायात व्यय कम होने से उद्योगी की प्रतियोगिता शक्ति बढेगी श्रीर माल का उपभोग भी बढेगा। किसी भी देश की प्रगति में उसके यातायात की व्यवस्था, रेलवे, सहकों श्रीर हवाई जहांनी तथा जलयान कम्पनियों की किराया एव भाड़ा नीति श्रीर उसमें विभिन्न प्रकार के सामानों के यातायात की सुविधा का विशेष योग होता हैं। यदि यातायात नीति दोषपूर्ण है तो उद्योगों का स्थानीकरण मी दोषपूर्ण होगा। यातायात पर केवल उद्योगों का विकास निर्मर नहीं करता है किन्तु श्रीद्योगिक विकास के प्रकार पर भी यातायात का मकार श्रीर उसका विकास निर्मर करता है।

पचवर्षीय योजना में बताया गया है कि त्रागामी कुछ वर्षों में देश में

खाद्याल का उत्पादन बढने से श्रीर सिन्द्री में रसायिन क खाद का अधिक उत्पादन होने से इन वस्तुश्रों का श्रायात कम करना पढ़ेगा, जिसके कारण बन्दरगाहों से इन वस्तुश्रों को देश के विभिन्न मार्गो म पहुँचाने के लिए यातायात की कम श्रावश्यकता होगी श्रीर ऐसी स्थित में देश के श्रन्दर हुए उत्पादन को नियत स्थानों तक पहुँचाने के लिए यातायात को ब्यवस्था में वृद्धि करनी पढ़ेगी। दूसरी श्रोर राजगगपुर के सिमेंट के कारखाने से जिसने १९५२ के श्रारम्म से उत्पादन श्रारम्म कर दिया है श्रीर विजयवाडा में स्थित श्रान्ध्र सिमेंट कम्पनी के प्रसार से उपभोग के केन्द्रा में ही उत्पादन व्यवस्था का प्रसार होने के फलस्वरूप यातायात की सुविधा की माँग कम हो जायगी। साधारणतया योजना को कार्यान्वित करने का प्रमाव यह होगा कि यातायात की सुविधाश्रों को बढाने की माँग बढेगी। इसलिए यह श्रावश्यक है कि (श्र) यातायात की सुविधा का प्रसार किया जाय, (व) यातायात की सुविधाश्रों को बढाने के कारणा का प्रसार किया जाय, की यातायात की सुविधाश्रों को बढाने के कारणा का पता लगाया जाय श्रीर (स) यातायात की सुविधाश्रों को बढाने के कारणा का पता लगाया जाय श्रीर सो वातायात की सुविधाश्रों का बढाने के कारणा का पता लगाया जाय श्रीर सम किया जाय।

भारत में वास्तविक कठिनाई यह है कि पचवर्षीय योजना के होते हुए भी विकास की गति बहुत धीमी है। पचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी यातायात की सुविधाएँ देश की आवश्यकता को देखते हुए कम ही रहेंगी। यातायात की सुविधा में तीव गति से प्रगति न होने के अनेक कारण हैं:

(१) वित्त का अभाव है, इस कारण अधिक सहको का निर्माण करने में,
अधिक रेलवे लाइन विछाने में और रेलवे के लिए अधिक रोलिंग स्टाक कय करने
में, सइकों के लिए मोटर तथा वस क्रय करने में और विमान तथा जलयानों को
क्रय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल प्रसार योजना
की माँग पूर्ण करने के लिए ही नहीं किन्तु वर्तमान में चालू गाड़ियों, बसों और
जलयानों को बदलने के लिए, जो कि प्रायः वेकार हो चुके हैं, अधिक गाड़ियों,
वसों और जलयानों की आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने सभी उपलब्ध वित्त
साधनो का यातायात की वर्तमान स्थिति के सुधार में और उसके असार में
सुसम्बद्ध उपाय से व्यय करना चाहिए। दूसरी कठिनाई यह है कि यातायात
के साधनों के लिए आवश्यक सामग्री के मूल्य बहुत बढे हुए हैं। यदि वित्त
आवश्यकता पूर्ण भी हो जाय तब भी उससे इतनी अधिक मूल्यों पर सभी आवस्थक सामग्री नहीं क्रय की जा सकती। वित्त अभाव और सामानों का अधिक
मूल्य होने के कारण भारत में यातायात की सुविधा के प्रसार में बत्ना उत्सन्न हो
जाती है।

- (२) सदक बनाने और रेलवे लाइन विछाने के लिए श्रावश्यक सामान का समाव है। इसके साथ ही मोटरों, रेलों के ढिव्बों, इखनों, जलयानों, विमानों श्रीर इनके श्रलग कल पुजों तथा स्टोर का भी बहुत श्रमाव है। इनमें से श्रिष्काश के लिए भारत को विदेशों से श्रायात पर निर्भर करना पडता है। इघर कुछ वर्षों से भारत में इखनों, जलयानों इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु स्त्रमी बहुत लम्बा मार्ग तय करना है। भारतीय यातायात के विकास की समस्या का (श्र) सदक श्रयवा रेल के निर्माण के लिए श्रावश्यक सामग्री का उत्पादन करनेवाले उद्योगों के विकास से श्रीर (व) मोटर तथा जलयानों का निर्माण करनेवाले उद्योगों के विकास से गहरा सम्बन्ध है। उद्यागों के वीरे-धीरे विकास होने से यातायात की सुविधा की प्रगति भी सीमित हो गई है।
  - (३) कुशल कारीगरो, इजीनियरों, विमान चालको इत्यादि का बहुत श्रमाव है, यातायात की व्यवस्था का विकास करने के लिए इनका श्रमाव नहीं होना चाहिए। इसलए इनकी सख्या को वहुत श्रधिक बढाने की श्रावश्यक्ता है। सरकार ने कारीगरी की शिज्ञा के लिए। वशेष व्यवस्था की है श्रीर यातायात की सुविधाश्रों का प्रसार उसी गति से होगा जिस गति से कारीगरों श्रीर श्रन्य कुशल कर्मचारियों के श्रमाव को पूर्ति होगी।

यातायात म सुसम्बन्ध स्थापित करने की नीति का उद्देश्य है कि उपभोक्ता को यातायात में कम से कम व्यय करना पड़े। इसका तर्कसगत परिणाम।यह निकला कि हमें यातायात के उन सभी साधनों को समाप्त कर नये साधनों का उपयोग करना पढेगा जो उपयुक्त नहीं हैं: समय की मॉग पूर्ण नहीं कर सकते हें श्रौर पुराने हैं। उपमोक्ता के लिए सड़क यातायात रेलवे की श्रपेन्ना श्रधिक सस्ता श्रीर सुविधाननक है क्योंकि सहकों से श्रासपास के सभी चेत्र लाम उठा सकते हैं श्रौर रेलवे स्टेशन तक माल ले जाने श्रीर वहाँ से लाने में जो श्रनावश्यक व्यय होता है उसकी बचत हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि सदक यातायाव के प्रसार त्रीर विकास से या तो रेल यातायात बन्ट हो जायगा या उसका चेत्र सक्कांचत हो जायगा। यदि मोटर, ट्रक श्रोर वसें वेलगाहियों से श्रधिक वचत वाले श्रीर तीवगति चल सकने वाले साधन हैं तो इसका तात्पर्य है कि नगरों श्रीर कस्बों में वैलगाहियों का श्रास्तत्व ही रह जायगा। यदि माप से चलानेवाले जलयान हवा से चलने वाले जलयानो से श्रधिक बचत वाले हैं तो हवा से चलने वाले जलयानों की त्रावश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु व्यवहारिक चेत्र में इस प्रकार का तीव परिवर्तन न तो संभव है ग्रीर न इसकी सलाह दो जा सकती है क्योंकि (१) पूँजी इस समय ऐसे साधनों में लगी हुई है जो आधुनिक सामनों की तुलना में कुशल साधन नहीं कहे जा सकते। यदि इन साधनों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या इनका कार्यचेत्र सकुचित कर दिया जाय तो इसके परिशामस्वरूप राष्ट्र को गहरी चिति पहुँचेगी। ऐसी स्थिति मे यातायात के दुराने साधनों के स्थान पर नये साधनों का उपयोग करना एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें काफी श्रिषक समय लगेगा। यातायात के कुशल श्रीर उपयुक्त साधनों का धीरे-धीरे उपयोग बढाया जायगा श्रीर श्रकुशल तथा श्रपेचाकृत कम उपयुक्त साधनों को धीरे धीरे हटाया जायगा। यह प्रक्रिया तब तक प्रचलित रहेगी जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता; (२) मारत में कुछ समय तक हवा से चलने वाले जलयानों श्रीर वैलगाहिया का उपयोग करना पढेगा श्रन्यथा यातायात की माँग श्रीर उसकी पूर्ति का श्रन्तर श्रीर बढता जायगा। मारत मे यातायात की कुल व्यवस्था ऐसी है कि इम श्रमी काफी समय तक श्रकुशल श्रीर पुराने साधनों को समाप्त नहीं कर सकते।

इस स्थित को स्थान में रखते हुए इस दिशा में सर्वोत्तम नीति यह होगी। कि वर्तमान के यातायात के साधनों को प्रचलित रखा जाय श्रीर (श्र) कार्य को सुनियोजित करके, कुछ साधनों के अत्यधिक कार्य भार को हलका करके श्रीर अनेक साधनों की उपयुक्त शक्ति का उपयोग करके यातायात की वर्तमान व्यवस्था का दुरुपयोग बचाया जाय, (व) यातायात से विभिन्न साधनों की परस्पर अर्जुचित मित्योगिता को रोका जाय, साथ ही एक ही प्रकार के साधन की विभिन्न इकाइयों की अनुचित मित्योगिता को समाप्त किया जाय, श्रीर (स) रेलवे, सहक, जल यातायात तथा हवाई कपनियों को उचित लाम के साथ ही साथ उपमोक्ताओं के लिये यातायात सस्ता किया जाय।

वर्तमान में रोडवेज और रेलवे, रेलवे श्रीर जल यातायात श्रीर रेलवे तथा वायु यातायात मे तीव प्रतियोगिता, नहीं है। यातायात के सभी साघनों का श्रभाव है श्रीर सभी साघनों के कार्यचेत्र पर्याप्त हें इसिलए कुछ अपवादो को छोड़कर व्यापार इियाने के लिए इनमे कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न साघनों का किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। सरकारी बसे वर्तमान में वम्बई तथा उत्तर प्रदेश में भिन्नभिन्न किराया वस्ति है। बम्बई का किराया में ह पाई प्रति मील है श्रीर उत्तर प्रदेश का ७३ से ह पाई प्रति मील है, जब कि रेल की तीसरी श्रेणी का किराया साधारण या डाक गाड़ी से १५० मील तक क्रमशः ५३ श्रीर ६५ पाई प्रतिमील है। वायुयान का किराया प्रायः ४ श्राना प्रति मील है श्रीर रात की हमान सर्विस से किराया २३ श्राना प्रति मील है । जब कि रेलवे की प्रथम

श्रेगों का किराया २ है से २ ई श्राना प्रति मील है। वसों श्रीर रेलों में कुछ चेत्रों में अवश्य प्रतियोगिता चलती है पर वड़े पेमाने पर कोई श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं है। वायुयान से यात्रा श्रमी श्रवश्य कुछ महगी है श्रीर रेलवे यात्रा से कुछ श्रिषक भयपद भी है। कुछ उच्च श्रेगों के यात्रियों के श्रांतिरक्त वायु यातायात से रेलवे को कुछ हानि नहीं है परन्तु मिष्य में जैसे-जैसे सहक श्रोर वायु यातायात श्रिषक सरता श्रीर कम भयपद होता जायगा वैसे-वैसे रेलवे से प्रतियोगिता भी वहती नायगी।

मारत के कुछ मागों में जलयानों द्वारा तटीय यातायात में श्रीर रेल वे यातायात में प्रतियोगिता चलती है श्रीर देश के विमानों की तटीय व्यापार में जलयानों से प्रतियोगिता चलती है परन्तु तटीय जलयान व्यापार को नियमित कर देने से यह प्रतियोगिता कम हो गई है। भविष्य में पुन प्रतियोगिता बढने की सम्मावना है, परन्तु इनमें प्रमुचित प्रतियोगिता बढने का कोई कारण नहीं है। भविष्य में रेलवे लाइन से समकोण बनाती हुई सडकों का निर्माण करक श्रीर सक्कों के प्रसार की ऐसी योजना बनाकर कि उनसे विभिन्न बन्दरगाहों में जल यातायात की श्रावश्यक्ताश्रों की पृति हो सके यातायात के विभिन्न साधनों के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकने की पूर्ण सम्भावना है। रेलवे तथा जल यातायात के बीच उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें व्यवस्था की गई है कि मंगलीर बन्दर से रेल सम्बन्ध चिकामगलुर होते हुए मद्रास से सम्बन्धित किया जाय।

यदि यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण किया जाय तो इनमें परस्पर ठाचत सम्बन्ध स्थापित कर सकना सुगम हो जायगा। यदि सभी साधनों की स्वामी सरकार हो श्रीर वही इनको चलाये तो सइकों को जोडने श्रीर एक स्थान पर कई प्रकार के यातायात उपलब्ध होने इत्यादि में व्यर्थ रुपया नहीं लगाना पढ़ेगा। निजी उद्योग होने पर ऐसा श्रावश्यक हो जाता है। सरकार ने सइक यातायात का एक सीमित चेश्र में राष्ट्रीयकरण किया है जिसके कारण इन चेत्रों में रोडवेज श्रीर रेलवे के मध्य कोई श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीयकरण किया है जिसके कारण इन चेत्रों में रोडवेज श्रीर रेलवे के मध्य कोई श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं है। यह सइके विभिन्न चेत्रों को रेलवे मार्ग से सम्बन्धित करती हैं। सइक यातायात को निष्टिचत चेत्र में एक विशेष दूरी तक सीमित करक श्रीर रोडवेज सर्विस को उन सइको पर चालू करके जहाँ रेलवे यातायात की सुविधा नहीं है यह परिणाम निकला है। रेला से यात्रियों की सुविधा का प्रवन्ध बढ़ा है श्रीर किराये में भी वृद्धि हुई है श्रीर इससे दोनों में श्रनुचित प्रतियोगिता की हानियों को समाप्त कर दिया गया

है। यद्यपि राष्ट्रीकरण कर देने से अनुचित प्रतियोगिता तो समाप्त की जा सकती है परन्तु यह न्यवस्था सभी स्थितियों में सुविधाजनक सिद्ध नहीं हो सकती। मारतीय रेलों श्रीर वायुयान कम्पनियों का कुछ थोडे छोटे मार्गों को छोड़ कर पूरी तरह राष्ट्रीकरण किया जा चुका है श्रीर सहक यातायात का बहुत सा भाग भी राज्य सरकारे ले चुकी हैं, परन्तु कुछ चेत्रों में सहक यातायात श्रीर पूरा जल यातायात श्रमी निजी उद्योगपितयों के हाथ में है। यातायात के सभी साधनों का राष्ट्रीकरण करना सम्भव नहीं है क्योंकि (१) श्रावश्यक कर्मचारियों का श्रमाव है श्रीर (२) हानि होने का डर है। यह हानि विशेषकर जल यातायात में श्रिषक हो सकती है क्योंकि इसका पूर्ण विकास नहीं हो सका है श्रीर उसे विदेशी जलयान कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। यह कहना श्रमुचित न होगा कि राष्ट्रीकरण से हानिकारक प्रतियोगिता की समस्या सुलक्ताई जा सकती है। इसके साथ ही इससे एकाधिकार के दोप भी उत्पन्न हो सकते हैं जैमे उपभोक्ता के हितों की उपेजा, कार्य ज्यय में वृद्धि श्रीर श्रकुशल कार्य। यदि हानिकारक प्रतियोगिता को समाप्त करने से नई समस्याएँ उत्पन्न हो जाय तो इस ज्यवस्था को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

यातायात का पूर्ण राष्ट्रीकरण न हो सकने पर भी यातायात के विभिन्न साधनों में निम्नलिखित उपायों से परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है:—(१) कानून द्वारा प्रत्येक प्रकार के यातायात के कार्यचेत्र को निर्धारित करके, विभिन्न साधनों के अधिकतम और न्यूनतम किराये की टर निश्चित करके और विभिन्न साधनों द्वारा यात्रियों को दी जानेवाली न्यूनतम सुविधाओं और सामान के यातायात की सुविधाओं को निश्चित करके, (२) यातायात के विभिन्न साधनों के कार्य के निरीक्षण के लिए और उनमें उचित सम्बन्ध स्थापित करने के लिये केन्द्रीय यातायात परिषद् स्थापित करके। यातायात की न्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार शीध परिवर्तन हो जाता है इसिलये यातायात के विभिन्न साधनों के तथा उपभोक्ताओं के हितों की केवल कानून द्वारा ही रचा की जा सकती है। इससे किराये की दरों में घटने-बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो सकती है और जनता को असुविधा हो सकती है परन्तु यह कठिनाइयाँ पर्याप्त अधिकार दिये जाने पर और सन्तोषजनक रीति से कार्य कर सकने के लिए व्यापक चेत्र देने पर राज्य यातायात परिषद् दर कर सकती है।

प्रथम पचवर्षीय योजना मे ५५७ करोइ रुपया यातायात श्रीर सचार विमाग के लिये नियत किया गया था। यह धन योजना के कुल व्यय का २३.६% था। द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत १३८५ करोड़ रुपया, जो कि कुल योजना के व्यय का रू ६% है, यातायात श्रीर सचार विमाग पर व्यय करने के लिये नियत किया गया है। इस १३८५ करोड़ रुपये में से रेलवे, सड़क, सड़क यातायात, वन्दरगाहो, जल यातायात श्रीर हवाई यातायात पर क्रमश ६०० करोड़ (कुल व्यय का १८ ८%), २४६ करोड़ (५१%), १७ वरोड़ (०'६%), ४५ करोड़ (०६%), ४८ वरोड़ (१०%) श्रीर ४३ वरोड़ (०'६%) व्यय किया जायगा। प्रथम योजना के श्रन्तर्गत ५५७ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इन्हीं शीर्पको पर क्रमश. २६८ करोड़ (११'४%), १३० वरोड (५५%), १२ करोड़ (०५%), ३४ वरोड (१४'४%), २६ वरोड (११%) श्रीर २४ वरोड़ रुपया (१०%) व्यय क्या गया था। इन श्रावड़ों से जात होता है कि कुल व्यय का प्रतिशत व्यय रेलवे पर बढ़ा दिया गया है।

	१९५०-५१ की स्थिति	१९५५-५६ में श्रनुमानित स्थिति	१६६०-६१ तक घ्येय
रेलवे			
(१) पैसेन्जर गाड़ियाँ (मील दस लाख में) (२) माल नो लाटा गया(दस लाख टनों मे) सडक	દપ દશ	१०८ १२०	१२४ <b>१</b> ६२
(१) राष्ट्रीय राजपथ (हजार मीलों में) (२) सरफेस्ड रोड्स (हजार मीलों मे) जहाज—	१२ ३ ६७	१२ E १०७	<b>१३</b> ∙⊏ <b>१</b> २५
(१) तटीय श्रीर पहोंची से सम्बन्धित टेन्करों को सम्मिलित करते हुये (लाख जी श्रार टी.) (२) समुद्र पार ट्रैम्प टनेज को सम्मिलित	<b>२</b> २	3 च्	8 3
करते हुये (लाख जी त्रार टी) वन्दरगाह—	१७	२८	80
स्वा करने की शक्ति (टस लाख टनों में)	२०	२५ ०	३२५

जपर दिये गये श्रॉकडों से यह ज्ञात होता है कि दितीय योजना के श्रन्त-गत स्वतोन्मुखी विकास का प्रयत्न किया जायगा। १९५५-५६ की तुलना में सब से श्रांघक प्रांतशत वृद्धि १९६०-६१ में समुद्र पार की जल यातायात के सम्बन्ध में की जायगी। जल यानायात के सम्बन्ध में ६८%, रेलवे में ३५%, तटीय जल यातायात में ३४% श्रीर बन्दरगाहों पर माल उतारने चढाने की शक्ति में ३०% की वृद्धि की जायगी।

प्रथम पचवर्षीय योजना का मुख्य स्येय यातायात सम्बन्ध मे यह या कि यथासम्भव गत १० वर्षों से ऋत्यविक कार्य में आने वाले प्रसाधनों को बदल कर नया कर दिया जाय। रेलवे के सम्बन्ध में यह कार्य बहुत कठिन था। जल यातायात, वन्दरगाहों, प्रकाशस्तम्भो, वायु यातायात श्रादि के सम्बन्ध में भी इस कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि नियत करना श्रावश्यक थी। प्रथम योजना काल में क्योंकि कृषि ग्रीर उद्योगों की उत्पत्ति में वृद्धि हो गई थी इसलिये याता-यात की सुविधा के ग्राभाव का ग्रानुभव विशेषकर योजना के तीसरे वर्ष से होने लगा था। इस स्थिति का सम्भालने के लिये श्रातिरिक्त धन का श्रनुमान रेलवे, सहकों, जन यातायात, निदयों श्रीर वायु पातायात के लिये किया गया श्रीर इन के विकास के कार्य-क्रम म भी वृद्धि की गई। रेलवे के गत्रयानादि के क्रय का कार्य-क्रम बढाया गया और उन दोत्रों में लाइने बढाने के लिये विशेष प्रयत्न किया गया जहाँ रेल यातायात की माँग अधिक थी। एक अन्तर्विभागीय अन्वेषण वर्ग द्वारा यातायात के सभी साधनों के पारस्परिक विकास सम्बन्धी प्रश्न पर श्रीर मुख्यतः सडक यातायात के विकास सम्बन्धी प्रश्न पर जो बढती हुई साँग के हिसान से बहुत दिनों से पिछड़ा हुन्ना था विचार किया गया । सड़क यातायात के व्यक्तिगत भाग मे विकास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय किये गए श्रीर लाइसेन्स देने की नीति को श्रधिक उदार बनाया गया । भारतीय जल यातायात की सहायता के उपाय भी किये गये।

यद्यपि प्रसाधनों के नवीनतम करने के कार्य अभी शेप हैं फिर मी द्वितीय योजना में देश के यातायात साधनों के समुचित विकास की (विशेष कर रेलवें की जिसके द्वारा सदा से अधिकतम यातायात की सुविधा प्रदान की गई हैं) व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के विकास के कार्य-कम का देश के औद्योगिक विकास के साथ विशेषकर बहे-बहें उद्योगों, जैस स्पात, कोयला, सिमेंट आदि, के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना आवश्यक होगा। द्वितीय योजना विभिन्न यातायात के साधनों के बीच पारस्पारक समजस्य स्थापित करने का भी प्रयत्न करती है। सक्त यातायात की सुविधा में जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है रेलवे द्वारा अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे और तटीय जन यातायात तथा रेलवे और नदी द्वारा यातायात के सामजस्य पर और भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजन के अन्तर्गत मुख्या मुख्य

यातायात साधनों श्रीर उनके पारस्परिक सामजस्य के श्रिषकतम विकास की श्रीर विशेष ध्यान दिया गया है तािक प्रत्येक श्रुपने-ग्रुपने चेत्र के कार्य को श्रुच्छे से श्रूच्छे दक्ष से पूर्ण कर सके। इस स्थिति का निष्कर्ष यह है कि श्रागामी पींच वर्षों में सभी प्रकार के यातायात साधनों की मौंग बहुत श्रिषक बढ़ेगी, इसिलये यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिवर्ष यातायात श्रीर सचार के विकास के कार्य-क्रम पर विचार किया जाये तािक जहीं कहीं श्रावश्यक हो ऐसे उपायों को श्रय-नाया जाय जिनसे यातायात की कितनाइयों के कारण योजना के श्रन्य कोई कार्य-कम में वाघा न पढ़े।

#### श्रध्याय ३६ प्रथम पंचवर्षीय योजना

नियोजन का तात्पर्य यह है कि देश के उपलब्ध साधनों का नियमबद्ध रूप से उपयोग किया जाय श्रीर इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकीण अपनाया जाय जिससे जुत्पादन बढे, राष्ट्रीय लामाश बढे, रोजगार श्रीर सामाजिक कल्याया में वृद्धि हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि उपलब्ध साधनों की सावधानी से र्जीच परख की जाय श्रीर राज्टीय उत्पादन श्रीर श्राय में निर्धारित वृद्धि करने के लिये इन साधनों के उपयोग की गति को भी नियोजित किया जाय। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना १६५१-५२ में लागू हुई श्रीर १६५५-५६ तक पूरी ही गई। इस योजना पर ५ वर्ष मे २,०६६ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। व्यय की मात्रा निर्धारित करने मे योजना श्रायोग ने इन बातो पर विचार किया कि (१) विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का समारम किया जाय जिसके श्राधार पर भविष्य में ह्योर बड़ी योजनाश्चों को कर्यान्वित किया जा सके, (१) विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश को कुल कितने साधन उप-लब्ध हो सकते हैं, (३) विकास की गति और निजी तथा सरकारी चेत्र के अन्तर्गत साधनों की आवश्यकता के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित हो, (४) योजना लागू होने के पूर्व वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा आरम्भ की गई विकास योजनाओं को पूरा किया जाय श्रीर (५) युद्ध तथा देश विभाजन से देश की श्रव्यवस्थित श्राधिक व्यवस्था को सुनियोजित श्राधार प्रदान किया जाय।

मारत की श्राधिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसङ्या में प्रतिवर्ष १ रे प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस तथ्य पर श्रौर देश के सभा उपलब्ध साधनों पर विचार करने के परचात योजना श्रायोग ने यह व्यवस्था की है कि १६७७ तक वर्षों में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी हो जाय। भारत की अपेचा अधिक विकसित देश में प्रति व्यक्ति की श्राय दूनी करने में कम समय लगेगा परन्तु मारत जैसे पिछाडे देश में इसमें श्रनिवार्यतः श्रविक समय लगेगा परन्तु मारत जैसे पिछाडे देश में इसमें श्रनिवार्यतः श्रविक समय लगेगा पर्योक देश में साधनों की कभी है, टेकनिकल कुरालता का अभाव है श्रीर सगठन की स्थित कमजोर है। मारत में प्रति व्यक्ति श्राय दूनी करने के लिए श्रनेक पचवर्षीय योजनाशों की श्रावश्यकता पढेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने इस दिशा में कार्य श्रारम्म कर दिया है। समय के साथ कार्य की गति मी जोर पकड़ती जायगी।

पूजी निर्माण की गित—योजना श्रायोग ने यह माना है कि श्राधारभूत वर्ष १६५० ५१ में भारत की राष्ट्रीय श्राय ६,००० करोड़ क्यया थी श्रोर कुल राष्ट्रीय श्राय का श्रोकतन ५ प्रतिशत बचत की जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि १६५०-५१ में सारी जनता की कुल बचत ४५० नरोड़ रुपया थी। यिट १६५१-५२ श्रोर १६५५ ५६ के बीच प्रात वर्ष २० प्रतिशत श्रातिरक्त श्राय पूँजी निर्माण में लगा दी जाय, श्रयांत मशीन हत्यादि श्रार काफी समय तक चलने वाले सामानों पर रुपया लगाया जाय तो पचवर्षीय योजना के श्रत तक भारत की राष्ट्रीय श्राय १०,००० करोड़ रुपये तक बढ जायगी श्रोर बचत की दर मी ६ श्रतिशत वार्षिक हो जायगी। १६५५-५६ में इस प्रकार कुल ६०५ करोड़ रुपया राष्ट्रीय बचत होगी। योजना श्रायोग ने बताया है कि इसके बाद १६६७-६ में समात होने वाले १२ वर्षों में नेवल २० प्रतिशत नहीं बिलक ५० प्रतिशत श्रातिक्त राष्ट्रीय श्राय प्रतिवर्ष पूँची निर्माण में लगाई जानी चाहिये। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो १६७७ तक प्रति व्यक्ति की श्राप (Per capita ıncome) दो ग्रनी हो जायगी।

प्राथमिकता का क्रम-राष्ट्रीय ग्राय में उक्त-लिखित वृद्धि करने के लिए प्रतिब्यक्ति की प्राय टोगुनी करने के लिए सशोधित योजना मे २,३५६ करोड रुपया विकास योजनाश्चा मे व्यय करने वा निश्चय किया गया। योजना में भारतीय स्त्रार्थिक न्यवस्था को सरकारी तथा निजी उन्नोग चेत्र मे विभाजित किया गया है। सरकारी चेत्र में वह उद्योग सम्मिलित हैं जिनका मालिक स्वय सरकार है, जिन पर वेन्द्रीय या राष्य सरकार अयवा इन सरकारों के आधीन श्रिधिकारियों ें, का नियत्रण है। निजी उद्योग चेत्र में वह उद्योग, वाणित्य श्रोर व्यापार शामिल हैं जिनके मालिक उद्योगपति हैं, जिन पर उनका नियन्नण है श्रोर जिनका सचा-लन स्पय इन्हीं उद्योगपितयों द्वारा होता है। इन दोनों उद्योग त्तेत्रों की समस्याएँ प्राय समान हैं ग्रीर दोनों को श्रेणियों में स्पष्ट विशेषतान्त्रों के श्राधार पर विभक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु सुविधा की दृष्टि से पचवर्षीय योजना में इन दोनों उद्योग चेत्रों पर पृथक रूप से विचार किया गया है। सरकारी उद्योग चेत्र के लिए कुल लागत की मात्रा नि ।।रत कर ली गई है श्रीर इस चेत्र की विचीय च्चावश्यकता सरकार पूरी करती ह**्रन्तु निजी उद्योग दोत्र के निर्धारित** लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ, न कह कर केवल सामान्य लक्ष्य बता दिया गया श्रीर इस लद्दय की पूर्ति तथा श्रावश्यक वित्त जुटाने के लिए भी उद्योग होत्र को स्वतत्र छोड़ दिया गया। सरकारी उद्योग होत्र में लक्ष्य की पूर्त सरकार का प्रत्यच्च उत्तरदायित्व है परन्तु यही शत निजी उद्योग चेत्र में लागू नहीं होती

है क्यों कि निजी उद्योग च्रेत्र में सरकार श्रयत्यज्ञ रूप से सहायता प्रदान करती श्रीर कारोबार के परिणामों का निरीक्षण करती रहती है। इसके मूल में यह विचार निहित है कि यदि निजी उद्योग च्रेत्र निवीरित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है श्रीर उसकी प्रगति श्रपेक्षित गिन नहीं हो पाती है तो सरकारी उद्योग का कार्य च्रेत्र बढ जायगा श्रीर सरकार इन निजी उद्योग च्रेत्र की विभिन्न इकाइयों का कार्य भार वीरे-घीरे स्वय ग्रहण कर लेगी। कुछ समय तक सरकारी श्रीर निजी च्रेत्र दोनों ही रहेंगे।

पचवर्षीय योजना के प्रारंप में जो जुलाई १६५१ में प्रकाशित किया गया था श्रीर स्वय पचवर्षीय योजना में जो दिसम्बर १९५३ में ससद के सामने प्रस्तत की गई थी कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है स्त्रोर इसके बाद यातायात तथा सचार, समाज सेवा कार्य थ्रोर उद्योग को रखा गया है। पचवर्षीय योजना की यदि योजना के प्रारुप में तुलना की जाय तो पता चलेगा कि योजना के अतिम रूप मे उद्योग के महत्र को कुछ अधिक बढा दिया गया है पर इससे योजना का प्राथमिकता कम नहीं बटलता है। योजना के अतिम रूप में कृषि. िचाई श्रीर विजली की लागत कुल लागत का ४३ २ प्रतिशत रखी गई, याता-यात तथा संचार की लागत २३६ प्रतिशत, समाज सेवा कायों पर व्यय की लागत २२.६ प्रतिशत श्रोर उत्राग की लागत केरल ७६ प्रतिशत रखी गई थी। योजना श्रायोग ने कृषि को श्रिधिक महत्व पदान करने के कारणों पर प्रकाश हाला है। ब्रायोग का मत है कि खायान ब्रोर कब्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त बहिन होने से उयोगों के तीन विकास की सभावना नहीं है। सबसे पहले यह श्चानश्यक है कि श्चार्यक स्थिति के मूल को दृढ़ किया जाय, कृषि चेत्र में पर्याप्त अतिरिक्त खाद्यान तथा कच्चा माल पैदा किया जाय ओर अन्य केन्नों का कार्य आगे बढाने में उसका उपयोग किया जाय। इसी उद्देश्य के कारण कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई है। संशोधित योजना में यद्यपि कुल व्यय बहाकर २३५६ करोड़ रुपया कर दिया गया फिर भी प्राथमिकता के कम में कोई विशेष परिवर्तित नहीं किया गया है।

जहाँ तक श्रौद्योगिक चेत्र का सम्बन्ध है प्राथमिकता निर्धारित करते समय इन बातों पर विचार किया गया है कि (१) जूट श्रोर प्लाईवुड जैसे उद्योगों (Producer goods industries) की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय श्रोर उपमोग की वस्तुश्रो का उत्पादन करनेवाले उद्योगों, जैसे सूर्ती कपडा, चीनी, साबुन श्रीर वनस्त्रति उद्योगों की भी वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाय, (१) लोहा श्रीर इस्पात, एल्यूमोनियम, िषमेंट रसायनिक खाद, मारी रसायनिक, मशीनो के श्रीनारीं इत्यादि उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढाई जाय, (३) उन श्रौद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाय जिन पर काफी पूँजी लगाई जा चुकी है ग्रीर (४) जिप्सम से गन्वक, विशेष प्रकार के रेशम का उत्पादन करने के लिए श्रावश्यक सामग्री, श्रीर श्रलीह धातुत्रों के टुकड़ों का उत्पाटन करने के लिये नये कारखाने स्थापित किये जाथॅ जिससे वहे श्रीर श्रत्यन्त महत्व के उद्यंगों के लिए श्रावश्यक कच्चे माल की पृति की जा सके। प्राथमिक्ता का यह क्रम यह प्रकट करता है। कि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया नायगा ख्रोर किसी भी उद्योग के प्रति उटासीनता नहीं श्रपनायी जायगी। राज्य श्रनेक कारखाने स्थापित कर सकते हैं परन्तु कृषि के विपरीत उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी उद्योग चेत्र के हायों में छोड़ दिया गया है। कृषि तो सरकारी उद्योग चेत्र के अन्तर्गत आता है। पच-वर्षीय योजना में ४२ उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे श्रीर यह श्रनुमान लगाया गया था कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाँच वर्ष में कुल २३३ करोड़ रुपया व्यय करना पडेगा। इसके साथ ही कारखानों के आधुनिकीकरण में श्रौर मशीनों को बदलने में १५० करोड़ रुपया श्रीर व्यय होगा। यदि इसमें चाल पॅजी की रकम भी जोड़ टी जाय तो पता चलेगा कि पाँच वर्ष में घेवल उद्योग ही की वित्तीय त्रावश्यकता ७०७ करोड़ रुपये के वरावर होगी। इस वित्तीय त्रावश्यकता की प्रति सरकार नहीं करेगी। इसके लिए निजी उद्योगों को स्वय प्रयत्न करना पहेगा ।

वित्त-योजना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय आवश्यकता पूरी करने में किसी प्रकार की बाघा न पढ़े। कृषि तथा श्रोद्योगिक साधनों का विकास करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है। यदि यह पूँजी देश के अन्दर ही प्राप्त नहीं होती तो इसके लिए हमें विदेशी खोतों की सहायता लेनो पड़ेगी। भारत की पचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वर्तमान आय में से बचत, भारतीय रेलवे की आय में से बचत, श्रूण तथा जनता की बचत और विदेशी पूँजी पर निर्मर करती है। योजना के ज्यय की पृति करने के लिए भारत के गैरह पावने, विदेशी सहायता और श्रूण पर भा पृरा विचार कर लिया गया है। इन सारे साधनों का उपयोग कर लेने के बाद भा कुछ कभी रह जाती है जिसकी पूर्त के लिए यह आशा की जाती है कि अतिरक्त कर लगाकर या स्वदेशी बाजार से आविक मात्रा में श्रूण लेकर इस कभी को पूरा किया जायगा परन्तु यदि ऐसा समय न हो सका तो पचवर्षीय योजना की लागत में इतनी रक्स वी कमी कर दी जायगी।

योजना की कुल लागत २,०६६ करोड़ रुपया थी; सरकारी तथा निजी बचत से पाँच वर्ष में १,२५८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा जबिक इन्हीं स्रोतों से योजना के मूल वर्ष १६५० ५१ में २२२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। १,२५८ करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से ७४० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और रेलवे बजट की श्रतिरिक्त श्राय से प्राप्त होगे और ५१८ करोड़ रुपया निजी बचत से। सशोधित योजना में बजट से प्राप्त श्राय में और व्यक्तिगत बचत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि श्राशा की जाती है कि ७४३ और ५१८ करोड़ रुपये कमश होगी। बढी हुई लागत श्रधिकाश घाटे के श्रध प्रवन्यन द्वारा पूरी की जायगी जैसा कि कमी की मात्रा में ६८८४ करोड़ रुपया बढकर हो जाने से प्रतीत होता है। यह श्राशा की जाती हैं कि पौरह पायने से प्राप्ति को विचाराधीन रखते हुये यह कमी ७०१ करोड़ रुपये की रह जायगी।

योजना को श्रितम रूप देने के पहले भारत को विदेशों से सहायता श्रीर श्रुरा के १५६ करोड़ रुपया मिला था। योजना श्रायोग ने इसे भी सम्मिलित कर लिया। योजना मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि घाटे का बजट बढ़ाकर २६० करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति की जाय। इसके बाद भी ३६५ करोड रुपयों की श्रीर पूर्ति शेष रह जाती है। यह बहुत सभव है कि यह कमा श्रीर श्रिधक हो यदि राज्य तथा निजी बचत की स्थिति श्राशा के श्रमुकुल न रही।

यदि सारी स्थिति पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सरकारी चेत्र
में जो कुल २,०६६ करोड रुपये की लागत रखी गई है उसमें से दीर्घकालिक व्यय
(Capital expenditure) केवल १,६०० से १,७०० करोड रुपये के बीच मे
होगा। यदि इसमें निजी उद्योग चेत्र में लगायी गयी पूँजी को भी मिला लिया
जाय (जिसमें उद्योग, वाणिज्य श्रीर व्यापार में लगी पूँजी भी सम्मिलत है) तो
पॉच वर्ष में स्वदेशी स्रोतों से ही दीर्घकालिक व्यय की २,७०० से २,८०० वरोड़
स्वये की राशि पूरी करनी पडेगी। यदि इसमें इसी श्रवध में पौरह पावने की मट
में से मिलने वाले २६० करोड़ रुपये (जा भारत में घाटे की वजट व्यवस्था का
श्राधार हैं) श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक, श्रमेरिका, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजालैंड
हत्यादि से प्राप्त १५६ करोड रुपया जोडा जाय तो कुछ साधन ३,१५० से ३,२५
करोड रुपया के बीच हो जाते हैं। सशोबित रूप में यह धनराशि ३३३० ३४३०

आलोचना—पंचवर्षीय योजना में भारत के कृषि तथा श्रोद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बड़ा श्राशाबाटी दृष्टिकोग् श्रपनाया गया। श्रॉकडों के श्रभाव श्रीर साधनों की कमी के कारण इससे श्रच्छी योजना तैयार करना सभव नहीं था। योजना पूर्ण होने पर राष्ट्रीय उत्पादन बढेगी, श्राय बढेगा श्रीर जनता श्रिषक धनवान श्रीर प्रवन्न हो सकेगी, भारत के श्राधिक निकास में जो किमर्या है उन्हें दूर किया जा सकेगा, खादाल ने देश निरन्तर स्वावलम्बी बनना जायगा श्रीर कुछ कच्चे मालों का जिनके लिये देश श्रायात पर निर्भर है, उत्पादन बढेगा। योजना में वंशिनक प्रगति श्रोर टेकिनकल शिक्षण की श्रायण्यकता को भी महत्व दिया गया है। इन पर उदान श्रीर कृषि की सफलता निर्भर करती है। वैज्ञानिक जाँच-परस्त, टेकिनकल शिक्षण इत्यादि के लिये भी योजना में विशेष व्यवस्था की गई है। कुछ समन बाद इसका प्रभाव प्रकट होगा।

यह श्रालोचना की गई है कि पांच वर्षों में बोजना को कार्यान्त्रित करने के लिए ब्रावश्यक वित्त के सम्बन्ध में पचार्याय योजना ने पहुत ब्राणावाटी दृष्टि-कोण अपनाया है श्रीर जनता से बहुत श्राशा की है। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि (३) योजना श्रायोग ने श्रनुमान लगाया है कि ५ वर्षी में केन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट ख्रोर रेलवे में क्रमश, १६० करोड़ रुपना, ४०८ परोड रुपया श्रीर १७० करोड़ रुपया श्रुतिरिक्त प्राप्त होगा परन्त इस माता में श्रांतिरिक्त श्राय होना समय नहीं है। जनता में श्रव श्रीर श्रिधिक कर देने की क्तमता नहीं है स्त्रोर रेलवे तथा सरकारा की स्त्राय भी उतनी स्रावक होना सभव नहीं है जिसनी की योजना में श्रापेक्षा की गई है। इसका तालर्य यह है कि पचनपीन बोजना ग्रपने नूलरूप में कार्यान्वित नहीं हो पायेगी श्रीर उसमें काट र्छौट करनी पहेगी। (प) योजना में यह माना है कि १६५१ श्रीर १६५६ के बीच प्रति वर्ष अतिश्क्ति आप का २० प्रतिशत पूँची निर्माण में लगावा जायगा और १६५६ से १६६८ तक अतिरिक्त आय का ५० प्रतिशत इसमें लगाया जायगा। मारत जैसे निर्धन देश में जहाँ की श्रिधिकतर जनता की ग्राप श्रापने जीवन निर्वाह के लिए हा प्रयाप्त नहीं है अर्तिरिक्त स्राय का इतना स्रिधिक अशा पूँजी निर्माण में लगा सकने की आशा करना वास्तविक त्थिति के अनुकूल नहीं है। यदि जनता की स्त्राय बढ़ती है तो वह उसको विनियोग में लगाने की स्रपेक्त उपयोग में व्यय करना श्रिविक परान्ड करेगी। यदि ऐसा होता है तो योजना ग्रायोग की यह श्राशा कि १६५६ तक कुल राष्ट्रीय श्राय १०,००० करोड़ रुपये तक बढ जायगी और १६७७ तक प्रति व्यक्ति की आय दूनी हो जायगी, पूरी नहीं हो सकती है।

इन म्रालोचनाम्रां में कुछ सत्य म्रवश्य है परन्तु यह योजना का म्राधार भूत दोप नहीं हैं। किसी भी योजना की म्रालोचना में यह तर्क दिये जा सकते हैं। नियोजन के लिए यह म्राश्यकीय है कि जनता त्याग करे। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना में सवमतः श्रन्य योजना श्रों की श्रपेचा कुछ श्रिष्क त्याग करने की भाँग की गई है। परन्तु इस विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं कि भारतीय जनता से किस सीमा तक त्याग करने की श्रपेचा की जाय श्रीर वह कितना त्याग कर सकने में समर्थ है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १९५१-५६ के बीच प्रति वर्ष श्रतिरिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाया जाय जबकि १९५०-५१ में, जो योजना का प्रथम वर्ष या, केवल ५ प्रतिशत के विनियोग की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद की योजनाशों में प्रतिवर्ष श्रितिरिक्त श्राय का २० प्रतिशत विनियोग में लगाने की श्राशा की जायगी। जहाँ तक इस पद्म का सम्बन्ध है योजना श्रमी पहला प्रयोग मात्र है। यदि जनता योजना में निर्धारित श्रनुपात में रुपया नहीं लगा सकी तो कम मात्रा में लगायगी परिगाम स्वरूप प्रगति की गति भी घीमी हो जायगी। यही बात श्रतिरिक्त श्राय के सम्बन्ध में भी लागू होती है। बिना सही स्वना के इस चेत्र में उपयुक्त श्रनुपात निर्धारित करना समय नहीं है। जैसे-जैसे योजना लागू की जायगी श्रीर नए श्रनुमव प्राप्त होगे उसी के साथ साथ योजना में श्रावश्यक परिवर्तन किए जायगे।

पचवर्षीय योजना के स्रालोचकों ने कुछ गमीर तर्क भी दिये हैं। उनका कहना है कि: (१) योजना में उद्योग की अपेद्धा कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि जो योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं उन्हें पूरा किया जाय श्रीर मिविष्य में देश के श्रीद्योगिक विकास के लिए मुद्द स्त्राधार स्थापित किया जाय। इस तर्कका मूल विचार यह है कि भारत का वर्तमान श्रीद्योगिक विकास कृषि विकास के श्रनुरूप हुश्रा है। परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। भारतीय स्थिति का जान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि भारत मे कच्चे माल श्रौर निजली इत्यादि का वर्तमान में जितना उत्पादन होता है उससे देश का बहुत श्रिधिक अौद्योगिक विकास किया जा सकता है। योजना श्रायोग ने एक श्रोर बात की श्रोर ध्यान दिया। यह बहुत सभव है कि जब तक इस मारत के भावी ख्रोद्योगिक विकास के लिए सुदृढ श्राधार स्थापित करेंगे तब तक विश्व स्थिति मे ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिससे भारत का स्त्रोद्योगिक विकास स्त्राज की स्त्रपेद्या स्त्रधिक कठिन हो जायगा। ऐसी स्थिति में कृषि के विकास का क्या उपयोग किया जा सकेगा १ अत में इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना का उद्देश्य भारत की आर्थिक व्यवस्था की घटियों को दूर करके देश का श्रधिक छन्तुलित विकास करना है। इस दिशा में सबसे बड़ी कमी यह है कि मारत में मशीनो के निर्माण करने वाले उद्योग नहीं हैं, विद्युत, इजीनियरिंग, फेमिकल इत्यादि के उद्योग का श्रन्छी तरह विकास नहीं हो सका है इसलिए श्राधिक सन्तुलित व्यवस्था बनाने के लिए योजना को इस दिशा की श्रोर श्राधिक प्यान देना चाहिए था श्रीर इन उद्योगों का विकास करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

- (२) योजना के अनुसार देश का औयोगिक विकास निजी उद्योगपितयों के रायों में सोंपा गया है। इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है क्योंकि श्रतीत में निनी उद्योगपितयों ने भारतीय उत्योगी का कुरालता पूर्वक विकास किया। परन्तु योजना के आलोचका का मत है कि आयोगीगक निकास अनिकास रूप ने निजी उद्योगपितयों के हाथों में संपने ब्रार उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त सापनी की न्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय उद्योगपतियों का मत है कि योजना मे २३३ करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोग वरने की श्रोर १५० करोड़ रुपये की पूँजी टूट-फुट उत्यादि के लिए रखने की व्यवस्था की गई है। परन्छ यह पूँची उत्पादन के निर्घारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए निल्कुल श्रपर्याप्त है। इसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि उद्योग क्वल वित्त की ही आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसके प्रतिस्कि श्रनेक सुविधायों की मी यावश्यकता होती है, जेसे कर सम्बन्धी, छूट टूट-फुट इत्यादि के लिए श्रधिक पूँजी ग्रीर कुछ परिस्थितियों मे नवद श्रार्थिक सहायता। यह खेद की बात है कि पचवर्णीय योजना में इसके लिए कुछ व्यवस्था नहों की गई है। इसके ग्रभाव में निजी उन्होंग देश के ग्रोवोगिक विकास के प्रति श्रपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है।
- (३) प्रथम योजना का एक ग्रोर गभीर टोप यह है कि इसमें टीर्घकालीन योजनात्रा पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि सुनियो- जित ग्रायिक व्यवस्था में दीर्घकालिक योजनात्रों पर विशेष जोर देना चाहिये। कुछ विदेशी राष्ट्रों में, जिसका समसे उत्तम उटाहरण सोवियत रुस है, टीर्घकालिक योजनात्रों को ही नियोजन का ग्राघार बनाया गया। परन्तु भारत की स्थिति उससे मिन्न है। मारत में टीर्घकालिक योजनाएँ ग्राधिक होनी चाहिये परन्तु साथ ही ग्रल्पकालिक योजनात्रों पर विशेष जोर देना चाहिये था। इससे प्रति एक इत्यादन में शीघ वृद्धि की जा सकती थी ग्रीर खाद्यान्न के सम्बन्ध में देश शीघ स्वायलम्बी बनाया जा सकता था। इससे बहुत सीमा तक मारत की बेरोजगारी की समस्या मी हल की जा सकती थी।

दीर्घकालिक योजनात्रों पर श्रिषक जोर देने में एक श्रीर हानि यह है कि वस्तुश्रों के उत्पादन में दीर्घकाल के बाद वृद्धि होगी जविक जनता की कय शक्ति शीव ही बढेंगी। इससे मुद्रास्फीति का जोर श्रीर वह नायगा। सुनियोजित व्य-वस्था में कुछ श्रश तक मुद्रास्फीति श्रीर परिणाम स्वरूप श्रिषक कीमते होना श्रिन-वार्य है परन्तु यदि नियोजन के द्वारा वस्तुश्रों की पूर्ति वहती है तो उससे मुद्रास्फीति का प्रभाव कम हो जाता है यदि पचवर्षीय थोजना में श्रह्मकालिक योजनाश्रों पर श्रिषक जोर दिया जाता तो ऐसा होना समय था। इसके श्रभाव में योजना के लागू होने से मुद्रास्फीति का जोर वहा है जिससे उपभोक्ताश्रों को हानि हुई है।

(४) योजना की सफलता विशेष कर उस संगठन की कार्यं जमता पर निर्भर करती है जिस पर उसके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। भारतीय प्रयम पचवर्षीय योजना की यह सबसे वही कमी थी कि इसमें योजना को लाग करने के लिए किसी विशेष सगठन की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ श्रौद्योगिक श्रीर नदी घाटी योजनाश्रों की कार्यान्वित करने का कार्य स्वतन्त्र कार्पोरेशनों को सींपा गया है। इन कार्पेरेशनों पर सरकार श्रपना नियत्रण रख सकने में विशेष समर्थ सिद नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप जनता का बहत सा रुपया नष्ट हो गया है. योजनाओं में पाय: सशोधन किया गया है और श्राशानुकूल उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। श्रन्य बहुत सी योजनाएँ राज्य सरकारों के श्रिधकार नेत्रों में रखी गई हैं श्रौर राज्य सरकारे इनको लागू करने का कार्य जिला श्रिषकारियों को सीप देती हैं। यह प्रवन्ध सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हो सका है। जिला श्रविकारी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विकास योजनाओं के प्रति पर्याप्त व्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजन अधिकारियों का कार्य विशेष सन्तों-षजनक नहीं रहा है। इसका परिगाम यह हुस्रा है कि योजना को उचित रीति से लागू नहीं किया गवा है और उससे जितनी खाशा की जाती थी उतना लाभ नहीं हो सका। इसके विपरीत जो कुछ प्रगति हुई है वह केवल कागजों तक ही सीमित है। यदि भारत सरकार आई॰ ए० एस० की तरह 'भारतीय आर्थिक प्रशासन' (Indian Economic Service) के श्रन्तर्गत उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करती और इस प्रकार योजना को कार्यान्वित करने के लिये विशेष सगठन को जन्म दिया जाता तो इस दिशा में श्रिधिक प्रगति की जा सकती थी। इससे कार्यालयों इत्यादि पर सरकारी व्यय में अवश्य वृद्धि होती परन्तु वह व्यय व्यर्थ नधीं जाता उससे पनवर्षीय योजना की उपयोगिता बह सकती यी।

इन दोषों के होते हुये भी इसमें सन्देह नहीं कि भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना देश के आधिक विकास के सम्बन्ध में एक प्रसस्नीय प्रयत्न या। आरम्भ में तो श्रवश्य ही योजना की सफलता कम होती। परन्तु यह देश के कृषि उद्योग, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति श्राय की वृद्धि करने के प्रयत्न का आरम्भ ही या।

#### सफलता की प्रगति

योजना त्रायोग द्वारा मर्ड १६५७ में प्रशाशित प्रथम पचार्यीय योजना के पुनर्वोद्धर के श्रनुभार सम्पूर्ण पाँच वर्षों में किया नया व्यय २०१२४ नरोड़ र० हुआ (जनिक सशोधित लहय २३७७७ करोड़ र० या)। इसमें में १२७७.३ करोड़ र० वजट में प्राप्त श्राय थी तथा २०३१२ करोड़ र० विदेशी सहायता ने प्राप्त हुये। इस प्रकार लगभग ३६६ करोड र० कम व्यय हुये। पहले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों ने ८६७१५ करोड़ र० तथा केन्द्रीय सरकार ने १११४९६ करोड़ र० ना व्यय किया।

चूँ कि १६५५-५६ की वास्तविक सख्यार्थे पता नहीं है अत्तर्य यह सम्भव है कि योजना का जुल न्यय २०१३ करोड के के बजाय १६६० करोड़ के ही जाय। प्रारम्भ में २६० करोड़ के के छुटि के अर्थ प्रयन्धन की न्यवस्या थी। वास्तव में यह ४२० कराड़ के हुआ। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थ न्यवस्था पर काफी मार पड़ा।

योजना मे राष्ट्रीय श्राय के ५% के विनियोग को नहा कर ७% तक करने का उद्देश्य था तथा पाँच वर्षों मे ३५००-३६०० करोड ६० के विनियोग का लध्य था। सरकारी चेत्र में लगभग १५०१ करोड ६० का विनियोग हुश्रा जन कि निजी चेत्र में १६०० करोड़ ६० का विनियोग हुश्रा। इस प्रकार पाँच वर्ष की अविध में ३,००० करोड़ ६० निनयोग हुश्रा। १६५० ५१ की तुलना में योजना के श्रन्त तक विनियोग का स्तर लगभग दृना हो चुका था।

कुछ कार्यों में प्रथम योजना की प्रगति श्रीर सफलता निरसन्देह श्राश्चर्य-जनक रही है। साद्यान इजन श्रीर सती कपड़ा के सम्बन्य में १६५५-५६ में उत्पादन सोचे हुये १६५५-५६ के त्येप से कहीं श्रागे बढ गया। श्रमानियम सल्फेट, तर्शय जलयात्रा श्रीर सीमेरट के सम्बन्ध में यद्यपि उत्पादन १६५५-५६ के श्रमुमानित त्येय से कम ही रहा फिर भी काफी वृद्ध हुई है। कुछ ही कार्य ऐसे रहे हैं जिनमें श्राशा ने निपरीत बहुत कम वृद्ध हुई है श्रीर उनमें १६५५-५६ तक भी सोचे हुये त्येय तक वृद्ध न हो। इस्र लिये इस निर्णय पर पहुँचना कि पचवर्षीय योजना ने श्रयं व्यवस्था पर श्रनावश्यक भार डाले विना संतोषप्रद प्रगनि की है, युक्ति सगत होगा।

#### श्रध्याय ४०

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पचवर्षीय योजना की श्रवधि १६५६ ५७ से १६६०-६१ तक है। प्रथम पचवर्षीय योजना की अपेद्धाकृत इसकी धारणा (Conception) अधिक व्यापक श्रीर सदृढ है। प्रथम पचवर्षीय योजना की रुफलता श्रीर विकास की गति से प्रोत्साहित होकर योजना आयोग ने द्वितीय पचवषीय योजना को अधिक कॅचे लक्ष्यों के साथ सामने रखा। द्वितीय योजना के प्रमुख उद्देश्य यह है कि (भ्र) राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप देशवासियों के रहन-सहन का म्तर ऊँचा किया जा सके, (ब) श्रत्यन्त शीवता से श्रौद्योगीकरण हो, जिसके अन्त-र्गत त्राधारभूत उद्योगो के विकास पर त्राधिक बल दिया जाय, (स) रोजगारी में वृद्धि हो, श्रीर (द) सामाजिक न्याय की ब्यवस्था की जाय। यह उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के श्रानुकृत ही हैं, श्रान्तर केवल इतना है कि दिवीय योजना में श्रीद्योगिक विकास को पहली योजना की श्रपेत्वा श्रधिक महत्व दिया , गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्तर और भी है। भारत-सरकार ने 'समाजवादी ढाँचे पर श्राघारित समाज (socialistic pattern of society) का श्राटर्श स्वीकार कर लिया है श्रीर इसी के फलस्वरूप दितीय पचवर्षीय योजना मे सामा-जिक न्याय पर इतना जोर दिया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियोजन के द्वारा कृषि व श्रौद्योगिक उत्पादन श्रीर कुल राष्ट्रीय श्राय मे वृद्धि करने की उस समय तक कोई सार्थकता नहीं जब तक कि उस वृद्धि के साथ साथ वितरण मे सधार न हो क्योंकि इसी वितरण के द्वारा निर्धन व्यक्तियों का जीवन पहले की श्रपेचाकत श्रधिक उत्तम हो जाता है।

पूँजी निर्माण की गति—प्रथम योजना ने आगामी २७ वषा के लिए प्रगित का एक आदर्श सामने रखा। उस आदर्श या लक्ष्य के अनुगार यह अनुमान है कि २२ वर्षों म राष्ट्रीय आय और २७ वर्षों मे प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो जायगी। इसके अतिरिक्त २५ वर्ष से कुछ अधिक समय में (१६५०५१ और १६७७ के बीच) प्रति व्यक्ति उपमोग की मात्रा में लगभग ७०% वृद्धि हो जायगी। दितीय पचवर्षीय योजना इस आदर्श के अनुरूप ही है।

सबसे कठिन समस्या जो योजना बनाने वालों के सम्मुख उपस्थित है वह विनियोग की उस दर का श्रनुमान है जिसको विना किसी श्राशका के कार्यान्वित किया जा सकता है श्रीर राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि पर उसका प्रभाव है। योजना वनाने वालों को अन प्रयम यो ना का अनुमन भी प्राप्त है निसके एहारे ने अपने कार्य में आगे वह एकते हैं। १६५०-५१ में निनयोग राशिय आय का ४६% था परन्तु १६५१-५२ में वहकर ७% हो गया। इस वृद्धि का एक अपन ता माल का निना निके जमा रहन के कारण था निस्के परिनाम स्तरूप आयात में याहुल्य हो अया था। अगले दो वर्षों में विनियेग को दर घट कर राशिय आय की ५% हो गई, १६५४५५ में पुनः बढ़ार ६% या ६ ५% हुई और बढ़ते बढ़ने योजना काल के अन्तिम वर्ष में ७२% हो गई। यदि योजना काल की पूरी अन्यि में विनियोग की दर का राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में मितरात जीवत लगाया जाय तो लगभग ६% होता है को कोई निरोप आकर्षय नहीं है। इस निनयोग के परियाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय आय लगभग १८% दही स्थान् ६,११० करोड़ रुपयों में जितनों कि १६५०-५१ में भी बहुकर १६५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये हो गई।

तालिका १ श्राय ग्राँर विनियोग में चाँद्ध जिमकी आशा की जाती धी १६४०-४१ से १९७१-७६ नक (१९५२-४३ के मृत्य स्तर के ग्राधार पर)

	प्रथम	<b>।</b> द्धरीय	विवाय	चतुर्प	पचम
	योजना	योजना	योजना	योजना	याजना
	१९५१-५६	१६५६-६१	१६६१-६६	1668-01	१६७१-७६
श्रवधि के अन्त में राष्ट्रीय	}		1	1	
श्राय (करोड़ रुपयों में)	१०८००	१३४८०	१७२६०	२१६८०	२७२७०
कुल वास्तविक विनियोग					,,,
(करोड़ कार्यों में)	3800	६२००	6600	₹¥50 €	२०७००
श्रवधि के श्रन्त में विनि-			}		
योग का कुल राष्ट्रीय ग्राय	j				
से प्रतिशत श्चनुपात	७•३	१०.७	१३.७	१६.०	१७०
श्रवधि के श्रन्त में जन	İ		• • •		,,,,
संख्या (१० लाख)	३८४	¥o⊏	<b>\$</b> 38	४६५	५०
वृद्धिकी मात्रा का पूँजी			•	670	~~
श्रीर उत्पादन श्रनुपात	१ ८८ र	२ ३० १	२६२१	३ ३६:१	३७०१
प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय					
श्रवधि के श्रन्त में					
( चपयों में )	२८१	3,3 <b>2</b>	३९६	332	3VF
					3 Y G

दितीय पचवर्षीय योजना में यह मान लिया गया है कि राष्ट्रीय बचत तथा विनियोग में वृद्धि के कारण १६५५-५६ की राष्ट्रीय श्राय के ७'३% से १६६०-६१ में १०'७% वह जाने से, राष्ट्रीय श्राय में लगमग २५% की वृद्धि हो जायगी श्रयांत् १६५५-५६ के १०,८०० करोड़ कार्यों से १६६०-६१ में बहकर १३,४८० करोड़ क्यां हो अहम इत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि करोड़ क्या हो जायगी। सबसे श्रिधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि क्या भारत इतने श्रिधिक विनियोग का भार वहन कर सकता है ! योजना श्रायोग के श्रनुसार बहन कर सकता है जैसा कि प्रयम योजना का श्रनुभव तथा श्रन्य देशों का श्रनुमव बतलाता है :

''प्रयम योजना रिपोर्ट में १९५६-५७ से ५०% वचत करने की सीमान्त दर मान ली गई थी और इसके श्राघार पर यह श्रुतुमान लगाया गया था कि १६६८-६६ तक देश की आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय श्राय का २०% विनियोग किया नायगा श्रीर श्रागे चलकर इष्ठी स्तर पर स्थायी हो जायगा। ग्रव ऐसा ग्रामास होता है कि यह अनुमान अत्यधिक है। जिन पच्यों (projections) का श्रनुगण्न किया गया है उनके श्राघार पर विनियोग का गुण्क (Coefficient) ७% से जो कि १६५५-५६ में था बढकर १६६०-६१ में ११% हो जायगा, १६६५-६६ तक गुग्क के १४% ग्रीर १६७०-७१ तक १६% तक वह नाने का प्रतमान है। उसके पश्चात् गुणक स्थिर रहेगा भ्रीर १६७५-७६ तक १७% तक वढ नायगा ( तालिका नं० १ के अनुमार )। १६% या १७% राष्ट्रीय आय का विनि-योग निस्सदेह ऊँची दर है पर पहुँच के वाहर नहीं है। पाश्चात्य देशों में जिन्होंने श्रपना श्रोद्योगिक विकास पहिले स्त्रारम्भ किया था पूँजी निर्माण की दर १० श्रीर १५ प्रतिशत के त्रीच रही है। जापान में विनियोग की दर का १६१३-१६३६ के वीच श्रीसत १६ श्रीर २० के बीच या। रूस में १५ श्रीर २० प्रतिशत की दर निरन्तर स्पिर रही है। उन देशों के श्राक हों से जोई० सी० ए० एफ० ई० (ecafe) चेत्र के श्रन्तर्गत त्राते हैं यह पता लगता है कि १६५० ते कुल पूँजी ना निर्माण वर्मा में १० से २० प्रतिशत के बीच, जापान में २४ ते ३० प्रतिशत के बीच, लका में १० से १३ प्रतिशत के बीच स्त्रोर फिलीपाइन्स में ७ से ८ ५ प्रतिशत के बीच रहा है। भारत के सम्बन्ध में तुलनात्मक श्रॉकडे १० से ११ प्रतिशत है। कुछ लैटिन श्रमरीकी देशों में इस सम्बन्ध के श्राँकडे १५ श्रीर २६ प्रतिशत के बीच पायः रहे है। कमी कभी स्तर कुछ ऊँचा भी हुआ है। पूर्वी योख्प के कुछ देशों में जैसे जैकोस्लोवेकिया श्रीर पोलैयड में पूँजी निर्माण की दर २० श्रीर २५ प्रतिशत के बीच रदी है। नये विकासोन्मुख देशों में विनियोग की दर वर्तमान स्तर से निश्चय ही बहाई जा सकती है-यदि उपयुक्त विनियोग नीति का अनुसरण किया जाय स्रौर यदि राज्य द्वारा विकास कार्यक्रम आरम्भ क्रिये जायँ। इस्रिलेथे भारत के सम्बन्ध में यह घारणा बनाना कि प्रयत्न करने से विनियोग की दर ऊपर बताये गये स्तर तक बढाई जा सकती है असगत नहीं हो सकता"।

प्रथम पचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में जीवन की ग्राधारभूत वस्तुश्रों के उपभोग को पुन. उस स्तर पर ले श्राया जाय जिस पर वह महायुद्ध के पूर्व था। द्वितीय पचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में एक पग श्रागे है श्रीर उसका लक्य यह है कि योजना काल के श्रन्तर्गत कुल उपभोग की मात्रा में लगमग २०% श्रौर व्यक्ति उपमोग की मात्रा में १२ से १३ प्रतिशत की वृद्धि हो। कुछ विशेष वस्तुश्रों के प्रति व्यक्ति उपभोग के श्राकड़ों में इस वात का श्रामाय मिलता है कि किवनी श्रिधिक प्रगति का श्रमुम न लगाया गया है। पोष्टिक सलाहकार समिति (Nutrition Advisory Committee) ने यह श्रनुमान लगाया था कि एक वयस्क के प्रतिदिन के सन्तुलित आहार में कम से कम १४ आँस अन होना चाहिये। १९५०-५१ में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन १३ ह्योंस स्रज्ञ का छोसत उपमोग करता था। किन्तु प्रथम पचवपीय योजना के परिसाम स्वरूप १९५३ ५४ में प्रतिब्यस्क प्रतिदिन श्रन्न के उपभोग की मात्रा बहकर १५ श्रीस हो गई। परन्तु चने ब्रोर दालों का उपभोग ब्राभी भी निम्नतम ब्रावश्यकतात्रों से कम है। यह श्रतुमान लगाया गया है कि मित व्यस्क को प्रतिदिन २ है से ३ श्रीस तक चने श्रीर दालों का उपमोग करना चाहिये। किन्तु बहती हुई जनसङ्या श्रीर प्रति व्यक्ति की श्राय में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रन्न के उपमोग में वृद्धि होगी श्रवणव द्वितीय पंचवर्षीव योजना मे देश के भीतर खाद्यान का उत्पादन बढाने के लिए प्रयत्न किया नाना चाहिये। "दूध, धी, मास, मछली, श्रहे, चर्ची, फल, तरकारियाँ श्रीर चीनी के उपभोग का वर्तमान स्तर निम्नतम श्रावश्यक्तात्रों से बहुत कम है। दितीय योजना में रहन-सहन के श्रिधिक ऊँचे स्तर की न्यवस्या करने के लिये पशु-पालन, मछली-उद्योग, मुर्गी पालन, तरकारियों की खेती ग्रीर श्रन्य प्रकार की खाद्य सामग्री के उत्पादन पर विशेष स्थान देना चाहिए"। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में प्रति व्यस्क प्रति वर्ष के हिसाव से १५ गन सूती कपढे का उपमोग करता या श्रोर प्रयम पचवर्णीय योजना के समाप्त होने पर कपडे के श्रीसत उपमोग का वही स्तर पुनः प्राप्त कर लिया गया है। स्ती कपटे की जाँच समिति की सिफारिश को मानकर द्वितीय पचवर्षीय योजना में १९६० तक प्रति व्यक्ति स्ती कपडे के श्रौसत उपमोग को १८ गज करने का लक्ष्य निर्घारित किया गया है।

प्राथमिकता का क्रम-प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई

श्रीर विजली की राक्ति के विकास को प्रमुख महत्व दिया गया था श्रोर हन महों पर योजना की कुल लागत की ४३ २% रकम व्यय करने का श्रनुमान था। इसके विपरीत दितीय पचवर्षीय योजना ने उत्रांगों को प्राथमिकता दी है। प्रथम पचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत उत्रांगों पर कुल लागत की ७६% रकम व्यय के लिये निर्घारित थी जबिक हस दूसरी योजना में (जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है) कुल लागत का १८.५% व्यय होने का श्रनुमान लगाया गया है। प्राथमिकता के कम में परिवर्तन करने के दो कारण हैं: (श्र) कृषि, सिचाई श्रीर शिक्त (विन्युत) ये निकास पर प्रथम पचवर्षीय योजना में पहले ही से पर्याप्त स्थान दिया गया है, श्रीर विकास की वर्तमान गित के हारा भी उन्हें पूर्ण रूप में निकसित किया जाना सभव है, श्रतएव उन पर कोई विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता नहीं है, श्रीर (व) श्रव यह श्रनुमान किया जाने लगा है कि देश के श्राधार भूत उत्रोंगों को वर्गर विकसित किए हुए यह समय नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय श्राय में एक कचे स्तर तक वृद्धि की जा सके श्रयवा वैरोजगारी की समस्या का ही कोई हल खोजा जा सके।

द्वितीय पचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य है कि देश की राष्ट्रीय श्राय में प्रति तालिका २ सरकारी क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुल लागत के तुलनात्मक आकडे

	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		
~ ^	कुल तागत (करोड़ रुपयों में)	कुल का प्रतिश्रत	कुल लागत (करोड़ रुपयों में)	कुल का प्रतिशत	
१ कृपि श्रीर धामुदायिक विकास	३५७	१५.१	<b>५६</b> ८	११८	
२ सिचाई श्रीर शक्ति (विजली)	६६१	रदं १	<b>६</b> १३	\$8.0	
<ol> <li>परिवहन श्रीर सचार</li> <li>उद्योग श्रीर सिनन</li> </ol>	प्रुष	१२३६ ७६	१३८५	२८°६ <b>१८ ५</b>	
💃 निर्माण कार्यं श्रीर	308			22.12	
शामानिक सेवार्ये ६ विविध	4.33 GE	२२ 🖣	#8E E&#</th><th><i>१६७</i> २१</th></tr><tr><th>कुत</th><th>२३५६</th><th>१००%</th><th>8200</th><th>१००%</th></tr></tbody></table>		

वर्ष लगभग ५% की वृद्धि हो श्रीर इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये पाँच वर्ष की श्रविष में कुल ६२०० करोड़ रुपये का वास्तिविक विनियोग (Net Investment) करने की श्रावश्यकता होगी, जबिक प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत मूल रूप में वास्तिविक विनियोग की रकम ३१०० करोड़ रुपये थी। श्रनुमान है कि इसमें से ३८०० करोड़ रुपये की रक्षम का विनियोग सरकारी चेत्र पर होगा, जिसकी व्यवस्था सरकार प्रयने वित्तीय साधनों से करेगी श्रीर शेप २,४०० करोड़ रुपये निजी चेत्र पर व्यवस्था होंगे, जो निजी विनियोग द्वारा उपलब्ध होंगे। विकास सम्बन्धी व्यय में ४८०० करोड़ रुपयों की कमी जो कि प्रस्तावित वास्तिविक विनियोग के कारण सरकारी चेत्र में श्रावश्यक होगा तालिका न २ में दिया हुश्रा है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना की 'त्राघारभूत नीति' यह है कि (श्र) इस्पात, यन्त्र-निर्माण, खनिज पदार्थ श्रादि के प्रमुख ग्रीर श्राघारभूत उद्योगो पर यथासभव श्रिषक से श्रिविक घन विनियोग किया जाय श्रीर इसके विपरीत सामान्य उपभोग में प्रयुक्त होने वाली वस्तुश्रों के उद्योगों पर यथासंभव कम से कम घन व्यय किया जाय, श्रोर (व) छोटे पैमाने के व घरेलू उद्योग-धघों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाय, चाहे इस प्रयास में बड़े पेमाने के उत्योगों की हानि ही क्यों न हो ।

उद्योगो श्रीर रानिज पर प्रस्तावित ८० करोड़ क्पयों के व्यय में से ६१७ करोड़ रुग्यों के लगभग वहें श्रीर मध्य वर्ग के उद्योगों पर, ७३ करोड़ रुपये खनिज के विकास पर श्रीर २०० करोड़ रुपये श्राम्य तथा छोटे उद्योगों पर व्यय किया जायगा। उद्योगों में से लोहे श्रीर इस्पात उद्योग को सबसे श्रावक भाग मिलेगा। प्रमुख विशेषता द्वितीय योजना की छोटे श्रीर कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने की है, जिस पर २०० करोड़ रुपया व्यय करने के लिए नियत किया गया है।

यद्यपि द्वितीय पचवर्षीय योजना में उद्योगों श्रीर खिनज पदायों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी गई है, किन्तु कृषि, परिवहन श्रीर सामाजिक सेवाश्रों की उपेक्षा नहीं की गई है। श्रनुमान है कि १६५५-५६ से १६६०-६१ तक द्वितीय योजना के श्रन्तर्गत खाद्यान्न का उत्पादन ६५० लाख से ७५० लाख टन, रई का ४२ लाख से ५५ लाख गाँठ, गन्ने का ५०० लाख टन से ७००१ लाख टन, तिलहन का ५५ लाख से ७० लाख टन, चाय का ६४४ करोड़ से ७० करोड़ पौंड हो जायगा। सिंचाई की जाने वाली भूमि का चेत्रफल ६७ करोड़ एकड़ हो जायगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों श्रीर सामुदायिक योजनाश्रों के मण्डलों की सख्या ५०० से ३८०० श्रीर ६२२ से ११२० कमश्च. हो जायगी। द्वितीय योजना की विशेषता यह है कि इसमें श्रनेकों कृषि उत्पत्ति की वस्तुयें जैसे

नारियल, सुपादी, लाख, कालीमिर्च श्रीर व्यक्कफल श्रादि, जिनकी श्रीर प्रथम योजना में घ्यान नहीं दिया गया था, इसमें सम्मिलित कर ली गई हैं श्रीर उनके विकास का ध्येय निश्चित कर दिया गया है। द्वितीय योजना में कृषि वा विकास श्रीषक विस्तृत दंग पर होगा।

जहाँ तक परिवहन से सम्बन्ध है भारतीय रेलों की यात्रियों तथा माल ले जाने की शक्ति नहा दी जायगी। रेलप्य १० करोइ ८० लाख मील से बहाकर १२ करोइ ४० लाख मील मोल मोर माल की दुलाई १२ करोइ मे १६ करोइ २० लाख हो जायगी। इसी काल मे राष्ट्रीय सहके १२,६०० मील से १३,८०० मील छोर कची सहके १०,००० मील से १२५,००० मील बहकर हो जायगी। तटीय व्यापार में जलयानो द्वारा टनेज ३'२ लाख जी० श्चार० टी० में बहकर ४७ लाख जी० श्चार० टी० हो जायगा। भारतीय वन्दरगाहों की माल चहाने श्चोर उतारने की शक्ति २ करोड ५० लाख टन से बहकर ३ करोइ २५ लाख टन हो जायगी।

तालिका २ मे प्रकट होता है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (अ) हाथ के करघे और राक्तिचालित करघे से तैयार किये गए कपहे, रासायनिक पार्टा, लोहे व इस्पात, एल्यूमीनियम और कोयले के उत्पादन में सब से अधिक वृद्धि होगी, (ब) मारी रसायनों, धाद्ध के सामान, अभ्रक, मेगनीज, साहकिलों, सीने की मशीनों ओर विजली के उत्पादन में अपेचाकृत कम वृद्धि की जायगी, और (स) मिल में तेयार होने वाले स्ती कपड़ों, कनी सामान, चीनी, साबुन, जूलों और वनस्पति तेलों के उत्पादन में और भी कम वृद्धि होगी। इस प्रयास में यह त्यान रागा गया है कि आधारमूत और प्रमुख उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन के द्वारा आत्मिनभैरता के अधिक से अधिक निकट पहुंचा जाय।

रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता (Employment potential)
—िद्वितीय पचवर्षीय योजना का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि रोजगारी के पर्याप्त अवसर उत्पन्न किए जार्ये। भागतीय अर्थं व्यवस्था की इसी आवश्यकता के फलस्वरूप कृषि की अपेद्धाकृत उद्योगों पर अधिक वल दिया गया है। इस योजना को इतना अधिक विस्तृत बनाने का आशिक कारण यह है कि वेकारी की समस्या को इल करने का प्रयत्न किया जाय। द्वितीय योजना काल मे नये काम करने वालों की सस्या जो वर्तमान सस्या में जुड़ जायगी लगभग १ करोड़ के अनुमान की गई है। यदि उसमें से ३८ लाख व्यक्तियों को, जो नगर की मजदूर सस्या में वृद्धि अनुमानित है, प्रयक कर लें तो जितने मजदूर देहातों के स्त्रेत्र में वहेंगे उनकी

रुख्या ६२ लाख के लगभग श्राती है। यदि एक करोड़ नये अमिकों की रुख्या में ५३ लाख पहले के वेकारों की सख्या (२५ लाख नगरों की श्रीर २८ लाख माम्य क्षेत्र में) जोइ दी जाय तो कुल वेकारो की सख्या १६५६-६१ में लगभग १ ५३ करोड़ हो लायगी। इतने नये व्यक्तियों को काम करने का अवसर प्राप्त करवाना सम्भव नहीं है। कदाचित ८० लाख व्यक्तियों के लिये द्वितीय योजना में काम के नये श्रवसर दिये जा सकते है। किंतु रोजगारी के श्रतिरिक्त श्रवसरी की केवल योजना-मात्र गढ जेने से तो समस्या इल नहीं की जा सकती। व्यापार श्रीर उद्योगों का प्रसार मात्र करके यह आशा करना कि उनके द्वारा श्रव श्रविक व्यक्तियों की खपत श्रपने श्राप होने लगेगी व्यर्थ है। इस समय ऐसे श्रनेक व्यवसाय हैं जिनमें श्राव-श्यकता से श्रिधिक लोगो को खपा लिया गया है। इसका परिखाम यह होगा कि जैसे-जैसे उन व्यवसायों में काम की वृद्धि होगी, वैसे-वैसे पहले से ही श्रधिक सख्या में काम करने वाले व्यक्तिया पर काम का बोक्त अधिक होता जायगा श्रीर इस प्रकार उन व्यवसायों में रोजगार के श्रवसरों में वृद्धि नहीं हो सकेगी। कुछ उद्योगों स्रार व्यापारिक सस्थास्रों में स्राभनवीकरण की योजनाएँ लागू किये जाने की भी सम्मावना है, जिसका फल यह होगा कि प्रसार किये गये उन उद्योगों में रोजगार के लिये और भी श्रिधिक कम सख्या में लोगों की खपत की जा सकेगी। योजना त्रायोग इन कठिनाइयो से भली भाँति परिचित है। "रोजगारी में ऋतु-मानित वृद्धि लाने के लिए वित्त और उपयुक्त नीति का अनुसरण करने की आव-श्यकता तो होगी ही, उसके साथ-साथ सुगठित सङ्गठन की भी व्यवस्था करनी पहेगी। वेकारी दूर करने के लिये छोटे छोटे उद्योग-धन्धों को विकसित करने पर श्रिधिक बल दिया गया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सुव्यवस्थित प्रयत्नों के श्रमाव में इनका उस सीमा तक विकास श्रीर प्रसार नहीं हो सकता। काम करने के श्रवसर पदान करने का शर्थ केवल नौकरियों की जगहें वढा देना मात्र नहीं है। यह जगहों के बढ़ा देने के प्रति जनता की प्रतिक्रिया पर निर्मर करता है। रोजगारी की न्यवस्था करने का यह भी श्रर्थ है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारियों के लिए जितने प्रशिच्य की स्रावश्यकता है उसे पदान करने की सुविघास्रों का प्रवन्ध किया जाय । यह त्रतुमान लगाया गया है कि श्रनेक चेत्रों में उत्पादन वृद्धि होने के फलस्वरूप उसी श्रनुपात में थोड़ी या बहुत मात्रा में रोजगारी में भी वृद्धि होगी। श्रतएव इस बात को श्रावश्यकता है कि अत्यधिक अभिनवीकरण पर नियत्रण किया जाय। साथ ही यह भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं पहले से रोजगार प्राप्त लोगों की मजदूरी बढ जाने से उस वस्तु की मौंग में कमी न आ जाय और इस प्रकार वेकार लोगों की स्पित श्रीर भी न विगढ़ जाय।"

वित्त व्यवस्था — योजना की सफलता वित्त की प्राप्ति पर निर्भर है। भारत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राष्ट्रीय बचत का स्तर राष्ट्रीय श्राय के अनुपात में बहुत कम है। इसिलये विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना श्रावश्यक हो जाता है। द्वितीय योजना के श्रनुसार विकास सम्बन्धी ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय का प्रवन्य तालिका न० ३ में जैसा दिखाया गया है किया जायगा। उसमें से ८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारों की श्रातिरिक्त श्राय से, १२०० करोड़ रुपया सरकारी श्र्या से, १२०० करोड़ रुपया सरकारी श्र्या से, १०० करोड़ रुपया श्रन्य वजट में व्यक्त श्राय खोतों से, ८०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता से श्रीर १२०० करोड रुपया घाटे के बजट से प्राप्त किया जायगा। इसमे ४०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ेगी जिस का प्रवन्ध या तो नये करों ने प्राप्त श्राय द्वारा श्रयवा श्रयक घाटे के श्रर्थ प्रान्ध द्वारा या श्रिषक विदेशी सहायता द्वारा या द्वितीय योजना के विस्तार को कम करके किया जायगा।

सरकारी चेत्र में विकास योजनात्रों का अर्घ पवन्य एक दूसरे दृष्टिकोश से भी देखा जा सकता है। पाँच वर्षी की श्रविघ में ४८०० करोड़ रुपयों के व्यय में से लगभग १००० करोड़ रुपयों का व्यय तो शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अन्वेपण श्रीर राष्ट्रीय विकास ब्रादि पर चालू व्यय के रूप में होगा । इस प्रकार के व्यय से प्रजी का प्रत्यक्त रूप से निर्माण नहीं होता श्रीर इसिलये विनियोजित व्यय नहीं माना जाता। ऐमे चेत्रों पर व्यय चालू ग्राय स्रोतों से पूरा किया जाता है। इसलिये वास्तविक विनियोग उद्भ०० करोड़ रुपयों का है श्रीर इसका प्रबन्ध ऋण द्वारा विया जा सकता है। विकासोन्मुख ग्रर्थ व्यवस्था में जहाँ पर प्ँजी निर्माण सम्बन्धी न्यय उत्तरोत्तर बढता जाता है, वहाँ यह वाछनीय होगा कि उसके एक अश का प्रबन्ध कर से प्राप्त अतिरिक्त आय में से किया जाय। इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में जोर दिया गया था और इस पर फिर जोर देना चाहिये। योजना के अर्थ प्रबन्ध की व्यवस्था में चालू आय में से केवल ८०० करोड़ रुपयों के प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है जब कि चालू व्यय के श्रनुसार १००० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। रेलवे से प्राप्त १५० ररोड़ रुपयों की आय को चालू श्राय का भाग सममना चाहिये। इसका श्रर्थ यह है कि कुल चालू श्राय से योजना के लिये प्राप्त वित्त ६५० करोड़ रुपयो का दुश्रा जब कि चालू व्यय की मात्रा १००० करोड़ रुपया श्रतुमान की गई है। इस प्रकार इम कह सकते हैं कि सरकारी श्राय में कुछ मी बचन नहीं है जिसका प्रयोग ३८०० करोड़ रुपये के विनियोग के लिए किया जाय, वास्तव में ५० करोड़ रुपयो का घाटा है। दूसरे शन्दों में कुल ३८०० वरोड़ पुंका जी निर्माण का श्रय-पवन्ध व्यक्तिगत बचत द्वारा

ही करना सम्मव होगा। यदि ८०० करोड रुपयों की विदेशी विक्तीय सहायता को अलग कर दिया जाय क्योंकि यह विदेशों की वचत पर निर्मर है और २०० करोड़ रुपयों की सहायता पौराड पावने की वची हुई रूप से प्राप्त की जाय, तो देश की आयिक व्यवस्था के अन्तर्गत चालू बचत की मात्रा जो कि सरकारी योजनाओं में विनियोजित की जायगी, २८५० करोड़ रुपयों के बरावर टहरती है। यदि यह मान लिया जाय कि ४०० करोड़ रुपयों की कमी सरकारी वचत द्वारा पूरी करली जायगी तो व्यक्तिगत बचत की मात्रा जो सरकारी चेत्र में स्थान।न्तरित की जायगी वह २४५० करोड़ रुपयों की होगी।

तालिका न० ३ सरकारी क्षेत्र के लिये वित्ता के स्रोत

(करोड क्पयों में)

				(कराह	व्यया म)
₹.	चालू श्राय के श्रतिरिक्त से		•		500
	(1) १९५५-५६ में प्रचलित कर की दर से		•		340
	(ii) त्रतिरिक्त कर मे		***		४५०
२	जनता से प्राप्त ऋण से .		***		१२००
	(1) बाजार ऋ्र्य (Market loans)	• (			600
	(11) छोटी वचत		•••		५००
₹.	वजट के श्रन्य श्राय स्रोतों से	•••			800
	(1) रेल का विकास कार्यक्रम में योगटान	•••			१५०
	(ii) प्रोविडेन्ट फरड तथा श्रन्य शीर्षों के ह	<b>ग्न्तर्ग</b> ट	जमा	धन से	२५०
٧,	विदेशों के स्रोतों से				500
યૂ	घाटे के श्रयं प्रवन्ध से		***	••	१२००
Ę	कमी—देशीय श्रतिरिक्ति स्रोतों से पूरी की व	ायगी		•	¥00
	<u>.</u>				8600
٠ 			• •	•	

"क्या यह मान लेना युक्तिसगत न होगा कि २४५० करोड़ रूपयों तक की व्यक्तिगत बचत की रक्षम सरकार को विनियोग के लिये प्राप्त हो जायगी? इस सबध में वाजार में ऋण लेने, छोटी मात्रा की बचत ब्रोर घाटे के अर्थ प्रवन्ध में अन्तर बहुत साधारण महत्व की बात है। ये सब व्यक्तिगत बचत को अपनी श्रोर से अयवा मृल्य की वृद्धि द्वारा वरवश राजकीय कोप में पहुँचाने के दक्क हैं। व्यक्तिगत बचत की मात्रा राजकीय कोप में कितनी श्रोर किस दक्क से पहुँचती है जनता की अपनी सम्पत्ति को रोकड़, सरकारी ऋग्य पत्रों, तथा छोटी मात्रा वाले सेविंग

सर्टी फिकेट के रूप में या जमा घन के रूप में रखने की इच्छा पर निर्भर रहता है। जब तक कुल बचत जो सरकारी कोप में पहुँचती है पर्याप्त मात्रा में रहती है तब तक इस बात से लोग उटासीन रहते हैं कि बचत की रक्षम ऋण पत्र, छोटी मात्रा के रेथिंग सर्टी फिकेट अपवा सरकारी नोट के रूप में है। ऐसी स्थित में सबसे ममुख महत्ता की बात यह जानने में है कि बया जनता की व्यक्तिगत बचत की मात्रा को हम व्यक्तिगत चेत्र की आवश्यकता से उतनी अधिक होने की श्राशा कर एकते हैं जितनी कि सरकारी चेत्र की श्रावश्यकता है। व्यक्तिगत बचत इस हिंछ कोण से पर्याप्त तभी हो सकती है जब कि उपमोग पर आवश्यक नियत्रण लगाया जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि प्रस्पन्त रूप से जितने ही कम अनुपात में जनता की बचत सरकार को श्राविरक्त करों की श्राय के रूप में अथवा सरकारी अनुक्तमों के लाभाश के रूप में होगी उतनी ही श्रिधक आवश्यकता ऐसे उपयोग में लाने की बढती जायगी जिनसे उपभोग आवश्यक स्था से श्राने न बढे"।

"केन्द्र श्रीर राज्यों के बजट स्रोतों में जो श्राय करों, श्राण, तथा अन्य उपायों से प्राप्त की जा सकती है वह लगमग २४०० करोड़ क्यये की है। घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध द्वारा लगभग १२०० करोड़ क्ययों की श्रोर श्राय वहाई जा सकती है। इस मात्रा में यदि ५०० करोड़ क्ययों की विदेशी वित्तीय सहायता श्रीर जोड़ दी जाय तो कुल श्राय जो सरकारी तेत्र में योजना के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये प्राप्त होगी वह ४४०० करोड़ क्यया होती है। इससे ४०० करोड़ क्ययों की कमी रह जाती है जिसके प्राप्त करने के विस्तृत उपायों को बाद में ढूँढा जायगा। यह तो मान लिया गया है कि यह कमी देश के स्रोतों में वृद्धि द्वारा ही पूरी की जायगी। घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध की सीमा को वित्ताराधीन रखते हुये जिसके चारे में ऊपर सकत किया जा जुका है तथा इस बात को मी वित्ताराधीन रखते हुए कि जिस अर्थ प्रवन्ध की योजना की रूपरेखा यहाँ बताई गई है उसमें श्रुण पर श्रावश्यकता से श्रिधक मरोसा किया गया है, इस कमी को पूरा करने का एक ही उपाय जिस पर निर्मर रहा जा सकता है वह करों का श्रारोग्य, तथा सम्भावित सीमा तक सरकारी उपकर्मों का लाभाश है।"

द्वितीय योजना को इस बात का पूरा शान है कि १२०० करोड़ रुपयो के घाटे के अर्थ प्रबन्ध किये जाने से मुद्रास्कीति की दशा उत्पन्न हो जायगी। योजना बनाने वालों ने ऐसी स्थिति से बचाव के लिये अनेक प्रतिबन्धों का निर्देश दिया है। उनके विचारानुसार:—

"सबसे प्रमुख सरज्ञ्या का उपाय बहुत बड़ी मात्रा मे खाद्यान एकत्रित करके

रख लेना होगा जिससे जब जब मुद्रास्फीति का प्रमाव जोर पकडे तो उसका निरा-करण किया जा सके। जहाँ की श्राधिक व्यवस्था में तीव्रगति से विकास का प्रयन्न किया जा रहा है वहाँ चाहे कितनी ही सममदारी से अर्थ प्रवन्ध क्यों न किया जाय मुद्रास्फीति का मय पूर्णतया मिटाया नहीं जा सकता। मुद्रास्कीति से सबसे उत्तम बचाव का ढग मुद्रास्कीति न होने देना है परन्तु ऐसी नीति जिसमें मुद्रास्फीति तो हो पर उसके दुष्प्रभावों से बच निकलें कभी सफल नहीं हो सकती । इस सम्यन्य में कुछ जोखिम तो उठानी ही पहेगी । इस जोखिम से बचने का सबसे श्राधक सफल उपाय खाद्याननों के श्रीर श्रन्य श्रावश्यक वस्तुत्रों के भगडार पर श्रधिकार रखना है ताकि जब इनकी कभी पढे तो बाजार में इनकी पति बढा दी जाय । भारतीय श्रार्थिक व्यवस्था में ग्रन्न श्रोर वस्त्र के मूल्यों का विशेष महत्व है श्रीर इनमें श्रधिक वृद्धि हर प्रकार से रोकना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जब तक इन वस्तुओं के मूल्य की युक्ति-सगत स्तर पर रक्खा जा सकेगा तब तक देश की श्रिधिकाश जन एख्या के जीवनस्तर की लागत नियत्र में रहेगी। श्रन्य वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्धि श्रपेज्ञाकृत कम महत्ता की बात होगी यद्यपि व्यवस्था में किसी भी वस्तु के मूल्य में श्रत्यधिक वृद्धि होने से द्रव्य के यपेचाकृत कम ग्रावश्यक उपयाग की वस्तुयों पर व्यथ किये जाने का मय है। यदि ऐसा हो जाय तब उसे ठीक करने का प्रयक्ष करना ग्रावश्यक होगा। मुद्रास्फीति के प्रभावों से वचने का दसरा उपाय विवेचनात्मक (discriminating) परन्तु तुरन्त हो करारोप के उपाय का श्रतुसरण कुछ वस्तुश्रों का श्रावश्यकता से श्रधिक उपयोग होने से वचाने के लिये श्रोर ऋत्यविक लाभाश तथा श्रमायास प्राप्त हुये लाभाश को रोक देने क लिये (जिनका कि घाटे के द्यर्थ प्रवन्ध में उत्पन्न हो जाना स्वामा-विक ही है) अत्यन्त आवश्यक होगा। अन्त में, कन्ट्रोल के उपाय का जिसमें राशनिंग तथा मात्रा नियत करना श्रादि सम्मिलित होंगे उपभोग के उचिन सीमा से आगे जाने से रोकने के लिये तथा दुर्जंम वस्तुश्रों और कच्चे माल आदि के प्रयाग में मितव्यता लाने के लिये प्रयोग करना स्त्रावश्यक होगा। परन्तु श्रवीत का अनुभव बताता है कि आवश्यक प्रयोग की वस्तुओं पर कन्ट्रोल लम्बी समया-विव के लिये विश्वस्त उपाय सिद्ध नहीं होंगे। इस कारण यह श्रमिवार्य हो जाता है कि इसके अर्तिरक्त ग्रन्थ बचाव के उपायों का प्रयोग पूर्य रूप से किया जाय क्योंकि योजना के कार्य-क्रम में कमी करने की सम्भावना तो ब्रात्यन्त कठिनाई में पड़ने पर ही करना उचित होगा।"

त्रालोचना—दितीय पचवर्षीय योजना की धारणा प्रथम योजना की श्रपेचा श्रधिक व्यापक श्रीर सुदृढ है। जब यह योजना समाप्त होगी तो प्रति

व्यक्ति की वास्तविक स्राय में स्रपेक्ताकृत स्राधिक वृद्धि होगी स्रीर लोगों की प्राधिक स्थिति में निश्चित रूपत्से सुधार होगा। द्वितीय योजना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

(१) इमके श्रन्तर्गत भौतिक (physical) नियोजन पर बल दिया गया है, न कि वित्तीय (financial) नियोजन पर। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य भीतिक उत्पादन के रूप में निर्घारित किये गये हैं जैसे इतने लाख टन इस्पात. कोयला, सीमेन्ट ग्रादि श्रोर फिर इन भिन्न-भिन्न वस्तुत्रों के लक्ष्यों के लिये वित्त को निर्घारण किया गया है। प्रथम पचवपीय योजना के श्रन्तर्गत पर्याप्त दर से व्यय नहीं किया जा सका श्रीर वास्तविक रूप में विकास का कम भी नहीं जारी रह सका, क्योंकि वह विज्ञीय नियोजन पर श्राघारित था। भौतिक नियोजन मे इस बात पर बल नहीं दिया जाता है कि अपुक योजना पर कितनी मात्रा में बन व्यय किया गया है, वरन उसमे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। इसका परिग्राम यह होता है कि नियोजन मे श्राधिक वास्तविकता श्रा जाती है। किन्तु भौतिक श्रीर वित्तीय लक्ष्यों में समन्त्रय स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्न विषयों पर विस्तृत और यथार्थ स्चना प्राप्त की जाय (य्र) भिन्न भिन्न वस्तुश्रो की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने में कितनी मात्रा में कच्चे माल, शक्ति, श्रम श्रादि की छावश्यकता होती है, श्रोर (व) भविष्य में इन विभिन्न कच्चे मालो व श्रम श्रादि का क्या-नया मूल्य होगा । श्रभाग्यवरा भारत मे इनसे सम्बन्धित सही-सही श्रीर विश्वसनीय स्वनाएँ उपलब्ध नहीं हैं श्रोर इसीलिए यह श्राशका उत्पन्न होती है कि भौतिक नियोजन से समस्या इल होने के स्थान पर कहीं और जटिल न हो जाय। ''लोकतान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत आधिक दृष्टि से पिछड़े हुये एक ऐसे देश में जहाँ का शासन-यत्र शार्थिक नियोजन की श्रावश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता ग्रीर जहाँ का प्रत्येक विभाग स्त्रोर प्रत्येक मन्त्रालय श्रपनी चलाई हुई योजनान्त्रों पर यथासभय श्रिषिकतम घन व्यय करने का प्रयत्न करता है, वित्तीय नियोजन के स्थान पर भौतिक नियोजन पर बल देने का श्रानिवार्य परिणाम यह होगा कि (क) श्रस्यधिक धन का श्रपब्यय होगा श्रीर (ख) श्रधिक मात्रा में सरकारी ब्यय के कारण मुद्रास्फोति की प्रवृतियों के उत्पन्न होने की सभावना है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्त मन्त्रालय ने यह सिद्धात सामने रखा कि विशेष परिस्थि-तियों को छोड कर अन्य स्थितियों मे किसी को भी निर्घारित रकम से अधिक व्यय करने भी स्वीकृति नही दो जानी चाहिये ख्रोर इस प्रकार सरकारी व्यय पर कड़ा नियम्रण स्थापित किया गया। किन्तु जहाँ तक भौतिक नियोजन का सम्बन्ध है, यह तर्क जिल्कुल निर्यंक है। चूँकि द्वितीय पचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य है कि निर्धारित किये गये मौतिक लक्ष्यों (physical targets) की पूर्ति की जाय, अतएव मिल-भिन्न विभागों और मन्त्रालयों को अपने निर्धारित वित्त से कुछ अधिक व्यय कर सकने की छूट प्राप्त होगी। सरकारी व्यय में कभी करना अयवा योजना-काल के अन्तर्गत अनुमानित रकम का विनियोग न कर सकना योजना का एक दोप है। किन्तु उससे भी बड़ा दोप यह है कि धन का अपव्यय किया जाय और उसके फलस्वरूप सरकारी धन की हानि तो हो ही साथ ही साथ अनियन्त्रित मुद्रास्कीति के दुष्परिणामों का भी सामना करना पडे । १० इससे यह प्रकट होता है कि विचीय नियोजन से सम्बद्ध खतरो और भूलों से बचने के लिये अत्याधक सावधानी की आवश्यकता है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि विचीय नियोजन के स्थान पर मौतिक नियोजन पर बल दिये जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक वास्तविकता आ गई है।

- (२) द्वितीय योजना ने प्रमुख रूप से श्रीद्योगिक विकास पर वल दिया है। प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत कृषि श्रीर शक्ति (विजर्ला) के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस प्रकार द्वितीय योजना से देश का श्रार्थिक विकास श्रिषक सन्तुलित हो जायगा। श्रीद्योगीकरण पर इसलिए जोर दिया गया है कि (श्र) प्रथम योजना के श्रन्तर्गत कृषि श्रीर सिचाई में पहले ही से काफी प्रगति हो सुकी है श्रीर इसीलिए उद्योगों पर श्रिषक ध्यान देना श्रावश्यक हो गया है, क्योंकि प्रथम योजना के श्रन्तर्गत उद्योगों की उपेका की गई थी; (व) यदि हम प्रमुख रूप से केवल कृषि पर ही श्रपना ध्यान वेन्द्रित करते हैं तो यह समव नहीं है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसख्या के साथ-साथ वेरोजगारी श्रीर श्राधिक रोजगारी की समस्या को इल किया जा सके। श्रीयोगिक विकास को प्राथमिकता देने का यह उद्देश्य है कि वेरोजगारी श्रीर श्राधिक रोजगारी की समस्या को इल करने में सहायता मिले, श्रीर (स) पहले की श्रपेकाकृत यह श्रिषक स्पष्ट रूप से श्रनुभव किया जाने लगा है कि देश की श्रार्थिक सम्पन्नता श्रन्तत श्रीद्योगीकरण से सम्बन्ध स्वर्ता है।
- (३) प्रथम पचवर्षीय योजना की श्रपेद्धाकृत दितीय योजना के श्रन्तर्गत -'सामाजिक न्याय' पर श्रधिक ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना का उद्देश्य यह या कि देश में महायुद्ध के पूर्व दैनिक उपयोग की वस्तुश्रों की जिस मात्रा में खपत

<sup>1</sup> Vide the Author's article on "Some Basic Considerations about the Second Five-year Plan" in the Commerce, dated July 2, 1955, page 15

होती थी, उसी स्तर को फिर से ले आया जाय। द्वितीय योजना एक पग श्रीर आगे बढ गई श्रीर उसका लक्ष्य यह है कि उसके समाप्त होने पर देश के कुल उपमोग में लगभग २०% श्रीर प्रति व्यक्ति के उपयोग में १२-१३ प्रतिशत की वृद्धि हो। यह समब होगा या नहीं, किन्द्र दितीय एचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक राष्ट्रीय श्राय की १०% राशि करों के रूप में लो जायगी, जबिक श्रमी तक करों के रूप में ली जाने वाली राशि इसकी ७% है श्रीर एह निर्माण, सामाजिक कल्याण श्रादि पर श्रिषक रकम व्यय करने की व्यवस्था की गई है क्योंकि इनके द्वारा धनिकों की श्रभेद्या निर्धनों को श्रिषक लाम होता है। इसी कारण दितीय पचवर्षीय योजना को प्रगतिशील कहा जा सकता है।

नि: सदेह द्वितीय पचवर्षीय योजना में ऐसे ख्रानेक दोव हैं जो इसे एकाङ्गी श्रीर श्रात-श्राकाची (over-ambitious) बना देते हैं। सबसे पहले तो यही तर्फ रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय योजना के लिए यह समय नहीं है कि वह पाँच वर्ष की अवधि में कुल ६,२०० करोड़ रुपए के वास्तविक विनि-योग (net investment) का प्रबन्ध कर सके, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि १६५५-५६ में राष्ट्रीय श्राय की जो ७ ३% राष्ट्रीय बचत होगी, उसे १६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय की १०'७% कर देना संमव नहीं होगा। इस धारणा का समर्थन कुछ ऐसे विदेशी राष्ट्रों के अनुभवों के दृष्टान्त देकर किया गया है जहाँ पर लोकतान्त्रिक आधार पर नियोजन हुआ है या हो रहा है। शो० नी० आर० शिनोय की यह धारण है कि "अपने पिछले वर्षों के श्रौर दूसरे जनतान्त्रिक देशों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रभी कुछ समय तक यह श्राशा करना न्यर्थ है कि विकास कार्य-क्रम के लिए इतने अधिक वित्तीय साधन उपलब्ब होंगे, जिनसे राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धिकी दर दुगुनी हो जायगा। इस समय इमारे देश में राष्ट्रीय बचत की दर राष्ट्रीय आय की ७% या इससे भी कुछ कम है। पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत इसमे लगभग १% वृद्धि हुई है। यह अनुमान करना कि मावी पाँच वर्षों में वृद्धि की दर बहुत श्रिषिफ तेज हो जायगी, केवल दुराशा-मात्र है। सरकार ने यह नीति घोषित की है कि स्राय वितरण की अस-मानवाश्रो को यथासमन कम किया जायगा, जिसका परिखास यह होगा कि सम्पूर्ण वचत की रकम में घटती हो जायगी। चूं कि हमारे देश के श्रिमिकाश लोग जिस मात्रा में खाद्याच का उपयोग करते हैं, वह राष्ट्रीय श्रीसत श्रीर पीष्टिक भोजन के निम्नतर स्तर से कम है, इसलिए यह अनुमान है कि दैनिक उपयोग के व्यय में जो वृद्धि होगी उसका ५.% तो खाद्यान्न पर ही व्यय कर दिया जायगा। परम्परा के क्राधार पर यह कहां जा सकता है कि यद्यपि इधर कई वर्षों में पैदावार श्रव्ही श्रवश्य हुई है, किन्तु फिर भी सभावना है कि श्रागामी वर्षों में फसलें विल्कुल ही खराब होंगी या उनसे कम पैटाबार होगी। इन परिस्थितियों में यह श्रतमान करना िमाबी पाँच वर्षों में बचत की दर प्रतिशत से श्रधिक होगी उचित नहीं है। किन्तु इसके साथ ही बचत की दर में श्रनमान से श्रधिक वृद्धि होना भी विल्कुल ग्रसमव नहीं है। श्रतएव इस बात की ग्रावश्यकता है कि बचत की उक्त दर से जिस मात्रा में वित्तीय साधन वास्तव में उपलब्ध होंगे, उन्हीं के श्रनुरूप योजना के श्रावार को बनाने के लिए उसमें सशोधन किए जाय श्रौर राष्ट्रीय श्राय की श्रनुमानित वृद्धि के श्रनुसार ही विनियोग की रकम निर्धाति की जाय"।

यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी भी योजना के अन्तर्गत अन्मानित व्यन की रकम स्वभावत: ही प्रयोगिक (Tentative) रूप में निर्वारित की जाती है यौर यदि श्रनुमानित साधन उपलब्य न हों तो योजना की लागत को उसी के श्रनुसार घटाया जा सकता है। किन्तु इस तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि (य्र) ''इस प्रकार सशोधन करने से नियोजन में गडबड़ी आ जाती है। सबमें वडा दोष तो यह है कि अनुमानित विनियोग श्रोर उत्पादन के स्तर में बहुत अविक कमी कर देने से सामान्य जनता में योजना के प्रति निराशा उत्पन्न हो जाने की सभावना रहती है। यदि सरकार कृत्रिम रूप से विनियोग की दर को लादने का प्रयास करता है, तो उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भीषण मुद्रास्फीति का उदय होगा। स्रार्थिक नियम ब्रत्यन्त कठोर होते हैं ब्रीर उनके लागू होने में र्मौल्यिको (Statisticians), श्रर्थ-शास्त्रियो या राजनीतिज्ञों की सुविधा-श्रसुविधा पर नोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि कोई मूल की जाती है, तो उसके दुष्परि-याम हमें निश्चित रूप से भुगतने पहेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक से अधिक यथार्थनादी होकर अधिकतम सावधानी वरतने की आवश्यकता हैं", और (व) "वास्तव में जितने साधन उपलब्ध हैं, उनकी ज्ञमता से ऋधिक विकास कार्य कम को वलपूर्वक गतिशील वनाने का श्रनिवार्य रूप से यह परिणाम होगा कि श्रनियत्रित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। एक ऐसे जनतान्त्रिक देश में, जहाँ की श्रिधिकारा जनता के पास जीविका-निर्वाह के केवल निम्नतम साधन हैं, वहाँ मुद्रास्फीति के परिगाम श्रत्यन्त भयकर होंगे श्रोर समव है कि उनसे समान का वर्तमान दाँचा भी जर्जर हो नाये। यदि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साम्यवादी

<sup>1</sup> Prof B R Shenoy, "A Note of Dissent on the Memorandum of the Economists' Panel", p 4 Also see for a summary of this note Commerce, dated May 28, 1955, p 15

श्चर्यं व्यवस्था के समान भौतिक साधनो का सहारा लिया गया तो योजना की श्चावरयकताश्चों को पूरा करने के लिए शासन-सम्बन्धी या श्चन्य वैधानिक उपायों के द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्चौर जनतात्रिक सस्याश्चों का (धीरे धीरे या तेजी से) लोप हो जायगा। श्चतएव श्चतिशाकात्ती योजना के भयकर दुष्परिणामों के प्रति हमे सचेत रहने की श्चावरयकता है"।

दितीय पचवर्षीय योजना की आलोचना का दूसरा आघार यह है कि उसके श्रन्तर्गत उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर उचित व्यान नहीं दिया गया है। जब किसी विकास कार्य-क्रम पर धन व्यय किया जाता है तो वह अमिका, कच्चे माल की पृति करने वालों श्रीर श्रन्य व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो स्वय उस धन को उत्पादित वस्तुश्रा पर व्यय करते हैं। वस्तुत: श्राधिक विकास की यही प्रक्रिया है। यदि सभी दृष्टिकोणों से विचार करें तो ज्ञात होगा कि धन-उपार्जन करने वालों के द्वारा उसका व्यय किया जाना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं का वेचने का श्रवसर प्राप्त होता है जिसका परिणाम यह होता है कि उन बिकी हुई वस्तुत्रों के फलस्वरूप फिर नई वस्तुत्रों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया को बरावर जारी रखने के लिए श्रावश्यक है कि उपमोक्तान्त्रों की क्रय-शक्ति (purchasing power) में वृद्धि हो। जब तक कि सभी साधनों का पूर्ण उपभोग नहीं हो जाता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। यदि किन्हीं कारणों से लोग उत्पादित वस्तुओं का उपमीग नहीं कर पाते तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया का चेत्र सकुचित हो जाता है। द्वितीय योजना में यह निर्देश किया गया है कि योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में राष्ट्रीय श्राय पर कर की ७ प्रतिशत दर को बढ़ाकर १६६०-६१ तक ६ या १० प्रतिशत किया जायगा। यही नही, कर की दर मे १२ प्रतिशत तक वृदि करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में कर की दर पहले ही से ऊँची है श्रौर इसीलिए योजना श्रायोग की यह धारणा है कि "करों के वर्तमान स्तर-राष्ट्रीय आय का ७%-को मी बनाए रखने के लिये उसमें कुछ न कुछ सशोधन श्रवश्य करने होंगे"। यदि करों में श्रव तनिक मी वृद्धि हुई, तो उससे लोगों को अत्यधिक कृष्टों का सामना करना पढेगा और व्यापार व उद्योगों के सामने भी श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी। यदि करों की किसी भी विधि से लोगों की फयशक्ति चीगा होगी श्रयवा वस्तुत्रों में वृद्धि होगी, ते यह निश्चित है कि दितीय योजना के कार्य-क्रम में बाघा पहुँचायेगी। जैसे जैसे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि

Wide the Author's article, loc at , p 15

होगी और श्रीद्योगिक व व्यवसायिक कायों का चेत्र विस्तृत होता जायगा, वैसे-वैसे करों से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होती जायगी। किन्तु यि उपमाक्ताओं की कय-शक्ति को श्वीय बनाते हुए करों में वृद्धि करने का प्रयास किया जायगा तो यह निश्चय है कि योजना के कार्यान्वित होने में वासा पहेगी श्रीर राष्ट्रीय श्राय में श्रनुमानित वृद्धि भी नहीं श्रा सकेगी। इसका परियाम यह होगा कि वाजार में तथा कारखानों के योदामों में वगैर विकी हुई वस्तुओं का देर लग जायगा श्रीर इस प्रकार उसका उत्पादन या तो घट जायगा या बिल्कुल ही चन्द हो जायगा। इस श्रव्यवस्था के फलस्वरूप योजना की प्रगति को गहरा धक्का लगेगा।

यदि लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ग्रापना उपमोग कम श्रौर बचत श्रधिक करें तो ठीक वैसे ही दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे। कल समय पूर्व यह यारणा प्रचलित थी कि श्रिधिक बचतों से उसी श्रानपात में श्रार्थिक विकास भी अधिक होता है। किन्त्र श्रर्थशास्त्र के श्राप्तिनक सिद्धान्त इस धारणा के विल्कुल विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचे हैं। उनके श्रनुसार जितना ही श्रधिक उपमोग किया जायगा उत्तना ही श्रिधिक श्रार्थिक विकास होगा । यदि कृत्रिम राशि का विनियोग करने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो श्रौर उसकी खपत हो जाने पर पहले की श्रपेचाकृत श्रधिक उत्पादन हो श्रीर यह सम्पूर्ण श्रार्थिक प्रक्रिया निर्विप्त रूप से चलती रहे, तो वचतों के सम्बन्ध में कठिनाई उठाने की कोई श्रावरयकता ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि होने के फलस्वरूप वचत की कुल रकम में भी वृद्धि होती है स्त्रीर श्रन्त में वचतो के द्वारा विनियोग सन्तुलिट हो जाता है। किन्तु यदि बहुत शीव्रता से वचत की रकम में वृद्धि करने का प्रयास किया जाय तो आर्थिक विकास का चेत्र सकुचित हो नायगा। यदि सरकार की कर नीति श्रयना श्रन्य नीतियों से वस्तुय्रों के मूल्य में वृद्धि हो श्रीर उपमोक्ताओं की क्रय-शक्ति घट जाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि कपडे, चीनी, खाद्यास श्रीर श्रन्य वस्तुश्रो की प्रति-व्यक्ति खपत (Per ca bita consumption) में अनुमानित वृद्धि नहीं होगी श्रीर न रहन-सहन का स्तर ही ऊँचा उठेगा, चाहे किसी प्रकार उन वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ा ही क्यों न लिया जाय।

तीसरी वात यह है कि योजना के अन्तर्गत अनुमानित घाटे के वजट की १,२०० करोड़ रुपये की रकम (जा देश की वर्तमान द्रव्य-पूर्ति का ५०-६०% है) से अत्यधिक मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाने की सभावना है। किसी भी ऐसे देश में, जहाँ व्यवस्थित रूप से आर्थिक विकास किया जा रहा है, मुद्रास्फीति का उदय

होना श्रवश्यम्भावी है। किन्तु श्रावश्यकता इस बात की है कि मुद्रास्फीति पर कहा नियत्रण रखा जाय जिससे कि श्रिषक हानि न होने पाये। प्रोफेसर शिनोय की यह घारणा ठीक ही है कि "यदि यह मान भी लिया जाय कि राष्ट्रीय श्रांय में वृद्धि की दर दुगुनी हो जायगी, तो भी श्रितिरिक्त रोकड़ बाकी (cash balances) के लिए इतनी श्रिषक माँग नहीं हो सकती कि कुल इन्य-पूर्ति (money supply) की ५०-६०% रकम की ज्यवस्था घाटे के बजट के रूप में करने की श्रावश्यकता पहे। यदि केन्द्रीय बैंक (Central bank) का एक-तिहाई श्रानुमानित द्रव्य घाटे के बजट के द्वारा चलन में श्राकर ज्यवस्थायक बैंको (Commercial banks) के सुरचित कोपों में वृद्धि करता है श्रोर उसके श्राघार पर वे ज्यवसायक वैंक ६-७ गुनी सास का निर्माण कर लेते हैं, तो योजना-काल के उपरान्त कुल द्रव्य की पूर्ति योजना प्रारम करने के समय की द्रव्य-पूर्ति से दुगुनी या उससे भी श्रिषक हो सकती है। इसके फलस्वरूप मुट्टास्फीति को निश्चित रूप से जन्म मिलेगा"।"

१ पर्यास सुचनायें न होने के कारण यह बताना कि किस सीमा तक बाटे का अर्थ प्रवन्ध भारतीय अर्थ व्यवस्था विना हानि पहुँचाये सहन कर सकती है श्रसम्भव है। प्रो० शिनीय ने श्रनुमान लगाने का साहस किया है। "इस शीर्वक के अन्तर्गत घाटे के श्रर्थ प्रवन्ध की मात्रा में पीयह पावने की मात्रा जो सरकारी चेत्र की प्रार्थिक छावश्यकता के लिये काम में लाई गई है जोड देने पर को मात्रा प्रावे उसे ही घाटे के अर्थ प्रवन्य करने की वह सीमा समसा जा सकता है जिस तक किसी हानि की आराका नहीं की जा सकती। पाँच पर्ने के मीतर पींड पावने की मात्रा १०० से लगाकर १५० करोड रुपमे तक योजना के अन्तर्गत मानी गई है। इसके एक अश को ध्यक्तिगत चेत्र के लिये नियत करना पदेगा और उसकी मात्रा के बराबर वैकों द्वारा साख उत्पन्न करनी पड़ेगी। यदि हम रोकड बचत तथा पींड पावने की रकमों को सरकारी चौर व्यक्तिगत चेत्रों में २:१ के श्रनुपात में फ्रमशः वॉर्टे तो कुल घाटे का र. में नर्पन १८० से लगाकर २२० करोड रुपये तक पाँच वर्षों की अविधि में दंशीमा, अर्थात ३५ से ४५ करीड रुपये प्रति वर्ष की दर के हिसाब से होगा।" इस मात्रा को घाटे के अर्थ प्रबन्ध की उचित सीमा चाहे हम मानें या न मानें पर इसमें कोई सदेह नहीं है कि २०० करोड रुपयों का घाट का प्रति वर्ष श्रीसत अर्थ प्रबन्ध जो कि द्विताय योजना में किया जाने वाला है बहुत अधिक है। इससे ऐसी सुद्रास्कीति शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती है कि योजना ही नष्ट अष्ट हो जाय।

श्रितिम बात यह है कि यद्यपि द्वितीय योजना द्वारा प्रथम योजना की एक भूल का सुधार किया गया है श्रीर श्रीद्योगिक विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, किन्तु फिर मी सभव है कि एक दोषपूर्ण श्रौद्योगिक ढाँचे का ही निर्माण हो, श्योंकि उसमें दैनिक उपयोग में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले कारखानों के उद्योगों की उपेन्ना की गई है। "यदि योजना श्रायोग की बढे पैमाने वाले उद्योगों के स्थान पर छोटे पैमाने के स्त्रोर घरेलू उद्योग-धर्घों को विकित करने की योजना सफल हो जाती है, तो इसका परिगाम यह होगा कि वहे-बढे उद्योगों का हास होने लगेगा श्रीर उनके द्वारा प्रत्यज्ञ या श्रप्रत्यज्ञ रूप में प्रयुक्त होने वाली मशीनें, इस्पात स्रोर श्रन्य श्राघारभूत चामग्री की माग बढ़ने के स्थान पर श्रोर भी घट जायगी"। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि "यदि संरक्त्य, सगठन ग्रीर श्राथिक सहायता के द्वारा जितना ही श्रिषिक घरेलू उद्योग-धर्षों का विकास होगा श्रीर कारखानो के चेत्र में श्रायुनिकीकरण व प्रसार करने का कार्यं जितने ही श्रिधिक समय के लिए स्थगित किया जायगा, तो उक्त समस्यात्रीं को इल करने वी कठिनाई भी बढती ही जायगी। यदि ऐसा विकास कार्यक्रम श्रपनाया गया, निसमें छोटे-छोटे उद्योगों का प्रसार करके श्रीद्योगिक नीति बिल्कुल परिवर्तन कर दी जायगी और मशीनो व विजली की शक्ति की पूर्ति भी इन्हीं घरेलू उद्योग-घर्षों के लिए की जायगी, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य श्रार्थिक इष्टि से निवान्त अनुचित होगाः । १

१ इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना उचित होगा कि "छोटे छौर प्रास्य उद्योगों को सगठित करने के लिये बहुत श्रधिक प्रयस्न करना श्रावण्यक होगा । ऐति-हासिक दृष्टि से तो प्रवृत्ति सुसगठित पेनिट्रयों की स्थापना के साथ प्राम्य उद्योगों के विद्धिकार करने की रही है। यह विद्धिकार जहाँ क्हीं मी हुआ है प्रशासन की श्राशानुसार नही हुआ है। यह तो श्रधिक छुशल उत्पादन की प्रणाली के प्रति पचपात जो कि श्राधिक विकास का तर्क युक्त परिणाम है उसके कारण हुआ। इसलिये स्वमावत नष्टप्राय प्राग्य उद्योगों का पुनरद्वार करने के लिये हमें विकास-प्रम्म के ऐतिहासिक मवाह के विरुद्ध चलना पड़ेगा और उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फेक्ट्री की व्यवस्था वाले उद्योगों के विस्तार के विरुद्ध वृत्रिम वाधायें उपस्थित करनी पढ़ेगी, और इस सम्बन्ध में मुद्दास्कीति की ऐसी स्थित उत्पन्न करनी पढ़ेगी कि जो आगे चलकर सम्भवत हमारे नियन्नण के बाहर हो जाँय अथवा हमारी श्राधिक व्यवस्था को सत्ता के लिये स्थिर कर दें। यदि परम्परागत उन्न के छोटी मान्ना में उत्पादन करने वाले उद्योगों को विकसित किया जाय तो सर्चीली व्यवस्था का प्रवन्ध करना

इस सम्बन्ध में एक दूसरा हिन्दकीया यह है कि भावी श्रीद्योगीकरण सरकार श्रीर निनी उद्योगों के सम्मिलित प्रयास पर श्राधारित होगा। यद्यपि द्वितीय पचवर्षीय योजना में निजी चेत्र के श्रान्तर्गता २४०० करोड़ रुपए के व्यय की रक्षम निर्धारित की गई है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इतनी श्रधिक राशि किन साधनों से उपलब्ध होगी। योजना के श्रनुसार, "निजी उद्योगों के निर्माण-कार्य के लिए बचत की रकम प्राप्त करने के क्या साधन होंगे, यह निर्देश करना कठिन है। इसके अतिरियत यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि निर्माग-कार्य में अनुमानित दृद्धि की पूर्ति होगी ही। कुल बचत के अपर्याप्त होने पर कमी कहाँ से पूरी की जायगी, इसका पता नहीं। चें कि सरकारी चेंत्र को सभी साधन उपलब्ध होने की कदाचित श्रधिक सभावना है, इसीलिये बहुत कुछ समव है कि निजी चेत्र को अनुमानित साधन न प्राप्त हो सके। इस परिस्थिति का फल यह होगा कि इधर सरकारी तेत्र के अवर्गत श्रीद्योगिक विकास होगा श्रीर उघर निजी च्रेत्र में श्रीद्योगिक प्रगति न होने के कारण सम्पूर्ण श्रीद्योगिक विकास की स्थिति बहत कुछ सीमा तक वैसी ही रह जायगी। श्रतएव दितीय योजना के श्रन्तर्गत जितना श्रीद्योगिक विकास होने का अनुमान किया गया है वह नहीं हो सकेगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी की समस्या को इल करने पर बहुत जोर दिया है। वास्तव में छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग घन्धों के विकास को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण भी यही है। किन्तु यन्त्र तैयार करने वाले उद्योगों का नियोजन इगलैंड, श्रमरीका श्रीर रूस के श्राधार पर किया जा रहा है। योजना श्रायोग को चाहिये था कि इमारी विशिष्ट श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के नये यन्त्र तैयार करने की व्यवस्था करता, जो इतने कार्यज्ञम होते कि उनके द्वारा प्रति इकाई के उत्पादन की उतनी ही लागत पड़ती जितनी कि विश्व के श्रन्य श्रीद्योगिक दृष्टि से विकिसत देशों में तैयार की गई 'श्रम की बचत करने वाली' (Labour-saving) श्रीर श्रपने श्राप चलने वाली मशीनों के द्वारा पड़ती है, किन्तु उनके (भारत की विशेष श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर बनने वाली मशीनों) द्वारा पूँजी-विनियोग की प्रति इकाई में श्रिषक श्रमिकों की खपत होती। यदि उचित व्यान दिया जाय तो इस प्रकार

आवश्यक होगा । ऐसा करने पर सफलता तो सीमित मात्रा में ही प्राप्त होगी पर यदि असफल हुये तो परिणाम मयावह होगा।" (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry's "Second Five-Year Plan, A Comparative Study of the Objectives and Techniques of the Tentative Plan-frame", pp 78)

के यन्त्रों का निर्माण होना पूर्णरूप से सम्भव है। केवल पूँजी की बचत करने वाले (Capital-saving) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करने का महत्व इसिलए भी बहुत ऋधिक है कि केवल हन्हीं के द्वारा भारत की वेरोजगारी श्रीर श्राशिक रोजगारी की समस्या स्थायी रूप से हल की जा सकती है। ऐसी व्यवस्था की कमी द्वितीय पचवर्षीय योजना का एक बहुत गम्भीर दोष है।

## योजना का पुनर्मूल्यन

द्वितीय पचवर्षीय योजना को पारम्म से ही श्रम्राधारण कठिनाइयों का सामना करना पडा। (श्र) श्रायात की हुई मशीनों, कच्चे माल तथा श्रम्य माल का मूल्य स्वेज-सकट के कारण बढ़ गया। विदेशों में भी मूल्य वढ़ गये। देश में विनियोग की श्रत्यधिक देर के कारण मुद्रास्कीति की दशा उत्पन्न हो गई जिसके परिग्णाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई। परिग्णाम यह हुस्रा कि योजना के अवर्गत विभिन्न योजनात्रों की लागत वढ गयी तथा प्रारम्भ में निर्घारित विच से मौतिक लक्ष्यो (physical targets) की प्राप्ति श्रवम्भव हो गई । (व) योजना के लिये ब्रत्यधिक कर लगाने तथा ब्रम्य उपाय करने पर भी साधनी की कमी पड़ गयी श्रोर विदेशी विनिमय का सकट उपस्थित हो गया। (स) द्वितीय योजनाका भार जनताकी वहन शक्तिके लिये श्रविक सात्रित हुश्रा। योजना में सदैव ही कुछ त्याग करना होता है किन्तु द्वितीय योजना में श्रपेिज्ञत त्याग बहुत श्रधिक हो गया। श्रतएव योजना श्रायोग तथा भारत सरकार को यह मुफाव दिया गया कि योजना में कटौती की जाय तथा विनियोग की दर कम की जाय। योजना ग्रायोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा भारत सरकार ने विचार-विमर्श के बाद योजना में कटौती करने के बजाय उसे दो भागों मे बाँट दिया। (१) माग स्त्र जिसके स्रान्तर्गत कृषि उत्पत्ति की वृद्धि से प्रत्यज्ञ रूप से सम्बन्धित योजनायें, मुख्य (core) योजनायें (रेलवे, वहे वन्दरगाह, स्टील, कोयला तथा श्रन्य शक्ति योजनायें) जो काफी श्रागे वढ गयी हैं तथा श्रन्य योजनायें जिन पर कुल ४५०० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है, तथा (२) भाग व जिसमें ३०० करोड़ रुपये की शेप योजनायें सम्मिलित है।

जैसा कि 'द्वितीय पवनर्षीय याजना : पुनर्मूल्यन व सम्भावनायें' (मई १६५८) से प्रकट है योजना श्रायोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि योजना पर प्रारम्भिक श्रातुमान की तुलना में ५४० करोड़ ६० कम श्रयांत् ४२६० करोड़ ६० व्यय होगा।

मई १९५८ में योजना श्रायोग ने बोपणा की कि यथार्थ उपलब्ध साधन ४२६० करोड़ रु० ही है, फिर मी भाग श्र के श्रर्थ प्रवन्धन का पूरा प्रयक्ष किया

## योजना के लिये प्रसाधन (१९४६-१९६१)

(करोड़ ६० मे)

साधन	योजना के लक्ष्य	उपल्िष की सम्भावना
१. बजट के साधन	₹500	२२६२ -
(श्र) चालू श्राय से बचत	2200t	<u> 58</u> 8
(म) रेलवे का ग्रशदान	१५०	१५०
(स) ऋण तथा श्रहा वचन	१२००	१०४४
(६) ऋग तथा विविध पूँ जी प्राप्ति	२५०	६६
२. विदेशी सहायता	500	<b>१०</b> ३⊏ ~
३. घाटे का श्रर्थ प्रयन्यन	१२००	१२००
<b>कु</b> ल	8200	४२६०

जायगा। सितम्पर १६५८ में यह घोपणा की गई कि भाग श्र की याजनात्रां को ४५०० करोड़ ६० तक नहीं सीमित किया जा सका श्रतएव १५० करोड़ ६० का ज्यय ग्रीर परना होगा श्रीर इस प्रकार कुल ज्यय ४६५० करोड़ ६० होगा। योजना श्रायोग ने यह सुमान दिया कि राज्य सरकार योजना की रोप श्रवांघ में १४० करोड़ ६० का ग्रातिरिक्त साधन प्राप्त करें—६० करोड़ ६० कर द्वारा, ५० कराइ ६० श्रमण श्रीर श्रव्य बचत द्वारा तथा ३० करोड़ ६० योजना के बाहर क ज्यय में कमा कर के। परन्तु राज्य सरकार ६० वराइ ६० कर द्वारा एकत्रित नहीं कर सकतीं। ऊचे मूल्यां के कारण जनता की बचत कम हो गई है तथा श्रशतः बचत निजी साहसी प्रयोग में ले श्रांत है ग्रतएव इस साधन से राज्य सरकारों को ५० करोड़ ६० प्राप्त करना समय नहीं प्रतीत होता। कुछ लोगो की राय में कही श्रच्छा होता यदि योजना ग्रायोग स्थिति का यगार्थता से सामना परता तथा ज्यय को देश की शक्त के श्रन्दर ही रखता।

श्रायात के मूल्यों में वृद्धि होने तथा श्रन्य लागतों के बढ़ने के कारण सबसे श्रिकि वृद्धि 'उद्योग तथा खनिज' में हुई है तथा सबसे बड़ी कटौतां 'सामाजिक

<sup>†</sup> इसके श्रन्तर्गत मूल योजना में दिखाया गया ८०० करोड ६० का चालू श्राय का श्रतिरेक तथा कर से पूरा होने वाला ४०० करोड ६० का घाटा भी सम्मिलित है।

## अध्याय ४१ तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

गभीर प्रश्न जो योजना श्रायोग तथा सरकार के समज्ञ है वह योजना के रूप श्रीर श्राकार के सम्बन्ध में है। तृतीय योजना के श्रारम्भ न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि द्वितीय योजना के कुछ ध्येयों की पूर्ति होना सम्मव नहीं है और देश का श्रार्थिक विकास इमारी श्राशा से कहीं कम हुश्रा है, फिर भी प्रथम श्रीर द्वितीय योजनाश्रों ने राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा श्राय, कार्य के श्रवसरों तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को प्रभावशाली ढग से बढाया है। यह सिल-**सिला चलता रहना चाहिये स्रोर इसके लि**पे श्रिधिक विस्तृत स्रौर महत्वाकात्ती नृतीय योजना की आवश्यकता है। इसके भी ध्येयों को लगमग प्रथम और द्वितीय -योजना के समान ही होना चाहिये, श्रर्थात् देश मे प्राप्त वस्तुश्रो के साधनों का सर्वोक्तब्द दग से उपयोग, ख्रोद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धो उत्पत्ति को ख्रधिक से श्रिधिक बढ़ाना ताकि काम करने के श्रवसरो की वृद्धि तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को वास्तविक रूप से ऊँचा उठाया जा सके, होना चाहिये। साराश यह कि भारत मे वास्तव रूप से कल्याग्यकारी सरकार की स्थापना हो सके। यह तो प्रत्यत्त है कि इन आदशों को पूरा कर लेने के लिये लोगों को कुछ वस्तुओं के अपने वर्तमान उपमोग को स्रविक कर (tax) देकर त्यागना पडेगा श्रोर श्रपनी बचत की मात्रा का पूँजी की वृद्धि करने के लिये बढाना पढेगा।

श्रभी तक तृतीय योजना के सम्बन्ध में मतमेद उसके श्राकार पर ही केन्द्रित रहा है। सरकारी मतानुसार तृतीय योजना का ध्येय १०,००० करोड़ रुपयों के विनियोग का ५ वर्ष की श्राधि में होना चाहिये जबिक द्वितीय योजना में प्रस्ता-वित मात्रा केवल ६२०० करोड़ रुपया ही थी। इस नीति के विरोधकों का कहना वित मात्रा का विनियोग श्रत्यधिक होगा श्रीर उन्होने यह सुमाव उपिस्त किया है कि तृतीय योजना में विनियोग का स्तर लगभग वही होना चाहिये जितना कि द्वितीय योजना में था। परन्तु तृतीय योजना के श्राकार के सम्बन्ध में मतमेद विना उसके रूप के समके श्रसगत श्रीर निरर्यक है।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक गम्भीर बात विनिमय की मात्रा में सरकारी श्रीर व्यक्तिगत चेत्रों के भाग की है। प्रथम योजना में श्रीदोगिक विकास के सम्बन्ध में व्यक्तिगत चेत्र का भाग कुल विनियोग में श्राधा या परन्तु द्वितीय

योजना मे वह घटाकर एक-तिहाई कर दिया गया था। ऐसा म्पष्ट रूप से लिखत हो रहा है कि तृतीय योजना में व्यक्तिगत चेत्र का भाग त्रोर भी श्रिधिक घटा दिया जायगा। इसका श्रर्थ यह है कि द्वितीय योजना में केन्द्रीय श्रीर राज्य सर-कारों द्वारा विकास सम्बन्धी विनियोग जो कि ४८०० करोड़ रुपया था (श्रीर जो बाद में घटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया था) उसे ७५०० करोड़ रुपया करना पहेगा यदि योजना का कुल व्यय १०००० करोड़ रुपया रख्या गया। यदि ऐसा हुआ तो १०००० करोड रुपयों के आकार की योजना देश की शक्ति के बाहर होगी स्रीर यदि लादी गई तो देश में वड़ी कठिनाई तथा स्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ४५०० करोड़ रुपयों की विकास याजना की वित्त व्यवस्था करने में वेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बहुत से नये करो का छारोप किया है छीर पहिले से श्रारोपित करों में वृद्धि की हैं जिनसे ५ वपा में ६०० वरोड़ रुपयों की कुल अतिरिक्त श्राय की श्राशा की जाती है। इन नरों के श्रतिरिक्त सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा मे घाटेकी श्रर्य-व्यवस्था भीकी है जा कि द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ६५० करोड़ रुपये की मात्रा के लगभग होगो यत्रिप सब के वित्त मत्री ने १९५९-६० तक उसका २२२ करोड़ काये ही अनुमान लगाया है। चूँकि यह सर्वं विदित है कि द्वितीय योजना की ५ वर्ष की पूरी प्रविध मे १५०० करोड़ रुपयो से य्रविक का घाटे का म्रर्थ प्रवन्धन होगा इसलिये इम यह परिगाम निकाल सकते हैं कि वित्तमत्री द्वारा श्रानुमानित मात्रा कम है। यदि सरकार श्रापनी विमास योजनाश्रों पर कर-ग्राय ग्रथवा जनता से लिये गये ऋग् का व्यय करती है तो मुद्रास्फीति उसका परिगाम नहीं होना चाहिये श्रौर उसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि भी न होनी चाहिये । ऐसा इसिलये होगा कि जनता की द्रान्यिक न्नाय, जिसमें से वह कर देती है श्रथवा सरकारी ऋगों में जिसका विनियोग करती है समान मात्रा की सेवाश्चों तथा वस्तुश्चों द्वारा सतुलित हो जाती है। यदि जनता प्रपनी श्राय का स्यय करती है तो वह इन सेवाग्रों श्रोर वस्तुश्रों का उपमोग स्वय कर लेती है श्रोर यदि वह कर (tax) देतो है श्रथवा सरकारी भ्रुण मे विनियोग करती है तो दूसरे शब्दों में वह इस प्रकार सरकार को उसी मात्रा की सेवाय्रो श्रीर वस्तुर्यो के उपभोग का स्रविकार प्रदान कर देती है। यदि सरकारी विकास योजनायों की वित्त ब्यवस्था कर-श्राय तथा ऋग् द्वारा प्राप्त धन से की जाती है तो देश में ऐसी वस्तुये श्लीर सेनायें प्राप्त होंगी जिन पर यह द्रव्य व्यय किया जा सकता है श्रीर कुछ ही समय मे ऐसी समायोजना स्वय हो जायगी कि ऐमें न्यय के कारण मूल्य स्तर में वृद्धिन हो। लगभग ऐसी ही स्थिति उस समय भी होती है जब कि विकास योजनाय्रों की वित्त व्यवस्था विदेशी त्रमुटानों प्रथवा

देश के विदेशी विनिमय निधियों से की जाती है क्यों कि यह धन भारत के वस्तुश्रों के श्रायात से ही प्राप्त होता है श्रीर इस प्रकार जो कुछ भी ज्यय सरकार योजना पर करती है उससे सद्धलित हो जाता है। यथार्थ मे ये श्रायात की हुई वस्तुये यही नहीं कि मूल्य स्तर की वृद्धि मे ही रोक्याम करें वरन् ये वास्तव में मूल्य स्तर को नीचे गिराने में सहायक होती हैं श्रीर इसलिये इन्हें हम मुद्रा सकुचन उत्पन्न करने का कारण कह सकते हैं। परन्तु ऐसा घाटे का श्रयं प्रवन्धन जिसका श्रयं ऐसी स्थित है जिसमें सरकार श्रयनी चालू कर-श्राय, श्रयण से प्राप्त धन, जमा धन श्रीर निवियाँ इत्यादि से जो कि उसके पास हैं श्रीवक व्यय करती है, मुद्रास्कीति उत्पन्न करने का कारण है श्रीर यदि इसकी कुल मात्रा श्रधिक हुई तो यह मुद्रास्कीति का बहुत श्रधिक प्रभावशाली कारण वन सकती है, रथों कि इन्य के न्यय का वस्तु की पूर्ति द्वारा इस स्थिति में सत्तलन नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि श्रपने देश में करारोप श्रपनो अधिकतम सीमा पर पहुँच चुका है और जनता विना श्रसहा कच्ट उठाये श्रव श्रीर श्रिष्क कर देने में श्रसम्पर्य है, श्रीर घाटे का श्रर्थ प्रवन्ध मयावह सीमा तक पहुँच चुका है श्रीर उसका परिणाम मुद्रास्फीति जन्य मूल्य स्तर मे वृद्धि हो चुकी है। इसिलये सरकार के लिये श्रव श्रीर श्रिषक घाटे के श्रर्थ प्रवन्धन का विचार करना श्रमुचित होगा। परन्तु यदि हमारी तृतीय योजना श्रिषक विस्तृत श्रीर महत्वाकाची है श्रीर सरकारी चेत्र श्रिषक विस्तृत है तो करों तथा घाटे के श्रर्य प्रवन्धन के स्तर को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना पढ़ेगा क्योंकि सरकार के लिये महत्वाकाची योजना को प्रा करने का कोई श्रम्य उपाय नहीं है। यदि कुल व्यय मे सरकारी चेत्र का माग श्रोर अधिक बढ़ाना है श्रीर सरकार को उसकी व्यवस्था करने के लिये धन कहीं से दूँढ निकालना है तो हमें समक्ता चाहिये कि श्रिषक विस्तृत योजना को प्रा करना हमारी सामर्थ के बाहर है चाहे हमारी कितनी ही श्रीषक श्रवश्यकता क्यों न हो।

परन्तु यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत कुल न्यय मे व्यक्तिगत त्तेत्र का माग बढ़ा दिया जाता है और यदि सरकार की आर्थिक, औद्योगिक तथा अन्य नीतियों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके उचित वातावरण का सजन किया जा सकता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हम अपनी तृतीय योजना को जिना किटिनाइयो तथा सुद्रान्स्फोति की दशा उत्पन्न किये हुये ही अदिक विस्तृत तथा महत्वाकाची बनाएँ। यह इसलिये सम्भव है कि व्यक्तिगत चेत्र में विनियोग का प्रवन्ध प्रायः बचत की मात्रा और कुछ थोड़ा सा विदेशी पूँजी से किया जाता है और यह व्यय वस्तुओं की पूर्ति द्वारा देश की आर्थिक व्यवस्था में सतुतित हो

जाता है। जहाँ तक वैंक द्वारा लिये हुये ऋगा से इसकी व्यवस्था होती है उस सीमा तक वस्तु की पूर्ति द्वारा सतुलन नहीं होता श्रीर मुद्रास्फीति उत्पन्न करने का कारण वन सकता है। परन्तु मारत में व्यक्तिगत चेन्न के कुल विनियोग के बहुत योडे से श्रश की व्यवस्था इस ढग से होती है इसलिये व्यक्तिगत चेन्न द्वारा विकास-योजना में विनियोग से मुद्रास्फीति के प्रोत्साहित होने की सम्भावना नहीं है। यही कारण है कि तृतीय योजना की रूपरेखा उसके श्राकार को प्रभावित करती है।

इसमें सदेह नहीं कि द्वितीय योजना में श्रारम्म किये हुये विकास कार्यों को उनकी शाला प्रशालाश्रों सहित तृतीय योजना में पूर्ण करना है इसलिये विनियोग की मात्रा द्वितीय योजना से श्रिषक श्रवश्य होगी। यद भी सत्य ही है कि यदि जनस्वया के श्रिषक श्रश को काम देना है तो यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि भारतवर्ष में जनता को काम करने के श्रिषक श्रवसर प्रदान किये जाने चाहियें। भारत की जनस्वया में २% की प्रतिवर्ष वृद्धि को विचाराधीन रखते हुये लोगों को वृद्धिमान रहन-सहन का स्तर प्रदान करने के लिये श्रिषक तीन गति से श्रार्थिक विकास की श्रावश्यकता है।

परन्तु यांट सरकारी चेत्र के विस्तार को बढ़ा दिया जाय तो यह सब सम्भव न हो सकेगा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग २% प्रतिवर्ष की स्त्रीसत टर से बही है स्त्रीर लगमग २७ लाख ५० हजार व्यक्तियों को काम करने के श्रविरिक्त श्रवसर प्रदान किये गये हैं जब कि द्वितीय योजना का ध्येय ५% प्रतिवर्ष की वृद्धि राष्ट्रीय श्राय में श्रीर ८० लाख व्यक्तियों को श्रुतिरिक्त काम देना निश्चित निया गया था। वृद्धि की इस दर ने जनता पर ऊँचे करों, जीवन-यापन के ऊँचे मूल्यों, और नीचे गिरे हुये रहन-सहन के दर्जे के रूप में बहुत कठिनाइयाँ लादी हैं। ताकि इन कठिनाइयों को विना स्रिधिक मात्रा से बढाये नुतीय योजना का विस्तार वढाया जा सके इसलिये योजना स्त्रायोग स्रौर सरकार ट को यह निश्चय करना पढेगा कि किसी विचारादर्श के प्रति श्रपनी ब्रास्था प्रदर्शित करने के लिये उसी पर यर्ड रहना, श्रयना ऋषिक तीव गति से देश का श्रार्थिक विकास करना देश के लिये कहाँ तक हितकर होगा। चूँ कि पूँजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवादी व्यवस्था द्वारा धीरे-धीरे लिये जाने का कार्य आरम्भ हो चुका है इसलिये वह तो श्रपना पूरा समय लेगा, परन्तु यदि उसके स्वामाविक विकास को जल्दी लाने का प्रयत्न किया गया तो इसका स्त्रर्थ स्त्रार्थिक उन्नति स्त्रीर देश की सम्पन्नता की प्रगति में बाधा हालना होगा।

नृतीय योजना की रूपरेखा का जानना उसके आकार को निश्चित

करने के लिये ही त्रावश्यक नहीं है वरन् देश को विकास योजनाम्रों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये भी श्रावश्यक है। व्यक्तिगत चेत्र को उसका उचित श्रश देने के बाद दूसरा श्रावश्यक प्रश्न योजना के श्रन्तर्गत श्राये हुये विकास कार्यों का क्रम है। क्या नृतीय योजना के विकास कार्यक्रम में कृषि को वही स्थान दिया जाना चाहिये जो कि उद्योग को दिया जाय १ द्वितीय योजना के अनुमव के द्याघार पर जिसमें कृषि को श्रौद्योगिक विकास की वुलना में कम महत्व का स्थान दिया गया था इस कह सकते है कि कृषि का स्थान श्रिधिक महत्व का होना चाहिये । दितीय योजना में सर्वप्रथम १०० लाख टन खाद्यान के उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया था जो कि बाद में बढाकर १९७५ लाख टन कर दिया गवा। द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस लक्ष्य का आपे से अधिक पूरा न किया जा सकेगा। कृषि के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप खाद्यात्र में कमी तथा उनके निरन्तर बढ़ते जाने वाल मूल्य देश के समझ आये। ऐसी अर्थ व्यवस्था में जहाँ खात्राञ्च क मूल्य का सबसे श्रिधिक महत्वशाली स्थान है वहाँ श्रम के मूल्य के बढ़ने के साथ ही साथ अन्य वस्तुत्रों के मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। श्रौर इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब वातों को उत्पन्न न होने देने के लिये तृतीय योजना में कृषि उत्पत्ति के अधिक बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसमें सैदेह नहीं कि देश की कुल आय तथा उत्पत्ति श्रीद्योगिक विकास के फलस्वरूप कृषि के विकास की वुलना में अधिक तीव गति से बढ जायगी। यही बात काम के श्रवसरों, निर्यात तथा जनता के रहन-सहन के दर्जों के बढ़ाने के सम्बन्ध में भी सत्य है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि ऐसी ब्रार्थिक उन्नीत का क्या प्रयोजन जब जनता को भर पेट भोजन मिलना ही दुष्कर हो जाय। कृषि क विकास के प्रति विशेष ध्यान देने का ऋर्य चाहे श्रार्थिक विकास में कमी करना ही क्यों न हो यह जो खिम उठाने योग्य है क्यों कि इससे ऋत की उपज तथा श्रन्य कृषि उत्पांत के बढ जाने के कारण श्रौद्योगिक विकास के लिये दृढ ग्राधार प्राप्त हो जाता है।

श्री द्योगिक विकास में वास्तविक किटनाई विभिन्न हितों क समायोजित करने की है जैसे: (१) छोटे स्तर के घरेलू उद्योग-धन्चे श्रीर ज्वाइट स्टाक कम्पनी ज्यवस्था वाले उद्ये स्तर के उद्योग, श्रोर (२) वहीं मशीनों के निर्माण करने वाले उद्याग तथा उपभोक्ता की वस्तुश्रो तथा श्रन्य छोटी-छोटो वस्तुश्रों का उत्पादन करने वाले उद्योग। भारतीय श्रार्थिक तथा उद्योग ज्यवस्था में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग-धन्घों का एक विशेष स्थान है श्रोर इसलिये उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि वडे स्तर

पर उत्पादन करने वाले उद्योगों का श्रह्ति करके ऐसा किया जाय। द्वितीय योजना में एक महान भूल बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगों की चिन्ता न करके छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाले तथा घरेलू उद्योग घन्धों को बढ़ाने की जी गई थी। इसके मूल में योजना के श्रन्तर्गत काम करने के श्रवसरों को बढ़ाने की भावना थी। इसका उदाहरण सूती कपड़ा उत्पादन करने वाले उद्योग थे। यह नीति काम के श्रवसरों के बढ़ाने में सफल नहीं हुई वरन् उसने बड़ी मात्रा में उत्पा-दन करने वाले उद्योगों को घाटा पहुँचाया। यह भूल तृतीय योजना मे बचाई जानी चाहिये श्रीर वेवल उन्हीं घरेलू उद्यागों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिनका विकास बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उत्योगों को हानि पहुँ-चाये किया जा सकता है श्रीर केवल ऐसे ही ढगो का प्रयोग विया जाना चाहिये जिनसे घरेलू उद्योगों भी तो सहायता प्रभावशाली ढग से हो पर बड़े उद्योगों मो किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। जैसे-जैसे बडी मान्ना मे उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास होता चलेगा श्रधिकाधिक काम करने के श्रवसर जनसंख्या को मिलते जायगे श्रीर इस बीच में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि श्रम-बचाव के ढग का प्रयोग न हो वरन् नये कारखानों में तथा उन पुराने कारए। नो में नहाँ मशीने बदली नाने वाली है श्राधिक कुशलता से काम लेने वाली मशीनों का प्रयोग हो।

तृतीय योजना में अधिक नृत्यूय होने के कारण ज्यों ज्यों लोगों नी श्राय बढेगी त्यों न्यों उन्हें श्रविक उपमोग की वस्तुश्रों की श्रावर्यकता होगी। मूत काल में ऐसी वस्तुयें श्रशत विदेशों में श्रपने विदेशी विनिमय निधियों के श्रीर श्रशत सुगतान सतुलन के अतिरेक के श्राघार पर श्रायात भी जा सकती थीं। श्रव उपमोक्ता की वस्तुश्रों की पूर्त देश में ही बढ़ानी है। परन्तु यदि इन्हीं उपोगों पर अधिक विनिमय कर दिया गया तो मशीनों के निर्माण, मारी रास्त्रयनिक प्रय, इन्जीनियरिंग तथा श्रन्य इस प्रकार के उद्योगों पर जो कि श्रमी भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुये हैं, श्रीर जिनके विकास को श्रीद्योगिक श्राधार प्रदान करने के लिये श्रावश्यकता है, त्यय करने के लिये पर्याप्त मात्रा से धन न वचेगा। इन उद्योगों के सम्बन्ध में योजना के हिण्टकोण से किटनाई यही है कि निकटस्य मिवष्य में ये उद्योग लोगों को इतने काम के श्रवसर न प्रदान कर सकेंगे जितने कि उपमोग की वस्तुश्रों के उत्यादन वाले उत्योगों वे विकसित करने से मिलते। इसके श्रतिरिक्त उनका उत्पादन वाजार में किती के लिये श्रधिक दिनों के पश्चात श्रायेगा श्रीर वढी हुई क्रय-शक्ति श्रधिक विनियोग होने के कारण वाजार में माल पहुँचने के पहिले पहुँच जायगी जिससे मुद्रास्कीति की स्थित उत्पन्न हो जायगी।

परन्तु इन सन काठनाइयों के होते हुये भी भारत की तृतीय योजना के प्रन्तर्गत भूत काल की श्रपेक्षा श्रिषक मात्रा में व्यय वही मशीनों के निर्माण करने वाले कारखानों के लिये नियत करना श्रावश्यक होगा।

कारखानों के लिये नियत करना श्रावश्यक हागा।

चूंकि श्रपने देश में साधन का श्रमाव है इसिलये महत्व में प्रयम वस्तु

को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिये। इसका श्रध्यं यह हुआ कि तृतीय योजना को

कार्यान्वित करने के लिये विकास से श्रसम्यन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना

कार्यान्वित करने के लिये विकास से श्रसम्यन्धित समस्त व्यय तथा तृतीय योजना

कार्यान्वित करने के लिये विकास से श्रसम्यन्धित समस्त व्या तथा हिये श्रीर मारत के

के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये श्रीर मारत के

के बाहर विकास सम्बन्धी व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिये। इस बात

सरकारी व्यय में जितनी मी मितव्ययता सम्भव हो, की जानी चाहिये। इस बात

पर बारम्वार योजना श्रायोग ने तथा सरकार ने जोर दिया है परन्तु श्रमी तक

पर बारम्वार योजना श्रायोग ने तथा सरकार ने कोई प्रयोगात्मक रूप नही दिया गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा इसे कोई प्रयोगात्मक रूप नही दिया गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा इसे कोई प्रयोगात्मक उपाय ढूँढ

योजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय ढूँढ

योजना के बाहर के व्यय को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रयोगात्मक उपाय ढूँढ